लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 16 मई, 1990/26 वैशाख, 1912११११

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
११११	1	"श्री पीयूष तिरकी" के स्थान पर "श्री पीयूष तीरकी" प्रदिये ।
११११	नीचे से 12	"287" के स्थान पर "322" प्रदिये ।
1	2	"बुधवार" के स्थान पर "बुधवार" प्रदिये ।
25	12	"सुश्चित" के स्थान पर "सुनिश्चित" प्रदिये ।
34	नीचे से 9	"ची जोसेफ एम०पी०" के स्थान पर "श्री जोसेफ एम०पी०" प्रदिये ।
63	नीचे से 14	"जालपोत" के स्थान पर "जलपोत" प्रदिये ।
95	19	"श्री सुखन्दू सिंह" के स्थान पर "श्री सुखेन्द्र सिंह" प्रदिये ।

विषय-सूची

नवम भागा, खण्ड 6, दूसरा सत्र, 1990/1911-12 (शक)

अंक 42, बुधवार, 16 मई, 1990/26 वैशाख, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 840, 841 और 845 से 847	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 3	21—27
प्रश्नों के लिखित उत्तर	27—267
तारांकित प्रश्न संख्या : 842, 843 और 848 से 859	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 8868 से 8886, 8888 से 8920, 8922 से 9000, 9002 से 9043, 9045 से 9057 और 9059 से 9105	
जभा पटल पर रखे गए पत्र	268—270
राज्य सभा से संदेश	271—273
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	273
पांचवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
अबिलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	274—278
आस्ट्रेलिया द्वारा पाकिस्तान को 50 मिराज III विमान बेचे जाने के सम्बन्ध में करार	
श्री सुधीर गिरि	274
श्री इन्द्र कुमार गुजराल	274

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

निधय 377 के अजीन मायने	278—28 0
(एक) सलेम जिले में वेयजल की कमी दूर करने हेतु गहरे कुएं खोदने के लिए तमिलनाडु सरकार को धन दिए जाने की मांग श्री पी० आर० कुमारयंगलम	278
(दो) कुमाऊं, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक सर्किट-न्यायपीठ खोले जाने की मांग श्री एम० एस० पाल	278
(तीन) चेतक एक्सप्रेस की गति बढ़ाए जाने की मांग श्री गुलाब चन्द कटारिया	279
(चार) बरेली, उत्तर प्रदेश में अधिक रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग श्री सन्तोष कुमार गंगवार	279
(पांच) धमाल, काशीपुरम, उत्तरमेकर और मधुरनचकम झीलों की मरम्मत करने/उनमें से गाद निकालने के लिए तमिलनाडु सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग श्री कांती पन्नीर सेलवम	280
(छः) केरल में वेयजल की समस्या के समाधान के लिए कवम उठाए जाने की मांग प्रो० के० बी० धामस	280
(सात) शिलांग दूरदर्शन केन्द्र में एक स्टूडियो का शीघ्र निर्माण किए जाने की मांग श्री पीटर जी० मरबनिमांग	280
अनुदानों की मांगें (साप्ताह्य), 1990-91	281—322
धन मन्त्रालय	और
और	324—339
कल्याण मन्त्रालय	
श्री गोपाल पचेरवाल	281
श्री ए० के० राय	285
श्री गोपी नाथ गजपति	289
श्री श्री० अचात	291

श्री पीयूष तिरकी	292
श्रीमती उमा गजपति राजू	294
श्रीमती सुमित्रा महाजन	295
श्री पी० वैशालैया	298
श्री रमेन्द्र कुमार रवि यादव	299
प्रो० यमुनाच पाण्डेय	302
श्री पूर्ण चन्द्र मलिक	304
श्री मानकूराम सोढ़ी	305
श्री रामेश्वर प्रसाद	307
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री	310
श्री बामनराव महाडीक	313
प्रो० प्रेम कुमार घुमाल	315
श्री पलाई के० एम० मैथ्यू	316
श्री प्यारे लाल हान्डू	317
डा० किरोड़ी लाल मीणा	319
श्री सुकदेव पासवान	321
श्री राम बिलास पासवान	324
कार्य-संरचना समिति	322
ग्यारहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	287
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91	339—350
नागर विमानन मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय और संचार मन्त्रालय द्वारा	
विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक	350—356
पुरःस्थापित	
प्रो० मधु दण्डवते	350
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
प्रो० मधु दण्डवते	350
श्री दुबराच	351
श्री गिरधारी लाल भार्ले	351
प्रो० राम गणेश कापसे	352
श्री राम माईक	353

सम्बन्धित विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
प्रो० मधु सम्बन्धते	356
वित्त विधेयक, 1990-91	356—375
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
प्रो० मधु सम्बन्धते	356
श्री बाई० एस० महाजन	362
श्री हरि शंकर महाले	367
श्री रावबजी	368
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	371
श्री हेमेश्वर सिंह बनेड़ा	373

लोक सभा

बुधवार, 16 मई, 1990/26 वैशाख, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सदन को श्री एम० कन्डप्पन के दुःखद निधन की सूचना देनी है। श्री कन्डप्पन तमिलनाडु के तिरुचेनगोडे और मेसूर निर्वाचन क्षेत्रों से क्रमशः 1962-67 और 1967-71 के दौरान तीसरी और चौथी लोक सभा के सदस्य थे।

श्री कन्डप्पन एक किसान होने के साथ-साथ जाने-माने सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, तथा ग्रामीण उत्थान तथा सामाजिक सुधारों में गहरी रुचि लेते थे।

श्री कन्डप्पन एक योग्य संसदविज्ञ थे और सभा की कार्यवाही में गहरी रुचि लेते थे। ऐसा करते हुए उन्होंने सभा की कार्यवाही में बहुमूल्य योगदान किया।

श्री कन्डप्पन का निधन 56 वर्ष की आयु में 11 मई, 1990 को मद्रास में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक करते हैं और मुझे यकीन है कि यह सभा लोक सन्तप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े हों।

(सत्सम्भात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कुब्जा नदी के जल के बंटवारे के सम्बन्ध में बैठक

*840. श्री मुस्नापल्ली रामचन्द्रन : क्या जल संसाधन बंधी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेलुगु गंगा परियोजना के माध्यम से कृष्णा नदी का जल कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बांटने के सम्बन्ध में हाल में हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला है; और

(ख) क्या जल संसाधन मंत्रालय के प्रतिनिधियों और केन्द्रीय जल आयोग के विशेषज्ञों ने बैठकों में भाग लिया था ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य सचिव श्री (श्री) मनुभाई कोटाडिया) : (क) मुख्यमंत्री आगामी विचार-विमर्श के लिए जून, 1990 में बैठक में भाग लेने हेतु सहमत हो गए हैं।

(ख) जी नहीं।

श्री मुस्लापल्ली रामचन्द्रन : तेलुगु गंगा परियोजना से कृष्णा नदी के जल का बंटवारा काफी समय से ज्वलंत विषय रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के तीनों मुख्यमंत्रियों का तिरुपति में हुआ ही में हुआ सम्मेलन इस जल विवाद की समस्या को सुलझाने की दिशा में एक महान घटना है।

क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि क्या यह सरकार तिरुपति में तीनों मुख्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों को अक्षरशः स्वीकार करती है अथवा क्या यह मध्य प्रदेश के पिछले मुख्यमंत्री श्री एन० टी० रामाराव द्वारा यह दावा करना कि वह कृष्णा नदी के अतिरिक्त जल का 2000 ईसवी तक उपभोग करेंगे, उसका समर्थन करती है।

श्री मनुभाई कोटाडिया : मेरे मंत्रालय द्वारा 5 अप्रैल को बैठक बुलाई गई थी। इसी बीच मुझे कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बीरेन्द्र पाटिल से एक पत्र मिला था।

श्री मुस्लापल्ली रामचन्द्रन : बैठक 22 अप्रैल को बुलाई गई थी।

श्री मनुभाई कोटाडिया : कृपया मेरी बात सुनिए। मेरे मंत्रालय द्वारा यहां दिल्ली में 5 अप्रैल को बैठक बुलाई गई थी। इसी बीच मुझे कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री बीरेन्द्र पाटिल का एक पत्र मिला था जिसमें यह कहा गया था कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के तीनों मुख्यमंत्रियों ने यह निर्णय लिया है कि स्वयं मिलकर इस विवाद को हल करने के लिए विचार-विमर्श करेंगे। उन्होंने मुझे लिखा कि यदि आवश्यक हुआ तो भविष्य में केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करेंगे।

(व्यवधान)

श्री मुस्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, यह उत्तर सही नहीं है। जल एक राष्ट्रीय सम्पत्ति है और ये सभी नदियां इस देश की हैं। सम्पूर्ण देश में जल विवादों से उठने वाली विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार की इस समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय जल न्यायाधिकरण स्थापित करने की कोई योजना है? मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सरकार अतिरिक्त जल के उचित बंटवारे को सुनिश्चित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय जल सिंडीकेट स्थापित करने के लिए कुछ निश्चित कार्यक्रम लाएगी।

श्री मनुभाई कोटाडिया : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रश्न का विषय बहुत ही सीमित है। यह केवल कृष्णा जल न्यायाधिकरण निर्णय से सम्बन्धित है। सम्बन्धित राज्यों ने इस विषय को

उठाया था—क्या इसे हल किया जाएगा अथवा नहीं और इसे हल करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं... (व्यवधान)

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : इस समस्या को हल करने की दृष्टि से मैं केवल मन्त्री से पूछ रहा हूँ।

श्री मनुभाई कोटाड़िया : मुझे यह निवेदन करना है कि कृष्णा जल न्यायाधिकरण ने पहले ही यह निर्णय दे दिया है कि इतना जल कर्नाटक को, इतना जल आन्ध्र प्रदेश को और इतना जल महाराष्ट्र को जाएगा। (व्यवधान)

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : इस निर्णय में भी काफी अन्तर है। (व्यवधान)

श्री मनुभाई कोटाड़िया : सम्बन्धित राज्यों द्वारा जो विषय उठाया गया था वह केवल मद्रास शहर को पीने के प्रयोजन के लिए 15 टी० एम० सी० जल की सप्लाई के बारे में है। (व्यवधान)

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : यह मेरा प्रश्न नहीं है। मैंने तमिलनाडु के बारे में कभी नहीं पूछा है। यह बिल्कुल भिन्न है। (व्यवधान)

श्री बाई० एस० राजशेखर रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, तेलुगु-गंगा परियोजना के दो हिस्से हैं। एक मद्रास को जल सप्लाई का है और दूसरा रायलसीमा में लगभग दो लाख एकड़ भूमि को जल सप्लाई का है। यह परियोजना विशेष लगभग पांच अथवा 6 वर्ष पहले शुरू की गई थी और इस परियोजना पर लगभग 30 करोड़ रुपए की धनराशि पहले ही खर्च की जा चुकी है। लेकिन यह परियोजना आन्ध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री एन० टी० रामाराव के अड़ियल रवैये के कारण अनावश्यक रूप से स्वयं विवाद का विषय बन गया। अतिरिक्त जल की दलील स्वयं राज्यों के हित के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस परियोजना के शुरू होने के समय से ही, हम प्रायः यह तर्क दे रहे थे कि तेलुगु-गंगा परियोजना अथवा परियोजना का कोई भी नाम है, आन्ध्र प्रदेश को निश्चित रूप से जल का आश्वासन दिया जाना चाहिए जो कि बचाव समिति की सिफारिशों के अनुसार निर्णय किया गया है। इसके बारे में कोई सदिग्धता नहीं है। यहाँ तक कि अब भी हम माननीय मंत्री से अनुरोध करते हैं, कि तेलुगु-गंगा परियोजना को बिल्कुल स्वीकृति न दी जाए यदि यह अतिरिक्त जल पर आधारित है। हमारा निश्चित मत है कि केन्द्रीय सरकार को इस बात पर जोर देना चाहिए...

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया ब्याख्या कीजिए। कृपया सूचना देने की बजाय प्रश्न पूछिए।

श्री बाई० एस० राजशेखर रेड्डी : मैं इसकी ओर आ रहा हूँ (व्यवधान) हम मन्त्री महोदय से अनुरोध कर रहे हैं कि इस परियोजना विशेष को सकारात्मक स्वीकृति केवल तभी दें यदि राज्य सरकारें बचाव समिति के निर्णय के अन्तर्गत वायदे के अनुसार जल देने का आश्वासन देती हैं। (व्यवधान) क्या मन्त्री महोदय स्पष्ट रूप से आश्वासन देंगे कि इस परियोजना को स्वीकृति केवल तभी जाएगी कि यदि राज्य सरकार वायदे के अनुसार जल देने को कहती हैं।

श्री मनुभाई कोटाड़िया : यदि राज्य सरकारें हमारे पास आती हैं तो हम विषय को हल करने के लिए तैयार हैं। यदि सभी सम्बन्धित पक्ष कहते हैं कि हम स्वयं इस विषय को हल करने का प्रयास कर रहे हैं, तब मैं किस प्रकार हस्तक्षेप कर सकता हूँ ?

श्री बाई० एस० राजशेखर रेड्डी : महोदय, यह मेरा प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दिया था कि यदि सभी राज्य सरकारें सहमत हैं, तब वह इस पर विचार कर सकते हैं। मेरे विचार में, यही उनका मुद्दा है।

(अध्यक्षान)

श्री बाई० एस० राजरोजर रेड्डी : महोदय, यह बैठक केवल दिखावा है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं। श्री नार्क।

[हिन्दी]

श्री राम नार्क : माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर तीन राज्यों का सवाल है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश। संयोग से इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री कांग्रेसी हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण भी है लेकिन तीनों साथ में नहीं आ रहे हैं। इनके पहले जो आये, उन्होंने कुछ रास्ता निकाला परन्तु इन तीनों की यह परम्परा ऐसी है कि कोई समस्या को सुलझाना नहीं, उसको लटकाना ही है।

मेरा सवाल यह है कि अनुभव को ब्याल में रखते हुए केन्द्रीय सरकार को फोर्सफुली इन्टरवीन करके कोई ऐसी मीटिंग कराकर इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्य करना चाहिए ताकि कोई रिजल्ट तो आए, ऐसा कोई काम माननीय मंत्री महोदय करेंगे?

श्री अनुभाई कोटाड़िया : श्री राम नार्क जी ने अच्छी बात की है।

[अनुवाद]

यदि सम्बन्धित राज्य कहते हैं कि वे स्वयं इस समस्या को हल कर लेंगे। मैं नहीं समझता कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। (अध्यक्षान)

श्री जगदीश गुजारी : दुर्भाग्यवश, माननीय मंत्री महोदय इस विषय के बारे में पूर्ण तथ्यों से अवगत नहीं हैं। यह विवाद मद्रास शहर को जल की सप्लाई के सम्बन्ध में नहीं है। तीन राज्य, अर्थात्, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र कृष्णा जल में अपने-अपने हिस्से से प्रत्येक 5 टी० एम० सी० पेय-जल मद्रास शहर को पूर्ति करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बारे में कोई विवाद नहीं है। विवाद तो अतिरिक्त उपसब्ध जल से जल के बंटवारे के बारे में है। आन्ध्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री एन० टी० रामाराव अतिरिक्त जल को सिंचाई कार्यों के लिए प्रयोग करना चाहते थे। लेकिन अन्य राज्य उनके इस विचार से सहमत नहीं थे। संघीय ढांचे में, इस प्रकार के विवाद बातचीत और सद्भाव से हल किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री इस सम्बन्ध में मिलते रहे हैं। यह विवाद केवल कम उठा है। लेकिन यह विवाद 1952 से रहा है। केन्द्रीय सरकार यह कहकर अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती कि उसका इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है और केवल तीन मुख्यमंत्रियों को बैठक बुलाने आदि के लिए सहमत होना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध कर रहा हूँ कि सभी सम्बन्धित मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाए और इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए इस विवाद को हल करें।

श्री अनुभाई कोटाड़िया : महोदय, मुझे कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा लिखा गया पत्र पढ़ने की अनुमति दी जाए "आपने 7 अप्रैल, 1990 को कृष्णा नदी जल विवाद पर विचार करने के लिए आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी। इन परिस्थितियों में 7 अप्रैल, 1990 को आपके द्वारा दिल्ली में बुलाई गई बैठक में कृष्णा जल के बंटवारे के प्रश्न को

विचार के लिए लिये जाने की आवश्यकता नहीं, और केवल काबेरी जल विवाद पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, कृष्णा जल मामले पर विचार करने के बाद, यदि हम यह महसूस करेंगे कि आपके हस्तक्षेप की अभी भी आवश्यकता होगी तो हम आपके पास आएंगे।" अभी तक हमें किसी भी सरकार से कोई सन्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयबन्ती नवीनचन्द्र मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि यह मामला पानी का है। जैसे इसके पहले कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमा के सबालों को आज तक लटकाये रखकर अलग-अलग प्रकार से मतभेदों को जागृत किया गया है, उसी प्रकार से इसका भी यही हाल है। फिर इसके अलावा हमें नर्मदा के सबाल पर भी इस प्रकार के मतभेदों की बातें सुनने को मिलती हैं। क्या इस कृष्णा के पानी के बारे में केन्द्रीय सरकार जल्दी कोई निर्णय लेकर, शीघ्रांतशीघ्र निर्णय लेकर, काम करना चाहती है। ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय स्वयं स्पष्ट नहीं कर पाये हैं क्योंकि जब प्रश्न में उनसे पूछा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बाटर रिसोर्सेज से सम्बन्धित एक्सपर्ट्स उस मीटिंग में उपस्थित थे या नहीं तो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि कोई एक्सपर्ट उपस्थित नहीं था। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मिलने के लिए ही वह मीटिंग बुलाई गयी थी, एक्सपर्ट लोगों का उसमें उपस्थित रहना किस वजह से आवश्यक नहीं समझा गया। एक्सपर्ट लोग उसमें क्यों उपस्थित नहीं थे। दूसरे, मेरा मूलभूत सबाल यह है कि नदियों के पानी से सम्बन्धित जो समस्या होती है, उसे सानों तक क्यों लटकाये रखा जाता है। जब इस ईशू में पानी के बंटवारे का सबाल है तो क्या केन्द्रीय सरकार अपना पानी दिखाएगी, इस सबाल को सुलझाने का प्रयत्न करेगी।

श्री मनुभाई कोटाडिंबा : जहाँ तक इस सरकार के पानी दिखाने का सम्बन्ध है, जहाँ ज़रूरत होती है, वहाँ यह सरकार अवश्य पानी दिखाती है और दिखाया भी है। यहाँ जयबन्ती बहन ने दो-तीन सबाल मुख्य रूप से उठाये। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि उस मीटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एक्सपर्ट हाज़िर क्यों नहीं रहा, उन्हें मालूम होना चाहिए कि वह मीटिंग चीफ मिनिस्टर्स ने ही बुलाई थी, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने नहीं बुलाई थी। हमें तो मात्र शामिल होने का निमंत्रण भर दिया गया था, बल्कि देखा जाये तो निमंत्रित भी नहीं किया गया था। इसलिए वह मीटिंग तीनों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स की थी। जैसे मैंने अभी पढ़कर बताया, हमें जैसे ही बोल भर दिया था कि हम लोग चाहें तो आ सकते हैं : बी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व बिदिन अबरसेल्सज, इसके आगे कहा गया है कि इफ इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नेसेसरी देन बी बिल एप्रोच यू, सिर्फ इतना ही हमें बोला था। यही कारण है कि हमारा कोई उच्च अधिकारी उस मीटिंग में नहीं गया। जहाँ तक पानी के बंटवारे का सबाल है, कृष्णा बेसिन में 2060 टी० एम० सी० पानी है, जिसका बंटवारा किया गया है। पूरे पानी का इस्तेमाल हो रहा है इसलिए नेशनल बेस्टेज का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न सिर्फ यह रह जाता है कि तीनों राज्यों के बीच कितने-कितने पानी का उपभोग हो, किस राज्य के हिस्से कितना पानी आवे और यह ईशू अभी चल रहा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० तन्वि बुरै : तेलुगु गंगा परियोजना केवल आन्ध्र प्रदेश के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह तमिलनाडु राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है।

एक सामग्रीय सचस्य : हमें कोई आपत्ति नहीं है।

डा० तन्वि दुरै : आपको कोई आपत्ति नहीं है परन्तु हमें पानी नहीं मिल सकता। मद्रास शहर में पानी की बड़ी कमी है। इस समस्या के समाधान के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तमिल के मुख्यमंत्रियों को पीने के लिए कृष्णा नदी का फालतू पानी मिलाने की आज्ञा है। परन्तु यहाँ मन्त्री महोदय बता रहे हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए बातचीत करने हेतु विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जा रहा है। मैं नहीं सोचता कि हम बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान कर सकते हैं। हाल ही हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि बातचीत के माध्यम से अन्तर्राज्यीय विवादों को हल करना सम्भव नहीं था क्योंकि विभिन्न राज्यों की राजनैतिक समस्याएँ हैं। पहले जब हमने पिछली सभा में तेलगू गंगा परियोजना के बारे में चर्चा की थी तो राष्ट्रीय मोर्चा तेलगू देशम सभा जनता दल के सदस्यों ने राजनैतिक कारणों से बिलम्ब की आलोचना की थी। अब वे सत्ता में हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि वे इस समस्या का समाधान किस प्रकार करेंगे तथा मद्रास शहर को पेय-जल की पर्याप्त आपूर्ति की जाएगी। तमिलनाडु सरकार ने भी इस परियोजना पर बहुत अधिक मात्रा में धनराशि व्यय की है।

[हिन्दी]

श्री मनुभाई कोटाड़िया : मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी एक ईशू को सोल्व करने में मद्रास सिटी को पानी देने में कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि (व्यवधान) क्योंकि तेलगू गंगा बांध का काम अभी चल रहा है और उस पर आज तक 306 करोड़ रुपये खर्च आ चुके हैं। उसके बाद कैनाल का सवाल है, जो कैनाल वहाँ निकलने वाली है, उसका काम भी चल रहा है। उसमें से रॉयलसीमा के लिए 29 टी० एम० सी० पानी दिया जाए या नहीं, इस मामले में आन्ध्रप्रदेश कहता है कि हमें 29 टी० एम० सी० पानी की जरूरत है और हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तक कूसरी दोनों स्टेट्स यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक का सवाल है, वे कह रही हैं कि यहाँ पानी ज्यादा नहीं है इसलिए वे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही सिर्फ ईशू सेंटल करने के लिए बाकी है। मद्रास सिटी को 15 टी० एम० सी० पानी देने का प्रश्न अलग से लिया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री के० एस्० राव : महोदय, मैंने पहले भी कहा था कि सदस्यों और सभा का समय बचाने के लिए इतिहास को देखा जाए। हमें उन्हें अपेक्षित जानकारी प्रदान करने के लिए वेतन नहीं दिया जाता है। अधिकारियों को उन्हें अपेक्षित जानकारी प्रदान करने के लिए वेतन दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। कृपया, आप प्रश्न के सम्बन्ध में बात कीजिए।

श्री के० एस्० राव : जैसाकि कुछ समय पहले श्री तन्वि दुरै कह रहे थे तथा जल संसाधन मंत्रालय की मांगों के बारे में चर्चा के दौरान मैंने भी कहा था कि नीति निर्माण में जल संसाधन मंत्रालय की भूमिका समन्वय करने की है। परन्तु वे कहते हैं कि जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक वह पानी के दुरुपयोग की, जो वहाँ किया जा रहा है, जांच नहीं करेंगे। वह अपनी कुर्सी पर बैठकर पानी के दुरुपयोग अथवा जल संसाधनों के अभाव को देखते रहेगे। पहले श्री एन० टी० रामाराव के अहं के कारण विवाद पैदा हुआ था। तत्कालीन जल संसाधन मन्त्री ने पहलू की ओर बैठक बुलाई। मैं सभा को बताना चाहता हूँ कि उस समय बैठक बुलाने के बावजूद भी उन सदस्यों ने, जो आज सत्रकक्ष पक्ष के

हैं, केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध समस्या का समाधान न करने का आरोप लगाया था। इसके विपरीत अब वह कहते हैं कि यह उनका कार्य नहीं है।

जनता द्वारा जल संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वे आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र अथवा तमिलनाडु के हों। यह स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य के बीच विवाद है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे इसमें जनता दल अथवा कांग्रेस पार्टी का शासन है। प्रश्न यह है कि मामले को अभी तक नहीं सुलझाया गया है। इसलिए इन सब बातों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब तक केन्द्रीय सरकार और जल संसाधन मन्त्री सभा को विश्वास में लेकर कोई निर्णय नहीं करेंगे तब तक पानी की समुची मात्रा बर्बाद होती रहेगी और वहाँ बाढ़ तथा तबाही मची रहेगी। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह अपने बक्तव्य में परिवर्तन करेंगे और समस्या के समाधान के लिए केन्द्र की ओर से बैठक बुलायेंगे जो जनता दल के हित में है।

श्री जगन्नाई कौटारिकिया : जैसाकि कर्नाटक के मन्त्री ने लिखा है कि वे जून में पुनः बैठक बुला रहे हैं। उन्हें इस पर विचार-विमर्श करने दीजिए। यदि वे निष्कर्ष निकालने में असमर्थ रहेंगे अथवा हमसे अनुरोध करेंगे तो हम उनके साथ विचार करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो हम निश्चित रूप से बैठक बुलायेंगे।

सेवानिवृत्त व्यक्ति योजना के अन्तर्गत आवेदन

*841. श्री रामजी लाल सुधन : क्या साहूरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सेवानिवृत्त व्यक्ति योजना के अन्तर्गत न्यू "हुडको" पैटर्न स्कीम, 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये थे;

(ख) क्या कुछ ऐसे मामले सरकार के ध्यान में आये हैं जिनमें सेवानिवृत्त व्यक्ति इस योजना की जानकारी न होने के कारण आवास के आबंटन हेतु निर्धारित समयबाध के अन्दर आवेदन नहीं कर पाये; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का ऐसे व्यक्तियों को एक और अवसर प्रदान करने का विचार है ताकि ये लोग फ्लैट आबंटन हेतु आवेदन कर सकें ?

साहूरी विकास मंत्री (श्री सुरासोली बारन) : (क) जी, हाँ।

(ख) उन व्यक्तियों से ऐसे कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो समय पर आवेदन नहीं कर पाये, यद्यपि, समाचारपत्रों में व्यापक प्रचार किया गया था।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण सेवा-निवृत्त हुए/सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर अवसर देता है। जो व्यक्ति गत अवसर पर चूक गये वे आगे आवेदनपत्र आमंत्रित किए जाने पर आवेदन कर सकते हैं।

[द्वितीय]

श्री रामजी लाल सुधन : अध्यक्ष महोदय, डी० डी० ए० 1979 में एक नियम बनाया था रिटायर्ड पब्लिक स्कीम के नाम से कि इसके अन्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर

प्लाट्स और भवन देने का काम डी० डी० ए० करेगा। ये कर्मचारी जिन्होंने इस स्कीम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, 1979 से बराबर डी० डी० ए० के सम्पर्क में हैं। इन्होंने 1987 में और 1988 में डी० डी० ए० को लिखा और 1989 में जब सरकार ने फ़ैसला किया, तो कुछ ऐसे समाचार-पत्रों में बिज्ञापन छपा जिसको लोग पढ़ नहीं पाए जिसके कारण काफी संख्या में लोग बंचित रह गए हैं। जो शेष सेवा-निवृत्त कर्मचारी हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर प्लाट और भवन देने का काम कब तक करेंगे ?

[अनुबाध]

श्री सुरासोली भारन : महोदय, मैंने मुख्य जवाब में बताया है कि नवम्बर, 1988, अक्टूबर, 1989 तथा जनवरी, 1990 के द्वा में 145 व्यक्ति रह गए। 145 में से 94 आवेदन पत्रों को आबंटन की स्वीकृति दे दी गयी थी परन्तु तृतीय श्रेणी के फ्लैट उपलब्ध न होने के कारण वे सम्बित हैं। इन्हें चालू वर्ष के दौरान निपटाए जाने की संभावना है। 51 आवेदन पत्रों को, जो अधूरे पाए गये अथवा अपात्र व्यक्तियों के थे, अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया। इस प्रकार शेष 94 आवेदकों को चालू वर्ष के दौरान फ्लैट मिल जायेंगे।

[हिनवी]

श्री रामजी लाल सुनन : अध्यक्ष महोदय, बार-बार लोगों को यह कहा जाता रहा कि प्राथमिकता के आधार पर हम भवन देंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कोई निश्चित अवधि है, कोई वक़्त मुकरर करेंगे जब तक प्राथमिकता के आधार पर भवन देंगे, कब तक देने का काम करेंगे ?

[अनुबाध]

श्री सुरासोली भारन : आप जानते हैं कि अधिक आवेदक नहीं बचे हैं। इसकी संख्या 94 है। इसलिए कुछ महीनों के अन्दर अर्थात् इस वर्ष के अन्त में उन्हें भी मकान मिल जाएगा।

[हिनवी]

श्री मदन लाल सुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि 1979 में जो टोटल नम्बर रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें पिछले दस सालों में कितने दिए गए और कितना बकाया है, उसके लिए क्या किया जा रहा है ? हम जानना चाहते हैं कि उनकी मनी का क्या हुआ क्योंकि इनट्रस्टिंग यह है कि 1979 में एक लाख 75 हजार लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, 16 करोड़ रुपया आया, उस समय सरकार ने मकान देने के बजाए एशियाइ 82 के नाम पर होटल बनाने शुरू कर दिए जो बने ही नहीं। मेरा निवेदन है कि 1979 में कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, आज बकाया कितने हैं और पिछले दस सालों में कितने दिए, यह बता दें ?

[अनुबाध]

श्री सुरासोली भारन : महोदय, वित्तीय विकास प्राधिकरण ने अभी तक 17 योजनाएं चलायी हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत 3,18,855 व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया है। इनमें से 31 मार्च, 1990 तक 1,91,916 व्यक्तियों को आबंटन किया गया है। 1-4-1990 तक 1,18,580 व्यक्ति शेष बचे थे। डी० डी० ए० ने आगामी चार वर्षों के लिए संवर्गी योजना बनायी है। वे इसे 1991

तक पूरा करना चाहते हैं। 1991-92 में 19,000, 1992-93 में 26,000 और 1993-94 में 26,500 फ्लैट्स तैयार कर दिए जाएंगे। वे एक साथ 84,100 फ्लैट्स तैयार करना चाहते हैं। यह संदर्शी योजना है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों के उचित मार्गदर्शन से इसे पूरा कर देंगे।

श्री सन्तोष मोहन बेब : मैं मंत्री महोदय से सेवानिवृत्त व्यक्तियों की श्रेणी के बारे में जानना चाहता हूँ। जब आप उन्हें श्रेणीबद्ध करते हैं तो सेवानिवृत्त राजनीतिज्ञों के, जो सांसद के रूप में चुनाव हार चुके हैं, सम्बन्ध में भी विचार किया जा रहा है।

श्री भुरासोली भारन : यह केवल सेवानिवृत्त अथवा सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के लिए है। राजनीतिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते हैं।

[हिन्दी]

श्री कृपाल सिंह : मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि क्या स्कीम आइन्दा भी जारी रहेगी। जो लोग रिटायर हो रहे हैं या अगले साल रिटायर होंगे, वे भी इनकी लिस्ट का पार्ट बनते जाएंगे और रिटायर करने वाले लोगों में शामिल होते रहेंगे या यह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने आज तक ऐप्साई किया है, जो अगले साल रिटायर होने वाले हैं। यह स्कीम परमानेंट है या टैम्पोरेरी है ?

[अनुबाध]

श्री भुरासोली भारन : महोदय, यह स्थायी योजना नहीं है। परन्तु इस योजना के अनुसार विसम्बर 1991 तक सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। यदि आवश्यक हुआ तो हम ऐसी अन्य योजनाएं भी चला सकते हैं।

आदिवासियों के उत्थान पर निगरानी रखने के लिए समिति

*845. श्री गुलाब चन्द कठारिया : क्या अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन शिकायतों की जानकारी है कि आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रदान की जाने वाली करोड़ों रुपए की धनराशि आदिवासियों तक नहीं पहुंचती है; और

(ख) क्या सरकार का आदिवासियों के उत्थान पर खर्च की जाने वाली धनराशि के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए प्रत्येक राज्य में एक समिति गठित करने का विचार है ?

[हिन्दी]

अन्न एवं कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत निवेशों का एक भाग आदिवासी क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास के लिए होता है। इनके लाभ सीधे ही और तुरन्त अथवा पर्याप्त रूप से आदिवासियों तक नहीं पहुंचते। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी विकास सम्बन्धी कार्यदल द्वारा इसका पता लगाया गया है तथा आदिवासी उपयोजना कार्य-नीति से आदिवासियों के सर्वोत्तम हितसाधन हेतु विभिन्न उपचारात्मक/एहतिवासी उपायों की सिफारिश की गई है। इनमें अवसंरचना विकास से हटकर परिवार लाभदायी उन्मुक्त स्कीमों का महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल है।

(ख) आदिवासी उपयोजना कार्यान्वित करने वाली राज्य सरकारों द्वारा आदिवासी विकास

श्रीलंका के सप्त-सप्त उच्च अन्तर्गत निधियों के उपयोग को मॉनीटर करने तथा समीक्षा करने के लिए विश्विज्ञान केंद्रों पर सख्त ही समितियां बठित की जा चुकी हैं। समय-समय पर राज्य सरकारों को अपने सर्वोद्वेग्य तम्य प्रतीक्षा प्रकल्पों को प्रभावी बनाने हेतु इन्हें सुदृढ़ करने के लिए लिखा गया है।

श्री गुणाल जय कृदारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि आदिवासी योजनाओं के तहत अब तक हमने करोड़ों रुपया खर्च किया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ नहीं मिला। जितना भी किसी बड़ी योजना में पैसा जाना चाहिए था वह सारा पैसा उसमें ट्रांसफर कर दिया। आदिवासियों के नाम से आया हुआ पैसा जो था, वास्तव में उसका बहुत बड़ा भाग दूसरी योजनाओं में और उनके अपने क्षेत्र में जो योजना थी, उस पर उसको खर्च कर दिया लेकिन उसका लाभ उन आदिवासियों और गरीब लोगों को नहीं मिला; 42 वर्ष की आजादी के त्वाप एक कौड़ी भी उसकी आय में वृद्धि नहीं हुई है।

श्री राध बिलास बासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जहाँ तक प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत झटपट है। आदिवासियों के विकास के ऊपर कितनी धनराशि खर्च की गई, यदि हम उस मात्रा को देखते हैं तो पता लगता है उससे उनको समुचित लाभ नहीं हुआ है। जो पांचवीं योजना थी उसमें एक हजार करोड़ रुपए आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर रखे गए थे और खर्च भी हुए। छठी पंचवर्षीय योजना में पांच हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए और सातवीं पंचवर्षीय योजना में 10 हजार करोड़ रुपए उनके ऊपर खर्च किए गए। यदि हम ये सब देखेंगे तो पता लगेगा कि 16 हजार करोड़ रुपए आदिवासियों के नाम पर खर्च किए गए। इसके विपरीत यदि अनुपात में लाभ को देखते हैं तो कहीं उसका लाभ नजर नहीं आता है। उसमें खर्च भी कुछ इस किस्म के रखे गए हैं कि अगर 40 परसेंट खर्चा है और जो ग्रेजर प्रोजेक्ट के लिए है जिसमें त्रिजली लगेगी, नेशनल हाई-वे बनेगा, उसको वहाँ से डाइवर्ट कर दिया जाता है। देखा यह जाता है कि दूसरे गांव में बिजली लग जाती है, लेकिन जो आदिवासियों के गांव हैं वहाँ बिजली के बर्तन नहीं हो पाते हैं; 40 परसेंट पैसा ऐसे ही चला जाता है और जो 20 परसेंट पैसा फीमिली ओरियंटड प्लान के अन्तर्गत शेडयूल्ड ट्राइब्स के परिवार के लोगों को सहायता के नाम पर दिया जाता है वह कुछ थोड़ा बहुत उनके पास पहुंच पाता है। जो बुनियादी लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर है या कोई माइनर इरिगेशन है, उनके ऊपर 40 परसेंट में से खर्चा होता है। कल हम इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री जी से भी मिलने वाले हैं और हमने योजना आयोग को भी लिखा है। माननीय सदस्य का जो दुष्टिकोण है और जो उन्होंने शिकायत की है, उसमें सत्यता है। हम निश्चित रूप से इसको नये ढंग से करेंगे।

श्री गुणाल जय कृदारिया : अध्यक्ष महोदय, इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए जो भी संस्थाएं त्वा रकी हैं, उनसे इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रहा है। इस कारण से वे संस्थाएं वास्तविकता की जानकारी नहीं देते कि इनकी ये समस्याएं हैं। ग्रेरे क्षेत्र में विशेषकर गुजरात, राजस्थान और मुख्य प्रदेस के जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ एक आग सुलग रही है। अगर आपने उनकी समस्या का प्रथम पर निदान नहीं किया तो अलग से प्रान्त की मांग ये लोग करने लगेंगे और यह मांग करेंगे कि क्यारे आदिवासी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रान्त बनाया जाए जिससे वे अपने हकों की रक्षा कर सकें और उन्हें लाभ मिल सकें। इस प्रकार का आन्दोलन न हो, इस कारण इसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई ऐसी संस्था का आप चयन करने वाले हैं जो हमेशा उनके दफ्तर में उनकी समस्याओं को सुनते रहें और ठीक प्रकार से उनकी समस्याओं का निदान कर सकें।

श्री राम बिलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो तरह के मामले हैं। यह सही है कि जो उनके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाए। जो स्वसंसेवी संस्थाएं हैं वह भी इस कार्य में लगी हुई हैं। राज्य सरकार के द्वारा ही यह सारा खर्चा होता है। दूसरी बात यह है कि हमें व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। राज्य सरकारें अपने बजट में विभिन्न प्रावधान करती हैं। अगर कहीं 10 परसेंट या 7 परसेंट सेड्यूल्ड-ट्राइम्स के लीग हैं तो ऐसे में कहा जाता है कि इतने सेड्यूल्ड-ट्राइम्स के लोग हैं तो उसको अलग किया जाए। लेकिन उसका अलग खर्च का विधान नहीं है। राज्य सरकार ही उसकी खर्च करती है। यदि ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में ही ट्राइबल डेवलपमेंट बोर्ड हो तो उस बोर्ड को पैसा दे दिया जाता है। ऐसे में बोर्ड सुनिश्चित करे कि आदिवासी इलाकों में किस चीज की जरूरत है। कहां रोड बननी है और कहां बिजली को पहुंचाना है। लेकिन देखने में यह आया है कि इसको जरूरतलाइज कर दिया जाता है जिससे आदिवासियों को लाभ नहीं मिलता है। पैसा कैसे खर्च हो और उसको कैसे उपयोग किया जाए, इसको भी हम देख रहे हैं।

प्रो० राम गणेश कापसे : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में ऐसी व्यवस्था है कि शी०पी०डी०सी० में आदिवासी उपयोजना के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, वह अलग से किया जाता है और जनरल बजट अलग रहता है। इसकी सब व्यवस्था इस तरह से रहती है कि केवल आदिवासी एम०एस० ए० और एम०पीज० उसमें जुड़े हुए रहते हैं। इसकी व्यवस्था इसी तरह देश भर में हो और आदिवासी हित के कमीशन को स्टैंडुटरी पावर्स मिलें, इस तरह की व्यवस्था करने के बारे में खासन सोचता है क्या ?

श्री राम बिलास पासवान : निश्चित रूप से मैं देखूंगा। महाराष्ट्र में जैसा इन्होंने कहा कि इस तरह से है तो हम उसको निश्चित रूप से सींचेंगे, सींचेंगे ही नहीं बल्कि करेंगे और यदि उससे भी अच्छी व्यवस्था हो सकेगी तो उसको भी करेंगे। जहां तक सेड्यूल्ड कास्ट्स, सेड्यूल्ड ट्राइम्स कमीशन की बात है, सरकार ने इसका फैसला कर लिया है कि हम उसको स्टैंडुटरी पावर्स देंगे।

[अनुवाद]

प्रो० के० बी० बामन : आदिवासी लीगों की भलाई के लिए बड़ी धनराशि खर्च की गयी है। परन्तु वास्तव में उन्हें वह सहायता नहीं मिल रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि वे शिक्षित नहीं हैं। यदि वे शिक्षित हो जाएं तो वे अपने अधिकारों के बारे में जान जाएंगे। क्या सरकार उन्हें शिक्षित करने के कार्य को प्राथमिकता देगी ताकि यदि वे एक बार शिक्षित हो जाते हैं तो वे अपने काम खुद करने में सक्षम हो जाएंगे ?

[हिन्दी]

श्री राम बिलास पासवान : निश्चित रूप से वह विचार सराहनीय है।

श्री आरिफ बेग : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मायबर मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि अभी मन्त्री जी ने खुद कहा कि पिछली योजनाओं में लगभग 16 हजार करोड़ रुपए आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर खर्च किए गए लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि उन इलाकों में अभी तक इस पैसे को लगाया गया, इस बात का कोई बर्तन नहीं होता, कहीं गबर ही नहीं आता। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस पैसे को कहां खर्च किया गया, क्या इसकी कम्पाचरी करपाये मन्त्री महोदय ? इस

पैसे को खर्च करने के लिए जो बहुत बड़ी सरकारी अफसरों की फौज खड़ी है, इस सफेद हाथी को हटाकर सीधे-सीधे इस रूप को खर्च करने का काम आदिवासी प्रतिनिधियों को देंगे क्या ?

श्री राम बिलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि जो खर्च किए गए हैं, जो राज्य सरकार ने खर्चा किया है, टोटल उसी में से निकाला गया है। आदिवासी क्षेत्र में वह खर्च हुआ है, राज्य सरकार द्वारा, तो उसकी जांच भी केन्द्र सरकार करवाती रहती है। वैंलफेयर मिनिस्ट्री के पास इतने साधन नहीं हैं कि सबकी जांच करवा सके लेकिन जैसा मैंने कहा कि निश्चित रूप से हम भविष्य में यह देखेंगे और यह भी देखेंगे कि कोई प्लान बने तो राज्य स्तर पर नहीं बनाया जाए बल्कि अभी जो आई० टी० सी० पी० चल रहा है, इण्टीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, हम चाहते हैं कि ओ भी खर्चा हो, वह लोकल स्तर पर प्रोजेक्ट बनाया जाए, वहां किस चीज की आवश्यकता है। यदि स्थानीय चीज को देखकर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उससे ज्यादा लाभ पहुंचेगा बजाय इसके कि सेन्ट्रल और स्टेट लेविल पर प्लान बनाएं।

श्री बाळू दयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि इतना सारा व्यय कर देने के बावजूद वर्तमान में महिला शिक्षा का प्रतिशत यो है ? क्या यह भी सही है कि केन्द्र सरकार ने कोई सैम्पल सर्वे कराया था जिसके तहत यह पता लगाना था कि प्रति व्यक्ति इतनी आय इस आदिवासी की बढ़ी ? क्या मन्त्री महोदय यह विचार करते हैं कि आदिवासी जनकल्याण के लिए अलग से कोई मंत्रालय बनाया जाए या बोर्ड का गठन किया जाए ? कृपया तीनों बातों का उत्तर दें।

श्री राम बिलास पासवान : पहले प्रश्न के लिए नोटिस नहीं दूँगे तो भी जवाब भेज देंगे लेकिन यहाँ तक दूसरा प्रश्न है, अनुसूचित जाति, जनजाति वैंलफेयर मिनिस्ट्री आदिवासी समस्या को देख रही है और हमारे पास जो कमीशंस हैं, वह इसकी मोनेटरिंग करते हैं।

श्री बाळू दयाल जोशी : रिजस्ट क्या आया, यह नहीं बताया।

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, बैठ जाएं। आप प्रश्न पूछ चुके हैं। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दिया हूँ। आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि धनराशि खर्च की गयी है, विकास नहीं हो रहा है और पृथक्तावादी गतिविधियों जैसे अनेक कार्य हो रहे हैं। क्या सरकार संविधान के प्रावधानों को कार्यान्वित करने पर विचार करेगी और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के लिए स्वायत्तशासी परिषदों का गठन करेगी जिससे कि धनराशि परिषदों के माध्यम से खर्च की जा सके और इससे आदिवासियों को लाभ मिल सके।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, इस पर हमने गौर नहीं किया है। माननीय सदस्य का जो सुझाव है, उसको हम देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री भबानी शंकर होटा : यह केवल आदिवासियों और जनजातियों के विकास के लिए अलग से धनराशि देने अथवा इस राशि को किस प्रकार खर्च करना है, अथवा खर्च की देखरेख का प्रश्न नहीं है। पूरा प्रश्न यह है कि पिछले दस वर्षों में जनजातियों के लिए जो योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए गए हैं—मैं इसे अपने अनुभव से जानता हूँ—जो आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हैं, क्या वे सभी उच्च स्तर पर तैयार किए गए हैं। आदिवासी और जनजाति के लोगों का उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं है न ही उन योजनाओं और कार्यक्रमों में उनकी कोई भागीदारी है। उनके दृष्टिकोण पर कभी विचार नहीं किया गया है। मैं आपकी अनुमति से अभी एक बात कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अपना प्रश्न पूछिए।

श्री भबानी शंकर होटा : जैसाकि आप इस बारे में जानेंगे, एक विशेष मामले में उड़ीसा में जनजाति के लोग और आदिवासी वन उत्पादों पर निर्भर करते हैं और वहाँ लगभग एक लाख जनजातीय लोग हैं जो वन उत्पादों को खोदते हैं और इन्हें बाजार में भेजते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार जनजातियों की विशेष आवश्यकता के लिए कोई विशेष प्रस्ताव लागू कर रही है जिससे कि भविष्य में उन जनजातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। क्या कोई ऐसी योजना है ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हमने यह भी निर्णय लिया है कि जो भी योजनाएं लागू की जाएंगी और बनाई जाएंगी, जिसमें आदिवासियों को हटाने का मामला हो, जो वन विभाग से सम्बन्धित है, उसमें जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, उनसे सलाह-मशिवरा लेने के बाद ही उस प्रोजेक्ट को अन्तिम रूप दिया जाएगा। यदि कहीं भी योजना बनानी है, वहाँ से आदिवासी को हटाया जाएगा तो पहले उसको बसाने की व्यवस्था कर दी जाएगी और तब उसको हटाने की बात सोची जाएगी। इसके लिए मन्त्रिमण्डल की उपसमिति कल्याण मन्त्री के अधीन बन चुकी है और हम उसको देख भी रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे मूल आदिवासी हैं जो जनजातियों के वर्ग में भी आते हैं लेकिन हम जो कुछ भी विकास योजनाएं और कार्यक्रम चला रहे हैं उनमें हम इस वर्ग की हमेशा उपेक्षा करते रहे हैं। इसी कारण मैं माननीय मन्त्री महोदय, जोकि मेरे एक अच्छे मित्र हैं, से जानना चाहता हूँ कि वे इन आदिवासी जातियों, जो शत्रुतापूर्ण रवियों वाली मूल आदिवासी जातियां हैं और अपने-अपने क्षेत्रों में भयंकर खाद्य समस्या का सामना कर रही हैं, के लिए क्या विशेष उपाय कर रहे हैं। विशेषकर अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एक डाबरा जनजाति है और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मन्त्री महोदय कोई उपाय करेंगे ताकि इन जनजातियों के उत्थान को भी सुनिश्चित किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री राम बिलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री मनोरंजन भक्त जी, ने कहा है कि ट्राइब में भी कुछ एक ट्राइब ऐसी हैं जो बहुत ही मूल निवासी हैं और आज भी उसी तरीके से रहती हैं, जिस तरीके से आदिम जमाने में लोग रहा करते थे। उनके लिए जितना विकास होना चाहिए था, उतना विकास नहीं हो पाया है। यदि कुछ विकास कर पाते हैं तो हम लोग ले जाकर दिखाते हैं कि यह ट्राइब है, एक अमुक आदिवासी है। हमने इस सम्बन्ध में मन्त्रालय से दिखवाया है, मैं भी आपसे इस सम्बन्ध में सदन को नहीं कहूंगा। मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य से बात कर्कगा और जो सम्भव प्रयास हो सकेगा, जो इस तरह के मूल आदिवासी निवासी हैं, उनके लिए विकास किया जा सकता है और उसके लिए हम विशेष ध्यान देंगे।

श्री रतिलाल कालीबास बर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि भारत के आदिवासियों के विकास के लिए धनराशि निश्चित की जाती है; लेकिन जंगलों में रहने वाले तो आदिवासी हैं उनका वहां जीना मुश्किल हो गया है; वहां के अधिकारियों के द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जाता है; उनकी मदद करने की बात तो दूर, उनसे भेड़-बकरियों की तरह काम लिया जाता है और जो ऐसा नहीं करते हैं उनको छोटे-मोटे अपराधों में फंसा कर दण्डित किया जाता है, परेशान किया जाता है; क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का इरादा है ?

श्री राम बिलास पासवान : निश्चित रूप से कार्यवाही का क्या प्रोसेस है, वह कहना तो अभी मुश्किल है। लेकिन जैसाकि मैंने कहा कि हम वन नीति तैयार कर रहे हैं। उसमें ये सारी चीजें होंगी कि आदिवासियों के शोषण को कैसे रोका जाए, उनके यहां जो प्रोजेक्ट लगाए जाएं उनमें किस तरह से उनकी हिस्सेदारी हो। नयी नीति जो हम बना रहे हैं उसमें ये सारी चीजें शामिल हैं।

श्री हरि शंकर महाले : अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों को लोग दामाद कहते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि उनको दामाद की तरह का लाभ और व्यवहार नहीं दिया जाता है। राज्य राज्य में पर्वतीय क्षेत्र में जो आदिवासी रहते हैं, उनके क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से जनरल बजट में धनराशि का हिस्सा होना चाहिए। क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ये गार्डिलाइज भेजेगी कि आदिवासियों के लिए जनरल बजट में से इतना-इतना हिस्सा देना चाहिए ?

श्री राम बिलास पासवान : मैंने पहले ही कहा है कि जो राज्य सरकारें अभी खर्च कर रही हैं वह अपने टोटल बजट में दिखलाती हैं। हम यह कोशिश करने जा रहे हैं कि उन पर होने वाले खर्च को अलग रखा जाए और उसको निश्चित रूप से उनके विकास के ऊपर खर्च किया जाए।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों के कल्याण की बात हो रही है। उनके लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं लेकिन यह सपना सही इन से आदिवासियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं मध्यप्रदेश की बात कर रही हूँ। वहां अस्तर एरिए में रहने वाले आदिवासी गरीबी और अज्ञान के शिकार हैं। उनकी गरीबी और अज्ञान का साम ठठकर के कुछ ऐसी एग्रेसिव हैं जोकि बिदेशी पैसे की ताकत पर उन आदिवासी लोगों को बहला रही हैं, फुसला रही हैं। क्या ऐसी बिदेशी ताकतों पर रोक लगाने की किसी नीति पर भी सरकार विचार कर रही है ?

इसके साथ-साथ कुछ ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जोकि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं और

जो आदिवासी एरिए में काम कर रही हैं। उनको बढ़ावा देने की दृष्टि से ताकि वे आदिवासी राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़े रहें क्या इस दृष्टि से भी सरकार कोई प्रयत्न कर रही है ?

श्री राम बिलास पासवान : जो स्वयंसेवी संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं उनको हम प्रोत्साहन भी देंगे। लेकिन कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिन्होंने आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के नाम पर पैसा कमाने का धंधा चला रखा है उनको हम दण्डित करने जा रहे हैं। रूरल डवलपमेंट और ट्राईबल प्रोब्लम्स पर विज्ञान भवन में एक सेमिनार किया था जिसमें सभी पोलिटिकल पार्टीज और इस काम में लगी स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों ने भाग लिया था और प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। उसमें बहुत अच्छे सुझाव आए थे। हम उन पर और आप जो कह रही हैं निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : मैंने विदेशी ताकतों के बारे में भी पूछा था। (व्यवधान)

श्री राम बिलास पासवान : वह मेरी मिनिस्ट्री में नहीं आता है।

श्री शोपन सिंह मक्कासर : मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा जितना पैसा आपने उनके विकास के लिए दिया वह उन तक नहीं पहुंच पाया है, यही नहीं है। सूदखोरों ने उनकी तमाम जमीन भी अपने कब्जे में ले ली है। क्या आप इस दृष्टिकोण से त्रिपुरा की तरह आदिवासी बहुल क्षेत्र में आदिवासी परिषद बना करके उसको सारे अधिकार देंगे ? क्या सरकार इस बात पर भी विचार करेगी ?

श्री राम बिलास पासवान : जहां तक सूद का सवाल है, जो फाइनेंशल डवलपमेंट एजेन्सी है उसके बाबजूद 78 फीसदी पैसा-बिजनेस कहिए या जो भी कहिए—लोग उनसे लेते हैं। इसमें कहीं न कहीं सरकार की एजेन्सियां फैंल्योर साबित होती हैं। उनके विकास के लिए फण्ड बनाए हुए हैं और फाइनेंशल डेवलपमेंट एजेन्सियां बनाई हुई हैं। उसके बाद भी टोटल पैसे का 78 फीसदी प्राइवेट लोगों से वे लेते हैं। इसका मतलब है कि या तो इस प्रणाली में कहीं जटिलता है या इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं ? तो निश्चित रूप से हम उसके भी सरलीकरण के बारे में विचार करने जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शोपन सिंह मक्कासर : जो आदिवासी बहुल एरिया है उसमें भी आदिवासियों को विकास परिषद बनाकर अधिकार दिए जाएं ?

श्री राम बिलास पासवान : मैंने बताया है कि आदिवासियों के कल्याण के लिए हम डेबीकेटेड हैं। उनके लिए जो बढ़िया से बढ़िया उपाय हो सकते हैं, वह हम करेंगे।

दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पुस्तकालय कार्यालयों का कार्य

[अनुवाद]

* 846. श्री सरजू प्रसाद सरोज : क्या शहरी विकास षंभी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न कालोनियों में स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पुस्तकालयों के कार्यों के बारे में कितनी निकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) शिकायतें किस किस्म की थीं; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों के कार्य में सुधार करने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क), (ख) तथा (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

औसतन एक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पूछताछ कार्यालय में प्रतिदिन 40 शिकायतें प्राप्त की जाती हैं। ये शिकायतें सामान्यतया सीवर लाइन बन्द होने, बिजली प्यूज होने, काच-पलक, दरवाजे, छिड़कियां, वाणर टपकते नल इत्यादि को बदलने से सम्बन्धित होती हैं। दिल्ली में 140 तथा अतिरिक्त पूछताछ कार्यालयों में प्राप्त की गई इस प्रकार की शिकायतों की संख्या पिछले एक वर्ष के दौरान हजारों में पहुंच गई है। तत्काल प्रकृति की शिकायतों पर 24 से 48 घण्टे के अन्दर कार्रवाई की जाती है। अन्य शिकायतें दूर करने में समय लगता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, कुछ पूछताछ कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त की गई थीं। ये शिकायतें निम्नलिखित से सम्बन्धित थीं :—

- (i) कर्मचारियों द्वारा दुर्भ्यंवार;
- (ii) पल्लटों को रहने लायक बनाने में विलम्ब;
- (iii) क्वार्टरों को उपयुक्त अवस्था में न सौंपना;
- (iv) शिकायतों पर ध्यान न देना; तथा
- (v) सहायक इंजीनियर द्वारा अनाचार।

इनमें से अधिकतर की जांच की गई है। चूंकि कुछ शिकायतों के प्रमाण नहीं मिले हैं, अतः कुछ वास्तविकता वाली अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों को या तो स्थानान्तरित कर दिया गया था या चेतावनी दी गई थी। पूछताछ कार्यालय की कार्य-प्रणाली में सुधार करने के लिए सम्बन्धित कार्यपालक इंजीनियर एक पक्ष में कम से कम एक बार पूछताछ कार्यालयों में रखे जाने वाले शिकायत रजिस्ट्रों का पुनर्लोकन करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पूछताछ कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में कम्प्यूटरों के माध्यम से प्रबोधन भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ आबधिक बैठकें भी बुलाई जाती हैं।

[हिन्दी]

श्री सरजू प्रसाद सरोज : माननीय मंत्री जी ने मूल प्रश्न के बारे में जो जवाब दिया है—कि जो छोटी-छोटी शिकायतें हैं उनका निदान 24 घण्टे से 48 घण्टे के बीच में कर दिया जाता है और जो उससे भी बड़ी समस्याएं हैं उनके लिए हम जांच करने की कार्यवाही कराते हैं और जांच पाए जाने पर, इंजीनियर या अधिकारियों को वहां से स्थानान्तरित कर देते हैं या उनको चेतावनी दे देते हैं। इसके

लिए मैंने पूछा है कि इस बारे में अभी तक जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनमें अभी तक कोई भी कार्यवाही की गई है और जो छोटी-मोटी शिकायतें हैं जैसे—सीवर बन्द होना, बिजली पकूब होना, घरबाजे-खिड़कियों की मरम्मत आदि इनसे सम्बन्धित जो शिकायतें हैं। इनके निदान होने में थोड़ा ठीक होने में 20 से 25 दिन तक लग जाते हैं और जो बड़ी शिकायतें हैं जैसे—कर्मचारियों का दुर्घटन, प्लैटों को रहने लायक बनाने में बिलम्ब, क्वार्टरों को उपयुक्त अवस्था में न सौंपना और इन शिकायतों और इन शिकायतों पर ध्यान न देना तथा कहीं सहायक इंजीनियरों द्वारा दुर्घटन कराना, इस प्रकार की शिकायतें आज भी वैसे की वैसे ही हैं। इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इंजीनियरों को स्थानान्तरण करना और उनको चेतावनी देना, यह कोई बड़ा दण्ड नहीं है। इस प्रकार की शिकायतों से सम्बन्धित इंजीनियरों को प्रभावी कार्यवाही करके उन्हें दण्डित करेगे।

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि वहाँ बिल्कुल भी शिकायतें नहीं हैं क्योंकि वहाँ लगभग 63444 मकान ऐसे हैं जिनकी मरम्मत की जानी है। वर्तमान पद्धति में उनके बर्ण बनाए जाते हैं। कुछ शिकायतों पर तत्काल ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर सिविल इन्जीनियरिंग में जल प्रवाह का अवरुद्ध हो जाना आदि अथवा इलेक्ट्रिकल विभाग में बिजली का गुम हो जाना अथवा स्विच का काम न करना है, इन शिकायतों पर 24 घण्टे के अन्दर कार्यवाही की जाती है। कुछ दूसरी शिकायतें हैं जो सामान्य समझी जाती हैं। उन पर 4 से 7 दिन के अन्दर कार्यवाही की जाती है। इसके बाद कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिनका मूल्यांकन करना पड़ता है और संभय भंगता है। उन्हें कार्य सक्षम बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही साथ अधिकारियों को तीन महीने में कम से कम एक बार वहाँ जाना चाहिए, रेजीडेन्ट एसोसिएशन से मुलाकात करके शिकायतों का पता लगाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सरजू प्रसाद सरोज : जो रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ बैठक करने की बात कही गई है, वह सत्य नहीं है, बल्कि एसोसिएशन वेलफेयर के लोग अभियन्ताओं से मिलने के लिए बराबर समय मांगते हैं, इसके लिए वह समय नहीं देते और न ही वहाँ उपलब्ध रहते हैं। हम जो शिकायतें लिख करके उनको देते हैं, उनका निदान भी वह नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर आर० के० पुरम, मधिर मार्ग, बी० के० एस० मार्ग पर भी, सी० पी० डब्ल्यू० डी० के इन्कवायरी आफिस में, वहाँ के कर्मचारी छोटी-मोटी शिकायतों को भी दूर करने में नाकामयाब हैं। आज भी इन समस्याओं का निदान नहीं किया गया है। क्या इन समस्याओं के निदान का आप प्रयास करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : निश्चित रूप से हम इस बात के इच्छुक हैं कि यदि व्यक्तिगत शिकायतें हमारी जानकारी में लायी जाती हैं तो हम कार्यवाही करेंगे।

श्री० श्रीकृष्ण लाल : श्री मुरासोली मारन जैसे सिविल मन्त्री के सामने सबसे बड़ी अवधान या तो सभ्यता निर्देशालय अथवा सी० पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा सहयोग न करने के कारण आती है। मैं इस बात को अपने निजी अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ जबकि मुझे उस अर्ध-सरकारी पत्र का उत्तर नहीं मिला जो मैंने मुख्य अभियन्ता को लिखा था। मैंने बड़ी कठिनाई से उनके नाम का पता किया और उसे ठीक प्रकार से लिखा—मेरे प्रिये मुख्य अभियन्ता आदि। मुझे समय-समय पर पता चला कि

मन्त्री महोदय ब्यस्त हैं अथवा दिल्ली से बाहर हैं। अतः मैंने एक अर्ध-सरकारी पत्र सीधे मुख्य अभियन्ता को लिख दिया। आज ढाई महीने से अधिक समय हो गया है परन्तु मुझे कोई उत्तर नहीं मिला है। इसके बाद मैंने जब इस मामले में अपने सहयोगियों से परामर्श किया तो मुझे मालूम हुआ कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० में मुख्य अभियन्ता, अथवा सुपरिटेन्डेंट इन्जीनियर अथवा अनेक दूसरे अधिकारियों का पिछले 8-10 वर्षों से तबादला नहीं किया गया है। मैं चाहता हूँ कि पूरे सी० पी० डब्ल्यू० डी० और सम्पदा कार्यालय में फेरबदल किया जाए। मैं माननीय मन्त्री महोदय से इस बात का उत्तर चाहता हूँ। क्या वे प्रशासन को कारगर बनाएंगे, उचित कार्यवाही करेंगे और मुख्य अभियन्ता से यह स्पष्टीकरण मांगेंगे कि उसने मेरे पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया ?

श्री मुरासोली भारन : महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से सहमत हूँ। मन्त्री बनने से पहले मैं भी 22 वर्षों से अधिक समय तक दूसरे सदन का सदस्य रहा हूँ और मुझे इसी प्रकार का अनुभव रहा है। परन्तु कोई भी एक दिन में कुछ नहीं कर सकता। इसमें समय लगता है। परन्तु जहाँ तक माननीय सदस्य द्वारा बलायी गयी विशेष समस्या का सम्बन्ध है, मैं इस बारे में तुरन्त जांच कराऊंगा।

महाराष्ट्र में कताई मिलों के लिए केन्द्रीय सरकार की भंजूरी

*847. श्री बल्लन्त साठे : क्या बल्लभ भंजी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में गैर-सरकारी/सहकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कताई मिलों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है तथा कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं और उन पर क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान वित्तीय सहायता देने के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

बल्लभ भंजी और लाल प्रसन्नकरण उद्योग भंजी (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) महाराष्ट्र सरकार ने दिसम्बर, 1988 के केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि वह एन० सी० डी०-31 विश्व बैंक सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए 4 सहकारी कताई मिलों को शामिल कर ले।

(ख) इन चार सहकारी कताई मिलों के नाम तथा निधियों के ब्यौरे निम्नोक्त अनुसार

हैं :

(माच ६० में)

नाम/स्थिति	परियोजना लागत	एन० सी० डी० सी० की सहायता का अंशदान	
		शेयर पूंजी	आवधिक ऋण
1. अकोट तालुका सहकारी सूत गिरनी लि०, अकोला	19.2	290.78	956.00
2. जल्ना विभाग सहकारी सूत गिरनी लि०, जल्ना	2104	290.80	1052.00
3. दरियापुर अंजनगाव सहकारी सूत गिरनी लि०, अमरावती	2031	315.50	1015.00
4. इन्दिरा सहकारी सूत गिरनी लि०, वार्धा	1987	330.25	993.50
	8034	1227.33	4016.50

(ग) विश्व बैंक ने राज्य सरकार को शेयर पूंजी के लिए एन० सी० डी० सी० की ऋण सहायता का 50 प्रतिशत वित्त पोषित करने पर तथा साथ ही परियोजना के लिए एन० सी० डी० सी० से आवधिक ऋण का 100 प्रतिशत वित्त पोषित करने पर भी सहमति प्रकट की है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक की आवधिक ऋण के लिए आन-लैंडिंग एजेंसी के रूप में अधिष्ठात किया है।

(घ) एन० सी० डी० सी०-31 विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत देश में 11 सहकारी कर्ताई मिलों के मामलों के लिए जिनमें महाराष्ट्र सरकार की 4 सहकारी कर्ताई मिलों के प्रस्ताव भी शामिल हैं, एन० सी० डी० सी० ने आई० डी० ए० की निधियों में से आवधिक ऋण के लिए 25 करोड़ रु० का प्रावधान किया है और साथ ही वर्ष 1990-91 के वित्तीय वर्ष के लिए इक्विटी सहभागिता के रूप में अपनी निधियों में से 15.58 करोड़ रु० का भी प्रस्ताव किया है।

श्री बल्लंत साठे : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य के संदर्भ में कि विश्व बैंक सहायता दे रही है और राष्ट्रीय सहकारी, विकास निगम ने आई० डी० ए० की निधि से 25 करोड़ रुपये के आवधिक ऋण का और इक्विटी सहभागिता के रूप में अपनी निधियों में से 15 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया है, क्या मंत्री महोदय उन 11 कर्ताई मिलों के लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाएंगे जो निर्माण को पूरा करने तथा अन्तिम रूप दिए जा सकने के कारण कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं? मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वे इस मामले की जांच करें।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विद्वान साथी साठे जी ने जिन 11 मिलों के बारे में कहा है और विशेषतौर से वर्धा में जो माननीय सदस्य के क्षेत्र में मिलें हैं, उनके बारे में मामला 1981 से लम्बित था। इस बात बताते हुए मुझे खुशी है कि एन० सी० डी० सी० ने बल्लं बैंक का मोन स्टेट कोआपरेटिव बैंक को देने के लिए कहा था, उसको रिलीज नहीं किया था, लेकिन इसे आप अपनी मेहरबानी समझिए या हमारे मंत्रालय की मेहरबानी समझिए, कल शाम को मेरे पास टेलिक्स जा गया है कि उन्होंने उसको रिलीज कर दिया है और 4 मिलों के बारे में आपका काम हो जाएगा। इस वक्त समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको विस्तार से बताता, बल्लं बैंक असिस्टेंट्स जिसको वे रोके हुए थे, उसको अब रिलीज कर दिया गया है।

श्री बसन्त साठे : यह चार मिलों के बारे में आपने बता दिया है, लेकिन बाकी जो मिलें हैं, जिनके बारे में इन्डरेड परसेन्ट एप्री कर लिया गया है और जो म्नेस्टनी बैंकवर्ड एरियाज में हैं, उनको भी जल्दी क्लीयर कर देंगे या नहीं? (ब्यबधान)

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, 4 मिलें, जिनके बारे में साठे जी असल में चिंतित थे, जो तात्कालिक सहायता पहुंचाई जानी थी, उस काम को हमने मुस्तंदा से कर दिया है, इसके लिए साठे जी ने धन्यवाद भी नहीं दिया। (ब्यबधान)

श्री बसन्त साठे : धन्यवाद तो दे रहा हूं। (ब्यबधान)

श्री शरद यादव : आपकी सरकार के चलते आप इतने दिनों से तंग थे, अब हमारी सरकार के आते ही यह काम हो गया है, अब 4 मिलों का मामला रह गया है। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र इस मसल्ले में बहुत आगे है। हिन्दुस्तानखबर में 102 स्पिनिय मिक्स हैं, इनमें से 3-1 महाराष्ट्र में चल रही हैं, 4 ये ह्वे गर्ड और 3 सेल्लर और हैं, इस तरह से तकरीबन 38 मिखें हो जाएंगी। इस तरह से बाकी को 4 मिलें हैं, उनके बारे में सारे देश को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय द्वारा बिचार किया जस्य्या।

श्री बसन्त साठे : मेरा कहना यह है कि जिनमें आलरेडी इनवेस्टमेंट हो गया है, सेंशन होने के बाद इन्वेस्टमेंट हो गया है, प्राइवेट लोगों ने कैपिटल शेयर्स जमा करके इनवेस्टमेंट कर दिया है, उन मिलों को भी क्या आप जल्दी क्लीयर करेंगे, जो एन० सी० डी० सी० के अन्तर्गत बची हुई हैं।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, तीन आलरेडी क्लीयर हो चुकी हैं, चार के बारे में कस मैसेज आ गया है कि वे क्लीयर हो गई हैं।

श्री बसन्त साठे : बाकी भी कर दीजिए तो एकमुस्त धन्यवाद दे दूंगा। (ब्यबधान)

श्री शरद यादव : जहां तक बाकी 4 मिलों का सवाल है, उनके सम्बन्ध में मंत्रालय बिचार कर रहा है।

12.00 मन्वाङ्क

अल्प सूचना प्रश्न

उपभोक्ता वस्तुओं की विक्री

[अनुवाद]

अ० सू० प्र० 2. प्रो० के० बी० चामस : क्या छात्र और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैकेटबन्द उपभोक्ता पदार्थ, उपभोक्ताओं को पैकेटों पर अंकित मूल्य पर बेचे जाते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को कोई निदेश जारी करने का विचार है कि थोक और खुदरा विक्रेताओं द्वारा मूल्य तथा स्टॉक प्रदर्शित करने के आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाए ?

[द्विती]

छात्र और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री मन्मू राज मिर्छा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) बाट तथा माप, मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के अनुसार प्रत्येक पैकेज, जिसमें पहले से पैक की गई वस्तुएं हों, पर पैकेज के ऊपर विक्रय मूल्य घोषित करना आवश्यक है। तथापि, यदि पैकेज पर घोषित विक्रय मूल्य में स्थानीय कर शामिल नहीं हैं तो खुदरा विक्रेता को उपभोक्ता से उस पर लगने वाले स्थानीय कर को वसूल करने का अधिकार होता है। सभी कर्तों सहित खुदरा मूल्य ही अंकित करने की व्यवस्था करने के वास्ते इन नियमों में संशोधन करने का निर्णय किया जा चुका है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मूल्य तथा स्टॉक प्रदर्शन आदेश को प्रभावपूर्वक ढंग से लागू करें। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मूल्य तथा स्टॉक प्रदर्शन आदेश जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

[अनुवाद]

प्रो० के० बी० चामस : महोदय, नियम 193 के अन्तर्गत मूल्यों पर एक मन्वी चर्चा हुई है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य प्रतिदिन बढ़ रहे हैं।

महोदय, मैं कुछ ठोस कदम उठाने पर बल दे रहा हूँ। बहुत सारी वस्तुएं जैसे दवाइयों, शराब,

पेयों इत्यादि और अन्य अनेक उपभोक्ता वस्तुएं पैकेटों में मिलते हैं। इन पैकेटों को देखें। इन पर खुदरा मूल्य अंकित होता है। वह मूल्य स्थानीय कर सहित होता है। एक साधारण उपभोक्ता यह नहीं जानता कि स्थानीय कर क्या होता है। इस प्रकार होता यह है कि खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य के साथ स्थानीय कर भी उपभोक्ता से वसूल करता जो उपभोक्ता को मालूम नहीं है। वह मनमानी मूल्य वसूल करता है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि मूल्य और स्थानीय कर अंकित करने के बदले सब कुछ मिलाकर कुल मूल्य अंकित करें ताकि उपभोक्ता, वस्तु को उसी मूल्य पर खरीदे जो अंकित है न कि मूल्य तथा स्थानीय कर जोड़ कर। आप पैकेट पर एक ही मूल्य अंकित करें ताकि साधारण उपभोक्ता जाने कि वास्तविक मूल्य क्या है।

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्घा : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया, सरकार ने उसी के अनुसार कार्यवाही कर दी। पहले दो आप्शनस थी—मेंबिसमम रिटेल प्राईस एक्सक्लूसिव आफ टैक्स। अब हमने सिर्फ एक आप्शन कर दी है। मेंबिसमम रिटेल प्राईस इन्क्लूडिंग आल टैक्स। अब कंज्यूमर को, जो कीमत लिखी हुई है उसी कीमत पर माल मिलेगा। टैंक्स से उसका कोई लेना-देना नहीं। कंज्यूमरस के हितों के लिए हमने एक आप्शन कर दी है। उसमें सभी टैक्स शामिल होंगे।

[अनुबाव]

पैकेटों पर अधिकतम खुदरा मूल्य 'अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित' अंकित होना चाहिए। वह ही एक मात्र मूल्य होगा जो दुकानदार वसूल कर सकेगा। इसलिए अब सभी बातें स्पष्ट हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

आप लोगों की कृपा है। मैं आपकी सेवा जितनी मुझसे बन पड़ेगा, करूंगा।

(व्यवधान)

[अनुबाव]

प्रो० के० बी० चामस : महोदय, सरकार के साथ समस्या यह है कि वे जो कहते हैं उसे लागू नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

महोदय, वे कहते हैं कि उन्होंने निर्माताओं को निर्देश दे दिया है कि पैकेट पर केवल अधिकतम मूल्य ही अंकित हों। लेकिन वह बाजार जाकर कोई भी या सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य को देखें। मैंने कई वस्तुओं को देखा है जिस पर 'मूल्य एवं स्थानीय कर' अंकित है। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूँ वह इसकी जांच करें और देखें कि जो भी निर्णय लिया जाता है उसे लागू किया जाए।

श्री कमल नाथ : वे यह नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : साठे जी कृपया आपस में बातें मत करें।

प्रो० के० बी० चामस : महोदय, आपातकाल के बारे में अलग-अलग मत हो सकते हैं। लेकिन

एक बात जिसकी लोग अब भी सराहना करते हैं वह है खुदरा दुकानों के सामने बस्तुओं के मूल्य और स्टॉक की सूचना देना। लेकिन अभी, यद्यपि माननीय मंत्री ने कहा है कि दुकानों पर मूल्य और स्टॉक सम्बन्धी सूचना लगाई जाएगी, कोई भी खुदरा या थोक व्यापारी ऐसा नहीं कर रहा है। केरल सहित सभी प्रांत सरकारों ने इस निर्णय को लागू नहीं किया है। अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार इसे लागू कराने का कोई दृढ़ निर्णय लेगी ताकि सरकार के निर्णय को लागू किया जा सके।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है।

श्री नाथू राम मिर्धा : मैं सब बता रहा हूँ। यह कोई नियम नहीं बदल गया है, यह 1977 का बना हुआ है और इस नियम से एक ही दाम लिखे जाएंगे। यह कोई निर्देश भी नहीं है। यह गजेट नोटिफिकेशन में आ जाएगा एक-दो-दिन में, लेकिन यह तो मुमकिन नहीं कि आज मैं कहूँ तो कल ही वह काम हो जाए, इसीलिए इसमें हमने 6 महीने का समय दिया है। इसके साथ ही तमाम कम्पनीज को सब राज्यों के टैक्सेज की जानकारी लेने के लिए कहा है कि वह जानकारी करके नए तरीके से इसको लागू करें। हर दुकानदार को अपने स्टॉक के बारे में दुकान पर दर्शाना होगा और कीमतें लगानी होंगी। इसके बारे में कानून बने हुए हैं आवश्यक बस्तु नियम के अन्तर्गत और राज्य सरकारें इसको लागू करती हैं। हम समय समय पर उनको हिदायतें देंगे, चिट्ठी लिखेंगे और 28-29 तारीख को मैंने सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया है। इस पर हम विचार करेंगे और उनसे कहेंगे कि इसको लागू करो और जो नहीं करता है उसको खींचो। इसलिए भारत सरकार इसके प्रति बड़ी चिंतित है कि नियमों की पालना होनी चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय मंत्री क्या कहना चाह रहे हैं। अपने उत्तर में उन्होंने कहा है कि नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है कि जिससे कि बस्तुओं पर अधिकतम मूल्य सभी करेंगे सहित अंकित किया जा सके। जब श्री विनेश सिंह ने प्रश्न किया तो तो उन्होंने कहा इसमें विक्रय कर भी सम्मिलित है। विक्रय कर प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है। मान लिया कि एक राज्य में विक्रय कर एक रुपया है और दूसरे राज्य में दो रुपया है, यदि वितरक किसी बस्तु का अधिकतम खुदरा मूल्य 2 रुपया निर्धारित करता है, तो एक राज्य में जहां विक्रय कर दो रुपया बहां तो ठीक है। लेकिन एक ऐसे राज्य में जहां विक्रय-कर एक रुपया है तो वहां वितरक को अधिक लाभ होगा बूँकि वहां भी वह 20 रुपए ही लेगा।

महोदय, हमारी कठिनाई को समझें और प्रश्न का उत्तर दें। क्या मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित किया जाएगा? क्या अलग-अलग स्थानीय कर को मद्देनजर रखते हुए प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग रिकेट तैयार किए जाएंगे? क्या मंत्री जी का यही कहना है?

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा : मैं आपके सवाल के इन्टीकेशन को जानता था। उपभोक्ता को हर राज्य के सेल्स टैक्स की जानकारी नहीं होती है, यह ठीक बात है। मैंने कम्पनीज पर दबाव डाला है कि आप

हर राज्य का सेल्स टैक्स मालूम करके अपने पैकेट्स पर सब कुछ जोड़ कर लिखें और जिन-जिन राज्यों को पैकेट्स भेजने हैं उन उन पर उस राज्य के सेल्स टैक्स बैगरहू को जोड़ कर दाम लिखें और वहां भेजें। जैसे मध्य प्रदेश का अलग सेल्स टैक्स है, राजस्थान का अलग सेल्स टैक्स है तो इन राज्यों में इसी सेल्स टैक्स के हिसाब के पैकेट्स पर दाम लिखकर वहां भेजें। (व्यवधान)

श्री कमल नाथ : अलग-अलग राज्यों को अलग-अलग पैकेट्स भेजेंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सदस्य को प्रश्न करने से नहीं रोक सकते।

[हिन्दी]

श्री यादवचन्द्र बल : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करेंगे कि इन्होंने जो नया आर्डर निकाला है, वह किस तारीख और किस महीने से निकाला है? लेकिन मेरे पास विस्की का ही एक पैकेट अभी मौजूद है जिसमें मैक्सीमम प्राइज एक्सक्लूसिविग सेल्स टैक्स लिखा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है? यह पैकेट मैंने आज ही खरीदा है।

श्री नाथू राम मिर्धा : पुराने पैकेट पर पुरानी कीमत को देना होगा, उसको नहीं बदला जा सकता है। इसलिए मैंने छ. महीने का टाईम दिया है।

श्री सोमनाथ षटर्जी : इनका इस तरह से एग्जीबिट ठीक नहीं है।

श्री नाथू राम मिर्धा : आजकल में गजट निकलेगा। जिस दिन निकलेगा, उस दिन यह लागू हो जाएगा। इसलिए छ. महीने का टाईम दिया है।

श्री विनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जहां तक सेल्स टैक्स का मामला है, क्या अब हर व्यापारी को सेल्स टैक्स का कोई हिसाब खुद नहीं रखना पड़ेगा या जो मैन्यूफैक्चरर्स हैं, वे सेल्स टैक्स दिया करेंगे या कैसे यह हिसाब होगा?

श्री नाथू राम मिर्धा : सेल्स टैक्स के एमाउन्ट को जानना उन कम्पनियों का दायित्व बन जाता है जो अलग-अलग स्टेट्स में सेल्स टैक्स को जान कर उन गुड्स पर मैक्सीमम प्राइसेज लिखकर भेजते हैं। इसलिए जो कम्पनियां बनाती हैं, यह उनके जिम्मे है कि उसमें इसको इन्कलूड करना है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति षटर्जी : मैं श्री पी० चिदम्बरम से पूरी तरह सहमत हूँ। यह प्रस्ताव खुदरा बिक्रेताओं की संतुष्टि के लिए है। यह खुदरा बिक्रेताओं के लिए लाभप्रद है न कि उपभोक्ताओं के लिए। मेरा प्रश्न बहुत ही साधारण है। बिक्रय कर और अन्य कर तथा अधिकतम अंकित मूल्य अलग-अलग होता है और वे राज्यों के लिए पैकेट तैयार करेंगे यह बिचार् जैसे आसमान से आ टपका है। मेरा प्रश्न यह है कि इस वर्षा के बाद क्या वे अपने निर्णय पर पुनर्बिचार करेंगे।

श्री नाथू राम मिर्धा : आपका सोचना गलत है। इस पर पुनर्बिचार करने का कोई प्रश्न नहीं है। यहां उपभोक्ता ही अनभिज्ञ है।

श्री हरमोहन चव्वा : माननीय मंत्री ने कहा है कि बस्तुओं के पैकेट पर लिखा मूल्य सही करेंगे

सहित होगा। वह इसका हिसाब कैसे लगाएंगे क्योंकि श्री पी० चिदम्बरम ने कहा है कि बिक्रय कर और चुंगी अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न है और इसका हिसाब लगाना अब्यावहारिक है। इसके अलावा, बिक्रय कर राज्य का मामला है। यह बहुत ही मुश्किल होगा और पूरी योजना ही अब्यावहारिक है। वे कैसे छोटी-छोटी कंपनियों द्वारा जमा किए गए बिक्रय करों को एकत्र करेंगे और विभिन्न राज्यों को लाटाएंगे ? जो कुछ भी माननीय मन्त्री ने कहा है वह अब्यावहारिक है और ऐसा नहीं किया जा सकता है।

श्री नाचू राम मिर्धा : मैं समझता हूँ कि सवस्य मामले की बारीकियों को नहीं समझ पाए हैं। उन्होंने इसे ठीक से नहीं समझा है।

श्रीमती उमा गणपति रावू : ठीक हमारी ही तरह माननीय मन्त्री भी भ्रमित हैं। वे यह नहीं जानते कि चुंगी और बिक्रय कर प्रत्येक राज्यों, शहरों और गांवों में अलग-अलग है। वे वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने से कैसे रोकेंगे ? यह पूरी तरह अब्यावहारिक है। माननीय मन्त्री यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं ताकि इन कठिनाईयों को दूर किया जा सके ?

[हिन्दी]

श्री नाचू राम मिर्धा : अध्यक्ष जी, मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने पेंकेजिंग करने वाली कंपनियों से बातें की हैं तो मुझे बताया गया है कि वे एबरेज सेल्ज टैक्स क्लेक-कुलेट करके उस हिसाब से प्राइसेज देंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : अब वह औसत कर (एबरेज टैक्स) की बात करते हैं। औसत कर कैसे निर्धारित किया जा सकता है ? हम क्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक के औसत कर को चुकाएं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नाचू राम मिर्धा : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सवस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि मौजूदा मैक्सिमम रिटेल प्राइस का जो तरीका है, एक्सक्लूसिव आफ टैक्स लिखने का, वह कन्ज्यूमर्स को प्लीज करता है (व्यवधान) अब जहाँ तक सबाल सेल्स टैक्स, दूसरे टैक्सेज मैक्सिमम प्राइस, वह जो कम्पनी पेंकेज करती है, उसका टाल्लुक है (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभी कर मूल्यों में सम्मिलित कर दिए गए हैं। इसमें किसी भी तरह का राजस्व की हानि नहीं हो रही है। अन्यथा, वितरक बिक्रय कर लेते रहेंगे। वे वस्तुओं को मनचाहे मूल्य पर बेचते हैं। और वे उससे कुछ अधिक ही लेते हैं जितना लिखा होता है ताकि कर अपबन्धन से बचा जा सके यदि वे इस तरह मूल्य अंकित करेंगे। तो राज्यों को बेहतर लाभ प्राप्त होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि आप वह क्यों नहीं समझ रहे हैं। (व्यवधान)

[द्वितीय]

श्री भवन लाल खुराना : अध्यक्ष जी महंगाई को कम करने के लिए माननीय मन्त्री जी ने अभी प्राइसज की बात की, परन्तु उससे कुछ विरोधाभास झलकता है, परस्पर विरोधी बातें सामने आ रही हैं। मैं उनसे एक सीधा-सादा सवाल जानना चाहता हूँ कि इस देश में कुछ मल्टी नेशनल कम्पनियां या बड़े-बड़े कारखानेदार, मिल मालिक जितने कंज्यूमर आइटम्स बनाते हैं, वे ऐसा कहीं नहीं लिखते कि उस आइटम की, वस्तु की कास्ट आफ प्राइस क्या है, उदाहरण के लिए कॅम्पा कोला को लीजिए, हमाम साबुन को लीजिए, किसी पर यह नहीं लिखा होता कि उसकी कास्ट आफ प्राइस क्या है, बिक्री मूल्य होता है, क्या माननीय मन्त्री जी उन्हें यह कहेंगे ... (व्यवधान)

जी हां, कास्ट आफ प्रोडक्शन (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप हिन्दी में या हिन्दुस्तानी में बोलिये।

श्री भवन लाल खुराना : मेरा मतलब कास्ट आफ प्रोडक्शन से ही है। अध्यक्ष महोदय, इस देश में कुछ मल्टी नेशनल कम्पनियां या बड़े मिल मालिक जितने कंज्यूमर आइटम्स या कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, जैसे कॅम्पा कोला है, हमाम साबुन है, किसी पर कास्ट आफ प्रोडक्शन नहीं लिखा होता। क्या मन्त्री जी आदेश देंगे कि हर कंज्यूमर आइटम या कंज्यूमर गुड्स पर उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन लिखना कम्पलसरी हो : आज स्थिति यह है कि किसी वस्तु की कास्ट आफ प्रोडक्शन तो एक रुपए होती है परन्तु उसका बिक्री मूल्य 5 रुपए लिखा होता है, कम्पनियां निश्चित करती हैं कि हम उस वस्तु को 5 रुपए में बेचेंगे। लोगली देखा जाए तो 5 रुपए कीमत सही है, अण्डर लॉ, वह बिक्री मूल्य सही है, परन्तु उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, उसका पता नहीं चलता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कास्ट आफ प्रोडक्शन लिखना भी कम्पलसरी कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : बस, हो गया, आप बैठिए।

श्री नाथू राम मिर्धा : जो सवाल माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, उसका मूल प्रश्न से किसी तरह का सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान)

हम यहां सारी इकॉनोमी पर या सारे गुड्स का प्राइस कंट्रोल नहीं करने जा रहे हैं। इसलिए आप कहां का सवाल, कहां जोड़ना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री भवन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, महंगाई को कम कम करने के लिए ही मैंने यह सवाल किया था, इसलिए मन्त्री जी को बताना चाहिए ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री भवन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ कि महंगाई को कम करने के उद्देश्य से मैंने यहां मन्त्री महोदय से जो सवाल पूछा, वे सिर्फ इतना बता दें कि क्या वह लाभदायक रहेगा या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

प्रो० संकुहीन सोज : खुराना जी के प्रश्न का मन्त्री जी उत्तर क्यों नहीं देना चाहते।

अध्यक्ष महोदय : सोज साहब, आप बैठिए ।

श्री बसन्त साठे : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी एक किसान के बेटे हैं और एक बड़े अच्छे इरादे से, कल्पना से, पैकेज स्कीम बनाना चाहते हैं जिससे कि आम कन्ज्यूमर्स को लाभ हो, उन्हें वस्तुएं एक ही कीमत पर मिलें, सारे टैक्सेज बर्गरह उसी में शामिल हों, किसी तरह की दिक्कत न हो, उपभोक्ताओं का शोषण न होने पाये, उनका इरादा नेक है, मैं मानता हूँ । लेकिन जिस तरह से इनके सहयोग, दोनों बैसाखियां, जो सलाह दे रही हैं उस तरह से यदि करेंगे, तो और गफलत और मुसीबत में जा जाएंगे । अच्छा है आप नहीं सुन रहे हैं । इन बैसाखियों की सलाह मत मानिए । लेकिन आपने अभी यह सुना अध्यक्ष जी कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग सेल्स-टैक्स होते हैं, लोकल टैक्सेज भी होते हैं और ऑक्ट्राय भी होती है । ये कम्पनियां आपको पैकेज की बात कहकर शायद गुमराह भी कर सकती हैं अपना मुनाफा कमाने के लिए । आपने इन कम्पनियों को इस कानून को लागू करने के लिए छः महीने दिए हैं, इन छः महीनों में आप भी पुनर्विचार कीजिए और घोष्ये में मत आइए इन कम्पनियों के । मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ ।

श्री नाथू राम मिर्धा : ये कम्पनियां मेरे साथ क्या घोष्य करेगी ? यह कानून तो मैंने कंजूमर को मुसीबतों से बचाने के लिए बनाया है । अगर कम्पनियों को कोई दिक्कत होगी या कंजूमर को कोई दिक्कत होगी, तो वे छः महीने के अन्दर उन प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज को हमारे सामने रखेंगी, उनको हम देख लेंगे । एक कानून बना है, इसको लागू होने दीजिए ।

श्री राज बंगल पाण्डेय : मान्यवर, बहुत दिनों से एक प्रपोजल सारे देश में है कि सेल्स टैक्स को कि स्टेट टू स्टेट वरी करता है, उसका मिटाकर एक्साइज-ड्यूटी के नाम से उसको एक ऐसा टैक्स कर दिया जाएगा, जिससे एकरूपता सारे देश में आ जाए । इसलिए मैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब पैकेट पर एक ही कीमत लिखी होगी जिसमें एक्साइज-ड्यूटी, सेल्स-टैक्स, ऑक्ट्राय सब कुछ मिला होगा, तो क्या आपने उसको प्रिंसीपली मान लिया है कि सेल्स टैक्स को एवांलिश कर के एक्साइज-ड्यूटी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है ? इस बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

श्री नाथू राम मिर्धा : अध्यक्ष जी, सेल्स टैक्स और ऑक्ट्राय और मारा मामला इस प्रश्न से जोड़ दिया । अब मैं ऐसे लोगों को क्या जवाब दूँ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ठेका श्रमिक पद्धति

[हिन्दी]

*842. श्री सुबेदार : क्या अम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और नार्बन कोल्फील्ड्स लिमिटेड जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में निर्माण कार्य में लगी विभिन्न एजेन्सियों में ठेका श्रमिक पद्धति समाप्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का ठेका श्रमिकों के कल्याण के लिए नई नीति कब से लागू करने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) "समुचित सरकार" ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए किसी प्रतिष्ठान में किसी कार्य/प्रक्रिया/प्रचालन में ठेका श्रमिकों के रोजगार को प्रतिषिद्ध कर सकती है। केन्द्रीय सरकार ने कोयला खनन कार्यकलापों में विभिन्न प्रचालनों में ठेका श्रमिकों के रोजगार को पहले ही प्रतिषिद्ध कर दिया है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के विभिन्न प्रतिष्ठानों और निर्माण कार्य में सभी एजेंसियों के बारे में, "समुचित सरकार" सम्बन्धित राज्य सरकार है। यह केन्द्रीय सरकार का प्रयास है कि जब कभी उपरोक्त अधिनियम के उपबन्धों द्वारा ज़रूरत पड़े तो वह ठेका श्रमिकों के रोजगार के प्रतिषेध को सुनिश्चित करे।

कपड़ा यूनितों के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा

[अनुचाप]

*843. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 30 अप्रैल, 1990 को समाप्त हुई तीन माह की अवधि के दौरान उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन विभिन्न कपड़ा यूनितों के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो किस यूनित का कार्य सर्वोत्तम पाया गया;

(ग) क्या सरकार का ऐसे यूनित के प्रबन्ध को कोई प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और ज्ञान प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद घाबरे) : (क) सरकार राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि० और ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि० के अधीन वस्त्र मिलों के कार्य-निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा करती है। जबकि सरकार ने 31 मार्च, 1990 को एन० टी० सी० मिलों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की थी, बी० आई० सी० मिलों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा 20 फरवरी, 1990 को की गई थी।

(ख) से (घ) अच्छा कार्य करने वाली मिलों को प्रोत्साहन तथा मान्यता देने के उद्देश्य से एन० टी० सी० मिलों के लिए पुरस्कार स्थापित किए गए हैं। वर्ष 1988-89 के लिए निगम के जो सहायक निगमों में से प्रत्येक निगम में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली एक मिल को पुरस्कृत करने के लिए चुना गया।

एन० टी० सी० (टी० एन० एण्ड पी०) लि०, कोयम्बटूर के अधीन बलराम बर्मा टैक्सटाइल मिल्स, शेनकोट्टा और कोयम्बटूर मुकूगन मिल्स, कोयम्बटूर की समस्त एन० टी० सी० समूह में क्रमशः श्रेष्ठ कताई और कम्पोजिट मिल्स के रूप में मान्यता दी गई है। पुरस्कार के साथ-साथ हम दो मिलों के कामगारों और अधिकारियों को अनुग्रह राशि के बतौर एक दिन की मजदूरी/वेतन भी दिया गया है।

परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए योजना

*848. श्री के० सुरलीधरण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परिवार नियोजन अभियान में तेजी लाने के लिए छोटे परिवार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने और कुछ सुविधाओं विशेष से बंचित रखने की एक नई समन्वित योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) परिवार कल्याण कार्यनीति की आठवीं पंचवर्षीय योजना के सन्दर्भ में समीक्षा की जा रही है। इस सन्दर्भ में प्रोत्साहनों और हतोत्साहनों सहित विभिन्न प्रस्तावों तथा विकल्पों की जांच की जा रही है। इस मामले में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण एकक

[हिन्दी]

849. श्री हरीश रावत :

श्री सुधीर गिरि :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य प्रसंस्करण एककों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) आठवीं योजनावधि के दौरान किन-किन राज्यों में नये खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में उपलब्ध फलों के प्रसंस्करण के लिए कोई व्यापक योजना बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

बस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित, असंगठित तथा सहकारी क्षेत्रों में है। केन्द्र द्वारा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के बारे में सूचना नहीं रखी जा रही है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सीधे ही किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण एकक लगाने को कोई निर्णय नहीं लिया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन आने वाले सरकारी क्षेत्र के दो उपक्रमों, माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इण्डिया) लि० तथा नार्थ इस्टर्न रीजनल एग््रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, ने बीड, फल पेय, फल साम्रक (कन्सनट्रेट) एक्सट्रैक्ट फूड, मैदा आदि का निर्माण करने के लिए विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण एकक लगाये हैं।

प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग की वृद्धि तथा विकास को प्रोत्साहन देने के लिए 1990-91 के लिए

कई विकास योजना स्कीमें बनायी गयी हैं। फल तथा वनस्पति क्षेत्र के लिए इन स्कीमों में, उत्पादकों तथा संसाधकों के बीच पिछड़े सम्पर्कों को मजबूत करने, गुणवत्ता नियन्त्रण मजबूत करने, विस्तार व शिक्षा, आधारभूत सुविधाओं के विकास और राज्य सरकारी उपक्रमों तथा सहकारी उपक्रमों को नये प्रसंस्करण एककों की स्थापना करने एवं विद्यमान प्रसंस्करण एककों को मजबूत करने में वित्तीय सहायता देने की स्कीमें शामिल ।

समन्वित जनजातीय विकास परियोजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों की सप्लाई

[अनुवाद]

*850. श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें इस बात को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय निदेश का पालन कर रही हैं कि समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए खाद्यान्नों की निर्धारित मात्रा में सप्लाई की जाए;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों द्वारा इस निदेश का पालन नहीं किया जा रहा है और उन्होंने इसके लिए क्या-क्या कारण बताए हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्यों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही का केन्द्रीय सरकार ने अब तक कोई मूल्यांकन किया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) भारत सरकार द्वारा जनवरी, 1990 में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों (आदिवासी बहुल राज्यों को छोड़कर) से अपेक्षा की जाती है कि वे अक्टूबर-दिसम्बर, 1980 की तीन मास की अवधि के दौरान वितरण हेतु जारी की गई मात्राओं के औसत के आधार पर समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के क्षेत्रों में विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर गेहूं और चावल की आपूर्ति करने के लिए इस योजना के अधीन वितरण हेतु विशिष्ट मात्राएं निश्चित करें। तथापि, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुल मासिक आवंटन के अन्दर रहते हुए, समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों में औसत से अधिक मात्रा नियत करने के लिए स्वतन्त्र हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि इस योजना के अधीन वितरण करने के लिए विशिष्ट मात्राएं नियत कर दी गई हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में किसी भी राज्य सरकार द्वारा लापरवाही करने की कोई विशिष्ट घटना अभी तक नोटिस में नहीं आई है हालांकि असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में सूचना अभी केन्द्रीय सरकार के पास प्राप्त होनी है।

(ग) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की होती है कि निश्चित की गई मात्राएं लाभगियों को ही मिलें।

भारतीय श्रमिक सम्मेलन

*851. श्रीमती बासव राजेश्वरी :

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या हाल ही में, दिल्ली में भारतीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था;
- (ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन मुख्य मुद्दों पर विचार किया गया;
- (ग) सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों एवं अन्य व्यक्तियों का ब्योरा क्या है;
- (घ) सम्मेलन में की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है;
- (ङ) सम्मेलन में की गई सिफारिशों को कहां तक कार्यान्वित किया गया है; और
- (च) पिछला भारतीय श्रमिक सम्मेलन कब हुआ था और अगर सम्मेलन आयोजित करने में असाधारण विलम्ब हुआ हो तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय श्रम सम्मेलन का 29वां अधिवेशन नई दिल्ली में 21-22 अप्रैल, 1990 को हुआ था।

इस सम्मेलन की कार्यसूची मर्दे निम्नानुसार थी :

1. भारतीय श्रम सम्मेलन के 28वें अधिवेशन के मतैक्य पर की जाने वाली कार्रवाई।
2. प्रबन्ध में श्रमिक सहभागिता।
3. औद्योगिक सम्बन्ध विधान की समीक्षा (औद्योगिक विवाद अधिनियम और व्यवसाय संघ अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों को शामिल करते हुए।
4. मामान्य सत्यापन प्रक्रिया और सत्यापन के उद्देश्य के लिए उद्योगों का वर्गीकरण।
5. असंगठित श्रमिकों से सम्बन्धित घटनाओं की समीक्षा।
6. श्रम कानूनों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा।
7. बाल, महिला श्रमिकों तथा उत्प्रवास श्रमिकों से सम्बन्धित कानून और नीतियां।
2. सम्मेलन में भाग लेने वालों की सूची अनुबन्ध में दी गई है।
3. इस सम्मेलन ने निम्नलिखित सिफारिशें की :
 1. भारतीय श्रम सम्मेलन हर वर्ष नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा।
 2. स्थायी श्रम समिति की बैठक हर छह माह में बुलाई जाएगी।

3. प्रबन्ध में श्रमिक भागीदारी प्रदान करने के लिए सांविधिक ढांचे की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। सहभागी मंचों पर कर्मकारों को प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान के आधार पर होना चाहिए तथा सभी स्तरों पर सहभागिता होनी चाहिए। इक्विटी में भागीदारी से सम्बन्धित प्रश्न को प्रस्तावित सांविधिक योजना से पृथक रखा जाए।

4. सम्मेलन का यह सर्व सम्मत विचार था कि व्यवसाय संघ तथा औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, जो राज्य सभा में 1988 में पेश किया गया था, वापस ले लिया जाए। साथ ही, यह महसूस किया गया कि अनेक अत्यावश्यक पहलू हैं, जिनमें उद्योग की परिभाषा शामिल है, जिसके लिए नये विधेयक को शुरू करने की आवश्यकता पड़ेगी। विशिष्ट प्रस्तावों को तैयार करते समय, यह सिफारिश की गई कि श्री जी० रामानुजम की अध्यक्षता में एक द्विपक्षीय समिति गठित की जाए।

5. इस सम्मेलन ने सत्यापन प्रक्रिया का समर्थन किया जैसाकि केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों द्वारा 31-12-1986 को हुई बैठक में स्वीकार किया गया था। ग्रामीण/कृषि क्षेत्र में सदस्यता के सत्यापन के लिए प्रक्रिया के बारे में, इस मामले पर केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में और विचार किया जाएगा।

6. निर्माण श्रमिकों तथा कृषि श्रमिकों के बारे में केन्द्रीय विधान पेश करने के प्रश्न पर आम मतैक्य था।

7. श्रम कानूनों के कार्यान्वयन और बाल श्रमिकों, महिला श्रमिकों तथा कानूनों तथा उत्प्रवास श्रमिकों से सम्बन्धित कानूनों और नीतियों के पुनरीक्षण के बारे में, यह स्वीकार किया गया कि इन मामलों पर स्थायी श्रम समिति में विचार-विमर्श किया जाएगा।

4. प्रबन्ध में कर्मकार भागीदारी के बारे में उपयुक्त विधान पर पहले ही विचार किया जा रहा है। भूमिहीन कृषि श्रमिक तथा निर्माण श्रमिकों से सम्बन्धित विधान के प्रस्ताव पर विचाराधीन हैं।

औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए द्विपक्षीय समिति गठित की गई है।

5. पिछला भारतीय श्रम सम्मेलन 25-26 नवम्बर, 1985 को हुआ था। यह दुर्भाग्य की बात है कि बीच के वर्षों के दौरान सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया।

अनुबन्ध

भाग लेने वालों की सूची

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	भाग लेने वालों का नाम
1	2	3
1.	असम	1. श्री बी० पी० तेलंग, श्रम एवं रोजगार मंत्री

1 2

3

2. आन्ध्र प्रदेश 3. अण्डमान और निकोबार 4. अरुणाचल प्रदेश 5. बिहार 6. चण्डीगढ़ 7. दिल्ली प्रशासन 8. वादर एण्ड नागर हवेली 9. गोवा 10. गुजरात	<p>2. श्री एस० के० पुरकायस्थ,
आयुक्त एवं सचिव, अम</p> <p>3. श्री एल० एम० बरजा, अम आयुक्त</p> <p>1. श्री जे० एस० शर्मा,
अम आयुक्त एवं आन्ध्र प्रदेश
सरकार के पदेन सचिव</p> <p>1. श्री अशोक कुमार, सचिव (एल)</p> <p>1. श्री जे० के० दादू, अम सचिव</p> <p>2. श्री मारगो इटे, उप अम आयुक्त</p> <p>1. श्री ब्रिस्तिन पटेल, अम मन्त्री</p> <p>1. श्री अशोक प्रधान
प्रशासक के सलाहकार,
संच राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़</p> <p>1. श्री डी० एम० सपोलिया
सचिव, (एल)</p> <p>2. श्रीमती एम० बासी,
उप सचिव (एल)</p> <p>1. श्री अशोक टी० नायक, सातगांवकर
अम मन्त्री</p> <p>1. श्री प्रवीन सिंह जडेजा
रोजगार, पर्यटन एवं पर्यावरण मन्त्री</p> <p>2. श्री फकीर भाई बाबला, अम मन्त्री</p> <p>3. श्री फाकर भाई नायक, राज्य अम मन्त्री</p> <p>4. श्री सी० बी० गिरधर, अपर मुख्य
सचिव</p> <p>5. श्री आर० एल० धीना, निदेशक,
रोजगार एवं प्रशिक्षण</p> <p>6. श्री जी० एल० भगत, अम आयुक्त</p> <p>7. श्री डी० बी० सोलंकी, अपर सचिव</p> |
|---|---|

1 2

3

11. हरियाणा

1. श्री बलबीर सिंह सेनी
राज्य श्रम मन्त्री
2. श्री कमल चौधरी, श्रम आयुक्त
3. श्री राम स्वरूप, संयुक्त श्रम आयुक्त

12. हिमाचल प्रदेश

1. श्री रूप सिंह ठाकुर, श्रम मन्त्री
2. श्री अतार सिंह, श्रम सचिव
3. श्री लाल जी सिंह, श्रम आयुक्त
4. श्री एम० राम, श्रम मन्त्री के निजी सचिव

13. जम्मू और कश्मीर

1. श्री काजी एम० अमीन,
जम्मू और कश्मीर सरकार के खाद्य,
आपूर्ति, परिवहन एवं श्रम सचिव

14. कर्नाटक

1. श्री बी० सिबन्ना,
समाज कल्याण एवं श्रम मन्त्री
2. श्री के० पी० सिंह,
कर्नाटक सरकार के समाज कल्याण
सचिव
3. श्री जी० के० संगमेश्वर
राज्य श्रम आयुक्त

15. केरल

1. श्री के० पंकजक्षसन मन्त्री (एल)
2. श्री सी० पी० नायर,
आयुक्त एवं सचिव (एल)
3. श्री जोसेफ एम० पी०,
श्रम आयुक्त

16. लक्षद्वीप

17. महाराष्ट्र

1. श्री एन० एम० काम्बले, मन्त्री (एल)
2. श्री के० एस० बारसी, सचिव (एल)
3. श्री सी० डी० डिगरो, आयुक्त (एल)

18. मध्य प्रदेश

1. श्री लीला राम भोजवानी,
राज्य श्रम मन्त्री
2. श्री एम० एम० राव,
प्रधान सचिव

1	2	3
		3. श्री आर० सी० जैन, अपर अम आयुक्त
19. मणीपुर		
20. मेघालय		1. श्री एल० एच० पीट्टे, अम आयुक्त
21. मिजोरम		1. श्री सैकापथिअंगा, राज्य मन्त्री
		2. श्री टी० गुप्ता, सचिव (एल)
22. नागालैंड		1. श्री भिखासेसामा, अम मंत्री
		2. श्री एन० जी० लालू, सचिव एवं आयुक्त
		3. श्री नुंगशी अय्यर, अम आयुक्त
23. उड़ीसा		1. श्री प्रफुल सामल
		राज्य मन्त्री
		2. श्री प्रणव कुमार डे, अम सचिव एवं आयुक्त
		3. श्री राम नाथ मोहन्ती, अम आयुक्त
24. पंजाब		1. श्री आर० पी० खन्ना, पंजाब सरकार के सलाहकार
		2. श्री जी० एस० सन्धू, अम आयुक्त
		3. श्री सी० एल० गर्ग, अपर अम आयुक्त
		4. श्रीमती गुरबिन्दर चहल, अम आयुक्त
25. पाण्डिचेरी		
26. राजस्थान		1. श्री गोबिन्द जी मिश्रा, अम सचिव
		2. श्री आर० के० तिवारी, विशेष सचिव एवं अम आयुक्त
		3. श्री ए० एन० भागव, संयुक्त अम आयुक्त
		4. श्री एस० एन० मल्होत्रा, संयुक्त अम आयुक्त
		5. श्री राम किशोर मीना, मंत्री
		6. श्री अशोक सिंह, खाद्य मंत्री के निजी सहायक

1	2	3
27.	सिक्किम	
28.	तमिलनाडु	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्री धीरु के० एम० नेहरू, सूचना एवं श्रम मंत्री 2. श्री धीरु ए० सुब्रह्मणियम, संयुक्त सचिव 3. श्री धीरु के० मलायसामी, राज्य आयुक्त 4. श्री जी० बरत राजन, श्रम मंत्री के विशेष निजी सहायक
29.	चिपुरा	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्री ए० के० कर, श्रम मन्त्री 2. श्री एम० मजूमदार, श्रम आयुक्त
30.	उत्तर प्रदेश	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्री मोहम्मद आजम खां, श्रम मंत्री 2. श्री महेन्द्रसिंह, श्रम सचिव 3. श्री विष्णू स्वरूप 4. श्री जे शंकर पांडे, अपर श्रम आयुक्त 5. श्री एम० पी० श्रीवास्तव, पी० एस०/यू० एस० टू यू० पी० (एस० एम०) 6. श्री के० एल० द्विवेदी, अपर श्रम आयुक्त 7. श्री एच० सी० जैन, वरिष्ठ अन्वेषक
31.	पश्चिम बंगाल	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्री दीपक कुमार घोष, श्रम सचिव 2. श्री एस० घाटक श्रम मन्त्री 3. श्री सेन गुप्ता, श्रम मंत्री के मुख्य सलाहकार 4. श्री आर० एन० मुखर्जी, संयुक्त सचिव 5. डा० टी० कुमार श्रम आयुक्त
32.	दमन और द्वीप	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्री आर० के० वर्मा, श्रम सचिव

21-22 अप्रैल, 1990 को नई दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन के 20वें अधिवेशन में भाग लेने वालों की सूची

निबोधक संघटन

भारतीय निबोधक परिषद

1. डा० बंसीधर प्रेबीशेंट, आल इण्डिया (प्रतिनिधि)

- भार्गनाइवेशन आफ इम्प्लायर्स,
चैयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, डी०
सी० एम० लि०, नई दिल्ली ।
2. श्री केशव महेन्द्रा, प्रेजीडेंट, ई० एफ०
आई० चैयरमैन महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा
लि० बम्बई । (प्रतिनिधि)
3. मेजर जनरल एस० सी० एन० जाटर,
चैयरमैन स्टेडिंग कान्फेन्स आफ
पब्लिक इन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली । "
4. श्री डी० डी० पुरी, बाइज प्रेजीडेंट,
ई० एफ० आई० चैयरमैन, इण्डियन
शुगर एण्ड जनरल इन्जीनियरिंग
कारपोरेशन, नई दिल्ली । "
5. श्री राजेन्द्र सिंह डायरेक्टर (पी),
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन,
नई दिल्ली । "
6. श्री प्रताप भाई लाल, बाइज प्रेजीडेंट
ई० एफ० आई० चैयरमैन बाटलीवाई
एण्ड कं० लि०, बम्बई । "
7. श्री ए० एस० काशलीबाल एस०
कुमार, इन्टरप्राइजेज प्रा० लि०,
बम्बई । "
8. श्री एस० सी० भट्टाचार्य, बाइज
प्रेजीडेंट, (कामिक एवं प्रशासनिक),
कलकत्ता । "
9. श्री सी० एम० कृष्णा डायरेक्टर
(पी) हिन्दुस्तान एयरोनोटिक, लि०,
बंगलौर । "
10. श्री रवि भूषालिंगम, बाइज प्रेजीडेंट,
ई० एफ० एस० आई० एण्ड मैनेजिंग
डायरेक्टर, बी० एस० टी० इंडस्ट्रीज
लि०, नई दिल्ली । "
11. श्री एम० आर० आर० नायर, डाय-
रेक्टर (पी) स्टील मथारिटी आफ
इण्डिया लि०, नई दिल्ली । "

12. श्री आर० बी० कनोरिया, ज्वाइंट मैने० डायरेक्टर कनोरिया कैमीकल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि० नई दिल्ली ।	(प्रतिनिधि)
13. श्री आर० पी० आनन्द, कारपोरेट शिक्षाघाने सेन्टर, नई दिल्ली ।	"
14. श्री वारिस आर० किदवई, जनरल सेक्रेटरी, स्टेडिंग कान्फेंस आफ पब्लिक इंटर प्राइजेज, नई दिल्ली ।	"
15. डा० राम एस० तरनेजा, मैनेजिंग डायरेक्टर डेन्नोट कोलमन एण्ड कं०, लि०, बम्बई ।	"
16. श्री आताराम सारोगी, प्रेजिडेंट, इंडियन कैमिकल मैनुफैक्चरर्स एसो०, कलकत्ता ।	"
17. श्री बी० एन० पारलीबाला	"
18. श्री के० डी० गुप्ता (एस० सी० ओ० पी० ई०)	"
1. श्री टी० सी० जैन, चीफ एक्जीक्यूटिव, इम्प्लाइयर्स एसोसिएशन आफ राजस्थान ।	(सलाहकार)
2. श्री अनिल सचदेव, एच० आर० डी० सब कमेटी, कोनफेडरेशन आफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली ।	"
3. श्री एन० साह, लेबर एडवाइजर, बंगाल चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, कलकत्ता ।	"
4. श्री एच० सी० धीबास्तव, सेक्रेटरी, फेडरेशन आफ एम० पी० चेम्बरस आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, भोपाल ।	"
5. श्री एन० कानन, सेक्रेटरी, एम्पलाइस फेडरेशन आफ सचन, इण्डिया, मद्रास ।	"
6. डा० पारेश रावल, सेक्रेटरी, फेडरेशन	"

- आफ गुजरात मिल, एंड इंडस्ट्रीज बङ्गोदा ।
7. श्री बी० पी० गुप्ता, सलाहकार पी० (सलाहकार)
एच० डी० चेम्बर आफ कामर्स एंड
इन्डस्ट्री ।
8. श्री आर० सी० पांडे, सेक्रेटरी, ए० "
आई० ओ० ई० फंडरेशन हाउस, नई
दिल्ली ।
9. श्री बी० बी० माहसे, सेक्रेटरी, ई० "
एफ० आई०, बम्बई ।
10. श्री आर० एम० भंडारी, नई दिल्ली । "
11. श्री जी० श्रीवास्तव, सेक्रेटरी, पटना । "
12. आर० बी० पिटाला, लेबर एडवाइजर "
बम्बई चेम्बर्स आफ कामर्स एंड इन्ड-
स्ट्रीज, बम्बई ।
13. डा० आर० सी० अग्रवाल, प्रेजिडेंट "
जे० के० जूट मिल्स, कम्पनी लि०,
कानपुर ।
14. श्री जे० पी० गोयल, एन० टी० सी० "
15. श्री पी० के० दास गुप्ता "
16. श्री अक्षय शंकर "
17. श्री पी० एम० साह, डायरेक्टर, "
कैमिकल वर्क्स, बङ्गोदा ।
18. श्री पी० सी जैन, इम्प्लायरस एसो- "
सिएशन, जयपुर ।
19. श्री सी० एम० कृष्णा "

आल इण्डिया मॅम्बर्सशिपस आर्गे०

1. श्री एन० आर० पाटिल, को० (प्रतिनिधि)
चैयरमैन ए० आई० एम० ओ०
स्पेशल कानसिल फोर इंडस्ट्रीयल
रिलेसन्स, बम्बई ।
2. श्री आई० पी० पोदार, पास्ट प्रेजिडेंट "
ए० आई० एम० टी०

	3. श्री बी० एन० बर्मा, सोसनीवाल ब्रदर्स ।	(प्रतिनिधि)
कर्मकार संगठन		
1. इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनितन कांफ्रेस, नई दिल्ली ।	1. श्री जी० रामानुजम, प्रेसीडेंट, इंटक, मद्रास ।	"
	2. श्री गोपेश्वर, महासचिव, इंटक, जमशेदपुर ।	"
	3. श्री बी० जी० गोपाल, उपाध्यक्ष, इंटक, जमशेदपुर ।	"
	4. श्री जी० संजीवा रेड्डी, उपाध्यक्ष इंटक, हैदराबाद ।	"
	5. श्री सुब्रतो मुखर्जी, उपाध्यक्ष, कलकत्ता ।	"
	6. श्री मनोहर फालका, संगठन सचिव, बम्बई ।	"
	7. श्री बी० पी० मोरक्का, अध्यक्ष, इंटक, कोचीन ।	"
	1. श्री आर० पी० पणिका, उपाध्यक्ष, इंटक, मिर्जापुर ।	(सलाहकार)
	2. श्री एस० एल० पास्तेय, सेक्रेटरी, इंटक, नई दिल्ली ।	"
	3. श्री तारा सिंह बियोगी, सचिव, इंटक, खालियर ।	"
	4. श्री आर० एल० ठाकुर, सचिव, इंटक, नई दिल्ली ।	"
	5. श्री आर० सी० आर्य, संगठन सचिव, भिलाई ।	"
	6. श्री एस० एन० राव, इंडीटर, इंडियन वर्कर, नई दिल्ली ।	"
2. भास इंडिया ट्रेड यूनियन कांफ्रेस	1. श्री इन्द्र जीत गुप्ता, संसद सचिव, महासचिव, नई दिल्ली ।	(प्रतिनिधि)

	2. श्री होमी दाजी, सचिव ।	(प्रतिनिधि)
	3. श्री के० एल महेन्द्रा, सचिव ।	"
	4. श्री एस० के० सन्याल	(आयजबर)
3. हिन्द मजदूर सभा	1. श्री समरेन्द्र कुंदू, संसद सदस्य, अध्यक्ष, हि० म० सं०	(प्रतिनिधि)
	2. श्री उमरावमल पुरोहित, महासचिव, हि० म० सं०	"
	3. श्री एस० आर० कुलकर्णी, अध्यक्ष, बम्बई ।	"
	4. श्री भीरेश्वर त्यागी, सचिव, हि० म० सं०	(सलाहकार)
	5. श्री ए० डी० नागपाल, सचिव	"
4. यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एल० एस०)	1. श्री प्रितिष चन्दा, अध्यक्ष, यू० टी० यू० सी० (एल० एस०) कलकत्ता ।	(प्रतिनिधि)
	2. श्री एफ० घोष, सचिव, यू० टी० यू० सी० (एल० एस०) कलकत्ता ।	"
	3. श्री ज्ञान सिंह, सचिव, यू० टी० यू० सी० (एल० एस०) हरियाणा ।	"
5. यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस	1. अनिल दास चौधरी	"
	2. जतिन चक्रवर्ती	"
6. भारतीय मजदूर संघ	1. श्री जी० प्रभाकर, महासचिव भा० म० सं०, नई दिल्ली ।	"
	2. श्री आर० के० भक्त, रेजी० सैक्रेटरी, भा० म० सं०, नई दिल्ली ।	"
	3. श्री ओम प्रकाश अषी, संगठन सचिव, भा० म० सं०, नई दिल्ली ।	"
	4. श्री आर० बेणुगोपाल, सचिव, भा० म० सं०, पालघाट ।	"
	5. श्री राम लुभाया बाबा, महासचिव, भा० म० सं०, पंजाब ।	(सलाहकार)

	6. श्री रास बिहारी मोयथा, महासचिव,
भा० म० सं०, पश्चिम बंगाल ।	(सलाहकार)
	7. श्री रिसब चन्द जैन, महासचिव,
भा० म० सं०, राजस्थान ।	"
	8. श्री राम घोर सिंह, भा० म० सं०,
कानपुर ।	"
	9. श्री आर० वी० सुब्बा राव, महा-
सचिव, भा० म० सं०, आन्ध्र प्रदेश ।	"
7. सौम्टर आफ इंडियन
ट्रेड यूनियन्स	1. कॉम० एन० के० पांघे, सचिव, सी०
आई० टी० यू०	(प्रतिनिधि)
	2. कॉम० आर० उमानाथ, उपाध्यक्ष	"
	3. कॉम० के० एम्० रत्नमन्नाथ, सचिव	"
	4. कॉम० एम० डी० अमीन, सचिव	(सलाहकार)
	5. कॉम० पी० के० गांगुली, सचिव	"
	6. कॉम० जिवोन राय, सचिव	"
8. ट्रेड यूनियन कार्डी-
नेशन सौम्टर	1. कॉम० पी० डी० पालीवाल, अध्यक्ष	(प्रतिनिधि)
9. नेशनल सेबर आरगे-
नाइजेशन	1. श्री एन० एम० बरोट, अध्यक्ष, एन०
एल० ओ०	"
	2. श्री एन० पी० सिंह, एन० एल० ओ०	"

21-22 अप्रैल, 1990 को नई दिल्ली में हुए भारतीय अम सम्मेलन के 29वें अधिवेशन में भाग लेने वालों की सूची

केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग :

1. ऊर्जा मंत्रालय	1. श्री आरिफ मु० खान, ऊर्जा मंत्री
	2. श्री के० के० माधुर, अतिरिक्त सचिव,
(विद्युत विभाग)
	3. श्री एस० पी० कुटार, उप सचिव,
(प्रशा०) (विद्युत विभाग)
2. जल संसाधन मंत्रालय	1. श्री मनुधार्ई कोटडिया, राज्य मंत्री (स्वतंत्र
प्रधार), जल संसाधन मंत्रालय ।

3. शहरी विकास मंत्रालय	2. श्री जे० पी० सिंह, अपर सचिव ।
	1. श्री मुरासोमी मोरन, शहरी विकास मंत्री ।
	2. श्रीमती जे० बन्ना, संयुक्त सचिव ।
	3. श्री यू० सी० प्रसाद, उप सलाहकार (अभ्य कल्याण) ।
4. ग्रामीण विकास मंत्रालय	1. श्री के० बी० सप्तसेना, संयुक्त सचिव ।
5. संचार मंत्रालय	1. श्री आर० के० सर्वेन्द्र, सचिव (शाक)
	2. श्री के० सीक, उप सहायक सचिव ।
6. रक्षा मंत्रालय
(रक्षा उत्पादन और आपूर्ति)	—
7. दूरसंचार मंत्रालय	—
8. शिक्षा विभाग	—
9. महिला व बाल विकास विभाग	1. श्रीमती मीनाक्षी आनन्द चौधरी, संयुक्त सचिव ।
10. कृषि मंत्रालय	1. श्री पी० आर० साहू, आर्थिक एवं सांख्यिकी सलाहकार ।
	2. श्री एस० आर० साहू, संयुक्त सचिव ।
11. पेट्रो और रसायन मंत्रालय	1. श्री टी० एस० पन्सेला, सलाहकार (एन० ई० एम०)
12. आयोजना मंत्रालय	1. श्री बी० शंकरजीवन, संयुक्त सचिव ।
13. भूतल परिवहन मंत्रालय	1. श्री एस० के० जोशी, निदेशक (कार्मिक), एन० टी० सी०
14. टैक्सटाइल्स मंत्रालय	1. श्री ए० बी० गणेश्वर, सचिव ।
15. नागर विमानन विभाग	1. श्रीमती आशा मूर्ति, निदेशक ।
16. पर्यटन विभाग	1. श्री पी० के० साहू, सचिव ।
17. खान विभाग	—
18. इस्पात विभाग	—
19. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	1. श्री एस० बी० मिश्रा, संयुक्त सचिव ।
20. खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	1. श्री सतीश चन्द्र, संयुक्त सचिव ।
21. खाद्य विभाग	1. श्री गुरुदेव सिंह, उप सचिव ।
22. विज्ञान एवं प्रायोगिकी मंत्रालय	1. श्री आरविद्यागाराइन, सलाहकार ।

23. रेलवे मंत्रालय

1. श्री के० बी० कृष्णामूर्ति, सदस्य स्टाफ, रेलवे बोर्ड और पदेन सचिव ।
2. श्री एस० गुरुशरण, सलाहकार (स्टाफ), रेलवे बोर्ड ।
3. श्री एन० सी० सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (औद्योगिक सम्बन्ध)
4. श्री पी० टी० चिन्मोगादम, कार्यकारी निदेशक (स्थापना)

श्रम मंत्रालय के भाग लेने वालों की सूची (भा० अ० सं० 21-22 अप्रैल, 90)
माननीय प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सम्मेलन की अध्यक्षता की

1. श्री राम विलास पासवान, श्रम एवं कल्याण मंत्री ।
2. श्री बी० पी० साहनी, सचिव, श्रम मंत्रालय ।
3. श्री एस० दयाल, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ।
4. श्री पी० जी० लाला, वित्त सलाहकार
5. श्री अशोक नारायण, संयुक्त सचिव
6. श्री जी० एस० लुभाना, संयुक्त सचिव
7. श्री एच० घोष, संयुक्त सचिव
8. कु० मीना गुप्ता, संयुक्त सचिव
9. श्री जगदीश जोशी, महानिदेशक (एल० डब्ल्यू०)
10. श्री ए० के० चन्दा, उप सचिव
11. श्री आर० पांडेय, उप सचिव
12. श्री एस० के० बेरी, कल्याण आयुक्त (मुख्यालय)
13. श्री आर० पी० मदान, संयुक्त निदेशक
14. श्री नन्द लाल, अवर सचिव
15. श्री एस० एच० एस० आईर, अवर सचिव
16. श्री शशी भूषण, अवर सचिव
17. श्री एस० सी० शर्मा, अवर सचिव
18. श्री अशोक साहू, उप निदेशक
19. श्री बी० एम० सोम, के० भ० नि० आ०
20. श्रीमती कुसुम प्रसाद, महानिदेशक (क० रा० बी० नि०)

21. श्री एस० के० दास, मुख्य सलाहकार (श्रम कल्याण)
22. श्री एस० एन० सिंह, ओ० एस० डी०, श्रम एवं कल्याण मंत्री
23. श्री सुनील गुहा, निदेशक, आई० एल० ओ० एरिया ओफीस
24. श्री जी० अबस्थानारायन, सचिव सदस्य
25. श्री आर० एस० श्रीवास्तवा, निदेशक रोजगार कार्यालय
26. श्री एस० के० गिरी, निदेशक प्रशिक्षण
27. श्री बाई० सिंह, निदेशक शिशुता
28. श्री आर० एन० तिवारी, डीन, एन० एल० आई०
29. कु० पी० करकेटा, अवर सचिव
30. डा० बेरियन जोजफ, एसोसिएट फेलो
31. श्री के० सी० जैन, अवर सचिव

दिल्ली के गांवों की लाल डोरा की सीमा बढ़ाना

*852. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के गांवों के लोगों द्वारा लम्बे समय से की जा रही इस मांग की ओर दिलाया गया है कि उनके गांवों के विकास के लिए गांवों की "लाल डोरा" की सीमा बढ़ाई जाए;

(ख) क्या सरकार का वर्तमान स्थिति की पुनरीक्षा करने का विचार है, यदि हां, तो जोन-बार इन गांवों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दिशा में (जोन-बार) अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में "लाल-डोरा" की सीमा बढ़ाने के लिए आदेश कब तक दे दिए जाएंगे ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुराली मोहन) : (क) जी, हां ।

(ख) संलग्न विवरण-1 में बिनिदिष्ट 77 गांवों को लाल डोरा के विस्तार के लिए अधिसूचित किया गया है ।

(ग) संलग्न विवरण-2 के अनुसार ।

(घ) कोई समय सीमा बताना सम्भव नहीं है परन्तु अधिसूचित गांवों को एक-एक करके सामान्यित किया जाना है ।

बिहार-1

उन गांवों की सूची जहाँ जाठों की योजना अखंड के दौरान सरकारों के परिवारों के कार्यवाही की जाती है

नरैला जिले

1. अकबरपुर माजरा
2. अलीपुर
3. भारगढ़
4. बुद्धपुर-बीजापुर
5. हरेमली
6. हिरांकी
7. इन्द्राहिमपुर
8. झंगोला
9. बबालकपुर
10. सुलतानपुर बबास
11. ताजपुर कलां
12. सूंघेरपुर
13. बंकनेर
14. बवाना
15. बजीतपुर धकरन
16. बुद्धपुर
17. चांदपुर
18. दरयापुर कलां
19. धौंधा
20. हमीदपुर
21. होलुम्बी
22. जटखोर
23. कटेबाड़ा
24. खेरा कलां
25. लामपुर

26. मोहमबपुर रामानपुर
27. मुज्जमेलपुर
28. मुंगासपुर
29. नांगल ठकरन
30. मौचन्वी
31. पल्ता
32. पूष खुर्द
33. काचिपुर
34. कुसुब गढ़
35. झाहपुर गढ़ी
36. सिधूं
37. सुरेश पुर
38. तिगीपुर
39. टिकड़ी खुर्द
40. बस्ताबरपुर
41. बिबपुर

मज्जमगढ़ खोल

42. बककरबाला
43. चतेसर
44. हिरण कुंदा
45. कंसाबला
46. लाहपुर
47. बपरीला
48. चारी रिरघाला
49. झड़ोवा कला
50. कौर
51. रोसनपुरा
52. सुरेरा
53. ताजपुर खुर्द

54. जप्करपुर कलां
55. सवादा

दिल्ली जोन

56. झड़ोदा माजरा बुरारी

पालम जोन

57. बमनौली
58. किराड़ी बुराड़ी
59. नानक हरी
60. राधोपुर
61. बाबू सराय
62. मदनपुर डबास
63. कमरूद्दीन नगर
64. रसूलपुर
65. रानी खेड़ा
66. तिलंगपुर कोटला
67. पिडवाला खुदं
68. नीलोधी
69. रनहोला

महरोली जोन

70. गदाइपुर
71. पुपह्लाद
72. सतबड़ी
73. छत्तरपुर
74. छटीरनी
75. रजोकरी
76. सिमालका
77. धाया नगर

बिबरन-2

उन गांवों की सूची जहां अफगन्वी के द्वारा आबादी क्षेत्र (साल डोरा) के विस्तार का कार्य किया जाना है

जहां कार्य पूरा हो गया हो	अग्रिम चरण में है	प्रगति पर है
नरेला जोन	नरेला जोन	नजफगढ़ जोन
1. बुढपुर—बीजापुर	1. अलीपुर	1. फौर
2. हमीदपुर		2. बखरबांसा
3. मूंगेशपुर		3. चतेशर
		4. हिरणकुंड
		नरेला जोन
		5. औचन्वी
		6. पूष खुर्द
		7. हीरकी
		8. जटखोर
		9. दरयापुर कर्मा
		10. काबिपुर

एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी के लिए बजट में आवंटन

*853. श्री गंगा चरण लोधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान होम्योपैथी, आयुर्वेद और एलोपैथी के लिए बजट में कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान होम्योपैथी और आयुर्वेद के लिए बजट में आवंटन में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उर्जा मंत्री तथा मानव विभाग मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ख) होम्योपैथी आयुर्वेद और एलोपैथी के लिए पिछले तीन वर्षों के योजना आवंटन (संशोधित बजट अनुभाग) नीचे

दर्शाए गए हैं :—

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	होम्योपैथी	आयुर्वेद	एलोपैथी
1987-88	0.97	3.24	182.64
1988-89	1.35	4.47	217.63
1989-90	1.55	4.78	225.62

(इन आंकड़ों में शहरी विकास मंत्रालय की मांग में पूंजीगत निर्माण कार्य के लिए बजट प्रावधान शामिल नहीं है)

यह देखा जा सकता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान होम्योपैथी और आयुर्वेद के लिए संशोधित बजट अनुमानों (प्लान) में कमी नहीं आई है।

कपास का निर्यात

[हिन्दी]

*854. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान कपास का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार का कपास के बढ़े हुए उत्पादन को ध्यान में रखते हुए इसके निर्यात में वृद्धि करने का विचार है;

(ग) क्या इसके निर्यात के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा उन्हें अपनी उपज का लाभप्रद मूल्य मिले ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) रई सलाहकार बोर्ड ने वर्ष 1989-90 के मौसम के दौरान रई की 122 लाख गांठ के उत्पादन का अनुमान लगाया है।

(ख) सरकार ने वर्ष 1989-90 के दौरान निर्यात के लिए रई की 13.85 लाख गांठ का कोटा रिलीज किया है जबकि पिछले वर्ष निर्यात के लिए रई की केवल 2.26 लाख गांठ का कोटा रिलीज किया गया था। ऐसा बढ़ रही घरेलू मांग को पूरा करने के बाद निर्यात योग्य बेशी को ध्यान में रख कर किया गया है।

(ग) और (घ) सरकार स्थिति की कड़ी मानीटरी कर रही है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है। निर्यात एजेंसियों से कहा गया है कि वे निर्यात कोटाओं का पूरा उपयोग सुनिश्चित करें।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार व्यक्ति

[अनुवाद]

*855. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा : क्या धम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के स्नातकोत्तर, स्नातक और मैट्रिकुलेट स्तर तक शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है; और

(ख) क्या सरकार ने इनको रोजगार प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई है, यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

धम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) और (ख) 1988 के अन्त में, रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वाले स्नातकोत्तर, स्नातक तथा मैट्रिकुलेट रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों, यह अनिर्धार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, की राज्यवार संख्या (अंतिम) संलग्न विवरण में दी गई है।

2. संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभागों तथा उनके उप-क्रमों में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। आरक्षणों के अतिरिक्त, सरकार ने सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति में भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को विभिन्न रियायतों तथा सुविधाएं दी हैं। इनमें ये शामिल हैं : (1) आयु में छूट, (2) शुल्क रियायत, (3) उपयुक्तता के मानदण्डों में छूट, (4) सीधी भर्ती में "अनुभव" अहंता में छूट, (5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए विशेष साक्षात्कार, (6) साक्षात्कारों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते की अदायगी, (7) प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक अवसर, (8) चयन समितियों/विभागीय पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व, (9) भर्तीपूर्व अध्यापन, इत्यादि।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां भरी जाती हैं, केन्द्र सरकार ने 1989 के दौरान एक विशेष भर्ती अभियान संचालित किया था। आगे, सरकार ने वर्ग 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' में रिक्तियों को भरने के लिए सीधी भर्ती के सभी मामलों में कनारक्षण पर रोक लगाने का भी निर्णय लिया है।

4. रोजगार कार्यालय नियोजकों से प्राप्त मांगपत्रों को ध्यान में रखकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रायोजित करते हैं। इन उम्मीदवारों को न केवल आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रायोजित किया जाता है अपितु उनकी उपयुक्तता एवं बरिष्ठता से अनुसार सामान्य रिक्तियों के लिए भी प्रायोजित किया जाता है।

संस्करण

31-12-1988 की स्थिति के अनुसार, रोजगार कार्यालयों में, बाहू रजिस्टर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नौकरों का हने वाले शिक्षितों (मैट्रिक और ऊपर) की संख्या (अन्यथा)

संख्या संकड़ों में

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	शिक्षित अनुसूचित जाति			शिक्षित अनुसूचित जनजाति			योग	स्नातकोत्तर	योग
		मैट्रिक/ इण्टरमीडियेट	स्नातक	स्नातकोत्तर	मैट्रिक/ इण्टरमीडियेट	स्नातक	स्नातकोत्तर			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
राज्य										
1.	आन्ध्र प्रदेश	973.4	50.0	7.7	1071.0	195.8	6.0	0.5	202.2	
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.1	†	—	0.2	1.0	†	—	1.2	
3.	आसाम	224.3	26.2	1.0	251.5	376.2	23.9	1.3	401.5	
4.	बिहार	1273.1	137.1	2.2	1412.4	746.7	122.5	1.0	870.1	
5.	गोवा	3.3	0.2	—	3.5	†	†	—	0.1	
6.	गुजरात	586.1	27.9	4.0	617.9	320.9	25.5	1.4	347.8	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. हरियाणा			296.5	16.4	1.3	314.2	0.1	—	†	0.1
8. हिमाचल प्रदेश			294.2	13.4	1.3	308.9	48.2	4.3	0.8	53.3
9. जम्मू और काश्मीर			24.9	15.5	1.4	41.8	5.4	0.5	0.2	6.1
10. कर्नाटक			532.5	61.1	13.0	606.6	64.2	5.4	1.8	71.4
11. केरल			1230.2	25.0	3.0	1258.1	47.7	0.6	0.1	48.4
12. मध्य प्रदेश			825.5	84.5	13.7	923.7	506.1	46.3	7.2	559.7
13. महाराष्ट्र			1906.1	170.8	34.0	2110.9	392.2	31.1	2.8	426.1
14. मणिपुर			8.3	1.1	0.1	9.5	232.9	21.9	0.7	255.5
15. मेघालय			0.8	0.1	—	0.9	59.6	5.2	0.3	65.2
16. मिचोरस			—	—	—	—	95.7	12.7	1.8	110.2
17. नागालैंड			4.2	1.0	0.1	5.3	110.2	9.6	0.9	121.0
18. उड़ीसा			307.1	31.7	1.8	340.6	178.9	16.2	0.6	195.7
19. पंजाब			442.4	65.8	4.8	513.0	0.2	†	—	0.2
20. राजस्थान			375.6	71.1	4.9	451.6	187.8	33.2	3.5	224.4
21. त्रिफिक्कम्										
22. तमिलनाडु			1841.3	178.3	13.1	2032.8	24.3	1.6	0.1	26.0
23. त्रिपुरा			39.2	4.1	0.1	43.4	19.4	1.1	0.1	20.6
24. उत्तर प्रदेश			2166.1	455.6	69.1	2690.8	26.1	5.8	2.2	34.0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. पश्चिम बंगाल			1282.1	316.2	14.9	1613.2	187.9	16.3	0.4	204.6
संघ शासित प्रदेश										
1. अद्यतन और निकोबार द्वीप समूह			—	—	—	—	0.8	0.1	†	0.9
2. बम्बईगढ़			143.8	19.1	0.3	163.1	0.7	0.2	†	0.8
3. रावर नागर हुबेली			0.8	†	†	0.9	4.8	0.3	†	5.1
4. विल्पी			473.8	79.1	13.2	566.2	22.5	4.3	1.8	28.6
5. दसन और द्वीब**			—	—	—	—	16.4	0.3	0.2	16.9
6. सक्कट्टीप			—	—	—	—	—	—	—	—
7. पाडिबेरी			26.6	3.2	0.3	30.1	0.4	0.1	†	0.5
योग :			15282.1	1894.4	205.2	17381.7	3873.2	395.2	29.7	4298.0

नोट : 1. * कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है ।

2. **आंकड़े नहीं रखे जाते ।

3. शून्य ।

4. †5 से कम आंकड़े ।

5. यह हो सकता है कि पूर्णकों के कारण आंकड़े जोड़ के साथ मेल न जाएं ।

6. अ =अनल्पिम ।

ठेका श्रमिक पद्धति समाप्त करना

[हिन्दी]

*856. श्री सत्यनारायण खटिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंधुआ श्रमिकों और ठेका श्रमिकों में क्या अन्तर है;

(ख) क्या सरकार का बंधुआ श्रमिकों की तरह ठेका श्रमिक पद्धति समाप्त करने का विचार है जिसे ठेका श्रमिकों को शोषण से बचाया जा सके; और

(ग) सभी ठेका श्रमिकों की सेवाएं नियमित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) से (ग) बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 में, अन्य बातों के साथ-साथ बंधुआ श्रमिक को बन्धित श्रम पद्धति के अधीन, जो बलात श्रम पद्धति है, किया गया कोई श्रम या की गई कोई सेवा के रूप में परिभाषा की गई है। दूसरी ओर, ठेका श्रमिक ऐसे कर्मकार होते हैं जिन्हें प्रधान नियोजक की जानकारी में या जानकारी के बिना किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से स्थापन के काम के लिए किसी काम में भाड़े पर रखा जाता है। जबकि पहले वाला अधिनियम बलात श्रम पद्धति का प्रतीक है, दूसरा अधिनियम ठेकेदार द्वारा काम करने के लिए स्थापन में कर्मकारों के अप्रत्यक्ष रोजगार की पद्धति का उल्लेख करता है।

बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1979 की तरह ही, जिसके द्वारा पूरे देश में श्रम दासता की पद्धति को समाप्त कर दिया गया है, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 में ठेका श्रमिकों के रोजगार के विनियमन और प्रतिषेध को परिकल्पना की गई है। इस अधिनियम में, जैसा यह इस समय है, किसी स्थापन में ठेका श्रमिकों के रोजगार के प्रतिषेध के बाद बेरोजगार हुए ठेका श्रमिकों को नियमित कार्यों में खपाने की व्यवस्था नहीं है।

सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार द्वारा अजित लाभ का प्रतिशत

[अनुवाद]

*857. श्री मदन लाल खुराना : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार द्वारा भारत सरकार के मन्त्रालयों और विभागों को फोटो कॉपींग पेपर, टाइपिंग पेपर आदि जैसी लेखन सामग्री की सप्लाय पर कितने प्रतिशत लाभ लिया जाता है;

(ख) क्या सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार द्वारा लिए जाने वाले लाभ के प्रतिशत में काफी अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो दोनों निकायों द्वारा लिए जाने वाले लाभ के प्रतिशत में अन्तर के क्या कारण हैं; और

(घ) उपरोक्त सहकारी निकायों को उनके द्वारा सरकारी मन्त्रालयों और विभागों को बेचे जाने वाले सामान पर लाभ का प्रतिशत कम रखने के बारे में आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) से (ग) केन्द्रीय भण्डार और सुपर बाजार फोटो-कापी कागज, टाइपिंग कागज आदि जैसी लेखन सामग्री की मरदों को क्रमशः 9% और 10% के सामान्य मार्जिन पर सप्लाई करते हैं। इस अन्तर को काफी अधिक नहीं कहा जा सकता।

(घ) इन उपभोक्ता सहकारी समितियों की अपनी-अपनी मूल्य-निर्धारण सम्बन्धी नीतियां हैं जो व्यापार के मानदण्डों, स्थापना प्रभारों तथा उन वस्तुओं पर ली जाने वाली अन्य लागत के अनुसार होती हैं। तथापि, उपभोक्ता के हित को ध्यान में रखा जाता है।

पपन कला परियोजना में संशोधन

*858. श्री विद्याधर गोखले : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पपन कला परियोजना सम्बन्धी पहले से ही स्वीकृत विकास-योजना की दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पुनः समीक्षा करने और उसमें संशोधन करने के वाध्यकारी कारण क्या हैं;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी सरकार द्वारा स्वीकृत किसी योजना में संशोधन हेतु सलाहकारों को नियुक्त करने के लिए सक्षम हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार सलाहकार एजेंसी/ग्रुप की नियुक्ति को रद्द करने तथा सरकारी घन को बर्बाद करने एवं पपन कला परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने का है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री भूरासोली मारन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार व अनुमोदित की गई विकास योजनाएं विचारार्थ व अनुमोदन के लिए दिल्ली नगर कला आयोग को इसी प्रकार या यदि वे सलाह देते हैं तो उसे उनकी टिप्पणियों/सुझावों के अनुसार संशोधित करके प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

(ख) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत निर्धारित किए गए अनुसार परियोजना भूमि के भू-उपयोग में परिवर्तन के लिए आपत्तियां/सुझाव मंगाने हेतु सांबंजनिक सूचना जारी करने के दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव के लिए सरकार की सहमति थी। भू-उपयोग योजना में सुधार करने और संरचनात्मक योजनाएं तैयार करने के लिए विशेषज्ञों को शामिल करना दिल्ली विकास प्राधिकरण के सामर्थ्य के भीतर था।

(ग) कोई व्यर्थ ब्यय या विलम्ब नहीं हुआ है। वास्तव में दिल्ली नगर कला आयोग ने वैचारिक दौर में संशोधित योजना को अनुमोदित कर दिया है। कोई जांच आवश्यक नहीं समझी जाती है।

सतलुज-यमुना लिंक नहर का निर्माण

[हिन्दी]

*859. श्री कपिल देव शास्त्री : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतलुज-यमुना लिंक नहर के निर्माण कार्य में वर्ष 1988-89 की तुलना में वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी प्रगति हुई है;

(ख) पंजाब में इस परियोजना पर पूरे किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; इस वर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और कितनी धनराशि खर्च किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या इस नहर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहीत कर ली गयी है और प्रभावित किसानों को मुआवजा दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो ऐसा कब तक कर लिया जाएगा;

(ङ) क्या उपरिपुलों तथा साइफनों का निर्माण जैसे अन्य सम्बन्धित कार्य पूरे कर लिए गए हैं और यदि नहीं, तो इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है; और

(च) परियोजना से सम्बन्धित पूरे किए गए निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है और शेष कार्य के कब तक पूरे किए जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क), (ख), (ङ) और (च) एक बिबरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) 1625 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया और 31.16 करोड़ रुपए के मुआवजे का भुगतान किया गया।

बिबरण

मद	कुल मात्रा	मार्च, 1989 तक पूर्ण की गयी	की गयी अतिरिक्त प्रगति		अभ्युक्ति
			1988-89 के दौरान	1989-90 के दौरान	
1	2	3	4	5	6
1. मिट्टी कार्य (साथ क्यूसिक मी०)	440.75	401.62	14.33	10.02	97 % मिट्टी कार्य और 94% पलस्तर पूरा कर लिया गया है। शेष मिट्टी कार्य और पलस्तर संरचनाओं के आस-पास छेदों में किया जाना है। और यह उनके पूर्ण किए जाने से सम्बन्ध है।

1	2	3	4	5	6
2. पलस्तर (लाख वर्ग मी०)	53.22	43.96	4.44	1.87	—
3. बृहद कास जल निकास कार्य (सं०)	10	2	2	6	सभी पूर्ण
4. सिरसा जल सेतु (सं०)	1	—	—	—	भार परीक्षण पूरा किया गया। शेष कार्य के जनवरी, 1990 तक पूरा होने की सम्भावना है।
5. मध्यम कास जल निकास कार्य	41	15	7	14	शेष 5 पर कार्य चल रहा है जिसके दिस०, 1990 तक पूरा होने की सम्भावना है।
6. गांव सड़क पुल	58	27	11	11	शेष 9 पर कार्य चल रहा है जिसके दिस०, 1990 तक पूरा होने की संभावना है। गांव के लोगों ने अब कुछ पुलों पर डेक बढ़ाने की मांग की है।
7. रेल पुल	3	1	—	—	शेष दो पुलों पर संर- चना पूरी कर ली गई है किन्तु रेल- मार्ग को अभी जोड़ा जाना है। घामबा- सियों ने एक पुल के नीचे सुरंगपथ और दूसरे पर एक पुलिया की मांग की है। रेल-

1	2	3	4	5	6
					मार्ग को जोड़ने सहित इन अतिरिक्त कार्यों के मार्च, 1991 तक पूरा होने की संभावना है।
8. राष्ट्रीय राजमार्ग पुल	4	—	—	3	शेष एक पुल भी प्रायः पूर्ण हो गया है।
9. राज्य सड़क पुल	11	—	2	3	शेष 6 पर कार्य चल रहा है और इसके दिसम्बर, 1990 तक पूरा होने की सम्भावना है।
10. सतलुज यमुना सम्पर्क एवं नांगल हाइड्रल चैनल का अन्तः सम्पर्क	1	—	—	मिट्टी कार्य प्रारम्भ किया गया	राज्यों के मध्य अन्तर्राज्यीय मामले केवल दिसम्बर, 1989 में सुलझाए जा सकें।
11. 67 कि० मी० से 81 कि० मी० क्षतिग्रस्त पहुंच की मरम्मत	—	—	—	-बही-	वर्ष 1988 की बाढ़ों से हुई क्षति के कारण नई मद की आवश्यकता हुई। कार्य प्रगति पर है और इसके नवम्बर 1990 तक पूरा होने की संभावना है।
12. निधियां (करोड़ रु०)	429.77	309.60	55.09	50.45	पंजाब सरकार ने केवल हाल ही में 560 करोड़ रु० का संशोधित अनुमान केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया है।

दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों/मिट्टी तेल के डिपों का आवंटन

8868. श्री गोबिन्द चन्द्र मुग्डा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों, विधवाओं तथा बेरोजगार शिक्षित युवकों को कोई उचित मूल्य दुकानों तथा मिट्टी तेल के डिपो आवंटित किए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये दुकानें/डिपो दिल्ली प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करके आगे पट्टे पर दे दी जाती हैं; और

(घ) यदि हा, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) 1987 से 1989 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के यमुनापार के क्षेत्र में 23 उचित दर की दुकानें और 8 मिट्टी के तेल के डिपो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को और 2 उचित दर की दुकानें और 1 मिट्टी के तेल का डिपो बेरोजगार स्नातकों को आवंटित किए गए।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि आवंटन के हस्तांतरण की अनुमति नहीं है और प्रशासन की जानकारी में ऐसी कोई घटना नहीं आई है।

शान्ति निकेतन कालोनी में खेल के मैदान के लिए भूमि

[अनुचाच]

8869. श्री सनत कुमार मंडल :

श्री शारदाराम पोटवले :

क्या शहरी विकास मंत्री दिनांक 10 मई, 1989 के अतारहित प्रश्न संख्या 8953 के उत्तर के अनुसार में 13 सितम्बर, 1989 को सभा पटल पर रखे गए आश्वासन-विवरण के भाग (ग) के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शान्ति निकेतन कालोनी में एक गैर-सरकारी मिशन स्कूल को खेल के मैदान के लिए किया गया 3.70 एकड़ भूमि का आवंटन रद्द कर दिया गया था, किन्तु यह भूमि इसे पुनः आवंटित कर दी गई है और इस बात की उपेक्षा कर दी गई है कि रेजिडेन्ट्स वेल्फेयर एसोसिएशन ने अपने अभ्यावेदन में इस बारे में भारी रोष प्रकट किया है और इस स्कूल भवन को पहले से आवंटित 2.5 एकड़ भूमि में खेल के मैदान के लिए पर्याप्त स्थान है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा इस मामले की पुनरीक्षा की गई थी। उन्होंने निर्णय

लिया कि श्रृंखला यह विद्यालय मूलतः बालिका विद्यालय है इसलिए विद्यालय द्वारा वास्तव में इसका उपयोग न किए जाने के समय क्षेत्र के निवासी यहां सैर आदि कर सकते हैं जिससे उनको कोई असुविधा नहीं होगी। 2.5 एकड़ का भूखंड प्राथमिक विद्यालय के लिए आवंटित किया गया था, जिसे बाद में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रूप में बढ़ाने की अनुमति दी गई थी, जिसके लिए 2.5 एकड़ से अधिक जगह की जरूरत है।

बुने हुए वस्त्रों का निर्यात

8870. श्री भीकान्त बंस नरसिंहराज बाबियर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बुने हुए वस्त्र अन्य देशों में अधिक लोकप्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो बुने हुए वस्त्रों का निर्यात किस वर्ष से किया जा रहा है;

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान बुने हुए वस्त्रों के निर्यात से सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई; और

(घ) वर्ष 1990-95 के दौरान बुने हुए वस्त्रों का कितनी मात्रा में निर्यात किए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद घाबरे) : (क) जी, हां। भारत से बुने हुए वस्त्रों के निर्यात में मात्रा और मूल्य की दृष्टि से वृद्धि होती रही है।

(ख) उस सही वर्षा का पता नहीं है जब से कि भारत बुने हुए वस्त्रों का निर्यात कर रहा है। फिर भी बुने हुआ वस्त्रों का निर्यात पिछले दो दशकों से भी अधिक समय से हो रहा है।

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान बुने हुए वस्त्रों के निर्यात से प्राप्त आय निम्नलिखित रही है :—

वर्ष	मूल्य करोड़ ₹० में
1985-86	182
1986-87	279
1987-88	399
1988-89	491
1989-90	7०2

(घ) वर्ष 1990-95 के लिए बुने बुनाए बस्त्रों का अनुमानित निर्यात निम्नलिखित है :
(करोड़ ₹०)

1990-91	785
1991-92	966
1992-93	1188
1993-94	1462
1994-95	1798

जोत : अपैरल निर्यात संबंधन परिषद ।

खेलगांव में मकानों का आबंटन

8871. श्री बान सिंह जाटव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) "एशियाड 1982" के लिए खेलगांव में कुल कितने मकान बनाए गए थे;
(ख) क्या एशियाड के बाद इन मकानों को बेच दिया गया था;
(ग) यदि हां, तो किसे तथा इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी; और
(घ) प्रत्येक मकान से कितना-कितना मूल्य प्राप्त हुआ है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 853 ।

(ख) जी, हां ।

(ग) तत्कालीन सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार "एशियाड फ्लैट" प्रवासी भारतीयों को विदेशी मुद्रा पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को, सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाओं को और खुली नीलामी के माध्यम से बेचे गए हैं ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आयोडीन की कमी के कारण होने वाली अस्वस्थता से प्रभावित राज्यों को आयोडीन युक्त नमक की सप्लाई

8872. श्री माधवराव सिंधिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयोडीन की कमी के कारण होने वाली अस्वस्थता से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों को आयोडीन युक्त नमक की सप्लाई की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ससम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) जी, हाँ । वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिन्हें आयोडीकृत नमक सप्लाई किया जा रहा है, इस प्रकार हैं :—

हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, असम, और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, दादरा व नागर हवेली एवं चण्डीगढ़ ।

आयोडीकृत नमक निम्नलिखित राज्यों के महामारी वाले क्षेत्रों को भी सप्लाई किया जा रहा है :—

आंध्र प्रदेश	3 जिले
गुजरात	3 जिले
मध्य प्रदेश	26 जिले
पश्चिम बंगाल	10 जिले
महाराष्ट्र	7 जिले

(घ) देश में घेचा और आयोडीन की कमी से होने वाले अन्य विकारों की समस्या का प्रभावी रूप से नियन्त्रण करने के लिए सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसमें वर्ष 1992 तक क्रमिक रूप में खाद्य नमक के व्यापक आयोडीकरण की बात सोची गई है ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में लगे जालपोत

8873. श्री हुन्मान मोस्लाह : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में मछुआरों को दी गई मशीनीकृत गाबों और जालपोतों की संख्या कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके लिए केन्द्र सरकार ने कितना धन आबंटित किया है; और

(ख) गहरे समुद्र में लगे चार्टर्ड जालपोतों की शर्तें क्या हैं ?

खस्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) भारतीय अनन्य आर्थिक जोन में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में लगे चार्टर्ड जालपोतों के लिए मुख्य-मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं :—

1. भारतीय चार्टरिंग कम्पनी को पूर्णतः खरीद अथवा संयुक्त उपक्रम प्रबन्ध के माध्यम से निर्धारित अवधि के भीतर इतनी ही संख्या में विशेष प्रकार के जलयानों को प्राप्त करना होगा ।
2. 25% भारतीय नाविक बस को चार्टर्ड विदेशी मछली पकड़ने के जलयानों पर प्रशिक्षित करना होगा ।

3. विदेशी और भारतीय कम्पनियों के बीच मछली पकड़ने का अनुपात 80:20 के आधार पर होगा।
4. चार्टर्ड जलयानों का संचालन मेरीटाइम जोन आफ इण्डिया एक्ट, 1981 और उसके अधीन बने नियम, 1982 की शर्तों के अनुसार होगा।

तेलुगु गंगा परियोजना

8874. श्री राजमोहन रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने तेलुगु गंगा परियोजना के संशोधित प्राक्कलन केन्द्रीय सरकार को भेज दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये कब प्राप्त हुए थे; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का परियोजना को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति कब तक देने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार से जनवरी, 1986 में प्राप्त 843.27 करोड़ रुपये के संशोधित/अद्यतन प्राक्कलन का तकनीकी-आर्थिक रूप से मूल्यांकन किया गया है और परामर्शदात्री समिति ने अप्रैल, 1988 में आयोजित अपनी बैठक में इसके अन्तर्राज्यीय पहलुओं के हल होने तक इस पर विचार-विमर्श को आस्थगित कर दिया। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में आपसी विचार-विमर्श कर रही हैं।

पंजाब में बेरोजगारी

8875. बाबा सुब्बा सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षित, अर्ध-शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा पुरुष और स्त्री, शहरी और ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या कितनी है; और

(ख) पंजाब में बाहर से आने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है तथा इसके कारण पंजाब में बेरोजगारी की समस्या किस सीमा तक बढ़ी है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1988 के अन्त में पंजाब के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले शिक्षित (मैट्रिक तथा उससे ऊपर) तथा अशिक्षित (मैट्रिक से कम तथा अनपढ़) व्यक्तियों, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, की संख्या निम्न प्रकार है :—

(हजारों में)

	शिक्षित	अशिक्षित
पुरुष	224.9	251.8
महिला	73.2	26.2

(ख) प्रवासी श्रमिकों की संख्या हर मौसम में भिन्न होती है तथा सही आंकड़े देना सम्भव नहीं है। तथापि, 1983 से श्रम विभाग, पंजाब द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, उद्योग और कृषि में प्रवासी श्रमिकों की संख्या 2.8 लाख होने का अनुमान लगाया गया था। प्रवासन सामान्यतः फासों के अवसरों की उपलब्धता के कारण होता है।

बागान श्रमिक

8876. श्री प्लाई के० एम० शंभू : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बागान श्रमिकों की दैनिकीय कार्य स्थितियों, कम मजदूरी और कमचोर सेवा शर्तों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बागान श्रमिकों के कल्याण हेतु कोई कानून बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा समा पटल पर रख दी जाएगी।

रोजगार कार्यालय में पंजीकृत पुरुष/महिलाएं

[हिन्दी]

8877. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रोजगार कार्यालयों में राज्य-वार, कितने-कितने बेरोजगार पुरुष और महिलाओं के नाम पंजीकृत हैं; 1

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कितने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है; और

(ग) सरकार इन रोजगार कार्यालयों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) फरवरी, 1990 के अन्त में देश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वाले पुरुषों एवं महिलाओं की राज्यवार संख्या, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की गई नियुक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	नियुक्तियां (हजारों में)
1987]	16.6
1988	13.3
1989	8.8

(ग) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे रोजगार कार्यालयों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनका कम्प्यूटरीकरण करें तथा इस उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम सातवीं योजना के दौरान शुरू की गई है।

बिहार

28-2-1990 को रोजगार कार्यालयों के बालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले पुरुषों/महिलाओं की संख्या

(हजारों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पुरुष	महिलाएं	कुल
1	2	3	4	5
राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	2406.6	412.7	2819.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.9	1.2	5.1
3.	असम	807.6	171.6	979.2
4.	बिहार	2906.0	174.1	3080.2
5.	गोवा	56.6	24.7	81.3
6.	गुजरात	831.5	121.9	953.4
7.	हरियाणा	483.1	94.8	577.8
8.	हिमाचल प्रदेश	337.6	86.2	423.8
9.	जम्मू व कश्मीर	111.1	12.2	123.4
10.	कर्नाटक	1026.4	233.8	1260.2
11.	केरल	1598.9	1509.9	3108.8
12.	मध्य प्रदेश	1766.6	301.4	2068.0
13.	महाराष्ट्र	2571.4	421.5	2992.9
14.	मणिपुर	190.4	62.1	252.5
15.	मेघालय	15.4	8.2	23.6
16.	मिजोरम	32.2	9.9	42.1
17.	नागालैंड	20.0	6.7	26.7

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	773.1	92.6	865.7
19.	पंजाब	482.7	112.5	595.2
20.	राजस्थान	850.3	76.6	926.8
21.	सिक्किम*	—	—	—
22.	तमिलनाडु	2191.8	823.6	3015.3
23.	त्रिपुरा	101.1	48.1	149.2
24.	उत्तर प्रदेश	2956.2	220.5	3176.7
25.	पश्चिम बंगाल	3644.9	935.8	4580.6
सब शालित प्रदेश				
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	11.5	4.1	15.5
2.	दादर नागर हवेली	1.7	0.5	2.2
3.	चण्डीगढ़	123.8	30.4	154.2
4.	दिल्ली	647.1	162.2	809.3
5.	दमन एवं दीव**	—	—	—
6.	लक्षद्वीप	4.0	0.9	4.9
7.	पाण्डिचेरी	82.2	30.6	112.8
कुल :		27035.17	6191.0	33226.7

टिप्पणी—1. *कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा।

2. **आंकड़े नहीं रहे जाते।

3. यह हो सकता है कि पूर्णों के कारण आंकड़े मेल न जाएं।

पंजाब में भारतीय खाद्य निगम के गोबाम

[अनुवाद]

8878. श्री कृपाल सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का पंजाब में गोबाम बनाने का ठेका उन व्यक्तियों को देने का विचार है, जिन्होंने बैंकों से लिए गए अपने बकाया ऋणों का भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम का उन व्यक्तियों से खाली गोदाम खरीदने का विचार है जिन्होंने बैंक से लिए गए ऋण की अदायगी कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री माधू राम मिर्षा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्राइवेट पार्टियों द्वारा निर्मित गोदामों को खरीदने की फिलहाल भारतीय खाद्य नियम की कोई योजना नहीं है।

रबीज के कारण मृत्यु

8879. श्री जनार्दन पुजारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति वर्ष रबीज रोग से 25,000 लोग मर जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि देश में 18 मिलियन कुत्ते हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस रोग से होने वाली मृत्युओं की संख्या कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार का कुत्तों की संख्या नियन्त्रित करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागरिक विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) यद्यपि जलांतक की घटनाओं के बारे में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, यह अनुमान है कि हर वर्ष जलांतक रोग के कारण देश में लगभग 25000 मौतें हो जाती हैं।

(ख) कृषि मन्त्रालय द्वारा 1982 में की गई कुत्तों की गणना के अनुसार देश में एक करोड़ 80 लाख कुत्ते हैं।

(ग) सरकार ने मौतों की संख्या को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) सरकारी अस्पतालों में जलांतक रोधी टीके नि:शुल्क उपलब्ध हैं।

(2) देश में 12 उत्पादन केंद्रों में लगभग 3.5 से 4.0 करोड़ नर्वस टिबू वैक्सीने तैयार की जा रही है।

(3) टिबू कल्चर वैक्सीनों (एडमिन डिप्लॉयड सेल एवं प्योरिफाइड चिक एम्ब्रयो सेल) का व्यापक विनाश जा रहा है और वे बाजार में उपलब्ध हैं।

(4) रोग की रोकथाम के बारे में जन-अपचार कार्यक्रमों द्वारा जनसामान्य को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जा रही है।

(घ) और (ङ) कुत्सों की संख्या को निर्धारित करना स्थानीय-नगरीय निकायों के क्षेत्राधिकार में है। स्थानीय-नगरीय निकायों की गतिविधियों को और बल प्रदान करने के लिए कृषि मन्त्रालय ने देश में 30 जलांतक नियन्त्रण यूनितें स्थापित की हैं।

कर्मचारी अभिव्यक्ति मित्रि संगठन में कम्प्यूटरों का उपयोग

8880. डा० महावीरपक सिंह शोष्य : क्या अम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी अभिव्यक्ति मित्रि संगठन के अधिकारियों ने इस संगठन का काम-काज कम्प्यूटरों के माध्यम से करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसा निर्णय किए जाने के क्या कारण थे; और

(ग) इस नई प्रणाली से कर्मचारियों के हितों पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

अम और कल्याण मंत्री (श्री राज बिलास बालबाल) : (क) जी, हां।

(ख) क० प्र० नि० संगठन की अपने अधिदाताओं की सेवा प्रदान करने में और विशेषकर सदस्यों की सेवाओं की वार्षिक विवरणियों की समय पर जारी करने की सुनिश्चित करने के लिए सम्पूर्ण कार्यक्षमता में सुधार की दृष्टि से, दो क्षेत्रीय कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण शुरू किया गया है। इसे अन्य क्षेत्रों में भी क्रमिक ढंग से शुरू किया जाएगा।

(ग) इस कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से कर्मचारियों के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य गाइड योजना

8881. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सामुदायिक स्वास्थ्य गाइड योजना को जारी रखने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य कमियों को दिए जा रहे मानदेय में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर बिमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) सरकार का ग्राम स्वास्थ्य गाइड स्कीम को जारी रखने का विचार है।

(ख) और (ग) ग्राम स्वास्थ्य गाइडों के मानदेय में वृद्धि करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

शहर और ग्राम योजना संगठन के लक्ष्य

8882. श्री एम० एम० फत्तम राजू : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहर और ग्राम योजना संगठन (टी० सी० पी० ओ०) के क्या लक्ष्य हैं; और

(ख) शहर और ग्राम योजना संगठन को अब तक किस रूप में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता प्राप्त हुई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली भारन) : (क) नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन का उद्देश्य (1) शहरी और क्षेत्रीय आयोजना तथा विकास नीति, (2) अनुसंधान और (3) प्रशिक्षण से सम्बन्धित विषयों पर शहरी विकास मन्त्रालय के शीर्ष तकनीकी सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना है। इस संगठन द्वारा किए गए अन्य कार्य शहरी विकास मन्त्रालय के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा पूर्वतित योजनाओं का प्रबोधन और मूल्यांकन एवं विभिन्न राज्यों/संगठनों को परामर्शी सेवाएं तथा परियोजना सहायता प्रदान करना है।

(ख) नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन प्रत्यक्ष रूप से कोई अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं करता है और यह शहरी विकास मन्त्रालय के माध्यम से किया जाता है। शहरी विकास और शहरी नवीकरण के प्रबन्ध पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए इस संगठन ने ब्रिटिश काउंसिल के माध्यम से सहायता प्राप्त की है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) की सहायता से इसने संगणक कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं। इसके अतिरिक्त, शहरी विकास मन्त्रालय शहरी मूलभूत सेवा कार्यक्रम चलाने के लिए यूनीसेफ से और नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन में संगणक कार्यक्रमों आदि में पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए इंटरनेशनल इन्स्टीच्यूट फार एरोस्पेस सर्वे एण्ड अर्थ साइसेस, नीदरलैण्ड से सहयोग करता है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से सम्बन्धित नीतियां

8883. श्री प्रकाश श्री० पाटिल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से सम्बन्धित विभिन्न नीतियों को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से सम्बन्धित विभिन्न नीतियां कब तक सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी ?

दत्त मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) गहरे समुद्र से मछलियां पकड़ने के कार्य के विकास में मदद करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न नीतियां बनायी व कार्यान्वित की जाती हैं।

नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

8884. डा० बेंकटेश काबडे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी घोषणा कब की जाएगी; और

(ग) इस नई नीति की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

बहुराष्ट्रिक कम्पनियों द्वारा औषधों का आयात

8885. श्री रामदास सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औषध आयात की कम्पनियों के नाम क्या-क्या हैं और उनमें बहुराष्ट्रिक औषध आयातक कम्पनियों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आयात की गई औषधों अथवा तत्सम्बन्धी कच्चे माल का ब्यौरा क्या है और उन्हें उपभोग्यताओं में किस प्रकार वितरित किया गया और औषधों को सप्साई करने से पूर्व उनके परीक्षण की वर्तमान पद्धति क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) देश में कच्ची सामग्री और बल्क औषधों बाणिज्य मन्त्रालय की आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत ओपन जनरल लाइसेंस के परिशिष्ट के अधीन आयात की जाती हैं। देश में आयात किए जाने वाले अनुमत्य निमित्त योगों के नाम उसी परिशिष्ट-4 की सूची-III में दिए गए हैं। प्रमुख बल्क औषधों, जिनका आयात एक करोड़ रुपए से अधिक का है उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ऐसी औषध कम्पनियां जिनकी विदेशी इक्विटी 40 प्रतिशत से अधिक है और जो औषधों का आयात कर रही हैं उनके नाम नीचे दिए गए हैं :—

1. मै० वेयर इण्डिया लि०, बम्बई।
2. मै० इण्डियन एक्मप्लोसिक लि०, मद्रास।
3. मै० पाइजर लि०, बम्बई।
4. मै० सैण्डोज, (इण्डिया) लि०, बम्बई।
5. मै० वेथ लैब्स, बम्बई।
6. रोश प्रोडक्ट्स लि०, बम्बई।

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में आयात किए गए योगों सहित कुल बल्क औषधों और इष्टर मीडिएट्स नीचे दिए गए हैं :—

1986-87	287.59 करोड़ रुपए
1987-88	349.44 करोड़ रुपए
1988-89	446.91 करोड़ रुपए

आयातकों द्वारा औषधों का वितरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा मॉनिटर नहीं किया जाता है। नमूने उठाए जाते हैं और खेप जारी करने से पहले आयात के समय औषधों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए उनकी जांच की जानी होती है।

बिबरण

एक करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की आयातित औषधों के नाम

क्रम सं० औषध का नाम

1	2
1.	एल्कालोडिम ऑफ अर्गाट
2.	एम्पिमिलिन सोडियम।
3.	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट।
4.	बेटामेथासोन और इसके डेरिवेटिक्स।
5.	कार्बोमेजेपाइन।
6.	सेफोटाक्साइम सोडियम।
7.	सेफालेक्मिन।
8.	क्लोराक्फेनकोल पाउडर।
9.	क्लोरोक्वीन साल्टस (बल्क)।
10.	क्लोक्सामिल्लिन सोडियम।
11.	सिमेटिडाइन।
12.	मेफाजोलाइन सोडियम।
13.	डेक्वामेथासोन और इसके लवण।
14.	डेक्व-क्लोरोफेनिरेमाइन मेलिएट।
15.	डाईपाइरिडेमोल।
16.	ड्रग फॉर वेट यूज।
17.	एपिडाइन और इसके लवण।
18.	फ्यूरेजोलिडोन।
19.	प्रिसियोफ्लूवीन।
20.	इबुप्रोफेन।
21.	आयोडीन।

1 2

22. एल-बेस (एमिनोडियोल) ।
23. मिथाइल डोपा ।
24. नोरजेस्टिरोल ।
25. नेप्रोक्सेन ।
26. नेलिडिबिसक एसिड ।
27. अन्य पोलियो वैक्सीन ।
28. वेंटोचिनेट सोडियम और कैल्शियम ।
29. वेंसिलीन जी पोटेशियम ।
30. वेंटाजोसाइन बेस/एच सी एल ।
31. प्रेडनिसोलोन ।
32. स्यूडोएफेड्राइन एच सी एल/सल्फेट ।
33. पाइरेजिनामाइड ।
34. पायरीथियोक्साइड एच सी एल (एनसेफेडोल) ।
35. रेनिटिडाइन एच सी एल ।
36. रिफेम्पिसीन ।
37. स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट ।
38. टेट्रासाइक्लिन एच सी एल ।
39. थियोफिलिन ।
40. टोलनेपेटेट ।
41. ट्राईपोलिडाइन एच सी एल ।
42. वेरपेमिल एच सी एल ।
43. विटामिन ए ।
44. विटामिन बी 6 ।

टिप्पण—तीन वर्षों में से कम से कम किसी एक वर्ष में एक करोड़ से अधिक मूल्य की प्रत्येक औषध का आयात किया गया था ।

बिहार के शाहाबाद जिले में हरिजन बहुत जनसंख्या वाले गाँव

8886. श्री तेज नारायण सिंह : क्या अब नजी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के शाहाबाद जिले में कुल कितने गांव हैं; और

(ख) कितने गांव हरिजन बहुल हैं ?

धन और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) और (ख) सूचना बिहार राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

देश में आधुनिक चिकित्सा प्रणाली

8888. श्री गुमान मल लोढा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में भारतीय चिकित्सा प्रणाली, होम्योपैथी तथा आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के अस्पताल खोलने के लिए अनुदान स्वीकृत करती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के अस्पताल खोलने के लिए कितना अनुदान स्वीकृत किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां। विशेष स्वास्थ्य योजना के अधीन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सभी चिकित्सा पद्धतियों के नए अस्पताल स्थापित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के अस्पताल खोलने के लिए कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं की गई है ।

संगीत भारती द्वारा दिया गया स्कूल भवन का नक्शा

8889. श्री जगपाल सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन मिला है कि संगीत भारती द्वारा भेजा गया स्कूल भवन का शहरी नक्शा कला आयोग ने नामंजूर कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्काल ब्यौरा क्या है और इसे नामंजूर किए जाने के क्या कारण थे; और

(ग) सरकार द्वारा अभ्यावेदन के बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

शहरी विकास मंत्री (श्री सुरासोली मारन) : (क) से (ग) मैसर्स संगीत भारती विद्यालय ने 23 दिसम्बर, 1989 को दिल्ली नगर कला आयोग को एक अभ्यावेदन दिया जिसमें उन्होंने भवन के धूलतल तथा प्रथम तल के सम्बन्ध में अनुमोदन के लिए उनके मामले पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया है। दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा यह अभ्यावेदन 24-1-90 को नई दिल्ली नगरपालिका को भेजा गया। नई दिल्ली नगरपालिका के विद्यालय के प्राधिकारियों से दिल्ली नगर कला आयोग की टिप्पणियों का अनुपालन करने के लिए कहा जोकि विद्यालय के प्राधिकारियों ने अभी तक नहीं किया है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लेटों के लिए प्रतीक्षा सूची

8890. श्री यशवन्तराव पाटिल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत प्लेटों के आबंटन हेतु कितने व्यक्ति योजना-वार और श्रेणी-वार प्रतीक्षारत हैं; और

(ख) सभी प्रतीक्षारत व्यक्तियों को कब तक आबंटन कर दिए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री सुरासोली मारन) : (क) निम्नलिखित विवरण के अनुसार 98,508 पंजीकृत व्यक्ति प्लेटों के आबंटन की प्रतीक्षा में हैं :

क्रम सं०	योजना का नाम	श्रेणी	शेष पंजीकृत व्यक्ति
1.	नवीन पद्धति योजना, '9	मध्यम आय वर्ग	24,429
		निम्न आय वर्ग	32,735
		जनता	16,193
2.	स्ववित्त पोषित योजना	श्रेणी-II और III	25,151
जोड़ :			98,408

इसके अलावा अम्बेडकर आवास योजना, 1989 के अन्तर्गत 20,000 व्यक्तियों को पंजीकृत किया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत लाटरी के ड्रा पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अस्थायी तौर पर रोक लगाई गयी है।

(ख) भूमि तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्लेट आबंटित किए जाते हैं। आगामी चार वर्षों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 84,100 प्लेटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं :

1990-91	12,600
1991-92	19,000
1992-93	26,000
1993-94	26,500
<hr/>	
	84,100

नई दिल्ली की मार्किटों के बुकानदारों को मालिकाना अधिकार

8891. श्री रीत लाल प्रसाद बर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले वर्ष मेहरबन्द खन्ना मार्किट, सोधी कालोनी और आई० एन० ए० मार्किट, नई दिल्ली के बुकानों के आर्बिटियों को मालिकाना अधिकार देने का निर्णय लिया था; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का उपरोक्त निर्णय पर पुनर्बिचार करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब ?

शहरी विकास मंत्री (श्री सुरासोली मारन) : (क) जी, हां। अन्य मार्किटों के साथ-साथ मेहरबन्द खन्ना मार्किट, सोधी कालोनी तथा आई० एन० ए० मार्किट के प्राधिकृत आर्बिटियों को पट्टाधारण आधार पर मालिकाना अधिकार देने का अक्टूबर, 1989 में एक निर्णय लिया गया था।

(ख) इस निर्णय के विभिन्न पहलू कार्यान्वयन हेतु जांचाधीन हैं।

भू-जल सम्बन्धी अध्ययन

8892. श्री एम० जी० रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 में सूखा प्रवण क्षेत्रों में भू-जल के बारे में कोई अध्ययन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1990-91 की व्यापक भूजल संसाधन विकास योजना में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले को शामिल किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान कुछ सूखा प्रवण क्षेत्रों में केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा भूजल अध्ययन किए गए।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान, बोर्ड ने, महाराष्ट्र के सूखा प्रवण क्षेत्रों के भागों में क्रमबद्ध जल भू वैज्ञानिक अध्ययन और उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान के सूखा प्रवण क्षेत्रों के भागों में पुनः भूल्यांकन जल भूवैज्ञानिक अध्ययन किए।

(ग) भूजल विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए गहन जल भूवैज्ञानिक अध्ययनों हेतु बोर्ड के वर्ष 90-91 के कार्यक्रम में चित्तूर जिले को सम्मिलित नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तेन्दु पत्ता-रोपण में कार्यरत मजदूर

8893. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा और मध्य प्रदेश में तेन्दु पत्ता उगाने के काम में कितने मजदूर लगे हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन मजदूरों के कल्याण हेतु कोई योजना शुरू की है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन मजदूरों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उन अस्पतालों के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

अब एवं कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) और (घ) बागान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इन कर्मचारों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल स्थापित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में भूमि के अर्जन पर बेय मुआवजे में वृद्धि

[हिन्दी]

8894. श्री कालका दास : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन की नीति क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में दिल्ली में किसानों को प्रति एकड़ कितना मुआवजा दिया जा रहा है;

(ग) हाल ही में मुआवजे की राशि में कितनी वृद्धि की गई है और पहले कितनी घनराशि दी जाती थी;

(घ) क्या इन किसानों को मुआवजे की राशि के अलावा कोई और सुविधा प्रदान की जाती है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी श्लोका क्या है; और

(ङ) अधिवृहृत भूमि के बदले में भूखण्डों के आबंटन से सम्बन्धित कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं और ये भूखण्ड कब प्रदान किए जाएंगे ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरारिसौली चारन) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा मुख्यतः दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए भूमि अधिवृहृत की जाती है ।

(ख) और (ग) समय-समय पर यथासंशोधित भूमि अधिवृहृत अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत निर्धारित सिद्धान्तों और पद्धतियों के अनुसार मुआवजे की मात्रा भूमि अधिवृहृत समाहर्ता द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर निर्धारित की जाती है। मुआवजे की वृद्धि के लिए अपील जिला जज के पास की जाती है। दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में (27-4-90) कृषि भूमि के लिए निम्नलिखित न्यूनतम कीमतें निर्धारित की हैं :—

(1) अन्न बन्धों के मध्य नदी तट पर स्थित भूमि के लिए 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ ।

(2) सभी अन्य कृषि भूमि के लिए 4.65 लाख रुपए प्रति एकड़ ।

1990 में जहाँ कहीं अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गई है, उन प्रयत्नों में मुआवजे के भुगतान के लिए न्यूनतम कीमतों को विचारार्थ लिया जाएगा। पहले जारी की गई अधिसूचनाओं के लिए 1990 की कीमतों पर प्रति बर्ष 15% की कटौती करते हुए न्यूनतम धुस्व

निकाला जाएगा। ये उन मामलों पर लागू नहीं होंगे जहाँ अबांड की घोषणा पहले ही कर दी गई है।

(घ) उन मामलों में जहाँ नियमों के अनुसार एक एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहित की जाती है। भू-स्वामी उपलब्धता की शर्त पर पूर्व-निर्धारित दरों पर विकसित रिहायशी प्लाटों और निर्मित दुकानों/स्टालों के आबंटन के लिए भी पात्र है।

(ङ) दिल्ली प्रशासन के पास लम्बित आवेदनों की संख्या 6906 है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास लम्बित मामलों की संख्या 3512 है जिनमें से 1695 मामलों में आबंटन की पेशकश जारी कर दी गई है। शेष मामलों का निपटान प्लाटों की उपलब्धता पर निर्भर है।

सम्पदा निदेशालय का कार्यकरण

[अनुचाप]

8895. श्री राम सागर (सदपुर) : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा निदेशालय के कार्यकरण का मूल्यांकन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिनांक 1 जनवरी, 1990 से अब तक टाइप-बार, कितने तदर्थ आबंटन किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली भारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय/अस्पताल

8896. श्री वासुदेवपुन्नम्मा सिंगम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आन्ध्र प्रदेश में कितने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय/अस्पताल कार्य कर रहे हैं;

(ख) आन्ध्र प्रदेश के किन-किन जिलों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय/अस्पताल नहीं हैं;

(ग) इन क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 1990-91 में आन्ध्र प्रदेश में और बिलेय कर ऐसे स्थानों पर जहाँ कोई केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय विद्यमान नहीं है, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधिक संख्या में औषधालय/चिकित्सालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(क) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा मागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) आन्ध्र प्रदेश में कोई भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अस्पताल कार्य नहीं कर रहा है। आन्ध्र प्रदेश में निम्नलिखित के० स० स्वा० यो० औषधालय/यूनिट कार्य कर रहे हैं :

एलोपैथिक औषधालय	13
आयुर्वेदिक औषधालय/यूनिट	2
होम्योपैथिक औषधालय/यूनिट	2
यूनानी औषधालय/यूनिट	2

(ख) आन्ध्र प्रदेश में के० स० स्वा० यो० केवल हैदराबाद में कार्य कर रही है।

(ग) के० स० स्वा० यो० के अन्तर्गत कवर न किए गए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमों के अन्तर्गत कवर किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। ब्योरा इस प्रकार है :

1. आर० सी० आई० केन्द्र, विज्ञान कांचा में एक उप-औषधालय खोलना।
2. अत्यधिक कार्यभार वाले दो औषधालयों—सिकन्दराबाद और हुंमायु नगर का विभाजन।
3. कंचन बाग में एक एलोपैथिक औषधालय खोलना।

राशन कार्ड के लिए झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र का सर्वेक्षण

8897. श्री भोगेन्द्र झा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वेक्षण दल ने दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों का वहां रहने वाले परिवारों की सूची तैयार करने के उद्देश्य से कोई सर्वेक्षण किया था, जिसके आधार पर उन्हें राशन कार्ड जारी किए जाने थे;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सर्वेक्षण करते समय अनियमितताएं बरती गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक प्राप्त ऐसी शिकायतों का ब्योरा क्या है; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री माधू राम मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि उन्हें कुछ झुग्गी समूहों/व्यक्तिगत झुग्गियों के शामिल नहीं किए जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त किए हुए थे। सत्यापन करने पर पाया गया कि कुछ झुग्गी वालों, जिन्होंने शामिल न किए जाने का दावा किया था, ने 31-3-90 को विधेयक तारीख (कट ऑफ डेट) के बाद नई झुग्गियां बनाई थीं। कुछ मामलों में सर्वेक्षण दल द्वारा लगाई गई नम्बर की

प्लेटों को उनके मूल स्थान से बदल दिया गया था। कुछ अन्य मामलों में कुछ व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जा सका, क्योंकि वे व्यक्ति सर्वेक्षण के दौरान वहां वास्तविक रूप में उपस्थित नहीं थे।

वास्तविक निवासियों, जिन्हें सर्वेक्षण के दौरान विभिन्न कारणों से शामिल नहीं किया जा सका था, को शामिल करने के लिए प्रशासन ने 2-4-90 से 16-4-90 तक की अवधि के दौरान ऐसे व्यक्तियों से आवेदन पत्र मांगे थे। उन्हें उचित सत्यापन के बाद दिल्ली प्रशासन के खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग के सम्बन्धित मंडल कार्यालयों द्वारा नये राशन कार्ड दे दिए जायेंगे।

कुछ शिकायतें अनियमितताओं के सम्बन्ध में भी मिली हैं। प्रथमदृष्टया अनियमितताओं से सम्बन्धित शिकायतों की जांच बरिष्ठ अधिकारियों/उप प्रभागीय मजिस्ट्रेटों द्वारा कराई गई थी। तथापि, इन आरोपों की सामान्यतया पुष्टि नहीं हो पायी है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया इन्जीनियरी कार्य

8898. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सारे देश में इस समय कृषि विभाग का कितना इन्जीनियरी कार्य किया गया है;

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियन्ता (खाद्य) का पद बनाए रखने का क्या औचित्य है;

(ग) मुख्य अभियन्ता (अर्थात् जोन), अधिशासी अभियन्ता (अर्थात् सर्किल) और कार्यपालक अभियन्ता (अर्थात् डिबीजन) के पदों के औचित्य के लिए कितना कार्यभार अपेक्षित है; और

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में एक यूनिट खोलने के क्या मानदण्ड हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इस समय कृषि विभाग और इसके सम्बद्ध संगठनों का 4184.96 लाख रुपये के मूल्य का इन्जीनियरी कार्य किया गया है।

(ख) खाद्य निर्माण-कार्यों के अतिरिक्त, यह अंचल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि में अन्य मंत्रालयों/विभागों के लिए कार्य कर रहा है और दिल्ली में अनुरक्षण कार्य भी कर रहा है। 1989-90 के दौरान इस अंचल का कुल कार्यभार लगभग 50 करोड़ रुपये था।

(ग) और (घ) मंडल के लिए मानदण्ड इस प्रकार हैं :

(आंकड़े लाखों में)

	सिविल	विद्युत
(i) केन्द्रीय निर्माण कार्य	315	194
(ii) प्रकीर्ण निर्माण कार्य	241	161
(iii) अनुरक्षण और लघु कार्य	119	64

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मंडल आधारगत इकाई है। सामान्यतः एक परिमंडल के अधीन 4 मंडल होते हैं और एक अंचल के नियन्त्रण में विद्युत और सिविल दोनों, के 4 परिमंडल होते हैं।

बिस्कोस स्टेपल फाइबर की मांग

8899. श्री माधवाता सिंह : क्या बस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कंपनियों का 'बिस्कोस स्टेपल फाइबर' की आपूर्ति और मांग पर पूरा एकाधिकार है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग में एकाधिकार को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

बस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) बिस्कोस स्टेपल फाइबर के उत्पादन के लिए लाइसेंसशुदा एककों के ब्यौरे निम्नोक्त अनुसार हैं :

क्रम संख्या	एकक का नाम	लाइसेंसशुदा क्षमता (मी० टन प्रति वर्ष)
रेगुलर बिस्कोस स्टेपल फाइबर		
1.	मैसर्स ग्रामिन्स इंडस्ट्रीज लि०	22,000
2.	मै० साउथ इण्डिया बिस्कोस लि०	11,000
हाईवेट मोड्यूस पोलीनोसिक फाइबर		
3.	मै० सैंचुरी रेयन	2,250
4.	मै० ग्रामिन्स इंडस्ट्रीज लि०	24,000
5.	मै० तुंगभद्रा फाइबरस लि०	10,000
6.	मै० भारत फाइबरस लि०	26,000
7.	मै० मोदी फाइबरस लि०	30,000

(ख) सरकार ने बिस्कोस स्टेपल फाइबर की नई क्षमताओं का सृजन करने के लिए समय-समय पर आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए हैं ताकि यह प्रतियोगी कीमतों पर अधिक मुक्त रूप से उपलब्ध हो सके।

शुष्की निवासियों से छनराशि एंठना

[शुष्की]

8900. श्री बालेश्वर यादव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में झुग्गियों पर नम्बर डालने के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारी झुग्गी-निवासियों से अवैध रूप से घन ऍठ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य और नागरिक वृत्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि प्रशासन द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार झुग्गियों की पहचान करने और परिवारों के मुखियाओं को पहचान-पत्र जारी करने, जिसके आधार पर राशन कार्ड दिए जाते हैं, का कार्य 5-2-1990 से 31-3-1990 तक किया गया था। सर्वेक्षण अधिकारियों के विरुद्ध अनियमितताओं की कुछ शिकायतें और उनके विरुद्ध कुछ आरोप प्राप्त हुए हैं। जो शिकायतें प्रत्यक्षतः अनियमितताओं से सम्बद्ध थीं, उनकी जांच वरिष्ठ अधिकारियों/उप प्रभागीय मेजिस्ट्रेटों द्वारा कार्रवाई की गई है। झुग्गी-झोंपड़ीवासियों से अवैध रूप से पैसा ऍठने की किसी शिकायत की पुष्टि नहीं हुई है।

कपड़ा उद्योग मजदूर संघ अकोला, महाराष्ट्र की मांगें

[अंगुष्ठाक्ष]

8901. श्री भाउसाहेब पुंडलिक कुंडकर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सावतराम मिल्स, अकोला और मोहातो मिल्स, अकोला में कार्यरत मजदूरों की मांगों से सम्बन्धित एक जापन कपड़ा उद्योग मजदूर संघ, अकोला (महाराष्ट्र) से प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या अकोला स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम की विभिन्न मिल्सों के लिए निर्धारित नियमों और विनियमों में कोई भेदभाव है; और

(घ) यदि हां, तो निर्धारित नियमों और विनियमों में विद्यमान भेदभाव को समाप्त करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री और स्वास्थ्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) कपड़ा उद्योग मजदूर संघ, अकोला से अप्रैल, 1990 में एक जापन प्राप्त हुआ था जोकि सावतराम रामप्रसाद मिल्स और आर० एस० आर० जी० मोहाता मिल्स, अकोला में कार्य कर रहे मजदूरों की मांगों के बारे में था। इस मामले पर राष्ट्रीय वस्त्र निगम के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

(ग) अकोला में एन० टी० सी० मिल्सों के बीच नियमों और विनियमों में कोई भेदभाव नहीं है। मिल्सों के कर्मचारी क्षेत्रीय-सह-उद्योग सम्बन्धी सिद्धांत/निर्णयों/करारों आदि द्वारा कवर होते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी का कारखाना बाह्य मूल्य

8902. श्री बाला साहिब बिसे पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी का कारखाना बाह्य मूल्य क्या है; और

(ख) गन्ना उत्पादकों को गन्ना का कितना बढ़ा हुआ मूल्य दिया जाएगा तथा 28 फरवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार इस समय गन्ने का कितना मूल्य दिया जाता है और यह मूल्य गत मौसम की इसी अवधि के मूल्य से कितना अधिक अथवा कम है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) न्यूनतम सांविधिक मूल्य और औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा दी गई लागत सूची के आधार पर चालू मौसम के लिए चीनी फंडिट्रियों को देय चीनी का कारखाना बाह्य मूल्य, विभिन्न अधिसूचित चीनी क्षेत्रों के लिए लगभग 459.69 रुपये से 643.46 रुपए है ।

(ख) 1987-88 और 1988-89 मौसमों के दौरान गन्ना मूल्य भुगतान से संबंधित तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपये)

मौसम	को स्थिति	कुल देय मूल्य	भुगतान किया गया मूल्य	बकाया	बकाया प्रतिशत
1988-89	28-2-89	1471.00	1273.93	197.07	13.4
1987-88	28-2-88	1346.98	1158.05	188.93	14.0

लाल डोरा क्षेत्र सम्बन्धी आदेश रद्द करना

[हिन्दी]

8903. श्री तारोफ सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब तक किसानों की आवश्यकता के अनुसार दिल्ली के गांवों में छद्म डोरा क्षेत्र बढ़ाया जाता रहा है;

(ख) क्या सरकार ने एक प्रशासनिक आदेश जारी करके लाल डोरा क्षेत्र को 500 मीटर तक सीमित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली प्रशासन को यह निदेश जारी करने का है कि किसानों को लाल डोरा क्षेत्र के अन्तर्गत उनकी आवश्यकता के अनुसार भूमि उपलब्ध कराई जाए और उपर्युक्त आदेश रद्द किए जाए ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) ऊंची कीमतों के कारण भूमि की सट्टेबाजी को रोकने के लिए और कृषि भूमि का अन्य उपयोगों के लिए परिवर्तन के दबाव को करने के लिए ।

(घ) इस मामले में विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है । इस मामले की जांच करने और चकबन्दी के दौरान विस्तार किए गए आबादी क्षेत्र (विस्तृत लाल डोरा) में मुहैया किए जाने वाले प्लाट के आकार की सिफारिश करने के लिए आवश्यक सिफारिशें देने हेतु दिल्ली प्रशासन ने पहले ही एक समिति का गठन कर लिया है ।

बिहार में सिंचित भूमि

8904. श्री ईश्वर चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान बिहार में कुल कितने हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की गई;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजनार्थ निधन वर्गों के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो इससे कितने किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) अद्यतन भूमि प्रयोग सांख्यिकी 1986-87 (अनन्तिम) के अनुसार बिहार में सकल सिंचित भूमि 3831 हजार हेक्टेयर है ।

(ख) और (ग) गत दो वर्षों के दौरान, विशेष खाद्यान्न उत्पादन तथा कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत बिहार को सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2977.71 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है । इसके अलावा सुवर्णरेखा परियोजना तथा बिहार नलकूपों के लिए 52.70 मिलियन अमेरिकी डालर की विदेशी सहायता प्रदान की गई है इन परियोजनाओं द्वारा सृजित सिंचाई परियोजनाओं से कमजोर वर्गों के किसानों को भी लाभ होगा । सिंचाई परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या के बारे में सूचना केन्द्र में नहीं रखी जाती है ।

पानी की भारी कमी

[अनुयाय]

8905. श्री रामेश्वर प्रसाद : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में वर्ष 1990 में पानी की भारी कमी होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) इस अवस्था में कोई ऐसा प्रक्षेपण नहीं किया जा सकता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नव-निर्वाचित सांसदों के अस्थायी आवास पर हुआ खर्च

8906. श्री ए० के० राय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नव-निर्वाचित संसद सदस्यों के लिए विभिन्न होटलों और किराए के अपार्टमेंटों में लिए गए आवासों पर 31 मार्च, 1990 तक खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) भूतपूर्व सांसदों से अनधिकृत कब्जा बनाए रखने के लिए दण्डरूप किराए के रूप में उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि वसूल की गई;

(ग) क्या सरकार का आवास खाली कराने सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने का विचार है; तौर

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) विभिन्न राज्यों के अतिथिगृहों (गेस्ट हाउसों) तथा होस्टलों से अभी भी बिल प्राप्त हो रहे हैं।

(ख) आठवीं लोक सभा के भूतपूर्व संसद सदस्यों से अनधिकृत दखल की अवधि के लिए नियमों के अन्तर्गत यथा निर्धारित दण्डनीय किराया अभी भी वसूल किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग "ग" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विशाखापत्तनम में परिष्कृत रेल सेवा

8907. श्री रामकृष्ण कौताला : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम में परिष्कृत रेल सेवा प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या होगी ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नारियल जटा उद्योग को नगर प्रतिपूर्ति सहायता

8908. प्रो० के० बी० घामस :

श्री ए० विजय राघवन :

क्या बस्म मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार और नारियल जटा बोर्ड ने नारियल जटा उद्योग की नगर प्रतिपूर्ति सहायता बढ़ाए जाने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) कयर उत्पादों और लेटेक्स के अस्तर वाले कयर के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता को जारी रखने के लिए कयर बोर्ड से अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) नकद मुआवजा सहायता केवल 31 मार्च, 1990 तक ही उपलब्ध थी। यह निर्णय लिया गया है कि लागत आंकड़ों के प्राप्त होने तथा उनके विश्लेषण होने तक नकद मुआवजा सहायता को तदर्थ आधार पर 31 मई, 1990 तक जारी रखा जाए।

बिहार में चावल मिलें

[हिम्बो]

8909. श्री राजमंगल मिश्र : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में एक चावल मिल स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय का बिहार में चावल मिल लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

घागा डिपुओं की स्थापना

[अनुषाच]

8910. श्री अनादि चरण दास : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कच्चा माल गारंटी योजना के अधीन कमी वाले क्षेत्रों में घागा डिपुओं की स्थापना में तथा विणन कम्प्लैक्स स्थापित करने में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को अब तक कितनी सफलता मिली है; और

(ख) घागा डिपुओं की स्थापना के सम्बन्ध में भावी कार्यक्रम का व्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एन० एच० डी० सी०) के तत्वावधान में मिल मॉड कीमतों पर हथकरघा क्षेत्र को हूक यानों की सप्लाई करने के लिए सितम्बर, 1989 में यान डिपो योजना लागू की गई थी। एन० एच० डी० सी० ने देश के विभिन्न भागों में स्थापित 20 डिपुओं के जरिए इस योजना के अन्तर्गत सितम्बर

1989-मार्च 1990 के दौरान यार्न की 52083 गांठों की पहले ही सप्लाय कर दी है। भुबनेश्वर (उड़ीसा) में स्थापित डिपो ने इस अवधि के दौरान यार्न की 2906 गांठों की सप्लाय की है। इस समय एन० एच० डी० सी० द्वारा उड़ीसा में बिपन्न परिसर स्थापित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) यार्न डिपो योजना चलते रहने की सम्भावना है।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में बहुद्वेषीय बांध के निर्माण से पैदा हुई समस्याएं

8911. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कोरापुट जिले में बहुत उद्देशीय बांधों के निर्माण के कारण कुल कितने गांव पानी से घिर गए हैं तथा मुख्य भूमि से अलग बलग हो गए हैं;

(ख) अभी तक कुल कितने परिवार विस्थापित हुए हैं और उनका पुनर्वास कर दिया गया है;

(ग) क्या विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए कोई नीति है; और

(घ) यदि हां, तो इन नीतियों को किस हद तक लागू किया गया है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) जबकि ऊपरी कोलाब परियोजना की जलमग्नता द्वारा प्रभावित सभी 52 (28 पूर्णतः और 24 आंशिक रूप से) गांव कोरापुट जिले में आते हैं, ऊपरी इन्द्रावती परियोजना की जलमग्नता द्वारा प्रभावित 95 (65 पूर्णतः और 30 आंशिक रूप से) गांवों में से केवल 44 (31 पूर्णतः और 13 आंशिक रूप से) कोरापुट जिले में आते हैं। शेष प्रभावित गांव कालाहांडी जिले में हैं।

(ख) इन परियोजनाओं से प्रभावित कोरापुट और कालाहांडी जिलों के 6985 परिवारों में से 3781 परिवारों को मार्च, 1990 तक पुनर्वासित कर दिया गया है।

(ग) जी, हां, राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास नीति तैयार कर ली गई है।

(घ) जिन परिवारों ने भूमि पर आधारित पुनर्वास का विकल्प दिया है, उन्हें तदनुसार पुनर्वासित किया गया है, जिन्होंने स्वयं पुनर्वास व्यवस्था करने का विकल्प दिया है उन्हें नीति के अनुसार नकद मुआवजा दे दिया गया है।

आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

8912. श्री पी० नरसा रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे कृषकों तथा किसानों की सहायता करने हेतु आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन का कोई प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे आंध्र प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों को लाभ प्राप्त होगा ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) से (ग) सिंचाई एवं

बहुउद्देशीय परियोजनाएं कमान क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं और उनसे प्राप्त लाभ उस क्षेत्र में बड़े एवं छोटे किसानों को उपलब्ध हैं। आंध्र प्रदेश में मार्च, 1990 तक सृजित सिंचाई सुविधाओं का पूर्वानुमान 6273.04 हेक्टेयर का लगाया गया है।

यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसिस द्वारा दी गयी उपाधियों को मान्यता देना

९9।3 श्री० के० एस० राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसिस के छात्रों को दी गयी उपाधियों को मान्यता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपयुक्त कालेज के ऐसे छात्रों को दी गयी उपाधियों को भारतीय चिकित्सा परिषद अथवा उनके मन्त्रालय द्वारा मान्यता दे दी गई है, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर मेडिकल कालेज और अस्पताल में "हाउस जाब" किया था;

(घ) यदि हां, तो इन उपाधियों को कब से मान्यता दी गयी है;

(ङ) क्या चिकित्सा परिषद/मन्त्रालय ने इस सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध लगाया है अथवा सीमा निर्धारित की है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की पहली अनुसूची में प्रकाशित विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान कालेज के छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई एम० बी० बी० एस० और अन्य स्नातकोत्तर चिकित्सीय उपाधियां उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताएं हैं। गुरु तेग बहादुर अस्पताल जो विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान कालेज का एक सम्बद्ध शिक्षण अस्पताल है, का हाउस जाब भी मान्यता प्राप्त है।

(ङ) और (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

कमजोर वर्गों के लिए आवास योजनाएं

89।4. श्री परसराम भारद्वाज : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कमजोर वर्गों के लिए आवास योजनाओं हेतु विदेशों से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई; और

(ख) इस सम्बन्ध में राज्यवार कौन-कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं और कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली भारन) : (क) और (ख) निम्न भाग वर्गों तथा आर्थिक

दृष्टि से कमबख्त वर्गों के लिए आवास योजनाओं हेतु विदेशों से प्राप्त/वचनबद्ध आर्थिक सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

आवास विकास वित्त निगम (एच० डी० एफ० सी०)

1. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम वाशिंगटन	25 लाख रु०	यह राशि सेयर पूंजी के प्रति अंशदान है।
2. आर्थिक विकास के लिए आगा पां निधि	25 लाख रु०	
3. अमेरिकी सहायता	35 मिलियन अमेरिकी डालर	पूर्व रूप से प्राप्त अमेरिकी डालर
4. के० एफ० डब्लू (पश्चिमी जर्मनी)	25 मिलियन डी० एम०	संवितरण अभी आरम्भ हुआ

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जुटाए गए संसाधनों से विशेष रूप से सम्बन्धित सहायता के राज्य-वार आंकड़े निधि प्राप्त करने वाले संगठन द्वारा नहीं रखे जाते हैं क्योंकि इन संसाधनों को देश में ही जुटाए गए संसाधनों के साथ मिलाया जाता है।

आवास विकास वित्त निगम के अनुसार लाभ भोगी मुख्य रूप से निम्न तथा मध्यम आय वर्ग हैं। तथापि, ऋण की के० एफ० डब्लू० लाइन के अन्तर्गत साभान्वित होने वाले अधिकांशतः वे परिवार होते जिनकी आय 700 रुपए प्रतिमाह से कम है।

गुजरात ग्रामीण आवास वित्त निगम लिमिटेड

1. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंगटन	10 लाख रु०	यह राशि सेयर पूंजी के प्रति अंशदान है।
2. आर्थिक विकासार्थ आगा पां निधि	10 लाख रुपए	—वही—

आवास तथा नगर विकास निगम (डुबको)

के० एफ० डब्लू (पश्चिमी जर्मनी)	30 मिलियन डी० एम०	करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं। संवितरण अभी आरम्भ नहीं हुआ।
--------------------------------	-------------------	--

महिला खेतिहर श्रमिक

8915. कुभारो उन्मत्त भारती : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतिहर श्रमिकों में कितने प्रतिशत महिलाएँ हैं;

(ख) महिला खेतिहर श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का कौन से कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में किए जाने वाले उपायों को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त संख्या में महिला अधिकारियों की नियुक्ति करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पातवान) : (क) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में असम को छोड़कर खेतिहर महिला श्रमिकों की प्रतिशतता 37.42 है।

(ख) राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे कृषि व्यवसायों में न्यूनतम मजदूरी लागू करें तथा इसमें समय-समय पर संशोधन करें। इसके अलावा, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं जिनका उद्देश्य समुदाय के सबसे गरीब वर्गों की दशा सुधारना है जिनमें खेतिहर महिला श्रमिकों सहित अधिकतम कृषि श्रमिक हैं।

(ग) सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कत्था का निर्माण

[हिन्दी]

8916. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अपमिश्रित कत्थे का निर्माण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसकी रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) कत्थे सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न विनिर्माताओं/वितरकों और विक्रेताओं से नियमित रूप से उठाए जाते हैं।

विश्लेषण करने पर यदि कोई नमूना किसी भी तरह अपमिश्रित पाया जाता है तो अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।

अपमिश्रित कत्थे के सेवन से मानव शरीर पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव अपमिश्रण की मात्रा और स्वरूप पर निर्भर करते हैं।

डा० बाबासाहिब अम्बेडकर की जन्म शताब्दी के अवसर पर
स्वीकार की गई भाँगे

[अनुवाद] :-

8917. श्री ज्ञानराज महाडकी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्गीय डा० बाबासाहेब अम्बेडकर की जन्म शताब्दी के अवसर पर लोगों की कुछ मांगों को स्वीकार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत की गई मांगों का ब्योरा क्या है और इन्हें किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) क्या इन लाभों को मान्यता प्राप्त जाति के आधार पर अथवा आर्थिक स्तर (आय ध्रुप) के आधार पर दिया जाएगा ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) से (ग) सरकार ने बाबा साहेब डा० बी० आर० अम्बेडकर की जन्म शताब्दी 14 अप्रैल, 1990 से 14 अप्रैल, 1991 तक उपयुक्त ढंग से मनाने का निर्णय लिया है।

सरकार विभिन्न कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दे रही है जिन्हें शताब्दी समारोहों के दौरान उपयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाएगा।

समाचारपत्रों में शराब के विज्ञापन

8918. श्री ए० विजयराघवन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचारपत्रों में शराब के विज्ञापन देने के अप्रत्यक्ष तरीकों की जानकारी है;

(ख) क्या सोडा और "स्त्रैक" के नाम पर अप्रत्यक्ष रूप से शराब के विज्ञापन दिए जा रहे हैं;

(ग) क्या ऐसे विज्ञापनों के सम्बन्ध में दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कार्य को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन में रख दी जाएगी।

नगरों में नई परिवहन प्रणाली

8919. श्री प्रकाश कोको बह्मभट्ट : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कई राज्यों में अंशतः भूमि सतह पर तथा अंशतः भूमिगत तौर पर रेल-परिवहन-प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार का, विभिन्न नगरों में, राज्य-वार इन नई परिवहन प्रणालियों को किस सीमा तक लागू करने का विचार है ?

शहरी विकास बंधी (श्री सुरजकुमारी बारन) : (क) आज की तारीख में केवल दो प्रणालियां नामतः कलकत्ता मेट्रो प्रणाली और मद्रास महानगरीय परिवहन प्रणाली निर्माणाधीन हैं, कलकत्ता मेट्रो प्रणाली का एक भाग, जो अधिकांशतः भू-गत है, पहले ही चालू हो चुका है मद्रास तीव्र जन परिवहन प्रणाली में उष्ण तथा क्रमिक दोनों ही घटक हैं।

(ख) कुछ राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों ने अपने शहरों में तीव्र जन परिवहन प्रणालियों को आरम्भ करने के लिए प्रस्तावित व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार कराई हैं। उदाहरणार्थ, टालीगंज से गारिया तक कलकत्ता मेट्रो रेलवे के विस्तार और लुज से तारामणी और तारामणी से विलीबकम तक मद्रास समुद्र तट-मुज आइन के विस्तार के लिए व्यवहार्यता रिपोर्टों के अलावा, बंगलौर, हैदराबाद, सिकन्दरबाद, अहमदाबाद आदि जैसे शहरों को ऐसे अध्ययनों के लिए चुना गया है।

(ग) चूंकि तीव्र जन परिवहन प्रणालियां अत्यधिक पूंजी निवेश वाली प्रणालियां हैं, इसलिए वृक्ष प्रकर की प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों की सहभागिता अपेक्षित है। महत्व तथा प्राथमिकता पर निर्भर करते हुए भारत सरकार सहित विभिन्न अधिकरणों के पास संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए राज्य सरकारों द्वारा इन योजनाओं पर उचित समय पर विचार किया जाएगा। कार्यान्वयन भी आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए निधियों के नियतन पर निर्भर करेगा।

पिछड़े और उपेक्षित जिलों को सिंचाई सुविधाएं

[सिंधी]

8920. श्री राम सच्चोबन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पिछड़े और उपेक्षित जिलों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने सम्बन्धी कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या कार्यदल को तुरन्त ऐसा करने के लिए कहा जाएगा ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जी, हां। बुन्देलखण्ड क्षेत्र की चालू एवं नई बृहद् एवं मध्यम परियोजनाओं के लिए परिषदों की सिफारिश की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता को राष्ट्रीय नगर घोषित करना

[अनुबाध]

8922. श्री सुब्रह्मण्य राय चौधरी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता को राष्ट्रीय नगर अथवा राष्ट्रीय महत्त्व का नगर घोषित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

साहरो विकास मंत्री (श्री बुरस्तोली आरण) : (क) जी, नहीं।

(ख) ब्रह्म नहीं उठता।

डाक्टरों द्वारा हड़ताल

[हिन्दी]

8923. श्री हरि शंकर महाले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा देश भर में चलाए जा रहे अस्पतालों में कार्यरत डाक्टर राज्यवार कितनी बार आंशिक अथवा सम्पूर्ण हड़ताल पर रहे; और

(ख) उनकी मांगों का ब्योरा क्या है और भविष्य में ऐसी हड़तालों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में कार्य कर रहे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा तथा संयुक्त कार्रवाई परिषद के अन्य सचिस डाक्टरों ने बेहतर वेतनमानों और परिलब्धियों तथा पदोन्नति सम्बन्धी अवसरों में सुधार करने की अपनी मांगों के समर्थन में जुलाई, 1987 में व्यापक हड़ताल कर दी। इन हड़ताली डाक्टरों के लिए सरकार द्वारा साभों के एक पैकेज की घोषणा की गई। पर, उन साभों से असन्तुष्ट होते हुए, सचिस डाक्टरों के संगठनों की संयुक्त कार्यवाई परिषद ने अप्रैल, 1989 में एक नया मांगपत्र प्रस्तुत किया। उनकी मुख्य मांगों में उच्चतर वेतनमान, समयबद्ध प्रोन्नति, प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति देने अथवा कोई सीमा निर्धारित किए बिना मूल वेतन का 50% प्रैक्टिस बन्दीभत्ता देने, सेवा निर्बतन की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 62-65 वर्ष करने, चिकित्सा अधिकारियों को पूर्व तारीख से विभिन्न भत्ते अर्थात् जोषिम भत्ता, बाहन भत्ता, आकस्मिकता भत्ता, स्नातकोत्तर भत्ता, अध्यापन भत्ता, प्रशासनिक भत्ता और ग्रामीण/दुर्गम क्षेत्र भत्ता, मंजूर करना/उनमें वृद्धि करना, सेवा मामलों के लिए सभी राज्यों की रेजीडेंसी सेवा की गिनती करना, सभी सचिस डाक्टरों के लिए समान वेतनमान और प्रोन्नति के अक्षर प्रदान करना, प्रोन्नति/तैनाती सम्बन्धी साभ 1-1-1986 से लागू करना, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के पदों की संख्या में वृद्धि करना हड़ताल की अवधि का वेतन देना, सभी घटकों आदि को यह साभ देना, शामिल हैं। उनकी समस्त मांगों के पूर्ण और अन्तिम निपटान के रूप में सचिस डाक्टरों के संगठनों की संयुक्त कार्रवाई परिषद के साथ 21 अगस्त, 1989 के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

जूनियर डाक्टरों (जिनमें जूनियर और सीनियर रेजीडेंट शामिल हैं) ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के नियमित डाक्टरों को दी गई उच्चतर परिलब्धियों को देखते हुए, अपनी परिलब्धियों के उच्चतर संशोधन की अपनी मांग के समर्थन में मई-जून, 1989 में हड़ताल कर दी। हड़ताल कर रहे जूनियर डाक्टरों को और भारत सरकार के बीच 1 जुलाई, 1989 को एक समझौता हो गया जिसके अन्तर्गत उनकी परिलब्धियों में वृद्धि कर दी गई है।

इन समझौतों के हो जाने और उनके लागू हो जाने के परिणामस्वरूप, सरकार को आशा है कि भविष्य में इन डाक्टरों के हड़ताल पर चले जाने का कोई कारण नहीं होगा।

दिल्ली के उचित दर दुकानदारों की मांगें

8924. श्री शिव शरण वर्मा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के उचित दर दुकानदारों ने सरकार को अपनी मांगें प्रस्तुत की हैं और धमकी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गयीं, तो वे हड़ताल कर देंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) जी हां, दिल्ली प्रशासन को प्रस्तुत की हैं। उचित दर दुकानों के मालिकों की मुख्य मांग उनके मुनाफे के मार्जिन को बढ़ाने के लिए थी।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने गेहूं और चावल की बिक्री पर उचित दर दुकानों के मालिकों को देय कमीशन में संशोधन करके उक्त मामले को सुलझा दिया है।

मंसस बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड का नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन के साथ विलय

[अनुवाद]

8925. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंसस बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड का अधिग्रहण किया गया था और वर्ष 1986 में इसका नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन के साथ विलय कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस एकक में सरकारी उद्यम ब्यूरो के सभी निर्णयों को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड में भी अन्तरिम/तदर्थ राहत सम्बन्धी सरकारी उद्यम ब्यूरो के परिपत्र को कार्यान्वित किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लि० का नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन के साथ विलय नहीं किया गया। यह कम्पनी अलग निदेशक बोर्ड के साथ कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत बनी रहेगी और बी० जे० ई० एल० में काफी संख्या में निजी शेयर धारक हैं। बी० जे० ई० एल० में सरकार के शेयरों को वर्ष 1986 में एन० जे० एम० सी० में अन्तर्गत किया गया था। यह कम्पनी नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन की एक सहयोगी कम्पनी है।

(ख) से (घ) सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के निर्णय बी० जे० ई० एल० में इसकी स्थापना के अनुसार लागू होते हैं। अन्तरिम/तदर्थ राहत के सम्बन्ध में बी० पी० ई० का परिपत्र केवल सरकारी

क्षेत्र के उन उपक्रमों पर लागू होता था जहाँ वेतन ढांचा औद्योगिक महंगाई भत्ते के साथ सम्बद्ध था। इस प्रकार यह बी० जे० ई० एल० में लागू नहीं था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नेशनल इलेक्ट्रोपंचो, होम्पोपंचो मेडिसिन आफ इण्डिया की भूमि का आवंटन

हिन्दी]

8926. श्री जगन्नाथ सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल इलेक्ट्रोपंचो, होम्पोपंचो मेडिसिन आफ इण्डिया (सेंट्रल काउन्सिल) जनकपुरी, नई दिल्ली ने भूमि के आवंटन हेतु अपना आवेदन पत्र कब प्रस्तुत किया था;

(ख) क्या चिकित्सा संस्थाओं को भूमि का आवंटन करने के लिए सरकार की सिफारिश की आवश्यकता होती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रयोजन के लिए भूमि का आवंटन कब तक किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली भारन) : (क) 13-4-1985।

(ख) और (ग) दिल्ली में चिकित्सा संस्थानों को भूमि आवंटित करने के लिए अग्य बातों के साथ आवेदक समिति की प्रमाणिकता, व्यवसायी क्षमता और वित्तीय सुदृढ़ता तथा उस वित्तीय के लिए विशिष्ट मेडि-केयर सुविधा की आवश्यकता, जिसमें भूमि के लिए आवेदन किया गया है, का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय/दिल्ली प्रशासन द्वारा उनका नाम भेजा जाना आवश्यक है।

(घ) आवेदक से अपेक्षित दस्तावेजों के अभाव में भूमि के आवंटन के लिए विचार नहीं किया जाता है।

बाणसागर बांध परियोजना

8927. श्री सुब्रह्मण्य सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाणसागर बांध परियोजना के लिए वर्ष 1990-91 के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार किया गया है;

(ख) इस परियोजना से गांवों के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों से वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही है और क्या अग्य शर्तों के साथ ऐसी सहायता प्राप्त करने हेतु द्विपक्षीय वार्ता चल रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में ऐसी वार्ता करने का कोई प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) 52 करोड़ रुपये।

(ख) विधानसभों के अनुसार, विस्थापित 90 × 50 के आकार के निःशुल्क आवासीय प्लॉट तथा 750 रुपए के पुनर्स्थापना अनुदान के पात्र हैं। वह परिवार जो आवास की व्यवस्था स्वयं कर रहे हैं, उन्हें 2000 रुपए का पुनर्स्थापना अनुदान प्रदान किया गया है। इसके अलावा, 500 रुपये से कम का मुआवजा प्राप्त करने वाले परिवार को 500 रुपए की अनुदान सहायता प्रप्त होनी है जो मुआवजे की राशि के बढ़ने पर आनुपातिक रूप से कम हो जाती है। साथ ही, बस्तर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 25% सीटें बाणसागर और बोधघाट परियोजनाओं के विस्थापितों के लिए आरक्षित की गई है। पुनर्वास कालोनियों को अन्यो के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, स्कूलों, पट्टूच सड़कों, खुदाई कुओं, तासाबों, पाकों तथा बिजली जैसी नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा।

(ग) और (घ) जो, नहीं।

नमक को आयोडीनयुक्त बनाने सम्बन्धी विशेषज्ञ तथा

[अनुवाद]

8928. श्री राम नाईक :

डा० बंकटेश काबड़े :

डा० दौलतराव सोबूजी अहेर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में समुचित भोजन उपलब्ध होने, भोजन में मसगंड रोम जन्म स्थानीय भोज्य पदार्थों की बहुलता, अस्वच्छता और कठोर जल के कारण ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में मसगंड रोग पाया जाता है; और

(ख) क्या सरकार का विचार नमक को अनिवार्य रूप से आयोडीनयुक्त बनाने और बाजार में इस आयोडीनयुक्त नमक को जरूरत मन्दों को मुफ्त देने का है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमलान मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) गलगण्ड सहित आयोडीन की कमी से होने विकार आयोडीन की कमी वाले पर्यावरण में रहने वाले लोगों को होते हैं, हालांकि आयोडीन की कमी स्थानिकमारी गलगण्ड का मुख्य कारण है, तथापि गलगण्ड के विकसित होने में अन्य पर्यावरणिक पहलू भी आयोडीन के साथ मिलकर सक्रिय हो जाते हैं, आयोडीन की दैनिक जरूरत मुख्य रूप से भोजन (90%) और प्राकृतिक जल द्वारा पूरी की जाती है। आतोडीन की कमी वाली मिट्टी में पैदा होने वाले अनाजों, दालों, सब्जियों और फलों में आयोडीन की कमी होती है। कुछ सब्जियों और फलों में गलगण्डजनक घटक निहित होते हैं लेकिन इन गलगण्डजनक घटकों को अलग किया जा सकता है। किए गए विभिन्न प्रयोगात्मक अध्ययनों से पता चला है कि गलगण्ड उत्पन्न करने वाले अशुद्धित गलगण्डजनकों की मात्रा प्रतिदिन ऐसे भोजन को काफी बढ़ी मात्रा में उपयोग करने से आवश्यक रूप से शरीर के अन्दर चली जाएगी। वनों के समाप्त होने के कारण मिट्टी से आयोडीन समाप्त हो रही है, यह बात बार-बार आने वाली बाढ़ों और अपना स्थान बदलने वाली नदियों से भी जुड़ी हुई है।

अनुमान है कि भारत में ग्रामीण और पिछड़ क्षेत्रों में रह रहे लोगों सहित 15 करोड़ लोगों को आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों के होने का खतरा है जिनमें से 5.4 करोड़ लोगों को आयोडीन की कमी से होने वाले विकार हैं और 22 लाख लोग केन्टिन्स हैं।

(ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि देश में किसी भी क्षेत्र को गलगण्ड और आयोडीन की कमी से होने वाले अन्य विकारों से पूर्णतया मुक्त नहीं समझा जा सकता है। नमक और आयोडीकरण आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों की रोकथाम की सबसे सस्ती और प्रामाणिक विधि है। यदि देश में आयोडीकृत नमक के उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों से सम्बन्धित कोई विशिष्ट वैज्ञानिक डेटा सरकार के ध्यान में लाया जाता है, तो यह मामला इस सम्बन्ध में तकनीकी मुद्दों की समीक्षा करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को भेजा जा सकता है।

राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

8929. श्रीमती बलुगंधरा राजे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कुछ सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गयी है अथवा करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) केन्द्र में दिसम्बर, 1979 से अगस्त, 1989 तक प्राप्त हुई 10 आधुनिकीकरण परियोजनाओं में से, 8 परियोजनाएं, मूल कमियों/केन्द्रीय जल आयोग की टीका टिप्पणियों का राज्य सरकार द्वारा अनुपालन एक वर्ष से अधिक तक न किए जाने के कारण लौटा दी गई। 29.1 करोड़ रु० की अनुमानित लागत की दो परियोजनाएं अर्थात् जैसामांड और गम्भीरी आधुनिकीकरण परियोजनाएं, जिनमें लगभग 24,000 हेक्टेयर को लाभ पहुंचाने की परिकल्पना है, की जांच की गई और टिप्पणियां राज्य सरकार को अनुपालन के लिए भेजी गईं।

(ग) राज्य सरकार ने अपनी 1990-91 की वार्षिक योजना में 5.3 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया है।

देश में होलीडे होम

8930. श्री बबनराव डाकणे : क्या सहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन होलीडे होमों/गैस्ट हाउसों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन होलीडे होमों/गैस्ट हाउसों के आबंटन का क्या तरीका है;

(ग) इन होलीडे होमों/गैस्ट हाउसों में लिया जाने वाला औसत किराया कितना है; और

(घ) क्या सरकार का कुछ राज्यों में नए होलीडे होमों/गैस्ट हाउसों के निर्माण का विचार है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली नारन) : (क) वीरे पर जाने वाले अधिकारियों के होस्टलों से यथा भिन्न होलीडे होम फिलहाल हिमाचल प्रदेश में शिमला, उत्तर प्रदेश में मसूरी और तमिलनाडु

में कन्याकुमारी में है। संसद सदस्यों, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों सांबंजनिक क्षेत्र उपक्रमों आदि के कर्मचारियों और उनके साथ आये अतिथियों को आबंटित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इस मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन कोई अतिथिगृह (गेस्ट हाउस) नहीं है।

(ख) होलीडे होमों में वास का आबंटन, आवेदन किए जाने पर पहले आओ पहले पाओ आधार पर साइसैस फीस की अग्रिम वसूली की शर्त पर किया जाता है। तथापि, अन्य श्रेणियों की तुलना में खसद सदस्यों तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) शिमला, मसूरी तथा कन्याकुमारी में विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित प्रभार क्रमशः संलग्न विवरण 1, 2 तथा 3 में दिए गए हैं।

(घ) निम्नलिखित स्थानों पर होलीडे होमों के निर्माण का, इन स्थानों पर भूमि की उपलब्धता की शर्त पर, सरकार द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन कर दिया गया है।

(1) गोआ, (2) ऊटी, (3) मसूर, (4) अमरकंटक, (5) नैनीताल, (6) पुरी, (7) दार्जिलिंग, (8) गंगटोक, (9) कैलिमपोंग, (10) कोडियाकनाल, (11) मदुरै, (12) श्रीनगर, (13) वाराणसी और (14) दिल्ली।

विवरण

ग्रांड होटल (हॉलिडे होम) शिमला में आवास के अग्रिम आरक्षण हेतु आवेदन

1. अधिकारी/संसद/पर्यटक का नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)
2. पदनाम व विभाग/मंत्रालय जिससे संबद्ध हैं (रक्षा सेवा अधिकारी द्वारा पर्सनल नं०, रैंक तथा पेरेंट यूनिट का उल्लेख किया जाना चाहिए)
3. (क) पूरा डाक पता, जहां पत्राचार किया जाना है।
3. (ख) स्थायी पता
4. (क) अवधि, जिसके लिए आवास की आवश्यकता है
- (ख) क्या आवास की आवश्यकता छुट्टी बिताने के लिए है अथवा छुट्टी के प्रयोजन हेतु हैं
5. अपेक्षित आवास के टाइप का वरीयता क्रम सिंगल/डबल/फोर बेड सूट

6. क्या पिछले दो वर्षों के दौरान छुट्टी
 बिताने के प्रयोजन हेतु आवास लिया
 गया था ।

घोषणा

(क) मैं प्रमाणित करता हूँ कि ग्रांड होटल, शिमला में मांगे गए आवास का कच्चा मेरे द्वारा अथवा मुझ पर आश्रित मेरे परिवारजनों द्वारा लिया जाएगा जिनकी पहचान कार्यालय/विभाग द्वारा विधिवत सत्यापित की जाएगी ।

(ख) मैं प्रमाणित करता हूँ कि :—

- (i) मैं राज्य सभा/लोक सभा सदस्य हूँ ।
- (ii) मैं केन्द्रीय सरकारी सेवा में हूँ ।
- (iii) मैं.....की सेवा में हूँ तथा मुझे.....
की निधियों में से वेतन का भुगतान किया जाता है ।
- (iv) अपनी तैनाती के स्थान पर मैं साधारण पूल आवास का पात्र हूँ/नहीं हूँ ।
- (v) प्राधिकारी का नाम जो तैनाती के स्थान पर मुझे रिहायशी आवास आबंटित करते हैं.....।

(ग) मैं वचन देता हूँ कि किसी भी हालत में सम्पदा निदेशालय की अनुमति के बिना आरक्षण की अवधि.....से अधिक अवधि तक नहीं ठहरूंगा और उक्त तारीख पर आवास को खाली कर दूंगा । ऐसा न करने पर हर्जाने के रूप में लाइसेंस फीस की बाजार दर का भुगतान करने तथा अन्य कानूनी कार्रवाई आदि का पात्र हूंगा ।

(घ) मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गयी सूचना सही है और कुछ भी नहीं छिपाया गया है । आबंटन को नियन्त्रित करने वाले नियम और आदेशों का भी मैं पालन करूंगा ।

(ङ) मैं भोजन प्रबंधक को प्रत्यक्ष रूप से सरकार के आदेशानुसार खाना खाने या सेवा प्रभार देने का वचन देता हूँ ।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर :

प्रतिदिन आवास का किराया इस प्रकार है :

कमरों का विवरण	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकारी कम्पनियों के कर्मचारी	गैर-सरकारी व्यक्तियों के लिए (सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त के कम में)
सिंगल बेड स्यूट	10.00 रु०	25.00 रु०	50.00 रु०
डबल बेड स्यूट	15.00 रु०	40.00 रु०	80.00 रु०
फोर बेड स्यूट	20.00 रु०	60.00 रु०	100.00 रु०

आरक्षण के आवेदन के साथ बैंक ड्राफ्ट साथ होना चाहिए जिसमें सहायक सम्पदा प्रबन्धक होटल, शिमला के पक्ष में दी गई पूर्ण राशि दी गयी हो और इसे सहायक सम्पदा प्रबन्धक, ग्रांड होटल, शिमला को सीधे भेजा जाना चाहिए।

15 अप्रैल से 15 जुलाई की सीजन अवधि के दौरान हॉलिडे होम, शिमला में आरक्षण के लिए आवेदन 1 मार्च तथा इसके बाद सहायक सम्पदा प्रबन्धक, शिमला के कार्यालय में प्राप्त किए जाते हैं और पहले आबो पहले पाबो के आधार पर आरक्षण किया जाता है।

प्रशासनिक कार्यालय द्वारा भरे जाने हेतु :—

स०

तारीख :

सहायक सम्पदा प्रबन्धक, ग्रांड होटल, शिमला को प्रेषित/प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०..... और उसका परिवार अवकाश/सरकारी ड्यूटी पर शिमला का दौरा करने आएंगे।

हस्ताक्षर :

कार्यालय की मोहर :

बिबरण-2

हॉलिडे होम मंजूरी (उत्तर प्रदेश) में आवास के आबंटन हेतु आवेदन पत्र

1. अधिकारी का नाम और कार्यालय का पता
2. पदनाम और रिहायशी पता (टेलीफोन नं० सहित)
3. परिवार के सदस्यों का ब्यौरा (बच्चों को भिन्न-भिन्न निर्दिष्ट करें)
4. अपेक्षित बिस्तारों की संख्या
5. वह अवधि जिसके लिए आवास अपेक्षित है (तारीखें निर्दिष्ट करें)
6. जमा राशि (बैंक ड्राफ्ट का ब्यौरा दें)

नोट : 7 दिनों से अधिक नहीं)

7. धोषणा : मैं घोषणा करता हूँ कि प्रापित आवास मरे और मेरे परिवार के सदस्यों के हक में रहेगा। मैं.....को आवास खाली करने का बचन देता हूँ और सम्पदा निदेशालय की पूर्ण लिखित अनुमति के बिना अधिक समय तक नहीं ठहरूंगा।

हस्ताक्षर :

तारीख :

सामान्य अनुवेस

1. आवास के लिए प्रतिदिन किराया निम्नानुसार है :

कमरों का ब्यौरा	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सरकारी कम्पनियों, राज्य सरकारों आदि के कर्मचारियों से	वैर सरकारी व्यक्तियों से जब आबंटन संसद सदस्यों/सरकारी कर्म- चारियों के मेहमानों के तौर पर किया जाता है
(1) 2 बैठ कम	9.00 रुपये	20.00 रुपये	30.00 रुपये
(2) 3 बैठ कम	13.50 रुपये	30.00 रुपये	45.00 रुपये
(3) 4 बैठ कम	18.00 रुपये	40.00 रुपये	60.00 रुपये
(4) 6 बैठ कम	27.00 रुपये	60.00 रुपये	90.00 रुपये

2. होलीडे होम में निम्नलिखित दरों पर गीजर, पानी और बिजली के प्रभार हैं :

प्रतिदिन दर

	2 बैठ कम	3 बैठ कम	4 बैठ कम	6 बैठ कम
गीजर पानी तथा	1.00 रुपये	2.00 रुपये	3.00 रुपये	4.00 रुपये
बिजली	2.00 रुपये	3.00 रुपये	4.00 रुपये	5.00 रुपये

इसके अतिरिक्त, हॉलीडे होम में यदि कोई कम्पन लिया जाता है तो उसके लिए अतिरिक्त प्रभार 1 रुपया प्रतिदिन होगा।

3. आरक्षण के लिए आवेदन पत्रों के साथ संपदा सहायक निवेशक (रोकड़) के नाम में काटा गया बैंक ड्राफ्ट होना चाहिए जिसमें वैरा (1) में दी गई दरों पर आवास का किराया दिया गया हो इसे सहायक सम्पदा (प्रादेशिक) कमरा संख्या 411-“सी”, सम्पदा निवेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली को भेजा जाना चाहिए ताकि आबंटन की वास्तविक तारीख से कम से कम 15 दिन पहले पहुंच जाए।

15 अप्रैल से जुलाई की सीजन अवधि के दौरान हॉलीडे मंडूरी में आरक्षण के लिए आवेदन

पत्र 1 मार्च के बाद इस निदेशालय में प्राप्त किए जाते हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आरक्षण किया जाता है।

(प्रशासनिक कार्यालय द्वारा भरा जाए)

सं०.....

तारीख.....

आवश्यक कार्रवाई हेतु इस निदेशालय को अप्रेषित।

हस्ताक्षर :

कार्यालय की मोहर :

बिबरण-3

बिबेकानन्दपुरम, कन्याकुमारी (तमिलनाडु) हॉलिडे होम में आवास के आबंटन के लिए आवेदन-पत्र

1. अधिकारी का नाम, पदनाम तथा कार्यालय का पता (टेलीफोन नं०) (स्पष्ट अक्षरों में)
2. रिहायशी पता :
3. अपेक्षित आवास :
4. अवधि जिसके लिए आवास की जरूरत है (तारीख बताएं)
5. जमा की गयी धनराशि : (बैंक ड्राफ्ट का ब्यौरा दें)
6. घोषणा :—मैं प्रमाणित करता हूँ कि अनुरोध किया गया आवास मेरे तथा मेरे परिवार के दखल में होगा। मैं बिबेकानन्द मे:ड के अनुशासन का अनुपालन करने का बचन देता हूँ।

अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख :

निम्नलिखित कार्यालयों में से किसी के साथ भी आरक्षण किया जा सकता है :—

उपलब्ध स्थलों की संख्या

1. सम्पदा सहायक निदेशक (प्रादेशिक) कमरा सं० 411 "सी" बिंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

दो 3-बैड डीलक्स स्टूट व दो 2-बैड स्टूट

	उपलब्ध स्टूटों की संख्या
2. सम्पदा प्रबन्धक, 5 एस्प्लानेड ईस्ट, कलकत्ता-69.	एक 2-बैंड स्टूट
3. सहायक सम्पदा प्रबन्धक, प्रथम तल, शास्त्री भवन, 26 हैबोज रोड, मद्रास	एक 2-बैंड स्टूट
4. कार्यपालक इंजीनियर, त्रिवेन्द्रम सेंट्रल डिबीजन, के० लो० नि० वि०, त्रिवेन्द्रम-4	एक 2-बैंड स्टूट

यदि आरक्षण (1) के साथ करना है तो सम्पदा सहायक निदेशक (रोकड़) के पक्ष में काटा गया बैंक ड्राफ्ट आवेदन के साथ होना चाहिए जिसमें कि आवास का किराया दिया गया है। यदि आरक्षण (2) से (4) तक में उल्लिखित अधिकारियों के में से किसी के साथ करना है तो बैंक ड्राफ्ट उनके पक्ष में काटा जाना चाहिए।

किराए की दर निम्न प्रकार हैं :—

	प्रतिदिन किराया	
	2-बैंड स्टूट	3-बैंड डीलक्स स्टूट
केन्द्र सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए	10 रु०	25 रु०
केन्द्र सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए	30 रु०	75 रु०

अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए प्रभार विवेकानन्द केन्द्र, कन्याकुमारी के परिसर प्रभारी को उनके द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर सीधा दिया जाना है।

(प्रशासनिक कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

सं०

दिनांक :

.....को अर्पित/प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमतीकालम सं० । में
.....द्विमा मध्य किमरण सही है।

हस्ताक्षर :

कार्यालय की मोहर :

महाराष्ट्र की गोसेखुर्द परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता

8931. श्री० महादेव शिबनकर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में भण्डारा जिले की गोसेखुर्द परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता के सम्बन्ध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) गोसेखुर्द परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा कुछ आवश्यकताओं, जैसे—पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन, के पूरा न करने के कारण योजना आयोग द्वारा परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निजी भूखण्डों का अधिग्रहण करना

[हिन्दी]

8932. श्री राजेश्वर अग्निहोत्री : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किन्हीं निजी भूखण्डों का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूखण्डों के मालिकों को मुआबजे का भुगतान कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसे कब तक भुगतान करने का विचार किया गया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कर्नाटक में अगरबत्ती श्रमिकों का कल्याण

[अनुवाद]

8933. श्री एच० सी० श्रीकान्तम्मा : क्या धन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक और अन्य राज्यों में अगरबत्ती बनाने वाले श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधाएं प्रदान करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

अधम और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम अग्रबत्ती के निर्माण में लगे प्रतिष्ठानों और 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर पहले से ही लागू है। इसी तरह, अग्रबत्ती के निर्माण में लगे कारखाने, जो या तो बिजली से चलाए जाते हैं और 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करते हैं या जो बिना बिजली से चलाए जाते हैं तथा जो 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करते हैं और उन क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां क० रा० बी० योजना को पहले ही लागू किया गया है, क० रा० बी० अधिनियम के अन्तर्गत पहले से ही आते हैं। उपरोक्त श्रेणियों के प्रतिष्ठानों/कारखानों के कर्मकार पहले से ही क० भ० नि० और क० रा० बी० सुविधाओं के हकदार हैं। इस समय दोनों अधिनियमों के अधीन परिधि का और विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गन्ने से चीनी की प्राप्ति

8934. श्री एम० बागा देवुी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु की सहकारी चीनी मिलों में गन्ने से औसतन कितने प्रतिशत चीनी प्राप्त हुई है; और

(ख) क्या यहां चीनी प्राप्ति की प्रतिशतता भिन्न-भिन्न रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) 1988-89 चीनी वर्ष के दौरान सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों में गन्ने से चीनी प्राप्ति का प्रतिशत इस प्रकार था :

राज्य	प्राप्ति प्रतिशत
1. महाराष्ट्र	11.06
2. आन्ध्र प्रदेश	9.77
3. कर्नाटक	10.63
4. तमिलनाडु	10.20

(ख) चीनी एक कृषि आधारित उद्योग है एवं इसकी प्राप्ति विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग है जो, मौसम की स्थिति, गन्ने की किस्म व गुणवत्ता, कटाई व पेरार्ई का समय आदि कई कारकों पर निर्भर करती है।

जाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र

8935. श्री अरविन्द तुलसीराम कांबले : क्या अधम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल कालेजों अथवा इंजीनियरी कालेजों आदि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर गैर-कानूनी रूप से प्रवेश लेने के अनेक मामले महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार, ऐसे कितने मामले हुए हैं; और

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाणपत्र के आधार पर प्रवेश लेने को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

अम और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(घ) भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को पहले ही विस्तृत अनुदेश जारी करके अनुरोध किया गया है कि वे उन कर्मचारियों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई करें जो जानबूझकर अथवा लापरवाही से उपयुक्त जांच किए बिना झूठे प्रमाणपत्र देते हैं । राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे गैर-अनुसूचित जातियों तथा गैर-अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सभी मामलों का पता लगाने के लिए हर प्रयास करें, जिनके पास अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति के झूठे प्रमाणपत्र हैं, इन्हें मिल रहे वे लाभ रद्द कर दिए जाएं जिनके वे हकदार नहीं हैं तथा उनके विरुद्ध और उनके भी विरुद्ध जो ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जिम्मेवार हैं/थे उपयुक्त कानूनी कार्रवाई करें । तथा उन्हें सख्त सजा दें । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से इस सम्बन्ध में कठोर तथा शीघ्र कार्रवाई करने और इस पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता का आग्रह किया गया है ।

विवरण

बम्बई उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामलों की सूची जिनमें भारत संघ एक प्रतिवादी के रूप में है

1. धमार समुदाय से सम्बन्धित याचिका दाता की जाति-जांच के सम्बन्ध में मालती एम० भण्डारी, याचिकादाता बनाम महाराष्ट्र सरकार तथा भारत संघ रिटयाचिका संख्या 4810/1987 ।
2. याचिकादाता की जाति-दर्ज के सम्बन्ध में गोपाल अक्षर बिरट बनाम महाराष्ट्र सरकार तथा अन्य रिट याचिका संख्या 4967/1988 ।
3. महाराष्ट्र में घांगर समुदाय को घांगड़ समुदाय के रूप में मानने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश याचिकादाता बनाम महाराष्ट्र राज्य सरकार तथा अन्य-बम्बई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद में रिट याचिका संख्या 1071/1987 ।
4. घांगड़ के नाम पर घांगर समुदाय को जाति, प्रमाणपत्र जारी करने के सम्बन्ध में श्री एम० ए० महात्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य सरकार तथा अन्य बम्बई उच्च न्यायालय के नागपुर पीठ में रिट याचिका संख्या 885/1987 ।
5. गुजरात राज्य से प्रवासी याचिकादाता के जाति दावे के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार बिनोद कठारिया बनाम महाराष्ट्र सरकार तथा अन्य-बम्बई उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 37.9/88 ।

शीतल पेय में ब्रोमिनेटेड बेजिटेबल ऑयल (बी० बी० ओ०) प्रयोग करने वाली कम्पनियों पर छापे मारना

8936. श्री डी० एन० पुट्टे गोडा :

श्री सरजू प्रसाद सरोज :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग ने शीतल पेय में ब्रोमिनेटेड बेजिटेबल ऑयल के तत्वों का पता लगाने के लिए शीतल पेय निर्यातकों के परिवारों पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विभाजन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ने ब्रोमिनेटेड वनस्पति तेल के इस्तेमाल का पता लगाने हेतु कार्बोनेटेड वाटर्स के विनिर्माताओं के परिवारों पर 17 अप्रैल, 19 अप्रैल और 30 अप्रैल को छापे मारे थे। फिर एप्रैल १९ मसूनों से 3 मसूनों को जन विश्लेषक द्वारा ब्रोमिनेटेड वनस्पति तेल से युक्त पाया गया है। ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

उन सभी तीन मामलों की, जिनमें ब्रोमिनेटेड वनस्पति तेल का पता चला है, जांच की जा रही है।

विवरण

तारीख	उत्पाद का नाम	विनिर्माता का नाम	विश्लेषण का निष्कर्ष
1	2	3	4
17-4-90	गोल्ड स्पॉट	मैसर्स दिल्ली बॉटलिंग कंपनी, शिवाजी मार्ग नई दिल्ली	अपमिश्रित ब्रोमिनेटेड वनस्पति तेल के चटक पाए गए
17-4-90	थम्स अप	—तदैव—	असली
17-4-90	गोल्ड स्पॉट	मैसर्स पर्स ड्रिक्स (प्रा०) लिमि० लॉरेंस रोड, दिल्ली	अपमिश्रित ब्रोमिनेटेड वनस्पति तेल के चटक पाए गए।
17-4-90	लिम्का	—तदैव—	—तदैव—
19-4-90	कोला साइट	मैसर्स प्योर ड्रिक्स शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली	असली

1	2	3	4
19-4-90	कैम्पा कोला	—तदेव—	असली
19-4-90	ट्रिप्प	—तदेव—	असली
19-4-90	सोडा स्पेशल	—तदेव—	असली
30-4-90	स्वीटंड कार्बोनेटिड (बंटा टाइप)	मैसर्स अरोड़ा साँपट ट्रिक्स, टैगोर गाडन मार्किट, नई दिल्ली।	असली

भूमि और विकास अधिकारी के पद के लिए भर्ती सम्बन्धी नियम

8937. श्री धर्मपाल सिंह गुप्त : क्या शहरी विकास मंत्री भूमि और विकास अधिकारी पद के लिए भर्ती नियम के बारे में 7 दिसम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3869 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या भूमि और विकास अधिकारी पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) पुनरीक्षण पर यह अनुभव किया गया कि विद्यमान नियमों में किसी प्रकार के संशोधन अपेक्षित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के अस्पतालों में कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के डाक्टर

[हिन्दी]

8938. श्री कल्पनाच सोनकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध डाक्टरों की पदोन्नति सरकारी आदेशों के अनुसार न कर इनमें विलम्ब किए जाने के कुछ मामले चर्चित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन डाक्टरों को कब तक पदोन्नति दे दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेलुगु गंगा परियोजना को पूरा करना

[अनुचाव]

8939. श्री आर० श्रीचरलम : क्या जल-संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेलुगु गंगा परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(ख) क्या इस परियोजना की फीडर नहर का रायलसीमा, पलामनार-बनियाम बड़ी और फिर [मद्रास तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश द्वारा तैयार की गई तेलुगु गंगा परियोजना में मद्रास को जल आपूर्ति के लिए कृष्णा जल के 15 टी० एम० सी० के स्थानांतरण की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, रायलसीमा और नेल्सोर जिलों के मार्गों में पड़ने वाले 1.99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया गया है। यद्यपि परियोजना का तकनीकी-आर्थिक रूप से मूल्यांकन किया गया है, फिर भी अप्रैल, 1988 में परियोजना पर विचार करने के पश्चात् परामर्श समिति ने इसकी स्वीकृति को आस्थगित कर दिया क्योंकि अन्तर्राज्यीय पहलुओं का समाधान नहीं किया गया था। राज्य सरकार को अन्य सह-बेसिन राज्यों की सहमति प्राप्त करनी है।

अन्धता निवारण के लिए कदम

8940. श्री श्री० कृष्ण राव :

श्री एडुआर्दो फॅलोरो :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नेत्रहीन लोगों में से 80 प्रतिशत के मामले में या तो इस रोग का निवारण उपचार किया जा सकता है या उपचार किया जा सकता है;

(ख) सरकार द्वारा लोगों में और विशेष रूप से बच्चों में अन्धता निवारण के लिए क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का ऐसे बच्चों के माता-पिताओं के लिए क्या-क्या निदेश जारी करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने लोगों में, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, दृष्टिहीनता के निवारण और नियन्त्रण के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे नेत्र परिवर्त्या और विटामिन 'ए' से भरपूर आहारों के उपयोग पर स्वास्थ्य शिक्षा, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में विटामिन 'ए' की कमी के कारण होने वाली दृष्टिहीनता से बचाव के लिए विटामिन 'ए' की गहन खुराकों का वितरण, रोहे के नियन्त्रण के लिए एंटी-

बायोटेक आई ऑयंटमेंट की सप्ताई, ज्योतिषी इच्छा करने के लिए प्रेरितियाबिन्द ऑपरेशन, नेत्र बैंकिंग और कानियस प्रत्यारोपण करना ।

(ग) स्वास्थ्य शिक्षा के अन्तर्गत शामिल किए गए संदेशों जैसे, सामान्य नेत्र स्वास्थ्य, हरे पत्ते वाली सब्जियों और विटामिन "ए" से भरपूर अन्य आहारों का उपयोग, विटामिन "ए" की कमी से होने वाली दृष्टिहीनता से बचाव के कार्यक्रम के अन्तर्गत सुविधाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना, माता-पिता, स्कूल के अध्यापकों और चिकित्सीय तथा परा-चिकित्सीय स्टाफ के लिए निर्देशित किया जाता है ।

भारत मूंगफली श्रेण

8941. श्रीमती सुभाषिनी अग्नी : क्या खाद्य और नागरिक पुति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा धारा मूंगफली के तेल का विपणन एक लीटर के टेट्रापैकों में किया जा रहा है;

(ख) क्या ऐसा करके वह तोल और माप अधिनियम का उल्लंघन कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस उल्लंघन के लिए किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का जालान किया गया है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पुति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजत पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) बाट तथा माप मूक्तक (पैकेज में रखी बस्तुएं) नियम, 1977 के अनुसार खाद्य तेलों को केवल वजन के हिसाब से पैक करना होता है । तथापि, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से प्राप्त एक अनुरोध पर कि उनके लिए तकनीकी कारणों से खाद्य तेलों को उक्त नियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मानक मात्राओं में टेट्रापैकों में पहले पैक करना सम्भव नहीं है, उन्हें कुछ विनिर्दिष्ट मात्राओं में आयतन (बॉल्यूम) के अनुसार टेट्रापैक में खाद्य तेलों को पैक करने की अनुमति दे दी गई है । इस मामले पर पुनर्बिचार किया जा रहा है ।

बोस्टास तथा पंजाब एघो उद्योग निगम के खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र का अधिग्रहण

8942. श्री जेम्सराजभाई सोमजीराई चावड़ा :

श्री मानिक सग्याल :

श्री एम० एस० पाल :

श्री के० प्रधानी :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अबोहर में बोस्टास का फल संसाधन संयंत्र और पंजाब एघो उद्योग निगम को हस्तान्तरित किया गया है;

(ख) क्या इसे पेप्सी फूड्स ब्रांडों ने अधिग्रहीत कर लिया है; और

(ग) यदि हां तो उसका विवरण क्या है ?

बस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रमिकों की मजदूरी

8943. श्री आर० एन० राकेश :

श्री भाषिकराव होडल्या गाबित :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजधानी में कार्य कर रहे, श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) उपयुक्त प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने, न्यूनतम मजदूरी दरों को निर्धारित/संशोधित करते समय, जो पहली मई, 1989 से लागू हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि में प्वाइन्ट 85 पैसे की दर से परिवर्ती महंगाई भत्ता शुरू करने का निर्णय लिया है तथा उसकी घोषणा हर वर्ष फरवरी तथा अगस्त माह में की जाएगी। यह महंगाई भत्ता जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि को निष्प्रभावी करेगा तथा न्यूनतम मजदूरी दरों में हर तीन वर्ष में संशोधन किया जाएगा।

चिकित्सा की "सिद्ध प्रणाली"

8944. श्री एन० डेनिस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चिकित्सा पद्धति "सिद्ध प्रणाली" के विकास के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) सरकार ने सिद्ध चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए हैं :

- (i) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद सिद्ध चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान कार्यक्रम चला रही है। परिषद के अधीन 14 संस्थाएं/यूनिट्स इस चिकित्सा पद्धति के अनुसंधान कार्य में लगी हुई हैं।

- (ii) राजकीय सिद्ध चिकित्सा पद्धति कालेज, पलायामकोट के दो विभागों को मरुयुवम और गुणपदम में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए समुन्नत किया गया है।
- (iii) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लाभाषियों को सिद्ध चिकित्सा पद्धति के अनुसार उपचार प्रदान करने के लिए मद्रास और नई दिल्ली में एक-एक यूनिट खोले गए हैं।
- (iv) इस चिकित्सा पद्धति की औषधियों की मानक फार्मूलरी और फार्माकोपिया तैयार करने के लिए एक सिद्ध फार्माकोपिया समिति गठित की गयी है। सिद्ध फार्मूलरी का पहला खंड पहले ही प्रकाशित हो चुका है।

फाइलेरिया नियन्त्रण हेतु कदम

8945. श्री ए० चार्ल्स : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या देश में राष्ट्रीय फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है;
- (ख) यदि हां, तो फाइलेरिया नियन्त्रण तथा इसके उन्मूलन हेतु कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु केरल को, वर्षवार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;
- (घ) केरल में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार फाइलेरिया के कितने मामले सामने आए हैं;
- (ङ) क्या जिन मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है उनकी संख्या में कोई कम हुई है; और
- (च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी, हां। इस समय राष्ट्रीय फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम 13 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के 204 कस्बों में चल रहा है। देश में, जिसमें केरल शामिल है जहां दो सर्वेक्षण यूनिटें और 9 क्लिनिक कार्य कर रहे हैं, फाइलेरिया स्थिति की मानिट्रिंग करने और फाइलेरिया रोगियों का उपचार करने के लिए क्रमशः 27 सर्वेक्षण यूनिटें और 192 क्लिनिक भी कार्य कर रहे हैं।

(ग) केरल राज्य को पिछले तीन वर्षों के दौरान नकद और सामग्री रूप में दी गई केन्द्रीय

सहायता इस प्रकार है :—

(लाख रुपए में)

वर्ष	नकद	सामग्री रूप में	योग
1987-88	5.00	11.53	16.53
1988-89	1.00	7.74	8.74
1989-90	1.00	8.77	9.77

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जांची गई रक्त स्लाइडों और पाए गए एम० एफ (माइक्रो-फाइलेरिया बाह्य) रोगियों और इस रोग के रोगियों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	जांचे गए रोगियों की संख्या	एम० एफ० के लिए एन० ओ० + बी० ई०	रोग के लिए एन० ओ० + बी० ई०
1987	109323	2160	1552
1988	82607	1334	1019
1989	57609	885	631

(ङ) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान माइक्रोफाइलेरिया बाह्यों और इस रोग के रोगियों, दोनों की संख्या में निरन्तर कमी हुई है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोटा के बितरण के लिए मापदण्ड

8946. श्री इरा अन्वारसु : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपयुक्त निर्यातकों को गारमेट एक्सपोर्ट इन्स्टिट्यूट्स के बितरण के लिए निर्धारित मापदण्डों, दिशानिर्देशों का ब्योरा क्या है; और

(ख) इस सन्दर्भ में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद की क्या भूमिका है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) वर्ष 1988 से 1990 तक के लिए परिधान कोटाओं के बितरण के लिए निर्धारित मानदण्ड और मार्गदर्शी सिद्धांतों के ब्योरे दिनांक 15 अक्टूबर, 1987 की सार्वजनिक सूचना संख्या 28-ई० सी० टी० (पी० एन०)/87 में दिए गए हैं जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) अर्पण निर्यात संवर्धन परिषद एक ऐसी एजेंसी है जो कि सरकार द्वारा घोषित परिधान निर्यात हकदारी बितरण नीति का संचालन करती है।

सिक्किम के लिए पाम आयल कोटा की मंजूरी

8947. श्री मन्वू थापा : क्या और नागरिक पूति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सिक्किम के लिए पाम आयल और रेपसीड आयल का मासिक कोटा मंजूर किया है; और

(ख) यदि हां, तो मासिक कोटे की मात्रा और इसे निर्धारित करने की तिथि क्या है ?

ज्ञात और नागरिक पूति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किया जाने वाला खाद्य तेलों का आबंटन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गयी मांग, सरकार के पास उपलब्ध आयातित खाद्य तेलों के भण्डार, बाजार में देशीय तेलों की उपलब्धता और उनके मूल्यों तथा राज्यों को पहले आबंटित किए गए तेलों को उठाने की गति पर निर्भर करते हुए माह-दर-माह आधार पर किया जाता है। उपर्युक्त बातों के आधार पर सिक्किम को पामोलीन तेल का आबंटन मई, 1990 के लिए 100 मी० टन के स्तर पर नियत किया गया है। इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए रेपसीड तेल का आयात नहीं किया जा रहा है।

केन्द्रीय भण्डारों को अनुवेश

[हिन्दी]

8948. श्री सूर्य नारायण थापन :

श्री राजबौर सिंह :

क्या ज्ञात और नागरिक पूति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में वसन्त विहार स्थित केन्द्रीय भण्डार को एक महीने में केवल दो बार राशन लेने के लिए अनुदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ज्ञात और नागरिक पूति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय भण्डारों द्वारा चलाई जाने वाली दुकानों सहित सभी उचित दर की दुकानों को गेहूं और चावल की आपूर्ति पाकिस्तान आधार पर तथा लेबी चीनी की आपूर्ति मासिक आधार पर की जाती है।

(ख) भण्डारण सम्बन्ध अवरोधों तथा समय पर उनकी दुलाई की बात को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान रूप से आपूर्ति करने का निर्णय किया गया है।

मातृत्व के दौरान मृत्यु दर की अधिक प्रतिसतता

[अनुबाध]

8949. डा० बीलतराव सोमजी अहेर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "इंटरनेशनल प्लाण्ड पैरेस्ट्रुड फीडरेसन" ने बताया है कि भारत में मातृत्व के दौरान मृत्यु दर बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो मातृत्व के दौरान ऊंची मृत्यु दर के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने मातृत्व के दौरान मृत्यु दर कम करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा मांगर बिमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी हां। देश में जच्चा मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्मे बच्चों के पीछे 4 से 5 तक होने का अनुमान है।

(ख) जच्चा मृत्यु दर की ऊंची प्रतिशतता के कारण रक्ताल्पता, गर्भावस्था और प्रासविकता के कारण रक्त बहना, गर्भावस्था की विषरक्तता, प्रासविक पूतितता, गर्भापात इत्यादि हैं।

(ग) जच्चा मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य नेटवर्क का विस्तार करने, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, दाइयों के प्रशिक्षण, प्रसूति कीटों इत्यादि की सप्लाई के लिए राज्य क्षेत्र योजना के अंग और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए हैं। प्रदान की गयी सेवाओं में गर्भावस्था, प्रसव काल के दौरान और प्रसवोत्तर अवधि में महिलाओं की परिचर्या है। परोबार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रसवोत्तर योजना का विस्तार और रोग प्रतिरक्षण के लिए योजनाओं के कार्य में तेजी लाना, आई० सी० डी० एस० के अन्तर्गत पोषणिकता रक्ताल्पता के विरुद्ध रोग निरोधक और पूरक पोषण जच्चा मृत्युदरों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कृष्णक अन्य कदम हैं।

खाड़ी के देशों में भारतीय श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करने
गए दल की रिपोर्ट

8950. श्री टी० बशीर : क्या भ्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाड़ी के देशों में भारतीय श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु वहाँ गए दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

भ्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) शिष्टमण्डल ने प्रक्रियाओं के सरलीकरण, कृषि श्रमिकों को भेजने, मजदूरी निर्धारण आदि के बारे में विभिन्न सिफारिशें कीं।

(ग) ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

पालिएस्टर स्टेपल फाइबर/यार्न की कीमतें

8951. श्री शान्तिलाल पुष्कोलम दास पटेल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान पालिएस्टर मिश्रित धागों की कीमतें क्या रहीं हैं;

(ख) इनकी कीमतें बढ़ने का क्या औचित्य है;

(ग) क्या हाल ही में पालिएस्टर स्टेपल फाइबर (बी० एस० एफ०) की कीमतों में कमी हुई है जबकि मिश्रित धागों की कीमतों में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो मिश्रित धागों की कीमतों को कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) पिछले एक वर्ष के लिए पालिएस्टर ब्लैंडिड यान की तिमाही कीमतें निम्नोक्त प्रकार हैं :

(रु० कि० ग्राम)

अवधि	पालिएस्टर/बिस्कोस ब्लैंडिड यान (विभिन्न ब्लेंड्स के लिए औसत)	पालिएस्टर/शुद्धी ब्लैंडिड यान (पालिएस्टर 65% और काटन 35%)
मार्च, 1989	76.29	103.00
जून, 1989	90.94	108.56
सितम्बर, 1989	100.77	123.67
दिसम्बर, 1989	99.67	117.56
मार्च, 1990	110.05	125.44
मई, 1990	109.28	120.56

(5.590 के अनुसार)

(ख) मांग और पूर्ति केवल कीमतों का निर्धारण करते हैं।

(ग) दिसम्बर, 1989 से मार्च, 1990 तक पालिएस्टर स्टेपल फाइबर की कीमतों में 17.41 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि इसी अवधि के दौरान पालिएस्टर बिस्कोस ब्लैंडिड ब्लेन्ड के मामले में पालिएस्टर ब्लैंडिड यान की कीमतों में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और पालिएस्टर/काटन ब्लैंडिड यान के मामले में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथापि, मार्च, 1990 से 5 मई, 1990 तक पालिएस्टर ब्लैंडिड यान की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट आई। इस समय पालिएस्टर ब्लैंडिड काटन यान की कीमत सितम्बर, 1989 की कीमत से कम है।

(घ) सरकार ने यान की कीमतों पर कोई प्रशासनिक नियन्त्रण नहीं जगया है लेकिन स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है।

रोजगारोन्मुख योजना का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

8952. डा० बंगाली सिन्हा : क्या अन्न संघों यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के भारत में रोजगारोन्मुख योजना के कार्यान्वयन में सहायता देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

अन्न और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कुष्ठ रोगियों की समस्याएं

[अनुवाद]

8953. श्री एम० जे० रायबा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ रोगियों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) इस समिति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, और वह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से भी इस प्रकार की समितियां गठित करने को कहा है ?

ऊर्जा मंत्री तथा आचर विमानन मंत्री (श्री ज्ञानिण श्रीहनुमन्त ज्ञान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत यूनानी अस्पताल

8954. श्री जी० एच० बजाजबाबा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत यूनानी औषधालय और अस्पताल है; और

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों में ऐसे औषधालय हैं तथा शेष राज्यों में ऐसे औषधालय स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कोई यूनानी अस्पताल कार्य नहीं कर रहा है। तथापि, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित यूनानी औषधालय/यूनिट कार्य कर रहे हैं :—

कवर किए गए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	औषधालयों की संख्या	यूनिटों की संख्या	कुल
आन्ध्र प्रदेश	1	1	2
उत्तर प्रदेश	—	1	1
संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली	1	3	4
कुल :	2	5	7

शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर क्रमिक रूप से कवर किया जाएगा।

असम के चाय बागान श्रमिक

8955. श्री जे० चोका राव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में चाय बागानों में कितने श्रमिक कार्यरत हैं;

(ख) श्रमिकों की मजूरी दरें क्या हैं और उनके कल्याण के लिए और क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में असम संयुक्त मुक्ति मोर्चा (उल्फा) की गतिविधियों के फलस्वरूप की गई तालाबन्दी के कारण कितने श्रमिक बेरोजगार हुए हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पटपड़गंज में भूमिगत पंदल पार पथ

8956. श्री एम० एस० पाल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-92 में पटपड़गंज रोड के रेल-फाटक पर एक भूमिगत पंदल पार पथ का निर्माण करने के लिए जनता से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

सहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली चारन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि पुल के नीचे सड़क का प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया है।

आयुर्वेदिक कालेजों/संस्थानों को सहायता अनुदान

[हिन्दी]

8957. श्री रेशम लाल झांगड़े : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक आयुर्वेदिक कालेज/संस्थानों को संस्थान-वार कितना सहायता अनुदान दिया गया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : पिछले 3 वर्षों के दौरान आयुर्वेदिक कालेजों/संस्थानों को दिया गया सहायता अनुदान का वर्षवार और संस्था-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयुर्वेदिक कालेजों/संस्थानों को दिया गया वर्ष-वार और संस्थान-वार अनुदान

वर्ष	संस्थान का नाम	अनुदान की धराराशि
1	2	3
1987-88	दयानन्द आयुर्वेद मेडिकल कालेज, बिहार, सिवान	1.60 लाख रुपये
	हबली आयुर्वेद सेवा समिति, हबली, कर्नाटक	1.60
	श्री बी० एम० कन्कनबाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय, शाहपुर, बेलगांव, कर्नाटक	1.60
	नितीश्वर भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, आयुर्वेदिक मुजफ्फरपुर, बिहार	1.60
1988-89	श्री अंबरलाल आयुर्वेद विश्व भारती, सरदार शेर, चुरू (राजस्थान)	1.60
	आर्य वैद्यन रामा बेरियर शैक्षणिक प्रतिष्ठान, कोयम्बेत्तूर (तमिलनाडु)	1.60

1	2	3
	एस० एन० एन० आयुर्वेदिक कालेज एवं अनुसंधान संस्थान, पाइकमल (उड़ीसा)	1.60 लाख रुपए
	गौड़ ब्राह्मण वैद्य परिचरणी सभा, रोहतास	1.60
	केरल आयुर्वेदिक एवं अनुसंधान सोसाइटी कोट्टाक्कल (केरल)	1.60
1989-90	स्वामी कल्याणदेव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश	1.60
	यूनानी मेडिकल कालेज, पुणे	1.60
अन्य संस्थानें		
1987-88	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	161.95
	केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	528.69
	स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर	104.00
1988-89	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	202.00
	केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	553.47
	स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर	114.29
1989-90	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	181.00
	केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	671.00
	स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर	172.00

राज्यीय एवं निजी

[अनुवाद]

8958. श्री सी० पी० नुबाल विरिदीया :

श्री श्री० कृष्ण राव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने यह बताया है कि रागी एक बहुत ही पोषक आहार है;

(ख) क्या यह विशेषरूप से मधुमेह के रोगियों के लिए उत्तम आहार है;

(ग) क्या रागी का निर्यात करने के प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

इसकी संबंधी तृतीय नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि रागी एक पोषक आहार है ।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से मिली सूचना के अनुसार ऐसे कुछ प्रमाण हैं जिनसे पता चलता है कि रागी मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा आहार है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान 15,000 मीट्रिक टन कोटे के निर्यात की घोषणा की गई थी जिसमें से कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कुल 217,500 मीट्रिक टन तक की सीमा की पूर्ति जारी की जिसकी कीमत 7.57 लाख रुपए है । वर्ष 1990-91 के लिए 15,000 मीट्रिक टन के कोटे की घोषणा की गई है । तथापि, चालू वर्ष के दौरान अभी तक कोई कोटा जारी नहीं किया गया है ।

डी० डी० ए० कालोनियों को दिल्ली नगर निगम को सौंपना

8959. श्री प्रतापराव डी० भीसने : क्या सहरी विकास मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डी० डी० ए० कालोनियों में समय-समय पर नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उन्हें दिल्ली नगर निगम को सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो 30 अप्रैल, 1990 तक सौंपी गई ऐसी कालोनियों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का कुछ और कालोनियां दिल्ली नगर निगम को सौंपने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सहरी विकास मंत्री (श्री मुदासोली आरब) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में उद्यान सेवाओं को छोड़कर सेवाओं का अनुरक्षण कार्य समय-समय पर दिल्ली नगर निगम को सौंपा जाता है । दिल्ली नगर निगम को 1976 से सौंपी गई ऐसी कालोनियों के विवरण इस प्रकार है :—

क्रम सं०	वर्ष	दिल्ली नगर निगम को सौंपी गई दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियां/पाकेटों की संख्या
1.	1976	11
2.	1980	75
3.	1983	32
4.	1989	108

(ग) और (घ) भावी अनुरक्षण के लिए दिल्ली नगर निगम को सौंपने-सौंपने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण की 311 और कालोनियां निर्धारित की गई हैं।

पंजाब में चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र

8960. श्री कमल चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार का विचार पंजाब में चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;
 (ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और
 (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री तथा मांगर बिमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पंजाब में एक और चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र खोलने के किसी प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार नहीं कर रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का पंजाब कृषि विषयविद्यालय, लुधियाना के प्राणि विज्ञान विभाग में मौलिक प्रजनन जीव विज्ञान का एक समुन्नत केन्द्र है।

नवजात शिशुओं की चोरी

[हिन्दी]

8961. श्री राजवीर सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में नवजात शिशुओं की चोरी तथा इनकी अदला-बदली के बारे में कितनी शिकायतें वर्ष 1989 के दौरान तथा मार्च, 1990 तक दर्ज की गई हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में तत्काल कानूनी कार्यवाही आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाए गए तथा इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) बोधी पाए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जून, 1989 में, श्री पी० शर्मा ने एक शिकायत की थी कि उनकी पत्नी ने एक जीवित बच्चे को जन्म दिया जिसे एक मृत-जात बच्चे से बदल दिया गया। तथापि, जांच-रिपोर्ट के अनुसार, श्री शर्मा की पत्नी को एक मृत बच्चा हुआ था और बच्चे के बदल-बदल किए जाने जैसी कोई बात नहीं थी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

“नगर मूल सेवाएं” योजना

[अनुवाद]

8962. श्री बी० एम० रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ चुनिन्दा जिलों में निम्न आय वाले परिवारों की महिलाओं तथा बच्चों के जीवन-स्तर में सुधार करने तथा उनका विकास करने के लिए सातवीं योजना के दौरान कोई “नगर मूल सेवाएं” योजना कार्यान्वित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन जिलों का चयन किया गया था तथा इनमें से प्रत्येक पर कितनी धन-राशि खर्च की गई थी; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री सुरासोली भारग) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्र सरकार द्वारा दी गई निधियों तथा उनमें चुने गए जिले संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) योजना की प्रमुख उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

महिलाएं तथा शिशु

1 वर्ष से कम आयु के 1.67 लाख शिशुओं को ओ० पी० बी०, बी० सी० जी०, डी० पी० टी० तथा खसरा निरोधी टीके लगवाए गए।

लगभग 38,000 गर्भवती महिलाओं को टिटनेस निरोधी टीके लगवाए गए।

लगभग 600 दाईयों को प्रशिक्षित करवाया गया।

लगभग 1.03 लाख बच्चों को आंगनवाड़ी/बालवाड़ी/शिशुरक्षण गृहों तथा प्राथमिक स्कूलों में स्वास्थ्य परीक्षा की गई।

स्वास्थ्य रक्षा

1.32 लाख ब्यस्कों को घर पर अतिसार के बरेलू उपचार में शिक्षित किया गया।

लगभग 30,000 ब्यस्कों को प्राथमिक उपचार प्रदान करने के कार्य में प्रशिक्षित किया गया।

लगभग 1.58 लाख स्लम निवासियों ने स्वास्थ्य शिक्षा सत्र में भाग लिया।

जल आपूर्ति तथा सामुदायिक स्वच्छता

- लगभग 9.00 हैण्ड पम्प लगाए गए हैं ।
- लगभग 9000 शौचालयों सीटों का निर्माण किया गया है ।
- लगभग 6680 रोशनदान/हवाकश लगाए गए हैं ।
- लगभग 24,000 घुआंरहित चूल्हे स्थापित किए गए ।

स्कूल पूर्व तथा गैर औपचारिक शिक्षा

- 3 लाख से अधिक बालवाड़ी बच्चे सम्पूरक खाद्य प्राप्त कर रहे थे ।
- 9000 से अधिक स्कूल पूर्व बच्चों को सहायता दी गई है ।
- लगभग 2800 साक्षरता केन्द्रों को सहायता दी गई है, जिसमें 38,000 महिलाओं ने भाग लिया ।

आय उत्पादक क्रियाकलाप

लगभग 27,000 महिलाओं को आय उत्पादक क्रियाओं में प्रशिक्षित किया गया है ।

सामुदायिक स्ट्रीक्वर्स का विकास

51,000 से अधिक निवासी सामुदायिक स्वयंसेवक (आर० सी० बी०) 3300 अधिक पड़ोसी समितियों में शामिल हुए हैं ।

विवरण

शहरी मूलभूत सेवा योजना के अन्तर्गत लाभान्वयन के लिए शिनास्त किए गए जिलों के नाम दी गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला	जारी की गई राशि				जोड़
		86-87	87-88	88-89	89-90	
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	मैहबूब नगर अनछीपुर कुडप्पा नलगोड़ा भी काकुलन	5.60	13.60	11.90	11.80	42.80

1	2	3	4	5	6	7
बसम	कामस्य	0.90	—	3.40	3.40	7.70
बिहार	पटना	—	6.80	—	7.60	14.40
गुजरात	धड़ोदा राजकोट	—	—	—	10.90	10.90
हरियाणा	फरीदाबाद	3.55	—	—	3.00	6.55
हिमाचल प्रदेश	ऊना	—	—	2.00	2.00	4.00
जम्मू कश्मीर	अनन्तनाग	2.50	2.00	2.10	2.40	8.80
केरल	इंभोरकुंजम अल्मपी	2.76	—	11.76	7.50	22.02
कर्नाटक	तमकुर	3.70	—	5.70	7.80	17.20
महाराष्ट्र	रत्नागिरि सिन्धुदुर्ग	3.70	—	—	—	3.70
मणीपुर	ईम्फाल	0.60	—	—	1.97	2.57
मध्य प्रदेश	इन्दौर	2.76	—	3.20	3.20	9.16
मेघालय	पूर्वाखासी हिल	—	5.20	—	—	5.20
नागालैंड	कोहिमा	—	—	—	—	—
उड़ीसा	सम्भलपुर पुरी कालाहांडी खोंसर बालागिरि सुनारगढ़	7.00	20.18	23.81	17.20	69.19
पंजाब	झुझियाना	3.40	3.00	9.40	9.10	24.90
राजस्थान	भिलवाड़ा बांस-वाड़ा	5.60	—	5.60	6.50	17.70
तमिलनाडु	तन्जावर	2.77	—	—	3.00	5.77
त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा	—	—	3.20	1.60	4.80
उत्तर प्रदेश	मन्थनऊ	—	—	2.85	4.00	6.85
पश्चिम बंगाल	दार्जीलिंग	2.76	2.00	—	2.30	7.06
पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी कराईकाल	1.60	—	—	1.00	2.60
दिल्ली	दिल्ली	—	3.00	6.70	6.70	16.40

तमिलनाडु में आदिवासी विकास योजना

8963. श्री एम० सेल्वारराजु : क्या अम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के आरम्भ के समय से तमिलनाडु में आदिवासी विकास के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों एवं दृष्टिकोणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम के आरम्भ के समय से इसके वास्तविक सक्ष्यों एवं उपलब्धियों का, वर्ष-वार तथा जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान मूल्य स्तर पर तथा इस कार्यक्रम के आरम्भ के समय से सम्बन्धित वर्षों के मूल्य-स्तरों पर भी आर्बिट्रिट धनराशि तथा उपलब्धियों का, वर्ष-वार तथा जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

अम और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) से (ग) तमिलनाडु राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा फर्नीचर सप्लाई करने के आर्डर

[हिन्दी]

8964. श्री जगदीश तिवारी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीनों के दौरान संसद सदस्यों के फ्लैटों के रख-रखाव के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के संसद निर्माण कार्य प्रभाग सं० 1 द्वारा फर्नीचरों और विभिन्न मर्चों की सप्लाई के लिए कितने क्रयादेश दिए गए और सिविल कार्य निष्पादन हेतु कितने ठेके प्रदान किए गए;

(ख) इनमें से कितने क्रयादेशों के मामले में नियमित निविदाएं आमन्त्रित की गईं और कितने मामलों में सीधे क्रयादेश दिए गए;

(ग) क्या बाद में इन क्रयादेशों की मूल शर्तों में कोई संशोधन किया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इसके फलस्वरूप वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी आई है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक क्रयादेश में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री बुरासोली मारन) : (क) 1-11-89 से 30-4-90 तक छः महीने की अवधि के लिए 239 ।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार है :—

	कुल संख्या
टैंडरों को आमन्त्रित करने के पश्चात् करार	57
दरें आमन्त्रित करने के पश्चात् कार्य आदेश	71
दरें आमन्त्रित करने के पश्चात् सप्लाई आर्डर	110
प्रत्यक्ष आर्डर (परन्तु प्रापण नहीं किया गया और आर्डर रद्द किया गया)	1
जोड़ :	239

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

धारीवाल बूलन मिल के स्वामित्व वाली भूमि

[अनुवाद]

8965. श्रीमती सुखबंस कौर : क्या बस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू इगर्टन बूलन मिस्त, धारीवाल के स्वामित्व में कितनी भूमि है;

(ख) इस भूमि का किस उद्देश्य हेतु उपयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या भूमि का कुछ भाग किसी धार्मिक स्थल के निर्माण हेतु दिया गया है; और

(घ) मिल की भूमि को किराए पर अथवा पट्टे पर देने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है ?

बस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) न्यू इगर्टन बूलन मिस्त बांध, धारीवाल के स्वामित्व में लगभग 180.61 एकड़ भूमि है।

(ख) भूमि का उपयोग औद्योगिक उद्देश्यों, आवासीय भवनों और साथ ही कर्मचारियों के कल्याण के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में किया जाता है।

(ग) 11-6-1981 से इस कम्पनी के सरकारी कम्पनी बन जाने के बाद से किसी भी नई भूमि को धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए आवंटित नहीं किया गया है।

(घ) मिल के प्रबन्धकों की सिफारिश के आधार पर निदेशक बोर्ड द्वारा गुणावगुण आधार पर अलग-अलग मामलों पर विचार किया गया है।

अनिवासी भारतीयों को फ्लैटों/भूखण्डों का आवंटन

8966. श्री प्रेम प्रवीण : क्या सहरो विकास मंत्री सर्वप्रिय हाउसिंग विलिजिंग सोसाइटी द्वारा अनिवासी भारतीयों को फ्लैट/भूखण्डों के आवंटन के बारे में 2 मई, 1990 के अतारंकित प्रश्न संख्या 7080 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सोसाइटी में फ्लैटों/भूखण्डों के निरसन किस तारीख को पंजीयक, सहकारी समिति को अधिसूचित किए गए थे तथा प्रत्येक ऐसे मामले में पंजीयक, सहकारी समिति द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है तथा प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) भूखण्डों/फ्लैटों को खाली करवा कर वापस सोसाइटी को दिलवाने में दिल्ली विकास प्राधिकरण की तुलना में पंजीयक, सहकारी समिति की अब तक क्या भूमिका रही है;

(ग) क्या सोसाइटी को दो भागों में बांटने का मामला पंजीयक, सहकारी समिति के पास नथित पड़ा है; यदि हां, तो कब से;

(घ) पंजीयक द्वारा इस बारे में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में मंजूरी कब तक दी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्री (श्री भुवनेश्वरी भारगव) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) पंजीयक, सहकारी समिति केवल दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972, इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और समितियों के उप-नियमों और समितियों के उल्लंघन से अन्तर्ग्रस्त मामलों में कार्रवाई करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण भूखण्ड का आबंटन रद्द किए जाने के पश्चात् लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के तहत बेदखली के लिए कार्रवाई करने की भूमिका निभाता है। फ्लैटों के मामले में कार्रवाई केवल समिति द्वारा की जा सकती है।

(ग) दिसम्बर, 1987 से।

(घ) समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की जांच की गई थी और इसे अपूर्ण पाया गया था। संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हो गया है।

(ङ) निर्णय के लिए कोई समय-सीमा बताना सम्भव नहीं है।

विवरण

क्रम फ्लैट/प्लॉट संख्या और सं० आबंटित की का नाम	पंजीयक, सहकारी समिति को निरसन (कंसलेशन) की सूचना देने की तारीख	पंजीयक सहकारी समितियों द्वारा की गई कार्रवाई	विद्यमान स्थिति/टिप्पणी
1	2	3	4
1. फ्लैट नं० 404 श्री सी० एल० मल्होत्रा	14-4-1988		चूंकि मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है इसलिए, कोई कार्रवाई करना सम्भव नहीं है।
2. फ्लैट नं० 703 धोमती शारदा बेहता	5-4-1989		कोई कार्रवाई लम्बित नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत निर्माण हटाया गया। आगे की कार्रवाई समिति द्वारा की जानी है।
3. फ्लैट नं० 708 श्री राजिन्द्र कुमार गुप्ता	22-2-1988		वही आगे की कार्रवाई समिति द्वारा की जानी है।

1	2	3	4	5
4.	फ्लैट नं० 607	3-12-1988	शून्य	श्रीमती कोहली को प्लाट नं० 45 न्यू फैंस कोसोनी और संबंधित बिहार में उनकी सवस्यता-धारण फ्लैट आर्बंटन के लिए भी अनुमति दी जा चुकी है।
5.	फ्लैट नं० 204-ए श्रीमती अनुराधा सोई	उनका मामला, अन्तिम निर्णय के लिए पंजीयक, सहकारी समिति के सम्मुख लम्बित है।		
6.	फ्लैट नं० 108 श्री दीपक मल्होत्रा	उनका मामला, अन्तिम निर्णय के लिए पंजीयक, सहकारी समिति के सम्मुख लम्बित है।		
7.	प्लाट नं० 10/11, श्रीमती धनदेवी कपूर	14-4-1988	चूंकि, मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित है इसलिए, कोई कार्रवाई करना सम्भव नहीं है।	
8.	प्लाट नं० 10/7 श्रीमती रश्मि नागरथ		चूंकि, मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित है इसलिए, कोई कार्रवाई करना सम्भव नहीं है।	
9.	प्लाट नं० 10/10 श्री राम कुमार कपूर		चूंकि, समिति से कतिपय स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है, इसलिए, सवस्यता समाप्त करने की कार्रवाई नहीं की जा सकती।	

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ताओं के पदों को भरना

8967. श्रीमती गीता मुलर्जी : क्या शाहरी विकास अंशो यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ताओं (सिविल) के पद विभागीय प्रोन्नति द्वारा भरे गए हैं; यदि हां, तो उनकी वर्षवार संख्या क्या है;

(ख) क्या सहायक अभियन्ता के पद के भर्ती नियमों में एक फीडर संवर्ग से प्रोन्नति की विभिन्न पद्धतियों का प्रावधान है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रोन्नति की प्रत्येक पद्धति द्वारा कितने सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति की गई है तथा सामान्य श्रेणी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रत्येक कलेंडर वर्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभियन्ताओं के लिए सहायक अभियन्ताओं के आरक्षित पदों का पता लगते समय आगे ले जाने सम्बन्धी नियम लागू किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान प्रत्येक कलेंडर वर्ष में उपलब्ध ऐसे आरक्षित पदों की संख्या कितनी है ?

सहूरी विकास मंत्री (श्री सुरासोली भारन) : (क) जी, हां। वर्ष-वार रिक्तियां, जिनके प्रति पदीन्नति की गई है, इस प्रकार है :—

1987	1988	1989
478	37	1

(ख) इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सहायक इंजीनियरों (सिविल) के पद निम्नलिखित किसी भी पद्धति द्वारा भरे जाने हैं :—

(1) भारत में प्रतियोगी परीक्षा द्वारा (1-4-72 से आस्यगित)।

(2) पदीन्नति द्वारा।

(1) 50% केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की सिविल इंजीनियरी शाखा में नियोजित स्थायी कनिष्ठ इंजीनियरों में से गुणावगुण (मेरिट) आधार पर चयन द्वारा; और

(2) 50% केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की सिविल इंजीनियरी शाखा में नियोजित कनिष्ठ इंजीनियरों में से चयन द्वारा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात् सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधर पर, जो संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

(ग) सहायक इंजीनियर (सिविल) के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

वर्ष	नियुक्त किए गए सहायक इंजीनियरों की कुल संख्या			योग
	साधान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	
1987	341	92	4	437*
1988	33	3	—	36
1989	1	—	—	1

*इसमें हुए "भ" की संयोग पुर्नरीक्षा के परिणामसंकरण संज्ञित किए गए पद शामिल हैं, जो भर्ती नियमों को शिथिल करते हुए चयन द्वारा भरे गए थे।

समित्वि विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा :—

वर्ष	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जम्माजाति	योग
1987	7	29	5	41
1988	1	—	—	1
1989	—	—	—	—

(घ) विद्यमान अबुवशों के अनुसार सहायक इंजीनियर (सिविल) के ग्रेड में खयन द्वारा पदोन्नति के मामले में किमी वर्ष-विशेष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के अभ्यर्थी ब्यपित संख्या में उपलब्ध न होने की दशा में आरक्षण को वर्ष प्रति वर्ष आगे नहीं ले जाया जाएगा। तस्मात्, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पदोन्नति के मामले में आरक्षणों को अनुवर्ती तीन वर्षों के लिए आगे ले जाया जाता है।

(ङ) चूँकि, आगे ले जाने का नियम केवल सीमित विभागीय परीक्षा के जरिए भरे गए पद के बारे में लागू है, आगे ले जाए गए पदों की उपलब्ध संख्या इस प्रकार है :—

अनुसूचित जाति—29

अनुसूचित जन-जाति—24

राष्ट्रीय बी०सी०जी० टीका कार्यक्रम

[हिन्दी]

8968. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के क्षयरोग निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाए जा रहे राष्ट्रीय बी० सी० जी० टीका कार्यक्रम को बहुदृशेय टीका कार्यक्रम में मिला दिया गया है;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत बिहार के स्वास्थ्य विभाग के सभी कमचारियों को बी० सी० जी० टीका कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षित किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को बिहार में भी कार्यान्वित करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो कब से; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) 1985 में आरम्भ किए गए व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में बी० सी० जी० टीकाकरण भी एक एग्योजन के रूप में शामिल है।

(ख) बिहार राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम सारे देश में चलाया गया है जिसमें बिहार राज्य भी शामिल है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

सिनेमा कामगरों के लिए कल्याण कोष

[अनुवाद]

8969. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या अम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म फेडरेशन ऑफ इण्डिया ने सभी श्रेणियों के सिनेमा कामगरों की मदद के लिए कल्याण कोष गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) उक्त कोष में इस समय प्रत्येक फिल्म निर्माता द्वारा कितना अंशदान किया जा रहा है; और

(घ) इस कल्याण कोष के गठन और इसे विनियमित करने में सरकार की भूमिका क्या है ?

अम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, फिल्म फेडरेशन आफ इण्डिया ने सिनेमा कर्मकारों की सहायता के लिए कोई कल्याण निधि गठित नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की उपलब्धियाँ

8970. श्री ललत कुमार शंकर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के क्रियान्वयन हेतु, कितनी पूंजी परिव्यय का अनुमान है;

(ख) यह राशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा मांगी गई पूंजी से कितनी कम है; और

(ग) स्वतः पूर्ण प्राथमिक कस्बों और दिल्ली महानगर क्षेत्र के कस्बों तथा दिल्ली में आने वाले लोगों की सम्भावित संख्या को अपनी ओर आकर्षित करने वाले इस क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए किए जाने वाले उपायों का विशेषरूप से उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को प्रबन्ध योग्य रखने और उसके सन्तुलित विकास के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अब तक क्या कारगर कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुराली भारन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए 2900 करोड़ रुपए (1750 करोड़ रुपए केन्द्रीय क्षेत्र में और 1150 करोड़ रुपए राज्य क्षेत्र में) की निवेश योजना तैयार की है। आठवीं योजना के केवल

प्रथम वर्ष (अर्थात् 1990-91) के लिए नियतन किए गए हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपए मुहैया किए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पढ़ने वाले नगरों में रिहायशी, औद्योगिक, वाणिज्यिक, औपचारिक क्षेत्र के विकास और आधारभूत सुविधा विकास के लिए कई परियोजनाओं को 117 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

8971. श्री रामचौलाल सुमन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में, क्षेत्रवार तथा टाईप-वार, केन्द्रीय सरकार के आवासीय क्वार्टरों की संख्या कितनी है;

(ख) दिल्ली/नई दिल्ली में प्रत्येक टाईप के लिए पात्र केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में क्वार्टरों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली में और अधिक संख्या में क्वार्टरों का निर्माण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी श्रेणी-वार तथा स्थान-वार ब्योरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में टाईप-वार सामान्य पूल रिहाइश दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) मांग पर निर्भर रहते हुए इन ब्योरों में समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इन्हें इस समय प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

विवरण

दिल्ली नई दिल्ली में सामान्य पूल रिहाइशी बास (टाईपवार) की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	टाईप	मकानों की संख्या
1	2	3
1.	I	13,768
2.	II	20,512
3.	III	21,402

1	2	3
4.	IV	5,114
5.	V	1,932
6.	VI-स्पेशल	128
7.	VI	503
8.	VII	116
9.	VIII	97
कुल योग :		63,572

पूर्वी दिल्ली के झुग्गी निवासियों के लिए बैकल्पिक प्लान

[हिन्दी]

8972. श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी दिल्ली में विश्वासनगर, शाहदरा दिल्ली के निकट कड़कड़डूमा में झुग्गियां ढाई गई हैं;

(ख) क्या सरकार का उन्हें बैकल्पिक भूमि आवंटित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें बैकल्पिक भूमि कब तक आवंटित की जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) विश्वासनगर सांस्थानिक क्षेत्र के समीप कड़कड़डूमा में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर झुग्गियों तथा अर्ध-पक्के कमरों के रूप में नए अतिक्रमणों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 11-4-1990 को हटाया गया था।

(ख) और (ग) सार्वजनिक भूमि पर नए अवधिकृत निर्माण तथा अतिक्रमण न होने देना सरकार की नीति है और ऐसे मामलों में बैकल्पिक भूमि आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हरे काजू का खराब चले जाना

[अनुबाव]

8973. श्री मुहतापल्ली रामचन्द्रन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय ने प्रति वर्ष खराब चले जाने वाले हर काजू की मात्रा के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) क्या सरकार का हूरे काजू के उपयोग के लिए कोई कार्यक्रम/योजना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन लोगों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देने का है जो हूरे काजू पर आधारित उद्योग शुरू करना चाहते हैं ?

बस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने हूरे काजू के सम्बन्ध में एक योजना कार्यान्वित की है जिसमें हूरे काजू के उपयोग के विभिन्न तरीकों का प्रदर्शन करके हूरे काजू पैदा करने वालों में हूरे काजू के उपयोग को लोकप्रिय बनाना शामिल है।

जबकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के पास केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में हूरे काजू के प्रसंस्करण के लिए कोई एकक स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है, फल और सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 1990-91 हेतु योजना स्कीमें तैयार की गई हैं, जिनमें नए एककों को स्थापित करने एवं मौजूदा प्रसंस्करण एककों को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार के उपक्रमों/सहकारी उपक्रमों को वित्तीय/तकनीकी सहायता देना शामिल है।

केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद में हिन्दी का प्रयोग

[हिन्दी]

8974. श्री गंगाधर लोधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने की नीति के अनुरूप केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद, नई दिल्ली ने अपने दैनिक कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद, जो होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है, सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के लिए राजभाषा नीति का पालन कर रही है।

आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जनता निर्यात

[अनुचाच]

8975. श्री एम० एम० पल्लव रावू : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में उन खाद्य प्रसंस्करण एककों का विस्तृत ब्योरा क्या है, जो सांघित खाद्य निर्यात करते हैं;

(ख) किन मुख्य मुद्दों का निर्यात किया जा रहा है. इस प्रकार प्रतिवर्ष कितने मूल्य का निर्यात किया जा रहा है तथा किन-किन देशों की निर्यात किया जा रहा है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरे देश की तुलना में आंध्र प्रदेश से संसाधित छात्रों के निर्यात के आंकड़े क्या हैं ?

बस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) वाणिज्य मंत्रालय निर्यात के राज्यवार आंकड़े नहीं रखता ।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पुत्रवधुओं को सरकारी आवास के नियमन से सम्बन्धित नीति

8976. श्री गंगा चरण लोधी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार सरकारी आवास को नियमित करने के उन मामलों में कौन-सी नीति अपनाती है, जहां कोई सरकारी कर्मचारी एक विधवा के रूप पूर्णतः कठणामूलक आधार पर अपने नियोजता से रोजगार प्राप्त करती है और मकान किराया भत्ता नहीं ले रही होती है तथा जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पर पुत्रवधु के रूप में पूरी तरह आश्रित है;

(ख) क्या हाल ही में क्वार्टरों को नियमित करने से सम्बन्धित ऐसे अनेक आवेदन-पत्र सम्पदा निदेशालय द्वारा विशेषरूप से वित्त मन्त्रालय (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता कार्यालय में), अस्वीकृत किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसे ही मामलों के अनेक पूर्वोदाहरण हैं, जहां क्वार्टरों के आवंटन को नियमित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का इन सभी मामलों पर पूर्वोदाहरण के अनुसार विचार करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो इन क्वार्टरों को कब तक नियमित किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सेवानिवृत्ति के समय श्वसुर द्वारा धारित आवास के नियमितकरण के लिए पुत्र-वधू पात्र नहीं है ।

(ख) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी आवास नियमित करना

8977. श्री गंगा चरण लोधी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों-विधवाओं के अनुकम्पा के आधार पर सेवा में आने के मामले में आवास नियमित करने के लिए क्या नीति निर्धारित की है;

(ख) क्या सम्पदा निवेशालय में ऐसे अनेक आवेदन-पत्र वर्ष 1987 से लम्बित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मन्त्रालय/विभाग-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि सम्पदा निदेशालय ने हाल ही में उक्त आवेदकों को क्वाटर् खाखी करने के नोटिस जारी कर दिए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विधवाओं के मामले में क्वाटर् नियमित करने के लिए मौजूदा नीति की समीक्षा करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सहूरी बिकस मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**भारतीय चिकित्सा पद्धति के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के
औषधालयों में पैरा-मेडिकल स्टाफ**

8978. श्री रामजी लाल सुमन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के एलोपैथी औषधालयों तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के औषधालयों/एककों में मेडिकल और पैरा-मेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने के मामले में अलग-अलग मानदण्ड अपनाए जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बिषयता को समाप्त करने तथा सभी चिकित्सा पद्धतियों के औषधालयों/एककों में समान आधार पर स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

उर्द्धा मंत्री तथा नगर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के एलोपैथिक और भारतीय चिकित्सा पद्धति के औषधालयों में चिकित्सा और अर्द्ध-चिकित्सा के कर्मचारियों की तैनाती कर्मचारी निरीक्षण एकक प्रतिमानों के अनुसार की जाती है क्योंकि भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की यूनिटें एलोपैथिक औषधालयों के अंग के रूप में कार्य करती हैं और ऐसी यूनिटों के लिए कर्मचारी निरीक्षण एकक के पृथक मानदण्ड नहीं हैं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय खाद्य निगम का कार्यकरण

[हिन्दी]

8979. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम को कितनी स्वायत्तता प्राप्त है और किस प्रकार की स्वायत्तता प्राप्त है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्यों में नागरिक पूर्ति निगम के प्रभावी रूप से कार्यकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण की समीक्षा करने का विचार है ताकि इसके द्वारा अपने संचालन कार्यों पर व्यय की जाने वाली भारी धनराशि का मूल्यांकन किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो इसकी समीक्षा कब तक करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जैसाकि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में व्यवस्था है, भारतीय खाद्य निगम का सामान्य संचालन, निदेशन और उनके कार्यों तथा कारोबार का प्रबन्ध निदेशक मण्डल में निहित है। यह बोर्ड नीति विषयक मामलों के बारे में केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है।

(ख) से (घ) भारतीय खाद्य निगम और राज्यों के नागरिक आपूर्ति निगमों के कार्य समान नहीं हैं। भारतीय खाद्य निगम की परिचालन लागत की समीक्षा करना एक निरन्तर प्रक्रिया है। तथापि, औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से निगम के परिचालनों की लागत लेखापरीक्षा करने के लिए कहा गया है।

विदेशों में नौकरी के लिए जाने वाले लोगों की संख्या

[अनुबाध]

8980. श्री एन० डेनिस : क्या अथ मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष कितने लोग नौकरी के लिए विदेश जाते हैं; और

(ख) इनमें से स्नातकों की संख्या कितनी है ?

अथ एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, नीचे दिए गए व्यक्तियों ने उत्प्रवासी संरक्षियों के विभिन्न कार्यालयों से विदेशों में रोजगार प्राप्त करने के लिए उत्प्रवास अनुमति प्राप्त की :—

1987	—	1,25,356
1988	—	1,69,888
1989	—	1,25,786

(ख) स्नातकों को उत्प्रवास अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती और इसलिए यह सूचना नहीं रखी जाती है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्रों/जीपों की खरीद

8981. श्री हरीश रावत : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कारें और जीप खरीदने की ऐसी प्रक्रिया है कि इनकी लागत परियोजनाओं पर हो रहे निर्माण कार्यों के खाते में शामिल कर ली जाती है;

(ख) क्या इन बाहनों का प्रयोग उच्च निर्माण कार्यों में सगे निरीक्षक कर्मचारी अथवा अन्य कर्मचारी ही करते हैं; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी परियोजनाओं के इन निर्माण कार्यों के लिए मोटर साइकिल, पिक-अप-बैन और ट्रक अधिक उपयोगी रहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्राधिकरणों ने वर्ष 1985 से 1988 की अवधि के दौरान परियोजना से सम्बन्धित निर्माण कार्यों तथा अन्य कार्यों के लिए कुल कितनी कारें, जीप, मोटर साइकिलें, पिक-अप-बैन और ट्रक खरीदे हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली वारन) : (क) जी, नहीं। निर्माण कार्य के अनुमान में इस प्रकार के बाहनों के लिए विशिष्ट प्रावधान होने की स्थिति के सिवाय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कारों और जीपों की खरीद के लिए इनकी लागत को निर्माण कार्य के अनुमान में शामिल करने की कोई प्रक्रिया नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कार	22
जीप	106
पिक-अप बैन/मासुति बैन	15
मोटर साइकिल	—
ट्रक/ट्रैक्टर	9

योग : 152

सरकारी आवासों को नियमित करना

8982. श्री भवन लाल खुराना : क्या शहरी विकास मंत्री सरकारी आवासों को नियमित करने के बारे में 9 अगस्त, 1989 के अतारंकित प्रश्न संख्या 3156 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा निदेशालय, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के आश्रितों के लिए सरकारी आवास नियमित करने के मामले में सरकार द्वारा निर्धारित नीति का सभी मामलों में पालन नहीं करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे मामलों में आश्रित नियमित न करने के क्या कारण हैं; जहां सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी का आश्रित उसका सेवा निवृत्त के तीन वर्षों की अवधि के अन्तर्गत सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाता है अथवा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होता है;

(ब) वत खिन वर्षों के दौरान श्रेणी-वार, ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिन पर कोई कार्य-वाही नहीं की गई है और वे लम्बित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(क) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में नीति की पुनरीक्षा करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा भवन पर रख दी जायेगी।

(ख) नीति का कोई पुनरीक्षण अपेक्षित नहीं है।

आवास-परिवर्तन

8983. श्री मदन लाल क्षुराना : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी कारणों से आवास परिवर्तन की मंजूरी देने के बारे में निर्धारित नीति के उल्लंघन के कई मामले उनके मन्त्रालय के ध्यान में लाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा भवन पर रख दी जायेगी।

खानाबदोश जनजातियों का पुनर्वास

[हिन्दी]

8984. श्री अर्जुनसिंह जाटव :

श्री गोपाल पचेरवाल :

डा० बंगाली सिंह :

प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खानाबदोश जनजातियों को स्थायी रूप से बसाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

अन्न और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : खानाबदोश जनजातियों के स्वर्द्धि बन्दोबस्त के लिए कोई केन्द्र प्रायोजित योजना नहीं है और यह पूर्णतः एक राज्य विषय है।

अन्वेषण के साथ गंगा-बाल का बंटवारा

[अनुवाद]

8985. श्री माधवराव सिधिया :

श्री श्री० भरसा सिन्हा :

क्या अन्न विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फरवका बाघ में बंजरवेश के साथ गंगा जल के बंटबारे के मामले पर कोई निर्णय न लिए जाने के कारण कलकत्ता बस्न के लिए मन्त्री संकट होने की सम्भावना बढ़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है अथवा उठाए गए हैं ?

बस संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इन दो देशों से सचिवों की संयुक्त समिति को प्रस्ताव तैयार करने का कार्य सौंपा गया है, जिन्होंने अपनी पहली बैठक 18-4-1990 को आयोजित की ।

बस्न उद्योग द्वारा अजित बिदेशी मुद्रा

8986. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

क्या बस्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास उत्पादों के लिए सहकारी विपणन और प्रोसेसिंग सुविधाएं जैसी सहकारी व्यवस्था का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों और चालू मौसम के दौरान बस्न उद्योग ने वर्ष-वार कितनी बिदेशी मुद्रा अजित की है तथा इस सम्बन्ध में कौनसा राज्य प्रथम स्थान पर है ?

बस्न मंत्री और बस्न उत्पादन उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बस्न उत्पादों (जिनमें कयर, पटसन और हस्तशिल्प शामिल नहीं हैं) के निर्यात निम्नोक्त अनुसार हुए :

(मूल्य (करोड़ रु० में)

1987-88	3785
1988-89	4365
1989-90	6468

स्रोत : बस्न निर्यात संवर्धन परिषद/केन्द्रीय रेशम बोर्ड राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते ।

राजस्थान में साक्षान्न का सड़ना

[हिन्दी]

8987. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या बस्न और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम के कितने भांडागार हैं और वहाँ प्रत्येक शाखा में कितने अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार को राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न के सड़ने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाबू राम मिर्छा) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

खाड़ी के देशों से वापस आने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय निधि

8988. श्री बालेश्वर यादव : क्या अम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाड़ी के देशों से वापस आने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए कोई राष्ट्रीय निधि स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस सम्बन्ध में नीतियां बनाने का कार्य सम्बन्धित राज्य सरकारों का है।

ऊपरी कृष्णा परियोजना को विश्व बैंक से सहायता

[अनुवाद]

8989. श्रीमती बासबराजेश्वरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ऊपरी कृष्णा परियोजना के दूसरे चरण के अन्तर्गत पांच परियोजनाओं के लिए धन देने को सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक कुल कितनी सहायता-राशि प्रदान करेगा;

(ग) जिन-जिन परियोजनाओं के लिए इस धन-राशि का उपयोग किया जाएगा, उनका ब्योरा क्या है; और

(घ) इस सहायता-राशि के कब तक मिलने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) विश्व बैंक सहायता हेतु राज्य सरकार से "ऊपरी कृष्णा परियोजना के दूसरे चरण" शीर्षक के अन्तर्गत कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मकान निर्माण ऋण की बसूली

8990. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय इनकी ओर बकाया मकान निर्माण ऋण की राशि एकमुश्त बसूल कर ली जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे इन कर्मचारियों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है;

(ग) क्या सरकार का विचार कल्याण उपाय के रूप में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से मकान निर्माण ऋण की बकाया राशि की बसूली आसान किरतों में करने के लिए कोई सुविधा प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री भुरासोली मारण) : (क) जी, हां। केवल 20 वर्ष से कम सेवा वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में, सेवा-निवृत्ति के समय बकाया गृह निर्माण अधिम तथा उस पर ब्याज को मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान की राशि में समायोजित किया जाता है।

(ख) यह एक कल्याणकारी उपाय है जिसके द्वारा एक सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान बसूली की निम्नतम मासिक किरतों के साथ गृह निर्माण अधिम की एक उच्चतर मात्रा प्राप्त कर सकता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सेवानिवृत्ति के पश्चात् मासिक पेंशन से बसूली सम्भव नहीं है, क्योंकि इस पेंशन अधिनियम, 1871 की धारा 12 का उल्लंघन है।

गृहरे समुद्र में मछली पकड़ने में व्यापारिक गृहों द्वारा क्वि बर्साणा

8991. श्री के० एस० राव : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़े व्यापारिक गृहों ने समेकित मात्स्यकी विकास परियोजनाओं की स्थापना करके गृहरे समुद्र में मछली पकड़ने में क्वि बर्साई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वहन मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद बाबब) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बंगलौर में सर्कुलर रेलें

8992. श्री जगदीश पुजारी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कलकत्ता की तरह बंगलौर नगर में सर्कुलर रेल चलाने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुराली मोहन) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है ।

(ग) रेलवे योजना के अन्तर्गत सभी महानगरीय परिवहन योजनाओं के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी और इसलिए कोई नई योजना आरम्भ करना सम्भव नहीं था ।

राजस्थान में रुग्ण चीनी मिलें

[हिन्दी]

8993. श्री गुलाब खन्ड कटारिया : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में चीनी मिलों का ब्योरा क्या है;

(ख) राज्य में रुग्ण चीनी मिलों का ब्योरा क्या है;

(ग) इन रुग्ण मिलों को अर्धक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और

(घ) इन रुग्ण मिलों के कामगारों की क्षतिपूर्ति किस प्रकार से करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (घ) 15-4-90 को राजस्थान राज्य में 3 चीनी फैक्ट्रियां संस्थापित थी । इन फैक्ट्रियों की स्थिति और उनकी संस्थापित क्षमता निम्न प्रकार है :-

क्रम सं०	स्थिति	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (टी०सी०बी०)
1.	धूपालसागर	संयुक्त क्षेत्र	1500
2.	श्री गंगानगर	सांबंजनिक क्षेत्र	1016
3.	केसोदरमपाटल	ब्रह्मकारी क्षेत्र	1250

चीनी फैक्ट्री की रुग्णता विभिन्न कारणों पर आधारित है, जिसमें गन्ने की उपसब्धता, तकनीकी

व प्रबन्धकीय सक्षमता, संयंत्र का आकार व स्थिति और कुछ अन्य कारक भी शामिल हैं। चीनी फैक्ट्रियों की रणनीति को दूर करने के लिए सरकार गन्ना विकास और व्यापारिकीकरण/पुनर्वासि कार्यों के लिए आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है।

कोचीन में मुद्रिका रेल सेवा-

[अनुवाद]

8994. प्रो० के० बी० चामस : क्या शहरी विकास बंधी यह कृपण की कृपा करने कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कोचीन में मुद्रिका रेलवे के निर्माण के लिए केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी शर्तों क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास बंधी, (श्री सुराजोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख), और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी अस्पतालों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य-योजना के
लाभार्थियों का उपचार-

8995. श्री रामजीलाल सुमन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण बंधी विधानी में होम्यो-पैथी और यूतानी अस्पताल के बारे में 28 मार्च, 1940 के अंतराङ्कित 43 संख्या 2502 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस उत्तर के अनुबन्ध में उल्लिखित अस्पतालों की सेवाएं केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों द्वारा प्राप्त किए जाते की प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या के० स० स्वा० यो० औषधालयों की चिकित्सा अधिकारी इन अस्पतालों के लिए मासिक भेज सकते हैं, बँसक्ति डा० राम मनोहर मोहिया अस्पताल और सफरजंन अस्पताल के मामले में किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो के० स० स्वा० यो० का कोई लाभार्थी डा० राम मनोहर मोहिया अस्पताल और सफरजंन अस्पताल के अलावा अन्य सरकारी अस्पतालों की सेवाएं किस प्रकार प्राप्त कर सकता है ?

ऊर्जा बंधी नया नागर विमानन बंधी (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी औषधालयों के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा भेजने पर केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार और नगर निगम के अस्पतालों से चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। बँसे, निजी और रेफरल अस्पतालों से चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति लेना आवश्यक होता है।

“बैन्ड ड्रिक्स स्टिल आन सेल” शीर्षक से समाचार

8996. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :
 श्री शिव शरण वर्मा :
 श्री आर० एन० राकेश :
 श्री मानिक राव होडल्या गाबील :
 श्री एम० बी० चन्द्रशेखर भूति :
 श्री पी० नरसा रेड्डी :
 श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा :
 श्री प्रताप राव बी० भोसले :
 श्री वामनराव महाडोक :
 प्रो० सावित्री लक्ष्मणन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 अप्रैल, 1990 के “हिन्दुस्तान टाइम्स” में “बैन्ड ड्रिक्स स्टिल आन सेल” शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन निर्माताओं का उनके शीतल-पेय के ब्रांड नाम सहित ब्योरा क्या है; जिन्होंने सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाए जाने के बावजूद “नोमिनेटेड वेजिटेबल आइल” के प्रयोग से शीतल पेय बनाने का उत्पादन बन्द नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस बारे में भविष्य में क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या “आल इण्डिया साफ्ट ड्रिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन” ने सरकार से “नोमिनेटेड वेजिटेबल आइल” के प्रयोग में कुछ महीने और छूट दिए जाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि देश में विनिमित तथा बेचे जाने वाले शीतल पेय तथा अन्य खाद्य उत्पाद 15-4-90 के बाद से नोमिनेटेड वेजिटेबल आइल के प्रयोग से मुक्त हों।

(घ) जी, हां।

(ङ) सरकार 15 अप्रैल, 1990 के पश्चात समय बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हुई।

खाद्य-अपमिश्रण निवारण विभाग, नई दिल्ली द्वारा भारे गए छापे

8997. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :
 श्री एन० बी० चन्द्रशेखर भूति :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण विभाग, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली थोक विक्रेताओं/निर्माताओं के परिसरों पर छापे मार रहा है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1990 से अब तक थोक विक्रेताओं/निर्माताओं तथा फुटकर विक्रेताओं से क्रमशः कितने-कितने नमूने उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार ने थोक विक्रेताओं/निर्माताओं पर छापे मारने के लिए आगे और क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना इस प्रकार है :—

दिल्ली प्रशासन का खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग दिल्ली में थोक विक्रेताओं, विनिर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं पर पहले से ही छापे मार रहा है। इस विभाग के प्रवर्तन स्टाफ द्वारा जनवरी, 1990 से उठाए गए विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूनों की संख्या नीचे दी गई है।

महीना	थोक विक्रेता	विनिर्माता	खुदरा विक्रेता	कुल
जनवरी	10	19	68	97
फरवरी	02	08	43	53
मार्च	08	05	26	39
अप्रैल	06	14	22	42

दिल्ली में राशन कार्ड

[हिन्दी]

8998. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या खाद्य और नागरिक पुति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में वर्ष 1981 की जनसंख्या की अपेक्षा दिल्ली में राशन की सुविधा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के राशन कार्डों में लिखी हुई यूनिटों की संख्या अत्यधिक है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981 में दिल्ली में राशन कार्ड यूनिटों की संख्या और दिल्ली की जनसंख्या कितनी थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि एक व्यक्ति विभिन्न स्थानों पर राशन कार्डों में अपना नाम दर्ज करवा लेता है, और

(घ) यदि हां, तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पुति मंत्री (श्री नाथू राम जिर्जा) : (क) और (ख) 1981 की जनगणना

के अनुसार दिल्ली की आबादी 62,28,406 थी, जबकि 31-12-1981 को राशन कार्डों के अन्तर्गत 73,45,809 व्यक्ति दर्ज थे।

(ग) यद्यपि एक ही व्यक्ति द्वारा झूठी घोषणाएं प्रस्तुत करके एक से अधिक स्थान पर राशन कार्डों में अपना नाम शामिल करवाए जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, तथापि दिल्ली प्रशासन ने कहा है कि लाभानुभोगियों की संख्या अधिक इस कारण से है क्योंकि कार्ड धारकों द्वारा अपनी घोषणाओं में अपनी निवास स्थान, बिना अपने राशन कार्ड वापिस किए अवैध रूप से लिए गए हैं।

(घ) झूठी सूचना देकर घोषणा करके खाद्य कार्ड प्राप्त करना या उसमें नाम शामिल करवाना एक अपराध है। दिल्ली प्रशासन द्वारा बड़ी हुई यूनियो की-छंटाई करने के लिए सप्ताह-सप्ताह पर घर-घर जाकर खाद्य कार्डों की जांच की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान वसूले गए ऐसे अभियानों में 74,79 खाद्य कार्डधारकों, जिनमें 61,114 अनाज की तथा 36,230 चीनी की यूनियो थीं, के कार्डों को रद्द कर दिया गया क्योंकि ये कार्डधारक बताए गए पतों पर निवास करते नहीं पाए गए।

चिकित्सकों के विदेश पलायन से अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी

8999. श्री मुलाक-अब्दु कटारिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी संख्या में चिकित्सकों के विदेश पलायन से देश के अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी हो गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन चिकित्सकों पर जो विदेश पलायन करना चाहते हैं, विशेष ध्यान हेतु पारपत्र जारी करते समय उनकी शिक्षा पर व्यय हुई सम्पूर्ण धनराशि जमा करने की शर्त लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

योग-संस्थानों को सहायता

[अनुषास]]

9000. श्री बसन्त साठे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में संस्थान-वार और वर्ष-वार प्रत्येक बीम के संस्थान को अनुदान सहायता के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ख) क्या सरकार की जानकारी में इस सम्बन्ध में अनियमितता की जाने के बारे में कोई तिकायत आई है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार किया गया है; और

(घ) वर्ष 1990-91 में कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ?

उत्तर श्री-सभा सागर-विमानन मंत्री (श्री-आरिफ-मोहम्मद खान) : (क) योग और प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान करने के लिए स्वयंसेवी/निजी संस्थानों/केन्द्रों को प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के जरिए सहायता अनुदान दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य के किसी भी योग केन्द्र/संस्थान को कोई सहायता अनुदान नहीं दिया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) इन केन्द्रों को सहायता अनुदान देने के प्रयोजनाय कोई विशेष बजट आबंटन नहीं किए जाते हैं।

आबिद हुसेन समिति की सिफारिशें

9002. श्री-असल छाठे :

श्री प्रकाश कोको बहामट्ट :

श्री फैलाश मेघवाल :

श्री-मृग.० जे० रामबा :

क्या कृष्ण मंत्री सरकार-आम-के-सम्बन्ध में आबिद हुसेन समिति की सिफारिशों के बारे में 14 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 350 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बातों की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1985 की वस्त्र नीति के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा के लिए आबिद हुसेन की अध्यक्षता में गठित समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) रिपोर्ट पर किस चरण में विचार हो रहा है/कार्यवाही हो रही है-और-सरकार द्वारा इस पर कब तक कार्यवाही किए जाने की सम्भावना है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सरव-जखन) : (क) श्री, हां।

(ख) वस्त्र मन्त्रालय में रिपोर्ट पर विचार-विमर्श हुआ है। पहले कदम के तौर पर यह निर्णय किया गया है कि प्रसिद्धि-रिपोर्ट को अंग्रेजी और हिन्दी में मुद्रित करवाया जाए तथा इसकी पर्याप्त प्रतियाँ संबंधित मन्त्रालयों के पुस्तकालय में रखी जाए तथा साथ ही इसे आम जनता में बिक्री के लिए रिलीज किया जाए ताकि आबिद हुसेन समिति द्वारा किए गए प्रस्तावों पर व्यापक विचार किया जा सके। इस प्रकार सरकार को इसके क्रियान्वयन-अथवा अन्यथा कार्रवाई करने से पहले इस-सम्बन्ध में वर्षों-प्रतिक्रिया मिल जाएगी।

नर्मदा घाटी का पर्यावरणीय विकास

9003. श्री प्रकाश कोको बह्मभट्ट : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक पूरी नर्मदा घाटी के पर्यावरणीय विकास के लिए भारत को ऋण देने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विश्व बैंक के उच्च अधिकारियों से बातचीत करने के पश्चात् हाल में वाशिंगटन से कोई शिष्टमण्डल भारत आया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में लिया गया अन्तिम निर्णय क्या है; और

(घ) नर्मदा घाटी के पर्यावरणीय विकास के लिए भारत को कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) परियोजना प्रस्ताव प्रारम्भिक स्तर पर है और इसलिए इस समय सम्भावित विश्व बैंक सहायता का मूल्यांकन करना संभव नहीं है ।

केन्द्रीय जल आयोग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति

[हिन्दी]

9004. श्री हरीश रावत : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति के कार्यान्वयन के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग की स्थानान्तरण नीति इस संगठन की अनिवार्य आवश्यकताओं में सामंजस्य स्थापित करने तथा कर्मचारियों के हित को सुनिश्चित करने के लिए बनायी गयी है । कर्मचारी संघों पदाधिकारियों के साथ परामर्श करके इस आयोग ने नीति की समीक्षा की थी तथा केन्द्रीय जल आयोग ने समूह ग और घ कर्मचारियों के लिए सितम्बर, 1989 में तथा समूह क और ख कर्मचारियों के लिए दिसम्बर, 1989 में संशोधित स्थानान्तरण नीति जारी की थी । स्थानान्तरण नीति की अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं :—

(i) एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र को स्थानान्तरण सब मिलाकर जहां तक सम्भव हो कम से कम किए जाने चाहिए;

- (ii) समूह "क" तथा "ख" कामिकों का स्थानान्तरण सामान्यतया भारत में कहीं भी किया जा सकता है। समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों का प्रशासनिक आकस्मिकता पूरी करने के सिवाय स्थानान्तरण सामान्यतया नहीं किया जाना चाहिए;
 - (iii) जब किसी कर्मचारी का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को स्थानान्तरण करना अपरिहार्य हो तो इसे एक स्थान पर लम्बी अवधि तक लगातार कार्य करने वाले कर्मचारी जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उचित और न्यायोचित ढंग से किया जाना चाहिए;
 - (iv) समूह "क" और "ख" के मामले में दो वर्ष तथा समूह "ग" और "घ" के मामले में 5 वर्ष की अवधि में अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सामान्यतया स्थानान्तरित नहीं किया जाना चाहिए;
 - (v) जहां तक सम्भव हो स्थानान्तरण मार्च/अप्रैल में ही किए जाएं ताकि ऐसे कर्मचारियों के बच्चों के शैक्षिक कार्यक्रम में कोई व्यवधान न पड़े;
 - (vi) किसी ऐसे स्टेशन के लिए जहां कर्मचारी के पति/पत्नी जो सरकारी सेवा में हैं तैनात कर दिए जाते हैं, तो उस केन्द्र पर तैनाती के लिए अनुरोधों को, जहां तक सम्भव हो, मान लिया जाएगा;
 - (vii) महिला कर्मचारियों को सामान्यतया गैर-पारिवारिक स्टेशन पर तैनात नहीं किया जाएगा; और
 - (viii) कर्मचारियों की तैनाती/स्थानान्तरण के अनुरोध के आवेदनों को एक रजिस्टर में नोट किया जाएगा तथा उन पर निष्पक्ष, उचित तथा न्यायोचित तरीके से विचार किया जाएगा।
- (ग) और (घ) स्थानान्तरण नीति की समीक्षा करते समय कुछ कर्मचारी संघों से कुछ आपत्तियां प्राप्त हुई थीं जिन्हें आयोग ने संशोधित स्थानान्तरण नीति को अन्तिम रूप देते समय ध्यान में रखा था।

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इन्जीनियरों की
हड़ताल की अवधि**

[अनुवाद]

9005. श्री हरीश रावत : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कामिक लोक-शिक्षा तथा और प्रशिक्षण मन्त्रालय के इस सुझाव के बावजूद कि हड़ताल अवधि के मामले में संलग्न नियन्त्रण मन्त्रालय द्वारा इस अवधि को बकाया पड़े अवकाशों में समायोजित किया जाए, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इन्जीनियरों की हड़ताल की अवधि को इनके बकाया पड़े अवकाशों में समायोजित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या दूर-संचार मन्त्रालय जैसे कुछ मन्त्रालयों ने हड़ताल अवधि को बकाया पड़े अवकाशों में समायोजित कर लिया है; और

(क) यदि हां, तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इन्जीनियरों के कौशल भेदभाव करने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री सुरासोली भारन) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इन्जीनियरों की हकतास, अवधि, को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की; विशिष्ट सलाह पर वेब छुट्टी के रूप में सम्मोचित नहीं किया गया कि ऐसे मामलों में मन्त्रालयों/विभागों द्वारा; "कार्मिक नहीं तो वेतन नहीं" की नीति का अनुयायन किया जाए और यह कि इस अवधि को छुट्टी की मजूरी देने सहित किसी प्रकार से शामिल नहीं किया जाए।

(ख) और (ग) संचार मन्त्रालय ने दूरसंचार कर्मचारियों की हकतास की अवधि को देय छुट्टी के रूप में मानने का निर्णय कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से परामर्श किए बिना अथवा सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना एक विशेष मामले के रूप में तत्कालीन संचार मंत्री के अनुमोदन से लिया था। परन्तु इस निर्णय को इसी प्रकार की नीति अपनाने के लिए मिसाल नहीं बनाया जाना है।

तिमरपुर, बिस्फी में खतरनाक घोषित किए गए
मकानों का आबंटन

9006. श्री हरीश रावत : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिमरपुर में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सेन्ट्रल सर्किल VI द्वारा "खतरनाक" घोषित किए गए कुछ मकान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपने कर्मचारियों को आबंटित कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान क्रमशः कितने मकान "खतरनाक" घोषित किए गए और ऐसे कितने मकान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को आबंटित किए गए; और

(ग) इन मकानों का आबंटन सम्पदा निदेशालय के माध्यम की बजाय स्वयं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किए जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री सुरासोली भारन) : (क) जै, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

शल्य चिकित्सा द्वारा लिंग परिवर्तन

9007. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शल्य चिकित्सा द्वारा लिंग परिवर्तन के अभिलेखित मामलों का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इसका बालकों और बालिकाओं की जनसंख्या अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर बिमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

खनिज तेल के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

9008. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार जिन पदार्थों में खनिज तेल मिलाने की विशेष अनुमति दी गई है, उनके अतिरिक्त खाद्य पदार्थ में इस तेल के किसी भी रूप में प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों में भी संशोधन किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर बिमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) प्रारूप नियम 2 जनवरी, 1990 के सरकारी राजपत्र संख्या 3(ई) में जारी किए गए थे जिनमें खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में एक अलग उप-नियम 44 क क क जोड़ने के लिए जनता के विचार मांगे गए थे जिसके अन्तर्गत उन खाद्य पदार्थों, जिनमें परिशिष्ट "ख" में निर्धारित मानकों के अनुसार खनिज तेल मिलाने की अनुमति है, को छोड़कर खनिज तेल मिले खाद्य पदार्थों की बिक्री, बिक्री के लिए देना या रखना, किसी भी रूप में बिक्री के प्रयोजन के लिए अपने परिसर में रखना बर्जित है ।

डिब्बा बन्द उपभोक्ता उत्पादों की मांग

9009. श्रीमती बासबराजेरवरी :

श्री श्री० एस्० बासबराज :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिब्बा बन्द उपभोक्ता उत्पादों की मांग में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के उपभोक्ता उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई है और कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) ऐसे उत्पादों की मांग में विशेषरूप से कर्नाटक में और वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद घाबरे) : (क) से (ग) जितनी सूचना उपलब्ध होगी, एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विधेय भोजन सम्बन्धी मामले

9010. श्रीमती वासुदेव राजेश्वरी :
 श्री आर० एन० राकेश :
 श्री बनबारी लाल पुरोहित :
 श्री बी० एल० बरसवाहा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र महीने में देश के विभिन्न भागों में बिचले भोजन सम्बन्धी अनेक मामलों के सम्बन्ध में प्रप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा खाद्य विभाग मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परिवार कल्याण विषय पर विचार गोष्ठी

9011. श्रीमती वासुदेव राजेश्वरी :
 श्री बनबारी लाल पुरोहित :
 श्री प्रताप राव बी० भोसले :
 श्री बी० एल० बरसवाहा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 अप्रैल, 1990 को नई दिल्ली में परिवार कल्याण विषय पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस विचार गोष्ठी में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई;

(ग) विचार गोष्ठी में क्या-क्या प्रमुख सिफारिशें की गईं; और

(घ) उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी ?

ऊर्जा मंत्री तथा खाद्य विभाग मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) 14 से 15 अप्रैल, 1990 तक नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा परिवार कल्याण के बारे में एक राष्ट्रीय संघोष्ठी का आयोजन किया गया था। कुछ मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम समेकित रूप से लोगों से सम्पर्क स्थापित कर एक बहुमुखी सेवा प्रदान करने वाला कार्यक्रम होना चाहिए। इस कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार, महिलाओं के स्तर में सुधार, परीबी उन्मुलन, सामरता में सुधार करने सम्बन्धी बातें सम्मिलित होनी चाहिए।

(2) परिवार कल्याण सेवाओं में पूरी स्वास्थ्य परिषदों प्रदान प्रणाली सम्मिलित होनी चाहिए जिसमें मातृ परिचर्या, पोषण और परिवार कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(3) बच्चों के जन्म में अन्तर रखने संबंधी तरीकों की अपभारण के लिए नव-दम्पतियों पर और अधिक जोर दिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए मुख्य-सेव्य गौरी सम्बन्धी कार्यक्रम पर प्राथमिकता के आधार पर जोर दिया जाना चाहिए।

(4) परिवार कल्याण कार्यक्रम विशेषतौर से मुख्य-सेव्य गोलियों के उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रचार साधनों का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए।

(5) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भारतीय चिकित्सा संघ के सदस्यों को और अधिक शामिल किया जाना चाहिए।

(6) भारतीय चिकित्सा संघ को संगोष्ठीयों द्वारा ही के माध्यम से अपने सदस्यों को शिक्षित करने के लिए वित्तीय सहायता और सुविधाएं दी जानी चाहिए।

इस संगोष्ठी की मुख्य सिफारिशें पहले ही परिवार कल्याण कार्यक्रम की कार्यनीति का एक अंग बन गयी हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम में एक बहु-आयामी तथा समेकित रूप से लोगों से सम्पर्क स्थापित करने की बात सोची गई है और महिला शिक्षा, महिलाओं का स्तर, रोजगार इत्यादि "परिवार नियोजन से परे" जैसे कारकों की महत्ता को मान्यता देती है क्योंकि इनका अन्तर्गत सम्बन्धी आचरण पर प्रमुख प्रभाव होता है। इसी प्रकार परिवार कल्याण सेवा में एक वैकेज को बात खोची नहीं है जिसमें पूरी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय सम्बन्धी प्रणाली शामिल है जिसमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य परिचर्या सम्बन्धी कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया जाए। बच्चों के जन्म में अन्तर रखने वाली विभिन्न विधियों को अपनाने के लिए नव दम्पतियों को इसके अन्तर्गत लाने के लिए और ज्यादा और भी दिया जा रहा है। मुख्य-सेव्य गोलियों के और अधिक उपयोग करने के प्रचार के लिए सभी सम्भव प्रयास भी किए जा रहे हैं। छोटे परिवार के आवर्ण और बच्चों में अन्तर रखने की विभिन्न विधियों समेत मुख्य-सेव्य गोलियों की स्वीकार्यताओं को लोकप्रिय बनाने के लिए बहु-प्रचार संघार कार्यनीति शुरू की गई है। भारतीय चिकित्सा संघ से सम्बन्धित डाक्टरों को इस कार्यक्रम में और अधिक शामिल किया जाएगा। भारतीय चिकित्सा संघ को अपने सदस्यों को प्रशिक्षित, शिक्षित और प्रेरित करने के लिए वित्तीय सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार का प्रयास है कि राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों और समाज की बहुत बड़े पैमाने पर शामिल करने की नीति का अनुसरण करते हुए भारतीय चिकित्सा संघ और इसके सदस्यों को शामिल किया जाए।

दिल्ली में उचित दर दुकानों को राशन सामग्री की सम्पदा

9C12. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या खाद्य और मनोरंजन वृत्ति दोनों यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विशेषरूप से दूरस्थ क्षेत्रों में उचित दर दुकानों के मालिक काफी समय से राशन की वस्तुओं की अपर्याप्त सप्लाई के बारे में शिकायत कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान इस सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) से (ग) दिल्ली में सभी उचित दर की दुकानों को विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं का आवंटन उनके पास पंजीकृत यूनिटों के आधार पर किया जाता है। दिल्ली प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है कि दूरस्थ क्षेत्रों सहित सभी उचित दर की दुकानों को आपूर्ति उचित समय पर की जाए। जब कभी भारतीय खाद्य निगम के किसी गोदाम में मजदूर समस्या, भन्डारों की कमी आदि के कारण कोई देरी होती है, तो अन्य गोदामों से आपूर्ति प्राप्त करने के वास्ते तत्काल कदम उठाए जाते हैं। तथापि, दिल्ली प्रशासन ने कहा है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल, 1990 के महीनों के दौरान भारतीय खाद्य निगम में मजदूर समस्या के कारण आपूर्ति में कुछ देरी हुई थी।

पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल एण्ड एज्युकेशन रिसर्च के जठरांत्र शोध विज्ञान विभाग का कार्यक्रम

9013. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिष्ठित डाक्टरों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल एण्ड एज्युकेशन रिसर्च के जठरांत्र शोध विज्ञान विभाग के कार्यक्रम के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं;]

(ग) क्या दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की रिपोर्ट में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के जठरांत्र रोग विज्ञान विभाग के कार्यक्रम के निम्नलिखित पहलू भी शामिल हैं :—

1. प्रशिक्षण और शिक्षण कार्यक्रम
2. अनुसंधान
3. रोगोपरिचर्या
4. एम्बोस्कोपी सेवाएं
5. जठरांत्ररोग विज्ञान की सुपर स्पेशलिटी का संस्थान के अन्य विभागों के साथ सम्बन्ध।
6. अन्तर विभागीय सम्बन्ध।

(ग) और (घ) समिति की रिपोर्ट पर संस्थान की शासनीनिकाय की 17-6-89 को हुई बैठक में विचार किया गया है और इस निकाय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

नई दिल्ली नगर पालिका के होम्योपैथिक डाक्टरों को बाह्य भत्ता

9014. श्री गंगाधरजी लोधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के होम्योपैथी डाक्टरों को रोगियों के घर जाकर देखने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई दिल्ली नगर पालिका के होम्योपैथी डाक्टरों को घर जाकर रोगी देखने के लिए बाह्य भत्ता मिलता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) चूंकि नई दिल्ली नगर पालिका के औषधालयों के लिए 9 होम्योपैथिक डाक्टर स्वीकृति किए गए हैं, इसलिए डाक्टरों के लिए रोगियों के घरों का दौरा करना सम्भव नहीं है।

गन्दी बस्ती हटाने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत मकानों
(टेनीमेंट्स) का निर्माण

9015. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्दी बस्ती हटाने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत दिल्ली में अब तक कितने मकानों (टेनीमेंट्स) का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने मकानों (टेनीमेंट्स) के दखलदारों को पट्टाधृति अधिकार देने का निर्णय किया है;

(ग) क्या परिनिर्धारण मूल्य के रूप में वार्षिक रियायती किराए की बीस गुना राशि निर्धारित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में स्थित इन मकानों (टेनीमेंट्स) के वार्षिक रियायती किराए का ब्यौरा क्या है;

(ङ) दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में स्थित इन मकानों (टेनीमेंट्स) के दखलदारों द्वारा कितनी धनराशि जमा कराए जाने की सम्भावना है;

(च) क्या इन दखलदारों को उक्त धनराशि जमा करने के लिए कोई नोटिस भेजे गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो इन नोटिसों में उल्लिखित धनराशि का ब्यौरा क्या है और यह राशि किस आधार पर निश्चित की गई है ?

शहरी विकास भूमी (बी धरातीली भाएक) : (क) 20489 ।

(ख) जी, हां । अतिकमणकारियों को छोड़कर ।

(ग) से (ङ) 1980-81 से पूर्व निमित टेनामेंट्स के सम्बन्ध में परिशोधन लागत इकात्मिक साइसेन्स फीस के 20 गुणा पर निकाली जाती है तथा उसके बाद निर्माण किए गए टेनामेंट्स के लिए भूमि की अधिग्रहण तथा विकास लागत तथा टेनामेंट की निर्माण लागत और सामान्य ऊपरी व्यय प्रभारों के संदर्भ में निर्धारित की जाती है । परिशोधन लागत के कालोनीवार ब्योरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं । इकात्मिक साइसेन्स फीस के कालोनीवार ब्योरे विवरण-2 में दिए गए हैं ।

(घ) पात्र दखलकारों को भुगतान के नोटिस जारी किए जाते हैं ।

(ङ) नोटिस में उल्लिखित रकम में परिशोधन लागत 3-1-3-1985 तक साइसेन्स फीस का पिछला बकाया व्यक्तिगत प्लम्बिंग प्रभार तथा भूमि की कीमत का 2½ प्रतिशत की दर से वार्षिक भूमि किराया शामिल होता है ।

विवरण-1

परिशोधन लागत का कालोनीवार ब्योरा

क्रम ई०	कालोनी का नाम	परिशोधन लागत
1	2	3

1. 1980-81 से पूर्व निमित टेनामेंट

1.	पन्त नगर	8250
2.	ब्रह्मपुरी	7650
3.	रेगरपुरा	7050
4.	बभूतकौर पुरी फेज-1	6900
5.	रतन नगर	7350
6.	सिम्बलिस कालोनी	5700
7.	न्यू मोतीनगर टी० सी०	7950
8.	न्यू मोतीनगर चरण-I	8250
9.	न्यू मोतीनगर चरण-II	9300
10.	न्यू मोतीनगर चरण-III	11550
11.	रंजीत नगर चरण-I	12300

1	2	3
12.	रंजीत नगर चरण-II	16200
13.	रंजीत नगर (स्वीपर टेनामेंट)	11250
14.	बंदा मुगल (बासुदेव नगर)	8250
15.	नेह्रू नगर चरण-I	7650
16.	नेह्रू नगर चरण-II	8100
17.	इन्द्र लोक चरण-I	29700
18.	स्वामी दयानन्द कालोनी	14550
19.	बागअम्बा	13950
20.	कालकाजी	25650
21.	एम० एस० रोड	36000
22.	जी० टी० रोड शाहदरा	17100
23.	संगम पार्क (स्वीपर टेनामेंट)	18600
24.	एन० जी० रोड (स्वीपर टेनामेंट)	14850
25.	तिष्क नगर (स्वीपर टेनामेंट)	21150
26.	अहाता केदार	10650
27.	बन्धुशेखर आजाद कालोनी	21900
28.	बन्धुशेखर आजाद कालोनी बाग कड़े खां	14850
29.	बाग कड़े खां, स्वागी दया नन्द कालोनी	15000
30.	पदम नगर	9900
31.	टी० सी० बागअम्बा	9900
32.	डी० ए० जी० चरण-I (अजमेरी गेट)	29250
33.	कटरा शीश महल	28200
34.	शुद्धार बस्ती	14100
35.	गई	24400
36.	नेह्रू नगर पार्किट फ्लैट	8800

1	2	3
37. सुकमान गेट		
(क) भू-तल		
	टाइप-ए	59900
	टाइप बी	57100
	टाइप सी	57150
(ख) प्रथम तल		
	टाइप-ए	56750
	टाइप डी	66880
(ग) द्वितीय तल		
	टाईप ई	53850
	टाइप एफ	66800
(घ) तृतीय तल		
	टाइप ई	53850
	टाइप एफ	63200

II. 1980-81 के बाब निर्मित टेनामेंट

1.	संगम पार्क	41500
2.	रघुबीर नगर	51500
3.	एम० एस० रोड	29800
4.	सराय रोयला	38400
5.	एन० जी० रोड शिवाजी कालोनी के समीप	54400
6.	अलमेरी गेट	37200
7.	जहांगीर पुरी	37600
8.	कटरा नवी करीम पहाड़गंज	41800
9.	गढ़ी ब्लाक सी	32200
10.	सराय बस्ती	55200
11.	तिलक बिहार	45000

1	2	3
12.	रंजीत नगर, ए ब्लॉक चरण-II	41800
13.	रघुबीर नगर सेक्टर बी तथा सी, नजफ गढ़ रोड	38700
14.	भादीपुर	29700

विवरण-2j

1. इकोनामिक लाइसेंस फीस के कालोनीधार व्यौर

क्र० सं०	कालोनी का नाम	इकोनामिक लाइसेंस फीस
1	2	3
1.	पन्त नगर	412.50
2.	ब्रह्मपुरी	382.50
3.	रेगरपुरा	352.50
4.	अमृतकौर पुरी चरण-I	345.00
5.	रतन नगर	367.50
6.	मिलेमिल कालोनी	285.00
7.	न्यू मोतीनगर टी० सी०	397.50
8.	न्यू मोतीनगर चरण-I	412.50
9.	न्यू मोतीनगर चरण-II	465.00
10.	न्यू मोतीनगर चरण-III	577.50
11.	रंजीत नगर चरण-I	615.00
12.	रंजीत नगर चरण-II	810.00
13.	रंजीत नगर (स्वीपर टेनामेंट)	562.50
14.	अंधा मुगस (बामुदेब नगर)	367.50
15.	नेहरू नगर चरण-I	337.50
16.	नेहरू नगर चरण-II	360.00
17.	इन्द्र लोक चरण-I	1440.00

1	2	3
18.	स्वामी दयानन्द कालोनी	682.50
19.	बागअम्बा	652.50
20.	कालकाजी	1237.50
21.	एम० एस० रोड	1755.00
22.	जी० टी० रोड शाहदरा	810.00
23.	संगम पार्क (स्वीपर टेनामेंट)	885.00
24.	एम० जी० रोड (स्वीपर टेनामेंट)	697.50
25.	तिलक नगर (स्वीपर टेनामेंट)	1012.50
26.	अहाता केदार	487.50
27.	चन्द्र शेखर आजाद कालोनी	1050.00
28.	चन्द्र शेखर आजाद कालोनी बाघकड़े खां	697.50
29.	बाघकड़े खां, स्वामी दयानन्द कालोनी	705.00
30.	पदम नगर	450.00
31.	टी० सी० बागअम्बा	450.00
32.	डी० ए० जी० चरण-I (अजमेरी गेट)	1417.50
33.	कटरा शीश महल	1365.00
34.	गुडार बस्ती	660.00
35.	गढ़ी	1175.00
36.	नेहरू नगर मार्किट फ्लैट	392.40
37.	सुकंभाम गेट	
	(क) झूलल	
	टाइप ए	2899.20
	टाइप बी	2763.45
	टाइप सी	2776.87
	(ख) अचम लल	
	टाइप ए	2880.67
	टाइप डी	3382.95

1	2	3
	(ग) द्वितीय तल	
	टाइप ई	2736.00
	टाइप एक	3383.00
	(घ) तृतीय तल	
	टाइप ई	2736.03
	टाइप एक	3201.90

बंधुभा मजदूर

9016. श्री छत्रेश प्रसाद बर्मा : क्या अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंधुभा मजदूरों को विदेशों को भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मजदूरों को विदेश भेजे जाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

अन्न और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास वात्सयान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

शहरी क्षेत्रों में निर्माण लागत में वृद्धि

9017. श्री छत्रेश प्रसाद बर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी क्षेत्रों, विशेष रूप से महानगरों में मकानों की निर्माण लागत में पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) पिछले दो वर्षों में इसमें कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) इनमें वृद्धि होने के क्या-क्या कारण हैं;

(घ) सरकार ने लागत घटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ताकि समाज के कम आय वर्ग और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता की जा सके ?

शहरी विकास मंत्री (श्री भुरासोली शारम) : (क) महानगरों सहित शहरी क्षेत्रों में मकानों के निर्माण लागत सूचकांक में प्रतिशत वृद्धि 20.65 से 67.65 रही ।

(ख) गत दो वर्षों अर्थात् 1987-89 के दौरान प्रतिशत वृद्धि अन्तर 5.2 से 30.0 रहा ।

(ग) निर्माण लागत में वृद्धि, भवन निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, स्टील, लकड़ी की कीमतों में

बुद्धि, मजदूरी तथा परिवहन लागत में वृद्धि और भवन निर्माण क्रियाकलाप में सामान्य वृद्धि के कारण हुई।

(घ) निर्माण लागत को कम करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार नवीन प्रौद्योगिकी तथा कम लागत वाली भवन निर्माण सामग्री और स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे मसल कृमि जन्य तथा औद्योगिक अपशिष्टों सहित, द्वारा विनिर्मित घटकों को अपनाने की सिफारिश करती रही है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अधीन केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, अद्यतनरचनात्मक इन्जीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र, औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अनुसंधान शालाएं तथा अन्य संस्थान कम लागत के आवास पर अनुसंधान करने में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। अनुसंधान तथा विकास प्रयासों में जैसे कम लागत/बैकल्पिक भवन सामग्रियों तथा घटकों, द्रामीण क्षेत्रों में निम्न आय बस्तियों के लिए आवास का प्रौद्योगिकी विकल्प कम खर्चीली नींव, अग्नि सुरक्षा तथा विपदा प्रवृत्त क्षेत्रों में ऊष्मा रहित भवनों आदि जैसे पहलू सम्मिलित हैं। कम लागत के आवास के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में अनुसंधान अभियानों को केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती है।

कम लागत की भवन निर्माण सामग्रियों के उत्पादन के लिए लूटके भवन निर्माण सामग्री विनिर्माण इकाइयों को उनकी साम्य पूंजी में अंशदान करके भी प्रोत्साहन देता है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में दवाइयों उपलब्ध न होने

9018. श्री धर्मेश प्रसाद शर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की ज्ञातकारी है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के विकित्सकों तथा विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई दवाइयों सामान्य केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में उपलब्ध नहीं होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का रेसिपियों को जमाबंदी अस्वहमकृतानुसार दवाइयों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) फार्मूली में शामिल सभी औषधियां कुल मिलाकर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में उपलब्ध है और लाभार्थियों को दी जा रही है। किसी औषध के उपलब्ध न होने पर उसे स्थानीय केमिस्ट से इन्डेंट करके लाभार्थियों को दिया जाता है। आपाती मामलों में लाभार्थियों को सुपर बाजार से बिना किसी भुगतान के औषध खरीदने हेतु सर्वप्रथम-पत्र भी दिया जाता है।

लेखिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

9019. श्री धर्मेश प्रसाद शर्मा : क्या लाल बंसी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लेखिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुरूप है;

(ख) यदि नहीं, तो उत्सम्भन्धी क्योंरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

धम और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलसल शास्त्रवत) : (क) और (ख) राज्य सरकारें उप-सोझवा मूल्य सूचकांक में वृद्धि के पञ्चदशक न्यूनतम मजदूरी दरों से समय-समय पर संशोधन करती रही हैं। अनेक राज्यों ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध परिवर्ती महंगाई भत्ते की भी व्यवस्था की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में सड़कों की मरम्मत

9020. श्री मदन लाल खुराना :

श्री राम सागर (सैदपुर) :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में सड़कों, पटरियों, पैदल पथों आदि की मरम्मत में बहुत घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग किया जात है;

(ख) यदि हां, तो बार-बार किए जाने वाले मरम्मत के कार्यों में फिजूल खर्ची रोकने और दिल्ली में सड़कों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में कितनी सड़को और कितने कूड़ेदानों की बार-बार मरम्मत की गयी ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, छाबनी बोर्ड और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सड़को की मरम्मत के लिए वे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित विशिष्टियों के अनुरूप मानक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, सड़कों/पटरियों की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए अनुमोदित मानदण्डों के आधार पर तैयार की गई अनुरक्षण योजनाओं के अनुसार मरम्मत कार्य किए जाते हैं और गत तीन वर्षों के दौरान सड़कों तथा कूड़ेदानों की बार-बार मरम्मत नहीं की गई है।

नशे के आदी व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वयंसेवी संगठनों की सहायता

[हिन्दी]

9021. श्री हरिश्चन्द्र बह्मले : क्या धर्म मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नशे के आदी व्यक्तियों के उपचार और पुनर्वास के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों का राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) इन संगठनों को दी गई धनराशि और उसके अनुपात का ब्योरा क्या है;

(ब) क्या सरकार को इन संगठनों में ब्याप्त कदाचार की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कितने संगठनों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच की है; यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

अम और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मछनिपेघ और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के निवारण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता योजना के अन्तर्गत भारत सरकार नशीली दवाओं के ब्यसनियों को परामर्श, निर्व्यसन और देखभाल की सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को कुल व्यय का 90% सहायक अनुदान देती है । चेतना, शिक्षा और प्रसार तथा भवन-निर्माण, बाह्य खरीदने आदि के लिए भी अनुदान दिए जाते हैं । निर्माण के मामले में, लागत का 50% तक या 5 लाख रु०, जो भी कम हो, स्वयंसेवी संगठनों को ग्राह्य है ।

संगठनों को दी गई धनराशि का राज्यवार विवरण संलग्न है ।

(घ) से (च) संगठनों का निष्पादन नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है । तथापि शिकायत प्राप्त होने पर या केन्द्र में अनियमितता सम्बन्धी जानकारी प्राप्त होने पर, उचित जांच के बाद, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से कार्रवाई की जाती है । अब तक, नशीली दवाओं के ब्यसनियों के परामर्श और उपचार के लिए स्वयंसेवी संगठनों के चार परामर्श केन्द्र बन्द किए जा चुके हैं ।

विवरण

1989-90 के दौरान नशीली दवाओं के निवारण कार्यक्रमों के लिए शामिल किए गए स्वयंसेवी संगठनों/संस्थानों को दिए गए सहायक अनुदान (31-3-1990 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सहायता दिए गए स्वयंसेवी संगठनों/संस्थानों आदि की संख्या	दिए गए अनुदान की राशि
1	2	3	4

(क) राज्य

1. आन्ध्र प्रदेश	2	3.60
2. असम	1	0.87

1	2	3	4
3.	बिहार	4	15.71
4.	गोवा	2	2.96
5.	गुजरात	7	36.73
6.	हरियाणा	6	38.09
7.	जम्मू और कश्मीर	1	1.33
8.	कर्नाटक	3	9.57
9.	केरल	4	7.43
10.	मध्य प्रदेश	6	13.65
11.	महाराष्ट्र	9	32.73
12.	मणिपुर	2	10.62
13.	मिजोरम	3	17.14
14.	नागालैंड	2	4.07
15.	उड़ीसा	4	8.53
16.	पंजाब	2	3.31
17.	राजस्थान	3	34.37
18.	सिक्किम	1	1.40
19.	तमिलनाडु	10	23.74
20.	त्रिपुरा	1	0.85
21.	उत्तर प्रदेश	6	29.42
22.	पश्चिम बंगाल	14	24.78
योग क		93*	320.90

(ख) श्रेष्ठ राज्य क्षेत्र

1. पच्छीमबंग

2

4.95

1	2	3	4
2.	दिल्ली	15	104.43
3.	वाडिचेरी	1	4.43
	योग ख	18	113.81
	कुल योग (क+ख) :	111*	434.71

नोट :—चूँकि कुछ संगठनों को एक से अधिक बार शामिल किया गया है, सहायता दिए गए स्वयंसेवी संगठनों/संस्थानों आदि की वास्तविक संख्या 108 है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का समय

9022. श्री हरिशंकर महाले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों की एक पाली होने से इसके साभाषियों को भारी असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को प्रातः और सायंकाल खोलने की पुरानी व्यवस्था पुनः शुरू करने का विचार किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को साप्ताहिक अवकाश के दिनों में भी खोलने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में वर्तमान प्रणाली केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की परामर्शी समिति की सिफारिशों पर शुरू की गई थी। दिल्ली के 81 औषधालयों में से 11 औषधालय सायंकाल को भी पूरी चिकित्सीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। थोड़े से स्टाफ को लवा करके सभी औषधालयों में सीमित चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को छुट्टी वाले दिनों को खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। तथापि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के साभाषी छुट्टी वाले दिनों में कार्य कर रहे औषधालयों से आत्यंतिक चिकित्सीय सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

महाराष्ट्र में क्षेत्रीय कौन्सल उपचार केन्द्र

9023. श्री हरिसंकर महाले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करके कि :

(क) महाराष्ट्र में जिले-वार कितने क्षेत्रीय कौन्सल उपचार केन्द्र हैं;

(ख) इन केन्द्रों में उपलब्ध कराए गए नैदानिक और उपचार उपकरणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक केन्द्र में किए गए आपरेशनों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा मातृत्व विभाग मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) एक-टाटा स्वारक अस्पताल एवं कौन्सल अनुसंधान संस्थान, बम्बई।

(ख) इन संस्थान को सभी प्रकार के आधुनिक रोग नैदानिक और उपचार उपकरण प्रदान किए गए हैं जिसमें कोबाल्ट धिरेपी यूनिट लीनियर एक्समिलरेटर, सीटी स्कैनर, ब्रैचि धिरेपी, एक्स-रे यूनिट, एनेस्थेसिया उपकरण, प्रयोगशालाएं सेवाएं और अल्प चिकित्सीय और अल्प चिकित्सीय उपकरण भी शामिल हैं।

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान 8847 बड़े और 13697 छोटे आपरेशन तथा वर्ष 1989-90 के दौरान 7877 बड़े और 14063 छोटे आपरेशन किए गए।

स्वामित्व के अधिकारों का हस्तोत्तरण

[अनुबाध]

9024. श्री माधवराव सिधिया : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मुक्तियारनामा धारकों को स्वामित्व का अधिकार देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो भूमि के ऐसे मामलों में (एक) जहाँ मुक्तियारनामा ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया हो जो स्वयं स्वामित्व का पूरा अधिकार रखता हो, (दो) जहाँ मुक्तियारनामा ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया हो जो केवल भूमि के पट्टेदार अथवा उप-पट्टेदार का अधिकार रखता हो, यदि कोई निर्णय लिया गया है, तो वह क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री सुरतोली मारन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुछ समय पूर्व ऐसे सौदों के नियमितकरण की योजना घोषित की थी। यह योजना मार्च, 1989 से मार्च, 1990 तक चालू थी। यह केवल रिहायशी सम्पतियों पर लागू थी और उन मामलों, जहाँ मालिकाना अधिकार अन्तर्निहित करने के लिए मुक्तियारनामों का तरीका प्रयोग में लाया गया है, को शामिल करने के लिए थी।

किसानों को मुआवजा देने के लिए मानदण्ड

9025. श्री माधवराव सिधिया : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में अधिग्रहीत कृषि भूमि के लिए भुगतान किए जाने वाले मुआवजे के लिए निर्धारित मानदण्डों की पुनरीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए वर्तमान मानदण्ड क्या हैं और उनमें क्या संशोधन किए जाएंगे ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली भारन) : (क) और (ख) मुआवजे का भुगतान समय-समय पर यथा संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है। तथापि, दिल्ली प्रशासन ने कृषि भूमि के लिए हाल ही में निम्नलिखित न्यूनतम कीमतें निर्धारित की है :—

(i) अग्र बांधों के मध्य नदी तल में स्थित भूमि के लिए प्रति एकड़ 1.5 लाख रुपए।

(ii) अन्य सभी कृषि भूमि के लिए प्रति एकड़ 4.65 लाख रुपए।

ये न्यूनतम मूल्य 27-4-90 से प्रभावी हैं और मुआवजे के भुगतान के लिए भूमि अधिग्रहण समाहर्ता द्वारा इनको ध्यान में रखा जाएगा और ये उन सभी मामलों में लागू होगी जिनमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत भूमि अधिमूचित की गई है। गत वर्षों में धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित की गई भूमि के लिए न्यूनतम मूल्य का हिसाब 1900 के मूल्यों में प्रतिवर्ष 15% तक कटौती करके लगाया जाएगा। यह न्यूनतम मूल्य उन मामलों पर लागू नहीं होगा जिनमें पहले ही अबाउंड घोषित किए जा चुके हैं। इस न्यूनतम मूल्य के अलावा भू-स्वामी 30% सान्त्वना उपहार तथा अधिनियम में मुहैया किए गए अन्य लाभों के पात्र भी होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन में प्रगति

9026. श्री माधवराव सिधिया :

श्री उत्तम राठौड़ :

श्री बनबारी लाल पुरोहित :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन हेतु सातवीं योजना में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र में धनराशि का आबंटन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रस्तावानुसार कितनी धनराशि आवंटित की गई, बस्तुतः कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई तथा केन्द्र एवं सम्बन्धित राज्यों द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड के प्रस्तावानुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिए केन्द्र एवं राज्यों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ब) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना में अब तक हुई प्रगति निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हुई है; और

(क) यदि नहीं, तो कमी का क्या कारण है, इसके क्या कारण हैं तथा निर्धारित लक्ष्यानुसार प्रगति की गति को सुनिश्चित करने के लिए कौन से सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री भुरासोली भारन) : (क) से (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने सातवीं योजना अवधि के दौरान 867 करोड़ रुपये (467 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में और 400 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र में) के परिष्कार का प्रस्ताव किया था। तथापि, सातवीं योजना में केवल 65 करोड़ रुपये (35 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में तथा 30 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र में) वास्तविक रूप से मुहैया किए गए थे। इसकी तुलना में ब्यय 79 करोड़ रुपये (केन्द्र द्वारा दिए गए 34.62 करोड़ रुपये सहित) तक बढ़ गया। राज्य सरकारों तथा उनके कार्यान्वयन अधिकारियों द्वारा किया गया ब्यय 31 दिसम्बर, 1989, जिस तारीख तक फिलहाल आंकड़े उपलब्ध हैं, तक 44.75 करोड़ रुपये है।

आठवीं योजना अवधि के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने 2900 करोड़ रुपये (1750 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में और 1150 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र में) की निवेश योजना तैयार की है। आठवीं योजना के केवल प्रथम वर्ष (1990-91) के लिए नियतनों को अन्तिम रूप दिया गया है और आठवीं योजना के प्रथम वर्ष के लिए 10 करोड़ रुपये मुहैया किए गए हैं। राज्य क्षेत्र के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

मायोपंथी के इलाज के लिए एक्यूपंचर

[हिन्दी]

9027. श्री शिवशरण वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मायोपंथी के इलाज के लिए एक्यूपंचर पद्धति अपनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इर्शा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) चूंकि एक्यूपंचर पेशी-दुर्बलता और तंत्रिका-पेशी संश्लेषण के अन्य विकारों में लाभदायक नहीं पायी गयी है इसलिए पेशी विकृति में उपचार को एक विधि के रूप में एक्यूपंचर को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डाक्टरों की भर्ती हेतु मलेरिया से अनुरोध

[अनुवाद]

9028. श्री शिवशरण वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मलेशिया की सरकार से डाक्टरों तथा चिकित्सा विशेषज्ञों की भर्ती के सम्बन्ध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितने डाक्टर और चिकित्सा विशेषज्ञ मलेशिया भेजने का प्रस्ताव है; और

(ग) उनकी नियुक्ति के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मलेशिया सरकार ने 99 डाक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए अनुरोध किया था । उनके अनुरोध पर विचार किया जा रहा है और सम्बन्धित विषय की विशेषज्ञता में उनकी क्वालिफिकेशन और अनुभव के आधार पर तथा मेरिट के अनुसार उनका चयन किया जाएगा । चयन करते समय विशेषज्ञी नोकरी के सम्बन्ध में सरकारी नीतियों को भी ध्यान में रखा जाएगा ।

रिक्त पदों का भरा जाना

9029. श्री जगन्नाथ सिंह :

श्री सुब्रह्मण्य सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में कितने वरिष्ठ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) वे कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) अब तक इन पदों को न भरने के क्या कारण हैं और इन रिक्त पदों को कब तक भरा जायगा ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में निम्नलिखित चार वरिष्ठ पद रिक्त हैं :-

1. उपसलाहकार (यूनानी)	(3000-5000 रु०)
2. निदेशक (मूल्यांकन)	(4500-5700 रु०)
3. संयुक्त निदेशक	(3700-5000 रु०)
4. कार्यक्रम अधिकारी (ए० बी०)	(3700-5000 रु०)

(ख) पद का नाम

वह तारीख, जब से रिक्त है

1. उप सलाहकार (यूनानी)	22-2-1985
2. निदेशक (मूल्यांकन)	27-1-1988
3. संयुक्त निदेशक	1-4-1990
4. कार्यक्रम अधिकारी (ए० बी०)	31-1-1990

(ग)	पद का नाम	वर्तमान स्थिति
१. उप सभाहकार (यूनानी)	२. निदेशक (मूल्यांकन) और	यह पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेशों के अनुसार, यदि अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण यह पद तीन वर्ष तक नहीं भरा जाता है तो इसे अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से बदला जाना है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह पद अप्रैल १९९० में विज्ञापित किया गया है और यदि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उपयुक्त उम्मीदवार चुन लिया जाता है तो इसके शीघ्र ही भरे जाने की संभावना है।
३. संयुक्त निदेशक	४. कार्यक्रम अधिकारी (ए० बी०)	ये आई० एस० एस० के पद हैं। सांख्यिकी विभाग से योग्य अधिकारियों का नामांकन करते हेतु।
		पहले ही अनुरोध किया गया है। इन रिक्तियों के शीघ्र ही भरे जाने की आशा है।
		संघ लोक सेवा आयोग और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करके रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। रिक्त पद के शीघ्र ही भरे जाने की सम्भावना है।

इलेक्ट्रॉपैथी संस्थाओं की जांच

[हिन्दी]

९०३०. श्री जगन्नाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉपैथी समिति ने २५ अप्रैल, १९९० को ममुरा और आगरा स्थित इलेक्ट्रॉपैथी संस्थाओं की जांच की थी;

(ख) इस समिति ने इससे पहले कितनी संस्थाओं की जांच की थी;

(ग) इन संस्थाओं की जांच में किन-किन सदस्यों ने भाग लिया; और

(घ) समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा माधर विभाजन मंत्री (श्री अग्रिका मोहनबहादुर शाह) : (क) जी, हाँ।

(ख) समिति द्वारा पहले दो संस्थाओं का निरीक्षण किया गया ।

(ग) आगरा और मथुरा के संस्थानों का निरीक्षण निम्नलिखित सदस्यों द्वारा किया गया :—

1. डा० एस० डी० शर्मा, उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ।

2. डा० बी० के गुप्ता, औषध नियन्त्रक भारत, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ।

3. डा० डी० पी० रस्तोगी, निदेशक, केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ।

(घ) रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण ये हैं कि समिति को विभिन्न स्थानों का दौरा करना था और इलेक्ट्रोपैथी के चिकित्सकों का भी विचार जानना था । यह कार्य अब कर लिया गया है और रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है ।

सफदरजंग अस्पताल में नसिग होम सुविधा

9031. श्री सुलेन्द्र सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफदरजंग अस्पताल में कितने नसिग होम हैं;

(ख) क्या सरकार का सफदरजंग अस्पताल में एक मेडिकल कालेज स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा इसे कब तक मंजूरी दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) सफदरजंग अस्पताल में कोई उपचर्या गृह नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक

[अनुषाच]

9032. श्री पी० नरसा रेड्डी :

श्री प्रकाश कोको बहाभट्ट :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 18 अप्रैल, 1990 को दिल्ली में भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा की गयी ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मंगुभाई कोटावुबा) : (क) जी, हां ।

(ख) बाढ़ प्रबन्ध और जल प्रवाहों पर सितम्बर, 1988 में गठित कार्य बल की रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने तथा गंगा और तीस्ता पर आवश्यकताओं के विशेष सन्दर्भ में साक्षात् नदियों की हिस्सेदारी पर विचार-विमर्श किए गए थे ।

रुग्ण कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण

9033. श्री बालासाहिब बिस्ले पाटिल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से रुग्ण हुई 8 कपड़ा मिलों के, राष्ट्रीयकरण के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि इस मामले में विलम्ब करने से लाखों कपड़ा मजदूरों को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीयकरण रुग्णता की समस्या का समाधान नहीं है । तथापि, अर्धसम मिलों के मामले में, जहां आवश्यक हो, इस पर विचार किया जा सकता है । इसलिए राज्य सरकार को इस उद्देश्य के लिए स्थापित नोडीय अभिकरण/बी० आई० एफ० आर० द्वारा इन मिलों की अर्धसमता की जांच के लिए सलाह दी गई है और सभी सम्बन्धित पार्टियों की सहमति लेने के लिए कहा गया है ताकि अर्धसमता पाई जाने वाली मिलों के पुनर्स्थापना पंकेजों में उनसे अपेक्षित राहत और रियायतें प्राप्त हो सकें ।

एसोपैथिक डाक्टरों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण

9034. श्री बालासाहिब बिस्ले पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बेरोजगार एसोपैथिक डाक्टरों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो दिनांक 28 फरवरी, 1990 की स्थिति के अनुसार राज्यवार, तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है;

(ग) दिनांक 28 फरवरी 1990 की स्थिति के अनुसार देश में प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके कितने पद खाली पड़े हैं; और

(घ) इन बेरोजगार एसोपैथिक डाक्टरों को रोजगार उपसब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) रोजगार और प्रशिक्षण महाविद्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार 31-12-88 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्ट्रों में चिकित्सा स्नातकों की कुल संख्या, जिसमें स्नातकोत्तर चिकित्सक भी शामिल हैं, 27,290 है। यह भी उल्लेख किया जाता है कि रोजगार कार्यालयों में बने सभी रोजगार चाहने वाले व्यक्ति बेरोजगार नहीं होते।

(ग) 31-12-89 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों के मंजूर पदों की कुल संख्या 23,619 बी० और 4132 पद रिक्त थे।

(ग) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के स्वास्थ्य क्षेत्रों में सीधाम्य विस्तार के कार्यक्रमों के अलावा सरकारी क्षेत्र में बेरोजगार डाक्टरों को रोजगार देने की कोई योजना नहीं है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंस

9035. श्री बालासाहिब बिल्ले पाटिल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को लाइसेंस जारी करने के लिए कोई मार्ग-निर्देश बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो मार्ग-निर्देश कब तक बना दिए जाएंगे?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद बाबब) : (क) से (ग) अधिकतर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लाइसेंस मुक्त हैं। किन्तु जहाँ कहीं औद्योगिक लाइसेंस आवश्यक होता है, सरकार द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त अधिसूचित किए जाते हैं।

माही जल विवाद

9036. श्रीमती वसुधारा राजे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माही जल विवाद काफी लम्बे समय से अनिर्णीत पड़ा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्थान तथा गुजरात सरकार द्वारा विवाद को शीघ्र निपटाने का अनुरोध किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस विवाद को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वसुधरई कोटाड़िय) : (क) माही जल के बंटवारे के सम्बन्ध में गुजरात और राजस्थान की सरकारों के बीच 1966 के द्विपक्षीय समझौते से उत्पन्न मामले वर्ष 1980 से निपटान हेतु लम्बित हैं।

(ख) और (घ) राजस्थान सरकार इन मामलों को शीघ्र हल करने के लिए दबाव डाल रही है। केन्द्र द्वारा 24-12-80 और 6-4-83 को मुख्य मंत्री स्तर पर बी धर्मेराज्जीय बैठकें आयोजित की

मन्त्री भी और इन दोनों राज्यों के सिंचाई मन्त्रियों ने 11-6-84 को द्विपक्षीय विचार-विमर्श भी किया था लेकिन इस पर कोई आम सहमति नहीं हो सकी थी। इसके अतिरिक्त, मुख्य मन्त्री स्तर पर अन्तर-राज्यीय बैठक आयोजित करने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं। नई पहल करते हुए इन मामलों को दोनों मुख्य मन्त्रियों के साथ अलग से उठाया गया है।

अस्वास्थ्य आवास (ट्राजिट होम्स)

[दिल्ली]

9037. श्री अनादि चरण दास :

श्री मंत्राराज मलिक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक ऐसी योजना बनाने पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत अन्तरंग रोप-उपचार के लिए आने वाले व्यक्तियों के परिवारकों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने हेतु अस्थायी आवास (ट्राजिट होम्स) का निर्माण करने के लिए रेडक्रास की जिला शाखाओं के माध्यम से जिला मुख्यालय अस्पतालों और उप-मंडल मुख्यालय अस्पतालों को सहायता दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उप-मंडल अस्पतालों में विशेष-रूप से अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले उप-मंडलों में ऐसे अस्थायी आवास (ट्राजिट होम्स) की अधिक जरूरत है क्योंकि कमजोर वर्ग के इन लोगों को मुश्किल से ही कोई आवास मिल पाता है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं और उड़ीसा में जिले-वार तत्सम्बन्धी उपलब्धियां क्या हैं/इनके लिए कितना खर्च रखा गया था ?

उर्जा मंत्री तथा मानव बिमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत अन्तरंग रोगी विभाग में उपचार के लिए आने वाले रोगियों के अटेंडेंटों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने हेतु अस्थायी आवास (ट्राजिट होम्स) का निर्माण करने के लिए जिला रेडक्रास शाखाओं के माध्यम से जिला मुख्यालय अस्पतालों और उपमंडलीय मुख्यालय अस्पतालों को सहायता प्रदान की जाती हो।

भारतीय रेडक्रास सोसाइटी, नई दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार, उनके पास भी अस्पतालों में अर्धी रोगियों के अटेंडेंटों के लिए आवास की व्यवस्था करने की कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है। लेकिन पंजाब और हरियाणा में रेडक्रास सोसाइटी की शाखाओं ने इन राज्यों में स्थित कुछ जिला अस्पतालों में अन्तरंग रोगियों के अटेंडेंटों के लिए आवास सुविधाएं स्थापित की हैं।

प्रधान मंत्री आवास का मचीकरण

[अन्तुवार]

9038. प्रो० के० बी० बालस : क्या लहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या प्रधान मंत्री रेसकोर्स रोड स्थित आवास में चले गए हैं;
- (ख) क्या इस आवास का नवीकरण किया गया है;
- (ग) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है; और
- (घ) क्या इस आवास का देश के भागी प्रधान मंत्रियों के लिए स्थाई आवास के रूप में उपयोग किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुराली मारन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) भारत के प्रधान मंत्री का सरकारी निवास नियत करने का प्रस्ताव बिचाराधीन है ।

विदेशी माता-पिताओं द्वारा गोद लिए गए भारतीय बच्चे

9039. प्रो० के० बी० चामस : क्या अम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी माता-पिताओं ने कितने भारतीय बच्चे गोद लिए हैं;
- (ख) क्या विदेशों में इन गोद लिए बच्चों के कल्याण के बारे में पता लगाने के लिए कोई सरकारी एजेंसी है;

(ग) क्या सरकार को कोई सूचना मिली है कि इन गोद लिए बच्चों को विदेशों में दास के रूप में बेच दिया जाता है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि भारत में बच्चे गोद लेने वाली कुछ एजेंसियों विदेशी माता-पिता द्वारा भारतीय बच्चे गोद लेने के लिए विदेशों से अत्यधिक धनराशि प्राप्त करती है ?

अम और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) भारत की विभिन्न अदालतों से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों में दत्तक ग्रहण के लिए न्यायालय के प्राधिकार के अन्तर्गत विदेश ले जाए गए बच्चों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	वत्सक ग्रहण की संख्या
1987	814
1988	698
1989	813

(ख) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार भारत सरकार समय-समय पर प्रस्थापित दत्तक ग्राही माता-पिता के देश में भारतीय दूतावासों अथवा उच्चायोगों से विदेशों में ले गए ऐसे बच्चों के नाम

फले तथा अन्य बिबरन, इस अनुरोध के साथ भेजती है कि वह वृत्तावास अथवा उच्चयोग, वीसी भी स्थिति हो, ऐसे बच्चों के कल्याण तथा प्रगति की सततापूर्ण निगरानी करेगा।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(घ) श्री लक्ष्मी कान्त शम्भेय द्वारा द.पर रिट याचिका (सी० आर० एल०) संख्या 1171/1982 में अपने निर्णयों की शृंखलाओं में उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है कि न्यायालयों को दत्तक ग्रहण करने वाले विदेशी माता-पिता द्वारा समाज अथवा बाल कल्याण एजेन्सी को भुगतान की जाने वाली धनराशि का विधायक करण आवश्यक है। यह अनुरोधन व्यय की शक्ति के रूप में है। केवल ऐसी धनराशि जो कि अनुरोधन व्यय के रूप में न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाए। समाज अथवा बाल कल्याण एजेन्सी द्वारा बच्चे के अभिभावक के रूप में नियुक्त विदेशी माता-पिता से बसूल करेगी। समाज अथवा बाल कल्याण एजेन्सी द्वारा बिल अथवा बाउचर प्रस्तुत करने पर, बच्चे पर किए गए शल्य तथा चिकित्सा व्यय को भी बसूल किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि समाज अथवा बाल कल्याण एजेन्सी, जो किसी विदेशी के आवेदन की जांच करती है; विदेशियों से न्यायालय द्वारा निर्धारित खर्च बसूल करने की हकदार है। यह बसूली 6000 रुपए की राशि से अधिक नहीं होगी।

महाराष्ट्र की लेंडी परियोजना

9040. डा० बेंकदेश काबडे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में लेंडी परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस परियोजना के निर्माण कार्य को पूरा करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वलुभाई कोटाडिकवा) : (क) और (ख) महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश सरकार को जल के उपयोग और लागत के बंटवारे के सम्बन्ध में किसी अन्तर्राज्यीय समझौते पर पहुंचने के पश्चात संशोधित परियोजना प्रस्ताव तैयार करने की सलाह दी गयी है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों को क्वाटर्नों का आवंटन

9041. श्री ओकाल बल नरसिंहराव चाडियर : क्या सहायी शिक्षा मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों को दिल्ली/नई दिल्ली में कितने क्वाटर्न किस-किस स्थानों पर आवंटित किए गए हैं;

(ख) क्या वरियार्ज में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रबन्ध और स्टाफ क्वाटर्न जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं और उनकी निवन्धित देख-रेख नहीं की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाही की है ?

सहरी विकास मंत्री (श्री भुरासोली मारन) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों को संलग्न विवरणनुसार 278 क्वाटर् आबंटित किए गए हैं ।

(ख) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है ?

विवरण

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के कम्बों में सरकारी बास के व्योरे

क्रम सं०	आबंटिती का नाम	निवास स्थान	बास का टाईप
1	2	3	4
1.	डा० ए० सी० हज़ारिका	ए-2453, नेताजी नगर	डी
2.	डा० सत्य शर्मा	डी-1/79, चाणक्यपुरी	ई
3.	डा० ए० सेन गुप्ता	डी-11/ए-2736, नेताजी नगर	ई
4.	डा० जे० खण्डपुर	डी-11/11, किदवाई नगर (पूर्वी)	ई
5.	डा० बी० के० अग्निहोत्री	डी-11/4, किदवाई नगर (पश्चिमी)	ई
6.	डा० बलचिन्दर कौर	23(एल० एफ०), तानसेन मार्ग	डी
7.	डा० ए० के० दास	सी-581, लक्ष्मीबाई नगर	डी
8.	डा० जी० सी० नायक	डी-1/ए-1, लोधी रोड	डी
9.	डा० जे० एस० अहूजा	151, लक्ष्मीबाई नगर	डी
10.	डा० कमलेश सूद	सेक्टर 13/357, आर० के० पुरम	डी
11.	डा० एम० के० चक्रवर्ती	ए-2521, नेताजी नगर	डी
12.	डा० एन० बनर्जी	सेक्टर 3/157, आर० के० पुरम	डी
13.	डा० टी० के० संवरिया	ए-67(2539), नेताजी नगर	डी
14.	डा० पी० गंडोत्रा	सेक्टर 12/1345, आर० के० पुरम	डी
15.	डा० एन० सी० दत्ता	डी-11/260, चाणक्यपुरी	ई
16.	डा० आर० नरुला	सेक्टर 12/एन-294, आर० के० पुरम	डी
17.	डा० रमेश तिवारी	डी-11/132, किदवाई नगर (प०)	ई

1	2	3	4
18.	डा० रेखा अग्रवाल	740, लक्ष्मीबाई नगर	डी
19.	डा० आर० एम० बालिया	785, लक्ष्मीबाई नगर	डी
20.	डा० एस० के० गुप्ता	ई-94(1862), नानकपुरा	डी
21.	डा० सरोज शर्मा	डी-32, पंडारा रोड	डी
22.	डा० एस० के० अधिकारी	897, लक्ष्मीबाई नगर	डी
23.	डा० एस० भट्टाचार्य	सेक्टर 4/369, आर० के० पुरम	डी
24.	डा० एस० अग्रवाल	डी-11/ए-23, नानकपुरा	ई
25.	डा० सन्तोष चड्ढा	एक्स बाई-49, सरोजनी नगर	डी
26.	डा० एस० सी० महापात्रा	एफ-134, नौरोजी नगर	सी
27.	डा० एस० बी० दास	सेक्टर 9/397, आर० के० पुरम	डी
28.	डा० शीला मोहन	सेक्टर 8/882, आर० के० पुरम	डी
29.	डा० मीरा श्रीवास्त	ए-23/184, लोधी कालोनी	डी
30.	डा० एस० मजुमदार	डी-11/79, काका नगर	ई
31.	डा० डी० कटोच	सी-784, लक्ष्मीबाई नगर	डी
32.	डा० एल० डी० सनवाल	सेक्टर 12/795, आर० के० पुरम	सी
33.	डा० सी० पी० बिधिना	सेक्टर 3/332, आर० के० पुरम	डी
34.	डा० डी० एस० शर्मा	ए-117, लक्ष्मीबाई नगर	डी
35.	डा० हरिकृष्ण	सेक्टर 1/203, आर० के० पुरम	सी
36.	डा० के० एन० अग्रवाल	सेक्टर 3/546, आर० के० पुरम	डी
37.	डा० आर० खिता	सेक्टर 4/803, आर० के० पुरम	डी
38.	डा० रामलाल	जी-30(2312), नेताजी नगर	सी
39.	डा० राजेश जरक	सेक्टर 8/एन-639, आर० के० पुरम	डी
40.	डा० आर० पी० सिंह	सेक्टर 1/117, साबिक नगर	सी
41.	डा० एस० मजुमदार	ए-71, नेताजी नगर	सी
42.	डा० डी० एस० रावत	ए-317, सरोजनी नगर	सी
43.	डा० अम्बिका दास	368, लक्ष्मीबाई नगर	डी
44.	डा० डी० आर० डे	बैड-49, सरोजनी नगर	डी
45.	डा० इन्दिरा बिसोई	सेक्टर 1/99, आर० के० पुरम	सी

1	2	3	4
45क.	डा० मीरा हजेला	बी० डी०-948, सरोजनी नगर	सी
46.	डा० एस० त्रिन्दा	डी-22/1028, लोधी रोड	सी
47.	डा० आर० सी० महापात्रा	585, लक्ष्मीबाई नगर	डी
48.	डा० के० आर० रथ	सैक्टर 4/292, आर० के० पुरम	डी
49.	डा० ए० राय	ए-2524, नेताजी नगर	डी
50.	डा० जी० एन० बहेरा	ए-170, लक्ष्मीबाई नगर	डी
51.	डा० कमल कुमार	जी-305, नानकपुरा	सी
52.	डा० नरेन्द्र सिंह	13, एन० डब्ल्यू० मोती बाग	सी
53.	डा० आर० के० गुप्ता	डी-22/1097, लोधी रोड	सी
54.	डा० पुष्पालता	जी-115, सरोजनी नगर	सी
55.	डा० निर्मलेन्दु धर	सैक्टर 8/एन-182, आर० के० पुरम	डी
56.	डा० ऊषा बाली	755, लक्ष्मीबाई नगर	डी
57.	डा० हिमांशु भूषण	सैक्टर 3/212, आर० के० पुरम	सी
58.	डा० बृज भूषण	ए-2/8, पेशवा रोड	डी
59.	डा० ए० के० कोहली	डी-1/104, चाणक्यपुरी	ई
60.	डा० एम० के० नंदिमोलियार	5-ए, वसन्त बिहार	सी
61.	डा० सिधाराज	डी-1/83, लोधी रोड	सी
62.	डा० सन्तोष कट्टारिया	सैक्टर 12/72, आर० के० पुरम	सी
63.	डा० शिमोश हर्सेन	306, लक्ष्मीबाई नगर	डी
64.	डा० दिशेष श्रीवास्तव	105, एफ, आराम बाग	सी
65.	डा० किरण कपूर	जैड-7, तिमारपुर	बी
66.	डा० टी० गर्ग	एस-डी-453, मंदिर मार्ग	बी
67.	डा० रीता श्रीवास्तव	डी-2/5, पेशवा रोड	डी
68.	डा० ए० के० माथुर	22(एल० एफ०), तानसेन मार्ग	डी
69.	डा० ए० सी० तिम्या	30 : 3-डी/सैक्टर III, डी० आई० जैड० एरिया	सी
70.	डा० भरतसिंह	400-ई, करोल बाग	सी
71.	डा० पद्मिनी दास	2-209, तिमारपुर	बी

1	2	3	4
72.	डा० टी० पी० सोलंकर	28-सी, प्रेस रोड	ई
73.	डा० एस० आर० हुलकर	डी-11/2/4, एम्बुबूच गंज	ई
74.	डा० एम० एम० भट्टाचार्य	14-सी(एम० आई० बी०), मायापुरी	ई
75.	डा० आर० मनचन्दा	एच-158, सरोजनी नगर	सी
76.	डा० एस० गुलाटी	213, राज एवेन्यू	ई
77.	डा० बी० के० घाटिया	75-11, एफ(795), तिमारपुर	सी
78.	डा० पी० एस० दास गुप्ता	डी-9-सी, मायापुरी	ई
79.	डा० ए० के० भार्गव	ई-396, करोल बाग	सी
80.	डा० एच० एस० भट्टाचार्य	108, प्रेस रोड	ई
81.	डा० एस० एन० मिश्र	डी-1/बी, मायापुरी	ई
82.	डा० एस० आर० सरोज	सेक्टर 4/209, आर० के० पुरम	बी
83.	डा० बी० आर० ब्रह्मान	सेक्टर 8/842, आर० के० पुरम	डी
84.	डा० एम० एस० खेडी	ए-179, पंढारा रोड	डी
85.	डा० नाथू लाल	119, लक्ष्मीबाई नगर	डी
86.	डा० एस० के० श्रीवास्तव	डी-21, देव नगर	ई
87.	डा० श्रीमती कृष्णा सिंह	डी-11/3, किदवाई नगर (पूर्वी)	ई
88.	डा० जो० एन० कृष्णा	18-सी, पार्क स्ट्रीट	ई
89.	डा० एस० एन० माधुर	डी-11/33, किदवाई नगर (पूर्वी)	ई
90.	डा० ए० के० शर्मा	डी-11/129, किदवाई नगर (पश्चिमी)	ई
91.	डा० श्रीमती पुष्पा सिंह	ए-38, पंढारा रोड	डी
92.	डा० एस० ए० पाशा	सेक्टर 1/135/बी, एम० बी० रोड	बी
93.	डा० एस० के० सूद	बी-जी/7(एस० एफ०) बाबर ब्लेस	डी
94.	डा० श्रीमती अलत्या अमन	19/967, लोधी रोड	सी
95.	डा० श्रीमती बी० जैन	17(एस० एफ०) तानसेन मार्ग	डी
96.	डा० बी० पी० चैतियार	ए-239, लक्ष्मीबाई नगर	डी
97.	डा० श्रीमती बी० बी० लक्ष्मी	925, बाबा खडक सिंह मार्ग	सी
98.	डा० श्रीमती एम० एच० रीसा	सेक्टर 11/2, डी-68, डी० आई० डी० एरिया	सी
99.	डा० आर० एन० सिंह	5, कानीबाड़ी मार्ग	डी

1	2	3	4
100.	डा० ए० आर० दास	एच-276, कालीबाड़ी मार्ग	डी
101.	डा० श्रीमती एम० पांडे	जे० जी० 30, मंदिर मार्ग	बी
102.	डा० ए० के० गुप्ता	ए-23/143, लोधी रोड	डी
103.	डा० जगदीश सरन	ए-64, पंढारा रोड	डी
104.	डा० एस० सी० मेहरा	1074-बी, के० एस० मार्ग	सी
105.	डा० बी० रामचन्द्रन	सेक्टर-4/271, आर० के० पुरम	सी
106.	डा० सी० पी० गुप्ता	सेक्टर-2/42-3बी, डी आई जैड	सी
107.	डा० पी० रविन्द्रन	बी-एल 61 एस 11/2-सी डी आई जैड	सी
108.	डा० एस० वी० रामकृष्णन	1081-बी० के० एस० मार्ग	सी
109.	डा० एम० वी० गनेश	ए-331, किडवई नगर	बी
110.	डा० सत्य प्रकाश	बी-4/36, लोधी रोड	सी
111.	डा० ए० के० कांगू	ए-23/152, —वही—	बी
112.	डा० सुरेन्द्र पंवर	ए-2'2, पंढारा रोड	बी
113.	डा० (श्रीमती) एम० त्यागी	बी-13, —वही—	डी
114.	डा० बिनोद सहगल	19-डी, सिमल बाग	डी
115.	डा० बी० डी० शर्मा	सेक्टर-12/1347, रा० क० पुरम	डी
116.	डा० (श्रीमती) एस० श्रीवास्तव	बी-64/536, नानकपुरा	डी
117.	डा० जे० एम० राव	जे-572, मन्दिर मार्ग	बी
118.	डा० एम० के० तोमर	एच-526 बी० के० एस० मार्ग	बी
119.	डा० सुरेश कुमार	1/259-सरोजिनी नगर	सी
120.	डा० सुधीर सिन्हा	6-एल० बी० नगर	डी
121.	डा० मानसिंह	सेक्टर-2/2डी/44, डी आई जैड एरिया	सी
122.	डा० बी० एम० दास	सेक्टर-3/44, सादिक नगर	डी
123.	डा० डी० एस० अरोड़ा	ए-23/182, लोधी रोड	डी
124.	डा० जी० डी० गुप्ता	डी-2/8, किडवई नगर (वेस्ट)	ई
125.	डा० श्रीमती के० के० कालरा	ए-2/2, पेगाबा रोड	डी

1	2	3	4
126.	डा० एम० के० गर्ग	डी-3/6 —बही—	डी
127.	डा० आर० एम० डे	29-सी, प्रेस रोड	ई
128.	डा० (श्रीमती) एस० उष्यल	डी-1/64, रवीन्द्र नगर	ई
129.	डा० पी० के० राय	9(एस एफ) बाबर प्लेस	डी
130.	डा० के० के० कंचन	डी-4/4, लोधी रोड	सी
131.	डा० (श्रीमती) रत्ना शर्मा	डी-2/368, पंढारा रोड	ई
132.	डा० (श्रीमती) सुरेन्द्र कौर	डी-46, एस० एस० पार्क	ई
133.	डा० (श्रीमती) स्नेह लता शर्मा	डी-2/335, पंढारा रोड	1/डी
134.	डा० एच० के० बलहोत्रा	डी-2/ए-24, मोती बाग (बालक)	ई
135.	डा० श्रीमती पी० संगम	डी-2/2781/नेताजी नगर	ई
136.	डा० बी० के० सिन्हा	ए-94, पंढारा रोड	डी
137.	डा० जीवन प्रकाश	5(एस० एफ०) टोडरमल रोड	डी
138.	डा० कृष्ण कुमार	ए-21/117, लोधी रोड	डी
139.	डा० (श्रीमती) एम० एल० जयलक्ष्मी	सेक्टर-4/683, रा० कृ० पुरम	डी
140.	डा० (श्रीमती) मुकुल सरकार	ए-20/54, लोधी रोड	डी
141.	डा० (श्रीमती) ऊषा भटनायर	5-ई, मिटो रोड	डी
142.	डा० जे० के० नायक	ए/5, एम्बुयूज गंज	सी
143.	डा० (श्रीमती) कमल बिसवाल	सेक्टर-1/3, साबिक नगर	सी
144.	डा० आर० बोयेव	सेक्टर-4/294, आर० के० पुरम	डी
145.	डा० बी० सी० लम्बाजी	2(एस० एफ०) टोडरमल झबावर	सी
146.	डा० बजरंग लाल	सेक्टर-2/51-2डी, डी० आई० जैड० एरिया	डी
147.	डा० बी० के० स्थाना	सेक्टर-8/एन-187, रा० कृ० पुरम	डी
148.	डा० एन० सी० भांडी	सेक्टर-2/2डी-73 डी० आई० जैड०	सी
149.	डा० सी० बी० प्रसाद	सेक्टर-9/एन-541, आर० के० पुरम	डी
150.	डा० जयप्रकाश	सेक्टर-2/61, 1ए डी० आई० जैड० एरिया	सी

1	2	3	4
151.	डा० आर० जे० अग्निहोत्री	252, लक्ष्मीबाई नगर	डी
152.	डा० पी० सी० राय	डी-2/152, किदवई नगर (वेस्ट)	ई
153.	डा० ए० के० बनर्जी	73, सरकुलर रोड	VI
154.	डा० बी० चक्रवर्ती	586, लक्ष्मीबाई नगर	डी
155.	डा० (श्रीमती) एस० चोपी देवी	ओ-7-2, रा० कृ० पुरम	ई
156.	डा० एम० आर० दास	सेक्टर-13/ओ-3-1, रा० कृ० पुरम	ई
157.	डा० के० सी० सिल	डी-25, देवनगर	ई
158.	डा० सुरेन्द्र चुग	डी-2/44, किदवई नगर (वेस्ट)	ई
159.	डा० यु० सी० गंग	सेक्टर-4, 539, आर० के० पुरम	डी
160.	डा० दीपक सेन गुप्ता	बी-86, नानकपुरा	डी
161.	डा० सुनील कुमार	एक्स बाई-48, सरोजिनी नगर	डी
162.	डा० के० पी० मलिक	24/15 एम० बी० रोड	ई
163.	डा० आर० के० नेगी	डी-2/21 किदवई नगर (ई)	ई
164.	डा० एम० बी० बाघुर	डी-2/7, पेशवा रोड	डी
165.	डा० गुरचरन सिंह	क्यू-6-1, आर० के० पुरम	ई
166.	डा० के० एन० हंस	ए-13, पंढारा रोड	डी
167.	डा० श्रीमती बी० एल० नैय्यर	डी-2/195, किदवई नगर वेस्ट	ई
168.	डा० श्रीमती भारती मिनोचा	एस-3/603, आर० के० पुरम	डी
169.	डा० यू० सेठिया	एस-3/329 आर० के० पुरम	डी
170.	डा० पी० के० सरीन	डी-2/22 शाहजहां रोड	ई
171.	डा० एस० के० कश्यप	डी-2/227 किदवई नगर (वेस्ट)	ई
172.	डा० बीरबल टण्डल	जी-428 नौरोजी नगर	डी
173.	डा० सरदार सिंह	एस-9/43 आर० के० पुरम	डी
174.	डा० चंचल ससुजा	सी-2/23 तिलक मार्ग	VI
175.	डा० अमर जीवन	डी-2/18 काका नगर	ई
176.	डा० अफन सहाय	सी-2/37 शाहजहां रोड	ई

1	2	3	4
177.	डा० के० के० चतुर्वेदी	ए-23/165 लोपो रोड	डी
178.	डा० एस० सी० शर्मा	डी-23 देव नगर	ई
179.	डा० एम० पी० अन्नवाल	15 फायर ब्रिज लेन	ई
180.	डा० एम० एन० साहिब	718 एम० डी० नगर	डी
181.	डा० केशव गोस्वामी	998 बी० के० एस० मार्ग	सी
182.	डा० बी० रमेश	एस-12/1082 आर० के० पुरम	डी
183.	डा० श्रीमती ज्योति पुरी	बी-1/5 पेसबा रोड	डी
184.	डा० डब्ल्यू० डी० भाटिया	एम 553-एस-9/आर० के० पुरम	डी
185.	डा० बी० आर० साहनी	64/2बी एस-2/डी० आई० जैड० एरिया	सी
186.	डा० यशबन्त सिंह	डी जी-855 सरोजनी नगर	सी
187.	डा० मधु गुप्ता	5(एल एफ) बाबा प्लेस	डी
188.	डा० अदन कुमार	76/2सी/एस-2/डी० आई० जैड० एरिया	सी
189.	डा० श्रीमती कुमुद	एस-1/2/447 डी० आई० जैड० एरिया	सी
190.	डा० के० आर० पाल	जैड-50 सरोजनी नगर	डी
191.	डा० एस० बर्मन	एस-1/26 आर० के० पुरम	सी
192.	डा० बी० सी० राय	11-डी देव नगर	ई
193.	डा० सी० पी० गुप्ता	एस-4/1069 आर० के० पुरम	IV
194.	डा० एम० पी० बुधे	डी-1/39 रविन्द्र नगर	V
195.	डा० पी० एस० सहारिया	डी-2/42 फिदबई नगर (ई)	ई
196.	डा० स्वर्णजीत देव	बी-4/6 पेसबा रोड	डी
197.	डा० बी० आर० शर्मा	ई-21/91 लोधी कोलोनी	डी

1	2	3	4
207. 2,	—बही—	IV	डा. श्रीकृष्ण कर्मि बावला
208. 1, श्री. जी. एच. एल. डिस्सेसरी, मोती बाग, नई दिल्ली	—बही—	—बही—	डा. एल. के. वर्मा
209. 2,	—बही—	—बही—	बंस श्री. जी. कुल्ल
210. 3,	—बही—	—बही—	डा. वे. के. बासु
211. 4,	—बही—	—बही—	डा. एल. एल. यवारीया
212. 1, सी. जी. एच. एल. डिस्सेसरी, नाबं एवेयू, नई दिल्ली	—बही—	—बही—	डा. बा. सी. बुराना
213. 2,	—बही—	—बही—	डा. बा. एल. एल. पांडा
214. 1, श्री. जी. एच. एल. डिस्सेसरी, रामकृष्णपुरम-3, नई दिल्ली	—बही—	—बही—	डा. के. के. पांडेय
215. 2,	—बही—	—बही—	डा. जी. बोहल
216. 1, सी. जी. एच. एल. डिस्सेसरी, रामकृष्णपुरम-4, नई दिल्ली	—बही—	—बही—	डा. रोबिन दास
217. 2,	—बही—	—बही—	डा. श्रीमती एच. श्रीबालिष्ठ
218. 1, श्री. जी. एच. एल. डिस्सेसरी तथा बालेन बालसतान, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली	—बही—	—बही—	डा. श्रीमती बुरसरन श्रीर
219. 2,	—बही—	—बही—	डा. श्रीमती सुलेखा सरत
220. 3,	—बही—	—बही—	डा. श्रीमती बनीषा कस्तेना

1	2	3	4
221. 4,	—बही—	IV	डा. श्रीमती रीता मोह्ल्ती
222. 1, सी. जी. एच. एस. डिस्पेंसरी, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली	—बही—	—बही—	डा. मिसेज नीलम भगवानी
223. 2,	—बही—	—बही—	डा. श्रीमती एस. दास
224. 3,	—बही—	—बही—	डा. श्रीमती मीरा बेसवा
225. 4,	—बही—	—बही—	डा. श्रीमती सुनीता कासिया
226. 1, सी. जी. एच. एस. डिस्पेंसरी, बैलीबली रोड, नई दिल्ली	—बही—	—बही—	डा. पी. पी. सी. रिबानी
227. 2,	—बही—	—बही—	डा. बी. एस. माटा
228. 3,	—बही—	—बही—	डा. जी. आर. बन्ना
229. 4,	—बही—	—बही—	डा. हरबन्स सिंह
230. 1, सी. जी. एच. एस. डिस्पेंसरी नानकपुरा, नई दिल्ली	—बही—	—बही—	डा. श्रीमती कल्पना सैकिया
231. 2,	—बही—	—बही—	डा. एस. के. गुप्ता
232. 1, सी. जी. एच. एस. डिस्पेंसरी, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली	—बही—	—बही—	डा. बी. दास
233. 2,	—बही—	—बही—	डा. एम. एल. शर्मा
234. 1, सी. जी. एच. एस. डिस्पेंसरी, होजबास, नई दिल्ली	—बही—	—बही—	डा. जी. एस. माथुर

1	2	3	4
235. 1, सी. जी. एच. एस. नरायण, नई दिल्ली		IV	डा. रमेश जानन्द
236. 2,	—बही—	—बही—	डा. एच. के. वाही रमानी
237. 1, सी. जी. एच. एस. डिप्लॉमरी, नांगलराय, नई दिल्ली		—बही—	डा. बी. चक्रवर्ती
238. 2,	—बही—	—बही—	डा. ए. के. गुहा
239. ए-सी. जी. एच. एस. डिप्लॉमरी, दरियाबंज, नई दिल्ली		II	डा. बी. बी. जैना
240. ए-1, द्वितीय तम	—बही—	—बही—	डा. एच. देव
241. बी-1, —बही—	—बही—	—बही—	डा. एच. के. बचीबा
242. सी-1, —बही—	—बही—	—बही—	डा. भीम सेन बहेड़ा
243. आई-1, —बही—	—बही—	—बही—	डा. श्रीमती मंजु लैन

दिल्ली/नई दिल्ली में सी० जी० एच० एल० डाक्टरों को सामान्य पूल
आवास के आबंटन वसति बाला विवरण

क्रम सं०	आबंटी का नाम	उनके दफ्तल में जो कमरों का सेट है उसका नम्बर
1	2	3
244.	श्रीमती अजीत कौर (स्वास्थ्य अधिकारी)	ई-503, सी. आर. एच.
245.	श्रीमती जी. पी. पार्वती, स्वास्थ्य अधिकारी	डी-301, सी. आर. एच.
246.	डा. श्रीमती एम. आर. सेमुअल	डी-501, सी. आर. एच.
247.	राजेन्द्र प्रसाद, स्वास्थ्य अधिकारी	डी-607, सी. आर. एच.
248.	डा. एम. आर. भौमिक	104 एम. आर. एच.
249.	टी. के. तालुकदार, स्वास्थ्य अधिकारी	507 एशिया हाउस
250.	डा. अजीत कुमार दास	716 एशिया हाउस
251.	डा. ए. के. अग्रवाल	ए-605, सी. आर. एच.
252.	डा. श्रीमती पुष्पावती सिंह	बी-206, सी. आर. एच.
253.	डा. श्रीमती पी. गोस्वामी	बी-606, सी. आर. एच.
254.	डा. सच्चिदानन्द त्रिपाठी	सी-201, सी. आर. एच.
255.	डा. के. बी. गुप्ता	सी-208, सी. आर. एच.
256.	डा. दीपांकर दास	सी-703, सी. आर. एच.
257.	डा. श्रीमती बिनोद लाल	डी-011, पी. बी. एच.
258.	डा. बी. आर. शर्मा	डी-315, पी. बी. एच.
259.	डा. श्रीमती अल्का मित्तल	ई-115, पी. बी. एच.
260.	डा. श्रीमती आशा रानी, गंडापें	ई-208, पी. बी. एच.
261.	डा. नरगिस सोलीना	ई-303, पी. बी. एच.
262.	डा. श्रीमती बीना नीलरत्न	डी-017, पी. बी. एच.
263.	डा. श्रीमती स्नेह लता	ई-219, पी. बी. एच.
264.	डा. एस. एस. लालबानी	एफ-414, पी. बी. एच.
265.	डा. श्रीमती रबील जसे	बी-102, पी. बी. एच.
266.	डा. जे. एम. दास	बी-213, पी. बी. एच.
267.	डा. एस. के. वर्मा	बी-222, पी. बी. एच.

1	2	3
268.	डा. श्री कान्ता बसिक	बी-319, पी. बी. एच.
269.	डा. जे. एन. भट्टाचार्य जी	बी-505, पी. बी. एच.
270.	डा. जी. के. विश्वास (डॉ. जी. एच. एस.)	सी-018, पी. बी. एच.
271.	डा. बी. एन. सरदाना (—बही—)	सी-303, पी. बी. एच.
272.	डा. कुमारी विजय लक्ष्मी	सी-122, पी. बी. एच.
273.	डा. बी. स्नेह	ए-005, पी. बी. एच.
274.	डा. एस. के. धर	ए-121, पी. बी. एच.
275.	डा. ए. के. सिन्हा	ए-304, पी. बी. एच.

क्रम सं०	क्वार्टर नं० तथा इलाका	टाइप	आबंटी का नाम
276.	सेक्टर 4/667, रामकृष्णपुरम	IV	डा. भार. के. गोयल
277.	सेक्टर 4/1042, —बही—	—बही—	डा. एस. बी. एस. दे
278.	डी-11/ए-24(72) नानकपुरा	V	डा. एच. के. मलहोत्रा

दिल्ली के दूसरे मास्टर प्लान को अन्तिम रूप देना

9042. श्री श्रीकांत वल्लभ नरसिंहराज बाबियर :

श्री यशवन्तराव पाटिल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लिए दूसरे मास्टर प्लान के अन्तिम रूप देने में देरी के क्या कारण हैं;

(ख) दूसरा मास्टर प्लान कब तक तैयार हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री सुरासोली नारम) : (क) से (ग) वर्ष 1962 में लागू की गई दिल्ली बृहद योजना में विस्तृत संशोधन किए जाने अपेक्षित थे। इस प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2001 तक के सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया प्राकृतिक संशोधनों पर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करना, प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार करना, विशेषज्ञों तथा दिल्ली नगर कला आयोग आदि जैसे विभिन्न अभिवादी वाले शर्कों के साथ पारस्परिक क्रिया शामिल है। उपर्युक्त को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए गए संशोधन प्रस्ताव औपचारिक अनुमोदनार्थ फिलहाल सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं।

नगर भूमि सीमा (अधिकतम और विनियमन) अधिनियम को समाप्त करना

9043. श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रवृत्त होने के बाद कर्नाटक में कितने एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया;

(ख) क्या उक्त अधिनियम स्थानीय आवश्यकताओं के लिए प्रभावी नहीं है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से उपर्युक्त अधिनियम को समाप्त करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) कर्नाटक सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1989 तक अधिनियम के अन्तर्गत 1942.8 एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई है।

(ख) इस आशय की कोई जानकारी केन्द्रीय सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

9045. श्री कृपाल सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने तरणतारण (अमृतसर) में 20,000 मीटरी टन की क्षमता वाले गोदामों का निर्माण करने के लिए कतिपय ठेकेदारों के साथ वर्ष 1980 में कोई अनुबन्ध किया था;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई सिफारिश की तुलना में पंजाब सरकार द्वारा इन ठेकेदारों को कितनी मात्रा में सीमेंट की आपूर्ति की गई;

(ग) क्या कम मात्रा में सीमेंट की आपूर्ति किए जाने के कारण गोदामों के निर्माण में विलम्ब हुआ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन ठेकेदारों द्वारा लाखों रुपए व्यय किए जाने के बावजूद भारतीय खाद्य निगम ने इन गोदामों को इन व्यक्तियों से किराए के आधार पर नहीं लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्छा) : (क) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम

ने तरनतारन (अमृतसर) में 20,000 मीटरी टन के गोदामों का निर्माण करने के लिए मै० गुरबवाल सिंह एण्ड को-ओनर्स के साथ जुलाई, 1980 में एक करार किया था।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम ने उपर्युक्त निर्माण कार्य के लिए 1200 मीटरी टन सीमेंट के लिए सिफारिश की थी। पंजाब सरकार द्वारा इन गोदामों के लिए उक्त पार्टी को वास्तव में सप्लाई की गई मात्रा के बारे में सूचना निगम के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) निगम द्वारा जुलाई, 1980 में किए गए करार के अनुसार, इस पार्टी को सात महीने के अन्दर गोदामों का निर्माण कार्य पूरा कर लेना चाहिए था। वे समय-समय पर 31 मार्च, 1984 तक बढ़ा दी गई अवधि के दौरान भी गोदामों को पूरा नहीं कर सके थे। अतः भारतीय खाद्य निगम ने गोदामों को नहीं लिया था।

अनाथों का कल्याण

[दिल्ली]

9046. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या धर्म मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में अनाथों के कल्याण में लगे संगठनों का जिला-वार ब्यौरा क्या है तथा वे सोसाइटियां और संगठन पूर्ण रूप से निर्वाचित और पंजीकृत हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक संगठन में कितने-कितने बालक और बालिकाओं की देखभाल होती है;

(ग) अनाथ तथा असहाय बच्चों के कल्याण के लिए इन संगठनों द्वारा क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(घ) सरकार इन संगठनों को प्रतिबर्ष कितने प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ङ) क्या कुछ संगठनों द्वारा धन के दुरुपयोग किए जाने तथा इन बच्चों से बलपूर्वक काम कराने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

धर्म और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय धार्मिक सम्मेलन

[अनुवाद]

9047. श्री बाई० एस० राकेश्वर रेड्डी : क्या धर्म मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में 21 अप्रैल, 1990 को आयोजित भारतीय धार्मिक सम्मेलन में चर्चा के दौरान नए धर्म कानून के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक एक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) और (ख) कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने महसूस किया कि बोर्ड स्तर पर, कर्मकार प्रतिनिधि बोर्ड की कुल सदस्यता का 50% होने चाहिए नियोजकों के प्रतिनिधियों ने सिफारिश की कि प्रारम्भ में बोर्ड में "कर्मकारों" और श्रमिकों का एक-एक प्रतिनिधि होना चाहिए। राज्य मन्त्रियों की राय यह थी कि इसे 25% तक सीमित रखा जाए।

(ग) इस सम्बन्ध में उपयुक्त विधान पर सरकार विचार कर रही है।

मेडिकल के आखार पर सरकारी क्वार्टरों का आबंटन

9048. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रत्येक कालोनी में टाइप-II के कितने सरकारी क्वार्टर खाली हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने सरकारी कर्मचारियों को मेडिकल तथा अन्य आधार पर, बिना पारी के सरकारी क्वार्टर आवंटित किए गए; और

(ग) टाइप-II के क्वार्टर किस तिथि तक आवंटित किए जा चुके हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री भुरासोली मारन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली क्लाय मिल्स, दिल्ली के कर्मचारियों को परिवार पेंशन

9049. श्री ईश्वर चौधरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिल्ली क्लाय मिल्स के 1 अप्रैल, 1989 को बन्द हो जाने से इसके कितने कर्मचारियों को भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत परिवार पेंशन का भुगतान किया जाना था;

(ख) 31 मार्च, 1990 तक इसके कितने कर्मचारियों को इस राशि का भुगतान किया जा चुका है;

(ग) इस मिल के बन्द होने के एक वर्ष के बाद भी इसके शेष कर्मचारियों को परिवार पेंशन के भुगतान में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें यह भुगतान कब तक किया जाएगा ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के अन्तर्गत परिवार पेंशन सदस्य की नौकरी में रहते हुए मृत्यु होने पर ही दी जाती है। वर्तमान मामले में, मिल के कर्मकार सेवानिवृत्ति-व-निकासी लाभ के हकदार हैं। कर्मचारियों की कुल संख्या 2669 है।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 1990 तक 1740 दावों का निपटारा किया गया था और 31 मार्च, 1990 के पश्चात् 615 दावों का निपटारा किया गया था। दावों के कर्मियों को दूर करने के लिए 52 दावों को वापस लौटाया गया है। शेष 262 कर्मकारों ने अपने दावे प्रस्तुत नहीं किए हैं।

(घ) जैसे ही हर प्रकार से पूर्ण दावे प्राप्त हो जायेंगे, सभी लेख दावों का निपटारा सीधे कर दिया जाएगा।

मौलाना आजाद रोड आफिसर्स होस्टल, नई दिल्ली के दुकानदारों की बैंकलिक स्थान उपलब्ध कराना

[हिन्दी]

9050. श्री ईश्वर चौधरी : क्या सहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौलाना आजाद रोड आफिसर्स होस्टल, नई दिल्ली के दुकानदारों को इच्छिमा गेट विकास योजना के अन्तर्गत उनकी दुकानें गिराये जाने के बचने बैंकलिक स्थान अथवा प्लॉट आवंटित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकलिक स्थानों/मकानों का वाणिज्यिक मूल्य इन दुकानदारों की मौजूदा दुकानों के मूल्य के बराबर होगा;

(ग) इन दुकानों को ये स्थान/प्लॉट कब तक आवंटित कर दिए जायेंगे; और

(घ) क्या सरकार का इन दुकानदारों को कोई वित्तीय सहायता भी प्रदान करने का विचार है ?

सहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) मौलाना आजाद रोड आफिसर्स होस्टल, नई दिल्ली के उन दुकानदारों को बैंकलिक स्थानों/प्लॉटों के आवंटन का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है जिन्हें रक्षा मन्त्रालय द्वारा लाइसेंस के आधार पर दुकानें आवंटित की गई थीं, जो दिसम्बर, 1987 में समाप्त हो गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

गेहूं की खरीद

[अनुवाद]

9051. श्री के० एस० राव :

श्री पी० नरसा रेड्डी :

क्या खाद्य और नागरिक वृत्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 में गेहूं की खरीद का जो लक्ष्य रखा गया था, वह पूरा नहीं हो पाया था;

(ख) यदि हां, तो गेहूं की खरीद का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वास्तव में कितना गेहूं खरीदा गया था;

(ग) इसमें गिरावट आने के क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1990-91 के लिए गेहूं की खरीद का क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ङ) उपरोक्त अवधि के दौरान बास्तब में कितना गेहूं खरीदे जाने की सम्भावना है ?

साथ और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) 9 मिलियन मीटरी टन के लक्ष्य के प्रति 9.004 मिलियन मीटरी टन की वसूली हुई थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। किसानों द्वारा वसूली मूल्य पर गेहूं का जो भी स्टॉक पेश किया जाएगा, उस सभी को खरीद लिया जाएगा।

(ङ) लगभग 10 मिलियन मीटरी टन।

विभिन्न अस्पतालों में पूल अधिकारियों का कार्यकरण

[हिन्दी]

9052. श्री कल्पनाच सोनकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न अस्पतालों में कार्य कर रहे पूल अधिकारियों का चयन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद एवं संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूल अधिकारी स्थायी रूप से नियुक्त होने तक उसी पद पर कार्य करते रहते हैं;

(ग) क्या इस समय पूल अधिकारी केवल दो वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पूल अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे डाक्टरों की सेवाओं को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) चिकित्सा पूल अधिकारियों को भारत में अस्पतालों और अन्य चिकित्सा संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है और वे अपने सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान अथवा जब तक उन्हें भारत में अस्थायी अथवा स्थायी रोजगार नहीं मिल जाता, जो भी पहले ही, पूल अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) पूल स्कीम की नवम्बर, 1989 में एक समिति द्वारा समीक्षा की गई थी, जिसकी सिफारिशों को संघ लोक सेवा आयोग और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा स्वीकार कर

लिया गया है। स्वीकार की गई सिफारिशों के अनुसार, चिकित्सा पूल अधिकारियों को इस समय केवल दो वर्ष की निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

(ड) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पूल अधिकारी स्कीम के अन्तर्गत पूल अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे डाक्टरों की सेवाओं को नियमित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में "मंकी" रोग से मौतें

[अनुवाद]

9053. श्री श्री० कृष्ण राव :

श्री श्री० श्री० मुबालगिरियप्पा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक में उत्तर कन्नड, दक्षिण कन्नड और शिमोगा जिलों में गत तीन वर्षों के दौरान "मंकी" रोग से 300 से अधिक मौतें हुई हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त जिलों में यह प्राणघातक रोग 1970 से फैला हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस रोग की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) क्या चिकित्सा वैज्ञानिकों और डाक्टरों ने "मंकी" रोग-निरोधी कोई "सीरम" बनाने में सफलता प्राप्त की है; और

(ङ) केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने उपर्युक्त जिलों में इस रोग के शिकार व्यक्तियों की चिकित्सा और पुनर्वास के लिए अन्य क्या उपाय किये हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) (i) राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा निदेशक की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय के एफ० डी० समन्वय समिति गठित की है जिसके बन, पशुपालन और स्वास्थ्य विभागों के अधिकारी शामिल हैं। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे तथा स्वास्थ्य सेवा महाविद्यालय के विशेषज्ञ महामारी स्थिति की समीक्षा करने तथा निरोधक उपायों के लिए उपयुक्त सुझाव देने हेतु समय-समय पर बैठकें करते हैं।

(ii) एक उपनिदेशक के अधीन एक विषाणु नैदानिक प्रयोगशाला तथा तीन क० एफ० डी० फील्ड स्टेशन कार्य कर रहे हैं। ये स्टेशन निगरानी कार्य करते हैं, जांच कार्य करते हैं और रोगियों का पता लगाने और उपचार करने तथा नियन्त्रण उपायों के बारे में जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अधिकारियों के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों तथा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थानों की सहायता करते हैं।

(iii) जहां से मंकी रोग की सूचना मिलती है वहां पर कीटनाशकों का छिड़काव तथा महान स्वास्थ्य शिक्षा कार्य अन्य विभागों, स्थानीय निकायों और जननेताओं की सहायता से जारी रखा जाता है।

(क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार पीड़ित लोगों के उपचार के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है।

लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय का कार्यकरण

9054. श्री बी० कृष्ण राव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान, वर्षवार, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय में कितनी शिकायतें दर्ज कराई गईं तथा कितनी शिकायतों के अनुसार मरम्मत आदि का काम नहीं किया गया;

(ख) शिकायत दूर करने में सामान्यतः कितना समय लिया जाता है;

(ग) क्या यह पता लगाने के लिए कोई अचानक मौके पर जाकर जांच की गई है कि शिकायत दूर करने में सामान्यतः कितना समय लिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी धोरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस गलती के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ख) दैनिक प्रकृति की शिकायतों को उसी दिन या अगले दिन दूर कर दिया जाता है। तथापि, ऊपरी टैंकों, जाफरियों, दरवाजों, खिड़कियों, डब्लू० सी० पेंस, फ्लशिंग सिस्टमों, फशों आदि जैसी प्रमुख मरम्मतों को बदलने की शिकायतों को निपटाने में अवश्य ही कुछ समय लगता है, और इन्हें संहिता सम्बन्धी औपचारिकताओं का अनुपालन करने तथा निधियों की उपलब्धता की शर्त पर दूर किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। पूछताछ कार्यालयों के नियमित दौरे किए जाते हैं और शिकायतों पर तत्काल ध्यान दिए जाने को सुनिश्चित करने हेतु शिकायत रजिस्ट्रारों का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है। चूंकि इस मामले में किसी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया है इसलिए किसी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष	शिकायतों की संख्या			
	गत वर्ष की शेष शिकायतें	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान दूर की गई	वर्ष के अन्त में दूर न की गई शेष शिकायतें
1988-89	—	43,781	43,685	96
1989-90	96	53,585	53,643	38

देश में रुग्ण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

9055. श्री श्री० कुल्लु राव :

श्री सी० पी० मुबालगिरियप्पा :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी रुग्ण खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद साधव) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित, गैर संगठित और सहकारी क्षेत्रों में हैं। केन्द्र द्वारा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में लघु स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण एककों के बारे में सूचना नहीं रखी जाती।

डिम्बाबन्द वस्तुओं पर उनके मूल्य अंकित करना

9056. श्री राम सागर (संदपुर) : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिम्बाबन्द वस्तुओं पर उनके बहुत अधिक मूल्य अंकित किए जाते हैं और डिम्बाबन्द वस्तु और उनके अंकित मूल्य में कोई समानता नहीं होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले की समीक्षा करने और मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए निर्माताओं, धोक विप्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं आदि का लाभ निश्चित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) पेंकेज में रखी वस्तुओं की बिक्री और उनका वितरण, बाट और माप मानक (पेंकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 जो कि पेंकेजों में बेची जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं के लिए उचित व्यापार और मूल्य अनुशासन स्थापित करने के वास्ते बनाए गए हैं, द्वारा शासित होता है। इन नियमों में यह निर्धारित किया गया है कि पेंकेज पर विक्रय मूल्य अनिवार्य रूप से चोषित किया जाए, ताकि खुदरा व्यापारियों को छपी हुई कीमत से अधिक कीमत वसूल करने से रोका जा सके और उपभोक्ता को, व्यापारियों द्वारा मनमानी तौर पर की जाने वाली मूल्य वृद्धि से, जिसका विनिर्माण लागत से कोई सम्बन्ध नहीं होता, बचाया जा सके।

पैक की हुई वस्तुओं के मूल्यों या विनिर्माताओं, धोक व्यापारियों, खुदरा व्यापारियों इत्यादि के लाभ के माजिन का निर्धारण करना इन नियमों के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

गुरु तेग बहादुर अस्पताल के वैदिकल छात्रों की हड़ताल

9057. श्री आर० एन० राकेश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 अप्रैल, 1990 को गुरु तेग बहादुर अस्पताल के कर्मचारियों और मेडिकल छात्रों की हड़ताल के कारण रोगियों को भारी कठिनाई हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) छात्रों की मुख्य शिकायतें क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ख) गुरु तेग बहादुर अस्पताल के साथ सम्बद्ध यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसिज के मेडिकल छात्र 18-4-1990 को हड़ताल पर थे। उन्होंने बहिरंग रोगी विभाग, कैज्युल्टी और बाडों के सभी दरवाजों को रोक दिया था। उन्होंने गुरु तेग बहादुर अस्पताल के कर्मचारियों और रोगियों को बहिरंग रोगी विभाग, कैज्युल्टी और बाडों में घुसने नहीं दिया जिसके परिणामस्वरूप, कैज्युल्टी और बहिरंग रोगी विभाग सेवाओं में बाधा पड़ी। काफी अनुनय विनय करने पर कैज्युल्टी और आपातकालीन विभाग में उसी दिन एक बजे अपराह्न के पश्चात कार्य शुरू हुआ। गुरु तेग बहादुर अस्पताल के कर्मचारी 18 अप्रैल; 1990 को हड़ताल पर नहीं थे।

(ग) और (घ) छात्रों की मुख्य मांग यह थी यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसिज के छात्रों को प्रदत्त मेडिकल डिग्रियों को मान्यता प्रदान की जाए। यू० सी० एम० ए० के छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त मेडिकल डिग्रियों भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हताएं हैं। ऐसी डिग्रियों की मान्यता को वापस लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के सम्मुख कोई प्रस्ताव नहीं है। यू० सी० एम० ए० के छात्रों की स्थिति स्पष्ट की गई और इस बात की भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा पुष्टि भी की गई। तत्पश्चात छात्रों द्वारा हड़ताल वापस ले ली गई।

आवास योजनाओं के लक्ष्य

9059. श्री ए० चार्ल्स : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत आवास निर्माता के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए;

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आवास निर्माण का कितना लक्ष्य पूरा किया गया है; और

(ग) क्या मातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों की दृष्टि से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली भारन) : (क) और (ख) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य तथा वर्ष 1989-90 (1-4-89 से 28-2-90 तक) के दौरान विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य आंशिक रूप से प्राप्त कर लिए गए हैं तथा

निष्पादन संतोषजनक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

लाखों में

(28-2-90 की स्थिति के अनुसार)

सातवीं पंचवर्षीय योजना

	लक्ष्य	उपलब्धि
(क) आवास स्थल का प्रावधान (परिवार)	22.88	21.33
(ख) निर्माण सहायता (परिवार)	22.88	21.1
(ग) इन्दिरा आवास योजना (रिहायशी इकाइयों)	7.60	6.26
(घ) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग आवास (रिहायशी इकाइयों)	7.75	6.85
(ङ) निम्न आय वर्ग आवास (रिहायशी एकक)	1.38	1.46

विवरण

सूत्र संख्या 14(क) : ग्रामीण भूमिहीन कामगारों के लिए आवास स्थल का प्रावधान (परिवार)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य 1989-90	उपलब्धि 1-4-89/28-2-90	वार्षिक लक्ष्य 1989-90 की उपलब्धि की प्रति-शतता
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	30,000	57,656	192
2.	असम	10,000	4,110	41
3.	बिहार	25,000	15,498	62
4.	गोवा	200	121	61
5.	गुजरात	35,000	49,230	141
6.	हरियाणा	1,000	367	37
7.	जम्मू तथा कश्मीर	1,200	155	13

1	2	3	4	5
8.	कर्नाटक	40,000	30,712	77
9.	केरल	5,000	3,351	67
10.	मध्य प्रदेश	40,000	93,581	234
11.	महाराष्ट्र	20,000	11,936	60
12.	उड़ीसा	15,000	19,989	133
13.	राजस्थान	30,000	35,115	117
14.	तमिलनाडु	2,20,000	3,32,992	151
15.	त्रिपुरा	6,500	2,310	36
16.	उत्तर प्रदेश	50,000	1,17,777	236
17.	पश्चिमी बंगाल	3,889	4,572	118

संघ राज्य क्षेत्र

1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	300	153	51
2.	चण्डीगढ़	1,000	0	0
3.	दिल्ली	250	0	0
4.	पांडिचेरी	850	661	78

योग : 5,35,189 7,80,286 146

द्विपक्षी : यह योजना (1) अरुणाचल प्रदेश, (2) हिमाचल प्रदेश, (3) मणिपुर, (4) मेघालय, (5) नागालैंड, (6) पंजाब, (7) सिक्किम, (8) मिजोरम तथा संघ राज्य क्षेत्र (1) दमन तथा (2) दादरा तथा नागर हवेली (3) लक्षद्वीप में प्रचालन में नहीं है।

सूत्र संख्या 14(ख) : आबादित आवास स्थलों पर निर्माण सहायता

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य 1989-90	उपलब्धि 1-4-89/28-2-90	वार्षिक लक्ष्य 1989-90 की उपलब्धि की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1,25,000	70,416	56
2.	अरुणाचल प्रदेश	600	140	23

1	2	3	4	5
3.	असम	10,000	410	41
4.	बोधा	200	189	95
5.	बुन्दारात	20,000	15,298	76
6.	हरियाणा	1,600	0	0
7.	जम्मू तथा कश्मीर	1,200	120	10
8.	कर्नाटक	40,000	27,992	70
9.	केरल	21,500	8,376	39
10.	मध्य प्रदेश	16,100	10,172	63
11.	महाराष्ट्र	18,000	11,833	66
12.	मेघालय	840	22	3
13.	मिजोरम	260	260	100
14.	उड़ीसा	3,333	3,000	96
15.	राजस्थान	30,000	32,417	108
16.	सिक्किम	200	185	93
17.	तमिलनाडु	22,000	23,420	106
18.	त्रिपुरा	6,500	2,409	37
19.	उत्तर प्रदेश	30,000	54,426	181
20.	पश्चिम बंगाल	3,889	1,135	29
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	20	55	205
2.	दादरा तथा नागर हवेली	600	564	94
3.	दिल्ली	100	0	0
4.	दमन तथा दीव	35	0	0
5.	पाण्डिचेरी	1,445	1,040	72
योग :		3,53,422	2,67,779	76

टिप्पणी : यह योजना (1) बिहार (2) हिमाचल प्रदेश (3) मणिपुर, (4) नागालैंड, (5) पंजाब संघ राज्य क्षेत्र (1) चण्डीगढ़ तथा (2) लक्षद्वीप में प्रचालन में नहीं है।

सूत्र संख्या 14(ग) : इन्दिरा आवास योजना

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य 1989-90	उपलब्धि 1-4-89/28-2-90	वार्षिक लक्ष्य 1989-90 की उपलब्धि की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9,095	6,199	68
2.	अरुणाचल प्रदेश	123	9	7
3.	असम	2,284	1,218	53
4.	बिहार	18,225	15,900	87
5.	गोवा	159	86	54
6.	गुजरात	3,587	3,152	88
7.	हरियाणा	897	1,217	136
8.	हिमाचल प्रदेश	273	448	164
9.	जम्मू तथा कश्मीर	381	882	216
10.	कर्नाटक	5,694	3,602	63
11.	केरल	3,093	13,431	434
12.	मध्य प्रदेश	12,061	8,028	67
13.	महाराष्ट्र	9,743	4,041	41
14.	मणिपुर	63	139	221
15.	मेघालय	183	25	14
16.	मिजोरम	75	85	113
17.	नागालैंड	202	0	0
18.	उड़ीसा	5,707	2,371	42
19.	पंजाब	757	0	0
20.	राजस्थान	5,563	2,717	49
21.	सिक्किम	79	85	108
22.	तमिलनाडु	8,167	39,545	484
23.	त्रिपुरा	217	15	7

1	2	3	4	5
24.	उत्तर प्रदेश	23,315	22,320	96
25.	पश्चिमी बंगाल	10,174	8,161	80
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	34	21	62
2.	चण्डीगढ़	8	0	0
3.	दादरा तथा नागर हवेली	22	110	500
4.	दमन तथा दीव	17	7	41
5.	दिल्ली	99	0	0
6.	लक्षद्वीप	13	0	0
7.	पाण्डिचेरी	71	205	289
योग :		1,20,381	1,33,919	111

सूत्र संख्या 14(घ) : आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लक्षण

(रिहायशी इकाइयां)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य 1989-90	उपलब्धि 1-4-89/28-2-90	वार्षिक लक्ष्य 1989-90 की उपलब्धि की प्रति-शतता
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,45,000	8,218	6
2.	असम	2,128	594	28
3.	बिहार	10,287	287	3
4.	गोवा	126	156	124
5.	गुजरात	4,500	2,101	47
6.	हरियाणा	550	129	23
6.	(क) हिमाचल प्रदेश	30	27	90

1	2	3	4	5
7.	जम्मू तथा कश्मीर	1,000	1,232	123
8.	कर्नाटक	2,000	2,389	119
9.	केरल	10,100	5,672	56
10.	सूक्ष्म प्रदेश	5,000	2,893	58
11.	महागण्ड	12,760	6,754	53
12.	मणिपुर	215	67	31
13.	मैत्रालय	240	29	12
14.	मिजोरम	200	200	100
15.	नागालैंड	100	0	0
16.	उड़ीसा	2,500	2,170	87
17.	पंजाब	100	41	41
18.	राजस्थान	3,000	2,522	84
19.	सिक्किम	200	185	93
20.	तमिलनाडु	30,000	7,621	25
21.	त्रिपुरा	160	139	87
22.	उत्तर प्रदेश	18,000	15,774	88
23.	पश्चिम बंगाल	180	513	285
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	दिल्ली	8,300	0	0
2.	चण्डीगढ़	100	1	1
3.	दमन दीव	5	0	0
4.	पांडिचेरी	64	64	100
योग :		2,56,558	59,778	23

टिप्पणी : यह योजना (1) अरुणाचल प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र (1) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह (2) लक्षद्वीप में प्रचालन में नहीं है।

सूत्र संख्या 14(ई) : निम्न माय वर्ग आवास

(रिहायशी इकाईयां)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या 1989-90	उपलब्धि 1-4-89/28-2-90	वार्षिक संख्या 1989-90 की उपलब्धि की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1,500	250	17
2.	असम	147	84	57
3.	बिहार	886	539	61
4.	गोवा	568	100	18
5.	गुजरात	2,700	3,115	115
6.	हरियाणा	950	97	10
7.	हिमाचल प्रदेश	180	197	109
8.	जम्मू तथा कश्मीर	50	22	44
9.	कर्नाटक	1,000	971	97
10.	केरल	2,500	4,727	189
11.	मध्य प्रदेश	1,500	2,572	171
12.	महाराष्ट्र	17,000	10,442	61
13.	मणिपुर	215	67	31
14.	मेघालय	20	5	25
14.	(क) मिजोरम	320	320	100
15.	नागालैंड	150	0	0
16.	उड़ीसा	2,000	2,130	107
17.	पंजाब	420	418	100
18.	राजस्थान	4,000	2,729	68
19.	तमिलनाडु	10,728	7,924	74
20.	त्रिपुरा	85	39	46
21.	उत्तर प्रदेश	7,500	6,885	92

1	2	3	4	5
22.	पश्चिम बंगाल	100	21	21
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	जम्बुमान तथा निकोबार द्वीप समूह	100	196	196
2.	चण्डीगढ़	420	0	0
3.	दिल्ली	119	16	13
4.	दमन तथा दीव	4	3	75
5.	पाण्डिचेरी	10	16	160
	योग :	55,172	43,885	80

टिप्पणी : यह योजना (1) अरुणाचल प्रदेश (2) सिक्किम तथा संघ राज्य क्षेत्र (1) दादरा तथा नागर हवेली (2) लक्षदीप में प्रचालन में नहीं है।

नारियल जटा उत्पादों का निर्यात

9060. श्री ए० चार्ल्स : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार नारियल जटा उत्पादों का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और इसका मूल्य कितना है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान नारियल-जटा उत्पादों के निर्यात का क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) सरकार द्वारा नारियल-जटा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो उसका ग्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कथर और कथर उत्पादों के निर्यात निम्नोक्त अनुसार रहे हैं :

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ ₹०)
1987-88	25148	32.20
1988-89	24979	33.32
1989-90	27246	39.59
	(अनन्तिम)	(अनन्तिम)

स्रोत : कथर बोर्ड।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कयर निर्यात के लिए 45 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) भारत में कयर निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों में शामिल हैं : व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों का भेजना, बाजार अध्ययन तथा बाजार अनुसंधान करना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन रिलीज करना, तथा प्रचार सामग्री का वितरण करना, प्रमुख बाजारों में मेलों में भाग लेना, कयर उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना, अधिक मूल्य वृद्धित उत्पादों पर बल देना तथा म्युनतम निर्यात कीमतों का सुव्यवस्थीकरण करना।

“पेप्सी फूड” की परियोजना लागत

9061. चौधरी राम प्रकाश : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सी फूड पोर्टो एण्ड ग्रैन प्रोसेसिंग यूनिट की लागत 18.5 करोड़ रुपए है जबकि इससे थोड़ी सी अधिक क्षमता वाले जगतजीत इण्डस्ट्रीज संयंत्र जिसकी स्थापना पर चार माह पूर्व 4.9 करोड़ रुपए की लागत आई है;

(ख) इतना अधिक अन्तर होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच करने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

बस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) में पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई सूचना के अनुसार उनके आसू तथा अनाज प्रसंस्करण एकक की लागत 18.42 करोड़ ४० है। जगतजीत इण्डस्ट्रीज, नोएडा प्लांट के मामले में परियोजना की कुल लागत 4.93 करोड़ ४० बताई गई है। सरकार दोनों परियोजनाओं के विभिन्न कम्पोनेण्टों की लागत के ब्यौरे दोनों कम्पनियों से पता लगाने का प्रयास करेगी और जितनी भी सूचना उपलब्ध होगी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उड़ीसा में टीका लगाने सम्बन्धी लक्ष्य

9062. श्री मंगाराज बलिक :

श्री अनादि चरण दास :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में चारू वित्तीय वर्ष के अन्त तक चसरे का टीका लगाने सम्बन्धी लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का जिम्मावार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में खसरे का टीका लगाने की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु का कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है; और

(घ) उड़ीसा में उन शहरी गन्दी बस्तियों के नाम क्या हैं, जहां इस प्रयोजन हेतु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं/करने का विचार किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) राज सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

फ्लूराइड के उपयोग के बारे में विरब स्वास्थ्य संगठन का प्रश्नोत्तर कार्यक्रम

9063. श्री सनत कुमार मंडल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की इच्छा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व स्वास्थ्य संगठन के उस प्रश्नोत्तर कार्यक्रम (विषय) की ओर दिलाया गया है जिसमें बच्चों को बताया गया है कि अतिरिक्त फ्लूराइड दांतों के लिए अच्छा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी परिस्थितियों में जबकि भारत में पेयजल में फ्लूराइड की मात्रा बहुत अधिक है, भारत में भी यह बात ठीक है;

(ग) क्या फ्लूराइड की अधिकता से स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली के अस्पतालों में दन्त-चिकित्सकों के पद

9064. श्री सनत कुमार मंडल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की इच्छा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न अस्पतालों में अवर तथा वरिष्ठ दन्त-चिकित्सकों के पदों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या ये डाक्टर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में स्थानान्तरित किए जा सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन डाक्टरों के एक अस्पताल में रहने के लिए कोई अवधि निर्धारित की गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एक अस्पताल में पांच वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे दन्त चिकित्सकों की संख्या कितनी है तथा उनके लगातार वहां कार्यरत रहने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) डा० राम मनोहर सोहिया अस्पताल के चार दन्त चिकित्सकों और लेडी हाडिंग मेडिकल कालेज में दन्त चिकित्सा के एक प्राध्यापक अपने-अपने अस्पतालों में पांच साल से अधिक समय से रह रहे हैं। सरकार दन्त शल्य चिकित्सकों की तैनाती के लिए मानदण्ड तैयार करेगी।

विचारण

अस्पतालों की स्वीकृत पद संख्या में दन्त चिकित्सा सम्बन्धी पदों के अस्पतालवार विभिन्न ग्रेड

	दन्त शल्य चिकित्सक	कनिष्ठ स्टाफ शल्य चिकित्सक	मैजिस्ट्रोकेशियल शल्य चिकित्सक	स्टाफ शल्य चिकित्सक	वरिष्ठ शल्य चिकित्सक	दन्त चिकित्सा के प्राध्यापक
सफदरजंग अस्पताल	2	—	1	—	—	—
डा० राम मनोहर सोहिया अस्पताल	2	1	—	—	—	—
लेडी हाडिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपसानी अस्पताल	—	—	—	—	—	1

आदिवासियों की भूमि हस्तांतरण रोकने हेतु कार्य योजना

9065. श्री सतल कुमार बंडल : क्या भ्रम भंडी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आदिवासियों की भूमि हस्तांतरित रोकने हेतु कोई कार्य योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे कब लागू किया जाएगा और इससे आदिवासियों की भूमि का हस्तांतरण किस सीमा तक रोका जा सकेगा ?

भ्रम और कल्याण भंडी (श्री राम बिलास वासवान) : (क) से (ग) सरकार अनुरोधित जन-

जातियों की भूमि के हस्तांतरण की समस्या से पूर्णतः अवगत है। आदिवासी भूमि के आगे हस्तांतरण को रोकने के उद्देश्य से राज्यों को समय-समय पर अपने वर्तमान भूमि कानूनों की कमियों को दूर करने हेतु इनकी समीक्षा करने हेतु के लिए लिखा गया है। उन्हें अनुसूचित जनजाति की हस्तांतरित भूमि को वास्तविक रूप से उन्हें शीघ्र वापिस कराने के लिए भी कहा गया है। सरकार का संविधान की नौवीं अनुसूची में 55 भूमि कानून लाने का भी प्रस्ताव है। ऐसे मामलों का पता लगाने हेतु कुछ राज्यों में विशेष कर्मचारी तैनात किए गए हैं। राजस्व अधिकारियों को हस्तांतरित भूमि का पता लगाने और इसे पुनः वापिस दिलाने के लिए अपनी ओर से ही कार्रवाई करने के अधिकार दे दिए गए हैं।

प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के लिए खरीदे गए टीकों और "सेरा" की गुणता

9066. श्री परसराम भारद्वाज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के लिए कौन से टीके और "सेरा" की खरीद की गई है;

(ख) क्या सरकार द्वारा खरीदे गए टीके और "सेरा" निर्धारित और मानक गुणता के थे;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन टीकों की खरीद, इनकी गुणता जांच के पश्चात् ही करती है;

(घ) क्या बुलाई और माल प्राप्त होने तक की अवधि के दौरान ऐन्टिजन, सीरम और टीकों की "पोटेंसी" (क्षमता) में ह्रास हो जाता है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन प्रत्येक "सेरा" और टीकों के कितने खेपों की जांच की गई और इनमें से कितने घटिया स्तर के पाए गए; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक "सेरा" और टीकों की खरीद किन निर्माताओं से की गई और प्रत्येक क्रयादेश देने का क्या मापदण्ड अपनाया गया ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमान मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार निम्नलिखित छः वैक्सीनें खरीदती है—

(i) ओ० पी० वी० वैक्सीन ।

(ii) बी० सी० जी० वैक्सीन ।

(iii) खसरा वैक्सीन ।

(iv) डी० पी० टी० वैक्सीन ।

(v) डी० टी० वैक्सीन ।

(vi) टी० टी० वैक्सीन ।

(ख) और (ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस्तेमाल किए जाने वाले सभी सीरम और वैक्सीनें भारत के औषध नियंत्रक द्वारा अधिसूचित की गई निर्धारित प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण किए जाने के बाद खरीदी जाती हैं ।

(घ) उपयुक्त कोल्ड चेन वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत वैक्सीनों को लाने-ले-जाने में उनकी शक्ति नष्ट नहीं होती है ।

(क) यह सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खरीदी गई विभिन्न बंक्सीयों के निर्वातार्थों के नाम इस प्रकार हैं—

डी० पी० टी० बंक्सीय

1. केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली
2. भारतीय पाश्चूर संस्थान, कुन्नूर
3. हाफकिन बायोफार्मैस्यूटिकल कार्पोरेशन लि०, बम्बई
4. भारतीय सीरम संस्थान, पुणे
5. मे० बायोलॉजिकल इवन्स लि०, हैदराबाद

डी० टी० बंक्सीय

1. केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली
2. भारतीय पाश्चूर संस्थान, कुन्नूर
3. हाफकिन बायो-फार्मैस्यूटिकल कार्पोरेशन लि०, बम्बई
4. भारतीय सीरम संस्थान, पुणे

टी० टी० बंक्सीय

1. केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली
2. भारतीय पाश्चूर संस्थान, कुन्नूर
3. हाफकिन बायो-फार्मैस्यूटिकल कार्पोरेशन लि०, बम्बई
4. भारतीय सीरम संस्थान, पुणे
5. बायोलॉजिकल इवन्स लिमिटेड, हैदराबाद
6. एस० बी० आई० पटवाडनगर

बी० सी० जी० बंक्सीय

1. बी० सी० जी० बंक्सीय प्रयोगशाला गिण्डी, मद्रास
2. कुछ मात्रा की खरीद की व्यवस्था यूनीसेफ के माध्यम से की जाती है।

खतरा बंक्सीय

1. 1988-89 तक यूनीसेफ के माध्यम से खरीद की व्यवस्था की गई।
2. 1989-90 से भारतीय सीरम संस्थान, पुणे से पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से खरीदी गई।

ओरल पोलियो वैक्सीन (ओ० पी० वी०)

1. रोटरी इंटरनेशनल द्वारा उपहार में तथा यूनीसेफ के माध्यम से खरीद की व्यवस्था की गई।
2. मै० बिबकॉल द्वारा मास्को से प्राप्त
3. हाफकिन वायो फार्मोस्यूटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई
4. मै० रेडिक्पूरा फार्मा, दिल्ली

सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माताओं की कुल मंस्थापित क्षमता का पहले उपयोग किया गया। शेष मात्रा बाद में पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से खरीदी गई।

राजस्थान में मलेरिया तथा चेचक उन्मूलन के लिए धनराशि खर्च करना

[हिष्बी]

9067. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में क्रमशः मलेरिया उन्मूलन तथा चेचक उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) इन उन्मूलन कार्यक्रमों में कार्यरत अधिकारियों, डाक्टरों, कम्पाउण्डरों और अन्य कर्मचारियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके फलस्वरूप पिछले तीन वर्षों में लाभान्वित हुए मरीजों/अन्य लाभ प्राप्तकर्ताओं की जिला-वार संख्या कितनी है; और

(घ) उपयुक्त उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितने प्रशिक्षण केन्द्र कहां-कहां खोले गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) मलेरिया : केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि इस प्रकार है :—

(रा० अ० उ० कार्यक्रम प्राप्ति और शहरी)

(लाख रुपए)

वर्ष	नगद	सामग्री	कुल
1987-88	79.54	416.31	495.85
1988-89	57.63	104.21	161.84
1989-90	48.65	911.98	960.63

चेचक : 5-7-1975 से भारत चेचक रोग से मुक्त हो गया जिसके फलस्वरूप इन्टरनेशनल कमीशन द्वारा अप्रैल, 1977 में भारत से चेचक के उन्मूलन की घोषणा की गई। इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में चेचक उन्मूलन के अन्तर्गत खर्च की गई राशि का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 50 : 50 लागत पर खेबी-II केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है और मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य परिषदों के बुनियादी ढांचे अर्थात् प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपकेन्द्रों और उनमें कार्य कर रहे कर्मचारियों के माध्यम से इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों का है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की संशोधित कार्य योजना के अनुमोदित पैटर्न के अनुसार राजस्थान में कर्मचारियों की नवीनतम स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य कार्यक्रमालाप मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के विरुद्ध अवशिष्ट कीटनाशकों का छिड़काव, सक्रिय निगरानी तन्त्र के द्वारा मलेरिया के रोगियों का पता लगाना तथा रोगियों का उपचार करना है।

(घ) विभिन्न स्तरों पर मलेरिया विज्ञान तथा मलेरिया कीट विज्ञान और मलेरिया के अन्य पहलुओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली में जिला स्तर तथा जोनल और राज्य स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों, प्रयोगशाला, तकनीशियनों, बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा राज्य परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। राजस्थान राज्य में दो परिवार कल्याण केन्द्र हैं—एक जयपुर में तथा दूसरा अजमेर में जहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है।

विबरण

राज्य का नाम राजस्थान (क) कार्यक्रम चलाए/समेकन जिलों की संख्या..... पी०ओ०पी०.....
 जोन संख्या 5 (ख) जिले के अनुभागों की संख्या (i) ए/सी चरण... पी०ओ०पी०.....
 (ii) रखरखाव चरण... पी०ओ०पी०.....
 जिलों की संख्या 27 (ग) रख-रखाव चरण वाले जिलों की संख्या..... पी०ओ०पी०.....

क्रम कर्मचारियों की सं० श्रेणी भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए/समेकन चरण रख-रखाव चरण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राह्य पदों की संख्या (जिसमें रख-रखाव चरण के जिलों के क्रम चलाए/समेकन चरण जिलों के भाग भी शामिल है) भाग भी शामिल है)

भारत सरकार की संशोधित कार्य संशोधित कार्य योजना के पैटर्न के अनुसार ग्राह्य	भारत सरकार की संशोधित कार्य योजना के पैटर्न के अनुसार ग्राह्य	भारत सरकार की संशोधित कार्य योजना के पैटर्न के अनुसार ग्राह्य	भारत सरकार की संशोधित कार्य योजना के पैटर्न के अनुसार ग्राह्य	भारत सरकार की संशोधित कार्य योजना के पैटर्न के अनुसार ग्राह्य	भारत सरकार की संशोधित कार्य योजना के पैटर्न के अनुसार ग्राह्य	भारत सरकार की संशोधित कार्य योजना के पैटर्न के अनुसार ग्राह्य	भारत सरकार की संशोधित कार्य योजना के पैटर्न के अनुसार ग्राह्य	भारत सरकार की संशोधित कार्य योजना के पैटर्न के अनुसार ग्राह्य	भारत सरकार की संशोधित कार्य योजना के पैटर्न के अनुसार ग्राह्य	भारत सरकार की संशोधित कार्य योजना के पैटर्न के अनुसार ग्राह्य
स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. जिला मलेरिया अधिकारी

27 26 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	सहायक मलेरिया अधिकारी		30	28	2					
3.	मलेरिया निरीक्षक		214	134	20					
4.	सेखाकार		27	24	3					
5.	उच्च श्रेणी लिपिक		46	45	1					
6.	मैकेनिक		27	17	10					
7.	इंजिन स्लीपर		50	45	5					
8.	ग्राइबर		103	90	13					
9.	बपराली		48	48	—					
10.	सफाई बाला		27	27	—					
11.	एस० एफ० इन्सु. (12 महीने)		47	45	2					
12.	एफ० इन्सु० (12 महीने)		120	101	19					
13.	निगरानी निरीक्षक/एच० निरीक्षक एस० एम० पी० इन्सु०		695	579	116					
14.	निगरानी कार्यकर्ता/बहुउद्देशीय कार्यकर्ता/दुनियावी स्तर पर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता		2751	1473	268					
15.	तकनीशियन		2342	202	30					

.....बाहू के लिए जोनल एवं राज्य मुख्यालय स्तर पर कार्वरत कर्मचारियों की स्थिति

क्रम सं०	कर्मचारियों की श्रेणी	संशोधित कार्य योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पैटर्न के अनुसार प्राप्त पदों की संख्या	राज्य सरकार द्वारा संजूर किए गए पदों की संख्या	इस समय मौजूदा पद	रिक्त पड़े पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

(ब) जोनल संगठन

1. जोनल अधिकारी (मलेरिया)
2. ड्राइवर
3. टाइपिस्ट/क्लर्क
4. चपरासी
5. सहायक कीटविज्ञानी
6. कीट संग्रहकर्ता
7. प्रयोगशाला तकनीशियन

राज्य मुख्यालय स्तर पर कर्मचारियों की स्थिति

1. संयुक्त निदेशक (मलेरिया)

1	2	3	4	5	6	7
2.	एडिन्बर्ग डी० एम० एच० एल० (मलेरिया)		1	1	—	
3.	सहायक निदेशक (मलेरिया)		1	1	—	
4.	बधीशक-कम-लेखाकार		1	2	—	
5.	स्टोरकीपर/ड०के०सि०		2	1	—	
6.	स्टेनोग्राफर		1	1	—	
7.	टाइपिस्ट		1	1	—	
8.	ड्राफ्टर		1	1	—	
9.	कपरासी		1	—	—	

न्यायालयों में लम्बित पड़े भ्रम सम्बन्धी मामले

[अनुवाद]

9068. श्री कलाश मेघवाल : क्या भ्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न भ्रम न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में हिन्दुस्थान जिक लिमिटेड, के उदयपुर संगठन के निर्णयाधीन मामलों का ब्योरा क्या है; और

(ख) विभिन्न न्यायालयों में ये मामले कब से निर्णयाधीन हैं और इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

भ्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) और (ख) एक बिबरण संलग्न है।

विचारण

हिन्दुस्तान बिक लि०, उद्ययपुर से सम्बन्धित विभिन्न श्रम न्यायालयों, औद्योगिक अधिकारियों, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय में सम्बन्धित श्रम मामलों के विस्तृत व्यौरे

क्रमांक एकक का नाम	उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, श्रम न्यायालय/अधिकरण में सम्बन्धित मामले	अन्तर्गत पक्षकारों के नाम	मामले का विस्तृत व्यौरे	कब से विचाराधीन है
1	2	3	4	5
				6
1. जाबार बानें	उच्च न्यायालय	केन्द्रीय क्षेत्र श्री हुसम चन्द दाहोरा बनाम हिन्दुस्तान बिक लि०	परोल्नति से इंकार करने पर कर्मकार द्वारा मामला दायर किया गया। (मामला सं० 199/88)	1988
2. —वही—	औद्योगिक अधिकरण	श्री भगवान सिंह बनाम हिन्दुस्तान बिक लि०	सेवा समाप्ति के बारे में कर्म- कार द्वारा दायर किया गया दाबा। (मामला सं० 1/87)	1987
3. —वही—	—वही—	श्री कमलधाम सिंह बनाम हिन्दुस्तान बिक लि०	सेवा समाप्ति के बारे में कर्म- कार द्वारा दायर किया गया। (मामला सं० 22/88)	1988

1	2	3	4	5	6
4.	अग्निदुहाला खाने	—वही—	श्री एस० के० सैदा बनाम हिन्दुस्तान जिक लि०	नौकरी से बर्खास्त किए जाने के बारे में कर्मकार द्वारा दायर किया गया दावा। (मामला सं० 45/88)	1988
5.	—वही—	उच्च न्यायालय	श्री बेंकटरमन बनाम हिन्दुस्तान जिक लि०	आयकर की कटौती किए बिना बकाया राशि भुगतान के लिए निवेश।	1987
6.	—वही—	—वही—	हिन्दुस्तान जिक लि० बनाम श्री वी० बालाकोहन्ना	अधिकरण के पंचाट के विरोध में।	1989
7.	सारणीपाली खाने	औद्योगिक अधिकरण	श्री एस० के० पांडेय, भूत- पूर्व मोटरवाहन चालक बनाम हिन्दुस्तान जिक लि०	नौकरी से बर्खास्त किए जाने के सम्बन्ध में कर्मकार द्वारा दायर किया गया दावा। (मामला सं० 48/87)	1987
8.	राजपुरा दर्रीबा खाने	—वही—	श्री मोहन लाल चमार बनाम हिन्दुस्तान जिक लि०	—वही— (मामला सं०/87)	1989
9.	प्रधान कार्यालय	उच्च न्यायालय	श्रीमती कान्कु बाई बनाम हिन्दुस्तान जिक लि०	कम्पनी में स्थायी नियुक्ति के लिए कर्मकार (नैमित्तिक) द्वारा दायर की गई अपील। (मामला सं० 2750/89)	1989

1	2	3	4	5	6	
1.	बिक स्मिटर देबारी	उच्चतम न्यायालय	राज्य क्षेत्र	श्री आर० एल० सनाढ्या, जिसका प्रतिनिधित्व सचिव, आई० टी० आई० ट्रेड कर्मचारी एसोसिएशन करती है, बनाम	श्री आर० एल० सनाढ्या की पिछली मजदूरी सहित बहाली के दावे के बारे में प्रबन्धन द्वारा उपयुक्त उच्च न्यायालय राजस्वान के निर्णय के विरोध में दायर की गयी अपील।	1987
2.	—बही—	उच्च न्यायालय	बनाम	कार्य प्रबन्धक, बिक स्मिटर लिमिटेड	(अपील सं० 733/1987)	1984
3.	—बही—	—बही—	बनाम	श्री पी० सी० रात बिक स्मिटर देबारी	श्री पी० सी० रात बिक स्मिटर देबारी को अस्वीकार कर देने पर श्री पी० सी० हरिजन अग्र न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील।	1984
			बनाम	श्री पी० सी० रात बिक स्मिटर देबारी	(आपला सं० 74/1984)	
				बनाम	कनिष्ठ इन्जीनियर के रूप में पदोन्नति के दावे को अस्वीकार कर दिए जाने के सम्बन्ध में श्री रात द्वारा अग्र न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील।	
					(आपला सं० 2398/84)	

228	1	2	3	4	5	6
4. —वही—	—वही—	श्री मोहम्मद खुर्शीद बनाम बिक स्मैल्टर देबारी	—वही—	श्री मोहम्मद खुर्शीद के पद के लिए पदोन्नति की मंजूरी दिए जाने पर प्रकल्प- तन्त्र द्वारा श्रम न्यायालय के आदेश के विरुद्ध दायर की गयी अपील । (मामला सं० 1846/83)	1983	
5. —वही—	—वही—	श्री सैम्यसन पीटर, जिसका प्रतिनिधित्व हिन्द-बिक मजदूर यूनियन करती है, बनाम महाप्रबन्धक, बिक स्मैल्टर देबारी	—वही—	पूरी पिछली मजदूरी सहित बहाली के अपने दावे को अस्वीकार कर दिए जाने पर श्री पीटर ने श्रम न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की । (मामला सं० 1703/85)	1985	
6. बिक स्मैल्टर विबारा।	—वही—	हिन्द-बिक मजदूर संगठन के प्रतिनिधि श्री पी० के० ब्येजी तथा श्री एस० एल० डेक बनाम महाप्रबन्धक, बिक स्मैल्टर विबारी	—वही—	कर्मचारों ने पुनर्विभाजन के अपने हक को रद्द करते हुए श्रम न्यायालय में अपीलका दायर की । (मामला सं० 944/87)	1987	

1	2	3	4	5	6
7. --बही--	--बही--		श्री गोपाल सिंह बनाम बिक स्वीटर दिवारी	प्रबन्धन के विरुद्ध अम न्यायालय ने एक याचिका दाख की जिससे 1973 से पुनर्नियोजन पूरे वेतन के साथ लागू किया। (मासला सं० 2995/87)	1987
8. --बही--	बीछोनिक अधिकरण		अखिल भारतीय मजदूर काँग्रेस के प्रतिनिधि श्री के० एस० हरिजन बनाम बिक स्वीटर दिवारी	कर्मकारी ने पिछले पूरे वेतन सहित पुनर्नियोजन के बारे में दावा दाखर किया। (मासला सं० 28785)	1985
9. --बही--	अम न्यायालय		हिन्द बिक मजदूर संगठन द्वारा श्री सी० सुशील का प्रतिनिधित्व बनाम बक प्रबन्धक, बिक स्वीटर दिवारी	2-7-1982 से कर्मकार द्वारा फिटर "ब" के पद पर पदोन्नति सम्बन्धी दावा दाखर। (मासला सं० 2/87)	1987
10. --बही--	--बही--		श्री एस० के० पाठक बनाम बिक स्वीटर दिवारी	कर्मकार द्वारा 1982 से ईकोनिक के पद पर पदोन्नति सम्बन्धी दावा दाखर करना। (मासला सं० 7/87)	1987

1	2	3	4	5	6
11.	जिक स्मिटर विभाग, विभागापटनम (जा० प्र०)	उच्च न्यायालय	हिन्दुस्तान जिक लि० बनाम श्री दिवा बापूजी जिक स्मिटर कर्मचारी संघ विजाग बनाम औद्योगिक प्राधिकरण तथा एच० जेड० एस० श्री जी० सिमहादरी बनाम हिन्दुस्तान जिक लि०	कर्मकार द्वारा सेवाओं को निलम्बित किए जाने पर याचिका दायर की। श्रम न्यायालय द्वारा पारित किए गए पंचाट के विरुद्ध यूनियन द्वारा दायर की गई याचिका। (मामला सं० 8433/89)	— 1989
12.	—वही—	—वही—	—वही—	कर्मकार द्वारा संघयी प्रभाव से देतलबुद्धि को रोकने के बारे में दावा दायर किया। (मामला सं० 11391/88)	1988
13.	—वही—	—वही—	श्री डी० प्रकाश राव बनाम हिन्दुस्तान जिक लि०	निलम्बन के आदेश को रद्द करने बाबत कर्मकार द्वारा दावा दायर किया गया।	—
14.	—वही—	—वही—	श्री डी० प्रकाश राव बनाम हिन्दुस्तान जिक लि०	प्रबन्धतन्त्र के० ओ० वि० अधिनियम के खण्ड 33(2) (ख) के तहत बोरी के मामले से सम्बन्धित दो कर्मकारों का निलम्बन करने की अनुमति मांगी। (मामला सं० 6/87)	1987
15.	—वही—	श्रम न्यायालय	श्री डोगरा तथा दामो- दरण		

1	2	3	4	5	6
16.	—बही—	—बही—	हिन्दुस्तान विक सि० बनाम श्री नागा पूषणम	प्रवचन ने ली० वि० अधिनियम के खण्ड 33(2) (ब) के तहत बोरी के मामले में शामिल दो कर्मचारियों को बर्खास्त करने की अनु- मति मांगी। (मामला सं० 7/87) सेवाओं को बर्खास्त करने के बाबत कर्मकार ने दावा दायर किया। (मामला सं० 40/87) सेवाओं को बर्खास्त करने बाबत कर्मकार द्वारा दावा दायर किया गया। (मामला सं० 71/88) सेवाओं को बर्खास्त करने बाबत कर्मकार द्वारा दावा दायर किया गया। (मामला सं० 129/88)	1987
17.	—बही—	—बही—	श्री बी० नागापूषणम बनाम हिन्दुस्तान विक सि०		1987
18.	—बही—	—बही—	श्री सी० एस० शोगरा बनाम हिन्दुस्तान विक सि०		1988
19.	—बही—	—बही—	श्री एम० एस० हुसैन बनाम हिन्दुस्तान विक सि०		1988
20.	—बही—	—बही—	डेका अमिक बनाम हिन्दुस्तान विक सि०	डेका अमिकों द्वारा पुनर्नियो- जन बाबत दावा शायर किया गया। (मामला सं० 415 तथा 418)	—

वाटर गंगाऊ बांध परियोजना

[हिन्दी]

9069. श्री राम सञ्जीवन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों ने राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की भेटर गंगाऊ बांध परियोजना की उपलब्धता से सम्बन्धित रिपोर्ट पर अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं;

(ख) क्या एजेंसी द्वारा जल उपलब्धता के बारे में अन्तिम रिपोर्ट शीघ्र देने हेतु कोई समय सीमा निश्चित किए जाने की सम्भावना है;

(ग) यह मामला केन्द्रीय जल आयोग को कब सौंपा गया था और इसका अपना प्रतिवेदन अभी तक न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है; और

(ङ) क्या इस जल विवाद को केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से शीघ्र हल किए जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) उत्तर प्रदेश ने सूचित किया है कि जल उपलब्धता का अनुमान स्वीकार्य है लेकिन मध्य प्रदेश ने महसूस किया है कि यह अधिक है।

(ख) रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के लिए मतभेद का समाधान करना आवश्यक है।

(ग) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने केन्द्रीय जल आयोग को जून, 1988 में जल उपलब्धता की अध्ययन रिपोर्ट भेजी थी। जांच के बाद केन्द्रीय जल आयोग ने राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को टीका टिप्पणियां अनुपालन के लिए भेजी हैं।

(घ) क्या जल उपलब्धता का उपयोग करके निवेश स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा परियोजना की संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

(ङ) क्षेत्रीय परिषद की बैठक में विचार-विमर्श परामर्शी और सिफारिशी स्वरूप के होते हैं।

वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड

[अनुवाद]

9070. श्री एम० एम० पल्लभ राऊ : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) बत तीन वर्षों के दौरान वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इण्डिया) लि० को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) बाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इण्डिया) लि० द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन सी परियोजनाएं तैयार की गई हैं; और

(घ) बाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड ने अब तक किन-किन परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) बाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इण्डिया) लि० का मुख्य उद्देश्य जल समाधानों, सिंचाई तथा जल निकास के विकास, विद्युत, बाढ़ नियन्त्रण और जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग तथा परामर्शी सेवाएं प्रदान करना होता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार ने कम्पनी को कोई राशि आवंटित नहीं की है। यह लाभ प्राप्त करने वाली कम्पनी है तथा उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत ही अपना व्यवसाय करती है।

(ग) और (घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान बापकोस ने 217 बोलियां लगायी तथा उनमें से 84 कार्य प्राप्त कर सका। इनके सहित अभी तक बापकोस ने 221 कार्य प्राप्त किए हैं।

भारतीय खाद्य निगम में बरीयता कम

9071. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालय ने भारतीय खाद्य निगम, दक्षिण जोन का अपने कर्मचारियों की बरीयता निर्धारित करने के लिए स्टाफ रेगुलेशन के नियम 16(?) को लागू करने के निर्देश दिए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इन निर्देशों का पालन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री माधू राम मिर्छा) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि उनके दक्षिण जोन में सहायक ग्रेड-3 (डिपो) की बरीयता सूची में केवल उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार संशोधन कर दिया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिष्ठान को सामिल करना

9072. श्री सन्तोष कुमार शंभर : क्या अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी प्रतिष्ठान पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम उस समय लागू होता है जबकि उसमें लगातार तीन महीने तक कर्मचारियों की संख्या 20 अथवा इससे अधिक रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि ब्राबुक, दिल्ली द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली में ऐसे प्रतिष्ठान भी सामिल किए गए हैं जिनमें केवल एक दिन के लिए बीस व्यक्ति कार्यरत हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में इस अधिनियम के अन्तर्गत साए गए ऐसे प्रतिष्ठानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इन दोषों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के बिस्वृद्ध क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 में उस अवधि को निर्दिष्ट नहीं किया गया है जिसके लिए प्रतिष्ठान की ब्याप्ति के प्रयोजन के लिए 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित किया गया है। अतः अधिनियम के अधीन ब्याप्ति को पिछले वर्ष में किसी दिन प्रतिष्ठान के नियमित व्यवसाय में नियोजित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(ख) और (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आर० बी० एच० एम० जूट मिल, कटिहार को पुनः चालू करना

[हिन्दी]

9073. श्री युबराज : क्या बस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स, कटिहार को पुनः चालू और प्रतिष्ठित करने सम्बन्धी परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त योजना के परिणामस्वरूप अनेक कामगारों की संख्या में कमी की जानी थी; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मिल के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि मंजूर करने का विचार है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मिल को पुनः चालू और प्रतिष्ठित करने सम्बन्धी योजना के फलस्वरूप फालतू हुए सभी कामगारों को मिल में पुनः नौकरी पर रखना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार किया गया है ?

बस्त्र मंत्री और श्राद्ध प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद बाबब) : (क) से (घ) आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स के पुनरुद्धार और पुनर्स्थापना की 3.75 करोड़ रु० के परिम्य वाली एक परियोजना की स्वीकृति दी गई थी। इसमें बिहार सरकार का अंशदान 1.50 करोड़ रु० तथा केन्द्रीय सरकार का अंशदान 2.25 करोड़ रु० था। इस समय आधुनिकीकरण के लिए किसी अन्य योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त परियोजना के पूरा होने के पश्चात् एकक में कम श्रमिक बल की आवश्यकता होगी। इससे फालतू हो जाने वाले कामगारों को पूरे टर्मिनल लाभ की अदायगी की जा रही है। इसकी दीर्घकालिक अर्थसमता को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित प्लांट-स्तरीय श्रमिक संघों के साथ लम्बी बातचीत करने के पश्चात् ही इस योजना पर निर्णय लिया गया था।

महाराष्ट्र में गव बौद्ध धर्म अपनाते वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में लोगों को आरक्षण लाभ

अनुचाच]

9074. श्री वामनराव महाडीक : क्या अब मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि महाराष्ट्र में केन्द्रीय सेवाओं, केन्द्रीय सरकार के कल्याण उपायों, केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित लाभों का पूरा उपयोग अन्यत्र हस्तेमाल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन शिकायतों की जांच करने का है और तत्संबंधी ध्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कानूनी आरक्षण अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

अब और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

औषधि नियंत्रक के प्रतिबन्धात्मक आदेश

9075. श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा औषध नियंत्रक के प्रतिबन्धात्मक आदेशों को ताक पर रखने तथा उन्हें न मानने की नीति अपनाए जाने और सर्वाधिक मांग वाली तेरह औषधियों को मूल्य नियंत्रण सूची से निकाल दिए जाने के कारण जबरत-मन्द उपभोक्ताओं के लिए ये बहुत महंगी हो गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति से बचने के लिए क्या ऐहृतियाती उपाय किए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) सरकार ने औषधों की 27 श्रेणियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है जिनमें निर्धारित खुराक वाले योग शामिल हैं। जब एक बार औषधों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है तो उनके मूल्य में बृद्धि होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रश्न में उल्लिखित 13 औषधों के नामों की अनुपस्थिति में, उन्हें मूल्य नियंत्रण से हटाने के सम्बन्ध में टिप्पणी करना सम्भव नहीं है। रसायन और पेट्रो-रसायन सचिव की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन मूल्य नियंत्रण के लिए औषधों को शामिल करने/हटाने के प्रश्न की जांच करने के लिए किया गया है। मूल्य नियंत्रण औषधों की सूची में विसंगतियों/भिन्नताओं से सम्बन्धित सभी अभ्यावेदन स्थायी समिति को सम्बोधित किए जा सकते हैं।

पेप्सी फूड परियोजना की लागत में वृद्धि

9076. श्री क्षेमचन्दभाई सोमाभाई चावडा :

श्री जयप्रकाश अग्रवाल :

श्री गोबिन्द चन्द्र मुण्डा :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और/अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा पंजाब एगो-पेप्सी संयुक्त उद्यम को कितनी ऋण दिया गया है;

(ख) क्या परियोजना लागत वृद्धि से क्षमता में भी वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने पेप्सी फूड्स की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की अनुमति दे दी है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) आई० एफ० सी० आई० जोकि प्रमुख संस्थान है, ने सूचना दी है कि उन्होंने पेप्सी फूड्स प्रा० लि० को अभी तक कोई वित्तीय सहायता मंजूर नहीं की है।

(ख) और (ग) सरकार ने उन विभिन्न मदों के निर्माण के लिए जिसके लिए मैं पेप्सी फूड्स प्रा० लि० को एक आशय पत्र मंजूर किया गया है, स्वीकृत क्षमता में कोई वृद्धि करने की अनुमति नहीं दी है।

नर्मदा बांध परियोजना के बारे में पारिस्थितिकी सम्बन्धी मानदण्डों का पालन

9077. श्री जी० एस० बासवराज : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नर्मदा बांध परियोजना पर अन्तिम निर्णय लेते समय पारिस्थितिकी सम्बन्धी मानदण्डों का कठोरता से पालन करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये मानदण्ड विश्व बैंक ने निर्धारित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विश्व बैंक द्वारा अन्य क्या सुझाव दिए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने विश्व बैंक के अनुदेशों का पालन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उनका किस सीमा तक पालन किया गया है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से बन एवं पर्यावरणिक दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति के बाद ही नर्मदा सागर परियोजना सहित बहुवृक्ष सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। स्वीकृति प्रदान करते समय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों के पारिस्थितिकी पहलुओं की सुरक्षा के लिए परियोजना क्रियान्वयन प्राधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ मानकों और कार्यों को निर्धारित करता है।

(ख) से (ङ) नर्मदा सागर परियोजना का अभी तक विश्व बैंक ने मूल्यांकन नहीं किया है। तथापि, परियोजना की पारिस्थितिकी आवश्यकताओं को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने निर्धारित किया है।

दिल्ली में जन: प्रभाषी औषधियों की खपत

9078. श्री पी० वेंबार्सेना : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल में कुछ ही दिनों से नशीली औषधियों और मन: प्रभाषी पदार्थों की खपत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ध्यौरा क्या है; और

(ग) इस खतरनाक प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नशीली दवाओं के व्यसनियों को परामर्श प्रदान करने, निम्ब्यसन तथा उत्तरवर्ती देहभ्रात अनुवर्ती सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों ने दिल्ली में 23 केन्द्र स्थापित किए हैं। लोगों में सामाजिक जागरूकता प्रदान करने के लिए ऐसे सभी केन्द्रों के पते दर्शाने वाली विबरणिकाएं तथा पत्रिकाएं छापे गए हैं तथा व्यापक रूप से वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय समाचारपत्रों में इन केन्द्रों के पतों के साफ प्रेस विज्ञापन जारी किए गए हैं। जनता को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक बनाने के लिए स्कूलों, कालेजों तथा समुदाय में नियमित रूप से शिविरों बाद विवाहों सार्वजनिक बैठकों भूकामिनय नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से जन चेतना कार्यक्रम नियमित रूप से किये गए हैं।

स्वायक और जनोप्रभाषी औषधों की खपत

9079. डा० देवी प्रसाद पाल :

बाबा लुच्चा सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अप्रैल, 1990 के "स्टेट्समैन" के नयी दिल्ली संस्करण में "टू सॉपट ऑन ड्रग-पुवर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकषित किया गया है;

(ख) पश्चिम बंगाल और पंजाब में लोग किस सीमा तक नशीली दवाओं के आदी हैं; और

(ग) सरकार का इस प्रमुख सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में पटसन मिल

[हिन्दी]

9080. श्री सुखदेव पासवान : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1974-75 में बिहार के फरीसगंज में एक पटसन मिल के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी;

(ख) क्या पटसन मिल का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया था;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का प्रस्तावित पटसन मिल का अथवा इसके बदले में एक रस्सी मिल की स्थापना करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) वर्ष 1981 में बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था। यह 30-6-1985 को समाप्त हो गया।

(ख) सरकार को निर्माण कार्य शुरू होने की कोई जानकारी नहीं है।

(ग) से (घ) सरकार किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

मशीनरी को अन्यत्र ले जाना

[अनुवाद]

9081. श्री काशीराम राणा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कामरेज विभाग खांड मंडली की ओर से गुजरात में नलाया के सिदेशवरी खांड मंडली से मशीनरी अन्यत्र ले जाने तथा चीनी उद्योग से सम्बन्धित लाइसेंस का हस्तांतरण करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) जी हां, यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

डाक्टर-मरीज अनुपात

9082. श्री कल्पनाच राय :

श्री एस० कृष्ण कुमार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के मेडिकल कालेजों से डाक्टर बनकर निकलने वाले व्यक्तियों की संख्या देश की कुल आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो डाक्टर और मरीज के बीच का अनुपात कितना है;

(ग) क्या डाक्टरों का अनुपात मरीजों की मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस विषय में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मेडिकल स्टोर संगठनों की बी० एम० एस० सूची में अस्पतालों का मान्य औषध कोष

9083. डा० भगवान दास राठीर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी अस्पतालों तथा संस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि वे मेडिकल स्टोर संस्थाओं की बी० एम० एस० सूची के अनुसार ही अपनी आवश्यकता की औषध तथा दवाइयाँ खरीदें;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बी० एम० एस० सूची में मेडिकल कालेजों तथा अन्य के साथ सम्बद्ध दिल्ली के अस्पतालों के मान्य औषध कोष में उल्लिखित औषध तथा दवाइयाँ शामिल हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन अस्पतालों के बरिष्ठ डाक्टरों द्वारा बनाये गये मान्य औषध कोष में सूचीबद्ध औषधों की, उनकी वास्तविक मांग को मेडिकल स्टोर डिपो किस प्रकार पूरा करता है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय (चिकित्सा सामग्री भंडार संगठनों) ने सरकारी अस्पतालों और संस्थाओं को चिकित्सा सामग्री भंडार सूची शब्दावली के अनुसार अपनी आवश्यकता की औषधों और दवाओं को खरीदने के कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं ।

(ख) चिकित्सा सामग्री भंडार सूची शब्दावली में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की भेषज संहिता में सूचीबद्ध सभी मदें शामिल नहीं हैं ।

(ग) चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन अपने पंजीकृत अस्पतालों और औषधालयों तथा अन्य मांगकर्ताओं द्वारा भेजी गई मांग को पूरा करता है जो सभी सरकारी अस्पतालों और संस्थाओं की जरूरत का केवल एक सधु अंश होता है । जो औषधें और दवाएं चिकित्सा सामग्री संगठनों द्वारा सप्लाई नहीं की जाती हैं, उन्हें अस्पतालों और संस्थाओं द्वारा आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय, सुपर बाजार और स्थानीय खरीद आदि के जरिए प्राप्त कर लिया जाता है ।

केन्द्रीय भांडारान्तर नियम का मनोरंजन खाता

[हिन्दी]

9084. श्री कुल चन्द वर्मा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के एक उपक्रम, केन्द्रीय भांडागार निगम में मनोरंजन खाता के अन्तर्गत प्रतिवर्ष कितनी धनराशि स्वीकृत की जाती है;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान मनोरंजन के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई, निगम द्वारा वस्तुतः कितनी धनराशि खर्च की गई तथा किन प्रयोजनों के लिए खर्च की गई; और

(ग) दिल्ली में मुख्यालय में मनोरंजन पर खर्च की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाबू राम मिर्जा) : (क) पिछले पांच वर्षों के लिए केन्द्रीय भाण्डागार निगम के आतिथ्य सत्कार खर्च के लिए बजट में निम्नानुसार प्रावधान किया गया था :

वर्ष	धनराशि (लाख रुपये में)
1985-86	2.30
1986-87	2.15
1987-88	3.00
1988-89	5.00
1989-90	8.25

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान आतिथ्य सत्कार के लिए 8.25 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई थी। निगम द्वारा अप्रैल से दिसम्बर, 1989 तक वास्तव में 6.16 लाख रुपये खर्च किए गए थे।

उपर्युक्त खर्च मुख्यतया विभिन्न फील्ड यूनिटों और मुख्यालय द्वारा जमाकर्ताओं को वार्षिक आम सभा, क्षेत्रीय प्रबन्धकों के सम्मेलन, कार्यकारी इंजीनियरों के सम्मेलन तथा भाण्डागार प्रबन्धकों के सम्मेलन जैसे अन्य अवसरों पर दी गई चाय/काफी, स्नैक्स, लंच/डिनर पर किया गया था।

(ग) दिल्ली में स्थित मुख्यालय में 1989-90 के दौरान आतिथ्य सत्कार पर किया गया खर्च नीचे तौर पर निम्नलिखित के कारण हुआ :—

- (1) वार्षिक आम सभा में अंशधारियों का आतिथ्य सत्कार।
- (2) निगम के अध्यक्ष द्वारा माननीय जमाकर्ताओं को दिया गया लंच/डिनर।
- (3) चीफ एग्जीक्यूटिव द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धकों और कार्यकारी इंजीनियरों के सम्मेलन में दिया गया लंच/डिनर।
- (4) क्षेत्रीय प्रबन्धकों, कार्यकारी इंजीनियरों, लेखा अधिकारियों आदि की आवधिक बैठकों में फील्ड से बुलाए गए अधिकारियों को दिया गया बकिंग लंच।
- (5) विभिन्न बैठकों में भाग लेने के लिए आए राज्य भाण्डागार निगमों के अधिकारियों का आतिथ्य सत्कार।

झुग्गी कालोनियों में महामारी

[अनुचाच]

9085. एम० बी० चन्द्रशेखर भूति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 मई, 1990 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "एपिडेमिक इन झुग्गी कालोनीज फिअर्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन ने झुग्गी बस्तियों आदि को पानी से वैदा होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में आगे और क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (धी आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के निवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने और अतिसार के उपचार की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित त्रिमुखी नीति अपनाकर एक कार्ययोजना बनाई गई है :—

(1) वर्तमान स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की पद्धति को तेज करना (पुनरभिबिन्यास) ।

(2) समुदाय आधारित (क्षेत्रीय अथवा आउटरीच स्तर पर) व्यापक स्तर की गतिविधियां जैसे स्वास्थ्य शिक्षा, ओ० आर० टी०, क्लोरीन की गोलियां, स्वास्थ्य परिचर्या, रोग प्रतिरक्षण आदि जैसे आवश्यक घटकों को सामाजिक तौर पर गतिशील बनाना और उन्हें प्रदान करना ।

(3) स्वास्थ्य परिचर्या के आधारभूत ढांचे और समुदाय आधारित गतिविधियों के बीच के सम्पर्क को सुदृढ़ करना ।

(ग) जलवाहित बीमारियों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम इस प्रकार हैं :—

(1) वर्तमान स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने वाली पद्धति का पुनरभिबिन्यास ।

(2) सभी प्रमुख अस्पतालों में ओ० आर० टी० कानरों की स्थापना ।

(3) झुग्गी झोपड़ी समूहों/पुनर्वास कालोनियों में ओ० आर० एस० वैकेटों और क्लोरीन की गोलियों का स्टॉक रखना ।

(4) कर्ताओं, पोस्टरों, पुस्तिकाओं और हैण्डआउटों के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा को तेज करना ।

(5) सफाई के सम्बन्ध में जागरूकता अभियान के लिए आंगनबाड़ी कामिकों को शामिल करना ।

(6) गस्ती स्वास्थ्य योजना के माध्यम से रोग प्रतिरक्षण की व्यवस्था एवं ओ० आर० एस० और क्लोरीन की गोलियों का वितरण ।

- (7) मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में अतिसार के उपचार की व्यवस्था के लिए एक मॉनीटिंग कक्ष एवं नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।

कलकत्ता के विकास के लिए सहायता

9086. श्री सुदर्शन राय चौधरी :

डा० देबी प्रसाद पास :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता की तीसरी शताब्दी की स्मृति में इसके विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली भारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना

9087. श्रीमती सुमित्रा महाजन :

श्रीमती जयबन्ती नबीनचन्द्र मेहता :

कुमारी उमा भारती :

क्या अम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे क्या उपाय करने का विचार है जिनसे भारतीय स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से किसी अन्य पर निर्भर न रहें;

(ख) क्या आदिवासी क्षेत्रों, अनुसूचित जातियों और सुदूर-पर्वतीय क्षेत्रों की स्त्रियों को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई विशेष उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक राज्य में इस सम्बन्ध में क्या-क्या ठोस उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं ?

अम और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में कृषि आधारित फल उद्योग को केन्द्रीय सहायता

[हिल्मी]

9088. श्री हरिशंकर महाले : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कृषि आधारित पल उद्योगों के विकास हेतु वित्तीय सहायता के लिए कोई अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

बजट. मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सरदर यारक) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

9089. श्री शिव शरण वर्मा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1990 में श्रम मन्त्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो श्रम अधिनियमों के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में विधेयक कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) जी, हाँ ।

(ख) श्रम मंत्री सम्मेलन ने निम्नलिखित मौजूदा विधान में संशोधनों की सिफारिश की :—

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम

2. व्यवसाय संघ अधिनियम

3. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम

4. ठेका श्रम अधिनियम

5. अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, और निम्नलिखित नए विधानों को पेश करने का प्रभाव दिया :

(i) प्रबन्ध में कर्मकार सहभागिता संबंधी विधेयक

(ii) निर्माण कर्मकार संबंधी विधेयक

(iii) कृषि कर्मकार संबंधी विधेयक ।

(ग) श्रम मन्त्री सम्मेलन सरकार को सिफारिश करता है । बाब में सरकार द्वारा इतनी खाफ़ न जाती है । अतः इस अवस्था पर वह तारीख बताने का प्रश्न नहीं उठता जब विधान पेश किया जाएगा ।

छोटी मिल धमिकों के नफ़ूरी बोर्ड की सिफारिशें

सम्बन्ध]

9090. श्री बालासाहिब बिजे पाटिल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी मिल श्रमिकों के लिए गठित तीसरे मजूरी बोर्ड की सिफारिशें किन-किन राज्यों ने लागू कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संसाधित फल मकों पर उत्पाद शुल्क

9091. श्री कुमुद कृष्ण मूर्ति :

श्रीमती जे० जमना :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मुरम्बा और मार्मलेड एवं अन्य संसाधित फल-पदार्थों पर उत्पादन शुल्क लगा दिया गया है तथा फल उत्पादों के निर्यात के 40 प्रतिशत पर से 15 प्रतिशत नकद प्रतिपूरक सहायता वापस ले ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस उद्योग को वर्तमान संकट से उबारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) फल उत्पादों के संबंध में उत्पाद शुल्क में वृद्धि करने तथा नकद प्रतिपूरक सहायता में कमी करने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) जब कभी ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो उन पर विचार किया जाता है तथा उचित कार्रवाई की जाती है।

बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु नए प्रस्ताव

9092. प्रो० के० बी० धामस : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने संबंधी किसी नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या स्तनपान को बढ़ावा देने तथा शिशु आहारों को निरूत्साहित करने हेतु कानूनी उपाय किए जाएंगे ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 नवम्बर, 1989 को अंगीकृत किए गए अन्तर्राष्ट्रीय बाल अधिकार कन्वेंशन को अभी भारत सरकार द्वारा अभिपुष्टि की जानी है।

(ख) जी, हां। स्तनपान के संरक्षण और संवर्धन के लिए कानून बनाए जाने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों की मांगें

9093. श्री श्रीकान्त बल्लभ नरसिंहराज बाडियर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाएं ग्रुप "क" के डाक्टर सेवाओं की स्थितियों और पदोन्नति के अवसरों को बेहतर बनाने की मांग कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने समय-समय पर उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए समितियां गठित की हैं;

(ग) यदि हां, तो डाक्टरों की समस्याओं पर विचार करने के लिए गत तीन वर्षों में उनके मंत्रालय द्वारा कितनी समितियां गठित की गईं;

(घ) उक्त समितियों ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं;

(ङ) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा मांगर विभाजन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टर बेहतर सेवा शर्तों एवं पदोन्नति के अवसरों की मांग कर रहे हैं ।

(ख) से (च) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, रेलवे चिकित्सा सेवा, और केन्द्रीय पुलिस संगठनों के अधीन चिकित्सा पदों से सम्बन्धित कैरियर में सुधार और सबर्गें डांचे के बारे में विचार करने के लिए जून 1987 में एक अन्तर विभागीय समिति गठित की गई थी । इस समिति ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न उप-संभागों के लिए बरिष्ठ प्रशासन ग्रेड स्तर (सुपर टाइम ग्रेड 5900-6700 ढ०) के निम्न-लिखित अतिरिक्त पदों की सिफारिश की :

सामान्य इयूटी	29
अध्यापनेसर	5
विशेषज्ञ	
अध्यापन विशेषज्ञ	10

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा सबिस डाक्टर संघ इस समिति की सिफारिशों से सन्तुष्ट नहीं थे । सबिस डाक्टरों की समस्याओं की जांच करने के लिए 1989 के शुरू में एक अन्य अन्तर्विभागीय समिति गठित की गई और जून, 1989 में समिति ने बेलगमानों, पदोन्नतियों, विभिन्न शर्तों आदि सहित विभिन्न पहलुओं पर अपनी सिफारिशें की थीं । तथापि, सबिस डाक्टरों के संगठनों की संयुक्त कार्रवाई परिषद ने अप्रैल, 1989 में अपनी मांगों का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया । तब यह निर्णय किया गया था कि सुपर टाइम ग्रेड में अतिरिक्त पदों का सृजन करने की आवश्यकता सहित सभी मांगों पर सामूहिक रूप से विचार किया गया ।

21 अगस्त, 1989 को सबिस डाक्टरों के संगठनों की संयुक्त कार्रवाई परिषद के साथ एक

समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया जिसमें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सुपर टाइम ग्रेड के लिए 134 पद जो इस प्रकार हैं बनाने पर सहमति दी गई है।

सामान्य ड्यूटी	116
अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपसंवर्ग	8
लोक स्वास्थ्य	2

उपर्युक्त पदों का सृजन कर दिया गया है और इस पदों को भरने के लिए प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिए गए हैं।

कैरियर में सुधार करने और संवर्ग पुनः संरचना के सभी पहलुओं की जांच करने और सविन्यता के केन्द्रीय सरकार की श्रेष्ठ ग्रुप "क" सेवाओं में अपना उपयुक्त स्थान हासिल कराने की दृष्टि से प्रस्ताव तैयार करने तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के 4 उपसंवर्गों में पदोन्नति के अवसरों में सदृश्यता सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 21-8-89 के समझौता ज्ञापन के अनुसरण में एक अन्य समिति गठित की गई है। इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट 30 अगस्त, 1990 तक प्रस्तुत कर दिए जाने की आशा है।

केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित उत्तर प्रवेश के बांध

[हिन्दी]

9094. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर और झांसी में उन बांधों और सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिव्या) : ललितपुर जिले में कचनाई बांध तथा झांसी जिले में पथराई बांध सम्बन्धी क्रमशः 15.68 करोड़ रुपए तथा 7.35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की परियोजना रिपोर्टें जिनमें 10335 हेक्टेयर तथा 2112 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता की परिकल्पना है, तकनीकी-आर्थिक रूप से मूल्यांकन हेतु क्रमशः मार्च, 1990 और फरवरी, 1990 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई हैं।

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ, बंगलौर का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव

[अङ्ग्रेजी]

9095. श्री एच० झी० श्रीकृष्णस्वामी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बंगलौर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज का दर्जा बढ़ाकर उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के समान राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

ऊर्जा तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के शासी निकाय ने 27 अगस्त, 1987 और 14 जुलाई,

1960 को हुई अपनी बैठकी में इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान बनाने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश की जांच वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ-साथ कर्जाटक सरकार के परामर्श से की जा रही है।

पेप्सी फूड्स

9096. कुमारी उमा भारती : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) पेप्सी फूड्स (प्रा०) लि० का अपने शीतल पेय कंसन्ट्रेट का प्रतिष्ठान किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार पेप्सी फूड्स (प्रा०) लि० को अपने एकक उद्योग स्थानों पर स्थापित करने का निर्देश देगी जहां शीतल पेय के संघटक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का कम्पनी का एक एक मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में स्थापित करने के लिए कम्पनी को निर्देश देने का विचार है जहां अदरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सरदर बाबू) : (क) श्री पेप्सी फूड्स प्रा० लि० का पंजाब में जिला संगरूर में अपना शीतल पेय कारखाना संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आपरेशन फ्लड डेयरियों द्वारा दूध में हाइड्रोजन पर आक्साइड का प्रयोग

9097. श्रीमती सुश्रुतिनी अली : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमूल तथा अन्य डेयरियों द्वारा आपरेशन फ्लड एक, दो, तीन, और चार तथा कुछ मिशन के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय व्यापार में सम्बन्धी दूरी तक डोये जाने वाले तरल दूध में प्रतिबन्धित क्षारवाक हाइड्रोजन पर-ऑक्साइड का प्रयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पदार्थों के बिना क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री तथा ज्ञान विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जनसंख्या में वृद्धि

[श्रीमती]

9098. श्री जनार्दन तिवारी :

श्री आर० श्रीवरदत्त :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सन् 1981 में

की गई जनगणना के अनुसार जनसंख्या के जो आंकड़े थे उनमें मार्च, 1990 तक हुई अनुमानित वृद्धि के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार भारत तथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की जनसंख्या तथा जनसंख्या अनुमानों पर विशेषज्ञ समिति के मध्यावधि अनुमान के आधार पर मार्च, 1990 तक हुई अनुमानित वृद्धि का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पहली मार्च, 1981 को भारत, राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों की जनसंख्या तथा पहली मार्च, 1990 का अनुमानित जनसंख्या

(मध्यावधि अनुमान)

(जनसंख्या संकड़ों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1981 जनगणना	1990 अनुमानित	वृद्धि संकड़ों में
1	2	3	4
भारत	685,159,0*	821,992,8	136,833,8
आन्ध्र प्रदेश	53,549,7	63,158,7	9,609,0
असम	19,896,9	24,455,9	4,559,0
बिहार	69,914,8	84,732,7	14,817,9
गुजरात	34,085,8	40,376,6	6,290,8
हरियाणा	12,922,6	16,140,4	3,217,8
हिमाचल प्रदेश	4,280,8	5,025,5	744,7
जम्मू व कश्मीर	5,961,7**	7,289,8	1,328,2
कर्नाटक	37,135,7	44,568,5	7,432,8
केरल	25,453,7	29,665,5	4,211,8
मध्य प्रदेश	52,178,8	63,047,7	10,868,9
महाराष्ट्र	62,784,1	74,203,4	11,419,3
मणिपुर	1,420,9	1,762,2	341,3
मेघालय	1,335,8	1,692,2	356,9

1	2	3	4
नागालैंड	774,9	1,097,6	322,7
उड़ीसा	26,370,3	30,923,9	4,553,6
पंजाब	16,788,9	19,571,3	2,782,4
राजस्थान	34,261,9	43,475,6	9,213,7
सिक्किम	316,4	435,7	119,3
तमिलनाडु	48,408,1	55,676,9	7,268,8
त्रिपुरा	2,053,0	2,529,9	476,9
उत्तर प्रदेश	110,862,0	133,691,4	22,829,4
पश्चिम बंगाल	54,580,6	64,816,3	10,235,7
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	188,8	283,1	943
अरुणाचल प्रदेश	631,8	807,0	175,2
चण्डीगढ़	451,6	722,5	270,9
दादरा व नागर हवेली	103,7	130,3	266
दिल्ली	6,220,4	8,910,0	2,689,6
गोवा, दमण व दीव	1,086,8	1,332,8	246,0
लक्षद्वीप	40,3	46,1	58
मिजोरम	493,7	688,4	194,7
पांडिचेरी	604,5	734,3	129,8

*असम की अनुमानित जनसंख्या सहित जहां 1981 में जनगणना नहीं हुई।

**जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या को 1 मार्च, 1981 के अनुसार दिखाया गया है। जन-गणना सन्दर्भ तारीख के रूप में 6 मई, 1981 को सूर्योदय से आरम्भ की गई थी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को संरक्षण प्रदान करना

[अनुवाद]

9099. श्री गिरिधर गोबांगी : क्या धर्म मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा ममाज के कमजोर वर्ग के अन्य लोगों को मोक्ष और उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई संविधिक उपबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या मार्गनिर्देश जारी किए हैं ?

धम और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पसवान) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत के संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों के हितों के संरक्षण तथा उनके समाजाधिक स्तर के विकास के लिए विभिन्न सुरक्षोपायों के व्यापक ढांचे की व्यवस्था है । ये सुरक्षोपाय संविधान के अनेक अनुच्छेदों में निहित हैं । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं : अनुच्छेद 15(4) नागरिकों के सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान के बारे में, अनुच्छेद 16(4) तथा 335 सेवाओं तथा पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण के बारे में, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन के बारे में, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों का संरक्षण करने के बारे में, अनुच्छेद 46 लोगों के कमजोर वर्गों के और विशेषकर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को प्रोत्साहन तथा उन्हें सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय तथा शोषण से संरक्षण प्रदान करना, अनुच्छेद 275 अनुसूचित जनजाति के कल्याण को प्रोत्साहन देने अथवा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को उन्नत करने के प्रयोजनार्थ कुछ राज्यों को संघ से अनुदान के बारे में, अनुच्छेद 330 लोक सभा में स्थानों के आरक्षण के बारे में, अनुच्छेद 332 विधान सभाओं में स्थानों के आरक्षण के बारे में तथा अनुच्छेद 341 तथा 342 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किर्निर्देशन के बारे में हैं । इसके अतिरिक्त, भेदभाव को रोकने तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के निवारण के लिए सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 बनाया है ।

(ग) अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजनाएं और आदिवासी उपयोजनाएं तैयार करने और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विकास के लिए योजनाएं शुरू करने हेतु स्वच्छिन्न संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए सरकार ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं । इसके अतिरिक्त विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उपयोजना दोनों के लिए केन्द्र सरकार विशेष केन्द्रीय सहायता विमुक्त करती है तथा विमुक्त की गई राशि के समुचित उपयोग तथा अन्य उपयोग के लिए राशियों के विचलन को रोकने के लिए दिशा निर्देश विद्यमान हैं । सरकार ने एहतियाती, सुरक्षात्मक, निवारक, दण्डात्मक तथा पुनर्वासितात्मक उपायों तथा आर्थिक नीतियों के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए ताकि अपराधों को रोकना जा सके और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को समुचित संरक्षण तथा राहत प्रदान की जा सके ।

महानगरों के विकास हेतु सहायता

9100. प्रो० के० श्री० कायस : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ने अपने राज्यों के महानगरों के विकास हेतु कितनी वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) अभी तक कितनी सहायता दी गई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मरुज) : (क) से (ख) महाराष्ट्र तथा पश्चिमी बंगाल

सरकार ने अपने राज्यों में महानगरीय शहरों के विकास के लिए केन्द्र से कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी है। मद्रास निगम की तृतीय शताब्दी के अवसर पर मद्रास के विकास के लिए तमिलनाडु सरकार से केन्द्रीय सहायता के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

राज्य सरकार को अपने अनुरोध के समर्थन में विस्तृत विशिष्ट योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

सेवानिवृत्त पत्रकारों को पेंशन

[हिन्दी]

9101. डा० बंगाली सिंह : क्या धर्म मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में सेवानिवृत्त पत्रकारों को पेंशन दी जा रही है;

(ख) किन-किन राज्यों में पत्रकारों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों को ऐसे निदेश जारी करने का है, जिससे कि सभी राज्यों में पत्रकारों को पेंशन मिल सके; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के निदेश कब तक जारी किए जाएंगे ?

धर्म और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) से (घ) इस समय, पत्रकारों के लिए सेवा-निवृत्ति पेंशन की कोई योजना नहीं है। अतः पत्रकारों को पेंशन देने के लिए राज्य सरकार को निदेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि योजना द्वारा पत्रकारों और अन्य कर्मचारों के लिए उपयुक्त सेवानिवृत्ति पेंशन योजना की व्यवस्था करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

रोजगार कार्यालयों के आंकड़े

[अनुबाध]

9102. श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी : क्या धर्म मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोजगार कार्यालय के आंकड़े वास्तविक स्थिति नहीं दर्शाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश में रोजगार सम्बन्धी आंकड़ों की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या-क्या उपाय करने पर विचार किया जा रहा है ?

धर्म एवं कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) रोजगार कार्यालय अपने पास पंजीकृत रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों के आंकड़े उपलब्ध करते हैं, यह आवश्यक नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों।

(ख) रोजगार स्थिति पर प्रामाणिक सूचना, राष्ट्रीय मजूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा संचालित रोजगार—बेरोजगारी के पंचवार्षिक सर्वेक्षणों से नियमित रूप से पहले ही उपलब्ध है।

मकानों का निर्माण

9103. श्री वामनराव महाडिक : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकानों के निर्माण की वर्तमान प्रणाली के कारण पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निम्न आय समूह के लिए मकानों के निर्माण के बारे में इन परिवर्तनों को कार्यान्वित करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री सुरासोसी चारन) : (क) और (ख) जी, नहीं। भू-उपयोग अभियोजना मानकों, भू-दृश्य को प्रशासित करने वाले राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संहिता उपनियम तथा कई भारतीय मानकों का उद्देश्य मानव बास्तियों में स्वस्थ, व्यवस्थित तथा सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त करना है।

(ग) अनौपचारिक निम्न आय बस्तियों, मलिन बस्तियों आदि के पर्यावरण में सुधार करने के लिए सामान्य मार्गनिर्देशन के रूप में भारतीय मानक 8888 की सिफारिश की जाती है। निम्न आय वर्गों द्वारा निर्माण क्रियाकलापों को सुसाध्य बनाने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों से स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बृहद योजना मानक, भू-उपयोग योजना तथा विनियमन, भवन (निर्माण) उपनियम अद्यतनरचनात्मक मानकों का पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया गया है।

महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में "जल प्रबन्ध" मेला आयोजित करना

9104. श्री ए० आर० अन्तुले : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार, विभिन्न सेवा संगठनों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, उपकरण वितरकों और किसानों का सहयोग प्राप्त करके केन्द्रीय सरकार का कोंकण क्षेत्र में किसी उपयुक्त स्थान पर "कृषि हेतु जल प्रबन्ध" विषय पर एक मेला आयोजित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह मेला कब तक आयोजित किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मन्नुभाई कीटाडिया) : (क) महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में कृषि के लिए जल प्रबन्ध पर मेला आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सामान्यतः जल संसाधन मंत्रालय/केन्द्रीय जल आयोग ऐसी प्रदर्शनियों के आयोजकों के अनुरोध पर प्रदर्शनियों, मेलों आदि में भाग लेता है। ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

इन्दुवकी बाँस क्षेत्र में भूकंपीय झटके

9105. प्रो० के० बी० चामस : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी मिली है कि पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में बड़े जलाशयों के होने के भूकंपीय झटके आने की सम्भावना बढ़ जाती है;

(ख) क्या पश्चिमी झटों में इटुबकी क्षेत्र पारिस्थितिक दृष्टि से एक लाजुक क्षेत्र है जहाँ इटुबकी जलाशय होने के कारण भूकंपीय झटके अधिक आते हैं; और

(ग) क्या सरकार का इटुबकी क्षेत्र में भूकंपीय झटके आने के सम्बन्ध में इस जलाशय का एक न्यायिक जांच कराने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) कुछ जलाशयों के स्थानों पर जलाशय से प्रेरित भूकम्प का कारण बड़े जलाशयों की मौजूदगी न होकर वहाँ की भौगोलिक विशेषताएँ बताई गयी हैं।

(ख) सारे देश को भूकम्पीय जोखिमों के विभिन्न स्तरों के पांच जोनों में बांटा गया है और इटुबकी बांध जोन-11 में पड़ता है। जून, 1988 से अंकित किए गए अधिकतम कंपन के कारण गति-वर्धन में वास्तविक तीव्रता इटुबकी बांध के लिए लपटाए गए डिजाइन मान से काफी नीचे रही। केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि इटुबकी क्षेत्र में महसूस की गयी भूकंपीय झटकों का इटुबकी जलाशय से सम्बन्ध नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

12.23 म० प०

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोग बैठ जाइए। श्री दिनेश सिंह।

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : महोदय, इस बात को आपकी जानकारी में लाते हुए मुझे अत्यन्त खेद हो रहा है जिस तरह से.....

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सस्टेंटिव मोशन के बारे में ज्ञापन करना चाहते हैं? वह नियम 184 के तहत आपने दिया है, मिल गया है। विचाराधीन है।

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी के बारे में अज्ञ कर रहा था।

[अनुवाद]

जिस तरीके से नागालैण्ड में सरकार बदली गई है वह बिल्कुल अवैध है... (व्यवधान) वास्तव में यह संविधान के साथ घोखा करने वाला कार्य है।

अध्यक्ष महोदय : राज्यपाल की कार्यवाही के सम्बन्ध में आप मूल प्रस्ताव के अन्तर्गत चर्चा कर सकते हैं। आपने इस प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ है। मुझे आपका नोटिस मिल गया है और उस पर विचार किया जा रहा है। मैं जब उस पर निर्णय ले लूंगा तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री विनेश सिंह : महोदय, मेरा यह कहना है कि अगर आप सविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 3 को देखें तो इसके अनुसार विधान सभा या संसद में किसी दल के विघटन से पहले मूल दल में विघटन होना आवश्यक है। जब तक मूल दल में विघटन नहीं होता, तब तक सदन अथवा संसद में विघटन को मान्यता नहीं दी जा सकती।

इसके साथ-साथ दसवीं अनुसूची के पैरा 3 में यह स्पष्ट लिखा है कि यह अध्यक्ष को निर्धारित करना होता है कि क्या सदस्यों ने सदस्यता खो दी है अथवा नहीं। अगर आप दसवीं अनुसूची के पैरा 3 को देखें तो आप पायेंगे कि यह निर्णय बिल्कुल न्यायोचित नहीं था। अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होता है। राज्यपाल, न्यायालय अथवा अन्य कोई व्यक्ति उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। मैं आपके सामने यह प्रश्न इसलिए भी प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि इसका सम्बन्ध आपसे भी है। इसलिए, इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। इसमें राज्यपाल या न्यायालय कुछ नहीं कर सकते।

(अध्यक्ष)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बाद सदन इस पर चर्चा कर सकता है।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : इस पर आज ही चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया कि इस सम्बन्ध में चर्चा का प्रस्ताव मेरे विचाराधीन है।

(अध्यक्ष)

श्री विनेश सिंह : हम एक मुद्दे पर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि आज नागालैंड में एक अर्ध-सरकार कार्य कर रही है। (अध्यक्ष)

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल मलिक (अलीगढ़) : मेरा निवेदन यह है कि एक बार नोटिस दे दिया है, नोटिस आपके सामने विचाराधीन है।

[अनुवाद]

आप इस मामले पर यहां चर्चा नहीं कर सकते। आपने नोटिस दिया हुआ है।

[हिन्दी]

नोटिस आपके पास है। उस पर जजमेंट होने के बाद डिबेट होगी, अब कैसे इस सवाल पर डिबेट हो सकती है ?

[अनुवाद]

इस समय इस विषय में कोई चर्चा नहीं हो सकती।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह एक सर्वैधानिक संकट है। राज्यपाल द्वारा स्थापित की गई सरकार असर्वैधानिक है।

अध्यक्ष महोदय : आप नियमों को जानते हैं। हम राज्यपाल की कार्यवाही पर चर्चा केवल मूल प्रस्ताव के अन्तर्गत ही कर सकते हैं। श्री विनेश सिंह का नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव मेरे विचाराधीन है।

(अध्यक्ष)

श्री संतोष मोहन बेब (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, पहले भी इसकी अनुमति दी जाती थी ।

अध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं । कृपया, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : मैं रूल 184 के अन्तर्गत अपना पाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूँ । (व्यवधान)

रूल 184 में प्रावधान है कि बिना आपकी अनुमति के कोई भी प्रश्न यहां पर नहीं उठाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है । मैं रंगुलेट कर रहा हूँ ।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन बेब : 1988 में, इन्हीं परिस्थितियों में विपक्ष ने तत्कालीन राज्यपाल की आलोचना करने के लिए 35 से 40 मिनट लिए थे । आज राज्यपाल ने अध्यक्ष को केवल पत्र ही नहीं लिखा बल्कि उसने निलम्बन को वापिस लेने की भी प्रार्थना की है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरी अनुमति के बाद ही सबन इस पर चर्चा कर सकता है ।

श्री सन्तोष मोहन बेब : यह लोकतन्त्र की हत्या है । हम यह चाहते हैं कि इस विषय पर, चर्चा की अनुमति आज ही मिलनी चाहिए क्योंकि उपप्रधानमन्त्री स्वयं नागालैंड गए और उन्होंने राज्यपाल को कहा कि अगर तुम इस सरकार को भंग कर दो तो मैं तुम्हें स्थाई राज्यपाल बना दूंगा । आज नागालैंड की यह स्थिति है । हम यह चाहते हैं कि आप नागालैंड की स्थिति पर आज ही चर्चा की अनुमति दें । इस पर आज ही चर्चा होनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : इससे पहले कि हम इस घटना पर अपना मत प्रकट करें, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो अखबारों में आया है, उसके अतिरिक्त मुझे कुछ पता नहीं और इस संबंध में आपको निर्णय लेना है कि इस मामले को इस सदन में कैसे निपटाना है । यह मामला आपके विचाराधीन है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आरम्भ में ही आपको बताया है कि श्री दिनेश सिंह ने नियम 184 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया है । जब तक मैं इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं ले लेता, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जा सकता । यह मामला मेरे विचाराधीन है ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो केवल संबैधानिक ही नहीं होते बल्कि उनका सम्बन्ध परम्परा से भी होता है । (व्यवधान) ...मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ मुद्दे जो कि सामने आ रहे हैं, निश्चित रूप से वे बहुत गम्भीर हैं । उन पर विचार किया जाना चाहिए । सबसे पहला प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या दल बदल कानून के अन्तर्गत सदस्यों को अव्योच्य ठहराए जाने की प्रक्रिया पर

अमल किया गया अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में मैं अभी कोई भी मत प्रकट करना नहीं चाहता। दूसरे प्रश्न यह है कि क्या अध्यक्ष यह सोचते हैं कि पिछली सरकार ने बहुमत गंवा दिया था और क्या बहुमत अथवा अल्पमत का निर्णय शतक में होना चाहिए अथवा किसी दूसरे तरीके से। तीसरा प्रश्न यह है कि क्या राज्यपाल अध्यक्ष को सलाह दे सकता है अथवा वह उसकी सलाह की अवहेलना कर सकता है। आपको यह पता लगाना होगा कि क्या यह तथ्य वास्तविक है अथवा भ्रामक है। मेरे विचार में आप समाचारपत्रों में प्रकाशित सामग्री से प्रभावित होकर कोई निर्णय नहीं करेंगे। आपको आवश्यक धार्मिकारी स्वयं प्राप्त करनी होगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत ही गम्भीर मुद्दे शामिल हैं। उनको स्पष्ट करना होगा अर्थात् यह देखना होगा कि क्या किसी ने अनुचित अथवा असंबंधानिक कार्य-वाही की है। (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन शेष : एक निम्नलिखित सदस्य विधान सभा की कार्यवाही में कैसे भाग ले सकता है ? यह तो एक बहुत ही अद्भुत स्थिति है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसलिए, यह सब मुद्दे इसमें शामिल है। महोदय, मैं नहीं जानता कि आप इसकी कैसे व्याख्या करेंगे कि क्या दल बदल कानून के अन्तर्गत कुछ सदस्यों को बिना उनके स्पष्टीकरण लिए निम्नलिखित करना उचित है अथवा नहीं।

श्री सोमनाथ बटर्जा (बोलपुर) : ऐसा कैसे हो सकता है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या प्रक्रिया में ऐसा विधान है ?... (व्यवधान)... मेरा निवेदन आपसे है, महोदय, न कि श्री साठे से। (व्यवधान)

श्री बसंत शरडे (बर्धा) : क्या अध्यक्ष के निर्णय पर राज्यपाल द्वारा अंकुश लगाया जा सकता है ? क्या आप यह सुझाव देना चाहेंगे। मैं इस मुद्दे पर आपके विचार जानना चाहता हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आपको सम्बोधित नहीं कर रहा हूँ। मैं अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित कर रहा हूँ। मेरी बात पूरी होने के बाद आप अपना प्रश्न उठा सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : साठे जी, दूसरों की बात में रुकावट मत डालिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विपक्ष के माननीय सदस्य बार-बार उसे दोहरा रहे हैं जोकि 1988 में हुआ। आप उसकी तह तक जा सकते हैं। इस बारे में आपके मन में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। जारी बस्तुस्थिति पर विचार किया जाना चाहिए परन्तु इसके लिए उचित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में अगर गृह मंत्रालय अथवा कोई और संस्था अपने विचार प्रकट करना चाहे तो वे इसके लिए स्वतन्त्र हैं। परन्तु इसके लिए एक उचित चर्चा की जानी चाहिए। महोदय, आपको इस सम्बन्ध में सही ज़ोरों से सारी जानकारी हासिल करनी चाहिए। ताकि हमें वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पहले ही बताया है कि मुझे नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा करवाने का नोटिस श्री विनेश सिंह से मिल चुका है। इस पर मैं विचार कर रहा हूँ।

श्री संतोष मोहन शेष : इस सम्बन्ध में आपका निर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अपना निर्णय तभी बता पाऊँगा जब मैं यहाँ से जाकर इस पर विचार करूँगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विषय में और कोई चर्चा नहीं होगी । अगर सरकार इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहती है तो मुझे कोई आमति नहीं । मैं उन्हें मना नहीं करता ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए.....मैं किसी बात का खण्डन नहीं करता.....सरकार यहाँ है । मैं सरकार को कुछ कहने से रोकता नहीं हूँ ।

(व्यवधान)

एक माननीय सचिव : कृपया मेरी बात सुनिए ।

अध्यक्ष महोदय : सुनने का प्रश्न ही नहीं है । श्री चिदम्बरम् ।

श्री पी० चिदम्बरम् (शिवगंगम) : महोदय, हम किसी राज्यपाल के व्यवहार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं; जिस पर चर्चा की जा रही है वह नागालैंड में लिए गए उस निर्णय के बारे में है जिसमें उस सरकार को अधिकार देने की पेशकश है जो पूरी तरह से अंतरिम है ।

अध्यक्ष महोदय : आप जनते हैं कि एक प्रक्रिया अपनाई जाती है ।

श्री पी० चिदम्बरम् : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा था कि बहुत गम्भीर मुद्दे उठे हैं । इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा है कि अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम है; यह उचित नहीं है । श्री दिनेश सिंह ने भी इसकी चर्चा की है । इन विषयों को स्पष्ट कौन करेगा ? हम देश में कानून बनाने वाली उच्चतम संस्था है । संविधान में संशोधन करके दसवीं अनुसूची को प्रस्तुत किया गया; यह संसद ने किया था । फिर से चर्चा का सहारा लेकर उस पर वाद-विवाद करके, पिछली चर्चा को ध्यान में रखकर ही इसे स्पष्ट किया जा सकता है । नागालैंड में एक गैर कानूनी सरकार को अधिकार कैसे दिया जा सकता है ? दस सदस्यों को अयोग्य सिद्ध किया जा चुका है । क्या राज्यपाल तब उन्हें बैठने की अनुमति दे सकते हैं जब अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि वे नहीं बैठ सकते ? मैं एक सीधा प्रश्न पूछता हूँ । कल, यदि आप कोई निर्णय लेते हैं, तो क्या भारत के राष्ट्रपति आपके निर्णय को अस्वीकृत कर सकते हैं ? हमारे यहाँ राजतन्त्र है अथवा संसदीय लोकतन्त्र ? हमें इस मुद्दे पर अक्षय चर्चा करनी चाहिए । एक प्रस्ताव है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे । हम वह नहीं करेंगे जो 1988 में हुआ था । वर्ष 1988 में; तत्कालीन विपक्ष ने संसद की कार्यवाही रोक दी थी । हम सिर्फ एक यथार्थ चर्चा चाहते हैं । एक प्रस्ताव है; आज हम इस पर चर्चा करेंगे । (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : महोदय, भारत के इतिहास का यह सबसे दुःखद अध्याय है, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो कुछ कहा है उसमें यह बताया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप श्री इन्द्रजीत गुप्त से सहमत हैं ।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, यह उचित होगा यदि मैं भारतीय मार्क्सवादी दल के सदस्य भी

सैफुद्दीन चौधरी की पंक्तियां उद्धृत करूं जो उन्होंने चर्चा के दौरान कही थीं। उन्होंने कहा था— पूर्वोत्तर राज्यों में जो होने जा रहा है उसके उत्तरदायी आप होंगे। यहां, कांग्रेस (ई) द्वारा शासित राज्य सरकार है जिसे विस्थापित किया गया है। मैं जानना चाहूंगा, कि क्या जन मोर्चा दल सरकार की यह निर्धारित नीति है कि कांग्रेस (ई) द्वारा शासित राज्यों की सरकारों को विस्थापित किया जाए। यदि सरकार की यह नीति है कि केन्द्र में एक विशेष दल हो और वही विशेष दल राज्यों में भी सत्तास्वरूप हो, तो तब हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। वे सभी कांग्रेस (ई०) शासित राज्यों को विस्थापित करें। वे देश में प्रजातन्त्र लाएं। महोदय, वे भारत के प्रजातन्त्र का कत्ल कर रहे हैं। अब, मेरा निवेदन है कि जो लोग यहां बंठे हैं—क्योंकि भारतीय मार्क्सवादी दल एक मार्क्सवादी दल है—वे हमें भाषण और उपदेश दे रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि भारतीय मार्क्सवादी दल को और आपको बोलने का अधिकार है।

श्री जगन्मोहन पुजारी : महोदय, कृपया इसे हल्केपन से न लें। यह एक गम्भीर विषय है।

अध्यक्ष महोदय : हां, यह एक गम्भीर विषय है। मैं इसे हल्केपन से नहीं ले रहा हूँ।

श्री जगन्मोहन पुजारी : महोदय, आप इस पर अपना निर्णय देने जा रहे हैं। कृपया सभी पहलुओं पर गौर करें। आप प्रजातन्त्र के संरक्षक हैं। कृपया अपने शासन में ऐसी घटनाएं न होने दें।

श्री बसन्त साठे : महोदय, मैं सोचता हूँ हमारी तरफ सभा की गम्भीरता और चिन्ता को आपने देख लिया है। हम चाहते हैं कि कोई भी असंवैधानिक सरकार, संविधान के अधिकार से बाहर, देश में जारी नहीं रहनी चाहिए। इस सम्बन्ध में नियम 184 के अधीन एक नोटिस दिया जा चुका है। आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है। आप को सभा के विचारों की जानकारी हो गई है। इसलिए आज ही हमें कार्य मंत्रणा समिति में इस पर औपचारिक रूप से चर्चा करने का निर्णय करना चाहिए। मेरा यही निवेदन है। (व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन बेब : महोदय, पिछली बार उन्होंने भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था और श्री सोमनाथ षटर्जी नेता थे।

एक माननीय सदस्य : आप को भी यह करने की स्वतन्त्रता है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ षटर्जी : अध्यक्ष महोदय.....

श्री टी० बशीर (चिरायिकिल) : मुझे उम्मीद है कि वे सरकारिया आयोग के बारे में भी कुछ कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री बशीर, कृपया आप बैठ जाइए। हम श्री सोमनाथ षटर्जी को सुनेंगे।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ षटर्जी : आप के पास सुनने के लिए धैर्य क्यों नहीं है? अध्यक्ष महोदय, प्रेस में जो हुआ है—ठीक है विभिन्न अखबारों का विभिन्न नजरिया है—बहु सत्य है। इस विषय में कुछ पहलू सोच पैदा करने वाले हैं और इसके बारे में कोई संशय नहीं है। किन्तु, महोदय...

श्री पी० आर० कुमारभंगसम (सलेम) : यह 'किन्तु' किसलिए ?

श्री सोमनाथ षटर्जी : जिस प्रकार यह सभा दूसरी सभा के अध्यक्ष के अचार-व्यवहार पर स्वतः चर्चा नहीं कर सकती। यह राज्यपाल के आचार पर भी चर्चा नहीं कर सकती सिवाए उसके अनुसार जो नियम के अनुसार है और उसका अनुसरण किया जाना चाहिए।

प्र० पी० जे० कुरियन : आपने इस पर पिछली बार कैसे चर्चा की थी ?

श्री सोमनाथ षटर्जी : महोदय, इसलिए इसका अनुसरण किया जाना चाहिए। जैसे श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ठीक ही कहा था, आंकों की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। किन्तु, महोदय, यह सभा किसी प्रकार का निर्णय नहीं दे सकती, जैसा कि श्री चिदम्बरम समझते हैं। वे कहते हैं कि यह संविधान की व्याख्या कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार की है। इस सभा में कांग्रेस दल की ओर से प्रजातान्त्रिक नियमों और परम्पराओं के बारे में सुनकर हंसी ही आती है। (व्यवधान)

प्र० पी० जे० कुरियन : अब हम भारतीय मार्क्सवादी दल और भाजपा को सुनते हैं।
(व्यवधान)

श्री सोमनाथ षटर्जी : महोदय, यदि आप अपनी समझ में वाद-विवाद की अनुमति देते हैं, इस पर उचित तरीके से उचित प्रस्ताव के साथ चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह पहले ही कह दिया है।

श्री सोमनाथ षटर्जी : किन्तु आज, यहाँ एक निर्णय दिया जा रहा है। इस सभा के पास इस पर निर्णय देने की क्षमता नहीं है। यह राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति का मामला नहीं है। यह सभा केवल अपने विचार प्रकट कर सकती है और इस बारे में कोई निर्णय नहीं दे सकती कि क्या हुआ है और सरकार क्या कर सकती है। यह सरकार को सिवाए राष्ट्रपति शासन लागू करने के अन्य कोई निर्देश नहीं दे सकती। (व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : महोदय, क्या भारत के मार्क्सवादियों ने स्तालिनवाद छोड़ दिया है क्योंकि वे हमें प्रजातन्त्र सिखा रहे हैं ?

श्री सोमनाथ षटर्जी : मैं जानता हूँ वे प्रजातन्त्र से दूर भागते हैं। वे तो प्रजातन्त्र की धारणा से ही दूर भागते हैं। हम यह जानते हैं। हमने पिछले चालीस वर्षों में देखा है कि कैसे इस देश के संविधान के साथ बिलबाद किया गया है, कैसे सभी काले कानून, कठोर कानून और असंबैधानिक कदम उठाए गए हैं।

निवारक नजरबन्दी कानून को संविधान में जोड़ा गया है और वे उस स्थिति का खुलेआम फायदा उठा रहे हैं। वे इस देश में कठोर और काले कानून जैसे 'मीसा' और 'एन० ए० ए०' लगाकर प्रजातान्त्रिक आन्दोलन को दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए, हम उनसे प्रजातन्त्र के ऊपर भाषण सुनने को तैयार नहीं हैं। किन्तु हम महसूस करते हैं कि यह ऐसा विषय है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और आप यदि अपनी समझ में इसकी अनुमति देते हैं तो, हमें इस पर उचित तरीके से चर्चा करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री विदेश सिंह : हम पर उचित तरीके से चर्चा की जाएगी। हम केवल उन माननीय सदस्य को अपनी बोले थे, के भाषण को उद्धृत करेंगे जो उन्होंने 1988 में कहा था।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं सोचता हूँ कि आप सभा की उस अनुभूति को समझेंगे कि सभा इस विषय पर चर्चा करना उचित समझती है। आपके सामने एक प्रस्ताव-नियम 184 के अधीन है। इससे पहले कि कार्य मंत्रणा समिति इसकी जांच करें, कृपया आप इसे स्वीकार कर लें। क्या मैं आपसे इसे आज ही स्वीकार करने का निवेदन कर सकता हूँ ताकि हम इस पर चर्चा करने का समय नियुक्त कर सकें ?

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

(अवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : नियमों के अनुसार कार्य मंत्रणा समिति केवल चर्चा के समय और अवधि के बारे में निर्णय लेगी।

महोदय, यह तो आपको निर्णय लेना है कि इसे स्वीकार करें और यह घोषणा भी करें कि चर्चा आज होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कहा है कि यह मामला मेरे विचाराधीन है।

श्री बी० आर० कुमारमंगलम : सारी सभा चाहती है कि इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। कृपया अपना फैसला देने से पूर्व सभा की संबंधित समिति को ध्यान में रखें। (अवधान)

श्री बसन्त साठे : कृपया इसे स्वीकार कर लें। हम इसके लिए समय निर्धारित कर लेंगे।

(अवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री लाल कृष्ण आडवाणी बोलें :

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : इस संसद में जब हम समाप्ततः चर्चा करते हैं तो या तो केन्द्रीय सरकार के निर्णय या किसी कदम के बारे में करते हैं। अगर किसी को लगता है कि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था टूट गयी है तो उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम चर्चा करेंगे तो प्रस्ताव का स्वरूप ऐसा हो जो कि नियमों के अन्दर बंधता हो। हम किसी विधान सभा के स्पीकर के बारे में कभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। यहां तक कि हम किसी राज्यपाल के बारे में भी प्रतिबन्धित हैं जब तक कि कोई औपचारिक प्रस्ताव न हो। (अवधान) आपने स्वयं कह दिया कि मैं उस पर विचार कर रहा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता। अगर सभी सदस्यों को, सभी पक्ष के लोगों को यह लगे कि समाचारपत्रों में जो छपा है उससे वे संतुष्ट नहीं हैं, या चिंतित हैं कि वहां ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसके बारे में भी व्यवस्था आपको देनी है कि चर्चा का रूप क्या हो। मैं चाहूंगा कि इस मामले में नागालैंड की बात भी होनी चाहिए, लेकिन नागालैंड की परिस्थितियां अब-जब प्रदेशों में पैदा हुई हैं, तब-तब केन्द्र सरकार ने क्या काम किया है? किस प्रकार का आचरण उन्होंने अपनाया है, इसकी चर्चा भी होनी चाहिए? जहां तक मेरी जानकारी है नागालैंड के घटना-क्रम में केन्द्र सरकार को इसमें कुछ लेना-देना नहीं है। (अवधान) आपकी तरह यह बहुत झोझियार नहीं थे। आप लोग ऐसी स्थिति में आगे बढ़ करके काम करते थे और इसलिये उस केन्द्रीय सरकार के आचरण को ही हम प्रकाश में लाते थे। लेकिन आज जो स्थिति पैदा हो गई है, जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने, माक्सवादी पार्टी के सदस्यों ने, सी० पी० आई० के सदस्यों ने निम्नलिखित कथित की है

उससे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा का स्वरूप क्या हो, प्रस्ताव क्या हो, इस पर भी निर्णय किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाच]

अध्यक्ष-महोदय : अब, श्री कमल नाथ बोलें।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, हम नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा के लिए निर्णय चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही सदस्यों के लाभ के लिए पुनः कह चुका हूँ कि यह मेरे विचाराधीन; मैंने कहा है कि यह मेरे विचाराधीन है। हाँ, कमल नाथ जी। आपने मेरी अनुमति मांगी है।

(व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : महोदय, क्या आप इसे कार्य मंत्रणा समिति के सम्मुख लाने की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा करूँगा।

श्री बसन्त साठे : कृपया ऐंसा कीजिए, अन्यथा इसका उद्देश्य बेकार हो जाएगा।

श्री कमल नाथ (छिदवाड़ा) : हम सब जानते हैं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो संसद सदस्यों तथा अन्य राजनैतिक हस्तियों के टेलीफोन गुप्त रूप से सुनने तथा उनकी इलेक्ट्रानिकी उपकरणों से निगरानी रखने के बारे में एक जांच कर रहा था। मुझे पता लगा है और ऐसी कुछ खबरें भी आ रही हैं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट में यह सही पाया गया है कि कुछ संसद सदस्यों तथा राजनैतिक नेताओं के टेलीफोन पर गुप्त रूप से निगरानी रखी जाती थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आगे कहा है... (व्यवधान)

यह बातसे सम्बन्धित है। मैं इस पर ही आ रहा हूँ। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है। कृपया इसके परिणामों को समझिए क्योंकि यह आप सभी से सम्बन्धित है।

(व्यवधान)

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह आरोप भी लगाया है कि अन्य गुप्तचर एजेंसियों ने सहयोग नहीं किया। यह रिपोर्ट सरकार के पास है। क्या सरकार इसे सभा पटल पर रखेगी; अबवा क्या इसे मैं रखूँ ? (व्यवधान)

दूसरा मुद्दा यह है कि हम जानते हैं कि यह एक छोटा मामला नहीं है। यह अल्पमत सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों की मदद से चल रही है। आज, यदि वे श्री आडवाणी, श्री सोमनाथ षटर्जी अथवा किसी भी अन्य के टेलीफोन पर गुप्त रूप से निगरानी रख रहे हैं तो यह मामला हम सभी से सम्बन्धित है। इसलिए क्या उनके पास यह रिपोर्टें हैं ? सरकार इस बारे में बतलावे कि क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह निष्कर्ष निकाला है उन्हें यह रिपोर्टें सभा पटल पर रखनी चाहिए।

श्री सोमनाथ षटर्जी : मुझे व्यवस्था सम्बन्धी एक प्रश्न करना है। उन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट का उल्लेख किया है। उन्हें इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखना चाहिए। (व्यवधान) अन्यथा

वह इसका उल्लेख नहीं कर सकते। उन्होंने सभा में इसका उल्लेख किया है। वह एक माननीय सदस्य हैं और मैं समझता हूँ कि वह एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं। वह इस रिपोर्ट में से उद्धृत कर रहे हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट का उल्लेख किया है। (व्यवधान)

यह क्या है? उन्होंने रिपोर्ट का उल्लेख किया है। उनके अनुसार जो कुछ पता लगा है उन्होंने उसी का उल्लेख किया है, उनके पास अवश्य ही इसकी एक प्रति होनी चाहिए। उन्हें इसे सभा पटल पर रखना चाहिए। (व्यवधान)

श्री कमल नाथ : वे यह कहें कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। कमल नाथ जी आप अपनी बात कह चुके हैं; क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

अब श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य बोलें। मैं किसी अन्य को अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

(व्यवधान)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैं असम पुलिस के कर्मियों द्वारा 37 बोडो आदिवासी महिलाओं से सामूहिक बलात्कार करने के बारे में 13 मई तथा 15 मई, 1990 को समाचारपत्रों में छपी कुछ खबरों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। सम्बन्धित गांव बारपेटा जिले में बाघमारा, अकरा तथा अगरगुंडी हैं। इस घटना से प्रभावित कुछ तो नाबालिग 18 वर्ष से कम आयु के थे। इनमें एक तो आठ वर्ष की बताई जाती है। अगर ये खबर सच है तो हम देखते हैं कि हमारे देश में शक्तियाँ जब भी असन्तोष को दबाना चाहती है तो वे महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं। यहाँ यह एकदम स्पष्ट है कि रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। यह कार्य ही भयानक है। फिर भी बोडो लोगों के इस क्षेत्र की संवेदनशीलता के कारण यह केवल एक राज्य का मामला बनकर नहीं रह सकता। हम सब जानते हैं कि वहाँ पर विभाजन, पृथकतावादी शक्तियाँ सक्रिय हैं। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि यह कार्य स्वयं ही घृणास्पद है बल्कि ऐसा इसलिए भी है कि ऐसे कार्य से खतरनाक राजनैतिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो सकती हैं। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वह इस मामले की जांच करे और अपराधियों को पकड़ने तथा उन्हें सजा देने में राज्य की मदद करे।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन में जो बात कहना चाहती हूँ, वह किसी घटना विशेष की तरफ इशारा नहीं करती, लेकिन वह बात इस देश में किसी घटना का कारण बन सकती है और जिसके परिणाम पूरे देश को भुगतने पड़ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में उपस्थित सभी सम्माननीय सदस्यों को भविष्य के खतरे के प्रति आगाह करना चाहती हूँ।

1947 में जब विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र बना। हमारे देश ने उस समय सेकुलर संबिधान को पसंद किया। वह एक शानदार घटना थी और हम अपने सेकुलर संबिधान के प्रति गौरवान्वित हैं, उस पर गर्व करते हैं कि हमारे देश में सभी नागरिक जाति-जाति, मजहब के भेदभाव से ऊपर उठ कर समान रूप से सम्मान पाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके माध्यम से यह निवेदन करना है कि लगातार 40 सालों से अभी तक एक विशेष प्रकार की सोच इस देश में विकसित हुई है और इस देश के कुछ लोगों की जो सोच है, राजनीतिक सोच है, किसी भय या लालच के कारण या अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की इच्छा के कारण इस प्रकार की सोच विकसित हुई है। हो सकता है मेरी बात आज पसंद न की जाए, लेकिन इस देश के बहुसंख्यक समाज के मन में यह भावना आने लगी है कि हम अल्पसंख्यक क्यों न हुए। इसका उदाहरण है जब राम कृष्ण मिशन के लोगों ने यह कहा था कि हमें अल्पसंख्यकों में बुझा दिया जाए, ताकि उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं मिल सकें। इस तरह की सोच के बाद मैं आपके सामने निवेदन करूँगी कि इस तरह की जो सोच है, उससे एक खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जैसे मथुरा में घटना घटी, साम्प्रदायिक दंगा भड़कने की सम्भावना हुई, उससे सदन के सभी माननीय सदस्य चिन्तित हुए और वहाँ पर गए, यह बहुत अच्छी बात है, माननीय सदस्य वहाँ पर सतर्कता के लिए, सजगता के लिए गए, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब कन्कलूड कीजिए।

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कन्कलूड कर रही हूँ। अगर मथुरा की घटना पर चिन्ता जाहिर की जाएगी और पालेज की घटना पर मौन रखा जाएगा, काश्मीर से लाखों की संख्या में जो शरणार्थी दिल्ली में पड़े हुए हैं अगर सरकार उनके प्रति लापरवाही का बर्ताव करेगी और सदन के अन्य माननीय सदस्य भी उनके प्रति इस तरह का बर्ताव करेंगे, हमारी पार्टी के लोग अगर उनके विषय में बोलेंगे तो हमारे ऊपर साम्प्रदायिकता का लेबल लगाया जाएगा तो इसके घातक परिणाम इस देश को भविष्य में भुगतने पड़ेंगे। इसके लिए इतिहास उन लोगों को ज़िम्मेदार मानता है जो इस देश के बहुसंख्यक समाज के अन्दर असुरक्षा की भावना उत्पन्न कर दी है। अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज अपने आपको असुरक्षित अनुभव करने लगा तो यह इस देश के लिए बहुत खतरनाक बात होगी। इसके लिए वे लोग जिम्मेदार होंगे जो पालेज की घटना पर मौन रखते हैं और मथुरा की घटना पर हंगामा करते हैं और काश्मीर के बारे में, वहाँ के शरणार्थियों के बारे में एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं हैं। इस खतरे के लिए मैं ऐसे लोगों को जिम्मेदार मानती हूँ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करती हूँ सभी लोगों से कि इस परम्परा को तोड़ा जाए और स्वस्थ परम्परा को देश में स्थापित किया जाए। अध्यक्ष जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कामिनी चटर्जी (दमदम) : हमारी नियम पुस्तिका में नियम 377 की तरह "न्यून 377" नाम से एक नियम शुरू करने की ज़रूरत है और मेरे विचार से यह नियम लाने से सभा को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकता है।

[हिन्दी]

1.00 घ० प०

श्री रमेश बंस (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मध्य प्रदेश के रायपुर शहर में नकली नोट छापने की जो मशीन पकड़ी गयी है, की ओर दिलाना चाहता हूँ। वहाँ जो मशीन पकड़ी

गयी है उससे भारतीय नोटों के साथ-साथ अमेरिकन डालर और नेपाल के नोट छापने की मशीन भी पकड़ी है। करोड़ों रुपए छापे गए हैं। यह देश की आंतरिक व्यवस्था को बिगाड़ने का षडयन्त्र है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी केन्द्रीय स्तर पर जांच करवायी जाए। इसमें चाहे स्वदेशी गिरोह हो या विदेशी गिरोह हो, अगर उसे पकड़ा जाएगा तो जो लोग हमारे देश की आन्तरिक व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, उससे बचा जा सकेगा।

[अनुवाद]

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : महीदय, जब उप-प्रधानमंत्री एक पत्र लिखते हैं तो यह एक खबर बन जाती है। जब वह एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखते हैं तो यह और बड़ी खबर बन जाती है और जब वह प्रधानमंत्री के निकट कुछ अधिकारियों के व्यवहार पर एक पत्र लिखते हैं तो इसे मुख्य खबर बनना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह मन्त्रियों की आपस की बात है।

श्री एम० जे० अकबर : हम जानते हैं कि हमारे उप-प्रधानमंत्री एक अत्यन्त प्रतिभावना वर लेखक हैं। एक दिन जब उनके पत्रों को एकत्रित किया जाएगा तो भविष्य के इतिहासकारों के लिए उनमें बेहतरीन जानकारी होगी। श्री देवी लाल के एकत्रित पत्र निश्चित रूप से हमारे इतिहास को बनाने में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।

महोदय, उन्होंने हाल ही में दो पत्र लिखे हैं और मैंने आपके सम्मुख इस विशेष पत्र का उल्लेख किया है जिसमें एक विशिष्ट व्यक्ति को मनोनीत करने के बारे में कहा गया है, मैं इसका उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि इस बारे में विस्तृत जानकारी प्रकाशित हो चुकी है और सबको पता है। लेकिन मैं तो आपका ध्यान इस दूसरे पत्र की ओर आकषित करना चाहता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि यह अत्यधिक चिंता का सामना है क्योंकि न तो विपक्ष के नेता ने और न ही सरकार के सहयोगी दल के नेता या सदस्य ने यह कहा है बल्कि इस देश के उप-प्रधानमंत्री ने अपने ही प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में यह आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री का नजदीकी एक अधिकारी उनकी शक्तियों को हड़प रहा है और कार्य करने के किसी भी सांकेतिक तरीके के विरुद्ध देश को चला रहा है। अगर वास्तव में ऐसा हो रहा है, जैसा कि उप-प्रधानमंत्री के पत्र में कहा गया है तो यह अत्यन्त चिंता का मामला है क्योंकि भारत का शासन इसमें सम्मिलित है और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप प्रधानमंत्री को यहाँ आने के लिए कहें और वह बताएं कि यह अधिकारी कौन है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री एम० जे० अकबर : मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप प्रधानमंत्री को यहाँ पर आने के लिए कहें और वह हमें बताएं कि यह अधिकारी कौन है जिसके बारे में उप-प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री से शिकायत की है।

[हिन्दी]

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जिस घटना को उठा रहा हूँ यह फरीदाकोट में नबीदय विद्यालय के बारे में है। फरीदाकोट में नबीदय विद्यालय में लगातार पिछले नौ महीने से नबी कक्षा के तीन आदिवासी छात्रों में उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली। पहली घटना

गत अगस्त में हुई, दूसरी अक्टूबर में और तीसरी घटना एक अप्रैल को हुई और उस बच्चे ने पत्र छोड़कर आत्म-हत्या कर ली। वह मनोहर लाल नाम का लड़का था जो कि न केवल पढ़ाई में अत्यन्त रहा, बल्कि उसने खेल में भी कई पुरस्कार प्राप्त किए। वह अपने भाई के साथ जो कि छोटी कक्षा में पढ़ता है रात भर अपने कमरे में रोता रहा, इसलिए रोता रहा कि खेल के मैदान में उसकी अध्यापक ने एक लड़के द्वारा शिकायत करने पर कि यह मेरा असली घी चुराकर खा गया उसकी पिटाई कर दी। उसका नन्हा भाई तो सो गया, लेकिन वह रात भर रोता रहा और बाद में अपनी किताब में एक चिट्ठी लिखकर छोड़ गया कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे काफी उत्पीड़ित किया गया है इसलिए मैं पास के बेंच में अपने जीवन को समाप्त करता हूँ। ऐसे ही पहले भी एक अमरजीत सिंह और दूसरे लड़के ने आत्म-हत्या की थी मैं भी आत्म-हत्या कर रहा हूँ। यह उसने चिट्ठी में लिखा है। ये तीन घटनाएँ हुईं इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये तीनों आदिवासी बच्चे ये और नौवीं कक्षा के विद्यार्थी ये और एक ही अध्यापक के द्वारा उत्पीड़ित होकर इन्होंने आत्म-हत्या की, इसकी जाँच की जाए और जिसके कारण इन्होंने आत्म-हत्या की उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

श्री शोपत सिंह भस्कासर (बीकानेर) : सरकार को इसके बारे में बयान देना चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में किसी हरिजन की हत्या हुई है तो उसका मापदण्ड दूसरा होता है और किसी नवोदय विद्यालय में बच्चों के द्वारा उत्पीड़न से आत्म-हत्या की जाती है तो उसके लिए दूसरा मापदण्ड अपनाते हैं और इस पर चुप रहें, यह नहीं हो सकता। यह बहुत गम्भीर विषय है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, पासबान जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्वश और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासबान) : इस सम्बन्ध में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन जो माननीय सदस्य कह रहे हैं यह बात सही है तो यह एक वास्तव में गम्भीर मामला है और निम्नलिखित रूप से हम रिपोर्ट अंगार्योमें और इस पर कार्रवाई करेंगे।

[अनुवाद]

श्री संकट्ठीय चौधरी (कटवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत गम्भीर मुद्दा उठा रहा हूँ और शायद इस मुद्दे को सदन में कुछ समय पहले भी उठाया गया था। लेकिन, सरकार द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अतः मजबूरन मैं इसे फिर से उठा रहा हूँ।

महोदय, जुलाई-अक्टूबर, 1988 के दौरान, मैसर्स ओसलक फार्मा लिमिटेड ने दूधित ग्लूकोस की तीस हजार बोतलें दिल्ली के उत्तर क्षेत्र में स्थित अपने वितरक को भेजी थीं (ब्यवस्थापक)

एक माननीय सदस्य : महोदय, यह बोटल है।

अध्यक्ष महोदय : बोटल मत दिखाइए।

श्री संकट्ठीय चौधरी : जब यह पता चला कि ये बोटलें दूधित थीं तो इस व्यक्ति ने इन बोटलों का वितरण रोक दिया था और औषधि नियन्त्रक को शिकायत दायर की। उसके बाद भारत के औषधि नियन्त्रक ने हेराल-फेरी स्टोर के दूधित बोटलों के स्वाम पर अच्छी बोटलें भेज दीं और जाली रिपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश की जिससे इस कंपनी को निर्दोष ठहराया जा सके। लेकिन, उसके बाद यह मामला इतना अधिक बढ़ गया कि सी० बी० आई० को इस मामले को अपने हाथ में लेना पड़ा और

जांच शुरू की गई। अब इन बोलियों को कलकत्ता भेजा गया है और प्राधिकृत प्रयोगशाला में इनकी जांच की गई तथा पाया गया कि यह दूधित घी और इसमें मिलावट की गई थी। अब क्योंकि जिनका इस कम्पनी से सम्बन्ध है वे दोषी व्यक्तियों को दण्ड नहीं दिलवाना चाहते, वे इस मामले को यह कह कर टाल रहे हैं कि सी० बी० आई० जांच कर रही है और उस व्यक्ति को, जिसने शिकायत दर्ज करवाई थी, उत्पीड़ित किया जा रहा है। इस देश में क्या ऐसे व्यक्ति शक्तिशाली हैं या सरकार शक्तिशाली है? भारत के औषधि नियन्त्रक तमिलनाडू और दिल्ली के औषधि नियन्त्रकों को निलम्बित क्यों नहीं किया गया है? (व्यवधान) मैं सरकार से कल तक एक स्पष्ट विवरण चाहता हूँ। यह बड़ी शर्म की बात है कि साहसी व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने के लिए सांसदों के घरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मन्त्री महोदय यहां कल आकर अपना बयान क्यों नहीं देते। कृपया मन्त्री महोदय से कहिए। (व्यवधान)

प्रो० संकुहीन सोज (बारामूला) : मैंने इस मुद्दे को पहले भी उठाया था। यह एक गम्भीर मामला है। मैंने एक नोटिस भी दिया था (व्यवधान)। औषधि नियन्त्रक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक गम्भीर मामला है।

[हिन्दी]

श्री भूहेरबर सिंह (मंडी) : अध्यक्ष महोदय, पर्यटन की दृष्टि से कुल्लू-मनाली का महत्वपूर्ण स्थान है। खेद का विषय है कि आज भी कुल्लू-मनाली में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध नहीं है। गत वर्ष वहां के महत्व को देखते हुए सरकार ने एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने और मनाली में इलैक्ट्रॉनिक्स एक्सचेंज उपलब्ध कराने के लिए साजो-सामान उपलब्ध कराया था लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण सारे का सारा सामान वापस मंगवाया गया। इसलिए शंका है कि इस वर्ष भी जो सामान उपलब्ध कराया गया है, कहीं विभाग ने समय पर उसका इस्तेमाल नहीं किया तो वह भी वापस हो जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से संचार मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि वह निर्देश प्रदान करे कि विभाग समयबद्ध कार्यक्रमानुसार वहां एस० टी० डी० की सुविधा उपलब्ध कराये।

श्री रतिलाल कालीदास बर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, अहमदाबाद शहर के पास पिछले एक साल के अन्दर कांग्रेस के समय में गैर-कानूनी रूप से ड्राईंग, प्रिटिंग और कैमिकल्स के कारखाने निर्मित किये गये हैं। इनमें काम करने के बाद जो कैमिकल्स बाहर जाता है, वह पानी में मिले होने के कारण पशु आदि उस पानी को पीते हैं और वे मर रहे हैं। जिन गाय-भैंसों की आयु 20 वर्ष की होती है, वह दस साल की रह जाती है और किसानों के बैल इत्यादि भी मरने लगे हैं और इस तरह से कम से कम 100-200 पशु मर गये हैं। जब उन कारखानों पर कार्यवाही होने लगी तो उन्होंने प्राईवेट तौर से ड्रिलिंग करके बाहर डालना शुरू किया और वे बाहर और गांवों में पहुंचने लगा। यह कैमिकल्स युक्त पानी भी पीने के पानी में मिलने लगा और मनुष्य उस पानी को पीने लगा। जब वह पानी क्यूे में जाने लगा और मनुष्य पानी पीने लगा तो वे भी मर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मानव जाति और पशु जाति के साथ जो बड़ा अन्याय हो रहा है, उसको रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ और यह अनुरोध करता हूँ कि पर्यावरण मंत्री गुजरात सरकार को आदेश दें कि ये कारखाने बंद किये जायें।

श्री राम प्रसाद सिंह (बिक्रमगंज) : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बिहार

राज्य के रोहतास जिले में हो रही अपराधिक घटनाओं की ओर खींचना चाहता हूँ। आचकल रोहतास जिले में अपराधी तत्त्व संगठित रूप से सक्रिय हो रहे हैं और वहाँ अपराध की इतनी घटनायें घट रही हैं कि लोगों को अपने घर से निकलना भी दूभर हो गया है। माम्यवर, मुझे अब तक की जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार पिछले दो माह में दस हत्यायें, 24 अपहरण, 7 आगजनी, और आठ डकैतियाँ हुई हैं। मुझे डर लगता है कि यदि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो कहीं यह जिला पंजाब का कश्मीर न बन जाये। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बिहम्बना तो यह है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ रही है और निर्दोष लोगों को झूठे केस में फँसाकर उनसे रुपये-बसूस किये जाते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि बिहार सरकार से अनुरोध किया जाये कि वह पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को चुस्त करे। इस संबंध में एक समिति बनायी जाये और इसकी जांच कराई जाये, साथ ही वहाँ के लोगों की जान-माल की सुरक्षा की जा सके ताकि जल्दमें विश्वास पैदा हो सके कि वे अपने घर में शान्तिपूर्वक रह सकें।

श्री मदन लाल खुराना (वर्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मेरे सामने यह 31 मई, 1940 का "इण्डिया टुडे" मैगजीन है, जिसमें एक बड़ा सनसनीखेज लेख तथ्यों के साथ प्रकाशित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आप वह कहिये, जो कहना है।

श्री मदन लाल खुराना : उसमें इस सदन के एक भूतपूर्व सदस्य के बारे में बनेक तथ्य दिये गये हैं। वे इस देश के एक बहुत बड़े फिल्म स्टार भी हैं। उन्होंने किस तरीके से इन्कम टैक्स बचाने के लिए काम किया, उसके कुछ एम्पल में आपकी जानकारी में लाया जाहता हूँ। इन उद्योग के एक भाई स्विटजरलैंड में रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप किमी का नाम यहां नहीं ले सकते।

श्री मदन लाल खुराना : मैंने नाम लिया ही नहीं है सर। जबकी एक साब स्विस् फ्रैंक मालिक अम्य बतानी गयी है और उनके बच्चों पर आने वाला खर्च 85 हजार फ्रैंक एनूअरी दिखाया गया है। इस तरह ढाई करोड़ खर्चा करके उन्होंने दो कंपनियों के शेयर खरीदे हैं। इन फिल्म स्टार महोदय के सम्बन्ध में इंटरैस्टिंग बात यह है कि इन्होंने देश में एक साल में 6-6 फिल्मों की हैं, परन्तु अपनी आय मात्र 4 लाख रुपये या 5 लाख रुपये ही दर्शायी है... (शयवधान) ... यह कहा गया है कि वे एक फिल्म से 50 हजार रुपया लेते हैं, जो उन्होंने दिखाया है, जब कि सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने किसी भी फिल्म के लिए एक करोड़ रुपये से कम राशि प्राप्त नहीं की। इसके अलावा इन्कम टैक्स बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, वह भी इंटरैस्टिंग है। वे सात देशों में गए, जिसमें स्विटजरलैंड और आस्ट्रेलिया भी शामिल हैं, वहाँ उन्होंने अपनी नाइटस की और इन्कम टैक्स रिटर्न में केबल एक शहर से हुई आमदनी की ही दर्शाया गया है, अन्य 6 देशों की आमदनी का कहीं कुछ पता नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन भूतपूर्व सदस्य और फिल्म स्टार के खिलाफ मैगजीन में जितने गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, उन सबकी मी० वी० आई० से जांच करायी जानी चाहिए, जांच रिपोर्ट को इस सदन में लाया जाये और उस पर बहस हो, मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ।

श्री कवरईन यादव (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में, पटना उच्च न्यायालय ने कुछ समय पहले एक बिशेष सचिबि बनायी थी जिसे बिहार स्थित बाल और महिला गृहों की हानत की जांच

करने का कार्य सौंपा गया था। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि उस कमेटी की जो रिपोर्ट आयी है, उसमें कहा गया है कि भागलपुर, गया, देवघर, कटिहार, पूर्णिया, मुंगेर, छपरा, मुजफ्फरपुर आदि जगहों पर जितने बाल और महिला गृह हैं, उनके कर्मचारी बालकों और महिलाओं के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं, कि सुधार गृहों में जितने बच्चे, महिलाएँ और सड़कियाँ रहती हैं वे सब मानसिक तौर से पागल हो चुकी हैं, खाने के अभाव में उनकी शरीर की हड्डियाँ दिखलायी पड़ती हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय कल्याण मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जब वे अपने मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांगों पर हुई बहस का उत्तर दें तो बिहार स्थित बाल एवं महिला सुधार गृहों की स्थिति पर विशेष प्रकाश डालें और उसमें सुधार लाए जाने के लिए की जाने वाली कार्यवाही को सदन के सामने रखें।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, पंजाब में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसने नया मोड़ ले लिया है। कल सदन में यह बताया गया था कि पुलिस की बर्दी में उन लोगों ने श्री टोहरा को गोली मार दी। कुछ दिन पहले यह खबर आयी थी कि आतंकवादी गांव में घुस गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुद्दे पर आइए।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। वे वहाँ गए और उन्होंने लोगों को बाहर बुलाया। वे उन्हें गोली मारना चाहते थे और कल बटाला पुलिस स्टेशन के बारे में बहुत-सी चर्चाएँ की गयी थीं एक समुदाय के लोगों को—मैं एक समुदाय के लोगों की बात कर रहा हूँ, को बाहर बुलाकर पुलिस की बर्दी में आतंकवादियों द्वारा गोली मार दी गई। अतः वास्तव में वे इसको साम्प्रदायिक रंग देना चाहते थे। मेरे विचार से पुलिस की बर्दी में आने का यह उनका नया तरीका है। अतः अगर वे सफल हो जाते हैं तो पंजाब की स्थिति और खराब हो जाएगी। मेरे विचार से पंजाब प्रशासन इस सम्बन्ध में इतना गम्भीर नहीं है। अतः इसे साम्प्रदायिक रंग देने से पहले सरकार को आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। कश्मीर में, जैसाकि आप जानते हैं, कड़ी कार्रवाई द्वारा स्थिति पर नियन्त्रण किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, कल यह मुद्दा उठाया गया था।

श्री लोकनाथ चौधरी : नहीं नहीं, यह भी प्रासंगिक मुद्दा है।

कल बटाला पुलिस स्टेशन के अधीन एक गांव में एक विशेष समुदाय के सात लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस तरह वे लोगों को मार रहे हैं और वे इसे साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। देश के लिए यह बहुत खतरनाक बात है। मैं इसे सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि सरकार को इस नई घटना पर विचार करना चाहिए और पंजाब सरकार से उपाय करने के लिए कहना चाहिए जिससे कि स्थिति और खराब न हो और इसे साम्प्रदायिक रंग न दिया जाए।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार महोत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न अभी उठाया गया है, मैं इसी को उठाना चाहता हूँ। कल पंजाब के अन्दर बटाला पुलिस स्टेशन एरिया में एक ही हरिजन परिवार के सात लोगों की बुलाकर रस्सी से बांधकर, खड़ा करके गोली से उड़ा दिया गया।

अध्यक्ष जी, पंजाब में एक नई बात यह हो रही है कि पंजाब पुलिस, सी० आर० पी० एफ० की गस्त रात 7 बजे के बाद बन्द कर दी गई है। जब पुलिस वहाँ जाएगी नहीं, सी० आर० पी० एफ० जाएगी नहीं, बी० एस० एफ० जाएगी नहीं और वहाँ के क्षेत्रों को खुले आम छोड़ दिया गया है, कोई भी आतंकवादी कहीं भी जाकर किसी-को मार डाले, सात बजे के बाद, पुलिस की बरबी पहन कर के। आतंकवादी पुलिस की बरबी पहनकर वहाँ गए और उन्होंने एक कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा करके, रस्सी से बांधकर गोली से उड़ा दिया और आराम से चले गए। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सी० आर० पी० एफ०, बी० एस० एफ० और पंजाब पुलिस की गस्त फौरी तौर पर चालू करनी चाहिए। अब तो यह हालत है कि सात बजे के बाद किसी को पंजाब में कोई डर नहीं है। चाहे कहीं भी कोई भी आतंकवादी किसी की भी हत्या कर दे। मैं सरकार से इस बटाला की हत्या की घटनाओं के बारे में कहना चाहता हूँ कि यह हरिजनों की हत्याओं का गम्भीर मामला है, इसलिए इस तरफ सरकार विशेष ध्यान दे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जटिया।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा न कहिए ! अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस समय मध्य प्रदेश में पीने के पानी का घोर संकट है जिसके कारण केन्द्र सरकार ने मदद की घोषणा की है, किन्तु वह मदद अभी तक नहीं पहुँची है। जब तक केन्द्रीय सरकार की मदद पहुँचेगी तब तक तो वहाँ पर बहुत भयंकर स्थिति हो जाएगी। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार की सहायता शीघ्र पहुँचनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जटिया जी, हो गया। बैठ जाए।

[अनुवाद]

अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे—श्री राम विलास पासवान।

श्री मनोरंजन भक्त : यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के बारे में बात नहीं सुनते।

अध्यक्ष महोदय : यह दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि हर रोज मैं आपको अनुमति देता हूँ। मैंने आपको अण्डमान और निकोबार के बारे में मामले उठाने की अनुमति दी थी। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

1.22 न० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

केन्द्रीय वक्फ परिषद का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और कार्यक्रम की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला एक विवरण

[हिन्दी]

अन और कल्याण भंडारी (श्री राम बिलास पासवान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

- (1) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(दो) केन्द्रीय वक्फ परिषद के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
(तीन) केन्द्रीय वक्फ परिषद के वर्ष 1988-89 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[संचालक में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 832/90]

- (3) (एक) केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(दो) केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
(तीन) केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1988-89 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[संचालक में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 833/90]

आचार्यक सभा अधिनियम, 1981 के अंतर्गत अधिसूचना

[अनुवाद]

केटोलिबन और रसायन मंत्रालय में राधिका भंडारी (श्री भजनन बेहेरा) : महोदय, श्री एम० एत०

मुख्यदस्तावेजी की ओर से, मैं आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 की धारा 2 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सांका० 370(अ), जो 7 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्राकृतिक गैस का उत्पादन सप्लाई या वितरण करने वाली किसी स्थापना या उपक्रम की किसी सेवा को एक आवश्यक सेवा घोषित किया गया है, को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[प्रचालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 834/90]

नेशनल इंस्टिट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का
वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यक्रम की समीक्षा

साहूरी विकास मंत्री (श्री मुरासोमी मारन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ—

- (1) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[प्रचालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 835/90]

औषधि और प्रसाधन सामग्री तीसरा संशोधन नियम, 1989, खाद्य अपमिश्रण
'निवारण अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ आदि

खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन शर्मा) : महोदय, श्री रशीद की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ—

- (1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री तीसरा संशोधन नियम, 1989, जो 28 अगस्त, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका० नि० 784(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[प्रचालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 836/90]

- (2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 1988, जो 8 अप्रैल, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका० नि० 437(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धि-पत्र, जो 17 नवम्बर, 1988 की अधिसूचना संख्या सांका० नि० 1081(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[प्रचालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 837/90]

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (पांचवां संशोधन) नियम, 1988, जो 16 मई, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 618(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धि-पत्र, जो 12 अगस्त, 1988 की अधिसूचना संख्या सांकांनि० 855(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[प्रचालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 838/90]

(3) उपर्युक्त (2) के (एक) तथा (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[प्रचालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 837-838/90]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) इण्डियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[प्रचालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 839/90]

(ख) (एक) हास्पिटल सर्विसेज कन्सलटेन्सी कारपोरेशन (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हास्पिटल सर्विसेज कन्सलटेन्सी कारपोरेशन (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[प्रचालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 840/90]

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[प्रचालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 839-840/90]

(6) (एक) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 19 के अन्तर्गत स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 18 के अन्तर्गत स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, षष्ठीगढ़ के वर्ष 1988-89 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशानि वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 841/90]
- (8) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशानि वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 842/90]
- (10) (एक) नेशनल अकेडेमी आफ मेडिकल साइंसिज (इण्डिया) के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल अकेडेमी आफ मेडिकल साइंसिज (इण्डिया) के वर्ष 1988-89 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशानि वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 843/90]

1.23 म० प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है:—

(एक) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निवेदन हुआ है कि राज्य सभा द्वारा बुधवार, 2 मई, 1990 को हुई अपनी बैठक में लोक सेवा समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया गया :—

“कि यह सभा लोक सभा की लोक सेवा समिति के 30 अप्रैल, 1991 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए, उक्त समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत है और वह सभापति द्वारा विहित रीति से इस सभा के सात सदस्यों का उक्त समिति में कार्य करने हेतु चयन करती है।”

2. इसके अतिरिक्त, मुझे लोक सभा को यह सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्न सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित किया गया है :—

- (1) श्री रामेश्वर ठाकुर
- (2) श्री एच० हनुमन्तप्पा
- (3) श्री विश्वजीत पी० सिंह
- (4) श्री कमल मोरारका
- (5) श्री टी० आर० बालू
- (6) डा० नगेन सैकिया
- (7) श्री सुनील बसु राय

(दो) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने बुधवार, 2 मई, 1990 को अपनी बैठक में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :

“कि यह सभा लोक सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 30 अप्रैल, 1991 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए, उक्त समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत है और वह सभापति द्वारा विहित रीति से इस सभा के सात सदस्यों का उक्त समिति में कार्य करने हेतु चयन करती है।”

2. इसके अतिरिक्त, मुझे लोक सभा को यह सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्न सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित किया गया है :—

- (1) श्री अजीत पी० के० जोगी
- (2) श्री सैयद सिद्दिके रजी
- (3) प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर
- (4) श्री बीरेन्द्र वर्मा
- (5) श्री दीपेन घोष

(6) डा० जी० विजय मोहन रेड्डी

(7) श्री प्रमोद महाजन

(तीन) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 2 मई, 1990 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :—

“कि सदन संकल्प करता है कि राज्य सभा दोनों सदनों की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के 30 अप्रैल, 1991 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए शामिल होती है और एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया के अनुसार इस सभा के सदस्यों में से 10 सदस्यों का उक्त समिति में नियुक्त करने हेतु चयन करती है।”

2. इसके अतिरिक्त मुझे लोक सभा को सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्न सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित किया गया है :—

(1) श्री एम० के० टी० रामचन्द्रन

(2) श्री खयोमो लोथा

(3) श्री राजूभाई ए० परमार

(4) श्रीमती कैलाशपति

(5) कुमारी मुणीला तिरिया

(6) श्री एम० विनसेंट

(7) श्री राज मोहन गांधी

(8) श्री रंजन प्रमाद यादव

(9) श्री संघ प्रिय गौनम

(10) श्री एन० ई० बलराम

1.24 $\frac{1}{4}$ म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

श्री शिवाजी पटनायक (भूवनेश्वर) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

1.24 १/२ म० प०

अबिलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

आस्ट्रेलिया द्वारा पाकिस्तान को 50 मिराज-111 विमान बेचे जाने के सम्बन्ध में करार

श्री सुधीर निरि (कन्ट्रई) : महोदय, मैं विदेश मन्त्री महोदय का ध्यान अबिलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में बक्षतव्य हैं :

“आस्ट्रेलिया द्वारा पाकिस्तान को 50 मिराज-111 विमान बेचे जाने के सम्बन्ध में किए गए करार से उत्पन्न स्थिति।”

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : 15 अप्रैल, 1990 को आस्ट्रेलिया की सरकार ने 3 करोड़ 60 लाख आस्ट्रेलियाई डालर (2 करोड़ 70 लाख अमरीकी डालर के बराबर) के मूल्य की एक संविदा पर पाकिस्तान को 50 मिराज-111 विमान की बिक्री के लिए हस्ताक्षर किए। यह सूचना आस्ट्रेलिया में हमारे हाई कमिश्नर को काफी बाद में 24-4-1990 को दी गई। उसी दिन आस्ट्रेलियाई रक्षा मन्त्री सेनेटर राबर्ट रे ने इस बिक्री की घोषणा की। आस्ट्रेलिया में निर्मित मिराज आस्ट्रेलियाई सरकार विमान फैक्ट्री द्वारा जारी किए गए लाइसेंस के अन्तर्गत बनाए जाते हैं। “कामनवैलथ कारपोरेशन” भी लाइसेंस के अन्तर्गत मिराज के इंजन बनाता है।

1.26 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

भारत सरकार ने मिराज-111 पाकिस्तान को बेचने के बारे में अपनी गम्भीर चिन्ता से नई दिल्ली में तथा कैनबरा में आस्ट्रेलियाई प्राधिकारियों को अवगत करा दिया है। आस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर को यह बताया गया कि यह एक अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक निर्णय है—खासतौर पर इस उप-महाद्वीप में मौजूदा तनाव की स्थिति को देखते हुए। इसका उद्देश्य पाकिस्तान को संयम का संदेश भेजना नहीं हो सकता और न ही इससे स्थिति में स्थायित्व लाने में सहयोग मिलेगा जोकि इस क्षेत्र में आस्ट्रेलियाई नीति का उद्देश्य बताया जाता है। यह भी कहा गया कि भारत और आस्ट्रेलिया के बीच के परम्परागत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के सन्दर्भ में यह निर्णय विशेषरूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान को मिराज-111 विमान देने का आस्ट्रेलिया का निर्णय, खासतौर पर ऐसे वक्त में शांति और स्थायित्व के हित को अनदेखा करते हुए भारत के और आस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय सम्बन्धों के सन्दर्भ में एक प्रतिगामी घटना है।

26-4-1990 को आस्ट्रेलिया के कार्यकारी विदेश मन्त्री श्री नील ब्ल्यूवैट ने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा कि “भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में अगर कोई और बिगाड़ आता है तो हम इस प्रबन्ध पर पुनर्विचार करेंगे।” श्री ब्ल्यूवैट ने कहा कि “ये विमान संचालन के स्तर पर पाकिस्तान को कम से कम छह महीने तक या हो सकता है, नौ महीने तक उपलब्ध न हो पाएँ।”

3-5-1990 को हमारे विदेश सचिव ने आस्ट्रेलिया के एक बरिष्ठ अधिकारी श्री कार्टेलो के समक्ष भारत की गम्भीर चिन्ता और खेद को दोहराया।

मैंने 11-5-1990 को आस्ट्रेलिया के बौद्धिक कार्य एवं व्यापार मन्त्री सेनेटर ग्रेग ईवांस को एक पत्र लिखकर इस विषय में अपनी गम्भीर आपत्ति व्यक्त की तथा इस बिक्री पर पुनर्बिचार के लिए अनुरोध किया।

श्री सुधीर गिरि : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के उत्तर में, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज के विश्व में युद्ध से नहीं बल्कि आपसी बातचीत द्वारा प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्रों के बीच उठने वाले विवादों और समस्याओं को हल किया जा सकता है। कुछ राष्ट्रों के पास बहुत खतरनाक हथियारों का होना ही इस बात को दर्शाता है। लेकिन हमारा देश गुट-निरपेक्ष देश है और हम इस सिद्धान्त में विश्वास करते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस सिद्धान्त को नहीं मानता। इसलिए वह बहुत खतरनाक हथियारों को इकट्ठा कर रहा है। उसने 15 अप्रैल को आस्ट्रेलिया सरकार से 50 मिराज III फाइटर जेट एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए एक समझौता किया। पाकिस्तान 1983 में अमरीका से एक गेयरिंग डेस्ट्रॉयर पहले ही प्राप्त कर चुका है। 1984 में उसने ब्रिटेन से 3 टाइप 21 फ्रीगेट, चीन से 100 कुआंग 5 एफ० जी० ए०-ए० सी०, अमरीका से 16 आर० जी० एम० 84, हारपून, चीन से 4 हुआंग फेन एफ० ए० सी०-जी० और अमरीका से 100 एम० 45 ए० 5 टैंक प्राप्त किए थे। 1985 में, उसने अमरीका से 500 ए० आई० एम-92 साइड बिन्टर ए० ए० एन० प्राप्त किए। यू० एस० ए० से 100 सिगर एस० ए० एम०। यू० एस० ए० से एम० आई 09 ए2 155 एम० एम० एस० पी० अमरीका से 110 एम 113 एन० ए० डी० सी० एच० ओ० चीन से 110 ए० एफ० फान्टन स्ट्राइक ए० सी०। 1986 में स्वीडन से आर० डी० 5 70 एस० ए० एम० जिराफ ए० डी० राडार।

यू० एस० ए० से 2030 बी० जी० एम० 71 सी। 1987 में यू० के० से 3 टाइप 23ए एफ० जी० एफ० आर० एम० शायद यह कुल प्राप्त किए गए हथियारों का अंशमात्र है, पिछले छः महीनों के दौरान पाकिस्तान ने काफी मात्रा में यू० एस० ए० से धीएटर क्रूज मिसाइल, 20 एम 113 ए2 आर्ममोडर्न पर्सनल कैरियर किट, 44 हारपून मिसाइलें, एफ 16 फाइटर जेट प्राप्त किए हैं। उसने चीन से भी 40 एफ 7 पी फाइटर जेट प्राप्त किए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जानकारी दे रहे हैं। नियमों के अनुसार, यदि वक्तव्य में कुछ अस्पष्ट होता है, तो आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। लेकिन, आप तो सदन की जानकारी दे रहे हैं।

श्री सुधीर गिरि : मैं सभी प्रासंगिक मुद्दे उठा रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : होता यह है कि इस तरह से एक जुरी परम्परा पड़ जाती है और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने का समय नहीं रहता। यह सदस्यों के हित में होगा कि वह केवल मतभंग की ही बात करें।

श्री सुधीर गिरि : इन खतरनाक हथियारों के अतिरिक्त, पाकिस्तान ने एटम बम की जानकारी और मूल संघटक प्राप्त कर लिए हैं। यह न केवल हमारे लिए चिन्ता की बात है बल्कि पड़ोसी राष्ट्रों के लिए गम्भीर विषय है। आज, पाकिस्तान इस स्थिति में पहुँच गया है कि वह दूसरे देशों को हथियारों का निर्यात करने लगा है। ऐसे देशों की संख्या लगभग 30 है। मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि पाकिस्तान के पास भारत से अधिक सैन्य शक्ति है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। आपको सदन में अन्य मामलों को इस चर्चा में शामिल नहीं करना चाहिए।

श्री सुधीर गिरि : पाकिस्तान की सैन्य शक्ति का ठीक तरह से अनुमान लगाना बहुत कठिन है क्योंकि वे देश अपने रक्षा बजट को विस्तार से प्रकाशित नहीं करते। यद्यपि लन्दन की पत्रिका से यह पता चला है कि हमारी और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति का अनुपात 21 : 17 है। किन्तु हमें यह बात ज्ञान में रखनी चाहिए कि कितना ही छोटा देश क्यों न हो, यदि उसके पास सैन्य शक्ति है तो यह मान्य कर सकता है। इसी तरह इजरायल भी एक छोटा-सा देश है लेकिन उसने अरब देशों से लड़ाई लड़ ली है।

पाकिस्तान ने कई बार धमकियाँ दी हैं जबकि भारत आत्मनिर्भरता की नीति को अपना रहा है, पाकिस्तान तुरन्त सैन्य शक्ति का पक्षधर है। यह माना जाता है कि पाकिस्तान के कुल हथियारों का 80 प्रतिशत हिस्सा आयातित है और 20 प्रतिशत स्वदेशी है। मुख्यतः यू० एस० ए०, स्वीडन, फ्रांस, चीन, यू० के० और अस्ट्रेलिया आदि देश पाकिस्तान को हथियार निर्यात करते हैं। हम यू० एस० ए० द्वारा पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के उद्देश्य को समझते हैं क्योंकि यू० एस० ए० की इस क्षेत्र में काफ़ी रुचि है। अफगानिस्तान से सोवियत सेनाएं हटाए जाने से भी हमें आशा हुई थी कि अमरीकी लोगों का इस क्षेत्र से दबाव कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण स्पष्ट है। यू० एस० ए० द्वारा गतिविधियों को तेज करने और सन्ट्रल कमान्ड के समन्वय के लिए कराची एक केन्द्र बन गया है। यू० एस० ए०, मूसवान कच्चे माल की पूर्ति के लिए हिन्द महासागर पर निर्भर है जो उसके रक्षा उद्योग के लिए जरूरी है। इसके अतिरिक्त, अमरीका द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुल तेल का 25 प्रतिशत इस क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में अमरीकी लोगों की बहुत रुचि है। इसके अतिरिक्त वे मुस्लिम देशों का एक अलग से गुट बना रहे हैं जिसमें टर्की और पाकिस्तान आदि देश हैं। साम्राज्यवादी और विधेयतया यू० एस० ए०, पाकिस्तान को सयुक्त भारत में बाधाएं उत्पन्न करने के लिए भड़काना चाहता है। इसलिए, वे हमारे क्षेत्र में कुछ साम्प्रदायिक समस्याएं और बिघटनकारी गतिविधियाँ उत्पन्न कर रहे हैं। इसके विरोध में, केन्द्र सरकार को पाकिस्तान से प्रतिरक्षा के लिए आनुपातिक कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सेना ने 'जवं-ए-मोमिन' नामक युद्ध अभ्यास किया था।

(व्यवधान)

उपस्थित महोदय : श्री गिरि, पाकिस्तान द्वारा विधान प्राप्त करने से यह स्थिति पैदा हो गई है।

श्री सुधीर गिरि : मैं यह कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी सेना मजबूत कर ली है। हमारे देश की क्या स्थिति है ?

उपस्थित महोदय : मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं। परन्तु उस समय नहीं जब आप इस तरह के मामले पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री सुधीर गिरि : मैं उसी का उल्लेख कर रहा हूँ। मैं अभी पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ।

उपस्थित महोदय : वास्तव में आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है आपको इसे मजबूत करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने सम्बन्धी प्रश्न करना है। अन्यथा यह गलत परम्परा बन जाएगी।

श्री सुधीर गिरि : कश्मीर, पंजाब और देश में साम्प्रदायिक हिंसा की पृष्ठभूमि में हम मन्त्री

महोदय की इस बात से सहमत है कि जब भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान द्वारा अल्पकालियों को सहायता और सक्रिय समर्थन के कारण शान्ति और स्थिरता खतरों में है तो पाकिस्तान को यह विमानों की बिक्री निश्चित रूप से एक नकारात्मक स्थिति है। मन्त्री महोदय ने यह बतलव्य दिया है। मुख्य बातें कौन सी हैं जिनसे ऐसी नकारात्मक स्थिति पैदा हुई है? मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सी बातें हैं? अन्यथा विपक्ष इसे निश्चित रूप से सरकार की कमजोरी समझेगा। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह साम्राज्यवाद के खेल का एक अंग है। साम्राज्यवाद बहुत दिनों से देश को विभाजित करने का प्रयास कर रहा है। ब्रह्मपुत्र ऑपरेशन ऐसी ही शरारतपूर्ण योजना है। आस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा है कि यदि भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध बिगड़ते हैं तो वे स्थिति पर पुनः विचार करेंगे। आस्ट्रेलिया सरकार के बतलव्य से यह प्रतीत होता है कि उन्हें पाकिस्तान और भारत के बीच सम्बन्ध बिगड़ने की जानकारी नहीं है। मैं सामान्यतः मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सच है अथवा नहीं? क्या सरकार ने इन 50 विमानों की बिक्री के लिए समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले आस्ट्रेलिया सरकार के साथ सम्पर्क किया है? यदि ऐसा है तो यह सरकार की ओर से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन फिर भी मेरा सरकार से अनुरोध है कि आस्ट्रेलिया सरकार के साथ इस मामले की सम्बन्ध में आगे कार्यवाही की जाए ताकि आस्ट्रेलिया सरकार द्वारा किए गए समझौते को रद्द किया जा सके।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि केवल आस्ट्रेलिया सरकार के साथ ही नहीं बल्कि विश्व की सभी सरकारों के साथ कूटनीति सम्पर्क करके उनके स्थिति के बारे में, जो पाकिस्तान ने भारतीय उपमहाद्वीप में पैदा कर दी है, विचार-विमर्श किया जाए।

हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि पाकिस्तान की प्रधानमन्त्री मुस्लिम राष्ट्रों को भारत के विरुद्ध करने में सफल न हो सके। इस उद्देश्य के लिए कूटनीतिक सम्बन्धों को मजबूत बनाया जाए ताकि दूसरे देश हमें गलत न समझें और भारतीय उपमहाद्वीप में शान्ति तथा स्थिरता की बहाली में हमारी सहायता कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय : शायद श्री हरीश रावत यहाँ उपस्थित नहीं हैं। मन्त्री महोदय जबकि वे सकत हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : माननीय सदस्य की बातों पर भली-भांति ढंग से ध्यान दिया गया है। समस्या के गहन अध्ययन के बारे में मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और उम्र बात के लिए भी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के मद्देन में हमारी रक्षा सम्बन्धी अड़चनों को समझने के लिए वास्तव में कठिन परिश्रम किया है।

मैंने अपने बतलव्य में इन 50 विमानों का बिक्रय दिया है। ये वे विमान थे जिन्हें आस्ट्रेलिया ने 1964 में प्रयोग किया था। धीरे-धीरे उनका प्रयोग बन्द कर दिया गया। 1988 में उन्होंने विश्व निविदा आमन्त्रित की थी कुछ देशों ने निविदाएं भेजी थीं। निविदाएं भेजने वाले देशों में पाकिस्तान भी था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इन्हें पाकिस्तान को भेजने का निर्णय किया था। इससे यह स्थिति पैदा हुई है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी बतलव्य है कि हमने इस स्थिति के बारे में आस्ट्रेलिया सरकार को बतलव्य दिया है कि उपमहाद्वीप की वर्तमान स्थिति पर इसके प्रभाव को देखते हुए उन्हें हम पर दुबारा विचार करना

चाहिए। मैं अपने साथी तथा सभी को आश्वासन देता हूँ कि केन्द्र सरकार को क्षेत्र की स्थिति की पूरी जानकारी है तथा उन्हें यह भी आश्वासन देता हूँ कि भारत की सुरक्षा और रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

श्री सुधीर गिरि : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस विशेष समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले आस्ट्रेलिया सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित किया गया था।

श्री इन्द्र कुमार गुब्बारा : मैंने अपने जवाब में बता दिया है कि हमने सम्पर्क किया है। मैंने पिछला पत्र इस महीने की 11 तारीख को आस्ट्रेलिया सरकार के लिए लिखा था।

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हमने करार पर हस्ताक्षर होने से पहले आस्ट्रेलिया सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित किया था।

श्री इन्द्र कुमार गुब्बारा : जी, नहीं। मैं जिम्मेदारी टालना नहीं चाहता परन्तु यह पिछली सरकार की जिम्मेदारी थी।

1.44 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सलेम जिले में पेयजल की कमी दूर करने हेतु गहरे कुएं खोदने के लिए तमिलनाडु सरकार को धन दिए जाने की मांग

श्री पी० आर० कुमारमगलम (सलेम) : पेयजल की कमी के कारण सलेम जिले के लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जल स्तर नीचे गिर जाने के कारण परम्परागत बोर कुएं निष्प्रभावी हो गए हैं। इसके समाधान के लिए 1000 से लेकर 1500 फीट तक गहरे बोर कुएं खोदने चाहिए इसके लिए केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के पास साधन उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त पेयजल मिनी मिशन के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी के लिए आबंटित 7.40 करोड़ रुपयों में से 1.30 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तमिलनाडु सरकार भी वित्तीय सहायता नहीं देना चाहती है। भीषण सूखा के कारण व्यापक आन्दोलन चलाए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में मेरा जल ससाधन मन्त्रालय से अनुरोध है कि प्रति राजस्व पंचायत के पीछे कम से कम तीन बोर कुएं खोदे जायें तथा सलेम की जनता को पेयजल दिया जाए।

(दो) कुमाऊं, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च-न्यायालय की एक सफ़िट न्यायपीठ खोले जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री एम० एल० पाल (नैनीताल) : उत्तर प्रदेश के कुमायूं क्षेत्र में न्याय-व्यवस्था को नियमित करने, मंडल के प्रत्येक व्यक्ति को सस्ता व सुगम तरीके का न्याय मिल सके, इसके लिए सम्पूर्ण कुमायूं क्षेत्र को उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच पीठ से शीघ्र जोड़ा जाना आवश्यक हो गया है।

इस सन्दर्भ में जस्टिस असबन्त सिंह आयोग की सिफारिश के अनुरूप कुमायूं में इलाहाबाद हाई कोर्ट की सर्किट बेंच खोली जाए तथा इस कमीशन की सिफारिशों को शीघ्र लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जायें।

(तीन) चेतक एक्सप्रेस की गति बढ़ाए जाने की मांग

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : उदयपुर (राजस्थान) आदिवासी बहुल, पर्यटन, खनिज एवं ऐतिहासिक महत्त्व का स्थान है पर देश की आजादी के 43 वर्षों के बाद भी रेल विभाग की तरफ से उपेक्षित रहा है। मेवाड़ राज्य के समय बनी रेल लाइनें हैं एवं लगभग उतनी ही गाड़ियां एक बो को छोड़ कर चल रही हैं। उनकी गति में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है।

राजस्थान की राजधानी जयपुर से सभी बड़े शहर—बीकानेर, गंगानगर, अजमेर, जोधपुर—को अलग से ट्रेनें चलती हैं पर उदयपुर तक चलने वाली अगल से कोई गाड़ी नहीं है। मात्र एक दिल्ली से उदयपुर चलने वाली चेतक एक्सप्रेस ही ऐसी गाड़ी है जो अत्यन्त उपयोगी है। लेकिन यह 734 किलोमीटर की दूरी 20 घण्टे में पूरी करती है। दिल्ली से अहमदाबाद जाने में समय कम लगता है पर उदयपुर जाने में अधिक। इस बारे में विभाग को तथा मंत्री महोदय को कई बार जनता ने लिखा, ज्ञापन दिए, मैंने स्वयं कई पत्र एवं अन्य तरीकों से ध्यान आकषित किया पर अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। अतः सरकार से पुनः आग्रह है कि वह इस पर तुरन्त कार्यवाही कर इस गाड़ी की गति बढ़ाई जाए जिससे जनता एवं क्षेत्र को लाभ मिल सके।

(चार) बरेली, उत्तर प्रदेश में अधिक रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : बरेली पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रमुख केन्द्र है तथा वहां कई प्रमुख औद्योगिक संस्थान हैं। जिनके मुख्यालय वम्बई में हैं। जैसे इफको उर्वरक कारखाना, सिन्थेटिकम केमिकल्स कैंधर एलाइव प्रोजेक्ट्स, विमको आदि। बरेली को केन्द्र सरकार ने काउन्टर मैननेट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। यह कुमायूं व गढ़वाल के लिए एक प्रमुख मण्डी है। परन्तु बरेली में रेल सेवाओं को सुविधाजनक नहीं बनाया गया है। इस कारण काफी संख्या में यात्रियों को परेशानी होती है। यहां तक कि बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन जो उत्तर रेलवे का प्रमुख स्टेशन है, पर विभिन्न रेल गाड़ियों में आरक्षण के कोटे भी अन्य जिलों की तुलना में काफी कम हैं। इन समस्याओं को लेकर मैं कई बार रेल मन्त्री से निवेदन कर चुका हूं। मेरा आपसे माध्यम से रेल मन्त्री जो से अनुरोध है कि बरेली में समस्त रेल गाड़ियों में आरक्षण के कोटे को आवश्यकतानुसार बढ़ाएं, बरेली से मुम्बई व दक्षिण भारत को जोड़ने वाली सीधी रेल सेवा प्रारम्भ करें, बरेली अलीगढ़ मार्ग पर एक्सप्रेस ट्रेन चलाएं तथा कम्प्युटरीकृत आरक्षण केन्द्र महित अन्य सुविधाएं प्रदान करें। नगरिया सादात रेलवे स्टेशन जो तहसील केन्द्र है, उस पर दिल्ली व देहरादून दिशा की एक्सप्रेस ट्रेन रोकी जाए। श्यामगंज स्थित रेलवे स्टेशन जो अनुपयोगी है, को गमाप्त कर व्यावहारिक भारी कम्प-लेक्स बनाएं।

(पांच) तमिल, कांचीपुरम, उत्तरमेरुर और मधुरनथकम जिलों की मरम्मत करने तथा उनमें से गाढ निकालने के लिए तमिलनाडु सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

[अनुवाद]

*श्री कर्त्ती पन्नीर सिलवम (वेंगलपट्टूर) : तमिलनाडु के वेंगलपट्टूर जिले में किसानों तथा कुनकरों की बहूत अधिक संख्या है। बड़ी जिलों अर्थात् घमल, कांचीपुरम, उत्तरमेरुर तथा मधुरनथकम से वेंगलपट्टूर के क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इन तीनों जिलों की मरम्मत तथा गाढ निकालने की आवश्यकता है। अत्यधिक लागत होने के कारण राज्य सरकार इन कार्यों को करने में असमर्थ है। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन तीनों जिलों से गाढ निकालने के लिए अपने संसाधनों तथा बाह्य ऋण से विशेष अनुदान दिया जाए।

(छ) केरल में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए कथम उठाए जाने की मांग

श्री० के० वी० धामस (एरणाकुलम) : महोदय, केरल राज्य में पानी की अत्यधिक कमी है। शहरों तथा गांवों में लोगों को पानी के टैंकरों को प्रतिक्षा करनी पड़ती है। राज्य सरकार ने पेयजल की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार से तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। केरल में पेयजल की कमी का समाधान अल्पकालिक और दीर्घकालिक आधार पर किया जाए। अल्पकालिक आधार पर उन सभी स्थानों पर पानी भेजा जाना चाहिए जहां पेयजल की आवश्यकता है। दीर्घकालिक आधार पर पेयजल वितरण प्रणाली को शक्तिशाली पम्पिंग स्टेशनों, पाइप लाइन बिछाकर तथा भूमिगत जल निकाल कर सुदृढ़ किया जाए।

(सात) शिलांग दूरदर्शन केन्द्र में एक स्टूडियो का शीघ्र निर्माण किए जाने की मांग

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलांग) : महोदय, शिलांग दूरदर्शन केन्द्र में स्टूडियो नहीं है। मंत्रालय के प्रभारी मंत्री महोदय ने 2 जनवरी, 1990 को शिलांग की सार्वजनिक सभा में वायदा किया था कि 31 मार्च, 1990 तक या इससे पहले स्टूडियो का निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा। परन्तु स्टूडियो का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा है। स्टूडियो का शीघ्र निर्माण किए जाने की जोरदार मांग जनता द्वारा की जा रही है। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें।

*मूलतः तमिल में उठाए गए मामले के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

1.49 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91

अथ मंत्रालय

और

कल्याण मंत्रालय—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अथ मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 56 तथा कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 79 पर, जो 10 मई, 1990 को प्रस्तुत की गई थीं, आगे चर्चा करेगी। इसत लिए 14 घण्टे का समय नियत किया गया है। इसमें से 3 घण्टे 45 मिनट व्यतीत हो चुके हैं तथा 10 घण्टे 15 मिनट शेष बचे हैं। अब मैं श्री गोपाल पचेरवाल को बोझने के लिए बुलाऊंगा।

श्री पचेरवाल।

[हिन्दी]

श्री गोपाल पचेरवाल (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम अथ और कल्याण मंत्रालय, दोनों ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें भी जो कल्याण विभाग की मांगें हैं, उन पर मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें और सुझाव रखना चाहता हूँ। आज इस समाज में जो सामाजिक विषमतायें हैं, इन विषमताओं को समाप्त किए बिना, इस समाज का जो शोषित, पिछड़ा और दलित वर्ग है, उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आजादी से लेकर अब तक इस सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाकर, समाज का जो निचला तबका है, पिछड़ा वर्ग है, उसको आगे लाने के प्रयास किए गए, लेकिन इसमें जहां तक मेरी जानकारी है, इसके परिणाम कोई अच्छे नहीं निकले हैं। आज हम देखते हैं कि समाज के बड़े लोगों के द्वारा छोटे गरीब लोगों के ऊपर जो सामाजिक अत्याचार और जुल्म होते हैं, उनके निराकरण के सम्बन्ध में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं।

आज छोटे-छोटे गांवों में, जहां हरिजन, पिछड़े और शोषित वर्ग के लोग रहते हैं उनको कुंजों पर पानी तक नहीं भरने दिया जाता है, नाई की दुकान पर उनकी कटिंग नहीं होती है। आज पिछड़े, शोषित वर्ग में विवाह के समय दूल्हे को चोड़े पर भी नहीं बँठने दिया जाता है। उनकी महिलायें अपने गांव में अच्छे वस्त्र तक नहीं पहन सकती हैं। समाज में फँसी इन विषमताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। केवल औपचारिकता पूरी करना, बजट बनाना आदि काम किए जाते हैं लेकिन इन लोगों को सामाजिक न्याय मिले, समाज में फँसी यह विषमताएँ दूर हों, इसके लिए सरकार ने कोई उपाय नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी जी ने सामाजिक परिवर्तन के साथ-साथ सत्ता परिवर्तन की लड़ाई भी लड़ी थी, लेकिन आज राजनीतिक दल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई तो लड़ते हैं लेकिन समाज परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। इसलिए हमारे राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति तो होती है लेकिन सामाजिक बदलाव की ओर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए मैं राजनीतिक दल और सरकार से कहना चाहता हूँ कि वास्तव में यदि पिछड़े, शोषित और दलित वर्ग को समाज में भाग लाना चाहते हैं तो उनको राजनीति की दृष्टियत देनी पड़ेगी और उनको राजनीति की दृष्टियत देने के लिए, आज तो बड़े-

बड़े पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं इसमें चाहे—राज्यपाल को नियुक्त करने का सवाल हो या प्रदेशों में आपकी सरकार बनाने का सवाल हो, डा० लोहिया जी का नारा था कि 60 परसेन्ट पिछड़े वर्ग के लोगों को विशेष अवसर देकर समाज में आगे लाना है, 60 संकड़ा की नीति को जब तक लागू नहीं किया जाएगा, तब तक पिछड़ा वर्ग आगे नहीं आ सकता है।

जब तक राजनीतिक दल, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार पिछड़े, दलित, शोषित लोगों को अच्छे पदों पर आसीन नहीं करेगी, तब तक इनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकेगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज चाहे कांग्रेस हो या दूसरे दल हों, सब समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन किसी भी दल ने अपने अध्यक्ष पद पर किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को नहीं बिठाया है। इसी तरह चाहे राज्यपाल बनाने का सवाल हो या न्यायालयों में स्थान देने का सवाल हो, कहीं भी उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। आज मन्त्रिमण्डल को ही ले लीजिए, कहीं पर किसी भी दल की सरकार हो, कहीं भी पिछड़े वर्ग के लोगों को उतना प्रोत्साहन नहीं दिया गया है जितना देना चाहिए था। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसी जगहों पर भी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। इसी तरह से जो राजनीतिक पद हैं, उन पर भी पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। पिछले दिनों बहुत बातें आरक्षण के सवाल को लेकर कही गईं, जब भी हम लोग चुनाव सभाओं में जाते थे तब हमें आरक्षण के मामले में काफी विरोध का सामना करना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाज के निम्न वर्ग, गिर पर मिला ढोने वाले वर्ग से आया हूँ, मुझे सामाजिक उपेक्षाओं को समझने का, अध्ययन करने का मौका मिला है। आज बहुत से राजनीतिक दल भी आरक्षण विरोध का समर्थन करते हैं, इस बारे में आन्दोलन करते हैं, इसमें बहुत से सरकार के सहयोगी दल भी शामिल हैं। मुझे अफसोस है कि जो दल चुनाव घोषणा पत्र में आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन बाद में आरक्षण का विरोध करते हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि ऐसे राजनीतिक दलों और राजनीतिक लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। उनको किसी भी पद के अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। जिस तरह से पिछली सरकार ने सती प्रथा का समर्थन करने वाले, इसमें सहयोग देने वाले के खिलाफ कानून बनाया, जिसके अन्तर्गत उन लोगों को अपराधी माना जाता है, उनको पदों के लिए अयोग्य माना जाता है, इसी तरह से एक कानून बनाया जाना चाहिए, जिसके अन्तर्गत आरक्षण का विरोध करने वाले, आरक्षण के प्रति बग़ावत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सके, उसको सभी पदों के अयोग्य माना जा सके, राजनीतिक दलों में या सरकारी नौकरियों में उसको कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। जब तक पिछड़े वर्ग के लोगों को राजनीतिक हैसियत नहीं दी जाएगी, जब तक अच्छे पदों पर आसीन नहीं किया जाएगा, तब तक इनकी स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता है, तब तक इनके साथ सामाजिक जुल्म और अन्याय होते रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि राजनीतिक दलों में, सरकारी नौकरियों में इनको समुचित प्रोत्साहन मिलना चाहिए, नहीं तो आज गांधी जी के देश में क्या हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने नौकरियों में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया है, उन्होंने अंग्रेजी को समाप्त करने की बात कही है, अंग्रेजी का विरोध किया है। मैं सरकार से चाहूंगा कि नौकरियों में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना चाहिए। आज नौकरियों में काबलियत का मापदण्ड अंग्रेजी को माना जाता है, यह नहीं होना चाहिए, तभी पिछड़े वर्ग के लोग आ सकते हैं। आज बड़े आदमी का बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है और हमारे बच्चों के पास बिजली नहीं है, चिमनी बँलाने के लिए चिट्ठी का तेल नहीं है, पुस्तकें नहीं हैं, बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो मास्टर नहीं है, अध्ययन सामग्री नहीं है, ऐसी स्थिति में दोनों बच्चों को समानस्तर पर कैसे माना जा सकता है। इसलिए मेरा सरकार से

निवेदन है कि अंग्रेजी की काबिलियत का मापदण्ड नहीं बनाना चाहिए, तभी पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी रोजगार में उचित स्थान मिल सकेगा।

एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हर साल सरकार मार्च-अप्रैल में गरीबों को जमीन देने की बात करती है। लेकिन रिकार्ड में तो जमीन दे दी जाती है, पटवारी अपनी रिपोर्ट भेजता है, तहसीलदार और एस० डी० ओ० जमीन आबंटित करते हैं, लेकिन आबंटित जमीन पर लोगों को कब्जा नहीं मिल पाता, सिर्फ कागज में कब्जा मिलता है, कब्जा बड़े जमींदारों और जागीरदारों का ही रहता है। जब गरीब लोग कब्जा मांगने के लिए जाते हैं तो उन पर जुल्म-ज्यादती की जाती है। यदि वह आदमी घाने में कलेक्टर के पास शिकायत लेकर जाता है तो वहाँ पर बैठे हुए लोग भी, जो कि जमींदार के बन्द टुकड़ों पर पलते हैं, वे उन्हीं जमींदारों और जागीरदारों का साथ देते हैं और गरीब आदमी को आबंटित जमीन पर कब्जा नहीं मिलता है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि पुलिस प्रशासन में एक स्पेशल सेल की स्थापना की जानी चाहिए, जिसका कार्य आबंटित भूमि पर कब्जा दिलवाना हो। अगर किसी गरीब आदमी को जमीन पर कब्जा नहीं मिलता है तो इसके लिए एस० पी० और कलेक्टर को जिम्मेदार ठहराना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि जमीन पर कब्जा दिलाने में वे अक्षम रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज यही स्थिति न्यायपालिका की है। मुझे बड़े अफसोस और शर्म के साथ कहना पड़ता है कि आप अगर आकड़ें देखें तो पता लगेगा कि राजस्थान में एक भी अनुसूचित जाति का जज नहीं है। वहाँ पर अबिलम्ब जजों की भर्ती के सिलसिले में राजस्थान सरकार द्वारा जो नाम भेजे गए हैं, उनमें भी एक भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब व्यक्ति का नाम नहीं भेजा गया है। वहाँ सारे के सारे उन लोगों के नाम भेजे गए जो बड़े घरों में जन्मे हैं, जिन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा ली है, जो पाश्चात्य सभ्यता के नाम का डिंडोरा पीटने वाले लोग हैं। किसी भी राज्य सरकार ने दलित, शोषित पीड़ित व्यक्ति का नाम नहीं भेजा। आप योग्यता की बात करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल प्वाइण्ट पर बोलिए।

श्री गोपाल पचेरवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी वर्ग का हूँ, मैं इन सारी बातों को समझता हूँ, आपकी तो मुझ पर विशेष कृपा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसलिए थोड़े समय में अच्छे प्वाइण्ट रख सकते हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं अच्छे प्वाइण्ट ही रख रहा हूँ। हो सकता है आपकी नजर में अच्छे न हों। आप मुझे थोड़ा और समय देंगे तो अच्छा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि न्यायपालिका में हमारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए और हमारे लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे राजस्थान में बाड़मेर में अभी कुछ दिन पहले हरिजन समाज के लोगों की वहाँ के बड़े सांगों ने पानी की टंकी को तोड़ दिया, उनके साथ मार-पीट की।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, यह कोई प्वाइण्ट हुआ।

श्री गोपाल पचेरवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि न्यायपालिका में हमारे लोगों को कैसे दबाया जाता है। मुन्शी मजिस्ट्रेट को, सी० जी० एम० को इसलिए वहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया कि उन्होंने मुन्शियमान की बयानत नहीं ली। न्यायपालिका में जो कानून बनते हैं

उनका पालन नहीं होता है। मैं इसलिए अर्ज कर रहा था कि एस० सी० और एस० टी० के मुन्शी और मजिस्ट्रेट के साथ कितना बढ़ा जुलूम होता है। यह हकीकत है। यह ऊपर बैठने वाले लोगों की समझ में नहीं आता। न्याय-पालिका में उस वर्ग को संरक्षण मिलना चाहिए और ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कि जो इस तरह से अपराध करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले।

2.00 म० प०

आज मैंने सरकार की प्रगति रिपोर्ट पढ़ी। उसमें करोड़ों रुपया स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान के रूप में दिया गया है। मैं पासवान जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 166 संस्थाएँ हैं आपकी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, उसमें अनुसूचित जाति कल्याण स्वयंसेवक संघ की 9 संस्थाएँ हैं, आदिवासी कल्याण की संस्थाएँ हैं बिकलांग कल्याण की संस्थाएँ हैं, कुष्ठ रोग निवारण की संस्थाएँ हैं, बूढ़ों के कल्याण के लिए 12 संस्थाएँ हैं, उनको प्रत्येक को एक लाख और बड़े लाख से अधिक सहायता दी गयी है। मैं एक संस्था का उदाहरण देना चाहता हूँ। दिल्ली में हरिजन स्वयंसेवक संघ चलता है। 19 लाख रुपए उसको मदद दी गयी है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसकी जांच करवायें कि 166 संस्थाएँ जो पूरे देश में अनुदान के नाम पर करोड़ों रुपए लेती हैं उन्होंने क्या काम किया है। ये संस्थाएँ केवल व्यक्तिगत संस्थाएँ हैं, अपनी रोजी-रोटी चलाने का साधन है। आप इनको 19 लाख रुपए दे रहे हो, हरिजन स्वयंसेवक संघ का समाज के लिए कोई बड़ा योगदान नहीं है। यह एक रोजी-रोटी का माध्यम बना हुआ है। सारी की सारी संस्थाएँ उन लोगों के हाथ में है जिनको पिछड़े वर्ग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सामाजिक विषमताओं का, पिछड़े वर्ग की परेशानियों का, उनके साथ होने वाली जुलूम-ज्यादती का उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन करोड़ों रुपया इन संस्थाओं को दिया जाता है।

मैं पासवान जी से निवेदन करूंगा कि आप उस वर्ग से आए हैं, आपको उनकी पीड़ा और तकलीफ का ज्ञान है, आपको उनसे लगाव भी है, आप एक संसदीय कमेटी बना कर पूरे देश में जो 166 संस्थाएँ इस तरह से अनुदान लेकर पैसे का दुरुपयोग करती हैं उसकी जांच करवायें। पिछले 40 वर्षों में करोड़ों रुपयों का अनुदान लेकर इन्होंने समाज के लिए क्या किया, इसकी जांच करवायें। इनका तो रोजी-रोटी का साधन बना हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, भंगी कुष्ठ मुक्ति योजना के अन्तर्गत बड़े-बड़े नारे लगते हैं—गर्ब से कहो हम यह हैं, गर्ब से हम वह हैं। मैं भी गर्ब से कहता हूँ कि इस धरती पर गांधी, लोहिया और जयप्रकाश जी पैदा हुए हैं। मैं गर्ब से कहता हूँ कि इस देश में सीता और सावित्री की पूजा होती है, राम और कृष्ण की पूजा होती है। लेकिन मैं गर्म से भी कहता हूँ कि इस देश में नारी अपने बच्चे को पालने के लिए सिर पर मूँल ढोकर अपनी जिव्न्गी बिता रही है। अपने पेट की अग्नि शान्त करने के लिए उसको गाँब में एक रोटी के लिए सिर पर मूँला ढोना पड़ता है। मरते हुए बच्चे की औषधि के लिए सिर पर मूँला ढोने का काम किया जाता है। सरकार योजनाएँ बना रही है, लेकिन योजनाएँ तो 40 साल से बन रही हैं। मन्त्री जी को याद होगा कि 1957 में मलकानी कमेटी बनी थी, उसने 1960 में अपनी रिपोर्ट पेश की। उसमें सिर पर मूँला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए गए थे। लेकिन आज तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में जो सिर पर मूँला ढोने का समाज के नाम पर कलंक है, गांधी जी के देश में जो कलंक है, यदि उसको समाप्त करना चाहते हैं तो ईमानदारी से उन लोगों को समझना पड़ेगा जो मजदूरी कानून में 18,

23 और 32 रुपए देने की बात कर रहे हैं। लेकिन गांव में एक मेहतर की बेटी अपने सिर पर इस-लिए मैला ढोती है क्योंकि शाम को उसके बूँदों में आग नहीं जलती है। उसे शाम को रोटी बना कर अपना पेट भरना है, इसलिए मैला ढोती है।

पासवान जी, आप लेबर मिनिस्टर भी हैं और कल्याण मन्त्री हैं। मैं इसमें और अधिक कहना चाहता था, लेकिन समय कम है। आज हमारे समाज की व्यवस्था में सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए योजना बनाने से, कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। आपको इसमें सामाजिक रचनात्मक काम करना पड़ेगा। आपकी रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि हमने 32 शहरों को मुक्त कराने का काम किया और 300 गांवों को भी सम्मिलित किया है। लेकिन आप ईमानदारी से अध्ययन करेंगे तो पायेंगे कि यह सिर्फ कागजों पर है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, राज्य सरकारों भी इस पर कोई विशेष पहल नहीं कर रही है। जो सिर पर मैला ढोने का काम करने वाले लोग हैं अगर आप वास्तव में उनसे यह काम छुड़ाना चाहते हैं तो उनके लिए आपको रोजगार के अवसर सृजित करने होंगे, उनको आप रोजगार दें, अच्छी जगह नौकरी दें, उनको जमीन दें और दूसरे धंधों में लगायें तो निश्चित रूप से वे यह काम नहीं करेंगे, क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा गन्धा काम नहीं करना चाहता है। लेकिन भूख के लिए उनको यह करना पड़ता है। इसलिए हम ईमानदारी से सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं तो उनका सेल बनाकर हिन्दुस्तान का सर्वे किया जाए और राज्य सरकारों से कहें कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिर पर मैला ढोने का काम करके अपना जीवन बसर कर रहे हैं, उनका पता लगाकर जिस दिन उनका काम बन्द कराएँ उनको उसी दिन नौकरी का कागज थमा दें। उनको कहा जाए कि तुम्हें यह नौकरी दी जाती है और अब तुम यह गन्धा काम नहीं करोगे। इस तरह की योजनायें चलायेंगे तो गांधी, जय प्रकाश और लोहिया जी के देश में जो सिर पर मैला ढोने का कलंक है उससे लोगों को मुक्ति दिलाई जा सकती है।

[अनुबाब]

श्री ए० के० राय (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे युवा श्रम मन्त्री की जो प्रवृत्ति की गई है। इससे पता चलता है कि हमें उनसे कितनी आशा है। यह एक जिम्मेदारी है तथा मैं सोचता हूँ कि स्थिति अनुकूल नहीं है लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि वह आशा के अनुरूप सिद्ध होंगे तथा हमें निराश नहीं करेंगे।

2.07 म० प०

[श्रीमती गीता मूखर्जी पीठासीन हुईं]

यदि आप बारीकी से देखें तो आपको प्रतीत होगा कि यह मालिकों, नियोजकों अथवा भ्रूस्वामियों की संसद है। यदि हम देश की तरफ ध्यान दें तो राजनीति मजदूरों के हाथ से बाहर हो चुकी है। यह केवल मालिकों तक ही सीमित है। इसलिए जब हमने कृषि की बर्चा की तो मजदूरों के सम्बन्ध में बर्चा न करके किसानों के लिए लाभकारी भूमियों के बारे में बर्चा की। किसान का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो भूमि के एक किनारे पर हाथ में छाता लेकर खड़ा रहता है। वह बाजार लाभ कमाने के लिए जाता है।

जहाँ तक औद्योगिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, जैसाकि मन्त्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि

बिगत तीन वर्षों में हड़ताल के कारण 14 मिलियन तथा तालाबन्दी के कारण 22 मिलियन श्रम दिवस नष्ट हुए। इस वर्ष हड़ताल के कारण 6 मिलियन और तालाबन्दी के कारण 10 मिलियन दिवस बर्बाद हुए। तालाबन्दी के कारण श्रम दिवस नष्ट होने से आपका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि इसके लिए नियोजक अपराधी हैं। श्रम कानूनों को श्रमिकों की सहायता के लिए नहीं बल्कि श्रम को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। अब श्रम मन्त्रालय को नियोजकों से निपटने तथा नियंत्रित करने के लिए कोई विभाग बनाना चाहिए। उन्होंने एक तालमेल तन्त्र अर्थात् केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र का गठन किया है। इसी प्रकार आपको भी नियोजकों से निपटने के लिए औद्योगिक तन्त्र का गठन करना पड़ेगा। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या यह कागजी कार्यवाही होगी अथवा इसे अमल में लाया जाएगा। यह आवश्यक सेवा बनाए रखने का अधिनियम लागू कर सकता है जिसका श्रमिकों के विरुद्ध प्रयोग किया जाना बिल्कुल प्रसांगिक नहीं था। क्या उनमें नियोजकों, मालिकों तथा उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने हमारी दुर्लभ पूँजी को जकड़ा हुआ है तथा जो अपने कारखानों को बन्द कर देते हैं, हथियार प्रयोग करने का सहारा है? आज श्रमिक हड़ताल की समस्या पैदा नहीं करते हैं। यह समस्या नियोजक और पूँजीपति पैदा करते हैं। मैं अपने युवा श्रम मन्त्री महोदय से सबसे पहले यह पूछना चाहता हूँ कि मालिकों तथा पूँजीमतियों की हड़ताल से किस प्रकार निपटा जाए।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। यह हमारे लोगों के लिए रोजगार की समस्या से जुड़ा हुआ है। सभी रुग्ण तथा बन्द एककों की जाँच और विश्लेषण किया जाना चाहिए। जो एकक अपनी तकनीकी सम्भावनाओं तथा आर्थिक व्यवहार्यता के कारण बन्द हो गए हैं, उनके सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी चाहिए जैसा कि मेरे साथियों ने सुझाव दिया है। उन एककों अर्थात् उन सभी उद्योगों या कारखानों से, जो कुप्रबन्ध तथा कार्यशील पूँजी के दुरुपयोग के कारण बन्द हैं निपटने के लिए दूसरी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए। मेरा सुझाव है कि केबल अधिग्रहण तथा राष्ट्रीयकरण ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इस सरकार को नए तरीके से पहल करनी चाहिए। हमारे यहाँ सरकारी तथा निजी क्षेत्र हैं। मैं चाहता हूँ कि एक श्रमिक क्षेत्र भी बनाया जाये। जब प्रबन्ध किसी कारखाने को, जो आर्थिक रूप से लाभप्रद हो सकता है तथा जिसके उत्पादों के लिए बाजार है, चलाने का इच्छुक नहीं है तो इसे चलाने के लिए श्रमिकों को सहकारिता बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा सरकार को इसे चलाने के लिए श्रमिकों को अधिकार देने तथा अर्थव्यवस्था में सहयोग देने तथा रोजगार बनाए रखने के लिए कानून बनाने चाहिए।

कुछ समय पहले कामनी श्रमिकों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। मैं चाहता हूँ कि उत्तर देते समय मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में भी अपने विचार व्यक्त करें तथा बिना किसी मुकदमेबाजी के श्रमिक क्षेत्र बनाने के लिए संसद में कानून बनाने का प्रयास करें।

दूसरे, मैंने मन्त्री महोदय तथा उनके अधिकारियों से केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र के संबन्ध में बातचीत की है। जब कोई औद्योगिक विवाद पैदा होता है तो उसे उस स्थिति में निपटाने के लिए तालमेल तन्त्र पर प्रयास किया जाता है। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विवादों को तय करने की दर धीरे-धीरे कम होती जा रही है इसलिए अधिकांश विवाद तय नहीं हो पाते हैं। यदि आप तालमेल की सफलता पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि प्रत्येक मामले में मजदूर संघ सफल के लिए सहमत थे परन्तु प्रबन्ध ने इसके लिए मना कर दिया। ऐसा सभी सरकारी क्षेत्र के एककों में हो रहा है।

इसलिए श्रम विभाग को सरकारी क्षेत्र के एककों को निर्देश देने चाहिए ताकि कम से कम अधिकतम मामलों में यदि वे तालमेल तन्त्र द्वारा तय नहीं हो पाते हैं, तो उनका फैसला मध्यस्थता द्वारा किया जा सके ताकि श्रम-न्यायालय और न्यायाधिकरण का बोझ कम हो। इस तन्त्र के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के एककों को स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए।

तीसरे, कुछ समय पहले उन्होंने एक गोष्ठी या कार्यशाला आयोजित की थी। राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। उस कार्यशाला में उन्होंने यह निर्णय लिया कि कैसे औद्योगिक विवादों को जल्दी से निपटाया जाए। उन्होंने कुछ निर्णय भी लिए। मैं जानना चाहूंगा कि वास्तव में कौन से कदम उठाए गए हैं, क्योंकि इस अवधि के दौरान मैंने स्वयं लगभग 50 मामले मन्त्रालय को भेजे। किन्तु एक या दो के अतिरिक्त, मुझे कोई जवाब नहीं मिला, हालांकि मैं इन विवादों को ट्रिब्यूनल को सौंपने के औचित्य को कानूनी रूप से अथवा अन्यथा समझा सकता था।

मैं इस सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह पिछली सरकार के पद बिल्कुल पर न चले और औद्योगिक विवादों को जल्दी से निपटाए ताकि कम से कम वे श्रम अदालत या ट्रिब्यूनल से न्याय पा सकें। मुझे आश्चर्य है कि पुरानी परिपाटी अभी भी जारी है। उदाहरण के तौर पर, हमारे पास श्रम अदालत रूपी ट्रिब्यूनल पहले से ही कम संख्या में हैं। धनबाद के ट्रिब्यूनल न०। में एक न्यायाधीश है, पर उसे मामलों में निर्णय देने का अधिकार नहीं है। ना तो उसे वहां से स्थानान्तरित किया गया है ना ही उसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तीन मास पूर्व मैंने सम्बन्धित अधिकारियों को यह मामला भेजा था। उन्होंने कहा, कि मन्त्रालय ने अनुमति दे दी है कि उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए और उन्हें वहां काम करने की अनुमति भी दी जाएगी, यह सिर्फ एक औपचारिकता है कि उन्हें अभी तक एक सरकारी आदेश नहीं दिया गया। किन्तु अब मुझे बताया गया है कि वह आदेश अभी तक बहा नहीं गया है और वह ट्रिब्यूनल काम नहीं कर रहा है। मैं सोचता हूँ कि इस तरह की परिपाटियों और परम्पराओं को बदलना पड़ेगा।

सरकारी क्षेत्रों की इकाइयों में चल रही घाघलियों से आपको जूझना होगा। आपको सिर्फ उनके खिलाफ काम ही नहीं करना है अपितु उनके खिलाफ लड़ने के लिए क्षमता भी अर्जित करनी है विशेषकर केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन चलने वाली उन सरकारी क्षेत्रों की इकाइयों में। वे ये गलत तरीके अपना रही हैं। आपने समान काम समान वेतन का एक नियम बनाया है। आपने यह भी कानून बनाया है कि यदि एक व्यक्ति 240 दिनों तक काम करता है तो उसे नियमित कर दिया जाएगा। उद्योग मन्त्रालय के अधीन बोकारो में एक इन्स्ट्र्यूमेंटेशन विभाग है। वहां 172 श्रमिक हैं जो सात बर्षों से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं; कुछ 15 बर्षों से काम कर रहे हैं। मेरे प्रश्न के जवाब में मन्त्री जी ने इसका उल्लेख किया था। किन्तु अभी तक उन सभी श्रमिकों को नियमित नहीं किया गया। यह कैसे हो रहा है? उन सभी श्रमिकों ने सम्बन्धित मन्त्री को भी अर्थात्वेदना दिया था। उन्हें इस मामले को सह-मन्त्रालय तक ले जाना चाहिए कि वे ऐसा न करें। यह निर्णय लेना उनके ऊपर है, कि वे इन ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों को रखें या नहीं रखें। समय-समय पर, वे परिपत्र जारी कर रहे हैं। ये सरकारी क्षेत्र की इकाइयां इन परिपत्रों को कोई महत्व नहीं देती; वे उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक देती हैं। कोयले की खदानों में कोयले की डुलाई, ऊपर उठाया, कोयले की डुलाई वे सभी चीजें ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों द्वारा कराए जाने पर रोक है। किन्तु वे ये सभी काम कर रहे हैं। सभी निर्भीक कम्पनियां इन खदानों का प्रबन्ध देख रही हैं और वे ये सभी काम मशीनों से

करबा रही हैं, आदमियों से नहीं। जब हमने इस मामले को सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेजा, तो उन्होंने उन पर मुकदमा चलाया। किन्तु वे इसकी परबाह नहीं करते क्योंकि वहाँ कोई ऐसा नहीं है जो अभियोजन के परिणाम का पालन कर सके।

कुछ दिन पूर्व, माननीय मन्त्री ने कहा था कि वे हर कानून में दण्ड का एक खण्ड रखेंगे। इस तरह दण्ड का खण्ड रखने का क्या मतलब है जबकि वास्तव में उन पर कोई दण्ड नहीं लगाया जाता ? क्या कभी उन्होंने यह पता लगाया है कि विभिन्न अदालतों में कितने मुकदमे वास्तव में लम्बित हैं और उन पर वे निर्णय क्यों नहीं ले रहे ? क्या एक भी मिल मालिक पर तथ्याकथित केन्द्रीय औद्योगिक श्रम मशीनरी द्वारा मुकदमा चलाया गया। आप उनके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ गरजते हैं, आप सिर्फ विलाप करते हैं; आप सिर्फ भाषण देते हैं; आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते। कोई परिणाम नहीं होता। सरकार को इतनी बड़ी मशीनरी रखने की क्या जरूरत है जबकि कोई परिणाम नहीं निकलता। आप काम के अधिकार का प्रचार कर रहे हैं। किन्तु आपके पास सभी अधिकार हैं। आपको उनके लिए काम करना है; आपमें उनके लिए काम करने का संकल्प होना चाहिए। आपके पास सभी अधिकार हैं और उनकी सहायता करने के लिए आपको उनका उपयोग करना चाहिए। किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला है। मैं आपको कुछ बहुत ही ठोस बातें बता रहा हूँ ताकि आप इस ओर आगे बढ़ सकें।

बिहार में न्यूनतम मजदूरी 20.50 रुपए है। इस देश में वास्तविक गरीबी रेखा क्या है ? 1984-85 में, यह 6,400 रुपए प्रति वर्ष थी। शहरी क्षेत्रों में यह 7,300 रुपए थी जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1960-61 को आधार वर्ष मान कर लगभग 625 रुपए था।

आज, यह 845 रुपए है। इसका अर्थ है, कि आय, वास्तव में एक परिवार के लिए गरीबी रेखा 900 रुपए है। पांच व्यक्तियों के एक परिवार की मासिक आय लगभग 900 रुपए से 1,000 रुपए है। अतः, यदि न्यूनतम वेतन भी दिया जाता है, तो भी श्रमिक गरीबी रेखा के नीचे ही रहेंगे। क्या सरकार को कोई विधान या कोई प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए जिससे अपने ही राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को ऊपर उठाया जा सके। उन्हें कोई राष्ट्रीय वेतन नीति बनानी चाहिए। मैं यही प्रस्ताव करना चाहता हूँ। चाहे यह सरकारी क्षेत्र हो या वे स्थायी कर्मचारी हो या अस्थायी कर्मचारी, या ठेका कर्मचारी हो, सभी बराबर हैं। उन्हें भी उसी बाजार से खरीदारी करनी होती है। अतः, यदि आप समाज में असमानता को नहीं मिटा सकते तो कम से कम श्रमिक वर्ग में असन्तुलन को तो दूर कर सकते हैं। मैं यही प्रस्ताव करना चाहता हूँ। इस सत्र में या बाद में, सभी विचारों, पक्षों को ध्यान में रखते हुए आप एक व्यापक राष्ट्रीय वेतन नीति लाइए।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री ए० के० राय : मैं अभी समाप्त कर रहा हूँ। मैं एक अन्य सुझाव दे रहा हूँ। ठेका श्रमिकों को लीजिए। हमारे देश में लगभग 30 से 35 करोड़ कामकाजी लोग हैं। उनमें से 15 करोड़ अपना व्यवसाय करते हैं। 12 करोड़ असंगठित क्षेत्र में हैं और तीन करोड़ संगठित क्षेत्र में हैं, और उनमें से सिर्फ साठ लाख या इससे भी कम किसी यूनियन से सम्बन्धित हैं। उन्होंने सभी कर्मचारी संघों की सदस्यता का जोड़ किया और यह सिर्फ 60 लाख है, अर्थात् कामकाजी लोगों का सिर्फ दो प्रतिशत। किन्तु महोदय, यहाँ भी हमें असंगठित क्षेत्रों, ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों के बारे में सोचना पड़ता है, और यहाँ भी श्रम विभाग में बड़े दकियानूसी लोग—जब भी हम उनके पास जाते हैं—हमेशा

निबन्धिता और विभागीकरण की बात करते हैं। उन्होंने मालिक—कर्मचारी सम्बन्ध की समस्या का ऐसे समाधान किया वे कहते हैं कि मालिक-कर्मचारी सम्बन्ध नाम की कोई चीज नहीं है। समस्याएँ सुलझाने का यह बहुत ही अजीब ढंग है। यह एक सामाजिक न्याय का प्रश्न है। ये मामले पृष्ठभूमि में रखे गए हैं। किन्तु एक के बाद एक, हमारे विवाह चिरस्थायी हैं।

मैं अपने मित्रों को एक सुझाव देना चाहता हूँ। वह यह है, कि आपको ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम में संशोधन करना होगा। यदि आप इस कानून की धारा 10 देखें, तो आप पाएंगे कि यह ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों के किसी स्थायी प्रकार के काम करने पर रोक लगाना है। किन्तु यह इन श्रमिकों को स्वतः ही विभागीय बनाने का अधिकार नहीं देता। किन्तु अभी भी, मैं सोचता हूँ, कि जब तक आप उन कानूनों में संशोधन नहीं करेंगे तब तक कुछ परेशानियाँ होंगी।

महोदया, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री कृष्ण अय्यर ने प्रख्यात हुसैन बाई के मामले में निर्णय दिया था और मैं उस निर्णय से उद्धृत करना चाहूँगा।

“तीसरी दुनिया की औद्योगिक शक्ति का श्रोत ………”

सभापति महोदय : आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री ए० के० राय : ब्रूटस तुम भी !

“तीसरी दुनिया के न्यायक्षेत्र की औद्योगिक शक्ति का श्रोत सामाजिक न्याय है जैसा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है। भारतीय न्याय अदालत उदारवाद से परे एक ऐसा कानून है जो जीवन के नियमों की सहायता के लिए है, ऐसा जीवन जो गरीबी या अमीरी की स्थितियों में है, जीवन-निर्वाह श्रम के साथ पारिश्रमिक से होता है। कानून की संरचना जटिल कानूनी नुकते नहीं करते अपितु सामाजिक कटु वास्तविकताएं करती हैं। कमजोर श्रमिक वर्ग को जीवनयापन के लिए श्रम के द्वारा उद्धार की आवश्यकता है।”

अतः, महोदया, मैं युवा श्रम मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे श्रमिक वर्गों के सम्पूर्ण कानून पर एक नया दृष्टि अपनाएं और उनके साथ कुछ न्याय करें।

श्री गोपीनाथ गणपति (बरहामपुर) : सभापति महोदया, यह सत्य है कि कमजोर वर्ग में अनुसूचित जनजातियों के लोग सबसे कमजोर हैं। सरकार और हम सभी लोगों से अपेक्षा है कि देश भर में इस वर्ग के लोगों को समुचित सहयोग दिया जाए। अनुसूचित जनजातियों के लोग अपने जीवन-शरण के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। जब तक अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा बेटी किए जाने वाली भूमि के लिए सिंचाई के समुचित प्रबंध हेतु सहायता नहीं दी जाती उनके लिए बाजीबिका उपार्जन करना सम्भव नहीं होगा।

जहां तक राजसहायता और ऋण की बात है उसके अधिकांश भाग का उपयोग होता है। वह विचोलिएटों द्वारा हड़प लिया जाता है। यद्यपि पिछड़ा वर्ग में मुख्यतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कमजातियों को मिलाकर हमारी आबादी का 52 प्रतिशत है फिर भी, उन्हें संविधान के तहत कोई मान्यता नहीं मिली है। उन्हें संविधान के तहत उचित मान्यता प्राप्त हो, इस पर ध्यान दिया जाना

चाहिए। गन्दी बस्तियों की सफाई, किसानों को ऋण राहत और विकलांग तथा सभी सेवानिवृत्त बयोवृद्ध कर्मचारियों को पर्याप्त पेंशन देने जैसी योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए।

बहुत से कमजोर वर्ग के लोग विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। वे प्राप्त होने वाली सुविधाओं से अनभिज्ञ हैं। सरकार द्वारा एक व्यापक विज्ञापन अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि इस वर्ग के लोगों को चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिल सके और वे इन योजनाओं से लाभ प्राप्त कर सकें।

महिला मजदूर, बंधुआ मजदूर, बाल मजदूर, अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर जैसी और भी कई समस्याएँ हैं। इन पर गम्भीरतापूर्वक गौर किया जाना चाहिए। हम इनके बारे में बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं। इन मामलों में सरकार को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। बेशक, हमने बाल श्रम को बहुत हद तक समाप्त कर दिया है। लेकिन हम लोगों की आर्थिक स्थिति के कारण इससे कुछ भी अधिक नहीं कर सकते। ये बच्चे भविष्य के अच्छे नागरिक बन सकते हैं बशर्ते उन्हें आवश्यक स्कूली शिक्षा और औपचारिक शिक्षा दी जाए। हमें कोई तरीका ढूँढ़ना होगा जिससे हम इन्हें लागू कर सकें। इसके साथ ही पूरे देश में अपराधी किशोरों और अनाथों के लिए चलाए जा रहे अनाथालयों और संस्थाओं को सरकार द्वारा उचित आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए जोकि उनके पुनर्वास का पूरा ध्यान देने जैसे प्रशंसनीय माननीय कार्य करते रहे।

मजदूर असंगठित क्षेत्र में बहुत ही कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पाती। इस असंगठित क्षेत्र के विभिन्न वर्गों को लाभ देने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। लेकिन यह सब कागज पर ही रह जाते हैं। उन कानूनों से जो लाभ उन्हें प्राप्त होना चाहिए। वह उन्हें नहीं मिलता है। इसलिए हमें एक तन्त्र तैयार करना है जिससे कि जिन लोगों के लिए यह कानून बनाया गया है वह भी उस तन्त्र को लागू करने में हिस्सा ले सकें। सत्तर प्रतिशत से अधिक श्रमिक ग्रामीण असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्हें चिकित्सकीय और अन्य सुविधाएँ भी प्राप्त नहीं हैं। उन्हें चिकित्सा सुविधा, ई० एम० आई० लाभ और भविष्य निधि इत्यादि के लाभ दिलाने के लिए आवश्यक है कि सरकार एक व्यापक कानून लाए।

दक्षिण उड़ीसा का गंजम जिला कृषि प्रधान जिला है। इसका एक संसदीय क्षेत्र बरहामपुर, जिमका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ उममें सात विधान सभा क्षेत्र हैं—क्षत्रपुर, गोपालपुर, बरहामपुर, छिकितो, मोहना, पारलाखेमुन्डी और रामगिरि। इन क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई की सुविधा की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। यहां तक कि जो स्रोत विगत वर्षों में मानवतावादी और दूरदर्शी व्यक्तियों ने उपलब्ध कराए थे, उनकी पूरी तरह अनदेखी की जा रही है।

कई गांव हैं, विशेषकर कृषि आधारित विधानसभाई क्षेत्र क्षत्रपुर और रामगिरि जहां न तो सिंचाई सुविधा उपलब्ध है और न ही पेयजल की सुविधा। क्षत्रपुर में सिंचाई परियोजनाओं को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है और जहां तक अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र राजगिरि का सम्बन्ध है वहां जो थोड़े बहुत जल स्रोत हैं वे पट्टच से बाहर हैं चूंकि गांवों को सड़कों से नहीं जोड़ा गया है। सरकार से निवेदन है कि वह इन ज्वलंत समस्याओं पर तुरन्त ध्यान दे।

हमारे सांसद और विधायक सरकार और जनता के बीच की कड़ी हैं। हम अपने सांसदों और

विधायकों के द्वारा, जोकि सद्भावना के संदेशवाहक हैं, लोगों में उचित विश्वास पैदा कर सकते हैं कि देश के महत्वपूर्ण श्रमिक शक्ति के अधिकार और कल्याण की रक्षा की जाएगी।

श्री डी० अमात (सुन्दरगढ़) : सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं केवल कुछ विशिष्ट बातों का ही उल्लेख करूंगा।

सबसे पहले, मैं उस कृषि क्षेत्र से हूँ जहाँ जनजातियों के लोगों का बाहुल्य है। मैं कृषि और उस पर निर्भर लोगों के विषय में चर्चा करूंगा।

भारत, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश है। मानचित्र के पूरे भू भाग का 2.45 प्रतिशत भाग इसके अन्तर्गत है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर यह ग्रेट ब्रिटेन से 11 गुना बड़ा है। भारत में 90 करोड़ एकड़ भू-भाग है। इसमें से 22.5 करोड़ एकड़ भू-भाग सूखा और तूफान प्रवण क्षेत्र है, 12.5 करोड़ एकड़ क्षेत्र रेतीला और भू-क्षरण से ग्रस्त है, पांच करोड़ एकड़ क्षेत्र क्षारीय है, दस करोड़ एकड़ क्षेत्र में नदी और पहाड़ हैं और 2.5 करोड़ एकड़ क्षेत्र रेसवे और राड़क के अन्तर्गत हैं। यह सब मिलाकर 55 करोड़ एकड़ जमीन है। बाकी 35 करोड़ एकड़ जमीन बचता है। यदि उस जमीन को समाजवादी आधार पर बांट दिया जाए तो हर व्यक्ति को .41 एकड़ जमीन मिलेगी। लेकिन वह क्षेत्र भी दिनोदिन विशिष्ट होने के कारण छोटा होता जा रहा है। प्रत्येक दो सैकेण्ड में एक भारतीय पैदा होता है। एक वर्ष में 2.5 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। इसी से जमीन कम होनी आ रही है। इस समस्या का समाधान कैसे हो? इस प्रकार से हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हमारे चार क्षेत्रों में लोग काम नहीं पानी मांगते हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि आबादी इस तरह बढ़ रही है कि हमें सभी को भोजन और हर हाथ को काम देना है। केवल जल ही हमारे कृषि का विकास कर सकता है। यहाँ 382 शहर और कस्बे हैं और 5.57 लाख गांव हैं। अस्सी प्रतिशत लोग गांवों में निवास करते हैं। उन्हें जल की आवश्यकता है। लेकिन इन बड़े-बड़े बांधों को बनाकर आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं बड़े बांधों के निर्माण का कट्टर विरोधी हूँ। दो दिन पहले कुछ मित्र दामोदर घाटी परियोजना में बाढ़ की बात कर रहे थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि दामोदर घाटी परियोजना से 300 एकड़ फुट भूमि में दलदल हो गई और नागार्जुन सागर बांध से 217 एकड़ फुट के दर से गांव जमा हो रहा है। यहाँ तक कि हमारा पलीराकुण्ड बांध भी गांव से बचा हुआ नहीं है। गर्मियों के मौसम में, लोग पानी को कृषि की ओर मोड़ देते हैं। टरबाइनों को चलाने के लिए पानी नहीं है। यदि पानी को विद्युत चैनल की ओर मोड़ा जाता है तो, कृषि खेती के लिए पानी नहीं रहता। इसलिए, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इन बांधों पर हर वर्ष गांव जमा हो रहा है और इनका तल और ऊपर से ऊपर बढ़ रहा है। वर्षा के मौसम में, हर वर्ष बाढ़ का पानी रेत को भूमि पर बिछा देता है। इसलिए, मैं इन सभी बांधों के विरुद्ध हूँ। यह आपराधिक क्षति है। मैं लघु, और मध्यम सिंचाई के पक्ष में नहीं हूँ। भूमिगत जल को खाने के लिए और इसे कृषि-क्षेत्रों में मोड़ने के लिए मैं खुदाई कुओं और ट्यूब वेल्स के पक्ष में हूँ (व्यवधान)

समापति महोदय : हम कृषि पर नहीं अपितु श्रम और कल्याण पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री डी० अमात : मुझे इस पर चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। भारत के गंगा के मैदान उपजाऊ हैं। दक्षिण बिहार, पश्चिमी उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से पहाड़ी, ऊंचे नीचे,

वर्ष से पूर्ण और चट्टानी भूमि है। पूर्वी उड़ीसा में भूमि मैदानी और उपजाऊ है। हरियाणा में हृदबन्दी के लिए 18 एकड़ भूमि सुनिश्चित की गई है जबकि उड़ीसा में यह 10 एकड़ है। यह पक्षपातपूर्ण हृदबन्दी है। इसलिए भूमि की हृदबन्दी उत्पादन के आधार पर सुनिश्चित की जानी चाहिए एकड़ के बख़्त पर नहीं।

अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि ६० एस० एम० ए० को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। यह अंग्रेजी रोलैट कानून, जो अंग्रेजों के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लाया गया था, की हूबहू नकल है। यह बिपक्षी नेताओं, ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों को दबाने के लिए और यहां तक कि प्रेस रिपोटर्स का मुंह बन्द करने के लिए बनाया गया है। यह एक कासा कानून है। इसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए।

मेरा क्षेत्र औद्योगिक इलाके का केन्द्र है। यहां श्रम कार्यालय के पास मजदूरों के कल्याण कार्यों के लिए पूरे आदमी, धन और अन्य वस्तुएं नहीं हैं। उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस मांग पर बोलने का अवसर दिया। मन्त्री द्वारा पेश की गई श्रम विभाग की मांगों का मैं समर्थन करता हूँ। इन शब्दों के साथ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।

श्री बीरबूब लिरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदया, मैं श्रम मन्त्री का ध्यान इस सत्य की ओर दिखाना चाहूंगा कि बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए पहले से ही एक कानून है। किन्तु, यह कानून तो आरम्भ से ही है। चाय बागानों ने बी सो वर्ष पूरे कर लिए हैं। किन्तु, चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति आज भी ऐसी ही है जैसी सैंकड़ों वर्ष पूर्व थी। बागान श्रम कानून के कल्याण विभाग द्वारा उन्हें दी गई सुविधाओं का बागानों में पालन नहीं किया जाता है। प्रबन्धक किसी निष्पक्ष कानूनानुसार नहीं करते हैं और प्रबन्ध के अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और स्वच्छता के आर्लीस वर्षों के पश्चात् भी उन्होंने चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की भलाई के लिए कुछ नहीं किया है। इसलिए महोदया, मैं जानता हूँ कि श्रम मन्त्री बहुत चुस्त हैं और उन्हें बागानों में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण के बारे में अवश्य ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, उन्हें चाय बागानों के सारे विभागों के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए और जो भी कानून मजदूरों के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं उन्हें चाय बागानों के प्रबन्ध द्वारा पूरी तन्मयता से लागू करें।

महोदया, चाय बागान देश के लिए 700 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। किन्तु चाय बागानों में मजदूरों की दशा और बख़तर हो रही है। हमारे सम्पन्न देश में उनसे इन्सानों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता है अपितु उन्हें मानवैतर समझा जाता है। 191 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं और 268 संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम हैं। संविधान की धाराएं, जिनका अनुसूचित जातियों के विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार हैं : 15(4), 76(4), 19(5), 46, 164, 244, 275(1), 330, 332, 334, 338, 339, 342 तथा संविधान का षष्ठवां और छठा अनुच्छेद। इसलिए, संविधान द्वारा इतना अभिरक्षण दिया जाता है। किन्तु सरकार चुप बंठी है। वे संविधान की इन धाराओं के अनुसार बिलकुल काम नहीं कर रही है जो जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए बने हैं। वे माननीय सदस्य जो मुझसे पहले बोले हैं वे भी काफ़ी चिन्तित थे और उन्होंने भी देश में जनजातीय लोगों के जीवन-निर्वाह की स्थितियों का जिक्र किया और कहा कि यह

सबसे अधिक शोषित लोग हैं। वे ही सबसे अधिक उपेक्षित लोग हैं और देश की स्वतन्त्रता का फल उन्हें अभी तक नहीं मिला है। इसलिए वह केंद्रीय सरकार का कर्तव्य बनता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जनजातीय लोगों को देश के विकास के लाभ में उनका पूरा हिस्सा मिले। जैसा आप जानते हैं, जनजातीय लोग राज्य सरकारों की दया पर हैं जैसे बिहार और अन्य राज्य जो जातिबों पर आधारित हैं। राज्य सरकारें वह धन खर्च नहीं कर रही हैं जो उन्हें उनके राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए मिलना है। इसलिए मैंने कहा था कि जनजातीय लोगों के लिए बनाई गई विकास योजनाओं के कार्यान्वित करने की प्रक्रियाओं को आंच छोटी करिए। जनजातीय संसद सदस्यों के एक संसदीय प्रतिनिधि-मण्डल को इन क्षेत्रों का दौरा करके यह पता लगाना चाहिए कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए जितना धन आवंटित किया गया है उसमें से कितना इस कार्य के लिए उपयोग किया गया है। वे यह भी पता लगाएं कि वे कौन लोग हैं जो विकास कार्यों के लिए धन खर्च करने के इन्चार्ज हैं और जनजातीय लोगों के लिए कौनसी विकास योजनाएं शुरू की गई हैं।

महोदया, अब मैं उद्योग पर आता हूँ। देश में कई छोटे और बड़े उद्योग हैं। इन उद्योगों में तालाबन्दी, और उद्योगों के बन्द होने की बातें आम ही गई हैं और श्रमिक-वर्ग को इसके कारण नुकसाह पहुंच रहा है। वे बेरोजगार हो जाते हैं और इन तालाबन्दीयों इत्यादि से उनके परिवारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सरकार उन लोगों को दण्ड क्यों नहीं देती जो हमारे देश के गरीब लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? इन लोगों को अन्य उद्योग खोलने का लाइसेंस कैसे मिल जाता है जब वे अपने पहले उद्योगों को क्लोज बना देते हैं? वे उन उद्योगों में निवेश नहीं करते जो रुग्ण हो गई हैं। उनके लिए तालाबन्दी, बन्द बहुत आसाम हो गया है और देश की अर्थव्यवस्था और गरीब जनता की परवाह किए बगैर मजदूरों को काम बन्द करने के लिए उकसाते हैं। इसलिए, महोदया, इन लोगों को दण्ड दिया जाना चाहिए और इन्हें अपनी फैक्टरी को बन्द करने या तालाबन्दी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि कोई फैक्टरी रुग्ण हो जाती है, तो सरकार को चाहिए कि वह मालिक को बिना कोई मुआबजा दिए उसे अपने नियन्त्रण में ले लें। मजदूर के हित को सवा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

रोजगार स्थिति इस प्रकार की है। देश में 332.1 मिलियन पंजीकृत नौकरी चाहने वाले हैं जिसमें से 61.09 महिलाएं हैं जो नौकरी चाहती हैं। इसलिए, महोदय, हम जानते हैं कि अधिकतम संख्या उन लोगों की है जो शिक्षित व्यक्ति हैं और जिन्होंने पंजीकरण करवाया है और जिन्हें मौकियां मिलेंगी। यह संख्या हर वर्ष बढ़ रही है और घट नहीं रही है। हर वर्ष लाखों लोग रोजगार काहालय में पंजीकरण के लिए आते हैं किन्तु उनके लिए कोई नौकरी नहीं है। वे लोग जो धनी हैं वे और अधिक धनी बन रहे हैं और श्रमिक और अधिक गरीब बन रहे हैं। यदि हम अपनी सरकार को समाजवादी कहते हैं, तो मैं कहूंगा कि समाजवादी सरकार इस प्रकार जी नहीं सकती। कम से कम सब लोगों के लिए जीने के साधन होने चाहिए। यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य बनता है कि गरीब लोगों और मजदूरों को सस्ती कीमतों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं। नहीं तो, विरोध पैदा होगा। बाज भी सभी विपत्ती बलों ने बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में आवाज उठाई है और वे अन्त तक लड़ेंगे। जीवन-यापन करने के लिए जो आय होती है उसे हाथ लगाए बिना आवश्यक उपभोग की वस्तुएं मजदूरों को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह इस और गम्भीरता से विचार करे और काले धन से छुटकारा पाना हीगा। हमारे देश में यह एक बीघारी है और यदि सरकार कुछ करना चाहती है तो वे लोगों से काले धन की रिपांट करने को क्यों नहीं कहते?

15 दिन के अन्दर जिन लोगों के पास काला धन है, उन्हें इसे खुले में लाना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते, तो उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्रीमती उमा गजपति राजू (विशाखापट्टनम) : सभापति महोदया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक महिला को बोलने का अवसर दिया। (व्यवधान)

मैं आज केवल दो मुद्दों पर बात करना चाहूंगी। एक है अनुसूचित जाति और जनजाति और दूसरा है महिलाओं के बारे में। समाज में इन दोनों वर्गों में सामाजिक असमानता है।

अब, महोदया, मैं यह कहना चाहूंगी कि सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए बहुत से झूठे वायदे करती है किन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है। जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार होते हैं तो सरकार चुप रहती है। लगता है कि वे राजाओं की परम्परा, ठाकुर हितों को अन्य सभी चीजों से अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। महोदया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माननीय प्रधान मन्त्री के चुनाव क्षेत्र में ठाकुर अकड़ कर रहते हैं और हरिजनो को जीवित जलाया जाता है। प्रतिदिन हम फतेहपुर में होने वाले अत्याचारों के बारे में सुनते हैं, प्रतिदिन हम त्यौहारों के दौरान होने वाले अत्याचारों के बारे में सुनते हैं और सरकार चुप रहती है। मैं उनकी चुप्पी का अर्थ सहभागिता और उनकी चुप्पी का अर्थ उनकी सहमति मानती हूँ। सरकार इन सब अत्याचारों का विरोध क्यों नहीं करती? सरकार ठीक प्रकार से बताती क्यों नहीं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति उनका रुख क्या है? मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगी कि हम अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक निश्चित कार्यक्रम क्यों नहीं बना सकते जैसी कि कांग्रेस दल ने हमेशा परिकल्पना की थी? पहले, उनके पास गांवों और शहरों में विभाजन था, ऐसा मैं कहती हूँ, तब उन्होंने देश को भाषा के मुद्दे पर विभाजित करना चाहा और आज सरकार जाति के आधार पर देश का विभाजन करने की कोशिश कर रही है। मैं माननीय मन्त्री महोदय को कहना चाहूंगी कि वे इस सत्य को ध्यान में रखें कि अनुसूचित जाति और जनजाति, जिन्हें महात्मा गांधी ने भगवान के बच्चे कहा, उनकी उपेक्षा की जाती रही है और इस सरकार द्वारा अभी भी उपेक्षा की जा रही है।

अब मैं महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों की चर्चा करूंगा। कृषि के क्षेत्र में हमेशा से महिलाओं का शोषण किया जाता रहा है। पुरुषों को जो मजदूरी दी जाती है उसकी तुलना में उन्हें मजदूरी देने में बहुत भेदभाव बरता जाता है। जब भूमि के पट्टे की बात आती है तो यह पट्टा सिर्फ पुरुषों को दिया जाता है महिलाओं को नहीं। मैं यह कहना चाहूंगा कि गांवों में शराब पीने की लत बहुत ही आम बात है और पुरुष लोग सम्पत्ति बेच कर शराब पी जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को पट्टा दिए जाने का विचार बहुत ही अच्छा साबित होगा। यहां तक कि सरकारी उपक्रमों में भी महिलाओं के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाता है। विशेष रूप से मैं विशाखा-पत्तनम इस्पात संयंत्र जो कि मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में है, का उल्लेख कर रहा हूँ। मैंने माननीय मन्त्री जी से अनेकों बार अनुरोध किया है कि जब सरकार किसी सरकारी उपक्रम की स्थापना करे तो उन्हें 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। वे ऐसा कदम क्यों नहीं उठा सकते हैं? वे चुप्पे क्यों हैं? उनकी चुप्पी का अर्थ है कि वे सिर्फ बातें बनाते हैं और समितियों का गठन करते हैं और फिर इस मामले में कुछ भी निर्णय नहीं करते हैं। हम उस सरकार से कंसते किसी बात की अपेक्षा कर सकते हैं जिसमें कि ऐसे उप प्रधानमन्त्री हैं जिन्होंने हरियाणा के मुख्यमन्त्री के रूप में उस कुख्यात विधेयक को पारित कराने की कोशिश की है जिसमें कि शादी के बाद महिलाओं को उनके पतृक सम्पत्ति

में हिस्सा न देने की बात कही गई है? हम उस सरकार से कैसे कोई आशा कर सकते हैं जिसमें कि सत्ता पक्ष में श्री कल्याण सिंह कालबी जी हैं जिन्होंने दूरदर्शन पर यहां तक कह दिया कि वे सती प्रथा जैसी पाशिवकता का समर्थन करते हैं? हम उस सरकार से कैसे कोई आशा कर सकते हैं जिसमें कि श्री जगदीप घनखड़ जैसे मंत्री हैं?*

मैं आशा करता हूँ कि सरकार इन सब बातों पर ध्यान देगी और भारत में महिलाओं के लिए कुछ करने का निर्णय लेगी।

[हिन्दी]

बस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : श्री घनखड़ के बारे में जो कहा जा रहा है वह ठीक नहीं है, श्री घनखड़ तो एंटी सती हैं।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : सभापति महोदया, मैं समाज कल्याण के बारे में कुछ विचार रखना चाहूंगी। समाज कल्याण मन्त्रालय का मूल उद्देश्य पूरे समाज का कल्याण करना है। 1887 में न्यायमूर्ति श्री रानाडे ने कहा था कि अगर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो राजनीति और समाज कल्याण, दोनों को साथ-साथ चलाना होगा। कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने यह बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सामाजिक परिषद होना जरूरी है। आज जब हम समाज कल्याण की बात करते हैं तो उसमें बच्चे, महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी लोग आते हैं और इनके विकास के लिए आप मदद भी करते हैं। इनका विकास करने के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से आप देखें कि कितना पैसा इन कार्यों पर खर्च होता है। आज स्थान-स्थान पर सामाजिक संस्थाएं स्थापित हो गई हैं, उनके कार्यक्रमों के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन कितना पैसा इस उद्देश्य के लिए खर्च होता है।

आज विकलांगों की सहायता के लिए मेरूदण्ड क्षति केन्द्र की स्थापना की गई है, लेकिन राष्ट्र का मेरूदण्ड तो बच्चे हैं। अगर राष्ट्र का विकास करना है तो बच्चों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। बच्चों के चरित्र का विकास होना चाहिए, तभी राष्ट्र के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। बच्चे राष्ट्र का भावी भविष्य हैं, लेकिन आज बच्चों की क्या स्थिति है। लाखों बच्चे कूड़ा-करकट बीतते हैं और 44 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा है। आज हम विकलांगों की बात करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि लाखों बच्चे आज कुपोषण का शिकार हैं।

2.15 म० प०

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी पीठासीन हुए]

पोषण आहार केन्द्र चलते हैं, लेकिन पोषण आहार केन्द्रों में आपके हिसाब से यदि 50 पैसा खर्च होना चाहिए तो खर्चा केवल 9 पैसा होता है। पोषण आहार केन्द्रों में बच्चों को जो आहार दिया जाता है उसकी उचित मात्रा बच्चों तक पहुंचती नहीं है।

मध्य प्रदेश में कई ऐसी संस्थाएं हैं, उनकी जांच के आदेश बहुत पहले दिए गए थे। जांच के बाद यह भी पाया गया कि ठीक ढंग से काम नहीं होता है। लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ।

* * अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकास दिया गया।

जब एक्शन लेने की बात सोची गई तो एक स्थान पर यहां तक हुआ, मैं पढ़ने की सरकार की बात कर रही हूं, जब जंच करने के लिए केन्द्र के अधिकारी गए तो उनके साथ मार-पीठ की गई क्योंकि मार-पीठ करने वालों को उस समय के राज्य मंत्री का संरक्षण प्राप्त था। 40 लाख से अलग-अलग योजनाएं बनाई गयीं लेकिन उन संस्थाओं को योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जो करोड़ों रुपये दिया गया, खर्च स्थिति यह है कि केवल अपने-अपने ही कुछ लोगों ने उस योजना को चलाया है। ऐसी संस्थाओं को पैसा दिया जाता रहा। इसलिए सही मायने में जिनकी सहायता पहुंचनी चाहिए वह पहुंचती नहीं है।

झूला-गृह के बारे में मैं कहना चाहती हूं। कहने के लिए तो 8 हजार झूला-गृह चल रहे हैं लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए तो केवल 4-5 हजार झूला-गृह चल रहे हैं, बाकी केवल अनुदान ले रहे हैं। वे वास्तविक रूप से चलते नहीं हैं। कहा जाता है कि 25 बच्चे एक झूला-गृह में होते हैं, लेकिन कुछ में तो इतने बच्चे भी होते नहीं हैं। उनको उचित आहार नहीं मिलता है।

बिकलांगों की बात की जाती है। उनको सहायता देने की बात करते हैं, बिकलांग मानसिक और शारीरिक रूप से होते हैं। शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से यदि हम चाहते हैं कि बिकलांग न हों तो इस पर काबू पाया जा सकता है। गर्भ में ही माता को उचित आहार मिलना चाहिए, उसकी देखभाल होनी चाहिए, जो नहीं होती है। अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तो फिर आगे बढ़ने वाली पीढ़ी बिकलांग पैदा होती है। तो आपको यहीं से शुरूआत करनी पड़ेगी। उसके बाद तकरीबन 12 लाख बिकलांग हैं शारीरिक रूप से, इसमें मानसिक रूप से बिकलांग शामिल नहीं हैं, इन लोगों के लिए अलग-अलग केन्द्र चलाए जाते हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगी कि हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसे जो उद्योग हैं, जो ऐसे बिकलांगों को रोजगार देते हैं, ऐसी कंपनियां, प्राइवेट फर्मों जो बिकलांगों को काम देती हैं इनको करों में थोड़ी छूट दें। बिकलांगों को रोजगार देने की समस्या केन्द्र स्थापित करके या पैसे का प्रावधान करके हल नहीं हो सकती। ऐसी कंपनियों को बढ़ावा देना होगा जो बिकलांगों को रोजगार देती है। बिकलांगों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उनके लिए मार्केट उपलब्ध कराने की तरफ भी हमें सोचना पड़ेगा। केवल अनुदान देने या मदद देने से काम नहीं चलेगा, उन्हें अपने पैसों पर खड़ा करने के बारे में सोचना होगा। ऐसे बिकलांगों को पुरस्कृत किया जाए जो आत्म-विश्वास के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ें हैं।

इसके साथ-साथ बूढ़ों के बारे में हमें सोचना होगा। कल्पना मन्नासब से जुड़ा हुआ यह विशय है, इस बारे में सोचना अब बहुत जरूरी हो गया है। वास्तविक रूप से हमारे भारत की संस्कृति में यह समस्या इतनी तीव्र नहीं हुई है लेकिन कुछ सामाजिक परिस्थितियां इस प्रकार की बनती जा रही हैं कि बूढ़ों की समस्या बढ़ रही है। उनके लिए दाल-रोटी का सवाल नहीं है, दवाई का सवाल नहीं है। मानसिक तौर पर ये लोग अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि कुछ सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हो गयी हैं, जैसे बड़े शहरों में रहने के लिए जगह नहीं है और एक ही कमरे में पूरा परिवार रहता है, ऐसे में जो बूढ़े हैं वे ऐडजस्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए कई सक्स्वरूप खड़ी हो जाती हैं। ऐसे जो बूढ़े हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए पूरा जीवन दिया है, मुझे बचपन की कविता याद आ रही है, कविता मराठी में है, एक बूढ़े पिता अपने बच्चे से कहता है कि मैं तेरा भविष्य उज्ज्वल बनाना चाहता हूँ तू जितना चाहे आकाश में उड़ान भर ले, मेरे हाथ चाहे कट भी जाएं, मेरे हाथ से चाहे खून भी बह निकले, वह पतंग को लेकर कविता है—

“ऊंच ऊंच रे पतंग घेई तू भरारी
कबिलास हाथ जरी सौधरीन दोरी

शिशुलेख्या भ्रम जीवा कां बच से राजीवा
मभी विकास सब ब्हाबा होच हीस भारी ।”

तू आकाश में उड़ान भर ले, मैं तेरी बोर पकड़े रहूंगा, क्योंकि मेरी आने वाली बुढ़ाबस्था का तू ही सहारा है ।

3.00 अ० प०

और इस दृष्टि से बुढ़ा जीवन भर अपने बच्चों के भविष्य की दृष्टि से प्रयास करता है, लेकिन बाद में अकेलापन महसूस करता है और इनकी संख्या देश में करीब साढ़ें पांच करोड़ है । मैं यह चाहूंगी कि उनके लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए, केवल सौ रुपये बुढ़ों को पेन्शन देकर उनकी समस्या हल नहीं हो सकती है, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है । इनका जो अकेलापन है उनको ब्यबसाय दे सकें, उनको सामाजिक संस्थाओं में काम दे सकें उनके लिए कोई राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए और समाज कल्याण की योजनायें सफल हो जायें तो वे मानसिक रूप से अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे और समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सकेंगे । स्वयं विवेकानन्द जी ने कहा था कि हर उस शिक्षित व्यक्ति को जो समाज के लिए नहीं सोचता है, कभी अपनी शिक्षा का उपयोग समाज के उद्धार के लिए नहीं करता है ऐसे शिक्षित व्यक्ति को मैं गद्दार मानता हूँ । अगर शुरू से ही इस प्रकार के संस्कार बच्चों में डाले जायें जैसे

मनसा सततं स्मरणीयं
बचसा सततं 'बदनीयं'
लोकहितं सम करणीयं ।

तो ही कल्याण मन्त्रालय का कार्य सही रूप से सफल हो सकता है । मुझे लोगों का हित करना है यह भावना ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार फैले इसके लिए जरूरी है कि जो इस भावना से काम करने वाली संस्थायें हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हम चलाते हैं । उनमें इन संस्थाओं का सहयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए । इस भावना से हमारे मन्त्रालय को काम करना चाहिए ।

मैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगी । पालीस साल पहले जब उनको आरक्षण की सुविधा दी गई थी तो उस समय डा० अम्बेडकर ने कहा था कि हम इसे 15 साल से ज्यादा नहीं चाहते हैं । हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन उनके बाव जो योजनायें बनाई गईं मैंने भी आदिवासी छात्रावासों का निरीक्षण किया है और देखा है कि ये योजनायें इस ढंग से बनाई गईं कि उनको उचित लाभ नहीं मिला । बास्तबिक रूप से उनके कल्याण के लिए योजना नहीं बनी, अगर बनी भी तो वह कागजों पर ही रही, पैसा खर्च होता रहा, लेकिन उसका बास्तबिक लाभ उस समुदाय को और उन लोगों को नहीं मिला जिससे उनका बास्तबिक रूप से उत्थान हो पाता ।

इस साल हम बालिका बचं बना रहे हैं । लेकिन हमने देखा है कि आज भी गर्भ का परीक्षण होता है और गर्भ में ही लड़की को मारने की योजना बनाई जाती है । केवल बालिका बचं घोषित करने से कुछ नहीं होगा । हमें इस पर सोचना होगा । मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी बालिकाओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से योजना बनाई है कि जहां-जहां उनके छात्रावास हैं उनका वहाँ स्वास्थ्य का परीक्षण

होगा और वहीं उनका उपचार किया जाएगा। कई केन्द्रों में क्लेश भी बने हैं लेकिन वहाँ बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण नहीं होता है। इसलिए जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने यह कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है मैं चाहूँगी कि अपनी सरकार भी इस दृष्टि से सोचे। केवल अनुदान देने की बात ही नहीं होनी चाहिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की दृष्टि से योजना का निर्माण करना चाहिए। जैसे विवेकानन्द जी ने कहा था कि हम अपने आप को गद्दार नहीं माने इस दृष्टि से योजनाएं बननी चाहिए और बूढ़ों के लिए राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए जिससे उनको अकेलापन महसूस न हो, केवल 100 या 150 रुपये की पेन्शन देने के बाद हम अपने कार्य की इति समझ लें यह नहीं होना चाहिए। अगर हम इन सब बातों को मोचें तो हमारे मन्त्रालय का जो उद्देश्य है "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" वह फलीभूत हो सकेगा। हमें गरीबों, आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लिए पूरी तरह से सोच कर उनके हित की योजनाएं बनानी चाहिए और उनका उद्धार करना चाहिए।

[अनुबाव]

श्री पी० पंचालैया (नेल्दोर) : माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मन्त्री श्री राम विलास पासवान जी को श्रम मन्त्रालय का कार्यभार सम्भालने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। वे युवा हैं और अति परिश्रमी हैं। मैं आशा करता हूँ कि उनके कार्यविधि के दौरान श्रमिकों का जीवन स्तर बेहतर होगा।

भारत में दक्ष और अदक्ष दोनों प्रकार के श्रमिक बहुतायत में हैं। हम औद्योगिक दृष्टि से अति विकसित राष्ट्रों में से भी एक हैं। हमारा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक आधार बहुत ही सुदृढ़ है। लेकिन दुर्भाग्यवश इन समस्त उपलब्धियों के पीछे जो श्रम बल है, देश में निरन्तर उनकी अपेक्षा की जा रही है। दिन प्रति दिन उनके जीवन स्तर में गिरावट आती जा रही है। चाहे कोई वैज्ञानिक आत्महत्या करे अथवा किसी बन्द मिल के मजदूर भूखें मरे, इससे सरकार द्वारा बरती जा रही अपेक्षा प्रमाणित होती है।

देश में अनेक उद्योग रुग्ण इकाई के रूप में बन्द हो रहे हैं। वित्तीय संस्थाओं से मिल मालिक भारी मात्रा में ऋण लेते हैं और उस धनराशि को उद्योग की उन्नति में लगाने की बजाये सम्पूर्ण राशि हड़प कर जाते हैं। फिर किसी दिन वे अपनी ईकाई को रुग्ण घोषित कर देते हैं और मजदूरों को बेरोजगार बना देते हैं। ये निर्धन मजदूर और उनके परिवार भूखें मरते हैं। ये तथाकथित उद्योगपति वित्तीय संस्थानों, मजदूरों और देश की अर्थव्यवस्था के साथ घोषा कर रहे हैं। प्रमुख कारण यही है कि इतनी प्रतिभा रहने पर भी विकास की ओर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अतः इस प्रकार के अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कारवाही की जानी चाहिए।

हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग देश के कृषि मजदूरों का है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। इन मजदूरों को वर्ष में सिर्फ तीन या चार महीने ही रोजगार मिलता है। शेष वर्ष उन्हें अपने जगह में कोई काम नहीं मिलता है। साधारणतया वे जीविका की तलाश में देश के अन्य भागों में चले जाते हैं। अक्सर उनका शोषण किया जाता है। अतः इन मजदूरों के लिए उनके ही स्थान में रोजगार सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाया जाना चाहिए। जैसाकि हर कीर्ति जानता है कि वे असंगठित मजदूर हैं, उनका कोई ट्रेड यूनियन नहीं है या उनकी तरफ से संघर्ष करने के लिए नेता नहीं है। इस असंगठित वर्ग के साथ सरकार को न्याय करना चाहिए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है और इसलिए अपने रोजगार के तीन या चार महीनों के दौरान भी इन गरीब कृषि मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिलती है। अतः सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनके मामले में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाए।

महोदय, देश के अनेक हिस्सों में बंधुबा मजदूर प्रथा अभी भी लागू है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बुराई को समाप्त करने में सरकार और अनेक स्वैच्छिक संगठनों ने काफी रुचि दिखाई है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह प्रथा अभी भी लागू है। सरकार और स्वैच्छिक संगठनों के बीच उचित सम्बन्ध होना चाहिए ताकि देश से इस प्रथा को जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके।

उत्तरोत्तर सरकारों ने बाल श्रम पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में अनेक बातें कही हैं और अनेक विधान बनाये हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बिना में कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ है। बाल श्रम को रोकने में कोई भी विधान तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि देश गरीब है। लाखों लोग अपनी कम आय के कारण बच्चों से काम करवाना चाहेंगे। इन परिवारों का निर्वाह बच्चों के रोजगार पर निर्भर होता है। बाल श्रम प्रथा समाप्त करने से पहले हमें प्रत्येक भूले परिवार के लिए रोटी का इन्तजाम करने की बात सोचनी चाहिए। प्रत्येक विषय पर हमें राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। लेकिन अभी तक बाल श्रम के मामले में कोई भी समन्वित नीति नहीं बनाई गयी है। इस समय हमें एक अच्छी और बिस्तृत नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके द्वारा गरीब बच्चों, उनके रोजगार उस मामले में ही जब इसका कोई विकल्प न हो, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दिया जा सके। फिर हम बच्चों को बाल मजदूर बनने से रोक सकते हैं। इन अभाग बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह एक राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में विशेष रुचि लेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषणा समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री रमेश कुमार रवि बाबू (मधेपुरा) : सभापति महोदय, श्रम और कल्याण मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। सदन में तरह-तरह के मुद्दाब आए, लोगों ने अपने-अपने विचार रखे। अभी मुझसे पूर्व श्रीमती राजू ने और श्रीमती महाजन ने भी अपने-अपने विचार सदन के सामने रखे और बिचारों को रखने के क्रम में श्रीमती राजू ने तो वर्तमान सरकार को ठाकुरों की सरकार का नाम तक दे बाला। उन्होंने ठाकुर सरकार द्वारा हरे रहे अत्याचारों और फतेहपुर की भी चर्चा की। कदाचित वे यह भूल गयी कि इस देश में जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार का गठन हुआ तो उसे बिरासत में क्या मिला और राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने इतनी अत्याबाधि में राष्ट्र के नाम क्या-क्या संकल्प किए, क्या बायदे किए, चाहे वे श्रमिकों के लिए हों, अनुसूचित जातियों-जनजातियों के लिए हों, इस देश के पिछड़े लोगों के लिए हों, जिसमें आरक्षण की बातें आती हैं, इतना ही नहीं अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में, संगठित और असंगठित मजदूरों के लिए, कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए तथा दूसरे तमाम लोगों के लिए एक बृहद योजना, काफी उदारतावादी दृष्टिकोण को सामने रख कर, बनायी जा रही है। मैं कहना चाहूँ कि इस राष्ट्रीय मोर्चा की

सरकार ने देशवासियों से जो वायदे किए, वे इस तरह हैं :—

यह राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार,
राजनीति को नया संस्कार देना चाहती है ।
सत्य सरिता को नया बहाव देना चाहती है ।
आदमी को शील का भण्डार देना चाहती है ।
नीतियों को आदर्श का संसार देना चाहती है ।
शोषकों को एक नई फटकार देना चाहती है ।
नौजवानों को नई समाजवादी तलवार देना चाहती है ।
रह गया जो राज था, उठ गयी जो भी नीतियां,
उन्हीं खोयी नीतियों को ढूँढना है फिर चाहती ।
और मानव-मात्र से है कहना चाहती ।

चाहे कोई भी काम हो, कल्याण का काम हो, किसी भी मन्त्रालय का काम हो, किसी भी विभाग का काम हो, जब तक देश में अमन-चैन नहीं होगा, खुशहाली और शान्ति नहीं होगी, तब तक किसी भी तरह का निर्माण और विकास का काम किया नहीं जा सकता । देश बड़े हम सब की यह परिकल्पना है और कदाचित् राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का यह संकल्प है—हमारा देश बड़े, काफी आगे बढ़े । हमने सोच रखा है और हम कहना चाहते हैं :—

“बढ़ने दो देश को बन्द करो ये दंगे
देने दो वस्त्र उन्हें जो घूम रहे हैं नंगे
देने दो अन्न उन्हें जो अधपेटे सरपट भूखे हैं
काम, रोजगार, बेकारी, अशिक्षा अंधकार बीमारी
करने दो दूर उन्हें, चलने दो सुदूर उन्हें
गढ़ने दो इतिहास देश का नब्य विहान रचाने को
मत घोषो रंग सम्प्रदायवाद का मत फेंको जहर जातिवाद का
यह धरती है मानवता की भारत है बलिदानों की
अरे रोको-रोको आसाम बन्द सिया-सुन्नी के जंग बंद
कश्मीर में पाकिस्तानियों का घुसपैठ बन्द
पंजाब में खालिस्तान की आग बन्द
क्या हिन्दू और क्या मुसलमान
वीर भगत सिंह या शहीद असफाक
शहीद आजाद या अब्दुलवारी
यह सब शब्दों का उलट-फेर है
मतलब साधो एक जान है
ऊपर देखो सब समान है

हम सब का अरमान एक है
 बढ़े हमारा देश गगन तक
 चढ़े हमारा प्राण लगन तक
 हम पहुँचें बापू के सपनों तक
 जन-जन को दिए गीतों तक''

ये हमारे सपने हैं, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के सपने हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश की जो अर्थ-व्यवस्था है, समाज-व्यवस्था है, उसको दृष्टि में रखकर अगर मुल्क में नीतियाँ बनाई गई होती, तो यह देश आज 42 वर्षों की आजादी के बाद भी इतना पिछड़ा नहीं होता। हम भी आज इंग्लैंड और अमरीका की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ इतने वर्षों की आजादी के बाद भी मजहबी दंगे होते हैं, जातीय दंगे होते हैं और इन दंगों में हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वह चरामरा जाती है जिसके कारण हम अपने देश में जो निर्माण और विकास करना चाहते हैं, वह कर नहीं पाते हैं और जल्दीबाजी में श्रम की महत्ता और श्रम की उपादेयता जो है, उसकी अनदेखी कर देते हैं और उसकी अनदेखी हो भी जाती है। आज कुशल और अकुशल श्रमिकों की समस्याएँ हैं, संगठित और असंगठित श्रमिकों की समस्याएँ हैं। ऐसे श्रमिकों की जो सरकारी कल-कारखानों में काम करते हैं उनकी और जो प्राइवेट सेक्टर में कोयलरी और खदानों में काम करते हैं, उन सभी की कुछ न कुछ अलग-अलग समस्याएँ हैं। जो सरकारी कल-कारखानों में काम करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति कुछ बेहतर है बनिस्बत उनके जो सरकारी कारखानों में काम नहीं करते हैं अर्थात् जो प्राइवेट कारखानों में काम करते हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार ने काम के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देने का वायदा किया है। कम से कम इस सरकार ने महसूस तो किया, अनुभव तो किया, कि हम इस काम को करना चाहते हैं, करने की अभिलाषा की है, ऐसा हमने महसूस किया है, वर्तमान सरकार ने महसूस किया है। मैं तो मानता हूँ कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की यह मानवीयता और नैतिकता की पहली मिसाल है। हमने इतना बड़ा साहस किया, नैतिक, ब्याबहारिक और सामाजिक कदम उठाया है। हम श्रम की महत्ता और व्यक्ति की महत्ता को छोटा नहीं कर सकते, उसके कद को घटा नहीं सकते। यह भी सच है, जो आज श्रमिक नियम हैं, उनमें बाल-श्रमिकों की समस्याओं के लिए भी हमारी सरकार ने नियम बनाए हैं। चौदह वर्ष तक या उससे कम उम्र के बच्चों से यदि काम कराया जाता है, तो हमारी सरकार उसको भी अनैतिक मानती है। लेकिन इस कानून पर अमल नहीं होता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो भी चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं और वे जिन कारखानों में काम करते हैं, सरकार को चाहिए कि उस पर अंकुश लगे। इसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि एक कमेटी बनाएं जो यह देखे कि जो छोटे बच्चे देश के भविष्य हैं, देश के नागरिक हैं, उनसे कम उम्र में काम कराया जाता है, तो इसको बह देखे और रोके। इससे कुपोषण तो होता ही है साथ-ही-साथ मानसिक विकास भी हो नहीं पाता।

सबसे अधिक दुःख स्थिति यह है कि हमारा भारत गाँवों का देश है, किसानों का देश है। जो गाँव के मजदूर होते हैं, उनकी सबसे बचत स्थिति होती है। यह सही बात है कि हमारे देश में उद्योग कम हैं। अधिकतर 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। श्रमिक मजदूर इस पर अवलम्बित रहते हैं

लेकिन वहां पर अतिदृष्टि, अनावृष्टि होती है, कभी बाढ़ कभी सुख्खा होता है। वे मजदूर बाढ़ के दिनों में तीन-तीन महीने तक बेकार रहते हैं। जो खेती के कामों से जुड़े हुए मजदूर हैं उनकी समस्या कल-कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से अधिक कठिन है। जब पानी नहीं होता है, खेतों में वर्षा नहीं होती है तो खेतों की बुवाई रुक जाती है, ऐसे समय में वे मजदूर बेकार और निठल्ले हो जाते हैं। सरकार को चाहिए कि इस अनिश्चितता, इस संदिग्धता में जो रहे, काम कर रहे जो मजदूर हैं, उन पर अधिक ध्यान दें। कल-कारखाने जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, दुर्गापुर, भिलाई, कटिहार, धनबाद में जो मजदूर काम करते हैं वहां पर ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन्स के एक से एक नेता हैं, दिग्गज हैं उनकी समस्याओं को देखने के लिए लेकिन 80 प्रतिशत मजदूर जो गांवों में रहते हैं, खेत-खलिहानों में रहते हैं, जो असंगठित हैं, उनकी समस्या इनसे अधिक है। वे शहरों में रहते हैं तो उनके बच्चों को शिक्षा भी मिलती है। गांवों के विद्यालयों में आज भी उनको वह शिक्षा नहीं मिल पाती जिसके वे हकदार हैं। श्रमिकों ने ही इस देश को बनाया है। इस मुल्क में ललित कला के संकटों उदाहरण हैं जिनके हाथों ने राजमहल बनाया, कुतुब मीनार बनाया लेकिन आज उनके भविष्य को, उनके सामाजिक रहन-सहन को अनदेखा किया जा रहा है। हम यहां पर आकर बात करते हैं, प्रचार करते हैं निर्माता कोई और होता है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे ही दिन का सपना देखा था आदर्श और यथार्थ के सेतू प्रेमचन्द ने जिन्होंने "पुस की रात" और "कफन" लिखा, ऐसा ही सपना महाप्राण निराला ने देखा था जिन्होंने "तोड़ती पत्थर" और "भिखू" लिखा, ऐसा ही सपना देखा था महापत्थेता महादेवी वर्मा ने जिन्होंने "बबलू" और "रामा" रेखाचित्र खींचा था। उन्होंने कल्पना की थी कि हमारा देश आगे बढ़े, इस देश का एक-एक व्यक्ति खुशहाल हो चाहे वह अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति का हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण या शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हो उन्हें आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इसके लिए हमें स्वस्थ दृष्टि, स्वस्थ हृदय चाहिए। नीतियां बनती हैं, कार्यक्रम बनते हैं, उसको लागू किया जाना चाहिए, करवाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि वर्तमान राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार जो माहौल बनाना चाहती है, जो संस्कार देना चाहती है, जो परिस्थितियां पैदा करना चाहती है, वह दिन दूर नहीं कि काल के अन्तराल में वे सारी विषमताएं मिटाएंगे और यह देश खुशहाल होगा। इन तमाम बातों के साथ मैं श्रम और कल्याण मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

प्रो० यदुनाथ पांडेय (हजारीबाग) : मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं बिहार के जिस क्षेत्र हजारीबाग से आता हूं वैसे भी उसका विकास नहीं हुआ है, कोयले खदानों से भरा पड़ा है, वहां मजदूरों की समस्याएं हैं, आज भी वहां मजदूर की हालत बड़ी बदतर है। आज जहां शहरों में फलाम चला दिया जाता है तो पन्द्रह सीटर पानी यूं ही बह जाता है लेकिन कोयले की खदानों में जो मजदूर काम करते हैं उनको पीने के पानी की सुविधा नहीं है। आज दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता शहर रोशनी से ऐसे जगमगाते हैं कि पता नहीं चलता कि यहाँ दिन है या रात, लेकिन हमारे क्षेत्र में अभी भी हमारे बंधु दीपक जलाते हैं। आज भी उनके रहने की सुविधा नहीं है। हमारे यहां तो अक्सर देखा गया है कि प्रधान मंत्री का बेटा प्रधान मंत्री बनता है, डाक्टर का बेटा डाक्टर बनता है, बकील का बेटा बकील बनता है लेकिन हमारे यहां हजारीबाग में कोयला मजदूर का बेटा एक मजदूर भी नहीं बन पाता है। वहां 943 जो नियम है, उसके अन्तर्गत वहां बहुत से विचोसिए बीच में पैसा लेकर काम करते हैं। मेडिकल टैस्ट होता है और उस मेडिकल टैस्ट में वहां जो फिट होता है, उसे अनफिट किया जाता है, जो अनफिट होता है, उसे फिट किया जाता है। आज जो मजदूर है उसका बेटा मजदूर भी नहीं बन पाता है। उस क्षेत्र में 42 वर्षों तक जिस सरकार ने राज किया है, वहां जो इष्टक की यूनियन है, वह मजदूरों में आतंक फैलाकर मजदूरों को जबरदस्ती अपनी यूनियन में

सदस्य बनाती है। मैं तो मांग करना चाहूंगा कि वहां यूनिशन का चुनाव हो तो बोट के द्वारा हो, बेल्ट पेपर के द्वारा हो क्योंकि वह संगीन की नौक पर डरा धमकाकर वहां के मजदूरों को सदस्य बनाते हैं। वहां बैंक अप सिस्टम को समाप्त करना चाहिए। बहुत से मजदूर लिखकर देते हैं कि हम इष्टक के सदस्य नहीं हैं, फिर भी उनकी वहां से सदस्यता काट ली जाती है। सुबिधा के नाम पर उनको अभी तक कुछ नहीं मिला है। आज वहां जो ठेकेदार हैं, जो कोयले की सेलरी है वह अभी भी बढ़े-बढ़े ठेकेदारों को दी जाती है, नरेश कुमार टिक्कन जैसी कम्पनी को दी जाती है लेकिन स्थानीय लोगों को उससे बंचित किया जाता है। जब तक स्थानीय लोगों को, स्थानीय मजदूर के बेटों को वहां की सेलरी को सेल करने के लिए नहीं दिया जाएगा तब तक इन श्रमिकों का कैसे उद्धार होगा। अभी-अभी हम लोग मई दिवस मनाकर चुके हैं, एक मई को बहुत-सी रूलियां हुईं और बहुत से बायबे हुए होंगे और बीछे वर्ष का लेखा-जोखा हम लोगों ने देखा होगा और आने वाले समय में संघर्ष की तैयारी भी कर रहे होंगे। माननीय श्रम मंत्री जी अपने भाषण में अक्सर कहा करते हैं कि हमारे यहां न नेता की कमी है, हमारे यहां न नीति की कमी है, हमारे यहां कमी है तो नीयत की कमी है। बन्धुओं, आज मैं यह मांग करना चाहता हूं कि नीयत को ठीक करके जो भी अनुदान हो, जो भी नीतियां बनती हों, उन्हें लागू करना चाहिए। आज बीमारी के नाम पर बहुत सी फैक्ट्रियां बन्द पड़ी हैं और उन्हें बन्द दिखाकर हजारों मजदूर बेकार बैठे हुए हैं।

मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसे उत्पादनों के लिए आयात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो विदेशी कच्चे माल व विदेशी श्रम पर आधारित है तथा जिसमें भारतीय श्रम का योगदान नगण्य है और जो अनावश्यक भी हैं।

आधारभूत उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र में विकास होना चाहिए। साथ-साथ भौतिक व मानवीय साधनों के इष्टतम प्रयोग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार भी आवश्यक है।

कृषि क्षेत्र में, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र तथा दालों व तिलहन के उत्पादन में प्रभावपूर्ण सुधार आवश्यक है, यद्यपि गेहूं व चावल की कृषि के क्षेत्र में प्रगति भी बनी रहनी चाहिए। इससे एक ओर तो पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास होगा और दूसरी ओर दालों व तेलों के आयात पर ब्यय होने वाले विदेशी विनिमय की भी बचत होगी।

विजली के वितरण में होने वाली हानियों को न्यूनतम करने तथा उत्पादन क्षमता के इष्टतम प्रयोग का भरसक प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि, इस क्षेत्र में लगभग बीस हजार करोड़ रुपए की बचत की सम्भावना है।

औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, खाद्य प्रक्रिया उत्पादन, कृषि आधारित उत्पादनों तथा अन्य ऐसे सभी उद्योगों पर अधिक बल देना चाहिए जिनमें श्रम की प्रधानता है।

वस्त्र, जेवर, हीरे व जवाहरात, चमड़े का सामान, हस्तशिल्प व कलात्मक वस्तुओं, हुस्के इन्जीनियरिंग सामान आदि ऐसी सभी वस्तुओं के निर्यात को अधिकतम बढ़ावा देना चाहिए, जिनमें श्रम की अधिक खपत है। इससे एक ओर तो रोजगार में वृद्धि होगी और दूसरी ओर सस्ते भारतीय श्रम के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा भी अधिक कठिन नहीं होगी।

गृह व लघु उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन देना भी बांछनीय है, क्योंकि, इनके द्वारा रोजगार की उपलब्धता तथा विकेंद्रित विकास दोनों ही सम्भव हैं। इनके अतिरिक्त छोटे उद्योग कच्चे माल व मशीनों के निर्यात पर भी अधिक निर्भर नहीं रहते और निर्यात में भी उनका भाग बढ़ रहा है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारत में उत्पादन व व्यापार की अनुमति केवल उसी दशा में देनी चाहिए जब कि यह प्रौद्योगिकी के सुधार के लिए अपरिहार्य हो। ऐसी अनुमति इन कम्पनियों प्रौद्योगिक हस्तान्तरण, उत्पादन में अधिकांशतः भारतीय श्रम के उपयोग तथा विदेशी विनिमय अर्जन सम्बन्धी शर्तों के साथ सम्बद्ध होनी चाहिए।

गरीबी, बेरोजगारी असमानता तथा घमी विकास दर से केवल उसी दशा में निजात पायी जा सकती है जबकि ऐसी भारतीय प्रौद्योगिकी का विकास किया जाए जिससे रोजगार विनिमय अनुपात में वृद्धि तथा पूंजी निवेश अनुपात में कटौती एक साथ हो सके। इसी प्रकार की प्रौद्योगिकी का विकास आठवीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य चुनौती होनी चाहिए जिससे सही मायने में अर्थव्यवस्था का समन्वित बिकेन्द्रित विकास हो सके तथा विकास का फल गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच सके।

मेरा यह भी सुझाव है कि एक राष्ट्रीय वेतनमान होना चाहिए। आज बिहार में मजदूरों को सबसे न्यूनतम मजदूरी मिलती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुबाह]

श्री पूर्णचन्द्र मलिक (दुर्गापुर) : सभापति महोदय, मैं श्रम एवम् कल्याण मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ।

1981 की जनगणना के अनुसार भारत के लगभग 23 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखते हैं। स्वतन्त्रता के 43 वर्षों के बाद भी अन्याय और अत्याचार के शिकार हैं। उनके लिए सभ्य जीवन के सभी दरवाजे बन्द हैं। वे लगभग सभी अनपढ़ हैं। अधिकतर ये लोग अपनी आजीविका कृषि मजदूरों के रूप में कमाते हैं। उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती। उन्हें वर्ष में केवल चार माह काम मिलता है। न्यूनतम मजदूरी की बड़ी-बड़ी बातें सिवाय मजाक के कुछ नहीं हैं। कानूनों को लागू करने के लिए सरकार की राजनीतिक इच्छा नहीं है। उनका दुःख क्या है? क्योंकि कृषि योग्य भूमि का 52 प्रतिशत भाग उन तथाकथित किसानों के पास है, जोकि जनसंख्या का केवल 10 प्रतिशत है। इन कृषक मजदूरों में अधिकतर भूमिहीन किसान हैं। एक सामन्ती समाज में जहाँ आज भी ग्रामीणों पर शासन किया जाता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकतर लोगों को इन जमींदारों और उनके गुण्डों के निरन्तर भय में जीना पड़ता है। सामान्यतः उच्च जाति के ये जमींदार लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का शोषण करते हैं। इन भाग्यहीन व्यक्तियों की कोई मानवीय गरिमा नहीं है। गरीबी में ये लोग पशुओं की तरह रहते हैं। जब ये लोग अधिक मजदूरी और अपनी महिलाओं की सुरक्षा की मांग करते हैं तो इनकी झोपड़ियाँ जला दी जाती हैं और इनकी महिलाओं का अपमान किया जाता है। कानून सदा जमींदारों की रक्षा करता है और पुलिस बल भी सदा इन्हीं के पक्ष में रहता है। अतः भूमि सुधार कार्यक्रमों के शीघ्र क्रियान्वयन की आवश्यकता है। यदि भूमि वास्तविक कृषकों के पास हो तो केवल तभी गरीब और दलित लोग साहस और मानवीय गरिमा का जीवन जीने योग्य हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में ऐसे ही अनुभव हुए हैं। उदाहरण के लिए दिसम्बर 1969 तक पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने 12,67,942 एकड़ फालतू भूमि का स्वाभिव्यक्त लिया और उसमें से 8,79,225 एकड़ भूमि भूमिहीन लोगों में बांटी। लाभ प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या 18,51,945 है;

इसमें अनुसूचित जाति के 6,84,945 और अनुसूचित जनजाति के लाभ प्राप्तकर्ता 3,51,938 हैं। बर्गा आपरेशन में दर्ज बटाईदारों की कुल संख्या 14,05,442 है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के घरों की संख्या 2,48,000 दर्ज की गई है। इसके फलस्वरूप पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजात के लोगों को प्रत्येक अधिकार प्राप्त है।

ठेका श्रमिकों की दुर्दशा और खदानों की सुरक्षा के बारे में भी मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित किया गया था, परन्तु इसे निजी क्षेत्र में लागू नहीं किया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान भी इसे लागू नहीं करते। ये एक चिरस्थायी किस्म का कार्य करते हैं, परन्तु इन्हें स्थायी श्रमिक के रूप में खपाया नहीं जाता। इन्हें पीने का पानी, चिकित्सा और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई जाती। दूसरी ओर खदानों के निजी ठेकेदार इन श्रमिकों का अत्यधिक शोषण करते हैं। इन ठेका श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी नहीं दी जाती। श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा सम्बन्धित के कानूनों के कई उपबन्धों का इन ठेकेदारों द्वारा उल्लंघन किया जाता है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि वह इसमें व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान सरकार और विशेष रूप से श्रम तथा कल्याण के युवा और गतिशील मन्त्री इस समस्या पर पूर्ण रूप से ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

श्री मानकूराम सोढ़ी (बस्तर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मन्त्री जी द्वारा श्रम और कल्याण विभाग की जो अनुदान मांगें प्रस्तुत की गई हैं उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। उसमें मैं केवल कल्याण विभाग पर ही अपना अधिक ध्यान दूंगा। खास कर उस आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में, जहाँ पर काफी कल्याण योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

उन योजनाओं में, जैसाकि माननीय मन्त्री जी ने बताया अब तक आदिवासी योजनाओं में लगभग 16 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यदि उस खर्च के अनुसार देखा जाए तो उसका कोई संतोषजनक रिजल्ट नहीं दिखता है। यह सही है कि जो योजनाएँ, जिन समाज के लोगों के विकास के लिए बनाई गई हैं, उस योजना को पूरी तरह से समझने के लिए, पूरी तरह से जानने के लिए, उनमें शिक्षा की कमी थी। शिक्षा की इस कमी को दूर करने के लिए कौनसी योजनाएँ लाभदायक होंगी, इसकी तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया, और जो योजनाएँ बनी थी, उन योजनाओं के बीच में भी बिचौलियों ने ही रूकावट डाली और इन योजनाओं में जिस ढंग से लाभ मिलना चाहिए था, उस ढंग से इसमें लाभ नहीं मिल पाया।

आज सबसे जरूरी बात यह है कि शिक्षा को हम अधिक से अधिक कारगर सिद्ध करें और यदि शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा तभी यह योजनाएँ या स्कीमें आगे बढ़ेंगी और लोगों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगी, नहीं तो यह स्कीमें सिर्फ कागज में ही दर्ज होंगी और इसका लाभ जनता को नहीं मिल सकेगा। इसमें करोड़ों-करोड़ रुपया खर्च होगा, लेकिन वह क्षेत्र बँस का बँसा ही रहेगा जैसा कि आज है। इसलिए यह जरूरी है कि शिक्षा के ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। आज शिक्षा की तरफ इस आगनबाड़ी को शुरू कर दिया है। यदि इस आगनबाड़ी पर सही ढंग से अभी से नियरानी

रखी जाए, तो बाल्य अवस्था के बच्चों के लिए जो आंगनबाड़ी में उनकी शिक्षा की तरफ, उनके स्वास्थ्य कीतरफ और उनके वर्तमान दृष्टिकोण से जो माहौल तैयार किया जा रहा है इस माहौल को यदि अच्छे रूप से तैयार किया गया तो यह स्कीम में लोकप्रिय कहलायेगी, लेकिन आज इन स्कीमों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शासन में जो योजनाएं चल रही हैं, उसमें जो अधिकारी और आफिसर हैं वह भी इन योजनाओं को सही ढंग से नहीं चला रहे हैं। इन योजनाओं में भी आज लोगों की, ग्राम की, पंचायत की, क्षेत्र की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन इसमें इनकी भागीदारी नहीं है। इसमें जो आफिसर बर्गरह होते हैं वह अपनी मनमानी से कार्य करते हैं। जो कुछ वह खरीदता है या जो भी कार्य वह करता है, उसमें वह अपनी मनमानी करता है। लोकल जो सिचुरेशन है उससे वह कोई ताल्लुक नहीं रखता है। इस स्कीम के अन्तर्गत इन लोगों की भी भागीदारी इसमें बुझे, इसके लिए भी आपको इसमें कुछ सुधार करना चाहिए, क्योंकि अभी शुरूआत है और यदि शुरूआत में ही इस स्कीम को अच्छी तरह से लागू किया गया तो पिछड़े क्षेत्रों में, दूरदराज के क्षेत्रों में, जो अज्ञातता वाले क्षेत्र हैं, उनमें यह स्कीम में लोकप्रिय कहलायेगी।

शिक्षा के लिए आज जगह-जगह पर स्कूल और कालेज खोले गए हैं लेकिन उसमें जो गुणवत्ता होनी चाहिए वह वहां नहीं है। स्कूल और कालेज खोले गए हैं लेकिन जहां स्कूल हैं वहां बच्चे नहीं आ रहे हैं और जहां बच्चे हैं वहां पर तो स्कूल का पता ही नहीं है। वहां पर बच्चे झाड़ के नीचे या पेड़ों के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी सूरत में जो स्कूल और कालेज खोले गए हैं उन्हें सक्षम किया जाए। बहुत सी जगहों पर बच्चे हैं लेकिन शिक्षक नहीं हैं, लेक्चरर पढ़ाने के लिए नहीं है, विषय के अनुसार सेटअप नहीं है। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर एक गुरु है और उसके पास पांच कक्षाएँ पढ़ाने के लिए हैं। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था में यदि आप सुधार नहीं करते हैं तो जो भी स्कीम आप इनकी भलाई के लिए बनायेंगे और यह सरकार जो करोड़ों-लाखों रुपया इसके लिए खर्च करेगी, उससे जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा।

नहीं तो आगे भी वही होगा। इसलिए इस समय शिक्षा की तरफ अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की बात है। आज शहरों में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं और लोभ इसकी सहायता से अच्छी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। बहुत से लोगों को इससे जीविका का साधन भी मिला हुआ है। आज आदिवासी क्षेत्रों में भी लोग अंधविश्वास, देवी-देवताओं को छोड़ कर आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन आज आदिवासी क्षेत्रों में, दूर-दराज क्षेत्रों में अस्पताल नहीं हैं, अगर अस्पताल हैं तो डाक्टर नहीं हैं, कर्मचारी नहीं हैं, डाक्टर हैं तो दवाइयां नहीं हैं। इसका कारण यह है कि डाक्टरों को वहां पर रहने आदि की सुविधाएं नहीं दी जाती। वहां पर जाने के लिए डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों को रहने आदि की और अन्य प्रकार की विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। यदि हम अपने आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को अंध-विश्वास से ऊपर उठाना चाहते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था करना आवश्यक है। इस तरह से आदिवासियों को स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध कराई जा सकेगी।

आज हरिजन-आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों की बात कही जाती है, इन घटनाओं में वृद्धि की बात की जाती है, जगह-जगह पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और यह आवश्यक बढेंगे। इसका मूल कारण पिछड़े वर्गों में आई जागृति है। जब इन लोगों में जागृति आयेगी तो ये अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का

बिरोध करेंगे, जब बिरोध करेंगे तो इन पर अत्याचार बढ़ेंगे। इसलिए इनके मामलों को निपटाने के लिए विशेष अदालतों का निर्माण करना चाहिए, ताकि इनको जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके और अत्याचारों पर अंकुश लग सके। इस तरह की व्यवस्था होने से पिछड़े वर्ग के लोगों को आभास होगा कि वे भी देश के साथ, दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। आज अत्याचारों की क्या स्थिति है, इसका एक नमूना देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के आदिवासी फदासी, सुन्दर लाल जाति प्रधान (आदिवासी) ग्राम बूढ़ा गांव, तहसील सिलवानी, उम्र लगभग 30 वर्ष को खेत मालिक नरेन्द्र सिंह कौरब अपने खेत में काम करने के लिए बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल करता था। बंधुआ मजदूरी से तंग आकर एक दिन वह काम छोड़ कर चला गया। उसे बुलाकर लाने के लिए खेत मालिक ने अपने भांजे मुन्ना और भतीजे सरजन को भेजा। वे उसको जबरदस्ती पकड़ कर ले आए और उसको एक पेड़ से बांध दिया और उसका एक हाथ काट कर अलग कर दिया। वह व्यक्ति अभी हमीदाबा अस्पताल भोपाल में भरती है और यह घटना 7 अप्रैल 1990 की सुबह 8 बजे की है। इस तरह के जघन्य अपराध बंधुआ मजदूरों पर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 5-10 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की है, लेकिन इससे उस व्यक्ति का कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इस तरह का अपराध करने वाले, हाथ काटने वाले अपराधी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। जिस व्यक्ति का हाथ कट गया है, उसके रोजगार और जीवनयापन की भी सरकार को उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार आरक्षण के बारे में मुझे अनेक बातें कहनी हैं। आरक्षण का अभी जो सिलसिला चल रहा है उसमें काफी प्रयास करने के बावजूद भी, आरक्षण के अभियान में लक्ष्य और प्रोग्राम बनाने के बाव भी कमी रह गयी है। आने वाले समय में बाबा अम्बेडकर के कार्यक्रम के अनुसार इसको पूरा करना चाहिए। आरक्षण नीति के तहत खाली बातें करेंगे तो यह काम पूरा नहीं होगा, इसमें पूर्ण विश्वास के साथ, नीयत के साथ काम करना होगा। जिस प्रकार माननीय मंत्री जी अपनी नीयत और विचार पैदा कर रहे हैं वैसे ही नीयत उस मशीनरी की बनानी होगी जिससे यह काम करवाना है। जो मशीनरी इसके लिए काम कर रही है उसकी नीयत भी ऐसी ही बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जो कुर्सी पर बैठता है उसका मन है, विचार है, इस काम को करने के लिए, लेकिन योजना को पूरा करने के लिए जिस मशीनरी की जरूरत पड़नी है, उसको भी ठीक करना होगा। यह देखना होगा कि शासन की भावना से, जैसा शासन चाह रहा है उसके अनुसार वह मशीनरी काम करती है या नहीं। हम भाषण देते रहें, दुःख-दयं बोलते रहें, मंचों पर रोना रोते रहें तो उससे यह पूरा होने वाला नहीं है। जो हम कहते हैं उसके अनुसार शासकीय मशीनरी को दुरुस्त करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी ने एक अच्छे संकल्प के साथ इस योजना को सम्भाला है और इसे पूरा करने का देश को बायदा दिया है। मैं तहे दिल से यह कहूंगा कि इनको इसमें सफलता मिलेगी और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले हरिजन, जो अत्याचारों से पीड़ित हैं, उनको लाभ पहुंचेगा।

श्री रामेश्वर प्रसाद (बार) : माननीय सभापति महोदय, श्रम और कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। श्रम के क्षेत्र में एक असंगठित क्षेत्र है और एक संगठित क्षेत्र है। जो अभी तक हम लोगों के सामने समस्या है, उसका कोई निष्कर्ष हम नहीं निकाल पाए हैं कि असंगठित और संगठित क्षेत्रों में कितने मजदूर काम कर रहे हैं और जो सरप्लस श्रम है वह कितना बचा हुआ है। जो सरप्लस श्रम है उसका उपयोग कहाँ कर पायेंगे, यह भी कहीं दशाया नहीं गया है। सरप्लस श्रम का कैसे बोझ हो रहा है। उन्हें कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मनिहारी व्याज में उन्हें आज भी 12 घण्टे काम करना पड़ रहा है जबकि दुनिया के देशों में श्रम के घण्टों को कम करने के लिए, इसे 6 घण्टे करने के लिए आन्दोलन चल रहा है। लेकिन

हिन्दुस्तान में 12 घण्टे उन्हें काम करना पड़ रहा है। तो हमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की यह समस्या दिखायी पड़ती है।

कृषि के क्षेत्र में हम देखते हैं कि 80 प्रतिशत जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वे कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। इनकी कोई निश्चित मजदूरी नहीं है, उन्हें कितना मिल पाएगा, कैसे अपनी जीविकोपार्जन करेंगे, कैसे अपना पेट पालते हैं और कैसे एक ही घर में सुअर भी रखते हैं, अपनी पत्नी को भी रखते हैं और स्वयं भी रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक वर्ग की यह स्थिति है। यह वर्ग आज 40 साल के बाद भी अपनी जिन्दगी बिता रहा है। उसको इस हालत से उबारने के लिए कोई नयी नीति, नयी योजना अख्तियार नहीं की जाती है। हम उसे कैसे मानवता के आधार पर तैयार कर सकते हैं, कैसे बराबरी के दर्जे पर लाकर खड़ा कर सकते हैं, यह दिखायी नहीं देता है। उनके बारे में हम रोज रट लगाते हैं, लेकिन उनको इस जिन्दगी से निकाल कर एक आदमी के बराबर खड़ा करने की जरूरत है। इसके लिए नीति बनाने की जरूरत है। एक आदमी जो सुअर के साथ रहता है, हमें आदमी और जानवर में फर्क करके उसे आदमी के दर्जे पर खड़ा करने की जरूरत है। हम देखते हैं कि यह चिन्तन के क्षेत्र में नहीं है कि हम उसको कैसे उस जगह से उठा कर इस जगह पर लाएं। जब वह काम करने जाता है, काम करवाने के लिए सामंत उसे ले जाता है और उसकी हत्या कर देता है। श्रमिक वर्ग की हत्या होती है। इससे कैसे मुक्ति दिलायी जाए? इस तरह के कानून नहीं बन रहे हैं कि उनकी जिन्दगी को गारण्टी दी जाए। जो आदमी काम करने जाता हो, उन लोगों की महिलायें काम करने जाती हैं तो उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनकी अस्मत् को लूटा जाता है, लेकिन इस तरह की चीजों को हम निकाल नहीं पाये हैं। जरूरत है इस बात की कि उन श्रमिकों की जान की गारण्टी कर सकें, उन मजदूरों की महिलाओं की अस्मत् की गारण्टी कर सकें। जो गांव में रहने वाले श्रमिक लोग हैं उनकी महिलाओं के साथ पुलिस के द्वारा बलात्कार किया जाता है और सनलाइट सेना जैसे संगठन पलामाउ, भोजपुर, रोहतास में बनाकर उन पर हमले ही हमले हो रहे हैं। आज भी गांव जलाये जाते हैं क्या यही उनकी सामाजिक सुरक्षा की बात है। अभी भी भीटा में उनके 900 घर जला दिये गये और वे लोग बिलख-बिलख कर रो रहे हैं। पाली गंज में आई० पी० एस० अधिकारी हैं जो बिहार में निगरानी विभाग में हैं उनके संरक्षण में वहां पर 80 हुरिजनों के घरों को उजाड़ दिया गया है। क्या यह समाज कल्याण की बात है, क्या यही चालीस सालों की उपलब्धियां हैं। इस अधिकारी के संरक्षण में और भी जघन्य अपराध होते हैं। ये बिहार में भागलपुर में पाली गंज निगरानी विभाग में हैं और उनके परिवार के लोग उनके संरक्षण में लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं। यह दो नम्बर के नागरिक समझे जाते हैं और इनके लिए बिहार सरकार और केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस कारण वह कैसे इस देश को अपना समझेंगे और हम कौनसी भावना उनके मन में अपने प्रति पैदा कर रहे हैं कि वह इस देश की मिट्टी को अपना समझें और इस देश को अपना समझें। आज उनको बर्हा से भगाया जा रहा है और उनकी महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। इस देश में आज भी उनको देवदासियां बनाया जा रहा है और उनके साथ भोग-बिलास किया जा रहा है। यह समाज की बनावट है और यह समाज की देन है। आदिवासियों को देवदासी बनाया जाता है धार्मिक भावना के आधार पर, मेरी मांग है कि इस पर पाबन्दो लगाई जाए और देवदासी बनाने की जो प्रक्रिया है जो छूट है उसको तुरन्त रोका जाये। तभी हम सचमुच उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर सकते हैं। क्योंकि आज वे लोग राष्ट्रीय धारा से कटते जा रहे हैं। राष्ट्र की धारा से जोड़ने की जिम्मेदारी समाज के प्रबुद्ध वर्ग की है, हम संसद सदस्यों की है, सरकार की है। अगर हम उन्हें नहीं जोड़ते हैं तो इसका दोष हम उनको नहीं दे सकते हैं। यह

बोप हमारी नीतियों का है जिनके चलते उन पर इसकी प्रतिक्रिया होती है और उनके साथ ऐसा बर्ताव होता है।

हजारीबाग क्षेत्र में आप देखें, पासवान जी भी बिहार के हैं उनकी नीति ठीक है, कानून ठीक है लेकिन ज़रूरत है नीयत ठीक होने की, वहां पर पांच दिन से मजदूरों ने रोड़ जाम की हुई है जो कोयला खदान में काम करते हैं, लेकिन बिहार की सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। आज मैं बिहार के मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव से मिला था और उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वहां गोली चला दो। जो आदमी अपने नियमित होने की बात कर रहे हैं, काम की मांग कर रहे हैं उस पर वहां के कलेक्टर और मुख्य मंत्री कहें कि गोली चला दो यह सही नहीं है, मुख्य मंत्री को उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए न कि गोली चलाने का आदेश देना चाहिए जैसाकि कलेक्टर ने कहा है। आज उनका नेचर है उत्पादन करना और वे कहते हैं कि हमें नियमित किया जाए, लेकिन ठेकेदारी सिस्टम के रहते उनको नियमित नहीं किया जाता है उनका शोषण किया जाता है। एफ० सी० आई० के गोवामों में भी इसी तरह से मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। जो एक तरह से अस्थाई मजदूर काम कर रहे हैं हम चाहते हैं कि श्रम मंत्री इन तमाम चीजों पर ध्यान दें और ध्यान देते हुए जो ठेकेदारी सिस्टम है और जो अस्थाई नेचर का काम है उसमें यह ठेकेदारी प्रथा बन्द करनी चाहिए। इसके लिए आपके कानून कुछ नहीं कर रहे हैं। ठेकेदार लोग सरकार के विरुद्ध षडयन्त्र करते हैं और उनसे जितना काम कराते हैं उतना पैसा नहीं देते हैं। हम मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए और उनको स्थाई किया जाए तथा रोजगार गारण्टी स्थाई हो जाए जिससे वह भटकें नहीं। ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के सवाल पर हम चाहते हैं कि गांव में कमेटी बने और वह कमेटी गांव के मजदूरों के सोक्रेट बैलेट से बने।

4.00 म० प०

और उस कमेटी के अन्दर एक रजिस्टर हो जिसमें यह दर्ज हो कि कोई सामान्य उस मजदूर को काम कराने के लिए ले जा रहा है, चाहे कोई किसान ले जा रहा है या बाहर ठेकेदारी में काम करने जाए या चिमनी भट्टा में काम करने जाए और चाहे कहीं भी काम करने जाए। जो उसे ले जाए उसका पूरा पता लिखा जाए और वह मजदूरी बीयर करे और वहां ले जाए। लेकिन जब उसकी हत्या होती है तो हत्या करने वाले पर एक्शन हो सकता है। इस प्रकार इस तरीके से उसपर रोक लग सकती है। जो अपना पता लिखाकर मजदूर को बाहर ले जा रहा है काम कराने के लिए, अगर उसका कोई नुकसान होता है तो वह पकड़ में आ जाएगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि इस तरह का कानून बने और इस तरह का प्राविकन हो। समाज में देखा जा रहा है कि दफा 107 और 109 में उन गरीबों को फंसाया जाता है जिन क्षेत्रों में हरिजनों की संख्या अधिक है। इसी कारण से बिहार में हरिजन काफी मात्रा में डकैत हो गए हैं या अपराधी हो गए हैं। इस सब मामले की जांच की ज़रूरत है। मेरा निवेदन है कि जिस दफा में उन गरीबों को फंसाया जाता है, इस कानून के अन्तर्गत इसको बदलने की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त पुलिस को जो मनमानी करने की छूट है, उसमें रोक लगाने की ज़रूरत है ताकि उन गरीब हरिजनों की सुरक्षा हो सके। इन तमाम बृटियों को जब तक दूर नहीं किया जाएगा, सही मायनों में उन गरीब हरिजनों और मजदूरों को न्याय नहीं मिल सकेगा जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण करते हुए देश को सही दिशा में ले जाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : सभापति महोदय, श्रम और कल्याण मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए देश में जो आज मजदूरों की स्थिति है, उसपर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। श्रीमन्, पिछले 43 वर्षों से इस देश में श्रमिक क्षेत्र के अन्दर पूरी तरह से अराजकता रही है। कानून-कायदे तो कुछ बने लेकिन सच पूछिए तो श्रमिकों को न्याय नहीं मिला। अलग-अलग उद्योगों में अलग-अलग मजदूरी तय हुई ? लेकिन मजदूरी तय करने का आधार क्या है ? आज तक जो भी सरकार रही है, वह कुछ तय नहीं कर पाई है कि मजदूरी किस आधार पर तय की जाए ? नतीजा यह हुआ कि कोयला क्षेत्र में 62/- रु० प्रति दिन, मैंगनीज खदानों में 22/- रु०, चीनी मिल में 25/- या 26/- रु० और अब ग्रामीण क्षेत्रों में 6 या 7 रुपए मजदूरी मिल रही है।

4.03 म० प०

[डा० लम्बि कुरं पीठासीन हुए]

तो इस तरह की स्थिति हमारे देश में है। यह अराजकता नहीं तो क्या है ? काम एक तरह का लिया जाता है, परिश्रम वही है। जो जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं, उनके महंगाई बही है लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी विभिन्नता, इतना अधिक भेद और इतना अन्तर, यह क्यों ? इस तरह से कहीं कोई देश चलता है। यह कहा गया है कि हम योजनाबद्ध तरीके से देश का विकास कर रहे हैं। यह कौन-सी योजना है कि मजदूरी तय करने का कोई आधार नहीं है ? किसी देश का भविष्य देश की श्रमिक शक्ति और श्रमिकों पर निर्भर करता है। अगर श्रमिकों के साथ न्याय नहीं तो वह देश कभी प्रगति नहीं कर सकता है। उस देश के उत्पादन में कभी भी वृद्धि नहीं हो सकती है और उस देश की दौलत में कभी बढ़ोतरी नहीं हो सकती है, अगर मजदूरों के साथ न्याय नहीं हुआ। तो आज इस देश के अन्दर राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार कायम हुई है और जो हमारे श्रम मंत्री हैं, उनसे बढ़कर अच्छी प्रगतिशील और क्रान्तिकारी बूझकर ब्यक्ति श्रम मंत्री नहीं हो सकता है। वे विचारों में परिपक्व हैं। श्रमिकों को इस देश में आगे ले जाने की नियत रखते हैं। वे चाहते हैं कि देश के श्रमिकों के साथ न्याय हो। इसलिए हमें और श्रमिक वर्ग को उनसे बड़ी आशाएं हैं। मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ कि देश के श्रमिकों के लिए कोई नीति बने। मजदूरी तय करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बने और उसका आधार तय होना चाहिए कि मजदूरी किस आधार पर तय की जाएगी ? यह नहीं कि जहाँ कुछ मजदूरों का दबाव हो तो वहाँ अधिक मजदूरी मिले या जिनका संगठन अच्छा हो और वे काम बन्द कर सकते हैं, आर्थिक व्यवस्था ठप कर सकते हैं तो उन्हें मजदूरी अधिक मिल जाती है। बल्कि यह तय होना चाहिए कि प्रत्येक मजदूर को उसकी आवश्यकता के आधार पर मजदूरी मिलेगी। बहुत पहले से इस विश्व में जो स्वर्णिम सिद्धान्त चला आ रहा है, अब उसी के अनुसार हमें यह तय करना होगा कि प्रत्येक मजदूर से उसकी क्षमता के अनुसार काम लिया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार उसे मजदूरी दी जाएगी। नीब वेस्ट मिनिमम वेजेज की बात हम इस देश में बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं लेकिन आज तक कुछ क्रियान्वित नहीं हुआ। इसलिए मैं अपने माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इस देश में सभी मजदूरों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन देना निश्चित किया जाए और यह नीति सभूचे राष्ट्र के लिए एक समान रूप से लागू हो। ऐसा न हो कि एक प्रान्त में मजदूरी कुछ तय की जाए और दूसरे प्रान्त में अलग मजदूरी तय की जाए बल्कि सभूचे राष्ट्र के लिए एक समान आवश्यकता पर आधारित मिनिमम वेतन तय होना चाहिए।

अभी सदन में मुझसे पूछें वक्तव्यों ने तरह-तरह के बिचार रखे, अनेक बातें कहीं। मैं मानता

हूँ कि कानून तो हमारे यहाँ पहले से ही बना हुआ है, कान्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट एबीसीशन एक्ट पहले से है, लेकिन अब समय आ गया है कि उसका विश्लेषण किया जाए। हम देखते हैं कि इस सम्बन्ध में जितने कानून बने हैं, सबका खुलमखुल्ला उल्लंघन हो रहा है। अब प्राइवेट सेक्टर में उनका उल्लंघन हो तो बात कुछ समझ में आती है, क्योंकि वे तो मनमानी करते हैं, उनके सामने तो एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमाना होता है, इसलिए वे मजदूरों का शोषण करते हैं, लेकिन इस देश में जितने पब्लिक सेक्टर के उद्योग हैं, सरकार की इण्डस्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, उनमें भी आज इस कानून का खुलमखुल्ला उल्लंघन हो रहा है। सरकार को तो एक आदर्श एम्प्लायर के रूप में, एक आदर्श नियोजक के रूप में मानने आना चाहिए। जिन कानूनों को स्वयं हमने यहाँ पार्लियामेंट में बँटकर बनाया है, यदि उनका उल्लंघन हो तो वह हम सबके लिए दुख की बात है। हमने स्पष्ट लिखा है कि यदि कहीं ठेके पर मजदूर लगाए जाएं तो मीनेजमेंट को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, तथा ठेकेदार को साइसेस लेना अनिवार्य है, परन्तु हम अपने यहाँ स्थित कोयला खदानों में देखते हैं कि कहीं इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। कोई ठेकेदार साइसेस नहीं लेता है, किसी मीनेजमेंट ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इस सबके बावजूद ठेकेदारी प्रथा चल रही है। इसके अतिरिक्त कान्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में लिखा हुआ है कि कुछ काम ऐसे हैं, जिन्हें कोई ठेकेदार अपने मजदूरों से नहीं करा सकता, जैसे रीनिंग का काम है, लोडिंग और अनलोडिंग का काम है, पत्थरों का काटने का काम है, ऐसे ही अन्य कई काम हैं, जिनका एक्ट में स्पष्ट उल्लेख है, परन्तु वे सारे काम हमारे यहाँ कोयला खदानों में, बहाँ का मीनेजमेंट ठेकेदार के मजदूरों से कराता है। कई सार्वजनिक उपक्रम हैं, दूसरे कारखाने हैं, उन सब में इस कान्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है और उनके विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। और तो और हमारे रेलवे विभाग में भी ठेकेदारों के मजदूरों से ऐसे काम कराए जा रहे हैं, जो उनसे कान्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अनुसार नहीं कराए जा सकते। इसे मैं कानून के प्रावधानों का खुलमखुल्ला उल्लंघन मानता हूँ। अब हमारे नए धर्म मंत्री जी आए हैं, मैं चाहूँगा कि वे देखें और इसकी व्यवस्था करें कि कोई अनुचित काम किसी ठेकेदारी मजदूरों से नहीं कराया जाएगा। हमारे यहाँ तो मजदूरों की स्थिति बहुत खराब है, 10 रुपये उन्हें रोज मजदूरी ठेकेदारों द्वारा दी जाती है। मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न भी किया था, तारांकित प्रश्नों में तो वह नहीं आ सका, परन्तु लिखित उत्तर मेरे पास आया है, जिसमें स्वयं मंत्री जी ने माना है कि उन्हें 10 रुपये से अधिक नहीं मिलते। मैं चाहता हूँ कि सरकार विभिन्न मजदूरों के लिए जो न्यूनतम मजदूरी तय करे, उसी मजदूरी तो कम-से-कम ठेकेदारों के मजदूरों को भी जरूर मिलनी चाहिए। आज तो स्थिति यह है कि इस अन्याय के खिलाफ यदि कहीं फरियाद की जाये तो उसकी सुनवाई नहीं होती, न्यायालयों के दरवाजे खटखटायें तो भी न्याय नहीं मिलता। हमारे यहाँ बिलासपुर में 1983 से गेबरा कोयला खदान मजदूरों का एक मामला लटकता आ रहा है और अब 1990 आ गया परन्तु आज तक वह मामला तय नहीं हो पाया। यदि चीफ लेबर कमिश्नर के यहाँ भी केस ले जाया गया तो वे भी कोई निर्णय नहीं दे पाते। इस तरह मजदूरों का शोषण हो रहा है। जहाँ उन्हें 10 रुपये रोज मजदूरी मिलती है, उनसे 18-1० घण्टे या 13-13 घण्टे काम ठेकेदारों द्वारा लिया जाता है और फरियाद करने पर कोई सुनवाई नहीं होती। आज यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने यह तय किया है कि हम मीनेजमेंट में, प्रबन्ध में मजदूरों को भागीदारी देना चाहते हैं। अब मजदूर प्रबन्ध में भागीदार बनाए जायेंगे, बॉर्ड में होंगे। मैं चाहता हूँ कि इसका निर्णय आप गुप्त मतदान के जरिए करायें। दो मांगें मजदूरों की बहुत दिनों से रही हैं : एक तो गुप्त मतदान के जरिए उनका प्रतिनिधि चुनने की और दूसरे प्रबन्ध में भागीदार बनाए जाने की। मैं तो यह भी चाहता हूँ कि मजदूरों को केवल प्रबन्ध में ही भागीदार न बनाया जाए बल्कि उन

कारखाने के मुनाफे में, उसकी आय में भी उनकी भागीदारी हो। मुझे आशा है कि वह दिन बहुत जल्दी आएगा जब यह सपना साकार होगा। मेरा विश्वास है कि वह दिन अब दूर नहीं। हमारी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार मजदूरों को प्रबन्ध में ही भागीदार नहीं बनाएगी, उसको आमदनी में, लाभ में भी भागीदार बनाया जाएगा, यूनियनों को मान्यता देने के लिए भी गुप्त मतदान प्रणाली का सहारा लेना आवश्यक है ताकि बोगस यूनियनों से बचा जा सके। प्रतिनिधि यूनियन का निर्णय गुप्त मतदान के जरिए लिया जाए। जिस तरह हम लोकसभा के लिए चुनाव कराया जाता है। वैसे ही व्यवस्था यूनियनों का प्रतिनिधि स्वरूप कराने के लिए भी गुप्त मतदान के द्वारा कराई जा सकती है। हमारे यहाँ संगठित क्षेत्र में केवल तीन करोड़ मजदूर हैं। एक करोड़ 60 लाख मजदूर पब्लिक सेक्टर में और करीब 90 लाख प्राइवेट सेक्टर में हैं और 50 लाख मजदूर दूसरे कामों पर लगे हैं। इस तरह से 3 करोड़ मजदूर हैं। इनमें से केवल एक करोड़ मजदूर यूनियन के सदस्य हैं। 38 हजार यूनियनों हैं जिनमें से 63% यूनियनों ऐसी हैं जो अपना अकाउण्ट वगैरह कुछ नहीं देती हैं। असंगठित क्षेत्र में 22 करोड़ मजदूर हैं जिनको कोई सुविधा नहीं है जिनमें से खेतीहर मजदूरों की संख्या करीब 8 करोड़ है। इनमें से 50 लाख लोग बांडेड लेबर हैं। कितनी बड़ी विसंगति है? यह कितना बड़ा अन्याय है? सारी दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक नहीं हैं। जहाँ 50 लाख लोग, अब तक, 43 वर्षों की आजादी के बाद भी बंधुआ मजदूर हों, बंधुआ के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस देश का क्या हाल होगा, यह आप स्वयं जानते हैं? इन खेतीहर मजदूरों के लिए, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए क्या मिलता है? इनके लिए न्यूनतम मजदूरी तय की गई है, वह भी हर प्रान्त में अलग-अलग है। उड़ीसा में 25 रुपए रोज हैं, तो मध्यप्रदेश में मात्र सोलह रुपए रोज नियत की गई है, वह भी मिलती नहीं है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भारत सरकार ने, आई० एल० ओ० का कन्वेन्शन स्वीकार किया था। जनता सरकार जब 1977 में आई, उसने आई० एल० ओ० कन्वेन्शन 141 में हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब तक उसका पालन नहीं हो रहा है। दिखाने के लिए आन्तरेरी रूलर आर्गनाइजर नियुक्त हैं। कोई पन्द्रह सौ रूलर क्षेत्र की यूनियनों बन रही है। जो पन्द्रह सौ रूलर आर्गनाइजर कोई पता नहीं है, वे कहां हैं क्या कर रहे हैं। इन यूनियन से सगठन का कोई काम नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह काम भी बड़ा दुर्लभ है। आगे चलकर वे संगठित हो सकेंगे (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें। समय समाप्त हो गया है।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : कृपया मुझे थोड़ा-सा समय और दें।

सभापति महोदय : मैं तो देना चाहता हूँ, परन्तु समस्या यह है कि बहुत से दूसरे सदस्य बोलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मन्त्री महोदय को भी 5.00 बजे उत्तर देना है।

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : तो श्रीमन, मैं यह कह रहा था कि इन प्राचीन क्षेत्रों या असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए हमको विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि इनकी संख्या बहुत अधिक है और इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। न इनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था है, न इनके लिए काम की गारंटी की व्यवस्था है। अब हमारी सरकार ने यह तय किया है कि काम के अधिकार का हम मौलिक अधिकार की सूची में सम्मिलित करेंगे। यह क्रांतिकारी कदम होगा, देश में ऐतिहासिक कदम होगा।

अगर एक बार यह हो गया और मुझे विश्वास है बहुत जल्दी यह हो जाएगा, काम का अधिकार संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में शामिल हो जाएगा, तो यह सिर्फ आज भर के लिए नहीं, यह सिर्फ इस सरकार भर के लिए नहीं, बल्कि अनन्तकाल तक, जब तक सूरज-बांद रहेगा, जब तक राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को याद किया जाएगा, तब तक यह रहेगा। इस देश के नौजवान हमेशा-हमेशा के लिए यह याद रखेंगे कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने काम के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल किया था।

सभापति महोदय, इसके बाद मैं थोड़े से शब्द विकलांगों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा, क्योंकि यह कल्याण मन्त्रालय है और यह विषय भी इसके अन्तर्गत आता है। श्रीमन् हमारे देश में दुनिया में सबसे अधिक नेत्रहीन हैं, यह एक बड़ी विडम्बना है। दुनिया की पांचवां हिस्सा आबादी हिन्दुस्तान में रहती है परन्तु दुनिया के एक तिहाई अंश इस देश में रहते हैं क्योंकि यह देश गरीब है, यहां कुपोषण की समस्या है। जिस देश में एक व्यक्ति के लिए प्रोटीन की दृष्टि से मात्र 40 ग्राम दाल मिलती हो, वहां अंधे नहीं होंगे, तो और क्या होगा? कोई एक करोड़ नेत्रहीन इस देश में हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? पूरे देश के अन्दर एक नेशनल इंस्टीट्यूट आफ विजुअली हैंडिकैप्ड देहरादून में स्थापित किया गया है जहां नेत्रहीनों को ट्रेनिंग दी जाती है। हिन्दुस्तान में एक करोड़ नेत्रहीनों के लिए, केवल एक नेशनल इंस्टीट्यूट, क्या पर्याप्त होगा? यह तो पुरानी सरकार की रस्म-अदायगी का काम है। उसने दिखाने के लिए यह किया था। ताकि दुनिया के लोगों को दिखा सकें कि हमारे देश में नेत्रहीनों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट है। विडम्बना यह देखिए कि उस नेशनल इंस्टीट्यूट में एक बर्ष से कोई डायरेक्टर ही नहीं है। एक नेत्रहीन, सुयोग्य डायरेक्टर थे, उनको पुरानी सरकार ने बड़े गलत तरीके से निकाल दिया और तब से वहां कोई डायरेक्टर नहीं है। इस तरह से एक उपहास नेत्रहीनों के साथ हो रहा है। इन नेत्रहीनों के पुनर्वास के लिए 11 सेंट्स पूरे देश में खोले गए थे। उन्होंने कुछ काम नहीं किया। पिछली सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद की तरफ से इनका मूल्यांकन कराया था, उन्होंने लिखा है कि ये सेंट्स कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे रीहैबिलिटेशन सेंट्स से क्या फायदा होगा? एक इंस्टीट्यूट नेत्रहीनों के लिए देहरादून में, एक मेटली रिटारिड्डेड के लिए इंस्टीट्यूट हैदराबाद में, एक आरथोपैडिकली हैंडिकैप्ड लोगों के लिए कलकत्ता में और इसी प्रकार का इंस्टीट्यूट डीफ एण्ड डम्ब (बहरे और गूंगे के लिए) बंगलौर में है। पूरे देश के लिए, अलग-अलग किस्म के लोगों के लिए केवल मात्र चार इंस्टीट्यूट खोले गए हैं, लेकिन इनमें भी कोई उपयोगी काम नहीं हो रहा है। जिस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है इसी तरह से जनता सरकार ने विकलांगों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की थी तीन प्रतिशत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में, और उस समय मैं संमद सदस्य था मैंने आवाज उठाई। तब यह आरक्षण दिया गया था। माननीय श्रम मन्त्री जी ने हमारे प्रश्न के उत्तर में बताया है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी में भी हनु आरक्षण देगे। यह आरक्षण पूरा होना चाहिए और उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के माध्यम श्रम और कल्याण मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री बामन राव अहाडीक (मुकबई दक्षिण मध्य) : महोदय, पिछले चार माह से मैं यह देख रहा हूँ कि सत्ताकण्ड दल और विपक्ष के बीच जब भी कोई समस्या उठती है तो विपक्षी सत्ताकण्ड दल पर यह आरोप लगाते हैं कि वे तो कांग्रेस से गए हैं और सत्ताकण्ड दल वाले कहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस से विद्रोह किया है। परन्तु चाहे वे कांग्रेस से गए हैं या उन्होंने विद्रोह किया है, इससे कोई अन्तर नहीं

पड़ता। अतः मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने काम करने के ढंग को बदले और पिछली सरकार की तरह कार्य न करें। कम से कम श्रम और कल्याण विषयों पर उन्हें श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, जिसमें सदन को यह बताया जा सके कि वे इन दोनों विभागों के बारे में क्या करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि प्रशासन में श्रमिकों को भागीदारी दी जाएगी। यह बहुत अच्छी बात है। परन्तु मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि मुम्बई में बहुत से कारखानों के मालिकों ने अपने कारखानों को बन्द करना और तालाबन्दी आरम्भ कर दी है। विभागीय वे अपने कार्य को आधार पर बांट रहे हैं और उस कार्य विशेष को कारखाने से बाहर विकल्प रूप में ठेके पर करवा लेते हैं। इसके परिणामस्वरूप कारखाने बन्द हो रहे हैं। 'बोम्बे मेटल वर्क्स' इस प्रकार की शरारत का ज्वलन्त उदाहरण है। ये एक प्रकार की सरकार को चुनौती है। सरकार ने इसे रोकने के क्या उपाय किए हैं? मैंने सदन में निवेदन किया है कि सरकार द्वारा, इस प्रकार की शरारत को रोकने के लिए घोषणा की जाए। कुछ सरकारी प्रतिष्ठान अपना काम निजी क्षेत्र को देना चाहते हैं और स्थान भी बदलना चाहते हैं। इसे निजी क्षेत्र को भारत इलेक्ट्रिकल कम्पनी भी महाराष्ट्र में 'तदोजा' से अपना स्थान परिवर्तित करना चाहती है। श्वेत श्याम टेलीविजन के निर्माण से इसे 10 करोड़ रुपये की आय होती है। यदि ये रंगीन टेलीविजन बनाना आरम्भ कर दें तो इससे इन्हें 100 करोड़ रुपये की आय होगी और सभी श्रमिक इग कारखाने को सहकारी आधार पर चलाने को तैयार हैं। अब इस कारखाने को निजी क्षेत्र में दिया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। यह लोगों में इस नई सरकार के प्रति गलतफहमी उत्पन्न करने का षडयन्त्र है।

दूसरे, जहाँ तक वस्त्र उद्योग का सम्बन्ध है, मुम्बई को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। आज डा० दत्ता सामन्त जैसे एक अनुभवी नेता द्वारा अखिवेकी हड़ताल करवाने से सारे उद्योग बेकार पड़े हैं और लगभग एक लाख श्रमिक आज बेकार बैठे हैं। उनकी भविष्य निधि उन्हें नहीं दी गई है। उनकी प्रेच्युटी की समस्या अभी भी लम्बित है। उनके पुनर्वास की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रुग्ण मिलों को अपने हाथ में लेने के लिए पिछली सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम का गठन किया था। परन्तु हाल ही में हमारी सरकार ने और रुग्ण मिलों को अपने हाथ में न लेने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि इसने 10 और रुग्ण मिलें अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है। हमारी सरकार इन सभी रुग्ण मिलों को राष्ट्रीय वस्त्र निगम के नियन्त्रण में क्यों नहीं ले लेती? मैंने देखा है कि ये कनाई विभाग तथा संस्करण विभाग कारखानों में हैं और बुनाई विभाग के साथ भिबंडी और इचरकरंजी में स्थापित किए गए हैं। मुझे यह नहीं पता कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम को इससे क्या लाभ प्राप्त हो रहा है परन्तु इसके द्वारा मजदूरों को रोजगार में कमी हो रही है।

श्रम विभाग का कोई भी अधिकारी इन मजदूरों की सुरक्षा के लिए सामने नहीं आ रहा है। मेरी सरकार को एक चेतावनी है। वे पता लगाएं कि क्या पिछले दस सालों में श्रम विभाग के अधिकारियों अथवा श्रम न्यायालयों अथवा श्रम अधिकारियों द्वारा मजदूरों को कोई सुरक्षा प्रदान की गई और क्या इसके लिए कोई कानून बनाया गया। अब मेरा यह निवेदन है कि इन सभी श्रम न्यायालयों के अनुभवी न्यायाधीशों अथवा श्रम आयुक्तों की एक साथ बैठक बुलाई जानी चाहिए। उन्हें अपने अनुभव द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बेरोजगारी न बढ़े।

इस सरकार को जबाहर रोजगार योजना में रुचि थी। यह योजना पिछले दस वर्षों में महाराष्ट्र में बड़ी सफल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसके पास भी काम नहीं था तथा जो भी भूमिहीन मजदूर थे, उसे कुछ न कुछ काम दिया गया। परन्तु, इसके लिए भी न्यूनतम मजदूरी तय की जानी चाहिए।

बहुत से ऐसे कानून हैं जो कि मजदूरों को दलालों यहाँ तक के सरकारी एजेन्सियों के घोषण से बचा सकते हैं। इस दिशा में कुछ नहीं किया गया। मुझे, नहीं पता कि ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का क्या बना। इस समस्या का समाधान ग्रामीण मजदूरों को व्यवस्थित ढंग से ऊपर उठाने से हो सकता है।

तीसरा मुद्दा यह है कि जहाँ तक श्रम कानूनों तथा अधिनियमों का सम्बन्ध है, जो श्रम कानून तथा अधिनियम मजदूरों के उत्थान के लिए बनाए गए हैं, उनके बारे में उनको ज्ञान नहीं है। कंसल मजदूर संघ ही इन पर विचार करते हैं। मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि कुछ मजदूर संघों के नेता पूंजीपति बन गए हैं। वे इसके लिए लड़ना चाहते हैं। परन्तु, जो कुछ लोग निष्ठावान हैं, वे यह चाहेंगे कि मजदूरों की बेहतरी हो और वे सुनिश्चित करेंगे कि मजदूर और पूंजीपति मिलकर साब चलें। उसमें कोई हड़ताल नहीं होगी। सरकार को इन नेताओं को बातचीत के लिए आमन्त्रित करना चाहिए और उन्हें विश्वास में लेना चाहिए। मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि मेरे मजदूर संघ, 'भारतीय कामगार सेना' में 550 मजदूर यूनियनों हैं। परन्तु इन्होंने कभी एक भी हड़ताल नहीं की। आप ऐसे लोगों को विश्वास में ले सकते हैं।

सदैव सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी बिलाने का आश्वासन दिया जाता है, परन्तु इस न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी तन्त्र का सर्वथा अभाव है। न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में घोषणा की जानी चाहिए।

कल्याण विभाग का मैंने विशेष उल्लेख किया था। मैं सरकार से पूरी तरह सहमत हूँ परन्तु क्या हम जातिवाद को फँसाकर लोगों का कल्याण कर सकते हैं अथवा हम आर्थिक पिछड़ेपन को आधार बनाएंगे जिससे कि प्रत्येक वर्ग के गरीब व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सके। हम इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि सभी गरीब वर्ग के लोग जातिवाद में फँस जाएँ। उदाहरणार्थ, गदीचिरोली जिले में गरीब और आदिवासी लोगों की सहायता एक विशेष धार्मिक मिशनरी द्वारा की जाती है। इसलिए वे अपना धर्म परिवर्तन करके उसी धर्म को अपना रहे हैं। सरकार को इस पर नियन्त्रण करना चाहिए। सरकार को लंगड़े लोगों, औरतों और बच्चों इत्यादि के प्रति अपनी नीति की प्रेस में घोषणा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम कुमार जूनाल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, मैं समाज के उस वर्ग की ओर इशारा के बारे में बोलना चाहूँगा जो हम सबकी खबर रखता है और जब हम ठीक काम नहीं करते तो हमारी खबर लेता है, वह है अखबारों की दुनिया के लोग। बाछाबत बेज बोर्ड बना लेकिन उसकी रिकमपेंडेशन अभी तक लागू नहीं हुई। बहुत से समाचार-पत्रों ने अभी तक बेज बोर्ड की रिकमपेंडेशन को लागू नहीं किया है। उसके अनुसार वेतन नहीं दिया है। इन्होंने त्रिपक्षीय समिति बनाने का सुझाव दिया था, ताकि इन सिफारिशों को लागू करने के बारे में ध्यान दिया जा सके, उसको सुपरवाइज किया जा सके, लेकिन वह त्रिपक्षीय कमेटी भी नहीं बनी है। न्यूज पेपर एडवलाइज एक्ट बहुत पुराना हो गया है। सभी यूनियन्स ने बार-बार मांग की है कि इसमें संशोधन किया जाए। मैं श्रम और कल्याण मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इस एक्ट को अमेड करने के लिए उचित कदम उठाए। नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स और इण्डियन फ़ेडरेशन आफ बकिंग जर्नलिस्ट्स ने बार-बार मांग की है कि रिटायरमेंट की एज को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष तक किया जाए। समाचारपत्रों में जो कर्मचारी काम करते हैं, उनको कोई मेडिकल एलाउन्स नहीं मिलता है। डी० ए० का जो प्रतिशत है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट

एम्प्लॉय के हिसाब से उनको मिलना चाहिए। हाउस-रेंट अधिकतर 15 प्रतिशत है और वह सात-आठ सौ से अधिक नहीं बनता है। दिल्ली के अन्दर रहने वाले पत्रकार को सात-आठ सौ रुपए महीने पर कंसे मकान मिल सकता है। आप खुद अन्दाजा लगा सकते हैं। इसमें सुधार होना चाहिए।

सभी बक्ताओं ने मुझसे पूर्व एक बात पर सहमति प्रकट की है कि जो यूनियन्स हैं, उन्हें गुप्त मतदान के आधार पर मान्यता प्रदान की जाए। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ और यही सही मूल्यांकन होगा किसी यूनियन के काम का कि उसका वर्कर्स में कितना नाम है। कर्मचारियों के हितों को, लेबर के हितों को बचाने के लिए सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। लेकिन साथ ही मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्रोडक्टिविटी को भी वेज के साथ लिंक करना पड़ेगा। एक ई० एस० आई० की स्कीम सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अन्दर चल रही है। मैं उसका यूनियन के तौर पर मॅम्बर रहा हूँ। मैंने देखा है, जिस भावना से उस एक्ट को बनाया था, उसका उतना लाभ छोटे वर्कर्स को, छोटे कर्मचारियों को और छोटे मधु उद्योग के कर्मचारियों को नहीं मिल पाता है। अक्सर ई० एस० आई० की डिस्पेंसरीज के बजाए बाहर जाकर वे बाजार से दवाई लेते हैं। मैं श्रम और कल्याण मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ई० एस० आई० वर्कर्स के बारे में विशेष रूप से ध्यान दें। यह समस्या बहुत अधिक है। छोटे वर्कर्स हमेशा वहाँ डाक्टरों से सही लाभ नहीं उठा सकते हैं। इस बारे में तो आम शिकायत होती है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे दो मिनट बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्री पलाई के० एम० शंभू (इदुक्की) : मैं बागान श्रमिकों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। अभी-अभी मुझे कुछ आंकड़े प्राप्त हुए हैं जिनके अनुसार भारत में 30 करोड़ कामगार हैं और उनमें से केवल दो प्रतिशत संगठित क्षेत्र में हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 98 प्रतिशत कामगार असंगठित हैं और उनके हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं। यह तथ्य मैं इसलिए उजागर कर रहा हूँ क्योंकि मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस समाज के इस अभागे वर्ग के उत्थान की कितनी बड़ी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर है।

मजदूरों के उत्थान के लिए चलाई जाने वाली प्रत्येक योजना नियोजित आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की भावना के अनुरूप होनी चाहिए। इसे आर्थिक योजना और शैक्षणिक योजना का हिस्सा बनना चाहिए। इसका वास्तविक उद्देश्य मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग और कामगार वर्ग के उत्थान के लिए अच्छी कार्य-कुशलता का विकास होना चाहिए। वर्तमान सरकार के दृष्टिकोण में कमी यह है कि उसे इस समस्या की व्यापकता का पूरा ज्ञान नहीं है। जैसा मैंने कहा है, उनकी नीति आर्थिक और शैक्षणिक योजना पर आधारित नहीं है।

बागान मजदूरों की एक या दो समस्याओं की मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि केरल राज्य में और विशेषकर मेरे चुनाव क्षेत्र इदुक्की में जोकि बागानों और बागान मजदूरों के लिए काफी प्रसिद्ध है, वहाँ पर इस पिस रहे वर्ग की समस्याएं बहुत गम्भीर हैं। 12 लाख के लगभग बागान मजदूर चाय, रबड़, इलायची और काँफी के क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। परन्तु इसका दुःखद पहलू यह है कि 15 प्रतिशत बागान मजदूरों का अपना कोई घर नहीं है और 70 प्रतिशत लोगों के पास

रहने के लिए केवल एक कमरा है। 34 प्रतिशत लोगों के कच्चे घर हैं। उनका वेतन बहुत कम है और उनकी ज़िदगी दयनीय है। आवास, अस्पताल, डिस्पेंसरी, स्कूल विशेषकर प्राथमिक स्कूल की सुविधाओं में सुधार होना चाहिए। महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन मिलना चाहिए। सापकारों हस्तकलाओं जैसे कि सिलाई, बुनाई, टोकरी बनाने इत्यादि के प्रशिक्षण का समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए ताकि कामकाजी महिलाएँ फालतू समय का सदुपयोग कर सकें। मनोरंजन की सुविधाओं का भी उचित प्रबन्ध होना चाहिए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उनके बहुत से लोग बेरोजगार हैं। उनका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस व्यापक असंगठित क्षेत्र में दिखावटी परिवर्तनों से कुछ नहीं होगा। इसके लिए सारे ढाँचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पड़ेंगे और सारे देश में मजदूरों की बेहतरी के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए जाने के साथ-साथ समुचित कानून भी बनाने पड़ेंगे।

श्री प्यारे लाल हांडू (अनन्तनाग) : सभापति महोदय सबसे पहले मैं अपने सक्रिय धर्म तथा कल्याण मंत्री, को एक मुझाव देना चाहूंगा। मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि वे एक बार जम्मू तथा काश्मीर की यात्रा करें क्योंकि भारतीय इतिहास में वे पहले ऐसे श्रम मंत्री होंगे जोकि कामगार वर्ग की समस्याएँ देखने और जानने के लिए जम्मू और काश्मीर राज्य की यात्रा करेंगे।

यह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि 1965 में बहुत से प्रतिभाशाली लोगों ने 23 श्रम कानूनों को जम्मू काश्मीर राज्य में लागू करना आवश्यक समझा था। इन नियमों को यहाँ इस तर्क पर लागू किया गया था कि इससे इस राज्य की बाकी देश के साथ एकता सुदृढ़ होगी। माननीय श्रम मंत्री को यह पता चलेगा कि 1965 में श्रम कानूनों को लागू करने के बावजूद इन केन्द्रीय कानूनों को जम्मू और काश्मीर राज्य में लागू करने सम्बन्धी प्रक्रिया आदि की अभी तक समीक्षा नहीं की गई। इस राज्य को बाकी देश के साथ जोड़ने का कभी भी प्रयास नहीं किया गया। केवल इन कानूनों को लागू करने से कोई लाभ नहीं हुआ है। यदि माननीय श्रम मंत्री जी मेरा मुझाव मान लें तो वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें बड़ा आश्चर्य होगा क्योंकि सबसे पहली बात जो उन्हें देखने को मिलेगी वह तालाबन्दी, बन्द, उद्योगों में एकाधिकार की समाप्ति तथा आतंकवाद के कारण कामगार वर्ग में फैली हुई असंगठन की भावना। मेरा यह निवेदन है कि यदि उन्हें समय मिले तो जून के महीने में एक सप्ताह के लिए वह जम्मू और काश्मीर आएँ और श्रम कानूनों को लागू करने वाले अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाएँ। इस सम्मेलन को दिल्ली में भी बुलाया जा सकता है, अन्यथा जम्मू और काश्मीर राज्य के सदस्य सदस्यों को भी इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है ताकि उन्हें समस्या की गम्भीरता का पता चल सके और तभी उसे पता चलेगा कि बस्तुतः जम्मू और काश्मीर राज्य में स्थिति कितनी खराब हो गई है। मैं यह चाहूंगा कि जम्मू-काश्मीर में एच० एम० टी० की इकाई के बन्द होने की भी वह तुरन्त जांच करें। केवल दो दिन पहले, मैं एच० एम० टी० अहाते में था जोकि जम्मू-काश्मीर राज्य में सांबंधिक क्षेत्र की एकमात्र इकाई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि औद्योगिक सुरक्षा बल के अतिरिक्त वहाँ और कोई नहीं था। जांच करने पर पता चला कि एक नोटिस बोर्ड पर लिखा था कि अगले आदेशों तक यह इकाई बन्द रहेगी, जिसमें कि 858 मजदूर तथाह हो गए हैं।

आज अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो मिल में कार्य कर रहे हैं उनके पास जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं रहा है। उनके पास जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़ने और दिल्ली में अथवा जम्मू में आने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

दूसरी महत्वपूर्ण इकाई जो बन्द पड़ी है वह पहले योग के शिक्षक श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा चलायी जाती थी। यह उनकी न्यास सम्पत्ति की एक इकाई है। वे उसे कटरा वैष्णव देवी में अनेक वर्षों से चलाते थे। यह अब बन्द पड़ी है। मैं प्रगतिशील श्रम मंत्री महोदय से उसके बन्द होने के कारणों का पता लगाने की आशा करता हूँ। वे यह बात जानकर शायद आश्चर्यचकित होंगे कि जून 1989 से उस इकाई के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। दिल्ली में गहन जांच पड़ताल कराने के बाद आप पायेंगे कि 52 कर्मचारी पिछले 11 दिनों से दिल्ली में हैं और सभी अधिकारियों के यहाँ जा रहे हैं। माननीय श्रम मंत्री महोदय को यह जानकारी भी होगी कि एक संकड़ों वर्ष पुराना उद्योग जो कश्मीर में चल रहा था और जो केवल जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए सम्मान प्राप्त करता रहा है, वह एक रेशम उद्योग था। अच्छे, बुरे अथवा मामूली कारणों से एक वर्ष पहले इसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय उन कारीगरों के मामलों की जांच करायें जो उद्योग के एकाधिकार समाप्त करने के परिणामस्वरूप बेकार हो गए हैं और पूरी तरह अस्तव्यस्त हैं।

इसके अतिरिक्त, हाल ही के घटनाक्रमों से उत्पन्न एक महत्वपूर्ण बात यह सामने आयी है कि निजी और सरकारी क्षेत्र की 80 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयां बन्द हो गयी हैं। यदि वे थोड़ा सा प्रयास करें और कारणों की जांच करायें तो उनमें से प्रत्येक इकाई को चालू किया जा सकता है। जो इकाई जम्मू-कश्मीर राज्य से बाहर के उद्यमियों द्वारा चलायी जाती हैं उन्हें उन उद्यमियों का दिल्ली में एक सम्मेलन करके और उनमें भविष्य के लिए आशा का संचार करके चालू किया जा सकता है। जम्मू-कश्मीर राज्य का होने के नाते मेरा एक विचार है कि श्रम मंत्री महोदय यदि दौरा करें तो पाएंगे कि बन्द इकाईयों में से 80 प्रतिशत इकाईयों को निश्चित रूप से चालू किया जा सकता है और शायद उससे जम्मू-कश्मीर राज्य में हालात सामान्य बनाने में मदद मिल सकती है। मुझे विश्वास है कि उनके दौरे से राज्यपाल शासन में बिल्कुल भी बाधा नहीं पड़ेगी। राज्य का शक्तिशाली प्रशासन एक सरकारी औद्योगिक इकाई के चलाने को सुनिश्चित करने की स्थिति में भी नहीं है। श्रम मंत्री महोदय यह भी देखेंगे कि जम्मू-कश्मीर राज्य में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो पर्यटन पर निर्भर रहते हैं। वर्ष 1988 में 6 लाख पर्यटकों ने जम्मू-कश्मीर का भ्रमण किया था। वर्ष 1989 में 20 प्रतिशत पर्यटक नहीं आये। इस समय पर्यटन का काम 80 प्रतिशत तक कम हो गया है। मैं श्रम एवं कल्याण मंत्री से चाहूंगा कि वे उन सामयिक श्रमिकों के भविष्य के बारे में विचार करें जो पूरी तरह पर्यटन पर निर्भर रहते हैं। यदि जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य बनाने हैं तो इन 80,000 से अधिक लोगों को कुछ न कुछ काम मुहैया कराना होगा जो पूरी तरह पर्यटन पर निर्भर हैं और जो आज श्रम मंत्री के आशीर्वाद के अतिरिक्त किसी अन्य पर निर्भर नहीं हैं। उनके दौरे से शायद स्थानीय प्रशासन को सहायता मिलेगी। मैं अन्त में जो निवेदन करना चाहता हूँ वह उन्हें भी प्रिय है अर्थात् कृषि श्रमिक के सम्बन्ध में है। कृषि श्रमिक की समस्या उतनी ही अच्छी अथवा उतनी ही खराब है जितनी कि देश के शेष भाग में है। श्रम मंत्री जब कश्मीर का दौरा करेंगे तो उन्हें रक्षा श्रमिक की वर्तमान दशा का अवलोकन भी करना चाहिए विशेषकर 'उड़ी' तहसील का जो कि पाकिस्तान की सीमा पर है। उन्हें इन लोगों के अस्त-व्यस्त जीवन को देखना चाहिए। उन्हें बिन्दा रखने के लिए उनकी सहायता की जानी चाहिए। उन्हें राज्य से

कुछ मिलना चाहिए यदि कुछ युद्ध सम्बन्धी कारणों से आज उनकी आवश्यकता नहीं है। उन्हें राज्य छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मैं उन्हें बताना चाहूँ कि छः से अधिक जो गांव युद्ध बिराम रेखा पर स्थित हैं वे पहले ही खाली हो चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप देश के श्रम मन्त्री के नाते वहाँ जाएँ और हस्तक्षेप करें और पता लगायें कि जो श्रमिक देश की रक्षा के लिए कार्य किया करते थे और कुछ युद्ध सम्बन्धी कारणों से आज उनकी जरूरत नहीं है, उन्हें कुछ राहत, छूट एवं खाद्यान्न जैसे गेहूँ मुहैया कराया जाये जिससे कि आज के हालात के बावजूद वे अपने उन गांवों को छोड़ने के लिए मजबूर न हों जो युद्ध बिराम रेखा पर स्थित हैं। इन निवेदनों के साथ मैं आपका इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बहस में हिस्सा लेने का अवसर दिया।

[हिन्दी]

डा० किरोड़ी लाल मीणा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, आज जिस उत्पीड़ित समाज के बारे में चर्चा की जा रही है, उस समाज के लिए सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की है। इस समाज की स्थिति बड़ी दयनीय है। यह समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। राजस्थान में उदयपुर डिवीजन है जहाँ आदिवासियों का प्रिडामीनेशन है, आज वहाँ पर उनकी स्थिति यह है कि चास और पत्तों का आटा बनाकर रोटी खाने के लिए उनको मजबूर होना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, आदिवासी विकास योजनाओं द्वारा करोड़ों रुपए इस इलाके के लिए भेजे गए, लेकिन उस इलाके का विकास नहीं हो पाया। आखिर इस पैसे को कौन उठार गया। 40 साल से कांग्रेस का शासन रहा, बिक्रम के नाम पर वहाँ पैसा भेजा गया, लेकिन विकास की जगह वहाँ विनाश कर दिया गया। आदिवासियों के आर्थिक विकास और सामाजिक उत्थान के लिए छठवीं पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत 454.66 करोड़ रुपए व्यय हुए, जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केवल 25.80 करोड़ रुपए व्यय किए गए। जनता शासन के दो साल के कार्यकाल में 69.75 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुल प्रावधान 348.37 करोड़ का था। जिसमें सिंचाई के लिए 130.34 करोड़ का प्रावधान था और विद्युत के लिए 72 करोड़ का प्रावधान था। सिंचाई की योजनाओं के लिए जो पैसा खर्च किया गया उससे वहाँ पर बड़े-बड़े डैम माही, जाधम, सोम कामवा, सोमकामला और अम्बा जैसे इरीगेशन प्रोजेक्ट बन कर तैयार हो गए। लेकिन इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के कारण वहाँ आदिवासी डिम्प्लेमड हो गए। उनकी रिप्लेसमेंट करने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। वहाँ पर जितनी भी भूमि इनसे सिंचित होगी उस भूमि को गैर-आदिवासी लोगों ने कब्जा लिया है और आज आदिवासी इधर-उधर भटकता फिर रहा है। आदिवासियों की दशा वहाँ पर दयनीय है।

माननीय सभापति जी, अभी कुछ दिन पहले भूय से एक पीड़ित एक बच्चे को कोटला तहसील में एक महिला जंगल में छोड़ आयी। उस बच्चे को भेटिया उठा कर ले गया और खा गया। यह स्थिति आदिवासियों की है। वहाँ पर विकास के नाम पर जितना भी पैसा गया उसका यूटीलाइजेशन सही ढंग से नहीं हुआ। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, आप हमारे इलाके में जाकर देखें, जहाँ पैसा तो चला गया है, उद्योग की दृष्टि से फासफोस कंसंट्रेशन प्लांट लग गया है, लेकिन बड़ा अफमोम और ताउजुव होता है कि सबटाईबल प्लान का पैसा बड़े-बड़े प्रोजेक्ट और इन्फ्रस्ट्रक्चर पर लगा दिया गया है। उससे आदिवासियों को कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके कारण उस इलाके में अंततः

पैदा हो रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो भी योजना केन्द्र सरकार की वहाँ गयी और जो विचाराधीन है, उससे आदिवासियों को कतई फायदा नहीं हुआ है। इस पैसे को वहाँ पर वहाँ के लोग कांग्रेस के लोगों के साथ मिल कर खा गए। इसकी जांच होनी चाहिए।

वहाँ पर शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरा हुआ है। शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान की औसत साक्षरता 34.38 प्रतिशत है। लेकिन अनुसूचित जनजाति के लोगों की साक्षरता दर 10 प्रतिशत है, वह भी सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी तक। जिसका परिणाम यह हुआ है कि एक भी आई० ए० एस० आफिसर या आई० पी० ए० एस० आफिसर ट्राईबल एरिया से बन कर नहीं आया। हमारे साथ पक्षपात किया जाता है। ट्राईबल एरिया सवाईमाधोपुर, जहाँ की भूमि समतल है, पानी की प्रचुर मात्रा होने के बावजूद वहाँ बड़े-बड़े प्रोजेक्ट नहीं लगाए गए। वहाँ का आदिवासी इस संसद में हो सकता था, उसका विकास हो सकता था, खेती के द्वारा वह अपना आर्थिक उत्पान कर सकता था।

आजकल अधिकारियों की मिली-भगत से ठेकेदार वनों को काट रहे हैं। जहाँ आदिवासियों का वन पर अधिकार था, उस वन को बुरी तरह से काट कर उसका सत्यानाश कर दिया। जो योजना आदिवासियों के लिए बनी थी उसका सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आदिवासी इलाके हैं, वहाँ वनों पर आदिवासियों का कब्जा होना चाहिए। वहाँ वनों को खड़ा करें और इसके मालिक बनें। सरकार को ऐसा प्रावधान रचना चाहिए। केन्द्रीय सरकार की आई० आर० डी० पी० और एन० आर० ई० पी० जैसी योजनाएँ हैं, लेकिन इन योजनाओं में भी भारी भ्रष्टाचार फैला है। और आदिवासियों को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिल पाया। हमारे श्रम कल्याण मंत्री ने बड़ी अच्छी घोषणा की है और अच्छी नीयत के साथ उसको लागू करने की बात भी कही है, लेकिन आज की स्थिति देखने में बड़ी दयनीय लग रही है। जसां तक बैंकलाग का मामला है आरक्षण के पवों का तो उस बैंकलाग को नहीं भरा गया है। पिछली सरकार ने इसको भरने के लिए एक विशेष अभियान चलाया था, लेकिन वह केवल चुनावी प्रोपेगंडा था और चुनावों में फायदा लेने की दृष्टि से इसका प्रचार किया गया था। मैं सरकार से मांग करूँगा कि आप इस पर विशेष ध्यान दें और विभागवार्डज तथा सेवावाइज सूची प्रकाशित की जाये जिससे झोंपड़ी में बैठे आदिवासी को पता लग जाएगा कि मेरा बच्चा 10वीं कक्षा पास है तो उसको नौकरी मिलेगी या नहीं। इस विशेष अभियान से उसको फायदा मिल सकेगा और आपको इसके लिए पूरा प्रयास करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम, 1989 सरकार लेकर आई है, आपने हमें प्रोटेक्शन दिया, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों ने इसे सख्ती से लागू करने का प्रयत्न किया तो उसका परिणाम यह हुआ कि उनको वहाँ से हटा दिया गया, सबर्ण जाति के अधिकारी एक हो गए। इसलिए सरकार सख्ती से कदम उठाये कि कोई भी अधिकारी हो चाहे सबर्ण जाति का हो या कोई और हो इस प्रकार से अनदेखी करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जितने शिङ्गूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के डोमिनेटिड जिले हैं, वहाँ जिला मुख्यालयों पर आप अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारी नियुक्त करें...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आप भाषण समाप्त कीजिए। सायं 5.00 बजे मंत्री महोदय को

जबाब देना है और अनेक ऐसे सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

हां, श्री सुकदेव हासवान बोलें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री पासवान का नाम पुकारा है। माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं उसे कार्यवाही बृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)*

4.53 म० ५०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, अम एवम् कल्याण मंत्रालय की बांधों का मैं समर्थन करता हूँ। माननीय पासवान जी इस विभाग के मंत्री हैं, 1973 से लेकर अब तक जितनी बार भी वह संसद में आए, उस वक्त से आज तक संसद के बाहर और भीतर हरिजनों और आदिवासियों तथा कमजोर वर्गों के लिए उन्होंने हमेशा अपनी आवाज बुलन्द की और जहाँ भी हरिजन आदिवासी लोगों पर अत्याचार हुए वहाँ वे गये और उसका सबंक्षण किया। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की ग्रामीण इलाकों में बड़ी दयनीय स्थिति है, यह कहने से बाहर की बात है। अभी भी ग्रामीण इलाकों में अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति के बच्चे जमींदारों के यहां, बड़े-बड़े मिल मालिकों के यहां नौकरी करते हैं और उनकी उम्र सात बरस से लेकर बारह बरस तक होती है। वे स्कूल नहीं जा पाते हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राईब्स के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए और सरकार की ओर से उनके लिए पूरी व्यवस्था की जाए उन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर मास्टर डिग्री तक की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए और इसकी व्यवस्था सरकार करे। दूसरा, अभी तक हरिजन आदिवासियों पर जो अन्याय एवं अत्याचार हो रहे हैं और ये गत 40 वर्षों से होते आए हैं, ये अभी भी देश के हर भाग में बरकरार है। जिस सरकार द्वारा हरिजन आदिवासियों को जमीन का पट्टा दिया गया है, उसे अभी तक कब्जा नहीं मिल रहा है। यह कब्जा तभी मिल सकता है जब सरकार की तरफ से भरपूर सभी दृष्टिकोण से उसे मदद दी जाए। यदि उसे आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप से मदद मिलेगी तो उसके बाद ही उन लोगों को जमीन का कब्जा मिल सकेगा अन्यथा उनको कब्जा कभी नहीं मिल सकेगा ?

मैं एक और बात यहां कहना चाहूंगा कि देश के हर प्रदेश में और खासकर दिल्ली में, पासवान जाति जो अनुसूचित जाति के अन्दर आती है, उसको अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं रखा गया है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि जब वे संसद में चुनकर आये वे तो उन्होंने तत्कालीन

*कार्यवाही बृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरकार से मांग की थी कि पासवान जाति को अनुसूचित जाति की सूची में रखा जाये और इसमें विलम्ब न किया जाये परन्तु ऐसा आज तक नहीं हुआ है। विगत 40 वर्षों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर करोड़ों रुपयों की योजना बनायी गयी और खर्च के नाम पर मात्र 20 से 25 प्रतिशत गाँव में किया गया। मैं सरकार से और खासकर माननीय श्रम मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ भी शूडरूळ कास्ट और शोडरूळ ट्राईब्स के लिए कोई योजना बने, वहाँ एक ऐसी समिति बनायी जाए कि शतप्रतिशत सरजमीं पर खर्च हो। बस इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

4.55 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

ग्यारहवाँ प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का ग्यारहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा तय किया गया है, वर्ष 1990-91 के बजट की बकाया सभी अनुदानों की मांगों को आज सायं 6.00 बजे बिना चर्चा के पारित कर दिया जाएगा। इससे सम्बन्धित विनियोग विधेयक पर उसके बाद चर्चा की जाएगी। विनियोग विधेयक पारित करने के बाद वित्त विधेयक 1990 को आज चर्चा के लिए लिया जाएगा और सदन की कार्यवाही 8.00 म० प० तक चलेगी।

अब मैं माननीय मंत्री महोदय से उत्तर देने का अनुरोध करता हूँ। परन्तु समय का नितान्त अभाव है आप 5 बजे आरम्भ करें और इसे 6 बजे तक पूरा कर दें न दो मिनट पूर्व न दो मिनट बाद।

[हिन्दी]

श्री आरिफ बेग (बेतूल) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने पूरी बहस सुनी है। इससे पहले कि मंत्री जी जवाब दें, मैं एक जरूरी विषय की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसा कि मालूम है कि यह बालिका वर्ष है लेकिन देश के अन्दर 20 लाख बेश्याओं में से 20% बेश्याएं बालिकाएं हैं। यह एक ऐसा गम्भीर मामला है जिसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, हर वर्ष बीस हजार छोटी उम्र की बेटियां नेपाल से लाकर इस शर्मनाक धंधे में डाल दी जाती हैं। इसलिए मैं श्रम और कल्याण मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस धंधे को और तबाहकुन धंधे की तरफ ध्यान दें और हमारे देश की इन कम उम्र की बेटियों को तबाह होने से बचाएं। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। (व्यवधान)

5.00 ब० प०

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं, इस प्रकार से नहीं चल सकता कि हर आदमी उठकर बोलने लग जाए तो कैसे काम चलेगा ।

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : उपाध्यक्ष जी, मैं ज्यादा से ज्यादा दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा । हमारे यहां एक बर्न कम्पनी है जो राष्ट्रीय उद्योग होते हुए भी, यूनिट को क्लोजर करने का नोटिस दे चुकी है । आज तक एक पैसे का उस उद्योग ने पूंजी नियोज नहीं किया । अनेक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होते हुए भी कामयाब नहीं कर रहे, इसमें मजदूरों का क्या कसूर है ।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० बामस (मुबलपुजा) : महोदय, मुझे केवल एक बात कहनी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अन्यथा यह चर्चा समाप्त नहीं होगी । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से नहीं चल सकता ।

[अनुवाद]

कृपया अपने स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बामस जी, आप स्थिति को समझ सकते हैं । यह जरूरी नहीं है ।

[हिन्दी]

इसीलिए मैंने उनको भी बोलने का मौका नहीं दिया ।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० बामस : मैं केवल दो मिनट अथवा ठीक एक मिनट का समय लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय नहीं दे सकता । ऐसे यह चर्चा समाप्त नहीं होगी । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अन्यथा, मुझे दूसरी माननीय महिला सदस्य को बोलने की अनुमति देनी होगी ।

(व्यवधान)*

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री धामस जी जो कुछ कहते हैं उसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय, श्री पासवान बोलें।

5.02 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91

श्रम मंत्रालय

और

कल्याण मंत्रालय—(जारी)

[हिन्दी]

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने श्रम और कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांगों पर होने वाली चर्चा में भाग लिया और अपने सुझाव दिए। निश्चित रूप से उनके सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। जो माननीय सदस्य इससे बंचित रह गए हैं, जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग नहीं लिया, उनसे मैं इतना आग्रह करना चाहूँगा कि यदि उनके कुछ प्वाइन्ट्स छूट गए हों उनके सुझाव छूट गए हों, चूंकि हमारे सामने समय की पाबन्दी है, एक निश्चित समय में मुझे अपने दोनों मंत्रालयों के सम्बन्ध में उठाए गए बिन्दुओं का उत्तर देना है, ऐसी परिस्थितियों में वे सुझाव मुझे लिख कर भिजवा दें, हम निश्चित रूप से उन पर कार्यवाही करेंगे और सम्बन्धित माननीय सदस्य को सूचित करेंगे, यह मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ। जैसाकि आप जानते हैं श्रम और कल्याण मंत्रालय दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और इस देश की लगभग 85 फीसदी या 90 फीसदी भाग की समस्याओं को डील करते हैं, उनकी समस्याओं से सम्बन्धित हैं। यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि इन दोनों मंत्रालयों को जितना महत्व दिया जाना चाहिए था, उतना महत्व नहीं मिल सका। उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। उपाध्यक्ष जी के आदेश हैं कि समय या अभाव है, इसलिए मैं दोनों मंत्रालयों से सम्बन्धित बिन्दुओं की एक साथ लेकर चलूँगा। यदि मैं दोनों मंत्रालयों को अलग-अलग लेता हूँ तो उसमें काफी समय लग जाएगा। मैं जानता हूँ कि 6 बजे से पहले मुझे खत्म करना है।

यहाँ कई माननीय सदस्यों ने इस देश के मजदूरों की विभिन्न समस्याओं और श्रम मंत्रालय के सम्बन्ध में अपने विचार रखे। मुख्य रूप से हमारे सामने 7-8 बिन्दु ही उभरकर आए हैं। जैसाकि सारा सदन जानता है इस देश में दो तरह के मजदूर हैं—कुछ मजदूर तो संगठित हैं, परन्तु कुछ असंगठित मजदूरों की समस्याएँ भी अलग-अलग हैं और समस्याओं के साथ-साथ दोनों की बारगेनिंग कंपैसिटी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

भी अलग-अलग हैं। आज संगठित क्षेत्र के मजदूरों में इतनी ताकत आ गयी है कि वे थोड़ा लड़कर अपने हक लेने की स्थिति में हैं, हालांकि अब भी उन्हें पूरे हक नहीं मिल पाए हैं और यहाँ श्री ए० के० राय जी जो कुछ बतला रहे थे, मैं उनकी भावना को समझ रहा था। फिर भी, उनमें इतनी ताकत अवश्य है कि वे प्रभावी ढंग से अपनी मांगों को रख सकें, अपनी मांगों को मनवाने के लिए बहुत हद तक सक्षम भी हैं। दूसरी तरह के मजदूर असंगठित क्षेत्र में हैं, उनमें अभी वह ताकत पैदा नहीं हो पायी है कि वे प्रभावी ढंग से अपनी मांगों को रख सकें, तथापि जैसा अभी हमारे एक साथी ने कहा, जहाँ तक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रश्न है, इसमें सेो तरह की बातें हैं : पहला तो यह कि मिनिमम वेजेज बहुत ही कम है। बहुत से साथियों ने इस राय को उठाया है कि पूरे देश में एक तरह के मिनिमम वेजेज क्यों लागू नहीं करते हैं। इसका मतलब यह होगा कि संगठित मजदूर हैं, उनके लिए भी हो, लेकिन आप जानते हैं कि बिहार में आज भी रिपोर्ट्स आती हैं और कई दूसरे भी प्रदेश हैं जहाँ दो रूपाया रोज मजदूरी पर भी कुछ दिन पहले तक काम करना पड़ता था। मिनिमम वेजेज 1987 में हमने तय किए थे कि कम से कम 11 रू० होने चाहिए, जो बहुत ही कम था, वह भी लागू नहीं होता है। वहीं दूसरी जगह पंजाब या हरियाणा में इसकी तुलना में तीन गुना अधिक मजदूर की मजदूरी तय है। इसलिए एक तो मजदूरी कम तय होती है, दूसरे यह है कि जो भी मजदूरी तय होती है, उसको लागू नहीं किया जाता है। अभी हमने तय किया है कि जो महंगाई बढ़नी है, उसके अनुसार, हर साल के बाद उसी अनुपात में यह मिनिमम वेजेज भी बढ़ाना चाहिए और अभी हमने निर्णय लिया है कि जो मिनिमम वेजेज होगा वह पंद्रह रूपाया से ज्यादा होना चाहिए, जो सरकार चाहे, वह इससे ज्यादा दे सकती है लेकिन इससे कम नहीं दिया जाएगा।

श्री शोपत सिंह मन्कासर (बीकानेर) : कम से कम 30 रुपए तो होनी चाहिए।

श्री राम बिलास पासवान : इसमें हमारे सामने कठिनाई यह है कि मजदूरी न तो केन्द्रीय सरकार देती है और न लेबर मिनिस्ट्री इसको लागू करती है। अभी हमारी जो आई० एल० सी० हुई थी, इण्डियन लेबर कॉन्फरेंस, वह सबसे बड़ी होती है। उसमें जितने भी ट्रेड यूनियन के प्रशस्ति प्राप्त नेता हैं, वे रहते हैं और फिर सरकार के पक्ष के लोग भी रहते हैं और उसमें राज्यों के श्रम मंत्री भी रहते हैं। वहाँ सब लोगों ने बैठकर जो तय किया था वह : 4.25 रुपए था। जब यह फाइल हमारे मंत्रालय के पास आई, तो मैंने कहा इसको 15 रुपए होना चाहिए। 14 रुपए 25 पैसे नहीं। यह न्यूनतम मजदूरी है, लेकिन यह बन जाती है अधिकतम। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मजदूरी वहाँ के हिसाब से दी जाती है।

श्री शोपत सिंह मन्कासर : राजस्थान में चौदह रुपए है।

श्री राम बिलास पासवान : हरियाणा में 33 रुपए है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह घटकर 15 रुपए हो जाए। बल्कि उसी अनुपात में यह मजदूरी और बढ़नी चाहिए। वहाँ का जो मिनिमम वेजेज है, वह बढ़ेगा, लेकिन किसी भी राज्य की सरकार को 15 रुपए से कम नहीं देना चाहिए इसके लिए मैं प्रत्येक राज्य को लिख रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन बीजों के सम्बन्ध में, मैं हमेशा लोकसभा के भीतर और बाहर कहवा आया हूँ। मैंने कहा है कि संगठित मजदूरों की समस्याओं के सम्बन्ध में बराबर चर्चाएँ होती रहीं हैं। इसके साथ मैंने यह भी कहा है कि श्रम में मजदूरों की सहभागिता हो। इसके सम्बन्ध में, हम पार्लियामेंट में एक विधेयक लाने जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में, मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता

हूँ और आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस वर्तमान सेशन में प्रबन्ध में मजदूरों को सहभागिता हो, विधेयक पेश कर दिया जाएगा। कॅबिनेट से जो भी फार्मलिटोज़ होनी चाहिए थी, वे सब पूरी हो गई हैं। बोर्डे-बहुत विलम्ब का कारण, जैसाकि आप जानते हैं यह रहा कि विधेयक आने के पहले यह हर खंत्ता-लय के पास गया, ला-मिनिस्ट्री के पास गया, ये सारी चीजें अब हो गई हैं और हम इसी अधिवेशन में उसे पेश करने जा रहे हैं। दूसरी बात लेबर पार्टिसिपेशन मॅनेजमेंट के सम्बन्ध में, बताया थी, जब कुमारमंगलम जी बोल रहे थे, उस समय भी दो-तीन चीजों के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था। उसमें एक तो यह था कि मॅनेजमेंट में लेबर की पार्टिसिपेशन प्रत्येक स्तर पर हो—फ्लोर स्तर पर, प्लांट स्तर पर और बोर्ड स्तर पर। जो मजदूर प्रतिनिधि हैं, वे सीक्रेट बैलट के द्वारा चुने जाएं। एक सवाल हमारे साथी ने उठाया था कि ट्रेड यूनियनों को रिकग्नीशन के लिए अलग से बिल लाएं। ट्रेड यूनियन की रिकग्नीशन भी सीक्रेट बैलट के द्वारा होनी चाहिए।

उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। जो लेबर पार्टीसिपेशन इन मॅनेजमेंट है, उस पर कानूनी बाध्यता होनी चाहिए, एक बार जो निर्णय हो जाए फिर चाहे मॅनेजमेंट हो या मजदूर पक्ष हो, दोनों में से किसी को भी उसमें से हटाना नहीं चाहिए। इसको प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में लागू किया जाए। इसके अलावा मजदूर का क्लंबिटव बारगेनिंग है ट्रेड यूनियंस का, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, कोई ऐनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। यह चार-पांच मुख्य चीजें हैं जिनके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि हमने एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी किया था। इसके अलावा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, त्रिवेन्द्रम, यू० पी०, मध्यप्रदेश, इन तमाम जगहों में भी सेमिनार करके एक आम सहमति की गई थी और उसके आधार पर सरकार काम कर रही है।

श्री सन्तोष मोहन बेब (त्रिपुरा-पश्चिम) : नार्थ ईस्टर्न में भी आइए।

श्री राम बिलास पासवान : आपके यहां भी चलेंगे। 19 तारीख को लेबर सॅक्रेटरीज कान्फ्रेंस हुई, 20 तारीख को लेबर मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस हुई थी, 21-22 को आई० एल० सी० की इण्डियन लेबर कान्फ्रेंस हुई थी। उसमें हमने सारे मुद्दों को रखा था और वहां पर भी इसमें अनुमति मिल गई।

माननीय सदस्यों ने एक मामला असंगठित मजदूरों के सम्बन्ध में उठाया था। काफी सदस्यों ने इसके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए। अभी सोठी जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने अपने यहां ट्राईबल लोगों का अत्याचार या उनके सम्बन्ध में जो घटनाएं घटती हैं उस सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट किया था। मैं ऐसे माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ जिनकी एप्लीकेशन मेरे पास आई हैं, हम उस सम्बन्ध में कार्यवाही तो करेंगे ही साथ-साथ हम बताना चाहते हैं कि असंगठित मजदूरों के बारे में भी सरकार चिन्तित है। ट्रेड यूनियन के लीडर के साथ और आई० एल० सी० की बैठक हुई थी उसमें भी मैंने कहा था कि चाहे संगठित मजदूर हो या असंगठित मजदूर हो, हम असंगठित को किसी भी रूप में संगठित मजदूर से कम दर्जा नहीं देना चाहते हैं। दो तरह के असंगठित मजदूर हैं। एक असंगठित मजदूर जो कंसट्रक्शन लेबरर है, दूसरे असंगठित मजदूर लैबर्स लेबरर हैं, खेतीहर मजदूर के नाम से जाने जाते हैं, इन दोनों की समस्याएं भयावह हैं। जहां तक खेतीहर मजदूर की समस्या है, उसक लिए हम लोगों ने तय किया है कि हम एक सेन्ट्रल लैजिसलेशन लाएंगे। गीता मुखर्जी यहां पर बंठी हुई हैं। इस सम्बन्ध में काफी जगह पर सेमिनार भी हुए, इन्होंने भी किए थे। सब जगह यह डिमांड शुरू से रही है कि जो खेतीहर मजदूर हैं उनके लिए सेन्ट्रल लैजिसलेशन बने और उसमें कम से कम उनकी कंडीशन तय की जाए, फिर उनके लिए बॅल्फेयर के तरीके अपनाए जाएं और इसके साथ-साथ इम्प्लायमेंट की

भी गारन्टी हो। कल रामबहादुर भाई बोल रहे थे। एक बात देखने को मिलती है कि जो मजदूर काम करते हैं उनके पास इतनी कंपैसिटी नहीं है कि मालिक से लड़कर अपना मिनिमम वेजेस ले सकें। गांधी में यह देखा जाता है कि कोई भी मजदूर जब काम करता है तो तीन महीने काम करता है, नौ महीने उसको बेकार बैठे रहना पड़ता है। खेत का मालिक, भूमिपति, जमींदार कहता है कि तुमने तीन महीने काम किया, इसकी न्यूनतम मजदूरी ले लो, फिर नौ महीने हम तुमसे काम नहीं लेंगे। उस स्थिति में मजदूर कहीं पर कम्प्लेंट नहीं कर पाता है। हमारे साथी बार-बार कहते हैं कि श्रम मंत्रालय यह क्यों नहीं करता है, श्रम मंत्रालय वह क्यों नहीं करता है। जितने भी माननीय सदस्य हैं, चाहे किसी भी दल के हों, आज खुशी की बात यह है कि जितनी भी मेजर पोलिटिकल पार्टीज हैं, कहीं न कहीं सबकी अलग-अलग राज्यों में सरकारें हैं। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार की मंशा है अपनी-अपनी जो राज्य सरकारें हैं वे यदि उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो कोई मेजर समस्या नहीं रह पाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत सरकार के श्रम मंत्री की हैसियत से चाहे मिनिमम वेजेस एक्ट हो चाहे कोई भी कानून हो, हम उस कानून को सिर्फ यहाँ से पास करते हैं कुछ ऐसे हैं जिनको राज्य सरकार की अनुमति के आधार पर करना पड़ता है। उसके लिए हमें राज्य सरकार के ऊपर निर्भर होना पड़ता है।

अभी न्यूनतम मजदूरी कानून है। यदि हम कल को सेन्ट्रल लैजिसलेशन बना देते हैं और उसमें यह कह देते हैं कि साल भर मजदूरों को काम मिलेगा तो वह कैसे मिल सकता है। जितने दिन खेत में मजदूर काम करेगा उतने दिन तक वह करता रहेगा लेकिन जिन दिनों उसे खेतों में काम नहीं मिलेगा तो ऐसे में वह हमसे काम की मांग करेगा। ऐसे में पहले सरकार को उसके लिए काम की व्यवस्था करनी होगी चाहे नहर खुदवा कर हो, चाहे रोड बना कर हो और चाहे तो दूसरे मध्यमों से हो। इसलिए जब तक हम बैकल्पिक काम की व्यवस्था नहीं करते हैं तब तक कानून को लाना मुश्किल है। आज हमारे मजदूर इतने संगठित नहीं हैं और न ही उनके पास इतनी ताकत है कि वह जाकर मालिक से अपनी मजदूरी मांग सकें। इसके लिए हम कौशिश कर रहे हैं और हमने योजना आयोग से भी बात की है कि वह बैकल्पिक काम की व्यवस्था करे। जब मजदूर को यह मालूम हो जाएगी कि हमें जब खेत में काम नहीं मिलेगा तो रोड में या दूसरी जगहों में काम मिल जाएगा तो ऐसे में वह बैंक में या किसी फंड में अपना पैसा जमा कराने के योग्य हो जाएगा। ऐसे में वह पैसा केन्द्र और राज्य सरकार जोड़ना शुरू कर देगी। वह सारी समस्याएँ हैं जिनका जिक्र हमारे साथियों ने किया।

बाल श्रमिक का मामला है। इसे हम कानून बनाकर हल नहीं कर सकते। कानून में इतना ही है कि जितने भी खतरनाक उद्योग हैं, माइंस है वहाँ हम उसको काम पर नहीं लगा सकते हैं। बहुत से माननीय सदस्यों की जानकारी में शायद यह बात हो या न हो लेकिन 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के ऊपर टोटली बैन नहीं लगा सकते। उसमें इतना ही है कि वह काम उन जगहों में नहीं कर सकते हैं जो खतरनाक किस्म की हैं। इसके लिए अलग-अलग एरिया बना दिए गए हैं और उसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वहाँ काम नहीं कर सकते हैं। चाय की दुकान या दूसरी जगहों में काम करने में मनाही नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अब इसको कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री राम बिलास पासवान : अगर कहीं कोई लड़का काम करता है तो उसको देखने के लिए लेबर इन्स्पेक्टर जाता है तो कोई उससे शिकायत करने के लिए तैयार नहीं होता है। आज तक की

तारीख में न तो फ़लां लड़का और न ही उसका बाप शिकायत करने के लिए तैयार होता है। बाप के दिमाग में होता है कि लड़का कुछ पैसा लाकर देता है और लड़का यह सोचता है कि यदि वह काम नहीं करेगा तो उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। जो सरकार ने घोषणा की है कि काम के अधिकार को संविधान के मूल अधिकार में जोड़ा जाए, यह एक बहुत बड़ा विषय है। इस विषय पर विचार करने में योजना आयोग और दूसरे तमाम मन्त्रालय लगे हुए हैं। इसको बर्क आउट किया जा रहा है। यदि हम खेत में काम करने वाले मजदूर को साल भर काम करने की गारण्टी दे देंगे तो भीख मांगने वाला बच्चा सड़क पर भीख नहीं मांगेगा और चाय की दुकान पर चाय पिलाने वाला लड़का चाय पिलाने का काम नहीं करेगा। ऐसी व्यवस्था करने से 90 परसेन्ट तक हम इसको रोक सकते हैं। आज कोई बाप यह नहीं चाहता कि उसका बेटा चाय की दुकान पर चाय पिलाए और कहीं जाकर भीख मांगे। उसके सामने गरीबी का मामला जुड़ा हुआ है जिसके कारण उसे अपने बच्चे को चाय की दुकान पर काम करने के लिए भेजना पड़ता है। जिस समय उसके पास पैसा आ जाएगा और परचेजिंग पावर आ जाएगी मैं समझता हूँ कि यह समस्याएँ बहुत दूर तक हम रोक सकेंगे।

हमारे काफी साथियों ने बांडेड लेबर के बारे में जिक्र किया। अभी हमारे पास जो आंकड़ा उपलब्ध है उसके अनुसार 2 लाख 43 हजार बांडेड लेबर की शिनाख्त हो चुकी है। अधिकांश लोगों का पुनर्वास कर दिया गया है। जो सबसे बड़ी बात बांडेड लेबर का पता लगाने की है वह हमने राज्य सरकार के ऊपर छोड़ रखा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एस० पी० के ऊपर सारी की सारी इसकी जवाबदेही है। अभी कुछ दिन पहले बांडेड लेबर के सम्बन्ध में यहाँ एक सेमिनार हुआ था। उस सेमिनार में हम भी गए थे, वहाँ इस पर एक सुझाव आया था कि इसके सम्बन्ध में एक कमिशन बनाया जाए और उस कमिशन को ही अधिकार दिया जाए, अधिकार प्राप्त कमिशन हो। वह कमिशन पता लगाने का काम करे और वही उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे।

हमारे कुछ साथियों ने कन्स्ट्रक्शन लेबर के सवाल को उठाया था कि जो मजदूर शहरों में काम करते हैं, एक तो दिल्ली का ही उदाहरण दिया था और दूसरी जगहों पर भी जो मजदूर काम करते हैं, उन मजदूरों के न तो काम के घण्टे तय रहते हैं और जो मजदूर काम करने के लिए जाता है उसके पास कोई प्रमाण भी नहीं है कि यदि उसका हाथ टूट जाए, पांव कट जाए या मर जाए तो फिर मजदूर किसके पाम कम्प्लेण्ट करे। कम्प्लेण्ट करने वाली एगॉरिटी भी यदि जाती है, अधिकारी जाता है तो अभी तक का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत कागज मालिक के पास में ही रहता है, मजदूर के पास नहीं रहता है। इसका नतीजा यह होता है कि मजदूर को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसके लिए एक नेशनल कम्प्लेण्ट कमेटी की एक रिकमेण्डेशन आई थी, जस्टिस कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी थी, उसने कहा था कि एक बोर्ड बनाया जाए, उस बोर्ड की यह जिम्मेवारी रहेगी कि मजदूर बोर्ड के माध्यम से काम पर जाएंगे, बोर्ड के पास उसका सारा लेखा जोखा रहेगा और जहाँ काम होगा, जो काम लेगा, उसको पहले बोर्ड से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। उसका कुछ परसेण्टेज बोर्ड के पास बैलफेयर फण्ड में जमा रहेगा और फिर बोर्ड की जवाबदेही रहेगी कि वह मजदूर के लिए साल भर काम की व्यवस्था करे और मजदूर के ऊपर कोई घटना घटे या कुछ हो तो बोर्ड उसको देखने का काम करेगा। यह हमारे पास विचाराधीन है और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि इस सम्बन्ध में कुछ हो। हमने एक सेमिनार भी किया था, उसमें भी सब लोगों की आमसहमति थी, इस आधार पर थी, सरकार को भी इसमें कोई आब्जेक्शन नहीं है लेकिन हमको लगता है कि इस सेशन में इसको हम नहीं ला पायेंगे। यदि एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से हो गया तो ठीक है, नहीं तो पार्लियामेंट में लाने की आवश्यकता पड़े तो अगले सेशन में लाने पर हमको विचार करना पड़ेगा।

विदेश जाने के सम्बन्ध में कई साधियों ने कहा कि विदेश में जाने वाले मजदूरों का भी शोषण होता है और उस शोषण को भी रोकने के निश्चित रूप से उपाय किए जाने चाहिए। हम इसके लिए स्वयं सोच रहे हैं, चिन्तित भी हैं। कुछ एक एजेण्ट्स के खिलाफ हमने एक्शन भी लिया है। जो मजदूर काफी दिनों से विदेश में काम कर रहे हैं, वहां आने जाने में काफी कुछ दिक्कत होती है लेकिन हम सोच रहे हैं। काफी दिन से यह मामला रुका हुआ है, हम एक विषिट देकर इस मामले की इन्कवायरी करना चाहते हैं और हम आपको विश्वास दिसाते हैं कि निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में जो भी कारगर कदम होंगे, हम उठाएंगे।

अभी विपक्ष के एक साधी ने पी० टी० ए० का मामला उठाया था कि पी० टी० ए० आने जाने का पहले ही ले लिया जाता है, यह उचित नहीं है। हम केरल में गए थे तो केरल के सेबर मिनिस्टर ने भी इस सम्बन्ध में बातें कही थीं लेकिन हम सिर्फ यहीं देख रहे हैं कि उसमें सेबर को कहीं घाटा नहीं लगना चाहिए। मजदूरों की तरफ से श्रमिक संगठन के जो लीडर्स हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और अगर मजदूर को घाटा नहीं होने वाला है, मजदूर को उससे हानि नहीं होगी तो पी० टी० ए० सिस्टम जो लागू किया गया है, हम उसको वापस लेने पर तुरन्त विचार करेंगे।

अभी कुछ साधियों ने महिला श्रमिकों के सम्बन्ध में कहा। मेरी निश्चित राय है कि महिला श्रमिकों में किसी भी तरीके से पुरुष श्रमिकों से कोई अन्तर नहीं होना चाहिए, चाहे वेतन का सवाल हो या जो सुविधाएं हैं, उनको विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनके लिए उचित है लेकिन जो मजदूरी का सवाल है, उसमें कहीं कोई अन्तर नहीं होना चाहिए और जो भी चीज उनकी भलाई के लिए की जा सकती है, उसको हम लोग अलग से देख रहे हैं।

नेशनल वेज पालिसी के सम्बन्ध में कुछ साधियों ने राय व्यक्त की थी कि नेशनल वेज पालिसी ही, राष्ट्रीय वेतन नीति हो। कल सोमनाथ जी मुझाव दे रहे थे, इन्होंने इस बुनियादी सवाल को उठाने का काम किया था लेकिन नेशनल वेज पालिसी का मामला थोड़ा पेचिदा मामला है और इसमें हम लोग विचार-विमर्श कर रहे हैं क्योंकि इसको अभी चलाना सम्भव नहीं लग रहा है लेकिन इस सम्बन्ध में हम लोग निश्चित रूप से बात करेंगे।

ठेकेदारी प्रथा के सम्बन्ध में भी माननीय सदस्यों के द्वारा सवाल उठाया गया है। मैं समझता हूँ कि ठेका मजदूरों की समस्या भी काफी भयावह समस्या है। कान्ट्रैक्ट लेबर की भी है। इसमें अभी तक जो कानून बने हुए हैं, उन कानूनों के तहत जहाँ परमानेंट नेचर का काम हो और इसमें चार दूसरी कंडीशन्स भी लगाई गई हैं, यदि ये हों तो ठेकेप्रथा को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये सारी की सारी कंडीशन्स होने के बावजूद भी ठेका प्रथा समाप्त नहीं हो पाई है। इसी सिलसिले में एफ० सी० आई० मजदूरों की एक एप्लीकेशन आयी थी। जब एप्लीकेशन आयी तो हमने तीनों तरफ के लोगों को बुलाया था। आप जानते हैं कि इसमें सिर्फ लेबर मिनिस्ट्री ही नहीं है, बल्कि जहाँ जिस विभाग में और जिस मन्त्रालय में वह मजदूर काम करता है, मेनली उससे डील करना पड़ता है। जब एप्लीकेशन आयी तो मैंने इससे सम्बन्धित मन्त्रालय को भी बुलाने का काम किया और एफ०सी०आई० के मजदूरों को भी और उनसे बातचीत करने के बाद हमको लगा कि इन मजदूरों की डिमांड्स जायज हैं। उसमें हमने निर्णय लिया कि 137 डिपो में, पहले हमने 57 डिपो में ठेका प्रथा को खत्म करने का काम किया था, लेकिन अब हम फैसला लेने जा रहे हैं कि सारे एफ० सी० आई० के 137 डिपो में खत्म करने जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि हमने उस कानून को देखा है। उस कानून में खामी है।

उसमें बहुत कुछ ऐसा है कि बाद में कर दिया गया है। उसमें बाद में जो एक्सप्लान रखा गया है उस एक्सप्लान को हम देख रहे हैं। जो भी कानून है, उस कानून का कड़ाई से पालन किया जाएगा। जहां कहीं पर भी ठेकेदारी प्रथा है, हम उस ठेकेदारी प्रथा को दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसमें आप लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता है। कल हमारे एक साथी बतला रहे थे कि जो कान्ट्रैक्ट एबालिशन एण्ड रीगुलेशन एक्ट बना है, जिसमें एक खतरनाक चीज यह है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म हो जाए और जब उसको रीगुलराइज किया जाए तो फिर कोई जरूरी नहीं है कि उसी मजदूर को वहां... (व्यवधान)... उपाध्यक्ष महोदय, ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी जाए तो उसमें एक सबसे बड़ी बात उत्पन्न होगी, वह यह होगी कि जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उन्हीं मजदूरों को वहां रखा जाएगा, फिर से उनकी नियुक्ति होगी। यह जो चीज है, मैं समझता हूं कि एक खतरनाक चीज है। यदि कहीं कोई मजदूर काम कर रहा है, वह 15-20 साल से काम कर रहा है, ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी जाए और फिर उसको रीगुलराइज करने का सवाल आए, तो उसको वे अधिकार न मिलें और मिलें भी तो मैनेजमेंट के मन पर और मालिक के मन पर निर्भर करें, तो इस चीज के बारे में हम सोच रहे हैं। हमारी निश्चित रूप से राय है कि ठेकेदारी प्रथा जितनी दूर तक सम्भव हो, जहां तक सम्भव हो, उसको खत्म करना चाहिए।

बीड़ी मजदूरों के सम्बन्ध में...

श्री बाळू बयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अब तो स्थिति यह है कि नगर पालिका परिषदों में भी सफाई ठेकेदारी प्रथा के आधार पर होने लगी है। इसके कारण भयंकरतम स्थिति उत्पन्न हो रही है। समान काम कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति साठ रुपए पा रहा है और दूसरा ग्यारह रुपए और चौदह रुपए पा रहा है निम्नम वेजेज एक्ट के तहत। काम वही है, एक ही मशीन पर दो व्यक्ति काम करते हैं, एक की उंगली कट जाए तो दो हजार मिलते हैं और एक का सिर भी कट जाए तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती है, ठेकेदारी प्रथा के आधार पर। इसलिए मंत्री महोदय आपको सख्ती से एक्शन लेना पड़ेगा। कोई भी कानून आप लाइए, मैं समझता हूं कि सदन दो मत नहीं होगा। आप इस ठेकेदारी प्रथा को जब तक सख्ती से नहीं दबाएंगे, तब तक यह समाप्त होने वाली नहीं है।

श्री राम बिलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, बीड़ी मजदूरों के सम्बन्ध में भी एक सवाल था, बीड़ी मजदूरों की संख्या 33.92 लाख है। लेकिन मैं समझता हूं कि इनकी संख्या दुगुने से अधिक होगी, दुगुने से कम संख्या नहीं है। इनके सम्बन्ध में जो भी कानून बने हैं, उन कानूनों का पालन नहीं हो रहा है। उसका पालन करवाने की हम कोशिश करेंगे। जहां तक प्रोविडेंट फण्ड का मामला है, उसमें अभी तक 2 : 7.83 करोड़ रुपया बकाया है। पहले उसके लिए हमारे पास कोई मशीनरी नहीं थी, लेकिन अब हम अपनी मशीनरी कायम करने जा रहे हैं। हमने कहा है कि एक जुलाई से हम आपरे-शन अभियान शुरू करेंगे और निश्चित रूप से कड़े से कड़े कदम उठावेंगे।

ई० एस० आई० के सम्बन्ध में भी कई माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। हम निश्चित रूप से उनको भी विश्वास दिलाते हैं कि हम ई० एस० आई० के कार्य को भी देखेंगे। लेकिन जहां तक उसमें सुधार किया जा सकता है, उसके सम्बन्ध में हम करेंगे।

जो कुछ बुनियादी सवाल उठाए गए हैं, मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं

कोई लेबर लीडर तो कभी रहा नहीं, लेकिन मैं एक मजदूर परिवार से जन्म आता हूँ और मैं हर किसी चीज को खुले दिमाग से सोचता हूँ और जो भी अच्छे से अच्छे सुझाव आप देंगे, चाहे किसी पक्ष के लोग दें, पार्लियामेंट के अंदर दें, पार्लियामेंट के बाहर दें, मिलकर दें, मजदूर और गरीब के हक में जो भी होगा, यदि कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो वह कानून बनायेंगे, यदि कानून बना हुआ है, उसके इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है तो हम उसका कार्यान्वयन करेंगे।

बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम कानून तो बना सकते हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए अलग एजेंसियां हैं। उनके लिए राज्य सरकार भी हैं। राज्यों में सभी तरह की सरकारें हैं, अलग-अलग पार्टियों की सरकारें हैं। उन सबका सहयोग लेकर के हम निश्चित रूप से जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। यह जो मजदूर की समस्या है, जिसके ऊपर में पूरे देश की धुरी कायम है, लेबर, मेनेजमेंट के सम्मेलन में मैं गया था, वहाँ हमने कहा था कि जब हम मजदूर की बात करते हैं तो हमारी मंशा यह नहीं है कि हम मेनेजमेंट को या देश की अर्थव्यवस्था को किसी खराबी में डालना चाहते हैं। बल्कि हम इस बात को लोगों के दिमाग से हटाना चाहते हैं कि मालिक और मजदूर का सम्बन्ध गुलाम और राजा का सम्बन्ध नहीं है। मालिक और मजदूर एक ही व्यवस्था के, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों के बल पर ही इस देश का उद्योग धन्धा खड़ा है। जब तक मालिक के दिमाग में यह बात रहेगी कि मजदूर मेरा नौकर है और हम इससे अधिक से अधिक काम लेंगे और इसे कम से कम पैसा देंगे और जब तक मजदूर के दिमाग में यह बात रहेगी कि किसी भी चीज को, किसी भी जायज मांग को मनवाने के लिए भी हमको आन्दोलन का सहारा लेना पड़ेगा तो मैं नहीं समझता कि यह अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। इसलिए अर्थव्यवस्था को यदि हमें सुदृढ़ करना है, आगे बढ़ाना है तो इंडस्ट्रियल डिस्पूट एक्ट को इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट में बदलना होगा। एक बात और है। हमारा जो आई० एल० सी० है उसमें इस बात पर आम सहमति थी और उसमें इस बात को रिकमण्ड किया गया था कि यह जो पुराना औद्योगिक विवाद अधिनियम है, उसको इमीडियेटली वापस लिया लिया जाए। हम उसको वापस लेने की दिशा में कार्यवाही कर रहे हैं। हम उसको वापस लेने जा रहे हैं। नए बिल के लिए एक कमेटी बना दी गयी है। यह कमेटी रामानुजम् की अध्यक्षता में बनायी गयी है और भी ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि इसमें हैं। हमने इस कमेटी से कहा है कि 31 जुलाई तक यह अपनी रिपोर्ट दे दे। 31 जुलाई के बाद उस रिपोर्ट पर विचार करके हम एक नया विधेयक प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जो पुराना विवादास्पद विधेयक है उसको वापस लेने का निर्णय से लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्वाइंट हमने आपके सामने रखा। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा मंत्रालय है वह कल्याण मंत्रालय है। मेरे पास 23 मिनट का समय बचा है। उसमें मैं अपने पूरे-पूरे विचार रखूंगा।

हमारा जो कल्याण मंत्रालय है जिसमें करीब सात विषय मुख्यतः आते हैं। पहला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समस्या। दूसरे पिछड़े वर्ग की समस्या। तीसरे अल्पसंख्यकों की समस्या। चौथे महिलाओं की समस्या। पाँचवें बच्चों की समस्या। छठे बिकलांगों की समस्या। सातवें मध्य निचध का मामला। यह भी एक बहुत बस्ट मिनिस्ट्री है। बिकलांगों का भी सारा मामला इसके अन्तर्गत आता है।

उपाध्यक्ष मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि इस मंत्रालय के महत्व को जितना समझा

जाना चाहिए था उतना आंका नहीं गया है। अभी तक यह हालत थी कि वेल्फेयर मिनिस्ट्री जिसको मिल जाती थी तो वह यह समझता था कि हमको पीछे की लाईन में डाल दिया गया है। मैं समझता हूँ कि गरीबों के लिए श्रम और कल्याण मंत्रालय से अच्छा मंत्रालय कोई नहीं है। यदि इस मंत्रालय के सुझाव और रिकमन्डेशंस को सरकार और सदन गम्भीरतापूर्वक लें तो इस देश की 90 फीसदी इन दोनों मंत्रालयों से कवर होती है। इसके लिए मैं इन सब पर एक-एक, दो-दो मिनट का ही समय खूंगा। मैं यह कह रहा था कि जहां तक आदिवासी अनुसूचित जाति और जनजाति की स्थिति है, इसके लिए मैंने सुझाव भी बतलाया था कि अनुसूचित जाति से जो भयंकर स्थिति अनुसूचित जनजाति की है। इसमें चाहे जमीन का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो या उसके शोषण का मामला हो। जहां पर बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे लगाये जाते हैं, आदिवासी इलाकों में उद्योग-धन्धे लगाये जाते हैं लेकिन आदिवासियों का उसमें कहीं प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। तृतीय श्रेणी की बात तो आप छोड़िये, चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है। उनकी जो जमीन ली जाती है उस जमीन का मुआवजा भी उनको नहीं मिलता है। सरकारी नौकरियों की हालत तो यह है कि—इसके लिए कानून तो बनाये हुए हैं कि रिजर्व कोटे में हम इनके लिए इतनी सीटें रखेंगे लेकिन जब इनकी बहाली होती है तो उस समय आप वहां जाकर पूछिये—कि रांची में, धनबाद में, बोकारो में आज कितने शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं तो मासूम होगा कि 200 लोग हैं। उनसे अगर यह पूछा जाएगा कि किसके अगेस्ट बहाली की गई और कितने शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को रिजर्वेशन मिला है तो वे दो सी चलाये जाएंगे रिजर्वेशन के नाम पर, जब पूछा जाएगा कि कितने लोगों को लिया गया, कितने लोगों को नौकरी दी और उसमें आदिवासियों की संख्या क्या है तो वहां पर भी वह दो सी पहुंच जाएंगे, इसी प्रकार वही दो सी को हर जगह पर जोड़ दिया जाता है। आज शोषण का सवाल यह है कि जिसकी जमीन है, वह आज चतुर्थ श्रेणी की भी नौकरी में नहीं है। मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है चाहे वह अधिकारी हो या और कोई हो। आज मुझे यह कहने में कोई सकोच नहीं है कि गरीब व्यक्ति को अपना अधिकार नहीं मिल पाता है। आप गांव में जा करके देखिए तो पता चलेगा कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में एक करोड़ रुपया खर्च किया गया, छठी पंचवर्षीय योजना में पांच करोड़ रुपया खर्च किया गया, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 10 करोड़ रुपया खर्च किया गया, यह सारा 16 हजार करोड़ रुपया कोई साधारण अमाउंट नहीं है। यह 16 हजार करोड़ रुपया आदिवासियों के विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए खर्च किया गया, लेकिन उसके अनुपात में उसका कोई विकास नहीं हो पाया है।

इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि हमको 2-3 मुद्दों पर ध्यान देना पड़ेगा, इसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार को केन्द्र सरकार पंसा देती है। केन्द्र सरकार का इसमें कभी 4 सी करोड़ रुपया, कभी पांच सी करोड़ रुपया होता है लेकिन प्रमुख रूप से इसमें राज्य सरकार का ही जिम्मा होता है। हम राज्य सरकार को लिख रहे हैं और सरकार ने योजना आयोग से भी कहा है कि आदिवासी का परसेंटेज जब मार्क करते हैं तो बताते हैं कि इतना परसेंटेज आदिवासियों के लिए है। बिहार में 10 परसेंट आदिवासी हैं, टोटल बजट का 10 प्रतिशत इन आदिवासियों के लिए खर्च किया जाएगा। यदि आप कहते हैं कि 10 परसेंट इनके लिए खर्च किया जाएगा तो आप 10 परसेंट अलग से इनके लिए निकाल करके रख दीजिए, उसकी चाहे आप कारपोरेशन बना कर रखें या डेवेलपमेंट बोर्ड बनाकर रखें और चाहे उसको डेवेलपमेंट मिनिस्ट्री बनाकर रखें। सीधे वहां जिले में जाकर जिला लेवल पर उनकी योजना को बनायें। इस प्रकार से उनका विकास किया जाये। लेकिन आज क्या होता है कि टोटल

छपया राज्य सरकार दे देती है और कहती है कि इसमें नेशनल हाइवेज बनाना है, इसमें आदिवासी का भी शेयर है, इसमें बिजली लगा रहे हैं तो आदिवासी का भी शेयर है। इसका नतीजा क्या होता है— बिजली दूसरी जगह पर लग जाती है लेकिन आदिवासी के क्षेत्र में नहीं लगती है। रोड बनाना होता है तो दूसरी जगहों पर बन जाता है लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में रोड नहीं बनता है। इसलिए इसके लिए जो पैसा दिया जाता है उसका उपयोग सही ढंग से नहीं हो रहा है। इसके लिए जो खर्चा किया जाता है निश्चित रूप से उसका सीधा लाभ आदिवासियों को नहीं मिल रहा है। इसका सीधा लाभ आदिवासियों को मिले, इसके लिए हम राज्य सरकार को भी लिख रहे हैं कि जो भी जंगल, फोरेस्ट सम्बन्धी कानून होंगे या जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, जहाँ कहीं भी उसकी जमीन का मामला हो, जहाँ कहीं भी उनके गांव पड़ते हैं, उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, उसको देखने वाला कोई नहीं होता है। इसके लिए हम यह सुझाव देते हैं कि जहाँ कहीं भी आदिवासियों को हटाने का मामला हो, वहाँ से हटाने से पहले आदिवासियों को कहीं बसाने की व्यवस्था की जाए और फिर बसाने के बाद उनको वहाँ से हटाने की व्यवस्था हो। फोरेस्ट सम्बन्धी जितने भी कानून बनें, उन तमाम कानूनों के अन्तर्गत आदिवासियों से मिल करके, उनसे बात-चीत करके सारे प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया जाये।

इसी तरह से रिजरवेशन का मामला है। अभी बाबा साहेब अम्बेडकर जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। इस वर्ष को सरकार सामाजिक न्याय वर्ष, इयर आफ सोशल जस्टिस के रूप में मना रही है और सेन्टेनरी कमिटी के प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष तथा वेलफेयर मिनिस्टर होने के नाते मैं उपाध्यक्ष हूँ। इसके अलावा देश के कई गणमान्य व्यक्ति, कई राज्यों के मुख्यमन्त्री इसके सदस्य हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस साल योजना को पूरी तरह से लागू करके काम किया जाए।

कुछ साधियों ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि 15 साल में जो बैंकलाग है, असमानता है, वह खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्होंने 15 नहीं बल्कि 10 वर्ष की बात कही थी, लेकिन 10 वर्ष में वह काम नहीं हो पाया। पिछली सरकार ने निश्चय किया था कि 3 महीने के अन्दर सारा बैंकलाग पूरा कर देगे, वह भी नहीं हो पाया। हमने निर्णय लिया है कि एक साल के अन्दर, 14 अप्रैल 1991 तक, जो कि अम्बेडकर साहेब का 100वाँ जन्मदिवस होगा, सरकारी नौकरियों में या किसी भी केटेगरी में बैंकलाग नहीं रहेगा। प्रत्येक तीन महीने में मानेटीरिंग की जाएगी और सारे का सारा बैंकलाग एक साल के अन्दर पूरा कर दिया जाएगा, यह निर्णय सरकार ने लिया है।

श्री गोपाल परचेवाल : हाईकोर्ट जजेज के बारे में बताइए।

श्री राम बिलास पासवान : जहाँ तक जूडिशरी का मामला है, इस बारे में बिधि मन्त्री श्री दिनेश गोस्वामी जी द्वारा सा मिनिस्ट्री द्वारा लिखा जा चुका है और कहा गया है कि इसको देखा जाए। इसमें एक तो सूटेबिलिटी का सवाल है, उसके सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है।

श्री गोपाल परचेवाल : सूटेबिलिटी की बात नहीं रखी जानी चाहिए।

श्री राम बिलास पासवान : सूटेबिलिटी की बात ही सारे मामले की जड़ में है। हम लोगों ने निर्णय लिया है और आदरणीय प्रधानमन्त्री जी की भी यही राय है कि जहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन बी० ए० है और बी० ए० पास लड़का उपलब्ध है, 5 फुट 7 इन्च लम्बाई चाहिए, वह भी है, 34 इंच सीना चाहिए, वह भी है, सारी क्वालिफिकेशन होने के बाद कोई सवाल नहीं उठता कि उसको अनसूटेबल करार दिया जाए। आज तो सिर्फ एक ही साइन लिख दी जाती है—

[अनुवाद]

यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलता है तो खाली स्थान को सामान्य उम्मीदवार से भर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

यह क्लाज सारी चीज को काट देती है, चाहे ज्यूडिशरी का मामला हो, एग्जीक्यूटिव का मामला हो, किसी भी क्षेत्र का मामला हो, जितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है, जो स्टैन्डर्ड फिक्स किया गया है, उसका उम्मीदवार मौजूद है तो सूटेबिलिटी का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद यदि कोई अधिकारी डिसक्रिमिनेशन करता है तो निश्चिततौर पर उसको दण्डित करने का काम भी किया जाएगा। यह कोई मामूली चीज नहीं है कि आजादी के 43 साल के बाद भी एस० पी० तो अनुसूचित जाति-जनजाति का मिल जाता है, कलेक्टर मिल जाता है, लेकिन चपरासी नहीं मिलता, क्लर्क नहीं मिलता। इसलिए कहीं न कहीं नीयत ठीक नहीं है। जहां नीयत साफ है वहां काम ठीक हो रहा है। इसलिए नीयत को साफ करना होगा। इसके लिए जैसा मैंने कहा कि हम कटि-बद्ध हैं।

अनुसूचित जाति-जनजाति के सम्बन्ध में हमने 4-5 घोषणाएं की हैं और उन घोषणाओं को यह न सोचते हुए कि हमने 5 साल पूरा करना है, जल्द से जल्द पूरा करने को कोशिश करेंगे। इस ओर जल्दी से जल्दी हम कार्यवाही करने जा रहे हैं। पिछले दिनों आरक्षण का 10 साल का समय बढ़ाया गया, इसके लिए मैं सभी दलों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सिर्फ सरकार को ही इसमें क्रेडिट नहीं जाता।

अटॉरिटीज की बात कही गई, मेरे पास आंकड़े हैं, इस बारे में राज्य सरकारों को लिखना शुरू कर दिया गया है और कई स्थानों पर, करीब 150 जिलों पर स्पेशल कोर्ट स्थापित होने की सूचना भी आ गई है। हमारी कोशिश है कि 550 के लगभग जितने जिले हैं, सभी जिलों में कम से कम एक स्पेशल कोर्ट की स्थापना कर दी जाए, ताकि इन लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। 1989 में लोक सभा और राज्य सभा द्वारा स्पेशल कोर्ट्स के सम्बन्ध में कानून पास हो गया था, लेकिन उस समय लागू इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि उस समय सरकार ने, ला मिनिस्ट्री ने कह दिया था कि राज्य सरकारें जब तक अनुमति नहीं देंगी, तब तक यह कानून लागू नहीं हो सकेगा। फिर जब हम मिनिस्टर बने तो हमने लॉ-मिनिस्ट्री से बातचीत की। लॉ-मिनिस्ट्री ने कहा कि राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करना जरूरी है। अगर राज्य सरकार "नहीं" कहे, उसके आधार पर केन्द्र सरकार अपने कदम को रोक दे, यह नहीं हो सकता है। पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया है और आप यह कानून लागू कर सकते हैं। उसके बाद हमने राज्यों के सचिवों की बैठक 15 जनवरी को बुलाई। बैठक में कहा कि 30 जनवरी के अन्दर-अन्दर आप तमाम राज्य सरकारों की तरफ से लिख कर भेजें। यदि आप नहीं लिखेंगे तो 30 जनवरी को हम इसको नोटीफाई कर देंगे। हमने 30 जनवरी को नोटीफिकेशन जारी कर दिया। हमने सब राज्य सरकारों को कहा कि आप 15 जनवरी तक लिख कर भेज दो। जो राज्य सरकारें लिख कर नहीं भेजेंगे तो यह समझा जाएगा कि उन्होंने अपने यहां स्पेशल कोर्ट्स बनाने से इन्कार किया है, तो हम उनके नाम अखबार में देंगे। खुशी की बात है कि तमाम राज्य सरकारों ने लिख कर भेज दिया है कि वे अपने यहां स्पेशल-कोर्ट्स बना रहे हैं या स्पेशल-कोर्ट्स बन चुके हैं।

तीसरा सवाल था नव बुद्धिष्ठ का। जो नव बुद्धिष्ठ हैं उनको भी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की फंसिलिटीज प्रदान करेंगे। बाबा साहिब अम्बेडकर की अन्त तक इच्छा रही कि उनको ये सुविधाएं मिलें। लेकिन नहीं मिल पायीं। हमने इसके सम्बन्ध में राज्य सभा में बिल पास किया है। यह बिल सर्वसम्मति से पास हो गया है। लोक सभा में भी इसी सत्र में यह बिल आएगा और हमें उम्मीद है कि आप सब साधियों का उसमें सहयोग रहेगा। यहां भी सर्वसम्मति से वह बिल पास हो जाएगा।

भारत रत्न का मामला था, मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी यहां हैं, किसी पॉलिटीकल पार्टी ने इसकी मांग नहीं की थी, सामाजिक संस्था के लोगों ने मांग नहीं की थी। यह क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को जाता है। प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न, जो सबसे बड़ा सम्मानजनक पदक है, उससे बाबा भीम राव अम्बेडकर को सुशोभित किया है। उन्होंने साफ कहा है कि इससे बाबा साहिब की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी है, इससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इस देश में डॉ० अम्बेडकर को 43 साल तक भारत रत्न पदक नहीं मिला तो सचमुच कहीं न कहीं दलित वर्ग के लोगों के मन में यह कसक थी। आज भारत रत्न की उपाधि देने से जो गरीब हैं, दलित हैं, उनके मन में नया उत्साह पैदा हुआ है, हौसला पैदा हुआ है। आज वे अपने आपको मुख्य धारा में जोड़ कर चलने के लिए कटिबद्ध हो गए हैं। पार्लियामेंट का सेन्ट्रल हाल बाबा साहिब की प्रतिमा के बगैर सूना लगता था। हमें खुशी है कि बाबा साहिब अम्बेडकर की प्रतिमा वहां लगी, जो सबसे बढ़िया जगह है। जो सेन्ट्रल हाल में जाएगा उसे भारत के संविधान के निर्माता को देखने का मौका मिलेगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में हमने कहा था कि इसको संबैधानिक दर्जा देंगे। उसके लिए सारे पेपर तैयार हैं। यह मामला कैबिनेट में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि एक हफ्ते या दो हफ्ते में इसका निर्णय हो जाएगा। अभी तक आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त दो बाँडे हैं। लेकिन दोनों में से किसी को भी पावर नहीं है। चार-पांच साल के बाद हाउस में रिपोर्ट पेश हो चुकी है, यह रिपोर्ट कभी पेश होती है, कभी नहीं होती है, कभी रिपोर्ट पर बहस हां गयी, कभी नहीं हुई। अगर बहस हो गयी तो कोई प्रछने वाला नहीं। हम चाहते हैं उसको स्टैंच्यूटरी पावर्स दें, उसको कानून हथियार से संस कर दें और संरक्षण का अधिकार दें ताकि वह एक पावरफुल बाँडे के रूप में उभर सके। अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति, जनजाति आयुक्त दोनों को मिलाकर एक बाँडे बनाया जाए, ऐसा हम चाहते हैं।

उसके अलावा जैसा मैंने कहा माइन्डोरिटी का सवाल है, अल्पसंख्यक का सवाल है, जो प्राइम-मिनिस्टर का 15 सूत्री कार्यक्रम है, प्रत्येक महीने की पहली तारीख को कैबिनेट की एक्शन टेकन बैठक होती है, उसमें उसकी समीक्षा की जाती है। निश्चित रूप से जो अधिकारी कम्युनल रॉयट्स के दौरान अच्छा काम करेगा, कम्युनल रॉयट्स रोकने का काम करेगा, उसके लिए जहां पुरस्कार की व्यवस्था है, वहीं जो अधिकारी कम्युनलिज्म को बढ़ावा देगा उसको दण्ड देने का भी प्रावधान है। मुआबजे की राशि को 20 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए करने का हमने निर्णय लिया है। सांशिक्षा इकोनॉमी और एजुकेशन के विकास के लिए हर सम्भव प्रयास करने का हम विचार कर रहे हैं।

विकलांगों का जहां तक सवाल है, उसके सम्बन्ध में कसकत्ता में, सोमनाथ चटर्जी साहब यहां बैठे हैं, 20 हजार विकलांग लोग बहाँ पहुंचे थे। वे लोग कह रहे थे कि हम लोग दो लाख की संख्या

में दिल्ली में ही पहुंचते हैं। अभी तक उनके लिए जो कानून बना हुआ है उसके अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में तीन-तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन वह भी नहीं मिल पाता है। हमने निर्णय लिया है कि हम उनको क्लास 1, 2, 3 और 4 में लाएंगे, क्योंकि उनमें भी योग्य लोगों की कमी नहीं है काफी योग्य लोग हैं। इसलिए चारों श्रेणियों में तीन-तीन प्रतिशत का आरक्षण देंगे। उसके लिए कानून बनाया जा रहा है और यह भी व्यवस्था की है कि जो मानसिक विकलांग हैं उनको चूँकि वे प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में नहीं लिए जा सकते इसलिए उनको चतुर्थ श्रेणी में लिया जाएगा। क्योंकि यह एक मानवता का मामला है, जब किसी का बच्चा विकलांग होता है तो उसको पता चलता है कि विकलांगता क्या है। इसके लिए भी कानून हम आप लोगों के बीच में लाने जा रहे हैं।

जहां तक महिलाओं का मामला है, उसके सम्बन्ध में काफी साधियों ने ध्यान आकृष्ट किया है। महिलाओं के लिए नेशनल कमीशन आन वूमेन एक्ट है और राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हुई है। उसके सम्बन्ध में सारी चीजें तैयार हैं और उसे भी हम आपके बीच में लाने जा रहे हैं। बाल कुटीर, बाल अपराधी और भिखारियों के सम्बन्ध में भी यहां सबाल उठे। मैं स्वयं उनको देखने के लिए गया था। मैंने बाल कुटीर में जाकर देखा जहां पर भीख मांगने वालों के साथ-साथ निर्दोष लोगों को भी बन्द किया गया है। 217 आदमियों में मैंने देखा कि 17 ही भिखारी होंगे, बाकी निर्दोष थे और उनको उठाकर यहां बन्द कर दिया जिसमें एक प्रोफेसर भी बन्द था मैंने अगले दिन उप-राज्यपाल के साथ भी वहां दौरा किया और उनको स्थिति से अवगत कराया...

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : कहने के बाद भी नहीं छोड़ा।

श्री राम बिलास पासवान : 13 लोगों के लिए मैंने कहा था मैं यह मानता हूँ कि निश्चित रूप से बैंगर्स के लिए ये घर बने हुए हैं जो सड़कों पर हैं, लेकिन जो भिखारी नहीं हैं उनको भी पकड़ कर बन्द किया जाता है यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। मैंने कहा था सबन में एक दिन, कि प्रत्येक राज्य में इसके लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। माननीय सदस्यों को जहां-जहां भी जानकारी मिले निश्चित रूप से एक बार चँक करें, चाहे बाल कुटीर का मामला हो या भिखारियों के लिए बैंगर्स होम का मामला हो समाज में यह जो उपेक्षित वर्ग है इसको भी सही स्थान दिलाना जरूरी है और इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए।

श्री० रासा सिंह रावत (अजमेर) : आज के समाचारपत्र में आफटर केयर होम और हेस्टीद्यूट चिल्ड्रन के बारे में बहुत भयावह चित्रण आया है, उस पर भी कुछ बोलें।

श्री राम बिलास पासवान : कानून बने हुए हैं छुआछूत के बारे में। सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है। पहले छुआछूत निवारण कानून था, लेकिन आज तक उसके अन्तर्गत किसी को सजा नहीं दी गई, रुपए-पैसे का जुर्माना तो हो जाता है, लेकिन सजा का प्रावधान नहीं हो पाता है। यह एक सामाजिक बुराई है। जहां सरकार को इसके बारे में सोचना है वहां समाज के प्रत्येक तबके के लोगों को इस पर सोचना होगा। कई माननीय सदस्यों ने स्वयंसेवी संस्थाओं के बारे में ध्यान आकृष्ट किया है उनमें से निश्चित रूप से काफी सस्याएं अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन ऐसी धो हैं जिनका मोटो पैसा कमाने का हो हो गया है। हम दिसम्बर में आए थे और चाहते थे उनका पैसा रोकना, लेकिन इस बार नहीं रोका है और उनको पैसा दिया है तथा मैंने यह भी कहा है कि 29 तारीख को पैसा दिया है और 31 तारीख तक कैंसे खर्च करेंगे यह हमें बताना। हमने स्वयंसेवी संस्थाओं से आग्रह किया है कि वे आगे आएँ और इस काम में अपने को समर्पित करने के भाव से आयेँ और इस दृष्टिकोण को लेकर आएँ

कि भारत सरकार ने जो पैसा दिया है उसका सदुपयोग हो। लेकिन हम भविष्य में उस पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।

श्री छवि राम अगल (मुरैना) : मंत्री जी जब उधर बैठते थे तब मांग करते थे कि सेपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए, क्या इस पर विचार करेंगे ?

श्री राम बिलास पासवान : जब मैं उधर था तो आपको मालूम होगा कि बेलफेयर मिनिस्ट्री उस समय नहीं थी, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स होम मिनिस्ट्री के अन्तर्गत था। मण्डल कमीशन के बारे में काफी माननीय सदस्यों ने जोरदार ढंग से अपनी बात को कहा है। मण्डल आयोग की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और निकट भविष्य में इस पर विचार किया जाएगा...

श्री बाळू बवाल जोशी : कब तक विचाराधीन रहेगी ?

श्री राम बिलास पासवान : मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर एक सप्ताह के अन्दर निर्णय ले लिया जाएगा। साथियों, मैं समझता हूँ कि आपने जो भूमि का मामला उठाया है, यह बहुत ही जटिल मामला है। देश के अन्दर केवल बिहार में ही नहीं, अपितु अन्य राज्यों में भी जितनी बटनाएँ बटती हैं, वे अधिकांश भूमि से जुड़ी हुई होती हैं। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं कि देश के अन्दर 51 लाख एकड़ भूमि सरपलस है और मैंने रिपोर्ट मंगायी है जिसमें पता चला है कि शेड्यूल्ड कास्ट को 16.15 लाख एकड़ और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को 6.36 लाख एकड़ भूमि वितरित की गई है। अब यह जमीन भी वितरित की गई है या नहीं, मैं जिम्मेदारी के साथ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि कानून की अपनी पेचीदगी है। जिसकी भी जमीन पड़ती है, वह कोर्ट में चला जाता है। इसलिए सरकार ने उस कानून को संविधान की 9वीं सूची में डालने का फैसला किया है। इससे भूमिपति का कोर्ट जाने का अधिकार खत्म हो जाएगा। जिस गरीब को जमीन मिली है, वह असली मालिक उस जमीन का होगा। इसके अतिरिक्त कई अन्य बातें भी हैं जैसे इग्ज एडीक्ट्स का सवाल है, लेकिन समय अभाव के कारण और ग्लोटेन का मामला यहां आने के कारण मैं तो सभी साथियों से अपील और आग्रह करूंगा कि सरकार की नियत एकदम साफ है जो भी आपके सुझाव गरीब लोगों के पक्ष में होंगे, निश्चित रूप से अनु०जा० और अनु० जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और बिकलांग या मजदूरों के पक्ष में आएंगे, हम हमेशा उनका स्वागत करेंगे। मैं एक बार फिर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो प्वाइंट्स या सुझाव छूट गए हैं, आप साथी लोग लिखकर देंगे तो उसपर उतनी ही कार्रवाई करेंगे जैसाकि मैं इस सदन में बचन दे रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप दोनों पक्ष के साथी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि जितने भी आपने कटौती प्रस्ताव दिए हैं, उनको वापस ले लें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अगर श्री पलाई के० एम० मॅपू को उनके सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ मतदान के लिए रखे जाने पर कोई आपत्ति न हो तो मैं श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांग पर वेश किए गए कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूँ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 91 से 94 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें तथा मैं मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

“कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में भ्रम मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 56 के सामने दिखाये गये मांग शीर्ष के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएँ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1990-91 के लिए भ्रम मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांग

मांग संख्या	मांग का नाम	28 मार्च, 1990 को लोक सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	4	5	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
56	भ्रम मंत्रालय	92,00,00,000	28,00,000	275,99,00,000	82,00,000

उपाध्यक्ष महोदय : कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है। अब मैं कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांग सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

“कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 79 के सामने दिखाये गए मांग शीर्ष के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएँ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1990-91 के लिए कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित
अनुदान की मांग

मांग संख्या	मांग का नाम	28 मार्च 1990 को लोक सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की राशि	लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि
1	2	3	4
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
79.	कल्याण मंत्रालय	94,00,00,000	2,29,00,000
		281,98,00,000	6,88,00,000

6.00 नं० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91

नागर विमानन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, संचार मंत्रालय इत्यादि

उपाध्यक्ष महोदय : अब हर गिलोटीन करेंगे। अब मैं क्षेत्र मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगें सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

श्री पी० चिदम्बरम (सिचगंगा) : महोदय, क्या आप अन्य मंत्रालयों, जिनकी मांगों पर चर्चा नहीं हुई है, के बारे में कुछ प्रश्न पूछने की हमें अनुमति देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। गिलोटीन के समय हम ऐसा नहीं करते।

श्री पी० चिदम्बरम : परम्परा यह है कि हम कुछ प्रश्न करते रहे हैं, मंत्रीगण तब उपस्थित रहेंगे। आप कुछ सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति क्यों नहीं दे सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपको वित्त विधेयक तथा विनियोग विधेयक पर चर्चा करते समय अवसर मिलेगा।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, यह प्रथा अनेक वर्षों से है।

उपाध्यक्ष महोदय : चिदम्बरम जी यह सही नहीं है। विनियोग विधेयक तथा वित्त विधेयक पर चर्चा के समय आपको ये प्रश्न करने का अवसर मिलेगा।

श्री पी० चिदम्बरम : यह प्रथा रही है कि हम कुछ सदस्यों को उल्लेख करने की अनुमति देते रहे हैं। ऐसा पहले हुआ है। गिलोटीन के समय सभी मंत्रीगण यहाँ पर होंगे।

(अवसर्जन)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। हम ऐसा नहीं करते। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हैं तो आपको प्रश्न करने का अवसर मिलता है बशर्ते कि आपने इसकी सूचना दी हो। बिना विधेयक पर चर्चा करते समय भी आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन सभा में गिलोटीन करते समय आप ऐसा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : पहले तो यही प्रथा अपनाई जाती थी।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : हमारे सहयोग का यही उत्तर है। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : यदि आप का विनिर्णय यह है कि यह प्रथा बदल दी गई है तो हम इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन कृपया यह मत कहिए कि यह प्रथा नहीं रही है। यह प्रथा रही है, गिलोटीन के समय सभी मंत्रीगण उपस्थित रहते हैं; प्रश्न पूछे जाते हैं; मंत्रीगण उत्तर देते हैं। यह प्रथा रही है और हरेक इसके बारे में जानता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चिदम्बरम जी, आप को इस मुद्दे पर सही जानकारी नहीं है। मुझे बताया गया है कि एक भी अवसर पर ऐसा नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चिदम्बरम जी, आपको विनियोग विधेयक पर चर्चा के समय अवसर मिलता है।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : अगर यह नया विनिर्णय है तो हमें यह स्वीकार्य है। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : हमेशा से यह प्रथा रही है कि जिन मंत्रालयों पर चर्चा नहीं हुई, उन पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए कुछ प्रश्नों की अनुमति दी जाती रही है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों के लिए टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। मैं कुरियन जी को आश्चर्य कि ऐसा नहीं होता और हम ऐसा नहीं करेंगे। विनियोग विधेयक पर चर्चा के समय वह ऐसा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मंत्रालयों/विभागों से सम्बन्धित बकाया अनुदानों की मांगें सभा में बतवाव के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

“कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में निम्नलिखित मंत्रालयों/सचिवालयों से सम्बन्धित निम्न-लिखित मांग संख्या(ओं) के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में संवदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित विधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :—

- (1) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 6;
- (2) वाणिज्य मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 7 और 8;
- (3) संचार मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 9 से 11;
- (4) ऊर्जा मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 19 से 21;
- (5) पर्यावरण और वन मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 22;
- (6) वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 24 से 27, 29, 30 और 32 से 36;
- (7) खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 37 और 38;
- (8) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 39;
- (9) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 40 और 41;
- (10) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 54 और 55;
- (11) विधि और न्याय मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 57;
- (12) संसदीय कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 58;
- (13) कामिक, लोक शिक्षायात और पेन्शन मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 59;
- (14) पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 60 और 61;
- (15) योजना मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 62 और 63;
- (16) कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 64;
- (17) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 65 से 67;
- (18) इस्पात और खान मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 68 और 69;
- (19) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 70 से 72;
- (20) वस्त्र मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 73;
- (21) पर्यटन मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 74;

- (22) शहरी विकास मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 75 से 77;
- (23) परमाणु ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 80 और 81;
- (24) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 82;
- (25) महासागर विकास विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 83;
- (26) अन्तरिक्ष विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 84;
- (27) लोक सभा से सम्बन्धित मांग संख्या 85;
- (28) राज्य सभा से सम्बन्धित मांग संख्या 86; और
- (29) उप-राष्ट्रपति सचिवालय से सम्बन्धित मांग संख्या 88”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1990-91 के लिए नागर विमानन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय संघार मंत्रालय इत्यादि से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	28 मार्च, 1990 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि	सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि		
1	2	3	4		
	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए		
			पूंजी रुपए		
नागर विमानन मंत्रालय					
6.	नागर विमानन मंत्रालय	19,42,00,000	1,25,00,000	58,25,00,000	2,76,00,000
वाणिज्य मंत्रालय					
7.	वाणिज्य विभाग	616,79,00,000	94,16,00,000	1850,36,00,000	282,49,00,000
8.	पूँति विभाग	6,85,00,000	—	20,57,00,000	—
संघार मंत्रालय					
9.	संघार मंत्रालय	2,02,00,000	—	6,03,00,000	—

	1	2	3	4
10. डाक सेवाएँ	327,35,00,000	13,40,00,000	982,04,00,000	40,20,00,000
11. दूरसंचार सेवाएँ	1041,57,00,000	583,50,00,000	3124,70,00,000	1747,49,00,000
ऊर्जा मंत्रालय				
19. कोयला विभाग	38,60,00,000	247,50,00,000	115,79,00,000	742,50,00,000
20. विद्युत विभाग	97,18,00,000	840,94,00,000	291,54,00,000	1747,82,00,000
21. नैर-न्यारम्यरिक स्रोत विभाग	30,06,00,000	1,46,00,000	90,18,00,000	4,39,00,000
पर्यावरण और वन मंत्रालय				
22. पर्यावरण और वन मंत्रालय	66,69,00,000	1,10,00,000	200,06,00,000	3,31,00,000
शिक्षण मंत्रालय				
24. वार्षिक कार्य विभाग	106,29,00,000	60,04,00,000	318,89,00,000	180,11,00,000
25. करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	75,56,00,000	52,25,00,000	226,69,00,000	156,76,00,000
26. वित्तीय संस्थानों को बढ़ावायियाँ	64,67,00,000	888,38,00,000	193,25,00,000	956,33,00,000
27. रेलमार्ग	125,16,00,000	—	375,48,00,000	—

1	2	3	4	
29.	राज्य सरकारों को अन्तरण	9 55,42,00,000	28 66,27,00,000	86,25,00,000
30.	सरकारी कर्मचारियों आदि को उधार	—	52,75,00,000	158,25,00,000
32.	बच विभाग	26,77,00,000	56,00,000	80,31,00,000
33.	सेवा परीक्षा	64,35,00,000	—	193,06,00,000
34.	राज्य विभाग	33,43,00,000	40,00,000	44,21,00,000
35.	प्रत्यक्ष कर	55,13,00,000	30,00,00,000	165,41,00,000
36.	अप्रत्यक्ष कर	87,09,00,000	36,69,00,000	261,25,00,000
छात्र और वाचरिड फुल्लि संभाल्य				
37.	छात्र विभाग	594,17,00,000	41,52,00,000	1782,52,00,000
38.	ताचरिड फुल्लि	2,15,00,000	1,01,00,000	6,43,00,000
छात्र संभाल्य उद्योग संभाल्य				
39.	छात्र संभाल्य उद्योग संभाल्य	5,70,00,000	2,90,00,000	17,10,00,000
स्वास्थ्य और वरिदार कल्याण संभाल्य				
40.	स्वास्थ्य विभाग	128,66,00,000	41,78,00,000	385,98,00,000
41.	वरिदार कल्याण विभाग	188,98,00,000	1,00,000	566,93,00,000
				4,00,000

	1	2	3	4
सूचना और प्रसारण मंत्रालय				
54. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	23,12,00,000	1,71,00,000	69,36,00,000	5,14,00,000
55. प्रसारण सेवाएं	179,06,00,000	86,54,00,000	537,18,00,000	259,60,00,000
बिधि और न्याय मंत्रालय				
57. विधि और न्याय	19,73,00,000	—	59,18,00,000	—
संसदीय कार्य मंत्रालय				
58. संसदीय कार्य मंत्रालय	25,00,000	—	75,00,000	—
कृषि, लोक-सिकायत और पेशाब मंत्रालय				
59. कृषि, लोक-सिकायत और पेशाब मंत्रालय	11,10,00,000	1,19,00,000	33,31,00,000	3,56,00,000
कौशल और पेशाब मंत्रालय				
60. कौशल और पेशाब मंत्रालय	25,42,00,000	37,50,00,000	76,26,00,000	112,50,00,000
स्वास्थ्य और पेट्रो-रसायन विभाग				
61. स्वास्थ्य और पेट्रो-रसायन विभाग	3,48,00,000	1,03,00,000	10,43,00,000	3,07,00,000

1	2	3	4		
बोझना बंचालय					
62.	बायोफना	12,67,00,000	3,43,00,000	38,01,00,000	10,27,00,000
63.	संश्लेषकी विभाग	10,80,00,000	—	44,49,00,000	—
कार्यक्रम कार्यालय बंचालय					
64.	कार्यक्रम कार्यालय बंचालय	21 00,000	—	64,00,000	—
विद्यालय और प्रौद्योगिकी बंचालय					
65.	विद्यालय और प्रौद्योगिकी- विभागीय विभाग	57,05,00,000	7,69,00,000	173,91,00,000	23,06,00,000
66.	वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग	60,68,00,000	1,37,00,000	182,05,00,000	4,13,00,000
67.	वैद्य-प्रौद्योगिकी विभाग	16,27,00,000	30,00,000	48,80,00,000	90,00 000
इस्पात और खनिज बंचालय					
68.	इस्पात विभाग	6,89,00,000	256,41,00,000	20,06,00,000	211,17,00,000
69.	खान विभाग	34,44,00,000	10,62,00,000	103,31,00,000	31,86,00,000
खान-पुल्ल परिवहन बंचालय					
70.	खान-पुल्ल परिवहन	8,92,00,000	44,36,00,000	26,75,00,000	118,08,00,000

1	2	3	4
71.	सड़कें	93,86,00,000	161,59,00,000
72.	परतन, दीपस्तम्भ नौवहन	30,18,00,000	55,32,00,000
	परमोद्योग मंत्रालय		281,60,00,000
73.	हरनोद्योग मंत्रालय	176,40,00,000	67,88,00,000
	पर्यटन मंत्रालय		529,19,00,000
74.	पर्यटन मंत्रालय	15,10,00,000	5,23,00,000
	शहरी विकास मंत्रालय		45,32,00,000
75.	शहरी विकास और आवास	71,00,00,000	34,82,00,000
76.	लोक निर्माण कार्य	53,57,00,000	212,99,00,000
	लेखन सामग्री और मुद्रण		160,69,00,000
77.	लेखन सामग्री और मुद्रण	21,58,00,000	39,32,00,000
	परमाणु ऊर्जा विभाग		64,72,00,000
80.	परमाणु ऊर्जा विभाग	110,28,00,000	148,80,00,000
81.	न्यूक्लीय बिद्युत सोवनाएँ	59,61,00,000	48,75,00,000
			330,86,00,000
			178,82,00,000
			444,24,00,000
			146,25,00,000

1	2	3	4
	इलेक्ट्रानिकी विभाग		
82.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	24,08,00,000	7,04,00,000
			74,82,00,000
			21,61,00,000
	सुशासन विकास विभाग		
83.	सुशासन विकास विभाग	896,00,000	1,33,00,000
			27,40,00,000
			5,47,00,000
	कलरिख विभाग		
84.	कलरिख विभाग	80,70,00,000	23,64,00,000
	संसद, राजपुसति, उपराजपुसति के सचिवालय और संसद लोक सेवा आयोग		258,58,00,000
			71,91,00,000
85.	लोक सेवा	4,64,00,000	—
86.	राज्य सेवा	1,86,00,000	—
88.	उपराजपुसति का सचिवालय	6,00,000	—
			13,93,00,000
			5,59,00,000
			18,00,000

उपाध्यक्ष महोदय : इन मन्त्रालयों/विभागों से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें पारित की जाती हैं ।

6.05 म० प०

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक*

वित्त मंत्री (प्रो० मधु बच्छते) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रो० मधु बच्छते : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय अब विधेयक को विचार के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं ।

प्रो० मधु बच्छते : मैं प्रस्ताव करता हूँ :**

“कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।”

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।”

अब उन सदस्यों के फायदे के लिए जो इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, मैं प्रक्रिया नियमों से सम्बन्धित भाग को पढ़ना चाहूंगा ।

“विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद लोक-महत्व के या विधेयक में आने वाले अनुदानों में अन्तर्निहित प्रशासकीय नीति के ऐसे विषयों तक सीमित रहेगा जो पहले ही उस समय न उठाए जा चुके हों जबकि संगत अनुदानों की मांगें विचाराधीन थीं ।

अध्यक्ष, वाद-विवाद की पुनर्वाक्ति को रोकने की दृष्टि से, विनियोग विधेयक पर चर्चा

*विनांक 16-5-90 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तुत ।

में भाग लेने के इच्छुक सदस्यों द्वारा उन विशिष्ट विषयों पर पूर्ण सूचना दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा जो वे उठाना चाहते हैं और वह ऐसे विषयों को उठाने के लिए अनुज्ञा रोक सकेगा जो उसकी राय में किसी अनुदान की मांग के सम्बन्ध में चर्चा किए गए विषयों की पुनर्कथित प्रतीत होते हैं या जो पर्याप्त लोक महत्व के न हों।”

अतः विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में वाद-विवाद सीमित है और केवल उन्हीं सदस्यों को उस पर बोलने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने नोटिस दिए हैं। जहाँ तक वित्त विधेयक के सम्बन्ध में वाद-विवाद का सम्बन्ध है, यह काफी व्यापक है और सबस्य वित्त विधेयक पर अपने विचार बिस्तार से व्यक्त करने के लिए स्वतन्त्र होंगे। मैं यह मुद्दा सदस्यों की नोटिस में इसलिए ला रहा हूँ जिससे इस विधेयक पर नोटिस दिए बिना सदस्यों को बोलने की मांग से बचा जाए। मेरे पास उन सदस्यों के नाम हैं जिन्होंने नोटिस दिए हैं। अब, श्री युवराज बोल सकते हैं। (अबबखान)

[हिन्दी]

श्री बाळू बयाल खोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हमारे यहाँ राजस्थान राज्य में यह परम्परा रही है कि वित्त-विधेयक पास हो जाने के बाद वहाँ के वित्त मन्त्री, सदन के सभी सदस्यों को बुलाकर भोजन की व्यवस्था करते रहे हैं, तो मेरा अनुरोध है कि माननीय वित्त मन्त्री यहाँ भी सभी माननीय सांसदों का भोजन की व्यवस्था करें। (अबबखान)

श्री युवराज (कटिहार) : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन मांगों पर चर्चा नहीं हुई वैसे वन की समस्या को ले लीजिए, वन पर चर्चा नहीं हुई। उसी प्रकार ऐनर्जी को लीजिए। उम्मीद करना चाहते हैं कि जो समस्या ऐनर्जी की है, यह बिल्कुल बुनियादी चीज है, इसके बिना हम चल नहीं सकते। आज बिजली की कमी की वजह से हमारी कृषि और औद्योगिक स्थिति काफी कमजोर हो गई है। जो डिमांड की गई है, जो बिल लाया गया है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ लेकिन यह कहना चाहता हूँ कि एक नई सामाजिक व्यवस्था कायम करना चाहते हैं या नई आर्थिक व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, जब तक इस पर जोर नहीं दिया जाता देश नहीं बढ़ेगा, जब तक बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा या वन लगाने का काम नहीं होगा क्योंकि चर्चा की कमी होती जा रही है, उसकी तरफ जब तक हम तबज्जह नहीं देंगे तब तक हमारी स्थिति सुधर नहीं सकती है। यह मौलिक समस्या है जिसकी अपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं।

श्री गिरधारी लाल भगंब (जयपुर) : मैं राजस्थान में बिजली की व्यवस्था की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाओं से राजस्थान का हिस्सा हमें तुरन्त मिलना चाहिए। लिंग नार्डट आधारित जो भी योजनाएँ हैं वे जल्द लागू की जानी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नई योजनाओं को भी तुरन्त स्वीकृति दी जानी चाहिए। इसी प्रकार से गैस आधारित अस्था की अमता युगनी की जानी चाहिए। प्रिंसेट एण्ड कम्पनी से कोटा में तुरन्त कोल हैंडलिंग प्लांट लगवाया जाना चाहिए। सोलर थर्मल पावर के विकास के लिए सौर ऊर्जा उचित फण्ड का प्रावधान आवश्यक है। इसी प्रकार से सूबा प्रदेश होने के नाते केन्द्रीय विद्युत ग्रहों से राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। देहर-घिबानी लाइन पर किया गया 21 करोड़ का खर्च राजस्थान को वापिस मिलना चाहिए। इसी प्रकार से संचार व्यवस्था के बारे में भी डिस्कशन नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान में दस हजार माइन के नए ऐक्सचेंज के बाद भी सन् 1982 से अभी तक जिन्होंने टेलीफोन मांगे हैं, वे प्रतीक्षा की सूची में हैं। सन् 2000 तक दो लाख नए टेलीफोन जयपुर में चाहिए,

20 हजार इलैक्ट्रानिक टेलीफोन चाहिए, 6-7 नम्बर के डिजिट जिनमें गड़बड़ी आती है वह ठीक हो सके। सन् 1986 से जयपुर शहर में टेलीफोन डायरेक्टरी भी नहीं छपी है। विभाग में हिन्दी टाईपिस्टों की भी हालत खराब है। सिविल ऐंबियेशन के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे में पर्यटन व उद्योग की दृष्टि से राज्य की आय बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देकर इसका विकास किया जाना भी आवश्यक है। जयपुर में हवाई जहाज की जो उड़ानें हैं उनकी संख्या बहुत कम है, उनको भी बढ़ाया जाना चाहिए। इससे स्टेट की रिबैन्सू बढ़ेगी और होटल वालों के लिए, टैक्सी वालों का भी काम बढ़ेगा। भारतवर्ष में जयपुर शहर पर्यटन दृष्टि से प्रथम श्रेणी में है। अरबन डवलपमेंट की दृष्टि से जयपुर शहर को चार चैनल रोड से जोड़ने का जो काम है, वह भी शीघ्र पूरा किया जाए। जयपुर में बाई पास के काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। जयपुर एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन व व्यापार केन्द्र होने के नाते इसकी सुन्दरता बढ़ाने व सड़क के विकास के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें सारी चीजें नहीं आ सकती हैं। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आपको बैठना पड़ेगा।

श्री गिरधारी लाल भागंब : राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। रामगढ़ शील पर 1982 के एशियाड खेलों में राज्य सरकार ने दो करोड़ रुपए खर्च किए जिसका कोई लाभ अब नहीं रहा है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जयपुर शहर को सुन्दर बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से कुछ धनराशि इसके लिए दी जानी चाहिए।

मैंने इन चार बिन्दुओं पर जो प्रकाश डाला है, आप उन पर अवश्य ही ध्यान दें। आपने मुझे बोलने का जो समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं किसी मंत्रालय के बारे में अध्ययन करता हूँ तो मैं पहली बात यह सोचता हूँ कि क्या पहले से इस विभाग में कुछ सुधार हुआ है। इस दृष्टि से मैं संचार विभाग पर जब नजर डालता हूँ तो पाता हूँ कि संचार विभाग में दस वर्ष पूर्व जब स्टीफन साहब मंत्री थे, उसके पूर्व जो स्थिति थी, आज सबसे ज्यादा वह बिगड़ी है। जहाँ पहले दिन में दो बार डाक मिलती थी, वहाँ आज केवल एक बार मिलती है। मुम्बई से पुणे डाक एक दिन में पहुंच जाती थी लेकिन आज उसे पहुंचने में तीन दिन लगते हैं। इसकी अबस्था इतनी बुरी न हो यही मैं चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पालिसी के बारे में या पब्लिक इण्टरस्ट के बारे में बताएं।

[अनुवाद]

यह शिकायतों का समय नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो० राम गणेश कापसे : कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लिए बजट में बढ़ोत्तरी होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि...

[अनुवाद]

देरी से मंत्रालय के सम्पूर्ण प्रभाव बिकल हो जाते हैं।

[हिन्दी]

यह स्थिति होने के कारण ऐसा माना जाता है कि इस विभाग में आय क्रम और खर्चा ज्यादा है। वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में जितना पैसों का व्यवहार होता है, उससे भी ज्यादा इस विभाग में होता है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि डाक विभाग में आय कम है। मैं यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस विभाग में कई छोटी-छोटी बातें हो रही हैं। भाईवर की बस्ती की संख्या 3 लाख है वहाँ के लोगों को तार भी नहीं मिलता है। तार आर्डनरी पोस्ट से भेजी जाती है। इसके अलावा डोबिवली में बारिश के दिनों में पानी भर जाता है। वहाँ नई सिंचिका नहीं बन रही है। इस प्रकार की अवस्था न हो इसलिए कुछ किया जाए। अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बरह पवार को विदेश गए तो उन्होंने जाते हुए कहा कि मेरे विदेश में रहते हुए महाराष्ट्र की राजनीति ज्यादा अच्छी तरह से चलती है क्योंकि वहाँ की टेलीफोन व्यवस्था ज्यादा अच्छी है। इससे अधिक कड़ी आलोचना इस विभाग की और नहीं हो सकती है ऐसा मैं मानता हूँ।

एक आखिरी बात में अपनी कांस्टीट्यूयेंसी के बारे में कहना चाहता हूँ। वहाँ रेलवे का पावर हाऊस बरसों से है। गए एक बरस में वहाँ बिजली का उत्पादन बिल्कुल नहीं हुआ। इसका कारण एक्सीडेंट का होना बताया जाता है। महाराष्ट्र शासन ने ऐसा बताया है कि वहाँ रेल बर आकाशिक बिजली घर खोला जाए। एनर्जी और कम्युनिकेशन इन दोनों विषयों पर जो यहाँ बहुत कड़ी हो पायी है इस कारण से मैंने ये विचार यहाँ रखे हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह उद्य किया गया है कि कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई शहर के जो हवाई अड्डे हैं उनके नाम नए दिए जायेंगे। उसके अनुसार कलकत्ता...

(अवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही यह मुद्दा उठा चुके हैं। आपने स्वयं यह मुद्दा उठाया था। अतः, इसे फिर से न दोहराया जाए।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : मेरी पहली मांग पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के सम्बन्ध में है। हम जो किसानों को मैन्यूर देते हैं, नई प्रकार की जो खाद देते हैं वह सबजीडाइज्ड रेट पर देते हैं लेकिन जो समुद्र और तालाब में मछली मार का काम करते हैं, वे सबसे अधिक डीजल का उपयोग करते हैं लेकिन उन मछुआरों को डीजल सबजीडाइज्ड रेट पर नहीं दिया जाता है। मेरा यह माहना है कि यह भी एक प्रकार की खेती और उद्योग है। सभी मछुआरों को डीजल सबजीडाइज्ड रेट पर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की मांग मैं करना चाहता हूँ।

दूसरी मांग मेरी इस दृष्टि से है कि शहरों की पालिसी की दृष्टि से गए 5 साल में जो आबादी बढ़ी है, उसके अनुसार पोस्ट आफिसेज बढ़े नहीं हैं और पोस्ट आफिसेज बढ़े नहीं, इतना ही नहीं पोस्टमैन भी नहीं बढ़ाए गए। इसका परिणाम यह हुआ है कि मेरे उत्तर मुम्बई मतदार संघ में गए पांच साल में 11 लाख की आबादी बढ़ी है। मैंने गए दिसम्बर अधिवेशन में सवाल किया था कि कितने नए पोस्टमैन नियुक्त किए हैं तो 11 लाख की आबादी के लिए केवल 4 नए पोस्टमैन नियुक्त किए हैं और केवल दो नए पोस्ट आफिसेज खुले हैं। मैं मांग करता हूँ कि जिस प्रकार से नए रिक्लूटमेंट्स पर जो बैं लगया था, पालिसी के अन्तर्गत वह बैं निकालना चाहिए और जहाँ-जहाँ जिस प्रकार से आबादी बढ़ी है वहाँ उस प्रकार से नए पोस्टमैन और नए पोस्ट आफिसेज खोले जाने चाहिए।

तीसरी बात, इस सम्बन्ध में यह है कि मुम्बई उपनगर में टेलीफोन लोकल काल केवल मुम्बई शहर तक ही मर्यादित हैं। सबअबॉन रेलवे सर्विसेज मुम्बई से विरार और कसारा कल्याण-कर्जन तक जाती है लेकिन वहाँ के लिए लोकल काल नहीं है तो मेरी मांग यह है कि जहाँ-जहाँ लोकल रेलवे सर्विसेज जाती हैं वहाँ कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को लोकल काल की व्यवस्था करनी चाहिए। एक गांव से आने जाने वाले लोगों को ट्रंक काल करना और एस० टी० डी० करना बड़ी मुश्किल का काम होता है इसलिए ऐसी पालिसी तय की जाए कि जहाँ सबअबॉन सर्विसेज हैं वहाँ पर लोकल काल की व्यवस्था होनी चाहिए।

आखिरी बात यह है कि ब्राडकास्टिंग एण्ड इनफोरमेशन मिनिस्ट्री में पहले यहाँ पर एक प्रथा थी कि एक्स्टेंडिड कोरेस्पोंडेंट्स थे, रिपोर्टर्स थे, उनको दिल्ली शहर में रहने के लिए जगह दी जाती थी, अब गए कुछ सालों से यह पद्धति बन्द कर दी और इसके लिए आज जो एक्स्टेंडिड कोरेस्पोंडेंट दिल्ली शहर में हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती है इसलिए मेरी मांग यह है कि ऐसे सब लोगों को जो एक्स्टेंडिड कोरेस्पोंडेंट्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनको दिल्ली शहर में रहने की जगह देने की पालिसी बनानी चाहिए और उसके अनुसार उन सब को जगह देनी चाहिए। हार्जिसिंग पूल उन लोगों के लिए नए सिरे से निर्माण करना चाहिए और इस बात को लेकर एक वाक्य में अन्तिम बात यह कहना चाहता हूँ कि पत्रकारों के लिए पेंशन की व्यवस्था नहीं है। यह सारे हिन्दुस्तान की व्यवस्था का प्रश्न है और यह पालिसी का डिमीजन है इसलिए मैं यह भी मांग करता हूँ कि पत्रकारों को पेंशन देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

बिल मंत्री (प्र० मधु बण्डवते) : उपाध्यक्ष जी, एप्रोप्रिएशन बिल की चर्चा के जो नियम हैं, उनका तकाजा है कि जो सवाल इस चर्चा में उपस्थित किए जाते हैं, वह ऐसे सवाल होने चाहिए कि आम पालिसी के साथ उनका ताल्लुक हो लेकिन जो विशेष समस्या है तो मैं समझता हूँ कि जितने साधियों ने सवाल उठाए हैं, वे समझते हैं कि विशेष मांगों की चर्चा के समय उन्हें समय और मौका नहीं मिला, इन सवालों को रखने के लिए इसलिए उन्होंने बिजली के बारे में, टेलीफोन के बारे में, विभिन्न केन्द्रों के बारे में, बम्बई के नाम के बारे में, पोस्ट आफिसेज के नम्बर के बारे में...

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने हमें अपने मुद्दे उठाने की अनुमति दी है और हमने कुछ विशेष समस्याएं उठाई हैं जिनका कि हम सामना कर रहे हैं। हमने उन समस्याओं को उठाने का प्रयास किया है। हम गलत हो सकते हैं लेकिन हमने यह दिखाने का प्रयास किया है कि

यह एक विशेष नीति है और उस विशेष नीति में हमने अपनी समस्याओं को उसमें फिट करने का प्रयास किया है, जिनका कि सामना किया जा रहा है। वे सभी नीति सम्बन्धी निर्णय हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में चर्चा बहुत ही औपचारिक है। क्योंकि आप नीतियों और अन्य बातों पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं इसीलिए, हमने उन्हें यहाँ बहुत ही संक्षेप में चर्चा करने का प्रयास किया है। लेकिन क्योंकि आपने उन्हें उठाया है—शायद बिल मंत्री स्वयं उन सभी मुद्दों का उत्तर देने की स्थिति में न हों—अतः उन सभी मुद्दों को अन्य मंत्रियों ने नोट कर लिया है और वे उनका सही तरीके से उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

प्रो० मधु बण्डवले : उपाध्यक्ष जी, मैं राम नार्डक जी का अवमान नहीं करना चाहता हूँ। मैंने यह नहीं कहा कि उन्होंने जो सवाल उठाए, वह आम पालिसी के सवाल नहीं हैं। मैं आगे चलकर यह बताने वाला था कि जैसे उन्होंने पोस्ट ब्यवस्था के बारे में सवाल उठाए, उन्होंने कोरेस्पोंडेंट्स को रहने की जगह के बारे में इन्तजाम होना चाहिए, यह सवाल उठाया। उन्होंने एक्सेटिब कोरेस्पोंडेंट्स के बारे में सवाल उठाया, उन्होंने पेंशन का सवाल उठाया, बिजली के सिलसिले में सवाल उठाए गए कि वैसे आधारित बिजली घर होने चाहिए। यह भी सवाल होना चाहिए कि जयपुर को ज्यादा सुन्दर बनाने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। मैं तो मानता हूँ कि जयपुर सुन्दर है, वह ज्यादा सुन्दर होना चाहिए, यह भी सरकार मानती है। युवराज जी ने बिजली का सवाल उठाया है, मैं उनको इतना ही बताना चाहता हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो विशेष नीति विशेष सवाल उठाया है, तो विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने आपकी राय सुनी है। बिल मंत्री सारे सवालों का जबाब देना शुरू करेंगे तो आम चर्चा बजट के बारे में होगी। इसलिए आपने जो सवाल उठाए हैं, उनको मैं विभिन्न मंत्रालयों को पहुँचाने की कोशिश करूँगा। संसदों की कमी, तो जहाँ तक सम्भव होगा संसदों की व्यवस्था हम करेंगे, इतना ही आश्वासन मैं सम्बन्धित सदस्यों को देता हूँ।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : इनको डाक मिलेगी या नहीं मिलेगी ?

प्रो० मधु बण्डवले : आपको मिलने के बाद पता लगेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संविधान निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी। प्रश्न यह है :

“कि खण्ड 2 से 4 और अनुसूची विधेयक का अंश बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 और अनुसूची, विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

प्रो० मधु बण्डवते : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि विधेयक पारित किया जाये।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.27 ब० ९०

वित्त विधेयक, 1990-91*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा वित्त विधेयक पर विचार करेगी। हम रात के 8 बजे तक बैठेंगे और यदि आवश्यक हुआ और सदस्य चाहेंगे, तो उसके बाद भी बैठेंगे। लेकिन उसके लिए हमें निर्णय करना होगा। इसके लिए 8 बजे का समय निर्धारित है। इस पर व्यापक रूप से चर्चा हो सकती है।

अब वित्त मंत्री।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु बण्डवते) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

महोदय, मैं वित्त विधेयक में निहित प्रस्तावों की मुख्य बातों के सम्बन्ध में अपने बजट प्राषण में पहले ही व्याख्या कर चुका हूँ। इस विधेयक में विशेष में प्रस्थापनाओं के ब्यौरे का स्पष्टीकरण माननीय सदस्यों को परिचालित व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है। अतः मैं सम्पूर्ण पृष्ठभूमि को फिर से यह बताना आवश्यक नहीं समझता।

वित्त विधेयक लगभग 8 सप्ताहों से माननीय सदस्यों के पास रहा है। बजट के सम्बन्ध में वाद-विवाद के दौरान, विधेयक में निहित विभिन्न पुस्तकों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने विभिन्न सुझाव रखे हैं। इस विधेयक में निहित प्रस्तावों के सम्बन्ध में युष्ते भी जनता के सदस्यों, मजदूर सघों, किसान संगठनों, उपभोक्ता निकायों, वाणिज्य मण्डल और अन्य व्यापार और व्यावसायिक एसोसिएशनों से

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

काफी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मैं माननीय सदस्यों तथा अन्य सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इन प्रस्तावों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा है और अपने रचनात्मक सुझाव दिए हैं। इन सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, मैंने अपने कुछ मूल प्रस्तावों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। सभा के अनुग्रह पर, मैं अब वित्त विधेयक की व्यवस्थाओं में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों का संक्षेप में स्पष्टीकरण दूंगा।

मैं सबसे पहले प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में प्रस्तावों के बारे में बताता हूँ। हमारी अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की विशेष भूमिका को स्वीकार करते हुए, आयकर अधिनियम की धारा 80त के अन्तर्गत उन्हें काफी रियायतें और छूट दी गई हैं। उन्हें उपभोक्ता सहकारी समितियों के मामले में 40,000 रुपए की और अन्य समितियों के मामले में 20,000 रुपए की मानक कटौती की भी अनुमति दी गई है। इसके अलावा उन्हें अपनी मलकियत के अनुसार कर देना होगा जिसमें न्यूनतम 15 प्रतिशत और अधिकतम 40 प्रतिशत होगा। सहकारी आन्दोलन को और प्रोत्साहन देने की दृष्टि से मेरा सभी स्तरों पर कर की दर को और 5 प्रतिशत कम करने का प्रस्ताव है।

केन्द्र और राज्यों दोनों की ओर से चाय उद्योग पर कर लगाया जाता है। निगमित कर के साथ-साथ, चाय उगाने और तैयार करने के व्यापार में करदाता की आय के 60 प्रतिशत भाग पर सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा कर लगाया जाता है, यह कर कृषि आय के रूप में लगता है। एक मुख्य कृषि उत्पाद के उत्पादक के रूप में, यहां मुनाफा वर्ष-दर-वर्ष घटता-बढ़ता रहता है। इस श्रम-प्रधान उद्योग को इस योग्य बनाने के लिए कि वहां विशेषतया बागानों को बढ़ाने के लिए स्त्रियों को उत्पन्न और उनका संरक्षण करे, मैं इस कार्य के लिए कटौती का प्रस्ताव रखता हूँ जो पहले आय-कर अधिनियम की धारा 33कख में उपलब्ध था। यह उसका संशोधित रूप है। वित्त विधेयक में इस सम्बन्ध में संशोधन पारित करके इसे करने का प्रस्ताव है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने अन्तर-निगमीय लाभांशों के कराधान में एक बड़े परिवर्तन का प्रस्ताव किया था। नई योजना के अर्धीन, अन्तर-निगमीय लाभांश के लिए कटौती उस कम्पनी के लाभांश के बितरण से जुड़ी हुई है जो लाभांश प्राप्त करती है। इसके साथ ही, मैंने यह भी कहा था कि नई योजना अनुसूचित बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों पर लागू नहीं होगी। इसी सिद्धान्त के आधार पर, यह प्रस्ताव किया गया है कि इस कार्य के लिए, राज्य वित्त निगमों और राज्य औद्योगिक निवेश निगमों को सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के समान माना जाए। जिस प्रकार कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अर्धीन पंजीकृत कम्पनियों को लाभांश घोषित करने की अनुमति नहीं है, धारा 8 जो '3ग' के वर्तमान प्रावधानों के द्वारा वे अब भी नियन्त्रित रहेंगी।

मैं अपंग बच्चों पर किए जाने वाले खर्च में और रियायत देना चाहता हूँ क्योंकि फिनहाल यह पर्याप्त नहीं है। मैं, इसके लिए माता-पिता अथवा संरक्षक की आय-सीमा को 60,000 रुपए से 1,00,000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूँ। अपंग बच्चे अथवा निर्धर व्यक्ति की आय कितनी भी हो मैं 6,000 रुपए की रियायत का भी प्रस्ताव करता हूँ। इसके अलावा, मेरा यह प्रस्तावित संशोधन केन्द्रीय सेवाएं (जिफिस्ता) नियम के अर्धीन स्वीकृत अस्पतालों और औषधालयों में काम करने वाले चिकित्सकों को आवश्यक चिकित्सा स्थिति को प्रमाणित करने के योग्य बनाएगा। इसमें सरकारी नगर-निगम अस्पताल और औषधालयों के अलावा बहुत से निजी अस्पताल भी सम्मिलित हैं।

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अधीन, इस बारे में कुछ अनिश्चितता है कि एक भारतीय समुद्री जहाज के कर्मियों के सदस्य के रूप में नौकरी करते हुए, भारत का निवासी गिने जाने बिना, किसी एक विशेष वर्ष में कितने दिन तक भारत में रह सकता है। हमारे समुद्री जहाजों को चसाने के लिए योग्य कर्मचारियों की भारी कमी होने के कई कारणों में से एक कारण यह भी है। इसलिए, मैं यह प्रस्ताव रखते हुए कि भारतीय समुद्री जहाजों के कर्मियों के सदस्य भी इस अधिनियम की धारा 6(1)(ग) की व्याख्या के अधीन नियन्त्रित किए जाएंगे, मैं इस विषय को अनिश्चितता से परे रखना चाहूंगा। किसी भी पूर्व वर्ष में वे भारत के निवासी होंगे यदि वे उस वर्ष भारत में 182 दिन अथवा ज्यादा दिन रहे हों और चाय उद्योग के लिए प्रस्ताविक नई कटौती के सम्बन्ध में, इस नए प्रस्ताव को वित्त विधेयक में संशोधन द्वारा लागू करने का कार्यक्रम है।

आयकर अधिनियम में ग्रामीण विकास और पर्यावरण की सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों के लिए दी गई दान राशि को छूट देने का विशेष प्रावधान है। मेरे बजट प्रस्तावों में, मैंने इन फायदों में वनरोपण को भी सम्मिलित किया है। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भाग लेने को बढ़ाने सम्बन्धी कई प्रस्ताव भी मेरे पास आए हैं। यह हमारी प्राथमिकता का क्षेत्र है और मैं पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए इन सुझावों पर ध्यान दूंगा।

मैं प्रत्यक्ष करों में अन्य संशोधनों को जो प्रारूप में परिवर्तन लाने, प्रक्रियात्मक अथवा अनुषंगी प्रकृति के हैं, सदन का समय लेने का प्रस्ताव नहीं करता।

अब मैं अप्रत्यक्ष कर सम्बन्धी सुधारों के बारे में कहता हूँ।

माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि बड़ी मत्स्य नौकाओं द्वारा उपभोग में लाए जाने वाले हाईस्पीड डीजल, तेल पर उत्पाद शुल्क में रियायत दी जाती थी। इसे असंगत माना गया क्योंकि इससे छोटे मछुआरों को लाभ नहीं पहुँचा और इसलिए इस रियायत को दिसम्बर, 1988 में वापिस ले लिया गया। छोटे मछुआरों की मदद करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि जो उत्पाद शुल्क हाई-स्पीड डीजल तेल से चलने वाले छोटे यन्त्रचालित मत्स्य नौकाओं पर लगाया जाता है, उसे सरकारी संस्थाओं द्वारा पूरी तरह से वापिस कर दिया जाए। इससे छोटे मछुआरों को हाईस्पीड डीजल तेल बिना कर के उपलब्ध हुआ करेगा। इस योजना का ब्यौरा अलग से दिया जाएगा। वर्तमान में एल्युमीनियम के बने बर्तनों पर 30 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगता है। कृषि क्षेत्र को राहत देने के लिए मैं कीटनाशक द्रव्य को जिन एल्युमीनियम के बर्तनों में डाला जाता है, उन्हें पूरी तरह से उत्पाद शुल्क से मुक्त रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

मैंने बजट में बेकार कागज पर 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि आयात कर में घोषित की थी। छोटी कागज मिलों से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, मैं इसे पहले की 20 प्रतिशत की दर पर पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

वर्तमान में, केवल वही छोटी कागज मिलें इस घटी हुई दरों की अधिकारी होंगी जो अप्रचलित कच्चे माल का प्रयोग करती हैं और जिनकी वार्षिक उत्पाद 24,000 टन से अधिक नहीं है। इन मिलों की निम्नतम वार्षिक क्षमता की बड़ी हुई सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, मैं हृदबन्दी सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूँ ताकि 24,000 से 33,000 टन की वर्तमान रियायती उत्पाद शुल्क सीमा उपलब्ध कराई जा सके।

बजट में, मैंने कुछ 'वेस्ट ग्रेड पी० बी० सी०' पर उत्पाद शुल्क में कुछ वृद्धि घोषित की थी जिससे कर-अपबन्धकों पर रोक लगाई जा सके। पी० बी० सी० आवृत्त बस्त्रों पर भी उत्पाद शुल्क बढ़ाए गए थे। चमड़ा बस्त्र उद्योग से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए चमड़ा बस्त्र के निर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाले कर भुगतान किए हुए पी० बी० सी० रेजिन के लिए मोडरेट का फायदा उठाने की अधिकतम सीमा आवृत्त बस्त्रों पर 3.50 रुपए प्रति मीटर से 5.25 रुपए प्रति मीटर तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

मैंने बजट में पी० टी० ए० पर 4.40 रु० प्रति किलोग्राम और डी० एम० टी० पर 3.60 रु० प्रति किलोग्राम उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। यह कहा गया है कि पोलिएस्टर स्टेपल फाईबर और सूत के उत्पादन में जिन निवेशों का प्रयोग किया जाता है, उन पर लगाए उत्पाद शुल्क की दरों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। इसके अनुसार, मैं दोनों डी० एम० टी० और पी० टी० ए० पर 15 प्रतिशत की समान दर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

बजट में घोषित पॉलिएस्टर स्टेपल फाईबर पर उत्पाद शुल्क में कटौती के साथ-साथ पालिएस्टर अपशिष्ट, जो ऐसे फाईबर के निर्माण से बचता है, पर 5 रुपए प्रति कि० ग्रा० की दर से कमी करने का प्रस्ताव करता हूँ।

बजट में, मैंने मछली पकड़ने के जालों के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले नायलोन फिलामेंट यार्न की विशेष किस्मों पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क में कमी करने की घोषणा की है। कुछ अन्य प्रकार के नायलोन फिलामेंट यार्न पर, जो इसी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मैं छूट बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

कर-अपबन्धन रोकने के एक कदम के रूप में, मैं बुने हुए सिथेटिक रैब्स पर उत्पाद शुल्क की दर 8 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का और टेप अवस्था में इसे 3.70 रुपए से बढ़ाकर 3.85 रुपए प्रति कि० ग्रा० करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इस प्रस्ताव से कुल मिलाकर राजस्व नहीं मिलेगा।

'मेटल कन्टेनर' उद्योग ने यह मत प्रकट किया है कि उनके उद्योग को कच्चे मास की कीमतों में बढ़ोत्तरी और दूसरी धातुओं से बनने वाले कन्टेनरों से प्रतिस्पर्धा के कारण बिपरीत प्रभाव झेलना पड़ता है। इस उद्योग को राहत देने के लिए, मैं मोहे अथवा स्टील निर्मित धातु कन्टेनरों पर उत्पाद शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

बजट में, मैंने फलों के रस पर 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक उत्पाद कर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। फिर भी, मुझे सूचना मिली है कि बर्गीकरण की विशेष समस्याओं के कारण, फलों के रस पर आधारित कुछ पेय पदार्थों पर कर की दर 15 प्रतिशत से बढ़ गई है। मैं इस अनियमितता को सुलझाने का प्रस्ताव रखता हूँ जिससे फलों के रस पर आधारित पेय पदार्थों पर कर केवल 10 प्रतिशत तक ही रहे।

निवेश को बढ़ावा देने और पूंजीगत मास सम्बन्धी क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से मैंने बजट में कुछ मशीनों पर विशेष आधार पर 5 प्रतिशत से उत्पाद कर में कमी का प्रस्ताव रखा था। मैं इस रियायत, को बस्त्र तैयार करने वाली मशीनों के कुछ विशेष उपकरणों पर उत्पाद कर 15 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

लघु सीमेंट उद्योग को राहत देने के रूप में, मैं लघु सीमेंट प्लान्ट्स द्वारा निर्मित सीमेंट पर, उत्पाद कर 115 रुपए प्रति टन से 90 रुपए प्रति टन तक घटाने का प्रस्ताव करता हूँ।

इस वर्ष के बजट में, वे खाली 'आडिओ' कैसेट्स और रिकार्ड की हुई 'आडियो' कैसेट्स जो सीधे रिकार्ड की हुई कैसेट्स से बनाई गई हैं, उन पर उत्पाद कर लगाया गया है। उत्पादकों ने यह कहा है कि इस उत्पाद शुल्क लगाने के कारण कई समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, जिनके बारे में कहा गया है, मैं ऐसी खाली और रिकार्ड की हुई श्रव्य कैसेट्स को पूर्ण रूप से छूट देने का प्रस्ताव रखता हूँ। फिर भी, मैं इस प्रकार के कैसेट में प्रयोग होने वाले 'मैग्नेटिक टेप' पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को 2.10 रुपए से 3.00 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

मैं 'इनेमेलित वाइरिंग तारों' पर उपलब्ध उत्पाद शुल्क की रियायतों को कृषि क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाली 'सबमसिबल मोटरों' में लगाई जाने वाली पी० बी० सी० 'इनेमेलित वाइरिंग तारों' पर भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ।

चूने का उत्पादन मुख्य रूप से विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में किया जाता है। तदनुसार, राहत के तौर पर मैं, चूने की विभिन्न विशिष्ट किस्मों पर उत्पाद शुल्क की पूर्ण छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि रोगाणु रहित अंतःक्षिरा द्रव की पैकेजिंग को प्रोत्साहन देने के लिए, मैंने 'फार्म फिल सील मशीनों' पर आयात शुल्क को 40 प्रतिशत कम कर दिया था। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त राहत देने के लिए मैं ऐसी रोगाणु पैकेजिंग के लिए पोलीइथायलिन रोसिन के विशिष्ट ग्रेडों पर, जो फार्म फिल मशीनों की सहायता से बनाई जाती हैं, आयात शुल्क में 40 प्रतिशत तक की कम का प्रस्ताव करता हूँ।

जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, मैंने बजट में आजकल जो मूलभूत भाड़ा लागू है उसकी जगह पूरी विमान यात्रा पर 10 प्रतिशत अन्तर्देशीय विमान यात्रा कर लगाए जाने का प्रस्ताव किया था। विमान यात्रा के लिए अमरीकी डालर भाड़े और भारतीय रुपए भाड़े में अन्तर को कम करने के लिए मैं वित्त विधेयक में एक संशोधन लाने का प्रस्ताव कर रहा हूँ ताकि विमान यात्रा कर की दर को कुल किराए के 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सके।

मैं वित्त विधेयक में जिप बांधने वाले पुजों पर आयात शुल्क सम्बन्धी एक संशोधन का प्रस्ताव भी कर रहा हूँ जो संशोधनात्मक प्रकृति का है।

अप्रत्यक्ष करों में उपरोक्त परिवर्तनों सम्बन्धी छूट की अधिसूचनाएँ यथासमय सभापटल पर रख दी जाएंगी।

मेरे द्वारा प्रस्तावित विभिन्न परिवर्तनों से होने वाली राजस्व हानि अपेक्षाकृत कम होगी और उसे बेहतर कर बसूली द्वारा पूरा कर लिया जाएगा।

अन्त में, मुझे 19 मार्च, 1990 के अपने बजट भाषण में किसानों, दस्तकारों और चुनकरों के लिए की गई ऋण राहत घोषणा के बारे में कहना है। ऋण राहत देने के लिए एक बिस्तृत परिचालन प्रोजेक्ट खर्च तैयार कर ली गई है। मुझे योजना की निम्न मुख्य विशेषताओं के बारे में सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है:

(एक) ऋण राहत उन किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, दस्तकारों और बुनकरों को दी जाएगी जिन्होंने कृषि और सम्बन्धित कार्यों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, बामिकी आदि के लिए ऋण लिया था।

(दो) राहत के अन्तर्गत वे सभी कालातीत ऋण आएंगे जो 2-10-1989 तक की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भूमि विकास बैंक सहित सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए कम अवधि के या मियादी ऋण हैं।

(तीन) राहत उन कर्जदारों को दी जाएगी जिनका मूलधन एक या ज्यादा बैंकों में, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों या सहकारी बैंकों में 10,000 रुपए से ज्यादा न हो। इस मापदण्ड पर यदि एक बार कर्जदारों की कर्जमाफी के लिए थोथ्यता सुनिश्चित हो जाती है तो 10,000 रुपए की सीमा तक मूलधन और ध्याज की माफी की अनुमति दी जाएगी।

(चार) पहले बताई गई शर्तों पर निम्नलिखित वर्गों के कर्जदारों को कर्ज राहत का लाभ मिलेगा :—

(क) ग्रामीण स्तर पर लागू 'अन्नाबारी ब्यबस्था' द्वारा जानबूझकर अबायगी में चूक न करने वाले किसान। अन्नाबारी ब्यबस्था के आधार पर जिन किसानों ने दो या ज्यादा खराब फसलों के लिए ऋण चुकाने में चूक की है वे कर अबायगी में जानबूझकर चूक न करने वाले किसान माने जाएंगे; और वे कर्ज राहत पाने के योग्य होंगे।

(ख) चूककर्त्ता किसान, दस्तकार और बुनकर जिन पर "पुराने कालातीत ऋण" है अर्थात् एक कालातीत ऋण जो 3 साल से ज्यादा समय तक अन्तिम तिथि अर्थात् 2-10-1989 तक चूककर्त्ता है।

(ग) मृतक कर्जदाता का जीवित परिवार जिस पर कर्ज बेनबारी था पकी है।

(घ) ऐसा किसान जिसने दिवालियापन की याचिका दायर की है या जो पहले से ही दिवालिया घोषित हो चुका है।

मैं अपने बजट भाषण और 4 मई, 1990 के अपने वक्तव्य में की गई घोषनाओं को इस सदन में दोहराना चाहूंगा जो ऋण राहत योजना द्वारा बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को होने वाली हानि के मुआबजे के बारे में हैं। केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, जो केन्द्रीय क्षेत्र में हैं, पूरा मुआबजा देगी। हार्मार्कि सहकारी बैंक राज्य क्षेत्र में हैं और राज्य कानून के अन्दर, राज्य अधिकारियों द्वारा स्थापित और चलाए जाते हैं, केन्द्रीय सरकार भूमि विकास बैंकों सहित सहकारी बैंकों पर कर्ज राहत में 50 प्रतिशत भार को बहन करेगी और आशा की जाती है कि शेष भार राज्य सरकार द्वारा बहन किया जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, 'नाबाइ' और भारतीय रिजर्व बैंक को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऋण देने वाली शाखाएँ योजना के अनुसार एक समबद्ध तरीके से कर्ज राहत देने का कार्य करें। हम राज्य सरकारों को भी ऐसी योजनाएँ बनाने या वर्तमान योजनाओं, में सहकारी बैंकों के लिए इसी तरह का सुधार करने की सलाह दे रहे हैं।

हमारा प्रयास है कि हम इस योजना को सरल, उद्देश्यपूर्ण, और तीव्र बनायें जिससे सारे देश के किसान, दस्तकार और बुनकर उचित रूप से और शीघ्रता से सही तथा उचित लाभ पा सकें। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के साथ इस वित्त विधेयक को अपना समर्थन दें।

श्री कै० एस्० राव (मछलीपटनम) : आगामी फसल मौसम को देखते हुए क्या आप इस ऋण राहत कार्यान्वयन के लिए कोई समय सीमा निश्चित करेंगे ?

प्रो० मधु बण्डवते : तत्काल। बजट सत्र खत्म होते ही कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा। 'नाबाई' को तथा अन्य सभी को हमारे सुझाव पहले ही मिल चुके हैं ताकि ग्रामीण कृषकों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर छः या सात घण्टे चर्चा करने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

श्री बाई० एस्० महाजन (जलगांव) : वित्त विधेयक पर टिप्पणी करने से पहले मैं माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी पूर्व घोषित विभिन्न योजनाओं में रियायतों और उदारताओं की घोषणा की है, तथा ऋण माफी योजना का ब्यौरा दिया है जो उनकी पहले प्रस्तावित योजना से कहीं व्यापक है। पहले, उन्होंने 'जानबूझकर ऋण अदायगी न करने वाले' शब्द का प्रयोग किया था। इसका अर्थ है कि बैंकों को जानबूझकर ऋण अदायगी न करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में निर्णय करने का अधिकार दिया गया था। अब उन्होंने एक वस्तुपरक परीक्षण का प्रस्ताव किया है जो बेहतर है क्योंकि यह सारी योजना में से व्यक्तिनिष्ठ तत्त्व को हटा देगा।

प्रो० मधु बण्डवते : मैं आपकी बुद्धि से लाभान्वित हुआ हूँ।

श्री बाई० एस्० महाजन : जहां तक वित्त विधेयक का सम्बन्ध है, मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा जहां माननीय मंत्री ने कन छोड़ा था जब वह कतिपय आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की बात कर रहे थे। उस समय, उन्होंने एक अल्पकालीन आधार पर समस्या का निपटारा किया था—घोड़ी अवधि के लिए पूर्ति और मांग का प्रबन्ध—ताकि कीमतों में अत्यधिक वृद्धि को रोका जा सके।

मैं लम्बी अवधि की स्थायी समस्याओं की बात करना चाहूंगा जो लगभग पेशीदी हैं और जिनमें कीमतों को बढ़ाने की प्रवृत्ति है, एक ऐसी प्रवृत्ति जो वर्षों से हमारी अर्थव्यवस्था में रही है। मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार ने कहा था कि सरकार का पहला कार्य महंगाई को रोकना होगा और मुद्रास्फीति का नियन्त्रण इसके कार्यक्रम के प्राथमिकता क्षेत्रों में से एक है। विश्व युद्ध के बाद की अवधि के दौरान मुद्रास्फीति विश्व की मुख्य समस्याओं में से एक है। इसके कुछ स्थायी घटक हैं। पहला है, राजकोषीय असन्तुलन जो 7206 करोड़ रुपए के घाटे के कारण उत्पन्न हुआ है। मैं नहीं जानता कि बजट में इतना घाटा रहते हुए वह कैसे मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण रख सकते हैं। इससे एक बड़ी घाटे की अर्थव्यवस्था उत्पन्न होगी जिससे केन्द्रीय बैंक पर सरकार का अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण बढ़ेगा। और हमारे देश में इस प्रकार की घाटे की अर्थव्यवस्था काफी समय से

चली आ रही है और वित्त मंत्री इस परम्परा को तोड़ने में सफल नहीं हुए हैं। किन्तु सिर्फ यही मुद्दा नहीं है। हमने घाटा बजट से जो अनुमान किया है घाटे की अर्थव्यवस्था उससे कहीं ज्यादा होगी। बजट में 7206 करोड़ रुपए का घाटा है। वास्तव में वास्तविक घाटा बहुत अधिक है। अनेक अलोचकों ने तथा पूर्व वित्त मंत्री ने भी यह कहा है कि यह घाटा कम करके बताया गया है क्योंकि एकमुस्त भुगतानों को वर्तमान वर्ष के बजाए विगत वर्ष के नामे डाल दिया गया है उदाहरणार्थ, भारतीय खाद्य निगम को 260 करोड़ रुपए का भुगतान, सार्वजनिक निगमों के 588 करोड़ रुपयों के ऋण को बट्टे खाते डालना तथा रक्षा भुगतानों के समायोजन के लिए 100 करोड़ रुपए। यावद् इन भुगतानों को इस वर्ष में उचित ढंग से दिखाया जाता तो यह घाटा इससे अधिक होता।

इस घाटे के साथ-साथ पेट्रोल तथा पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों और रेल भाड़े, दूरसंचार, डाक प्रचारों तथा उत्पाद शुल्क में बृद्धि के कारण भी मूल्यों में बृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय मोर्चा के घोषणा पत्र में कहा गया है कि गरीबी हटाने तथा अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मूल्यों में स्थिरता लाना आवश्यक है। मूल्यों को स्थिर करने की कोई सम्भावना नहीं है। वस्तुतः हम अत्यधिक मूल्य बृद्धि से परेशान हैं। इसलिए राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने ये बाधे पूरे नहीं किए हैं।

घाटे की अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त दूसरा दीर्घकालीन कारक काला धन है जिसके कारण विगत वर्षों से मूल्यों में बृद्धि होती रही है। काले धन की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। परन्तु विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि यह बहुत बड़ी मात्रा में है और यह मूल्य स्तर पर अत्यधिक दबाव डालता है। इस काले धन से अत्यधिक असमानताएं, नबधनाइयों द्वारा नकली आश्चर्यपूर्ण जीवन और धनी व्यक्तियों द्वारा गरीबों पर अत्याचार तथा आर्थिक शोषण जैसे अनेक गम्भीर सामाजिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं।

हम वित्त मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हैं कि काला धन एक सामाजिक अपराध और आर्थिक बुराई है। हम उनकी भावनाओं से सहमत हैं। परन्तु उन्होंने हमें यह नहीं बताया है कि काले धन के सृजन में कमी करने के लिए उनका क्या विचार है। वह कहते हैं कि लोगों के पास मौजूद काले धन का पता लगाने की बजाय इसके सृजन पर रोक लगाना अधिक महत्वपूर्ण है। उनका काले धन के सृजन पर रोक लगाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं किया है। जहां तक काले धन का पता लगाने का सम्बन्ध है, उन्होंने कुछ सुझाव मांगे हैं।

मेरा सुझाव है कि काले धन के उपयोग की योजना बनाते समय गन्दी बस्तियों की सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारे लाखों लोग गन्दगी, दरिद्रता और बीमारी पैदा करने वाली अकथनीय परिस्थितियों में रह रहे हैं जो हमारी सभ्यता पर कलंक है। जब लाखों लोग ऐसी परिस्थितियों में जीवन निर्वाह कर रहे हैं तथा कुछ लोग आलीशान मकानों में रहते हैं तो हम इस देश को लोकतांत्रिक किस प्रकार कह सकते हैं। इसलिए मेरे विचार से गन्दी बस्तियों की सफाई को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरी प्राथमिकता कृषि पर आधारित छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना को देनी चाहिए। बड़े पैमाने पर श्रमिणी औद्योगिकीकरण के द्वारा ही हम अपने देश के लाखों युवाओं और युवतियों को, जो प्रत्येक वर्ष रोजगार की तलाश में सम्मिलित होते हैं, रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। केवल इसी तरीके से हम बड़ी मात्रा में रोजगार बुटा सकते हैं, अन्य दूसरे तरीके से नहीं।

तीसरे, मकान निर्माण के लिए निम्न तथा मध्यम आय वर्ग को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि हमें स्रोतों की, जहाँ से धनराशि प्राप्त हुई है, जांच करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा किया जाएगा तो यह समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इच्छुक व्यक्तियों, विशेषतः व्यापारियों ने काले धन के उपयोग के सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिए हैं। परन्तु मैं सोचता हूँ कि उन्होंने ये सुझाव अपनी व्यापारिक गतिविधियों में सुधार अथवा सहायता के लिए दिए हैं।

मैंने जो उपर्युक्त तीन सुझाव दिए हैं उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

वित्त मंत्री महोदय ने बजट सम्बन्धी परिणामों की अर्द्ध-वार्षिक समीक्षा का वायदा किया है। यह अच्छी बात है।

प्रो० मधु बच्छवते : मैंने इसमें संशोधन किया है। अब इसे तिमाही किया जाएगा।

श्री बाई० एस० महाजन : यह एक अच्छी बात है परन्तु मैं आशा करता हूँ कि इस अवसर पर और कर नहीं लगाए जाएंगे।

प्रो० मधु बच्छवते : यह घाटे में वृद्धि के लिए नहीं है।

श्री बाई० एस० महाजन : धन्यवाद।

बहुत अधिक असन्तुलन केवल मुद्रास्फीति का ही नहीं बल्कि भुगतान सन्तुलन की कठिन स्थिति का कारण भी है। इस असन्तुलन का मुख्य कारण पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर हमारी निर्भरता है; इसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है और विदेशी ऋण बढ़ जाता है। इसके उपभोग तथा पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर रोक लगाने के लिए उन्होंने मोटर स्प्रिट, हार्ड स्पीड डीजल ऑयल तथा विमानन टरबाइन ईंधन के मूल्यों में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है। यह नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि इसके परिणामस्वरूप पेट्रोलियम पदार्थों की मांग में कमी नहीं आती। विगत अनेक वर्षों के अनुभव से स्पष्ट है कि पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के बावजूद प्रत्येक वर्ष पेट्रोलियम उत्पादों में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसलिए मेरा सुझाव है कि मूल्यों में वृद्धि के उपायों को अपनाने के बजाए वित्त मंत्री महोदय को और अधिक कृओं की खुदाई पर ध्यान देना चाहिए। हाल ही में अनेक पेट्रोलियम स्रोतों की खोज की गयी है। यदि आप इन सब बातों पर विचार करें और घरेलू उत्पादन में वृद्धि करें तो विदेशी स्रोतों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी।

विगत तीन या चार वर्षों के दौरान निर्यात के क्षेत्र में हमारी अच्छी उपलब्धि के बावजूद आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भुगतान सन्तुलन पर दबाव जारी रहने की संभावना है। यह एक मान्य राय है। निकट भविष्य में सन्तुलन की उपलब्धि निर्यात की सतत वृद्धि पर निर्भर है। ऐसी नीतियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा हमारी व्यापार नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जो आयातित औद्योगीकरण को निरुत्साहित करे और आर्थिक वृष्टि से सक्षम आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करे। इस नीति के अन्वयान में हमें विनिमय दर में उतार-चढ़ाव की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। निर्यात में अधिकांश वृद्धि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में रुपए के मूल्य में पर्याप्त ह्रास के कारण होती है। विगत दस वर्षों के दौरान डालर की तुलना में रुपए के मूल्य में इतनी अधिक गिरावट आई

है कि आज एक डालर की कीमत 16 रुपए 80 पैसे है जो 1980 में रुपए 80 पैसे थी। इससे प्रमुख मुद्राओं जैसे पौंड स्टर्लिंग, येन, ड्यूग मार्क की तुलना में रुपए के मूल्य में ऐमा ही अबमूल्यन स्पष्ट हो जाता है। यद्यपि हम अन्य मुद्राओं के सन्दर्भ में रुपए का बाहरी मूल्य व्यक्त करते हैं परन्तु डालर के सन्दर्भ में इसमें जो परिवर्तन होता है वह बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका हमारे व्यापार का प्रमुख साझेदार है। बिगत दो वर्षों के दौरान ही डालर की तुलना में रुपए में 33 प्रतिशत का अबमूल्यन हुआ है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रतियोगी लाभ में उल्लेखनीय लाभ की बजाए रुपए के अबमूल्यन के कारण ही व्यापार घाटे में कमी आयी है। इस मामले के सम्बन्ध में विचार करते समय हमें क्सी क्बल के सन्दर्भ में रुपए की विनिमय दर पर भी ध्यान देना चाहिए। आर्थिक मामलों में क्स के लोग पक्के सौदेबाज होते हैं। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्बल के साथ विनिमय दर निर्धारित करते समय व्यापार के सन्दर्भ में हमें घाटा न हो।

7.00 म० प०

महोदय, लघु औद्योगिक एककों का हमारे औद्योगिक विकास में बड़ा महत्व है। उनमें से लाखों एककों में हमारे कुल औद्योगिक उत्पादन का 50 प्रतिशत उत्पादन होता है तथा वे रोजगार प्रदान करते हैं क्योंकि उन्हें प्रति शीर्ष कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारी नीति इन एककों को प्रोत्साहित करने की होनी चाहिए क्योंकि वे उद्योगी आधार का विस्तार करते हैं और बिकेन्द्रीयकरण के लिए रास्ता बनाते हैं। केन्द्रीय निवेश छूट को पुनः शुरू करना आवश्यक है। जितना जल्दी इसे किया जाएगा, उतना ही बेहतर होगा। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदय सभा के समक्ष शीघ्र ही कोई योजना प्रस्तुत करेंगे। लघु उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बड़े लाभप्रद हैं। मेरा वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि योजना बनाते समय उन एककों की सहायता की जाए जिनका नुकसान हुआ है तथा जिन्होंने निर्धारित समय में निवेश-छूट के लिए आवेदन किया है तथा जिनके आवेदनों पर राज्य स्तर की समितियों ने विचार किया था परन्तु छोटे-छोटे प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों अथवा अचानक योजना को अचानक वापस लेने के कारण निर्णय नहीं लिया जा सका था। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि वित्त मंत्री महोदय केन्द्रीय निवेश सम्बन्धी छूट की पुनरीक्षा करते समय इस मामले पर सावधानीपूर्वक ध्यान देंगे।

इसके अतिरिक्त, मैं कुछ शब्द सरकारी क्षेत्र के, जिसमें मेरी बड़ी रुचि है, बारे में कहना चाहता हूँ। सरकारी क्षेत्र ने हमारे औद्योगिक विकास की नींव डाली है। इसने न केवल हमारे औद्योगिक विकास के लिए ही बल्कि कृषि विकास के लिए भी आधारभूत संरचना तैयार की है। इसलिए सरकारी क्षेत्र के एककों की क्षमता में वृद्धि का हमारी नियोजित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत विकास में बड़ा महत्व है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदय उद्योगों के प्रबन्ध तथा स्वायत्त में श्रमिकों की भागेदारी के लिए शीघ्रता से कार्यवाही करेंगे जैसाकि उन्होंने विचार किया है। इन एककों को अपने संसाधनों के माध्यम से अपना विकास करने योग्य होना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के कार्यकरण में रुचि रखने के नाते मेरा वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि द्विवार्षी और बिगत सरकार की तरह सरकारी क्षेत्र पर यथासम्भव ध्यान दिया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी क्षेत्र अर्थव्यवस्था का कर्णाधार बना रहे। तथापि यह संदेहास्पद है कि क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योग आगामी वर्ष तक मूल्य वृद्धि के बिना 4,506 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन जुटा सकेंगे जैसी कि वित्त मंत्री महोदय ने आशा की है। वित्त मंत्री महोदय को हमारे देश के उन लोगों के गुमराह करने वाले

तकों का शिकार नहीं होना चाहिए जो निजी व्यक्तियों को पूंजी का एक भाग बेचने के रूप में निजीकरण करने अथवा निजी पूंजीपतियों को सरकारी क्षेत्र के एकक बहुल क्षेत्र में उद्योग शुरू करने की अनुमति देने की मांग कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाएगा; क्योंकि समूचे विश्व में निजीकरण की बात चल रही है। रूस और पूर्वी यूरोप भी सरकारी उद्यम के प्रति अपने पुराने कठोर रबैये को छोड़ने की बात की जा रही है।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : धन्यवाद; आप इसके विरोधी नहीं हैं।

श्री बाई० एस० महाजन : मुझे आशा है कि इन प्रस्तावों पर विचार करते समय वित्त मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि जो कुछ भी परिवर्तन किए जाएं, अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र का प्रभुत्व बना रहेगा।

सरकारी क्षेत्र श्री जवाहरलाल नेहरू की कल्पना और योग्यता का एक कीर्ति स्तम्भ है। यह हमारी आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूंजीपति ताकतों द्वारा समाज का शोषण न किया जाए। शुरू में हमने निश्चय किया था कि मूलभूत उद्योग सरकारी क्षेत्र में होंगे तथा उस समय निजी पूंजीपति इस स्थिति में नहीं थे कि वे अपने संसाधनों से इन उद्योगों को शुरू कर सकें सरकारी क्षेत्र ने देश के आर्थिक विकास में काफी योगदान किया है।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। वित्त मंत्री जी, मैं आपके ध्यान में एक आम समस्या लाना चाहता हूँ जिस पर पहले ध्यान नहीं दिया गया है। यद्यपि हमारा देश राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन शुरू करने वाला पहला देश था और हमने इस दिशा में काफी प्रगति की है तथा जन्मदर कम हो रही है, तथापि जन्मदर को कम करने की गति धीमी है तथा केवल 35 प्रतिशत दम्पतियों ने ही इस योजना का लाभ उठाया है। चाहे यह आंकड़े सही नहीं हैं; कभी-कभी आंकड़े सही नहीं होते। कभी-कभी एक ही दम्पति की दो बार गणना हो जाती है और जिस दम्पति का नसबन्दी आपरेशन किया जाता है उसके पहले ही पांच या छः बच्चे होते हैं। हम तीस वर्ष से अधिक उम्र की महिला के और बच्चा न होने देने सम्बन्धी अपने उद्देश्य से अभी बहुत दूर हैं। हमें उन दम्पतियों का आपरेशन करना चाहिए जिनके दो बच्चे हैं। इससे जनसंख्या की वृद्धि को कम करने में बहुत सहायता मिलेगी।

मैं वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि हमारा देश चाहे जितना भी सम्पन्न हो जाए लेकिन हमारे पास इतनी विशाल और बढ़ती हुई जनसंख्या को बढ़िया जीवन-स्तर प्रदान करने के संसाधन नहीं हैं। दोनों तरफ की पार्टियों और राजनीतिज्ञों को यह महसूस करना चाहिए कि अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हमें जनता के विरोध का भय नहीं होना चाहिए। अब लोगों ने परिवार नियोजन के महत्व को महसूस कर लिया है। इस क्षेत्र में कुछ ठोस सामाजिक कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए, मैं सुझाव देता हूँ कि हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि यह कार्यक्रम तेजी से बढ़ सके। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे अपनाने वालों को प्रोत्साहन दिए जाएं और इस पर अमल न करने वालों को अनुत्साहन दिए जाएं तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि परिवार नियोजन एक सरकारी कार्यक्रम के बजाए एक जनान्दोलन बने। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक हमारी अधिकतर सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याएं, जो इसके कारण असाध्य हो गई हैं, को साध्य नहीं किया जा सकेगा। मैं कई वर्षों से यह बात कहता आ रहा हूँ। कोई पार्टी और कोई

सरकार इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। इस विषय पर हम जितना कम ध्यान देंगे, उतनी ही हमारे लिए तथा हमारी भावी पीढ़ी के लिए समस्याएं उत्पन्न होंगी, यदि हमारी जनसंख्या इसी दर से बढ़ती रही तो 40 वर्षों के बाद हम जनता को उच्च जीवन स्तर देने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। हम देश में कानून और व्यवस्था भी कायम नहीं कर पाएंगे और इसलिए मैं सरकार से तथा वित्त मंत्री से वित्तीय समस्याओं से निपटने से पहले इन समस्याओं की ओर पर्याप्त ध्यान देने का अनुरोध करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब डा० बिप्लव दासगुप्त बोलेंगे।

डा० बिप्लव दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : मैं आज नहीं, कल बोलूंगा।

[हिन्दी]

श्री हरि शंकर महाले (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 31 मार्च को जनरल विधेयक यहां रखा था और आज वित्त विधेयक रखा है। मुझे उम्मीद है कि ये ये जो वित्त विधेयक और जनरल बजट पेश किया गया है, इसको देखते हुए हमारी आर्थिक स्थिति में स्थिरता और अमता जरूर आएगी क्योंकि पहले कृषि के लिए 32 प्रतिशत बढ़ावा दिया जाता था, लेकिन अब गरीबी दूर करने के लिए 23 प्रतिशत बढ़ावा दिया है। केन्द्रीय योजना और परियोजनाओं के लिए इस सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए और कृषि आदि के लिए कुल बजट का लगभग 49, 50 प्रतिशत भाग निश्चित किया है। इस प्रकार से इन कामों के लिए ज्यादा रकम दी है। ग्रामीण विभाग में परियोजना के लिए बजट में 14 प्रतिशत रकम ज्यादा बढ़ गई है। राज्य योजना के लिए 23 प्रतिशत रकम ऋण सहायता देने के लिए घोषणा की है। चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार गारंटी देने के लिए भी तय किया है, कृषि नीति का संकल्प किया है, यह बात बहुत गर्व की है। कालाधन रोकने के लिए भी मंत्री महोदय ने जोर से बात की है, मुझे आशा है कि कालाधन रोकने में यह सरकार समर्थ हो जाएगी। बिलायिता की वस्तु में कर कुछ ज्यादा बढ़ गया है, यह ठीक है। प्राप्ति के लिए पुनर्गठन किया है, यह भी ठीक है। लेकिन प्राप्ति कर मंत्री महोदय ने 18 से 22 हजार तक किया है, उसे 25 हजार तक करना चाहिए था। मेरी मांग है कि इस पर सोचना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनता दल का सदस्य हूँ। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो कार्यक्रम किया, यह सहकारी बैंक का है ऐसा वायदा नहीं किया था, दस हजार कर्जा माफ करने का वायदा किया था। अभी वित्त मंत्री जी ने बोला है कि 50 प्रतिशत कर्जा राज्य सरकार देगी और 50 प्रतिशत भारत सरकार देगी। मैंने दो-चार मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि यह तो केन्द्र का सबाब है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री मधु दण्डवते : महाले जी, कई राज्यों की असेम्बलियों ने 12-13-16 हजार तक प्रस्ताव किया है।

श्री हरि शंकर महाले : मेरी मांग है कि राज्य सरकार पर दबाव डालना चाहिए और आधा-आधा कर्जा देने के लिए करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वित्त मंत्री जी समाजवादी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बत्ती जलती है लेकिन नीचे धोड़ा अग्घेरा हो जाता है। ऐसा सगता है कि हर घर के बने कपड़े में और मिलों के कपड़े में अन्तर है। हथकरघा के लोग बहुत काम करते हैं, बहुत कपड़ा बनाते हैं। मेरी मांग है कि इसमें जरा ज्यादा अन्तर रखा जाए ताकि मिलों के कपड़े के मुकाबले हथकरघा के

कपड़े पर कम टैक्स लगे। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। आर्थिक स्थिति स्थिर रखने के लिए इस बिल का उपयोग जरूर होगा और देश का भला होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।

श्री राघवजी (विदिशा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक समय के सिद्धार्थ कालेज के विज्ञान के प्रोफेसर ने जब पिछली बार एक अर्थशास्त्री के रूप में बजट प्रस्तुत किया तो ऐसा लगा कि बहु-आयामी प्रतिभा का परिचय दिया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे बैज्ञानिक से अर्थशास्त्री बन गए बल्कि इस बीच में यातायात के प्रभारी रहकर रेलमंत्री का कार्य भी किया। और बिपक्षी दल के नेता के रूप में कार्य किया है। एक बहुआयामी प्रतिभा का बजट इन्होंने पेश किया है। वैसे तो इनके नाम से ही मिठास आ जाता है। परन्तु इस बजट में मधु कम छिड़का गया, कड़वी दवा ज्यादा छिड़की गई है, इसमें फूल कम बिछाए गए हैं, कांटे ज्यादा बोए गए हैं। हालांकि यह बात ठीक है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था पिछली सरकार ने बता दी उस कारण से आपका काम इतना कठिन था। आपकी यह कठिनाई मैं समझता हूँ। स्थिति यह है कि जब इस सरकार ने सत्ता सम्भाली, सरकार के ऊपर 2 लाख 60 हजार करोड़ का कर्जा था। देशी और विदेशी कर्जा मिलाकर और प्रति वर्ष 17 हजार करोड़ रुपए का ब्याज चुकाना पड़ता है। जितना हम अपने डिफेंस में खर्च करते हैं, उससे ज्यादा ब्याज चुकाने पर खर्च करना पड़ रहा है। यह स्थिति कांग्रेस की सरकार ने पिछले 40 वर्षों में करके छोड़ दी है।

जहां तक विदेशी व्यापार का सवाल है, उसकी हालत भी बहुत खराब हो गई है। विदेशी व्यापार एक समय 1950 में हमारा कुल विश्व का जितना व्यापार हुआ करता था, उसका 2.2 परसेंट विदेशी व्यापार भारत करता था लेकिन आज स्थिति यह है कि हम 0.45 परसेंट व्यापार पूरे विश्व के व्यापार के मुकाबले में कर रहे हैं। यह स्थिति कांग्रेस के राज में इस देश की हो चुकी है।

जहां तक डेफिसिट फाइनांसिंग का सवाल है, सारे पिछले कीर्तिमान कांग्रेस ने तोड़ दिए हैं जिसके कारण से भयंकर मुद्रास्फीति हुई है। इसी प्रकार से काले धन का भी प्रचार और प्रसार जितना पिछले 40 वर्षों में हुआ है, ऐसा लगता है कि सामान्यतर रेखा की अर्थव्यवस्था चल रही है।

जहां तक इस देश की गरीबी का सवाल है गरीब राष्ट्रों में हमारी गिनती नीचे से 21वें नम्बर पर है। हमारी जनसंख्या पूरे विश्व के मुकाबले में 15.5 परसेंट है। हमारी प्रति व्यक्ति आय विश्व की कुल आय का मात्र 1.5 परसेंट है। इस स्थिति में और ऐसी पृष्ठभूमि में बजट प्रस्तुत करना कितना कठिन कार्य है, यह समझा जा सकता है। शायद इसलिए मधु जी ने उचित समझा कि कुछ कड़वी दवा मिलाना जरूरी है ताकि मजं जल्दी ठीक हो जाए।

आयकर की सीमा 18 हजार से बढ़ा कर 22 हजार की गई है। वह सीमा 22000 करने से कुछ नाममात्र को ही राहत मिल पायी है। 1985 में यह सीमा 18 हजार की गयी थी। 1985 के मूल्यों की आज के मूल्यों से गणना की जाए जिसमें 8.7 परसेंट प्रति वर्ष कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, वह 18 हजार रुपए आज के 27 हजार रुपयों के बराबर है। अगर आप इसको 27000 करते तो भी 1985 की स्थिति में कायम रहते; वर्ष 1981 की स्थिति ली जाए तो उस समय 15 हजार रुपए की सीमा थी, ऐसे में 32 हजार की छूट करते तो 1981 में पट्टूच पाते। आज 22000 रुपए की सीमा का कोई औचित्य समझ नहीं आता है। अगर यह सीमा 30 हजार, 25 हजार या फिर 24 हजार ही

मान लेते तो यह समझ सकते थे कि दो हजार प्रति माह कमाने वाले व्यक्ति को आपने कुछ छूट दे दी है लेकिन 22 हजार की छूट की सीमा हमारे समझ में नहीं आई है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह इस पर पुनर्विचार करें क्योंकि यह 22 हजार की छूट अपर्याप्त है खास तौर से उनके लिए जिनकी आमदनी सीमा से बोझी अधिक होती है। उनके लिए तो यह बहुत कष्टदायक है। अगर आप इसको 30 हजार नहीं कर सकते तो 25 हजार या 24 हजार इसे अवश्य करें।

अब मैं रजिस्टर्ड फण्ड के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। एक समय था जब रजिस्टर्ड फण्ड में 50 हजार से अधिक आमदनी होने पर टैक्स लगता था लेकिन बाद में इसे बढ़ा कर 10 हजार कर दिया। अभी इसको बढ़ाया गया है और 15 हजार तक कर दिया है। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। रजिस्टर्ड फण्ड का मतलब है कि कम से कम दो व्यक्ति मिलकर या फिर दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार कर सकते हैं। अगर दो व्यक्ति मिलकर व्यापार कर रहे होंगे तो भी छूट की सीमा 15 हजार तक सीमित रह गई है। इसका मतलब यह है कि प्रति व्यक्ति को साढ़े सात हजार प्यए मिलेंगे तो भी उसे टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा उनका व्यक्तिगत आय पर भी टैक्स लगता है। वह सब होने के बाद रजिस्टर्ड फर्म में मात्र 15 हजार की छूट ही क्यों रखी है। यह मुझे आज तक समझ में नहीं आया। यह छूट 50 हजार करनी चाहिए तभी इसका कोई औचित्य है। 8000 से 22000 व्यक्तिगत छूट की सीमा कर दी लेकिन संयुक्त हिन्दू परिवार के मामले में यह छूट सीमा 12 हजार ही कायम है। यह लम्बे समय से चली आ रही है और इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है इसलिए इस 12 हजार में भी वृद्धि करनी बहुत जरूरी है। यह संयुक्त हिन्दू परिवार के साथ अन्याय है, अगर यह छूट नहीं बढ़ाई गयी। बहुत लम्बे समय से 80सी के जो कटौतियाँ हैं, वह प्रथम 6 हजार पर प्रतिप्रतिगत और इसके बाद 50 प्रतिशत डम रूप में चले आ रहे हैं, इसमें थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। वर्तमान परिवर्तन वैज्ञानिक अवश्य है और जो खास तौर से गणित का प्रोफेसर होगा, वही इस प्रकार का परिवर्तन कर सकता है और उन्होंने अपनी वह कला दिखाई है। उसमें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह 10 हजार की सीमा और 20 परसेंट में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए, क्योंकि लम्बे समय से 6 हजार वाली बात चली आ रही है, उसको देखते हुए 20 की जगह 30 परसेंट कर देते, अधिकतम सीमा 10 की जगह 15 हजार कर देते तो इसका कोई औचित्य होता, इसलिए मैं माननीय वित्त जी से मांग करूंगा कि इस बारे में भी पुनर्विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आयकर कानून, सम्पत्ति कर कानून, गिफ्ट टैक्स, इन सबके सरलीकरण की बहुत आवश्यकता है, जितनी कानून की निरर्थक जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं, जितने एग्जेंडमेंटस होते हैं, जितने संशोधन होते हैं, उतनी जटिलतायें और बढ़ती जा रही हैं और बहुत सी छोटी-छोटी तकनीकी त्रुटियों के कारण से एक-एक लाख तक की शास्ति के प्रावधान रखे गए हैं, जिसका कोई धर्म, जिसका कोई औचित्य नहीं है। मैं एक दो उदाहरण इस उारे में देना चाहता हूँ और इस मामले में चाहता हूँ कि जरूर संशोधन किए जायें। धारा 271ए, इसमें अगर कोई व्यक्ति लेखा पुस्तिकायें ठीक से नहीं रख पा रहा है तो इसके लिए अधिकतम जुर्माना एक लाख रुपये है, इसका कोई औचित्य नहीं है। लेखा पुस्तिकाएं कई लोग अज्ञानतावश भी नहीं रख पाते हैं, कई लोगों को उसकी जानकारी ठीक तरह से नहीं होती है, वह नहीं रख पाते हैं और इसलिए उनके ऊपर एक लाख अधिकतम शास्ति की राशि प्रस्तावित की जाय, यह बहुत गलत है और इसलिए मैं प्रस्तावित करता हूँ कि यह अधिकतम धीमा जो एक लाख रखा गया है उसको दस हजार तक किया जाय। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का 40 लाख से ऊपर का टर्न ओवर है तो उसको ऑडिट कराना है। कई बार कुछ लोगों के टर्न ओवर 40

लाख से कम होते हैं लेकिन किसी वर्ष अचानक बढ़ जाता है, 40 लाख हो गया और उनको कोई ध्यान नहीं रहता, क्योंकि, उनका पहले ऑडिट का काम नहीं पड़ा है और इसलिए वह ऑडिट नहीं करा पाता है तो आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसे प्रकरणों में जुर्माना कितना है, जुर्माना कुल विक्रय राशि का आधा प्रतिशत और एक लाख रुपया, दोनों में से जो भी कम हो। अर्थात् एक लाख रुपये का जुर्माना तो उसको लग ही जाएगा। उसकी कोई महत्वपूर्ण त्रुटि नहीं है, बड़ रिटर्न भर रहा है, टैक्स भर रहा है, पैसा जमा कर रहा है, उसके बाद भी एक तकनीकी त्रुटि के कारण से उसको एक लाख रुपया जुर्माना भुगताना पड़ रहा है। इससे कितना झंझटाचार पनप रहा है, यह कल्पना बही लोग कर सकते हैं जो इसको भुगत रहे हैं इसलिए इस तरह के प्रावधान निकाले जाने चाहिए और एक लाख रुपए जुर्माने की जगह अगर एक हजार, दो हजार, पांच हजार कर देते तो पर्याप्त था।

इसी प्रकार से 271डी का प्रावधान है, जिसके ऊपर जुर्माना अनिवार्य रूप से अगर किसी से भूल से भी कोई भुगतान 20 हजार रुपए का बजाय चैक के नकद में हो गया तो अनिवार्य रूप से शास्ति 20 हजार रुपए की ही लगेगी, चाहे भूल से हो गया हो, चाहे पहली बार हुआ हो। इसमें 'शैल' शब्द है इसलिए 'शैल' को हटाकर 'मै' करना चाहिए। इसी प्रकार से 271ई है। एक और प्रावधान है जिसके बारे में मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वह है संकथन 272ए (2), इसमें बहुत ही छोटी तकनीकी त्रुटि के कारण से आयकर विधान में एक कानून बना दिया गया है कि जो ब्याज चुकाएगा, डिबीडेंड चुकाएगा उसको उसमें से 10 प्रतिशत टैक्स काटकर सरकारी खजाने में जमा करना पड़ेगा। ब्यापारी 10 परसेंट काट रहा है, सरकारी खजाने में जमा भी कर रहा है लेकिन उसको एक फार्म भरना पड़ता है, जो इन्कम टैक्स आफिसर को 30 दिन के अन्दर भेजना पड़ता है। वह 26ए और 27ए का फार्म उसने नहीं भरा है तो मालूम है, उसका जुर्माना कितना है? उसका जुर्माना प्रति दिन 200 रुपए है। अगर भूल से वह बात तीन साल तक चली जाए, 4 साल तक चली जाए तो उसको डेढ़ दो लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा और वह अनिवार्य है। इस मामले में परिवर्तन करना चाहिए और इसको ठीक करने की आवश्यकता है।

अब मैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कहना चाहता हूँ। आपने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, इसका मुख्यतः भार या बोझ जो पड़ने वाला है, वह कुल मिलाकर आम जनता पर आ रहा है। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़नी शुरू हो गई है। इसका प्रभाव यातायात पर पड़ता है। बसों में डीजल प्रयोग होता है, स्कूटर में पेट्रोल प्रयोग होता है, ये दोनों ही आम जनता के प्रयोग में आने वाले साधन हैं। ट्रेन के किराए बढ़े हैं, इसका असर भी पड़ेगा। इसी प्रकार से सारे बाहन डीजल प्रयोग करते हैं और 80 प्रतिशत वाहन सरकार के हैं। सरकार का खर्चा बढ़ेगा, इसलिए इस पर आपको पुनर्बिचार करना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है उससे सारी अर्थ-व्यवस्था चौपट हो जाएगी। इससे किसानों को घाटा है, यात्रियों को घाटा है, उद्योगों को घाटा है, उपभोक्ताओं को घाटा है, इससे सब को परेशानी होगी। इसलिए इस पर आपको पुनर्बिचार करना चाहिए।

माचिस के बारे में वही पुराना 1990 का टैक्स स्ट्रक्चर ठीक से लागू करेंगे तो जो दस हजार छोटे उद्योग हैं माचिस बनाने वाले, उनको लाभ होगा। फूब प्रोसेसिंग में जो टिन प्रयोग होता है, उसके ऊपर आपने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। उनके द्वारा जो माल पैदा होता है, उसमें एक्साइज ड्यूटी बढ़ा

दी गई है। इस बारे में भी आपको पुनर्विचार करना चाहिए। टायरों के दाम भी अनाप-शनाप बढ़ाए गए हैं। इसलिए इसके बारे में पुनर्विचार होना बहुत ही जरूरी है। कर्जा माफी के बारे में चर्चा की गई है, कर्जा माफी के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत कुछ घोषणाएँ की हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। को-ऑपरेटिव बैंक का भी पचास प्रतिशत केन्द्र सरकार अदा करें, लेकिन यदि आनाबारी की पद्धति लागू की, तो किसी के कर्ज माफ नहीं होंगे। यह एक छलावा है और भुलावा है, क्योंकि छः आने की स्थिति में कर्ज माफी घोषित होना इतना व्यर्थ काम है कि उसमें लाभ मिलने वाले किसानों की मुश्किल से पांच प्रतिशत संख्या भी नहीं होगी। उनको बिलफुल डिफाल्ट माना जाएगा, जो आनाबारी में शामिल नहीं है। इसलिए यह स्कीम आनाबारी पर लागू की गई तो यह सारी स्कीम बेकार है। इसलिए आनाबारी को खत्म किया जाए। आनाबारी में कहीं ऐसा नहीं होता है कि कोई बिलफुल डिफाल्ट कर रहा है। आनाबारी की बात को समाप्त करके मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सरकार के पास जो योजना प्रस्तुत की है, उसको आप पूरा-पूरा स्वीकार कर लें, तो किसानों को लाभ प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने जो फार्मूला प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने यह कहा है कि खेती के अतिरिक्त किसी का दूसरा आय का स्रोत है तो छूट नहीं मिलेगी। जो सरकारी नौकरी करता है, और खेती भी करता है, उसको छूट नहीं मिलेगी। इस प्रकार से ऐसी कुछ बातों को छोड़कर बाकी सब लोगों को जिन्होंने ट्रैक्टर खरीदा है, बड़े-बड़े कर्ज लिए हैं ट्रैक्टर और स्ट्रिकल के लिए, लाखों में कर्ज लिया है, इनके अलावा बाकी सब किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। वही योजना अगर वित्त मंत्री जी स्वीकार कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन आनाबारी से कोई लाभ किसानों को होने वाला नहीं है।

श्री के० डी० मुस्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से वित्त मंत्री महोदय द्वारा जो फाइनेंस बिल प्रस्तुत किया है, मैं नहीं समझता कि इससे सारे राष्ट्र को मार्गदर्शन मिलेगा। जिस दिन से यह बजट प्रस्तुत हुआ है, उस दिन से आज महंगाई ने जो रूप धारण किया है, उससे आम जनता पिसती जा रही है। इसके बावजूद भी सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। सबसे बड़ी बात यह हुई है कि दण्डबते जी के समय में सारे राष्ट्र में हाहाकार मचा हुआ है, हर जगह लोग एजीटेशन कर रहे हैं कि महंगाई को कम करो, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आपने डीजल के दाम बढ़ाए, आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए, इससे बड़ा भारी फर्क पड़ता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र के अन्दर महंगाई की वजह से गरीब लोग तंग हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो वित्त बिल रखा है, मैं उसका विरोध करता हूँ। मोर्चा सरकार ने लोगों से झूठे वायदे किए थे कि जैसे ही आप वोट डाल कर आगे लाएंगे, हम गरीबी को खत्म करने के लिए पग उठाएंगे। लेकिन इस सरकार की नीति रही है कि भाषण द के इनकां खुश करो, एलान करके खुश करो। इस तरह से गरीबी खत्म होने वाली नहीं है और न ही इस प्रकार की क्षमता है सरकार में।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने को-ऑपरेटिव बैंक के कर्जों के बारे में कहा है कि 50 फीसदी कर्जा भारत सरकार देगी और 50 फीसदी वहाँ की राज्य सरकार देगी। मैं यह जानता हूँ कि हर जगह राज्य सरकार ने हर साल की तरह घाटे के बजट रखे हैं और जितने बजट इस साल पेश हों रहे हैं उन बजटों में टैक्स का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जब टैक्स नहीं लगेंगे तो उनके लिए आप न पैसा देंगे और न देने वाले हैं। जो लोग पैसे का दु्रूपयोग करते हैं उन लोगों को छूट मिलेगी। दस हजार रुपए के कर्ज की माफी से आम किसान का भला नहीं होगा। किसानों का भला तब होता

जबकि उनकी आर्थिक दशा सुधरती। यहाँ पर कहा गया है कि जिसके पास 50 एकड़ जमीन है और जिसकी फसल अच्छी होती है उसके कर्ज माफ करने की बात होगी। ऐसे लोगों के भाई आई०ए०एस० अफसर बन जाते हैं, एम० पी० बन जाते हैं, दूसरे अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे लोग कर्ज माफ करा ले जाएंगे। जो समाज में गरीब आदमी है, हम चाहते हैं कि उसको इसका लाभ मिले। आज हम कहते हैं कि जिसकी सात हजार रुपए की आमदनी है वह गरीबी रेखा से पार हो गया, सरकार यह मानती है कि वह गरीबी रेखा से निकल चुका है। लेकिन सात हजार तो उसी की आदमी की आमदनी होगी जो बहुत गरीब से गरीब है। आपने बस हजार रुपए की बात करके लोगों में बेईमानी फैलाने का काम किया है। कुछ को लाभ होगा, निर्धन छूट जाएंगे।

मैं समझता हूँ कि सही मायनों में आप गरीब लोगों का भला करना चाहते हैं तो खेतिहर मजदूरों के, हरिजन, आदिवासियों और छोटे किसानों के कर्ज माफ कीजिए। आपने ट्रेक्टर की कीमत बढ़ाई, आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए। इनका भी नुकसान किसानों को हुआ। इस कर्ज के लिए आपने एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इतनी रकम से किसान लाभ नहीं उठा सकेगा। आपने इलेक्शन से पहले एलान किया था कि आप दस हजार रुपए तक के हर किस्म के कर्ज माफ करेगे अगर आप इस पर कायम रहते हैं तो भी मैं समझता हूँ कि सरकार ने कोई अच्छा काम करने के बारे में सोचा है, मगर शहर के गरीब को भुला दिया।

आपने कहा कि वहाँ बन खेती लगाएंगे और इसके लिए पैसे का प्रावधान करेंगे। आपने कहा कि हम किसानों को ऊपर उठाने के लिए पैसे का प्रावधान करेंगे, हम मछुआरों को मदद करने के लिए काम करेंगे। आपने अभी अनाऊस किया कि मछुआरे के लिए टैक्स उठा दिया। मैं यह समझता हूँ कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश का, गढ़वाल का जो भी पहाड़ी इलाका है जहाँ कि पनबिजली योजनाएँ बन रही हैं उनमें राष्ट्र को कितना लाभ होगा। आपने पहाड़ी इलाकों में नदी-नालों पर जो बड़े-बड़े डेम लगाए हैं उन डेमों में भूमि का कटाव रोककर इनकी हिफाजत में बल लगाकर वहाँ पर भूमि का कटाव रोका जाए, पेड़ लगाए जाएं। अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो वहाँ पेड़ में फल वाले वृक्ष लगाने और दरख्त लगाने के लिए प्रावधान करें। आप बन-खेती लगाने की बात करते हैं। बन खेत तो हमेशा लगते हैं, हर साल लगते हैं। इसके लिए प्रावधान करने से क्या होता है कि जो राज्य सरकारें हैं वे इस पैसे का दुरुपयोग करेंगी। वह सारा पैसा ऐसे ही जाता है, उससे कोई प्लान्टेशन नहीं होता। मैं कहना चाहता हूँ कि जो पहाड़ी इलाके हैं, उनमें आप चाहते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और अच्छी भूमि के कटाव को रोका जाए तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप सारे पहाड़ी क्षेत्रों का सब राष्ट्रिय सरकार से करवा लीजिए और खुद आप अपनी एजेन्सी से भी इसका सब करवा लीजिए। जहाँ-जहाँ पर जमीन खाली पड़ी हुई है वहाँ पर बन खेती करने के लिए आप उनकी मदद करें और फोरेस्ट के लिए, बन-खेती के लिए जो पैसा रखा हुआ है, उसके लिए मैं आपको एक मुझाव दूंगा कि फलदार वृक्ष लगाने के लिए किसानों को अगर यह पैसा मिलेगा तो इससे उनकी खेती भी हो सकेगी और उनकी इन्कम भी बढ़ेगी। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कई जगह इस तरह की हैं, जैसे अभी आपने कहा है कि जो फौजी आदमी और सूबेदार हैं या अधिकारी हैं। मैं समझता हूँ कि उनके लिए पेंशन का प्रावधान किया जाना चाहिए और पेंशन इस तरह की होनी चाहिए, जो उनका पद है उसके हिसाब से जो आज का रिटायर है और पुराने रिटायरमेंट वाले लोग हैं, उन सबको समान पेंशन मिलनी चाहिए।

बिजली के बारे में मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जो आज बड़े-बड़े डेम हिमाचल प्रदेश में लव रहे हैं और उसके लिए स्वीकृति भी ही चुकी है लेकिन उसके लिए पूरे साधन उपलब्ध नहीं हैं। उसमें नाथपा साखड़ी है, उसमें 1500 (पन्द्रह सौ) मेगावाट बिजली पैदा होगी, उससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और इसके साथ-साथ पड़ोसी राज्यों की भी स्थिति मजबूत होगी। उसके लिए भी आप पैसे का प्रावधान करें और और हमारे प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में सेंटर द्वारा मंजूर है, उनके लिए आप ज्यादा से ज्यादा धन रखें। साथ ही साथ यह भी जरूर करें कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनके लिए भी आपको ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस देश के अन्दर जितने स्मगलर, टैक्स को न देने वाले और इन्कम को छिपाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के आंकड़े बहुत ज्यादा हैं और उनको आप बट्टे खाते में डाल रहे हैं। आप उनके ऊपर छापे मारिए और जो पैसा उनकी तरफ बकाया है, उसको बसूल करके, सरकारी खजाने में ला करके राष्ट्र के ऊपर उस पैसे को खर्च करें ताकि राष्ट्र के लोग आगे बढ़ सकें, वरना यही बड़े लोग ही पैसे को खाते रहेंगे।

आज हजारों-करोड़ों रुपये उनके पास हैं और उसको वे अपने इस्तेमाल में लगा रहे हैं और सरकार से कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। मैं आपकी यह बताना चाहूंगा कि जो इन्फ्लैटरीज है या ग्रामों में बड़े-बड़े लोग हैं, उन्हीं लोगों के पास ही ज्यादा पैसा होता है। आप यह पैसा उनसे बसूल करके राष्ट्र के लोगों पर लगाएं, जिससे आम जनता का भी भला हो सके और पूरे राष्ट्र का भला हो सके। इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है तभी यह राष्ट्र उन्नति कर सकता है।

श्री हेमेश्वर सिंह बनेड़ा (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक का समर्थन करते हुए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस सूझ-बूझ से उन्होंने बजट पेश किया है और जो विधेयक स्थिति हमें विरासत में पूर्व सरकार से मिली, वह इतनी बिगड़ी हुई मिसी थी, लेकिन इसके बाद भी आपने गरीब जनता के ऊपर बगीर कोई भारी बोझ डाले या भारी कर लगाए हुए यह वित्त विधेयक और बजट पेश किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं विशेष रूप से सरकार का ध्यान इस ओर आकषित करना चाहता हूँ कि जो चुनाव के समय हमने 10 हजार रुपए तक के कर्ज की माफ़ी की घोषणा की थी, उसमें आज छः महीने हो चुके हैं और केवल सरकार की तरफ से आश्वासन मात्र का ही शब्द सुनाई पड़ रहा है। हम जब कभी भी अपने क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे पहले हमसे यही सवाल किया जाता है कि जो 10 हजार रुपए तक के कर्ज माफ़ी की घोषणा आपने की, उसको कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया? मैं सरकार से अपेक्षा रखता हूँ कि जो भी कदम उठाने हों, जो भी आपको नियम बनाने हों, जिस तरह से भी कर्ज माफ़ी के लिए आपको राय लेनी हो, वह जो प्राति-शीघ्र ले करके उनकी तकलीफों को दूर करें। जिन काश्तकारों और दस्तकारों को वास्तव में तकलीफ है, उनको तुरन्त राहत दिलाने के लिए आप यह कार्य शीघ्र करें।

मैं यह निवेदन करूंगा कि आज भी विशेषकर के काश्तकारों और दस्तकारों ने जो मोन और कर्ज सरकारी संस्थाओं के माध्यम से लिए हैं, वह उनके ऊपर ज्यों के त्यों हैं। इन कार्य को आपको अपने हाथों में ले लेना चाहिए। विशेषकर काश्तकारों ने जो मोन लिए हैं, वहकारी संस्थाओं के माध्यम से लिए हैं। मैं इस बात का इसलिए जोर देकर उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि विशेषकर राबन्धान में सहकारी संस्थाएं अभी तक हमारे विरोधी भाव्यों के नियन्त्रण में हैं और सरकार को बदलाव करने के लिए गरीब काश्तकार को, जिसने बड़े हजार, दो हजार रुपया कर्जा लिया है, उसको हर 15 दिन के

बाद नोटिस भेज दिया जाता है, उन पर सक्ती की जा रही है। मेरा निवेदन है कि जब तक सारे नियम नहीं बन जाते, तब तक कम से कम कर्जा बसूली स्थगित करने के आदेश तुरन्त दे दिए जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य आज अभावग्रस्त स्थिति में है। उसके ऊपर अकाल की छाया मंडरा रही है। जून के महीने में पीने के पानी की समस्या हमारे प्रदेश के सामने इतनी भयंकर होगी इसका उल्लेख मैंने बार-बार किया है। अभी केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार को इसके लिए जो मदद दी है, वह बहुत ही कम है। राजस्थान के गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए यहां से और राशि दी जानी चाहिए, ताकि वहां की जनता को राहत मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं वित्त विधेयक के सम्बन्ध में तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, इन बातों का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ।

पहली बात यह है कि आयकर की सीमा 30000 रुपए तक बढ़ाने की मांग पूरे देश से आ रही है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि 30000 रुपए की आय हमारी सरकार की नजर में इतनी बड़ी आय कैसे दिखती है कि इस पर आयकर में छूट नहीं दी जा सकती। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि आयकर सीमा 18000 से बढ़ा कर कम से कम 30000 तक करनी चाहिए।

दूसरी बात, जिसका जनता से सीधा ताल्लुक है, वह है राशन में मिलने वाले गेहूँ की कीमत का, जिसको सरकार ने बढ़ाया है। राशन का गेहूँ कौन लेता है, कहां पर वितरित किया जाता है, जहां पर वास्तव में उसकी आवश्यकता होती है। गरीब आदमी, गरीब मजदूर, किसान उसको प्राप्त करता है। विशेष कर राजस्थान राज्य में जहां 6 वर्ष से किसान ने अपने खेतों में गेहूँ पैदा होते नहीं देखा, जहां पर अकाल है, उस किसान को इस गेहूँ की आवश्यकता है। राशन की दूकानों से गरीब लोगों को यह गेहूँ वितरित किया जाता है, उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। इससे गरीब किसान, मजदूर के दिल पर क्या बीत रही है, इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कम से कम राशन की गेहूँ की कीमत पहले की तरह ही रखनी चाहिए, इस बढ़ोत्तरी को वापिस लिया जाना चाहिए।

एक बात एस्टेट ड्यूटी के बारे में कहना चाहता हूँ। यह जो सम्पदा कर ब्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होने वाली सम्पत्ति पर लगाया जाता है, इसको लेने का उद्देश्य सरकार का यह है कि जिनको करोड़ों रुपए की सम्पत्ति प्राप्त होती है, उनसे टैक्स लिया जाए। मेरा सरकार से वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि इसकी सीमा बांध देनी चाहिए, 10-20-25 लाख रुपए की संपत्ति जिसको उत्तराधिकार में प्राप्त होती है, एक सीमा बांध कर इस पर टैक्स लिया जाना चाहिए, लेकिन 4-5 लाख या इसी तरह की और संपत्ति प्राप्त होने पर इस नियम के अन्तर्गत असेसी को बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है और उसको काफी परेशानी उठानी पड़ती है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, वन मैन-वन रैंक की घोषणा हमारी सरकार का एक बहुमूल्य और क्रांतिकारी कदम है। वन मैन वन रैंक की जो घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की, पूरे देश ने उसको सराहा है। इसको लागू किया जाए। साथ ही साथ, मेरा निवेदन है कि जो पूर्व सेना के आफिसर, मिलाटरी आफिसर, आर्मी आफिसर या नेवी आफिसर रिटायर हुए हैं उनको कम पेंशन मिलती है। क्योंकि उनकी तनखाह बहुत कम थी। तो उनकी पेंशन बढ़ाने की आवश्यकता है। जो आफिसर वर्तमान में

रिटायर होता है उसको आज की तनख्वाह के आधार पर पेंशन दी जाती है। पूर्व के जो आफिसर हैं, उनकी प्रतिशत वैसे ही बहुत कम है, उनको भी पेंशन आज के हिसाब से दी जाए तो उनको राहत मिल जाएगी। यह एक सही कदम होगा।

[अनुबाध]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम नाईक, अगर आप बोलना चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप अपना भाषण 10 या 15 मिनट में समाप्त कर सकते हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : मैं आज शुरू करूंगा, और कल समाप्त करूंगा।

प्रो० मधु बच्छवते : तब तो आप सारी रात बोलते रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, श्री नाईक, अगर आप बोलने के लिए तैयार हैं और आज ही समाप्त करते हैं, तो ठीक है। अन्यथा हम देखेंगे कल किसको बोलना है।

मुझे आशा है कि अन्य कोई सदस्य बोलना नहीं चाहता। सभा अब स्थगित होती है।

7.42 म० प०

सत्परचात् लोक सभा गुरुवार, 17 मई, 1990/27 वैशाख, 1912 (शक) के प्यारह बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।